

देवरिया जनपद के विकास में सेवा-केन्द्रों की भूमिका

**THE ROLE OF SERVICE CENTRES IN THE
DEVELOPMENT OF DEORIA DISTRICT**



**इलाहाबाद विश्वविद्यालय, की डी०फिल्० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध**

**सोधकर्ता
सतीश कुमार सिंह**

**निर्देशक
डॉ० बी०एन० सिंह**
ग्रामीण विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

**भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
2002**

प्राक्कथन

किसी भी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के प्रादुर्भाव एवं इनकी बढ़ती गहनता के साथ कुछ ऐसे बिन्दु अस्तित्व लेने लगते हैं, जिनपर क्रमशः विकास की प्रेरक इकाइयाँ स्थापित होती जाती हैं। कालान्तर में वह बिन्दु क्षेत्र के विकास का केन्द्र बन जाता है और क्षेत्रीय विकास में नियामक भूमिका निभाने लगता है। परिवहन के विभिन्न माध्यम इसी बिन्दु से प्रसरित होकर क्षेत्र में फैले होते हैं, जिनके सहारे वह अपने क्षेत्र को कार्य एवं सेवाएँ प्रदान करता है। इसी विशेषता के कारण इसे 'सेवाकेन्द्र' कहते हैं। क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा प्रशासकीय कारक इसके स्वरूप को तय करते हैं। इस प्रकार सेवाकेन्द्र मानवीय रचना है। इसका उद्भव-विकास मानव अधिवास की स्थापना से सम्बन्धित है, जिसका यह अभिन्न अंग है। चूँकि क्षेत्र में विकास का संचार इसी से होता है, अतः किसी भी क्षेत्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सेवाकेन्द्र पर स्थापित विकास के विभिन्न प्राचलो (कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) की इकाइयों की गहनता एवं क्षेत्रीय सम्बद्धता का सेवाक्षेत्र के आकार तथा विकास से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक सम्बन्ध होता है। अतः किसी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सेवाकेन्द्रों पर विकासात्मक इकाइयों की स्थापना से विकास प्रोत्साहित होगा। इसलिए क्षेत्र के समन्वित विकास के आयोजन के लिए प्रथमतः सेवाकेन्द्र एवं विकास के सम्बन्ध का विश्लेषण एवं विकास में इसकी भूमिका का विवेचन आवश्यक है।

शोध का उद्देश्य

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय 'देवरिया जनपद के विकास में सेवाकेन्द्रों की भूमिका', का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य जनपद के सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन, सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम, सेवाकेन्द्रों का क्षेत्रीय वितरण, सेवाकेन्द्रों की क्षेत्रीय अन्तर्प्रक्रिया एवं विकास ध्रुव के रूप में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। इस हेतु वर्णित परिकल्पनाओं का अपने क्षेत्र के सन्दर्भ में परीक्षण करना है, जिससे नियोजकों को सेवाकेन्द्र एवं विकास के पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात हो सकें तथा क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु वे उन सेवाकेन्द्रों का चयन कर सकें जिनपर विकास के आधारभूत अवस्थापनाओं की स्थापना कर क्षेत्र का समन्वित विकास किया जा सकता है।

विकासोन्मुख क्षेत्रीय संरचना की यह रूप रेखा अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक, ऐतिहासिक स्वरूप विवेचन, उनमें सेवाकेन्द्रों का उद्भव विकास उनका क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्रीय अंतर्प्रक्रिया

तथा क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका के अवलोकन के उपरान्त ही प्रस्तुत किया जा सकता है। स्पष्ट है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु सेवाकेन्द्रों की भूमिका का विश्लेषण करना ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन क्षेत्र का चयन

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यगंगा मैदान में स्थित देवरिया जनपद का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन के पीछे प्रधान कारण विकास के लिए आवश्यक ससाधनों की उपलब्धता के बावजूद इसका पिछड़ापन रहा है। समतल भूमि एवं उर्वर मृदायुक्त श्रमबहुल यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, परन्तु ससाधन, प्रशिक्षण, तकनीकी-ज्ञान के अभाव एवं अशिक्षा के कारण कृषि प्रधान इस क्षेत्र में कृषि कार्य परम्परागत एवं जीवन निर्वाहन स्तर का है।

कृषि आधारित उद्योगों की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, कुछ उद्योगों (चीनी उद्योग) का विकास हुआ भी पर अब इनकी बीमार स्थिति के कारण ये क्षेत्रीय विकास के प्रेरक न होकर, लागों के शोषक सिद्ध होते जा रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं, परन्तु लोगों की आर्थिक बदहाली, वित्तीय सेवाओं की अपर्याप्तता एवं सरकार की दोषपूर्ण नियोजन प्रणाली इसके विकास में गतिरोध बने हुए हैं। समतल भूमि के बावजूद परिवहन मार्ग की सम्बद्धता मात्र 52.13 प्रतिशत तक ही सीमित है, जिससे अध्ययन क्षेत्र के 47.87 प्रतिशत क्षेत्रों तक विकास का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। प्रतिवर्ष बाढ़ की आवृत्ति के कारण बरसात में सम्बद्धता और कम हो जाती है।

ज्ञान-विज्ञान के प्रति लोगों की अभिरुचि है तथा वे नवीनतम सूचना तकनीकों को जानने को जिज्ञासु एवं अपनाने को उत्सुक हैं, परन्तु अशिक्षा इसमें बाधक बन रही है। शिक्षण संस्थाएँ, ससाधन अपूर्ण हैं तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास का भी अभाव है।

ऊर्जा की उपलब्धता एवं खपत विकास की प्रतीक मानी जाती है। 90 प्रतिशत आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन प्रणाली अपनाने के आधी शताब्दी के बाद भी 29 प्रतिशत गाँव अभी भी अंधेरे में हैं, बिजली नहीं पहुँची है। शेष में उपलब्धता भी मात्र 11 घंटे औसत दैनिक ही है। ये स्थिति तब है जब विकास के लिए ऊर्जा की प्रत्येक क्षेत्र में माँग है और गैरपरम्परागत ऊर्जा संभाव्यता की दृष्टि से जनपद सम्पन्न है, पर इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है।

आवास एवं पेयजल सुविधा की अपर्याप्तता वाली घनी आबादी युक्त इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तथा जो हैं भी उनमें उचित प्रबन्धन का अभाव है।

अशिक्षा एवं पर्यावरण-बोध के अभाव में वनों की अधार्धुध कटाई के कारण यह क्षेत्र 'देवारण्य' से 'देवरिया' हो गया, पर जनता इसके होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति अनभिज्ञ है। अनपढ़ किसान सिंचाई की अनियोजित प्रणाली, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का मनमाना अधार्धुध

प्रयोग इस बात को जाने बिना ही कर रहा है कि इससे न सिर्फ उसकी लागत बढ़ रही है, बल्कि जलप्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के रूप में वह पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचा रहा है और खुद शिकार हो रहा है।

इस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र का चयन इसके सर्वांगीण विकास हेतु सेवाकेन्द्रों की भूमिका के परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ही किया गया। इस अध्ययन से पूर्वी उत्तरप्रदेश की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सेवाकेन्द्रों की उनमें भूमिका का आकलन किया जा सकता है।

शोध छात्र का इस क्षेत्र से निकटतम सम्बन्ध है तथा यहाँ की विभिन्न समस्याओं को निकटता से महसूस किया है। अतः उक्त विषय पर शोध के लिए प्रस्तुत क्षेत्र का चयन स्वाभाविक था।

अध्ययन की परिकल्पना

संकल्पनात्मक स्तर पर सेवाकेन्द्र एवं विकास की निम्न परिकल्पनाओं पर वर्तमान अध्ययन आधारित है।

1. सेवाकेन्द्र एक मानवीय रचना है, परन्तु इसके उद्भव एवं विकास में प्राकृतिक एवं मानवीय कारक एवं प्रक्रियाएँ कार्य करती हैं।
2. किसी क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक विकास में सेवाकेन्द्र विकास-ध्रुव का कार्य करता है।
3. क्षेत्रीय विकास हेतु ऊर्जा का घनीभवन सेवाकेन्द्रों पर ही होता है। अतः विकास के लिए यह संरचनात्मक आधार प्रस्तुत करता है।
4. प्रत्येक क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का एक पदानुक्रमिक तंत्र होता है, जिनपर कार्यों एवं सेवाओं का संकेन्द्रण रहता है।
5. सेवाकेन्द्रों पर स्थापित विकासात्मक इकाइयों की सघनता तथा क्षेत्र से इसकी परिवहनीय सम्बद्धता का विकास के स्तर एवं सेवाक्षेत्र से प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक सम्बन्ध होता है।
6. क्षेत्र विशेष से परिवहन जाल द्वारा सेवाकेन्द्र सर्वाधिक सम्बद्ध होता है, सेवाकेन्द्र से विकास इन्हीं माध्यमों द्वारा संचरित होता है। अतः सेवाकेन्द्रों पर अतिरिक्त विकासात्मक इकाइयों की स्थापना से क्षेत्रीय विकास प्रोत्साहित होगा।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवावृत्ति ही सेवाकेन्द्रों का आधार होता है, अतः यह अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में वाह्यातित अभिज्ञानों (Innovations) एवं उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं का नियामक एवं संचालक होता है।
8. विकास की भौगोलिक संकल्पना-आर्थिक विकास, आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक प्रगति से भिन्न एक समन्वित संकल्पना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं

पर्यावरणीय दृष्टिकोण समाहित है। विकास की यही परिकल्पना सेवाकेन्द्र की क्षेत्रीय अतर्प्रक्रिया का आधार है।

ऑकड़ों का संकलन, विश्लेषण एवं प्रयुक्त विधितंत्र

अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्र एवं विकास आव्यूह का विश्लेषण सकल्पनात्मक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से किया गया है। सकल्पनात्मक विश्लेषण में यथा संभव उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन से प्राप्त विचारों को प्रस्तुत किया गया है। व्यावहारिक विश्लेषण ऑकड़ों एवं क्षेत्रीय अनुभवों पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के सूक्ष्म-स्तरीय स्वरूप होने के कारण प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक ऑकड़े—जिला उद्योग केन्द्र, देवरिया, औद्योगिक प्रतिष्ठान केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालय, देवरिया, लोक-निर्माण विभाग, देवरिया, तहसील मुख्यालय, देवरिया, रुद्रपुर, बरहज, सलेमपुर, भाटपाररानी, सभी विकासखण्ड मुख्यालयों, जिला प्रबन्धक-दूरभाष, देवरिया कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जिला स्वास्थ्य केन्द्र, देवरिया और पशु चिकित्सालय, देवरिया, जिला समाज कल्याण विभाग, देवरिया से प्राप्त किये गये हैं। **द्वितीयक ऑकड़ों** के मुख्य स्रोत जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद देवरिया, 1971 तथा 1981, गजेटियर, जनपद देवरिया, 1988, सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद देवरिया-2000 एवं 2001, सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद देवरिया-2001, देवरिया जनपद के अग्रणी बैंक-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंचायतन, जिला पंचायती राज विभाग, देवरिया-2000, खरीफ फसलों की सघन पद्धतियाँ-2001, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उद्योग निर्देशिका, जिला देवरिया 1996-97 एवं 1999-2000, रबी एवं खरीफ उत्पादन कार्यक्रम-2000-01, एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देवरिया; 1991, से प्रकाशित पुस्तिकाओं; भारत की जनसंख्या-2001, ऑकड़े एवं तथ्य, उपकार प्रकाशन, भारत-1991, 1999, 2000 एवं 2001; योजना एवं कुरुक्षेत्र वर्ष 2002 के अंक हैं। उपर्युक्त ऑकड़ों के अतिरिक्त यथा स्थान व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं अनुभव का भी आश्रय लिया गया है।

ऑकड़ों के विश्लेषण में दुरुह सांख्यिकीय विधियों का उपयोग नहीं किया गया है, किन्तु सेवाकेन्द्रों के निर्धारण, सेवाक्षेत्रों का सीमांकन, जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि का आंकलन, शस्य गहनता, शस्य साहचर्य, शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन, सेवाकेन्द्र सम्बद्धता, परिवहन जाल सम्बद्धता आदि में यथा आवश्यक सामान्य सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन को सुस्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए यथा-स्थान विश्लेषित एवं सश्लेषित ऑकड़ों को आरेखों, डायग्रामों मानचित्रों एवं सारणियों द्वारा प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास हुआ है।

सेवाकेन्द्रों का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समय एवं ससाधनों के अभाव में, समन्वित क्षेत्र-विकास में सेवा

केन्द्रों की भूमिका के अध्ययनार्थ केवल कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा विकास में सेवाकेन्द्रों की भूमिका का विश्लेषण, विवेचन एवं नियोजन प्रस्तुत है। इस सन्दर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई सेवाकेन्द्रों के चयन की है। सिद्धान्ततः किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा अथवा सुविधा न्यूनतम स्तर पर भी प्रदान करने वाले केन्द्र को शामिल करना चाहिए, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसे सभी केन्द्रों को अध्ययन में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है। अतएव सेवाकेन्द्रों का किसी न किसी आधार पर चयन अपरिहार्य हो जाता है।

सेवाकेन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सेवाकेन्द्रों के निर्धारण के लिए उपलब्ध साहित्यों के अनुशीलन तथा क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के 2004 बस्तियों में से डाबी एन मिश्र (1980) द्वारा प्रयुक्त विधि का उपयोग करते हुए कार्यों की औसत कार्याधार जनसंख्या, उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप और बस्तियों की सम्बद्धता के माध्यम से 47 सेवाकेन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यों के क्षेत्रीय महत्त्व, औसत कार्याधार मूल्य और उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप के आधार पर 51 आधारभूत कार्यों/सेवाओं का चयन किया गया है, जो अध्ययन क्षेत्र में वितरित बस्तियों द्वारा सम्पादित होते हैं। तत्पश्चात् कम से कम 5 केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाले तथा 258 से अधिक केन्द्रीयता मान एवं 30 से अधिक परिवहनीय सम्बद्धता वाले बस्तियों को अध्ययन हेतु सेवाकेन्द्र की मान्यता प्रदान की गयी है।

सेवाकेन्द्रों के मूल्य अभिनिर्धारण में चतुर्थ क्रम के कार्यों (औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टेशन, साप्ताहिक बाजार, पशुसेवा केन्द्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाकघर) को छोड़कर शेष को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है तथा अधिकांश बस्तियाँ ऐसे कार्य सम्पादित करती हैं। इसी प्रकार तृतीय क्रम के कार्य—पीसीओ का उच्च मूल्य होने के बावजूद अत्यधिक संख्या के कारण अभिनिर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

शोध प्रबन्ध की रूपरेखा

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का संयोजन निम्न प्रकार से आठ अध्यायों में किया गया है।

अध्याय—एक में संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सेवाकेन्द्र की संकल्पना, सेवाकेन्द्र का संकल्पनात्मक क्रम विकास तथा 'विकास' की संकल्पना, विकास की आर्थिक, पर्यावरणीय एवं भौगोलिक अवधारणा एवं विकास के सिद्धान्तों का संकल्पनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय—दो में क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भौतिक पृष्ठभूमि में उच्चावच, अपवाह, सरचना, जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति आदि का विश्लेषण; सामाजिक—सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जनसंख्या, अधिवास आदि का विवेचन तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कृषि, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, संचार आदि का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय—तीन में सेवाकेन्द्रों का ऐतिहासिक क्रम में उद्भव—विकास प्रस्तुत है। इसमें सेवाकेन्द्रों के उद्भव—विकास को प्रोत्साहित करने वाले कारक, सेवाकेन्द्रों के पुरातात्विक स्थल,

क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक क्रम में सेवाकेन्द्रों का उद्भव—विकास तथा सेवाकेन्द्रों के प्रकार का विवेचन है।

अध्याय—चार में सेवाकेन्द्रों के स्थानिक कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का निर्धारण—औसत कार्याधार जनसंख्या, उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप एवं परिवहनीय सम्बद्धता के आधार पर किया गया है। पुनः सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता, उनका पदानुक्रम एवं सेवाक्षेत्रों को निर्धारित किया गया है।

अध्याय—पाँच में सेवाकेन्द्र और कृषि—औद्योगिक विकास के अंतर्गत प्रथम भाग में कृषि विकास के आकलन क्रम में कृषि के आधारभूत सघटक, विकास के सहायक तत्व, विकास की प्रवृत्तियों एवं कृषि के वर्तमान प्रतिरूप के मूल्यांकन के उपरान्त कृषि विकास नीति की व्याख्या की गयी है। *द्वितीय* भाग में औद्योगिक पृष्ठभूमि एवं विकास का वर्णन कर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की अवस्थापना एवं विकास की नीति निर्धारित की गयी है।

अध्याय—छ. में सेवाकेन्द्र तथा परिवहन संचार एवं विकास के अंतर्गत प्रथम भाग में परिवहन सम्बद्धता एवं विकास, परिवहन माध्यम प्रतिरूप, घनत्व, अभिगम्यता, सम्बद्धता, तथा परिवहनीय सम्बद्धता, सेवाकेन्द्र सम्बद्धता और मार्ग—जाल सम्बद्धता की गणना *अल्फा*, *बीटा* एवं *गामा निर्देशांक* के माध्यम से की गयी है। पुनः वर्तमान पिछड़े स्वरूप के सन्दर्भ में तीव्र विकास नियोजन का प्रस्ताव है। *द्वितीय* भाग में संचार और सूचना प्रसार के महत्व एवं विकास का विश्लेषण तथा क्षेत्र विकास हेतु संचार तंत्र के नियोजन का प्रस्ताव है।

अध्याय—सात के अंतर्गत सेवाकेन्द्र तथा सामाजिक सुविधाओं के विकास का विवेचन है। इसके प्रथम भाग में शिक्षा के विकास एवं वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण, कर वांछित विकास हेतु उनका नियोजन प्रस्तुत है। *द्वितीय* भाग में जनस्वास्थ्य एवं विकास का विश्लेषण उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में किया गया है। जनस्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास हेतु समुचित नियोजन का प्रस्ताव है।

अध्याय—आठ में ऊर्जा एवं समन्वित क्षेत्र विकास के अंतर्गत ऊर्जा की विकास में भूमिका का विश्लेषण कर, क्षेत्र में गैर पारम्परिक ऊर्जा संभाव्यता का आकलन कर ऊर्जा विकास हेतु नियोजन प्रस्तावित है। इस अध्याय में समन्वित क्षेत्र विकास हेतु उन पक्षों की समीक्षा प्रस्तुत की गयी है, जिनका समन्वित क्षेत्र—विकास में महत्वपूर्ण योगदान है; किन्तु अनेक कारणों से शोध अध्ययन में सम्मिलित नहीं किये जा सके हैं।

सेवाकेन्द्र, विकास तथा नियोजन से सम्बन्धित साहित्य अनेक सामाजिक विज्ञानों में उपलब्ध हैं। उन सभी का विवरण देना दुरुह कार्य है। यथा स्थान उल्लिखित सन्दर्भों को प्रत्येक अध्याय के अंत में संख्या क्रम में प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध के अन्त में तीन परिशिष्ट दिए गए हैं। प्रथम में शब्दावली, द्वितीय में शब्द संक्षेप तथा तृतीय में प्रस्तुत शोध विषय एवं क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रन्थों एवं लेखों का उल्लेख किया गया है।

आभारोक्ति

एक भूगोलवेत्ता के लिए शोधकार्य- क्षेत्रीय भ्रमण, आँकड़ों के संग्रहण, उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण- सरल्लेख, आरेखों, मानचित्रों आदि के द्वारा उनका प्रदर्शन आदि के रूप में विविध जटिलताओं से भरा चुनौतीपूर्ण कार्य है। शोध के दौरान क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरे प्राप्य एवं सभाव्य ससाधनों का अन्वेषण एवं मंथन कर विकास में उनकी भूमिका आकलित करना तथा समन्वित और संतुलित विकास हेतु एक उपयुक्त नियोजन प्रणाली प्रस्तुत करते हुए उसमें इनकी भूमिका निर्धारित करना, एक जटिल कार्य था। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है।

इस क्रम में सर्वप्रथम शोध प्रबन्ध निर्देशक गुरुप्रवर डा. बी.एन. सिंह, 'रीडर' भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति कृतज्ञतापूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शैक्षणिक, अकादमिक एवं लेखन सम्बन्धी व्यक्तताओं के बावजूद अपने उत्कृष्ट एवं कुशलतम निर्देशन में न सिर्फ शोध प्रबन्ध को यथारीति पूर्ण कराया, बल्कि आपके विराट, सघर्षशील, ऊर्जावान और उत्साही व्यक्ति की प्रेरणा सदैव मेरा पथ-प्रदर्शन भी करती रही। आपका असीम स्नेह और आशीर्वाद कवच की भाँति हताशा और निराशा से मुझे सदा सुरक्षा प्रदान करता रहा; आपके प्रति अर्द्धापूर्वित शीश नतमस्तक है।

परमादरणीय गुरु प्रो. सविन्द सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, का कृतज्ञ हृदय आभारी है, जिन्होंने स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक न सिर्फ विषय के प्रति मेरी जिज्ञासाओं को अपनी उत्कृष्ट अध्यापन शैली द्वारा संतुष्ट किया, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भूगोल की उपयोगिता निर्धारण तथा उस हेतु शोध की बारिकियों को समझने का विवेक भी पैदा किया। पुनः शोध का अवसर प्रदान कर सम्बन्धित जटिलताओं का निवारण किया। अपने उत्कृष्ट अध्यापन एवं लेखन से आपने न सिर्फ भूगोल विषय को उत्कर्ष पर पहुँचाया बल्कि विषय के साथ भूगोल-विभाग को भी भूगोल जगत में अपनी पहचान दिलाई। शोधकार्य के दौरान आपका स्नेह एवं सहयोग मुझे अनवरत प्राप्त होता रहा, ये मेरा परम सौभाग्य है।

विषयगत समस्याओं एवं शोध की जटिलताओं के निराकरण में अर्द्धेय गुरु डा. बी.एन. मिश्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, से भरपूर, सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला। आपके उदारतापूर्ण सहयोग एवं स्नेह से शोधकार्य सहजतापूर्वक पूर्ण हुआ; आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। शोध के दौरान अर्द्धेय डा. सुधाकर त्रिपाठी के द्वारा प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भूगोल विभाग के उन समस्त विद्वानों का भी मैं हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने कई प्रकार से मुझे रचनात्मक सहयोग प्रदान किया।

मानवीय मूल्यों के पोषक डा. माधव प्रसाद पाण्डेय, डी.फिल., डी.लिट.; प्रो. आर.एन. सिंह अध्यक्ष, भूगोल विभाग, हेमवतीनंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल; प्रो. शिवशंकर वर्मा, भूगोल विभाग, दी.द उ. विश्वविद्यालय गोरखपुर; प्रो. रामएकबाल सिंह (गोपालगंज), श्री चिरंजी सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक, गोपालगंज); श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय (पूर्व सदस्य कार्य परिषद, इ.वि.वि.); का मैं हार्दिक आभारी हूँ, जिनका अनुकरणीय व्यक्तित्व न सिर्फ मुझे क्रियाशील बनाए रखा बल्कि आपके स्नेह, प्रोत्साहन एवं सुझावों ने शोधप्रबन्ध की पूर्णता में विशेष भूमिका निभाया।

ममता की प्रतिमूर्ति श्रीमति सुमति सिंह के द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए कृतज्ञ हृदय के उद्गार को शब्द दे पाने में मस्तिष्क असमर्थ है। अपने पारिवारिक व्यक्तताओं के बावजूद आपने जिस उदारता से शोधकार्य को पूर्ण करने हेतु सुअवसर एवं सहयोग प्रदान किया तथा खड़े होने के लिए प्रयासरत शिशु की भाँति क्षण-प्रतिक्षण प्रोत्साहित करती रही, वंदनीय है।

डा. धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद (उ.प्र.); श्री यशपाल सिंह, रेल अभियंता डा. दीनबन्धु शर्मा, एवं डा. प्रभासिंह का भी हार्दिक आभारी हूँ, जिनके समय-समय

पर प्राप्त शोधपरक सुझावों एवं प्रोत्साहन से शोधकार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सका। श्री अनुपम पाण्डेय के प्रति भी हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, आप शोध सम्बन्धी चुनौतियों के प्रति सर्वदा आगाह करते रहे, आपके सुझावों ने शोध कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु उद्वेलित किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (लो नि वि से सम्बद्ध), ने अपनी व्यवस्तताओं के बावजूद क्षेत्रीय भ्रमण, आँकड़ों के संग्रह एवं क्षेत्रीय समस्याओं को समझने में मेरी भरपूर सहायता की। आपके सहयोग से शोधकार्य सफलतापूर्वक यथार्थीघ्र पूर्ण हुआ। आपके प्रति विनम्रता पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ।

मैं उन समस्त पुस्तकालयों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आँकड़ों के संग्रह एवं सम्बन्धित साहित्य को उपलब्ध कराने में भरपूर सहयोग प्रदान किया। इस क्रम में श्री अरुण कुमार चौबे, टी.डी.एम. देवरिया, श्री मुकेश कुमार मेश्राम (तत्कालीन सी.डी.ओ. देवरिया एवं वर्तमान जिलाधिकारी, आजमगढ़), डा. ओ.पी. मिश्र, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवरिया, डा. विजय प्रकाश सिंह, डी.आई.ओ.एस. देवरिया, एवं श्री ओ.पी. सिंह, (जिला उद्योग केन्द्र, देवरिया), के प्रति कृतज्ञ हृदय विशेष आभारी हूँ।

अपने अनन्य मित्रों, श्री मनीष शुक्ल (एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट), डा. रामराज तिवारी, डा. मित्रपाल सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह तथा शोधरत सहयोगियों ककणा सिंह, जितेन्द्र कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, पंकज कुमार जायसवाल द्वारा प्राप्त विविध रचनात्मक सुझावों एवं सर्वेश कुमार सिंह के आँकड़ों के संगणन में प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।


आजीवन त्याग, सघर्ष, कर्तव्यपरायण और वात्सल्य के प्रतीक रहे प्रातः स्मरणीय पिता स्व. पारस नाथ सिंह को मैं किन शब्दों में श्रद्धा स्मरण अर्पित करूँ, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने राष्ट्रपति पदक (१९८१) से विभूषित किया, पर आज जब उनके त्याग, प्रेरणा के प्रतिफल स्वरूप शोधकार्य सम्पन्नता को प्राप्त हुआ तो संतोषसुख का पारितोषिक पाने के लिए हमारे बीच नहीं है। उस पुण्य आत्मा को मेरा रात-रात नमन।

मैं त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति माँ रामपति देवी, अनुज राकेश, रेनू, पत्नी आभा तथा शिवम, शुभम का आजीवन ऋणी रहूँगा, जिनके त्याग, प्रेरणा, स्नेह एवं सतत-सहयोग ने मुझे इस योग्य बनाया।

अंत में मैं 'आइडियल कम्प्यूटर सेंटर' कर्नलगंज, इलाहाबाद; को, जिसके माध्यम से बड़ी ही सूक्ष्मता एवं बारीकी से शोधप्रबन्ध का कम्प्यूटर कार्य यथार्थीघ्र पूर्ण हुआ, विनम्र आभार ज्ञापित करता हूँ।

कार्तिक पूर्णिमा

१९ नवम्बर, २००२


 (सतीश कुमार सिंह)
 शोध छात्र 'भूगोल'
 इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
 इलाहाबाद.

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन	i - vi
आभारोक्ति	vii - viii
अनुक्रमणिका	ix - xiv
चित्र/आरेख सूची	xv
सारणी सूची	xvi - xvii
अध्याय एक : संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि	1 - 26

(क) 'सेवाकेन्द्र' की संकल्पना

- 1.1 सेवाकेन्द्र, केन्द्रस्थल, सेवाप्रदेश
 - (अ) सेवाकेन्द्र
 - (ब) सेवाकेन्द्र एवं केन्द्र
 - (स) सेवा प्रदेश
- 1.2 सेवाकेन्द्र तंत्र
- 1.3 सेवाकेन्द्र संकल्पनात्मक क्रमविकास एवं केन्द्रस्थल सिद्धान्त—
 - 1- बाजार सिद्धान्त
 - 2- परिवहन सिद्धान्त
 - 3- प्रशासकीय सिद्धान्त
 - 4- लॉश का आर्थिक भू-दृश्य सिद्धान्त
 - 5- लॉश-क्रिस्टलर की तुलना
- 1.4 भारत में सेवाकेन्द्रों से सम्बन्धित अध्ययन

(ख) 'विकास' की संकल्पना

- 1.5 विकास, प्रगति एवं संवृद्धि की अवधारणा
 - (अ) प्रगति और विकास
 - (ब) संवृद्धि और विकास
 - (स) क्रांति और विकास
- 1.6 विकास की भौगोलिक अवधारणा
- 1.7 आर्थिक विकास की अवधारणा
- 1.8 संविकास (इकोडेवलपमेन्ट) की अवधारणा
- 1.9 विकास के निर्धारक तत्व
- 1.10 विकास के सिद्धान्त
 - (अ) मिरडल का 'क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल'
 - (ब) प्रीडमैन का 'केन्द्र परिधि मॉडल'
 - (स) रोस्टोव का 'आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धान्त'
 - (द) 'विकास ध्रुव' एवं 'विकास केन्द्र' सिद्धान्त

अध्याय दो— अध्ययन क्षेत्र का महत्व एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि

27-61

अध्ययन क्षेत्र का नामकरण एवं महत्व

- 1 अध्ययन क्षेत्र का पौराणिक महत्व
 - 2 अध्ययन क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व
 - 3 भौगोलिक पृष्ठभूमि
- 2.1 भौतिक पृष्ठभूमि
 - [1] अवस्थिति एवं स्थिति विस्तार
 - [2] उच्चावच
 - [3] भू-आकृति प्रदेश

- (क) उत्तरी-पूर्वी भाट क्षेत्र
- (ख) बागर क्षेत्र
 - (1) उत्तरी बागर क्षेत्र
 - (2) दक्षिणी बागर क्षेत्र
- (ग) कछारी क्षेत्र
- [4] अपवाह—तत्र एव प्रतिरूप
 - (क) राप्ती नदी तत्र
 - (ख) छोटी गण्डक नदी तत्र
 - (ग) घाघरा नदी तत्र
- [5] भौमिकीय सरचना
- [6] भूकम्पीय स्थिति
- [7] जलवायु
 - (क) तापमान
 - (ख) वायुदाब
 - (ग) वायु वेग
 - (घ) वायु दिशा
 - (ङ) वर्षा
 - (च) सापेक्षिक आद्रता
 - (छ) ऋतुएँ (वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु)
- [8] मृदा
- [9] प्राकृतिक वनस्पति
- 2.2 सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि**
 - [1] जनाकिकीय वैशिष्ट्य
 - (क) जनसंख्या वृद्धि
 - (ख) जनसंख्या घनत्व
 - (ग) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या
 - (घ) लिंगानुपात
 - (ङ) साक्षरता
 - (च) अधिवास
 - (छ) जनसंख्या वितरण
 - (ज) नगरीकरण
 - (झ) जनसंख्या स्थानान्तरण
 - [2] सामाजिक सरचना
- 2.3 आर्थिक एवं वाणिज्यिक पृष्ठभूमि**
 - [अ] कृषि (Agriculture)**
 - (1) भूमिउपयोग प्रतिरूप
 - (2) कृषिजोत का आकार
 - (3) कृषि भूमिउपयोग प्रतिरूप एवं शस्य साहचर्य
 - (4) शुद्ध कृषित क्षेत्र एवं सकल कृषित क्षेत्र
 - (5) फसल चक्र एवं फसल सघनता
 - (6) कृषि उत्पादकता
 - (7) सिंचाई एवं बाढ़
 - (8) जल एवं मृदा संबंधित पर्यावरणीय समस्याएँ एवं उनका सरक्षण
 - (9) कृषि वैशिष्ट्य
 - (10) पशुपालन
 - (11) मत्स्य पालन
 - [ब] ऊर्जा**
 - (1) ऊर्जा उपभोग
 - [स] औद्योगिक स्थिति**
 - [द] परिवहन व्यवस्था**
 - (क) रेल परिवहन
 - (ख) सड़क परिवहन
 - [य] संचार**
 - [र] श्रम एवं रोजगार**

अध्याय तीन : सेवाकेन्द्रों का उद्भव-विकास

62-84

3.1 सेवाकेन्द्रों के उद्भव-विकास को प्रभावित करने वाले कारक

- (ब) मानवीय कारक
 - (क) विनिमय प्रक्रिया
 - (ख) क्षेत्रीय आवश्यकता
 - (ग) प्रशासकीय, क्रियाएँ
 - (घ) परिवहन संबद्धता
 - (ङ) कार्यात्मक आधार
- 3.2 अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों के पुरातात्विक स्थल
- 3.3 अध्ययन क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 - (अ) प्राचीनकाल
 - (ब) मध्यकाल
 - (स) आधुनिक काल
- 3.4 ऐतिहासिक कालक्रम में देवरिया जनपद में सेवाकेन्द्रों का उद्भव-विकास
 - (अ) प्राचीन काल
 - (ब) मध्यकाल
 - (स) आधुनिक काल
 - (क) प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना
 - (ख) पक्की सड़कों का विकास
 - (ग) वस्तुनिर्माण उद्योग एवं व्यापार का विकास
- 3.5 ऐतिहासिक कालावधि में उत्पन्न सेवाकेन्द्रों के प्रकार
 - (क) प्रशासनिक सेवाकेन्द्र
 - (ख) व्यापारिक एवं यातायात सम्बन्धी सेवाकेन्द्र
 - (ग) धार्मिक सेवाकेन्द्र

अध्याय चार : सेवाकेन्द्रों का स्थानिक कार्यात्मक संगठन

85—112

- 4.1 सेवाकेन्द्रों का स्थानिक कार्यात्मक संगठन
- 4.2 सेवाकेन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य
- 4.3 सेवाकेन्द्रों का निर्धारण
 - (क) औसत कार्याधार जनसंख्या
 - (ख) उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप
 - (1) उपभोक्ता संचरण सर्वेक्षण
 - (2) उपभोक्ता संचरण सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम
 - (ग) परिवहनीय संबद्धता
- 4.4 सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता
- 4.5 सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम
- 4.6 सेवाकेन्द्रों का सेवाक्षेत्र

अध्याय पाँच : सेवाकेन्द्र और कृषि-औद्योगिक विकास

113—164

कृषि विकास

- 5.1 कृषि सम्पत्त्य एवं विकास
- 5.2 कृषि-विकास
- 5.3 भूमि-उपयोग प्रतिरूप
- 5.4 कृषि के आधारभूत संघटक
 - (अ) मृदा
 - (ब) जल की उपलब्धता
 - (स) श्रम एवं तकनीक
 - (द) उर्वरक प्रयोग
- 5.5 कृषि विकास के उत्प्रेरक एवं सहायक तत्व
 - (1) बीज गोदाम, उर्वरक डिपो
 - (2) ग्रामीण गोदाम
 - (3) कीटनाशक डिपो
 - (4) शीत भण्डार

- (5) कृषिसेवा केन्द्र
 - (6) कृषि उत्पादन मण्डी समिति
 - (7) पशु चिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
 - (8) सहकारी समितियों एवं बैंकिंग
- 5 6 कृषि विकास की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप
- (क) फसल प्रतिरूप
 - (अ) खरीफ फसल
 - (ब) रबी फसल
 - (स) जायद फसल
 - (ख) फसल प्रतिरूप में परिवर्तन
 - (ग) उत्पादकता
 - (घ) शस्य गहनता
 - (ङ) शस्य—विविधता
 - (च) शस्य संयोजन
 - (छ) फसल—चक्र
 - (ज) पशुपालन
 - (झ) मत्स्यपालन

औद्योगिक विकास

5 7 सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

5 8 औद्योगिक स्वरूप

5 9 उद्योगों का वर्गीकरण

- (अ) वृहद् उद्योग
 - (क) चीनी उद्योग का विकास
- (ब) लघु उद्योग
 - (क) कृषि पर आधारित उद्योग
 - (ख) दफती एवं कागज उद्योग
 - (ग) लकड़ी पर आधारित उद्योग
 - (घ) पशुओं पर आधारित उद्योग
 - (ङ) हैण्डलूम उद्योग
 - (च) रसायन उद्योग
 - (छ) इंजीनियरिंग उद्योग
 - (ज) रेशम उद्योग
 - (झ) ईट उद्योग
 - (ञ) प्रिंटिंग प्रेस
- (स) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग

5.10 औद्योगिक अवस्थापन सुविधायें

5.11 समस्या एवं विकास नियोजन

- (अ) कृषि समस्या एवं विकास नियोजन
 - (1) भूमि/मृदा एवं सिंचाई सम्बन्धित
 - (क) ऊसर भूमि की समस्या
 - (ख) सिंचाई समस्या
 - (ग) बाढ़ की समस्या
 - (घ) मृदा—उर्वरक साहचर्य एवं मृदा परीक्षण
 - (ङ) मृदा—क्षरण एवं संरक्षण
 - (2) उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयोग सम्बन्धित
 - (क) उर्वरकों की पहचान
 - (ख) सस्तुत उर्वरक उपयोग
 - (ग) जैव उर्वरक, हरित खाद एवं कम्पोस्ट प्रयोग
 - (घ) एकीकृत नाशीजीव प्रबन्ध (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट)
 - (3) कृषि प्रविधि, प्रशिक्षण एवं ज्ञान से संबंधित
 - (क) बीज शोधन
 - (ख) वैज्ञानिक कृषि, फसल—चक्र
 - (ग) पारम्परिक अनुभवों, उक्तियों का उपयोग
 - (घ) कृषि—पशुसाहचर्य विकास
 - (4) कृषि—वित्त एवं सुरक्षा संबंधित
 - (क) किसान क्रेडिट कार्ड

- (ख) बीमा योजनाएँ
- (ग) किसान मित्र योजना
- (ब) औद्योगिक समस्याएँ, सम्भावनाएँ एवं विकास नियोजन
- (क) कृषि आधारित उद्योग
- (ख) फलाधारित उद्योग
- (ग) पशुधन आधारित उद्योग
- (घ) पर्यटन उद्योग

अध्याय छ: : सेवाकेन्द्र परिवहन—संचार एवं विकास

165—194

(क) परिवहन व्यवस्था

- 6.1 सेवाकेन्द्र— परिवहन सम्बद्धता एवं विकास
- 6.2 परिवहन माध्यम—प्रतिरूप
 - (अ) जल—परिवहन
 - (ब) रेल—परिवहन
 - (स) सड़क परिवहन
- 6.3 सड़क परिवहन — महत्व
- 6.4 सड़क घनत्व
- 6.5 सड़क अभिगम्यता
- 6.6 सड़क सम्बद्धता
 - (अ) परिवहनीय सम्बद्धता
 - (ब) सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता
 - (स) मार्ग—जाल की सम्बद्धता
 - (1) अल्फा निर्देशांक
 - (2) बीटा निर्देशांक
 - (3) गामा निर्देशांक
- 6.7 यातायात प्रवाह

(ख) संचार और सूचना प्रसार

- 6.8 महत्व एवं विकास
- 6.9 अध्ययन क्षेत्र में संचार एवं सूचना प्रसार
 - (अ) व्यक्तिगत संचार
 - (1) डाक सेवा
 - (2) तारसेवा
 - (3) टेलीफोन सेवा
 - (4) पी.सी.ओ.
 - (ब) जनसंचार
 - (1) दूरदर्शन
 - (2) चलचित्र
 - (3) समाचार पत्र
- 6.10 परिवहन एवं संचार का नियोजन
 - (क) परिवहनतंत्र का नियोजन
 - (अ) रेलमार्ग नियोजन
 - (ब) सड़कमार्ग नियोजन
 - (स) ग्रामीण सड़क मार्ग
 - प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
 - (ख) संचार तंत्र का नियोजन

अध्याय सात : सेवाकेन्द्र तथा सामाजिक सुविधाओं का विकास

195—226

- 7.1 सेवाकेन्द्र एवं सामाजिक बुनियादी क्षेत्र

(क) शिक्षा विकास

- 7.2 शिक्षा—महत्व एवं विकास

- 7.3 साक्षरता—परिभाषा एवं प्रयास
- 7.4 अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा एवं साक्षरता विकास
- 7.5 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप
(अ) जूनियर बेसिक विद्यालय
(ब) सीनियर बेसिक विद्यालय
(स) हायर सेकेंड्री विद्यालय
(द) उच्च शिक्षा केन्द्र
- 7.6 जनपद में शिक्षण संस्थाओं की शिक्षक विद्यार्थी संरचना
(अ) जूनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षक—विद्यार्थी संरचना
(ब) सीनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षक—विद्यार्थी संरचना
(स) हायर सेकेंड्री विद्यालयों की शिक्षक विद्यार्थी संरचना
- 7.7 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
(ख) जनस्वास्थ्य विकास
- 7.8 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
- 7.9 जनस्वास्थ्य एवं विकास
- 7.10 स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रारूप
- 7.11 स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता
(क) धिकित्सालय
(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(ग) नर्सिंग होम
(घ) परिवार एवं मातृशिशु कल्याण केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र आदि
(ङ) सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
(च) अन्य धिकित्सकीय सुविधाएँ
- 7.12 जनस्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन
- 7.13 स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की असफलता के कारण
- 7.14 सामाजिक सुविधाओं का नियोजन
(क) स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन
(ख) शैक्षणिक नियोजन

अध्याय आठ : ऊर्जा अवधारणा एवं समन्वित क्षेत्र विकास

227—239

- 8.1 ऊर्जा की अवधारणा और समन्वित विकास में इसकी भूमिका
- 8.2 विकास में गैरपरम्परागत ऊर्जा की अवधारणा
- 8.3 गैर परम्परागत ऊर्जा : स्रोत एवं सभाव्यता
(क) राष्ट्रीय स्तर पर गैरपरम्परागत ऊर्जा सभाव्यता
(अ) कृषि उत्पादों से ऊर्जा
(ब) पवन ऊर्जा
(स) लहर ऊर्जा
(द) सौर ऊर्जा
(इ) भूतापीय ऊर्जा
(ख) जनपद (देवरिया) स्तर पर गैर गैरपरम्परागत ऊर्जा सभाव्यता
- 8.4 ग्रामीण क्रियाकलापों में गैरपरम्परागत ऊर्जा का उपयोग
- 8.5 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम
- 8.6 समन्वित विकास के अन्य पहलू।

सारांश

240—256

परिशिष्ट—1 (शब्दावली)

257—258

परिशिष्ट—2 (शब्द संक्षेप)

259

परिशिष्ट—3 (चयनित संदर्भ सूची)

260—263

चित्रो एव आरेखो की सूची List of Maps & Diagrams

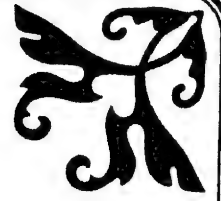
चित्र स (Fig No)	शीर्षक (Title)
1 1	<i>Classical Models of Central Place Theory</i>
1 2	<i>Central Place theory</i>
1 3	<i>Myrdal's process of cumulative causation</i>
1 4	<i>Rostow Model of Economic Development</i>
2 1	<i>Location Map of Study Area (Deoria Dist)</i>
2 2	<i>Drainage pattern of Deoria District</i>
2 3	<i>Climatic Conditions of Deoria District</i>
2 4	<i>Weather Conditions of Deoria District</i>
2 5	<i>Population Growth of Deoria District (1901-2001)</i>
2 6	<i>Transport Network of Deoria Dist (2002)</i>
3 1	<i>Orgin & Evolution of Service Centre in Deoria Dist</i> A Ancient Period B Medieval Period C Modern Period D Post Independent period
3 2	<i>Main Service Centre of Historical Period</i> A Administrative Service Centre B Trade & Transport Service Centre C Religious Service Centre
4 1	<i>Spatial Distribution of Service Centre in Deoria District (2002)</i>
4 2	<i>Spatl Preference of Consumers in Deoria District</i>
4 3	<i>Connectivity of Service Centres in Deoria District (2002)</i>
4 4	<i>Hierarchical level of Service Centre, District Deoria (2001)</i>
4 5	<i>Hierarchical Distribution of Service Centre District Deoria</i>
4 6	<i>Service Areas of Service Centre, District Deora</i>
5 1	<i>Land Use Pattern of Deoria District</i>
5 2	<i>Means of Irrigation and Irrigated Area in Deoria District- 2000 01</i>
5 3	<i>Block wise cropping pattern, District Deoria 2000-01</i>
5 4	<i>Percentage of area under different crops District Deoria- 2001</i>
5 5	<i>Changing of Cropping pattern in Deoria District</i>
5 6	<i>Productivity of Different crops in Deoria District 2001</i>
5 7	<i>Block wise Crop-Combination pattern in Deoria District</i>
5 8	<i>Major Industries of Deoria, 2001-02</i>
6 1	<i>Transport Network of Deoria District, 2002</i>
6 2	<i>Road Density of Deoria District</i>
6 3	<i>Accessibility map of Deoria District</i>
6 4	<i>District Deoria Frequency of Buses 2002</i>
6 5	<i>Flow map of buses, District Deoria</i>
7 1	<i>Literacy Pattern of Deoria 2001</i>
7 2	<i>Block wise Literacy growth pattern (1991-2001)</i>
8 1	<i>Percentage of Electrified Villages in Deoria District</i>

सारणी—सूची

सारणी स	विवरण
1 1	केन्द्रस्थलो और उनके प्रदेशो का सैद्धान्तिक वितरण तन्त्र
2 1	देश प्रदेश एव जनपद मे जनसख्या वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति
2 2	जनपद एव प्रदेश का जनसख्या घनत्व
2 3	जनपद प्रदेश देश की नगरीय जनसख्या (प्रतिशत मे) की तुलनात्मक स्थिति
2 4	जनपद प्रदेश एव देश का लिंगानुपात
2 5	भूमिउपयोग प्रतिरूप देवरिया जनपद— 2000—01
2 6	देवरिया जनपद के क्रियात्मक जोतो का आकार के अनुसार विवरण
2 7	प्रदेश मे क्रियात्मक जोतो का आकार के अनुसार विवरण
2 8	देवरिया जनपद मे विभिन्न शस्यान्तर्गत क्षेत्र का विवरण
2 9	शुद्ध एव सकल कृषित क्षेत्र का तहसीलवार विवरण
2 10	देवरिया जनपद मे औसत कृषि उत्पादन एव उत्पादकता कु/हे (1995—1998)
2 11	जनपद मे स्रोतवार सिचाई के साधनो द्वारा सिचाई का विवरण (2000—2001)
2 12	जनपद मे विभिन्न कार्यों मे विद्युत उपभोग (ह कि वा घ)
2 13	विभिन्न सेक्टरों मे कार्यरत श्रमिकों का विवरण 2001
4 1	केन्द्रीय कार्य एव सेवाएँ
4 2	कार्य कार्याधार जनसख्या सूचकांक एव कार्य अनुक्रम
4 3	जनपद मे निर्धारित सेवाकेन्द्र
4 4	परिवहनीय सबद्धता सूचकांक जनपद देवरिया
4 5	सेवाकेन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक
4 6	सेवाकेन्द्र पदानुक्रम
4 7	सेवाकेन्द्रों की पदानुक्रमीय व्यवस्था
5 1	जनपद मे विकासखण्डवार भूमिउपयोग (हे मे)
5 2	सिचाई के विभिन्न साधनो की स्थिति
5 3	विकास खण्डवार विभिन्न साधनो द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्र (हे मे)
5 4	जनपद मे वर्षवार उर्वरक खपत का विवरण (केजी/हे)
5 5	जनपद मे विकास खण्डवार उर्वरक खपत (मी टन) एव एन पी के अनुपात
5 6	जनपद में विकास खण्डवार प्रति हे सकल बोये गये क्षेत्र पर उर्वरक उपभोग (एन पी के)
5 7	विकास खण्डवार कृषि से सम्बन्धित मुख्य सुविधाएँ (वर्ष 1981—2001)
5 8	विभिन्न फसलो के अतर्गत क्षेत्रफल (हे मे) —2001
5 9	खरीफ रबी एव जायद फसलो के अतर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत विवरण (2001—02)
5 10	जनपद में फसल प्रतिरूप मे परिवर्तन (1971 एव 2001)
5 11	विभिन्न फसलो का उत्पादकता परिवर्तन (कुन्तल/हे)
5 12	शस्य गहनता सूचकांक (2001)
5 13	फसल प्रतिरूप (1971—2001)
5 14	विकास खण्डवार शस्य प्रतिरूप एव शस्य संयोजन (2000—01)
5 15	फसल—चक्र 1971—72
5 16	जनपद मे फसल—चक्र 2001
5 17	पशुधन संख्या परिवर्तन (1993—1997) जनपद देवरिया
5 18	वृहद् एवं मध्यम वर्गीय उद्योग देवरिया, 2001
5 19	औद्योगिक अवस्थापन सुविधाएँ देवरिया जनपद—2001
5 20	हरीखाद, विवरण
6 1	जनपद मे विकास खण्डवार पक्की सड़को की लम्बाई

- 62 जनपद में विकासखण्डवार सड़कों का घनत्व (क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर)
- 63 नागपुर तथा बम्बई योजनाओं द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड
- 64 देवरिया जनपद में सड़क मार्ग द्वारा अभिगम्य बस्तियाँ
- 65 *Metalled Road Connectivity Matrix Dist Deoria-2001*
- 66 देवरिया जनपद में उपलब्ध संचार सेवाएँ
- 67 जनपद में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज एवं उनकी क्षमता (2002)
- 68 विकास खण्डवार विभिन्न प्रकार के सड़कों की लम्बाई (2002)
- 69 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद में स्वीकृत मार्गों की सूची (2002)
- 71 देश प्रदेश एवं जनपद में साक्षरता स्थिति (1991-2001)
- 72 साक्षर व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से प्रतिशत एवं साक्षरता वृद्धि। (1991-2001)
- 73 जनपद में विकास-खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं प्रतिलाख जनसंख्या पर उनकी संख्या (2000-01)
- 74 जनपद में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (2000-2001)
- 75 जनपद में विकासखण्डवार ऐलोपैथी चिकित्सा सेवा-2001
- 76 जनपद में विकास खण्डवार आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा- 2001
- 77 प्रतिलाख जनसंख्या पर जनपद में विकासखण्डवार स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति 2001
- 78 निवास स्थान के अनुरूप भारत में स्वास्थ्य की स्थिति 2000
- 81 विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत एवं विकास

★★★★★



अध्याय-एक



संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

(क) सेवाकेन्द्र की संकल्पना

1.1 सेवाकेन्द्र, केन्द्रस्थल, सेवा प्रदेश

(अ) सेवाकेन्द्र

‘सेवाकेन्द्र’ से तात्पर्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्र विशेष में एक ऐसी केन्द्रीय स्थिति से है जो क्षेत्र के निवासियों को वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करता है। सेवाकेन्द्र के लिए 1931 में मार्क जेफरसन ने ‘Central Place’ शब्द का प्रयोग किया। इसी शब्द के समानार्थक के रूप में क्रिस्टालर² ने ‘Zentralort’ शब्द का उपयोग किया। बाजार केन्द्र (Market centre) शब्द का उपयोग भी केन्द्रस्थल के ही अर्थ में होता है क्योंकि प्रत्येक केन्द्र स्थल के लिए बाजार का कार्य करना अनिवार्य है।³ सेवाकेन्द्र के सन्दर्भ में वाल्टर क्रिस्टालर⁴ द्वारा प्रतिपादित केन्द्रस्थल सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा दक्षिणी जर्मनी के केन्द्रस्थलों के अध्ययन के पश्चात् भूगोलवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों का ध्यान केन्द्रस्थल अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। इस सिद्धान्त के शैक्षणिक एवं सैद्धान्तिक महत्व के साथ ही इसका व्यावहारिक महत्व भी है, जिससे भूगोल में नया आयाम विकसित हुआ। क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की, विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने समीक्षा कर, उसे आवश्यकतानुरूप सशोधित कर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने-अपने अध्ययन प्रस्तुत किये।

(ब) सेवाकेन्द्र एवं केन्द्रस्थल

सेवाकेन्द्रों को ‘केन्द्रस्थल’ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे भिन्न-भिन्न प्रकार की ‘सेवाओं’ अर्थात् तृतीयक कार्यों के केन्द्र होते हैं। चूँकि वे अपने प्रदेश के केन्द्र होते हैं और प्रायः लगभग केन्द्रस्थ भी होते हैं, इसीलिए उनको केन्द्रस्थल कहते हैं। लेकिन कोई भी केन्द्रस्थल अपने प्रदेश के ठीक-ठीक केन्द्र में ही स्थित हो ऐसा अनिवार्य नहीं है।⁵ सेवाकेन्द्र मात्र नागरिक केन्द्र ही नहीं होते अपितु ऐसे ग्रामीण अधिवास भी जो अपने चतुर्दिक क्षेत्रों को सेवाएँ प्रदान करते हैं सेवाकेन्द्र हो सकते हैं। नगर, कस्बे तथा बाजार, ये सभी अपनी आंतरिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ कार्य अपने चारों ओर स्थित समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए भी करते हैं। ऐसे ही आर्थिक सामाजिक कार्य, जिन्हें कोई स्थान या केन्द्र न केवल अपने लिए प्रत्युत मुख्यतया चारों ओर के समीपवर्ती घेरते हुए क्षेत्रों के लिए करते हैं केन्द्रीय कार्य कहते हैं तथा ऐसे केन्द्रों को जिनमें अथवा जिनके द्वारा ये कार्य होते हैं सेवाकेन्द्र कहते हैं। आस-पास के सभी क्षेत्र इन

केन्द्रों पर अपनी बहुत सी सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार सेवाकेन्द्रों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है— *‘ऐसे स्थायी मानव अधिवास या निर्माण जहाँ पर सामाजिक—आर्थिक तरह की वस्तुओं सेवाओं तथा आवश्यकताओं का विनिमय आधारभूत रूप से और प्राथमिक रूप से अस्थानीय या अकेन्द्रीय जनसंख्या के लिए किया जाता है और इसलिए अपरोक्ष रूप से समीप स्थित चारों ओर को घेरते हुए क्षेत्रों पर जिनका अपने प्रदेश के रूप में अधिकार और नियंत्रण रहता है केन्द्रस्थल कहते हैं।’*⁶

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि न केवल नगर वरन् ग्रामीण बस्तियाँ भी सेवाकेन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि कोई ग्रामीण या अर्द्धनगरीय बाजार तथा इससे भी छोटा स्थल क्षेत्रीय केन्द्र या सेवाकेन्द्र के रूप में कार्य कर सकता है।

कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त नगरीय केन्द्र **‘सेवाकेन्द्र’** होते हैं। परन्तु समस्त सेवाकेन्द्रों को **‘नगर’** नहीं कहा जा सकता। सेवाकेन्द्रों का प्रमुख आधार अपने सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवावृत्ति में ही निहित होता है। इस प्रकार प्रत्येक सेवाकेन्द्र के चतुर्दिक कुछ न कुछ क्षेत्र होने आवश्यक है जहाँ वे अपनी सेवाओं सुविधाओं को प्रदान करते हैं। सेवित क्षेत्रों के अभाव में सेवाकेन्द्रों की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

(स) सेवा—प्रदेश

किसी केन्द्र स्थल को घेरते हुए और अपरोक्षतः समीप स्थित उस समूचे क्षेत्र को उसका सेवा प्रदेश कहते हैं, जो अपनी विनिमयात्मक आवश्यकताओं या सेवाओं के लिए पास में स्थित लगभग उसी स्तर के अन्य केन्द्रों की अपेक्षा इस केन्द्र पर अधिक निर्भर रहता है। ये प्रभाव प्रदेश सेवाकेन्द्रों के ही होते हैं। चूँकि भिन्न—भिन्न कार्यों के अपने अलग—अलग प्रदेश होते हैं अतः किसी भी एक या अधिक सेवाओं को रखने वाले स्थानों का सेवा प्रदेश केवल उन्हीं सेवाओं के लिए होगा, जो इन स्थानों में उपलब्ध हैं।

इस प्रकार का प्रदेश एक बहुकार्यात्मक सकेन्द्रीय प्रदेश होता है। केन्द्र के किसी एक व्यक्तिगत कार्य का प्रदेश एक कार्यात्मक सकेन्द्रीय प्रदेश होता है। किसी केन्द्र के सभी कार्यों के सभी ऐसे प्रदेशों को संयुक्त रूप से एक साथ देखने पर या एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करने पर एक ऐसा **‘सामान्य सेवा प्रदेश’** बन सकता है जिसमें दिए हुए केन्द्र का कुल प्रभुत्व या नियंत्रण पास के प्रतिस्पर्धा करते हुए केन्द्र की तुलना में अधिक होता है। ऐसे ही सामान्य सेवा प्रदेश को सम्बन्धित सेवाकेन्द्र के **‘प्रदेश’** या **‘सेवा—प्रदेश’** के रूप में जाना जाता है।

1.2 सेवाकेन्द्र तन्त्र

किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान कुछ तत्वों में परस्पर अन्तर्प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उन तत्वों में परिवर्तित सम्बद्धता जाल को तन्त्र (System) कहते हैं। **‘तन्त्र’** के अनुरूप ही किसी प्रदेश के

सेवाकेन्द्र तन्त्र में सेवाकेन्द्रों के आकार प्रकार वितरण तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनके पारस्परिक एवं प्रभावी सेवाक्षेत्र से अन्तर्सम्बन्धों का जिससे उनमें एक सूत्रबद्धता परिलक्षित हो अध्ययन किया जाता है। एक सामान्यतन्त्र की मुख्य विशेषताएँ निम्नांकित होती हैं—

- 1 तन्त्र के अन्तर्गत अनेक तत्व एक सूत्रबद्ध होते हैं।
- 2 इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे कार्यशीलता बनी रहती है।
- 3 ऊर्जा प्रवाह के विस्तार एवं सकृचन के अनुसार तन्त्र विकसित या सकृचित होता है।

सूत्रबद्धता तन्त्र अवधारणा का अनिवार्य तत्व है जो प्रदेश विशेष में ऊर्जा प्रवाह से निर्धारित होती है। सेवाकेन्द्र एवं सेवा प्रदेश के सन्दर्भ में गमनागमन ऊर्जा प्रवाह का द्योतक है जो किसी भी सेवाकेन्द्र तन्त्र के अस्तित्व व विकास हेतु अनिवार्य है। प्रादेशिक अर्थतन्त्र के सन्दर्भ में यह ऊर्जा प्रवाह जनसंख्या प्रवजन समाक सन्देश अथवा द्रव्य के रूप में हो सकता है। अतः किसी सेवाकेन्द्र तन्त्र में जिन केन्द्रों के मध्य ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है वह मार्ग सापेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण होगा। परिणाम स्वरूप इस सुदृढ मार्ग जाल पर धीरे-धीरे सगम बिन्दु स्थापित होते हैं जो कालान्तर में नगरीय केन्द्र के रूप में उभरते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार नये सेवाकेन्द्र बनते हैं अथवा पूर्व स्थित सेवाकेन्द्र तन्त्र में अभिवृद्धि होती है।

इस प्रकार सेवाकेन्द्र तन्त्र प्रादेशिक तन्त्र का सरचनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। किसी सेवाकेन्द्र तन्त्र में ऊर्जा प्रवाह के विस्तार एवं सकृचन के अनुसार वह तन्त्र भी विकसित एवं सकृचित होता है यथा दो प्रमुख सेवाकेन्द्रों के मध्य उपलब्ध गमनागमन मार्ग को अवरुद्ध करके किसी अन्य मार्ग से उन केन्द्रों को सम्बद्ध किया जाय तो इसके परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती मार्ग पर अवस्थित सक्रिय सेवाकेन्द्रों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा तथा दूसरी ओर नवीन परिवहन मार्ग पर नये-नये सेवा केन्द्र विकसित होंगे।

1.3 सेवाकेन्द्र . सकल्पनात्मक क्रम—विकास एवं केन्द्रस्थल सिद्धान्त

यद्यपि सेवाकेन्द्रों के लिए केन्द्रस्थल शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मार्कजेफरसन⁸ द्वारा किया गया, परन्तु इससे पूर्व सेवाकेन्द्र सम्बन्धी सकल्पना का प्रयोग वानथ्यूनेन,⁹ कोहल,¹⁰ ललाने,¹¹ गाल्पिन,¹² कुले,¹³ आदि विद्वानों द्वारा किया जा चुका था। केन्द्रस्थल (सेवाकेन्द्र) सिद्धान्त का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन का श्रेय जर्मन विद्वान् वाल्टर क्रिस्टालर (1933) को है, जिन्होंने दक्षिणी जर्मनी के 800 से 40 लाख आबादी वाले विभिन्न केन्द्रों के विशेष सन्दर्भों में अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनकी मान्यता है कि ऐसे प्रदेशों में जिनमें उच्चावचीय समानता हो प्राकृतिक ससाधन एवं जनसंख्या समवितरित हो, सभी केन्द्रों से सभी दिशाओं में परिवहन एवं गमनागमन अबाधित हो व उन पर होने वाला व्यय दूरी के समानुपातिक होता है, अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगितावादी हो एवं आर्थिक मनुष्य ही

निर्णायक इकाई हो, विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाओं के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न पदानुक्रमिक स्तरों के केन्द्रस्थलों का विकास होता है। इनमें अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकार्यों का सकेन्द्रण अधिक होता है। *क्रिस्टालर* ने इन्हीं बिन्दुओं को केन्द्रस्थल कहा तथा जो प्रकार्य इस केन्द्रस्थल या इसके चतुर्दिक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं *केन्द्रीय प्रकार्य* कहलाते हैं। प्रत्येक केन्द्रस्थल एवं उनके केन्द्रीय प्रकार्यों के मध्य अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पाया जाता है क्योंकि जहाँ एक ओर सेवा प्रदेश विभिन्न सेवाओं के लिए अपने केन्द्रस्थल पर निर्भर रहता है वही दूसरी ओर सेवाकेन्द्र भी प्राथमिक प्रकार की क्रियाओं एवं तदजनित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने सेवा प्रदेश पर निर्भर करता है।

अपनी परिकल्पना के माध्यम से *क्रिस्टालर* ने बताया कि सभी तरह से एक समाग क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का वितरण परस्पर बराबर दूरी पर प्रोत्साहित होगा एवं इस तरह व्यवस्थित सेवाकेन्द्रों का सेवाक्षेत्र षट्भुजाकार होगा क्योंकि षट्भुज ही एकमात्र ऐसी आदर्श ज्यामितीय आकृति है जिसमें एक ही स्तर के सेवाकेन्द्रों के समूह के चतुर्दिक सम्पूर्ण क्षेत्रों में न तो कोई भाग असेवित रह जाता है और न कोई उभयनिष्ठ ही होता है। प्रत्येक सेवाकेन्द्र एक निश्चित वृत्ताकार क्षेत्र को सेवाये प्रदान करता है जिसकी त्रिज्या वस्तुओं के वहनीयता के समानुपाती होती है। इस प्रकार प्रत्येक सेवाकेन्द्र का एक वृत्ताकार सेवा प्रदेश होता है किन्तु सेवितक्षेत्र केन्द्रों द्वारा सेवित क्षेत्रों के मध्य कुछ भाग या तो सेवाओं के प्राप्ति से वंचित रह जाता है या तो कुछ भाग दोनों के सेवाप्रदेशों में उभयनिष्ठ हो जाता है। इन समस्याओं के कारण ही *क्रिस्टालर* ने अपने सेवाकेन्द्रों द्वारा सेवित प्रदेशों के आकार को षट्भुजाकार माना है।

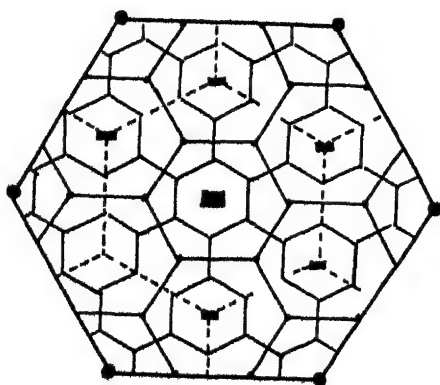
सेवाकेन्द्र संकल्पना के दो मूलभूत आधार हैं— *प्रथम* कुछ आर्थिक नियंत्रक कारक होते हैं, जो विपणन केन्द्रों के स्वरूप एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं और *दूसरा* आधार सरचनात्मक स्वरूप से सम्बन्धित है। यह स्वरूप मानव अधिवासों की आदर्शतम स्थिति में ही परिलक्षित होता है, जो केन्द्रीय क्रियाकलापों को सम्पन्न करता है। आर्थिक नियंत्रक कारकों में *प्रभाव सीमा (Threshold)* तथा *वस्तु-परास (Range of Goods)* निहित हैं। *क्रिस्टालर* के अनुसार किसी सेवाकेन्द्र को कार्यरत रहने के लिए न्यूनतम मागे होनी आवश्यक हैं। *वस्तु-परास* के अतर्गत वह दूरी आती है जहाँ तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति लाभदायक ढंग से की जा सकती है। इस तरह सेवाकेन्द्र के प्रभाव प्रदेश का निर्धारण होता है। सामान्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले सेवाकेन्द्र संख्या में अधिक होते हैं तथा विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले सेवाकेन्द्र संख्या में कम होते हैं। *क्रिस्टालर* द्वारा परिकल्पित आदर्श दशाओं के उपस्थित होने पर एक ही प्रकार के विपणन केन्द्रों की आपसी दूरी बराबर होती है।

हैगेट " (1979) के अनुसार षट्कोण वृत्त का निकटतम ज्यामितीय स्वरूप है। सरचनात्मक स्वरूप के अतर्गत *क्रिस्टालर* द्वारा प्रतिपादित सेवा प्रदेश का स्वरूप षट्कोणीय ही होता है। यदि

CLASSICAL MODELS OF CENTRAL PLACE THEORY

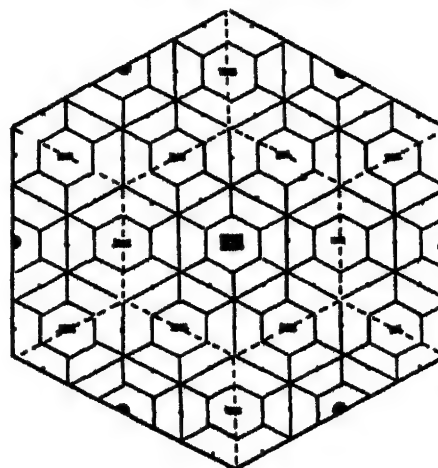
VERSORGUNGSPRINZIP MODEL

(K=3 Network)



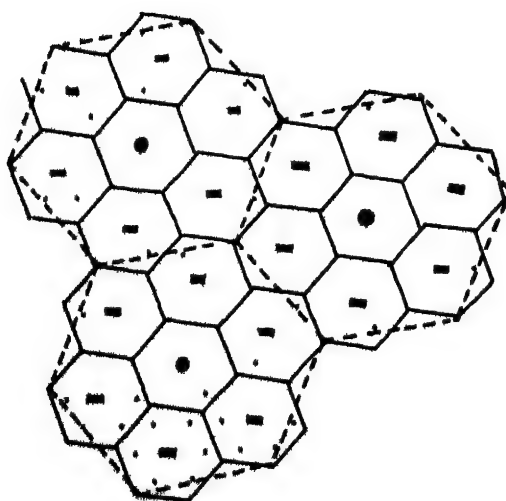
VERKEHRSPRINZIP MODEL

(K=4 Network)



ABSOUNDERUNGSPRINZIP MODEL

(K=7 Network)



- — CITY & CITY LEVEL UMLAND
- - - - TOWN & TOWN LEVEL UMLAND
- — VILLAGE & VILLAGE LEVEL UMLAND
- — HAMLET & HAMLET LEVEL UMLAND

सर्वाधिक महत्व के सेवाकेन्द्रों की स्थिति ज्ञात है तो उनसे क्रमशः कम महत्व के सेवाकेन्द्रों की स्थिति ऐसे तीन केन्द्रों द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्ष पर होती है। क्रमशः कम महत्व के सेवाकेन्द्रों के षटकोण भी एक ही तरह के वस्तुओं के लिए बराबर होंगे। इस तरह क्रमशः कम महत्व के सेवाकेन्द्रों की स्थिति उनसे अधिक महत्व के तीन सेवाकेन्द्रों के बीचों-बीच निश्चित की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक सेवाकेन्द्र के चतुर्दिक उससे क्रमशः कम महत्व के 6 सेवाकेन्द्र होंगे।

सेवाकेन्द्रों का विकास विभिन्न पदानुक्रमों में होता है तथा वे अपने विविध विस्तार वाले सेवा प्रदेशों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनमें निम्नस्तरीय पदानुक्रम के सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति पास-पास होती है तथा उनके द्वारा सेवित प्रदेश छोटा होता है जिनमें निम्नस्तरीय पदानुक्रम वाले प्रकार्यों की सेवाएँ सुलभ होती हैं। इसके विपरीत उच्चस्तरीय पदानुक्रम वाले सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति दूर-दूर होती है तथा उनके सेवा प्रदेश बड़े होते हैं। इनमें निम्नस्तरीय सेवाओं के साथ-साथ उच्चस्तरीय सेवाओं की सुलभता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय सेवाकेन्द्रों के मध्य अन्योन्याश्रिता पायी जाती है जिससे वे एक दूसरे के विकास एवं सम्पोषण में सहायक होते हैं। सेवाकेन्द्रों की अन्योन्याश्रितता तथा उनके मध्य पदानुक्रम स्थापित करने हेतु क्रिस्टालर ने कई पद-सोपान बताया एवं बताया कि इसमें आनुपातिक सम्बन्ध होता है। इस अनुपात को उन्होंने 'K' मूल्य नाम दिया 'K' का मान किसी एक प्रदेश के पदानुक्रम हेतु स्थिर रहता है। इसलिए इसे "*Fixed 'K' Hierarchy*" कहते हैं।

क्रिस्टालर ने अपने केन्द्रस्थल सिद्धान्त में विभिन्न दशाओं में 'K' के तीन मूल्य बताये हैं तथा इसके आधार पर तीन प्रतिरूपों या सिद्धान्तों की व्याख्या की है।

- 1 'K' = 3, बाजार सिद्धान्त
- 2 'K' = 4, परिवहन सिद्धान्त
- 3 'K' = 7, प्रशासकीय सिद्धान्त

केन्द्रस्थल सिद्धान्त के इस शास्त्रीय माडल को चित्र — 11 में प्रदर्शित किया गया है।

1 बाजार सिद्धान्त [*'K' = 3*]

यह सिद्धान्त उस दशा में उपयुक्त है, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण प्रधान हो। इस अवस्था में किसी केन्द्रस्थल की केन्द्रीय वस्तुओं की आपूर्ति यथा सभव निकटवर्ती स्थान से की जाती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता को वस्तुओं और सेवाओं के लिए न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है। अतः इसमें निचली श्रेणी के छ केन्द्रों की स्थिति षटभुज के शीर्ष बिन्दुओं पर होती है। इन छ केन्द्रों के प्रदेशों के केवल एक तिहाई ($6 \times 1/3$) भाग—अर्थात् दो केन्द्र और केन्द्रों की संख्या का भी एक तिहाई भाग ($6 \times 1/3$) ही बड़ी श्रेणी के प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं और बड़े केन्द्र से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करते

है। चूँकि बड़ी श्रेणी का केन्द्र अपने से छोटी श्रेणी के स्तर के कार्यों का सम्पादन भी उस श्रेणी के केन्द्र की हैसियत से करता है। अतः कुल मिलाकर एक बड़े केन्द्र और उसके प्रदेश के साथ दो छोटी श्रेणी के केन्द्र और उनके प्रदेश ($6 \times 1/3 + 1$), सम्बद्ध रहते हैं। इस प्रकार बाजार सिद्धान्त में पदानुक्रम में स्थित प्रत्येक उच्च श्रेणी का केन्द्र एवं प्रदेश अपने से निम्न श्रेणी के केन्द्र एवं प्रदेश के बीच तीन गुने का आनुपातिक सम्बन्ध रखता है (चित्र— 12A)। इसमें केन्द्रों का पदानुक्रमीय स्वरूप 1 2 6 18 54 एवं पूरक प्रदेशों का अनुपात 1 3 9 27 81 होता है। परन्तु केन्द्रों की जनसंख्या सिद्धान्त तीन गुनी कम होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में प्रत्येक केन्द्रस्थल अपने तीन उच्चस्तरीय केन्द्रस्थलों के बराबर प्रभाव में रहेगा।

सारणी-11
केन्द्रस्थलों और उनके प्रदेशों का सैद्धान्तिक वितरण-तन्त्र¹⁵
(बाजार सिद्धान्त पर आधारित संख्याएँ किमी तथा वर्ग किमी में)

क्र.सं.	पदानुक्रम का प्रकार स्तर वर्ग या श्रेणी	केन्द्रों की संख्या	केन्द्रों और प्रदेशों की कुल संख्या	प्रदेश का अर्धव्यास	दो केन्द्रों के बीच की दूरी	केन्द्रों की जनसंख्या (लगभग)	प्रदेश का क्षेत्रफल	प्रदेश की प्राकारिक जनसंख्या
1	Markort (M) बाजार पुरवा	486	729	4.0	6.9	1 000	44	3 500
2	Amtsort (A) कस्बा केन्द्र	162	243	6.9	12.0	2 000	133	11 000
3	Kreistadt (K) काउण्टी नगर	54	81	12.0	20.7	4 000	400	35 000
4	Bezirkstadt (B) जिला नगर	18	27	20.7	36.0	10 000	1 200	1 00 000
5	Gaustadt (G) छोटी प्रांतीय राजधानी	6	9	36.0	62.1	30 000	3 600	3 50 000
6	Provinzstadt (P) प्रांतीय मुख्य नगर	2	3	62.1	108.0	100 000	10 800	10 00 000
7	Landstadt (L) प्रादेशिक राजधानी नगर	1	1	108.0	186.8	500 000	32 400	35 00 000

'Stadt' means a town (नगर) स्रोत- नगरीय भूगोल ओम प्रकाश सिंह तारा, पब्लिकेशन्स, वाराणसी।

सारणी से स्पष्ट है कि क्रिस्टलर के बाजार सिद्धान्त का सबसे छोटा सेवाकेन्द्र, बाजारकेन्द्र (M) का अपने निकटतम पड़ोसी बाजार केन्द्र से दूरी 7 किमी, उसके प्रदेश का अर्ध व्यास 4 किमी तथा उससे सेवितक्षेत्र का क्षेत्रफल 44 वर्ग किमी एवं सेवित जनसंख्या 3500 व्यक्ति है। साथ ही इसकी अग्रिम उच्चतर श्रेणियों में सेवाकेन्द्रों के मध्य दूरी तथा उनका अर्धव्यास 3 या

(1 73205) गूना अधिक होता जाएगा। इसी प्रकार अगली श्रेणी में क्षेत्रफल या जनसंख्या भी तीन गुना बढ़ जाएगी, यथा कस्बा केन्द्र (A या Amtsort), जो बाजार केन्द्र M की अगली श्रेणी है की आपसी दूरी 12 कि मी उनके प्रदेश का अर्द्धव्यास 7 कि मी उनका क्षेत्र 132 वर्ग कि मी एवं उनकी सेवित जनसंख्या 11 000 हो जाएगी।

2 परिवहन सिद्धान्त [$'K' = 4$]

यह सिद्धान्त परिवहन जाल के अत्यधिक सक्रिय होने पर लागू होता है। इस सिद्धान्त का लक्ष्य परिवहन लागत को न्यूनतम करना है। इसमें निचली श्रेणी के छ केन्द्र षट्भुज के शीर्ष बिन्दुओं पर स्थित होते हैं। परिणाम स्वरूप छ केन्द्रों में से प्रत्येक के प्रदेश के आधे भाग बड़े प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं और चूँकि इनमें से प्रत्येक केन्द्र पास के दोनों बड़े केन्द्रों से सेवाएँ प्राप्त करता है अतः छ केन्द्रों और उनके प्रदेशों का आधा $(6 \times 1 / 2 = 3)$, बड़े केन्द्र और उसके प्रदेश के साथ मिलकर $(3+1)$ $K=4$ पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। इसमें से प्रत्येक उच्च श्रेणी का केन्द्र और प्रदेश अपने से निम्न श्रेणी के केन्द्र और प्रदेश से चार गुने का आनुपातिक सम्बन्ध रखता है जैसे 1 4 16 64 आदि। इसीलिए इसे $K=4$ प्रतिरूप कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सेवाकेन्द्रों के विभिन्न पदानुक्रमीय वर्गों में सेवाकेन्द्रों का अनुपात क्रमशः 1 3 12 48 192 और उनके पूरक प्रदेशों का अनुपात क्रमशः 1 4 16 64 256 होता है (चित्र 12 A)।

3 प्रशासकीय सिद्धान्त [$'K'=7$]

यह सिद्धान्त राजनैतिक किस्म का है। आर्थिक ढग से विलग यह सिद्धान्त उस दशा में लागू होता है, जब प्रशासनिक तंत्र प्रधान होते हैं। इसका उद्देश्य होता है, प्रत्येक उच्च स्तरीय केन्द्र स्थल द्वारा अपने निम्न स्तरीय केन्द्रस्थलों पर एकछत्र प्रभाव स्थापित करना क्योंकि प्रशासकीय नियन्त्रण, शक्ति का उचित क्षेत्रीय विभाजन सुरक्षा और राजनैतिक—प्रशासकीय सेवाओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार निचली श्रेणी के सभी छ केन्द्र बड़ी श्रेणी के केन्द्र के षट्भुजाकार प्रदेश के पूर्णतः भीतर षट्कोणीय ढग से इस प्रकार स्थित होते हैं कि सभी छ केन्द्रों और उनके प्रदेश पूरी तरह से एक ही बड़े केन्द्र और उसके प्रदेश से सम्बद्ध होते हैं। अतः इसमें उच्च कोटि के केन्द्र एवं प्रदेश का निम्न श्रेणी के केन्द्र एवं प्रदेश से सात गुने का आनुपातिक सम्बन्ध होता है। इसमें सेवाकेन्द्रों का अनुपात 1 6 42 294

तथा उनके पूरक प्रदेशों का अनुपात 1 7 49 343 होता है। इसमें वृद्धि 7 के गुणक में होती है। अतः इसे $K=7$ प्रतिरूप कहते हैं (चित्र 12 A)।

क्रिस्टालर द्वारा प्रतिपादित केन्द्रस्थल सिद्धान्त का प्रयोग आगे चलकर विभिन्न विद्वानों ने किया। अधिसंख्य विद्वानों का सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रमिक वर्गीकरण के प्रयासों का प्रधान उद्देश्य

यह सिद्ध करना रहा है कि वस्तुतः सेवाकेन्द्र सापेक्षिक केन्द्रीयता के अनवरत क्रम में नहीं प्रत्युत एक दूसरे से सर्वथा विलग कोटियो में होते हैं। इनके अनुसार पदानुक्रम वर्ग की एक कोटि दूसरी अग्रिम कोटि से सर्वथा भिन्न एवं स्पष्टतया विलग होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि *क्रिस्टालर* ने परिवहन के साधन एवं प्रशासनिक सीमाओं के सन्दर्भ में केन्द्रस्थल सिद्धान्त का परिमार्जन किया था। *ब्रश*¹⁶ 1953 ने *क्रिस्टालर* के परिकल्पना की पुष्टि की तो *विनिग*¹⁷ 1955 तथा *थामस*¹⁸ 1961 ने सेवाकेन्द्रों की कोटिबद्ध पदानुक्रम व्यवस्था को गलत सिद्ध करते हुए कहा कि सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रमिक श्रेणियों में स्पष्टतया कठोर विलगाव नहीं पाया जाता प्रत्युत सेवाकेन्द्र एक अनवरत क्रम में स्थित होते हैं। *बेरी* तथा *गैरीसन* 1958¹⁹ ने केन्द्रस्थल सिद्धान्त का संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण करने के उपरांत बताया कि सेवाकेन्द्रों की स्थापना समाग दशाओं में ही होगा ये आवश्यक नहीं है। जनसंख्या के असमान वितरण एवं असमान क्रयशक्ति के होने पर भी केन्द्रस्थल सिद्धान्त लागू हो सकता है। इन्होंने *विनिग* एवं *थामस* के पदानुक्रमिक विचारों पर गहरी असहमति व्यक्त करते हुए *क्रिस्टालर* के स्पष्ट विलग कोटियों का जोरदार समर्थन किया तथा पदानुक्रम का निर्धारण कार्याधार जनसंख्या एवं वस्तुओं की परिवहनीयता के आधार पर करते हुए केन्द्रस्थल सिद्धान्त को अधिक व्यापक बना दिया।

4 लॉश का 'आर्थिक भूदृश्य सिद्धान्त'

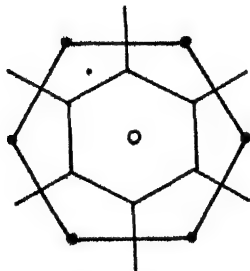
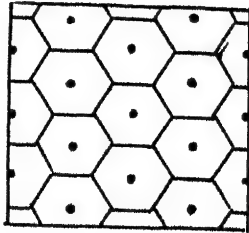
क्रिस्टालर के परिकल्पना से प्रेरित होकर विभिन्न विद्वान किसी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति, प्रतिरूप तथा सेवा प्रदेश के विकास में इनके प्रभाव के विश्लेषण की ओर उन्मुख हुए। इनमें कुछ विद्वानों ने *क्रिस्टालर* के मत के प्रति सहमति व्यक्त की जबकि अन्य ने इससे असहमति व्यक्त करते हुए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुकूल इसमें परिमार्जन प्रस्तुत किया। इनमें *लॉश* प्रमुख हैं।

*लॉश*²⁰ ने *क्रिस्टालर* के केन्द्र स्थल तत्र सिद्धान्त की विचारधाराओं एवं मान्यताओं के आधार पर इसमें कुछ वास्तविकता एवं लचीलेपन का समावेश करते हुए अपने आर्थिक भूदृश्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया (चित्र 12B)। *लॉश* ने *क्रिस्टालर* के षट्भुजाकार बाजार क्षेत्र से सहमति जताते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत निश्चित पदानुक्रम को नहीं माना, साथ ही अपने भूवैय्यासिक संगठन में ना तो उच्चस्तर के केन्द्रस्थल द्वारा सेवित निम्न स्तर के केन्द्रों की कोई संख्या निश्चित की और न ही *क्रिस्टालर* की तरह उनके आकार का ही परिसीमन किया।²¹ *लॉश* के प्रतिरूप में एक उच्च केन्द्र होता है जहाँ सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा इन्हीं पर वास्तविक विशेषीकरण, श्रम विभाजन एवं अन्य केन्द्रों के मध्य व्यापार सम्पन्न होता है। निम्नस्तरीय केन्द्र बड़े केन्द्रों को अपने विशिष्ट उत्पादन की आपूर्ति करते हैं। नगरों से सेवाकेन्द्रों में दूरी बढ़ने के साथ साथ केन्द्र का आकार बढ़ता है एवं लघु केन्द्र बड़े केन्द्र के मध्य समाहित होने की प्रवृत्ति

CENTRAL PLACE THEORY

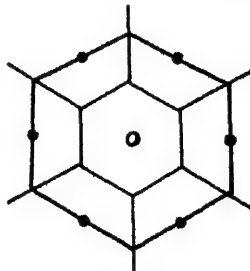
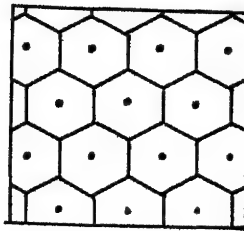
(A)

MARKETING PRINCIPLE



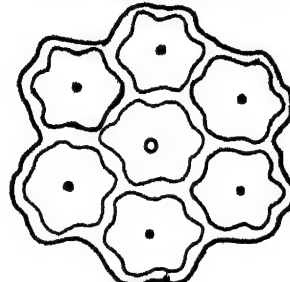
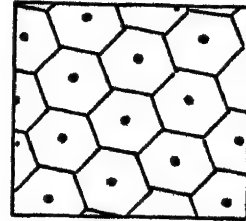
$K = 3$

TRANSPORT PRINCIPLE



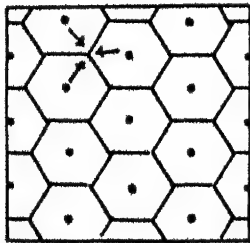
$K = 4$

ADMINISTRATIVE PRINCIPLE

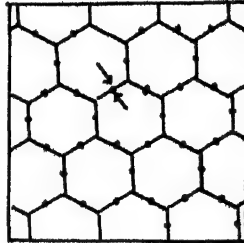


$K = 7$

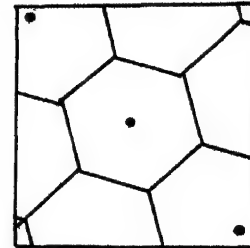
(B)



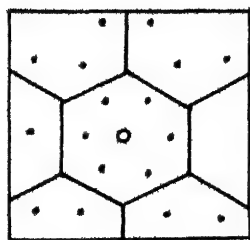
$K = 3$



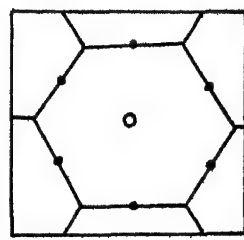
$K = 4$



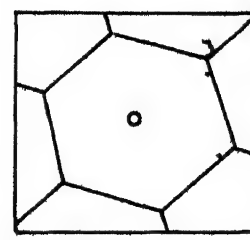
$K = 7$



$K = 9$



$K = 12$



$K = 13$

(C)

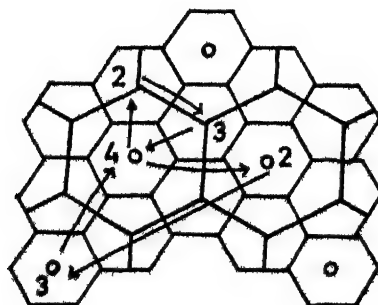


FIG 1 2

रखते हैं।

लॉश ने लघुतम कृषि ग्रामो को अपना प्रारम्भिक बिन्दु माना है जो समान रूप से वितरित नाभिकीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इनमें से जब कोई ग्राम विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करता है तो उसे बाहर क्षेत्र की आवश्यकता होती है और ये क्षेत्र एक षटभुजाकार आकार में ही प्राप्त होता है। यदि फार्म द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार क्षेत्र अतिरिक्त उत्पादन के कारण विस्तृत होता है तो वह अन्य प्रतियोगी उत्पादन केन्द्रों के प्रभाव क्षेत्रों पर षटभुजों द्वारा अतिक्रमण द्वारा ही सम्पन्न होता है। इन्होंने षटभुजों के आकार को भौगोलिक के साथ-साथ उत्पादित वस्तुओं के केन्द्र के सम्बन्ध में भी माना है। इस प्रकार एक केन्द्र विशेष के विभिन्न उत्पादनों के लिए कई षटभुजाकार बाजार क्षेत्र प्राप्त हो सकते हैं। परिवहन लागत को लॉश ने दूरी का परिणाम बताया है। इसलिए यदि उद्योग की परिवहन लागत दूसरे से कम है तो उसका षटभुजाकार बाजार क्षेत्र दूसरे की अपेक्षा अधिक विस्तृत होगा।

लॉश की मान्यता है कि जिन वस्तुओं की अवसीमा आवश्यकता आधारभूत षटभुजाकार बाजार क्षेत्र की 1 से 3 होती है वे $K=3$ रेखा जाल में जबकि 3 से 4 के मध्य रहने वाली वस्तुएँ $K=4$ प्रतिरूप में तथा 4 से 7 के मध्य अवसीमा वाली वस्तुएँ $K=7$ प्रतिरूप में स्थित होंगी। ऐसी स्थिति में एक ऐसा आर्थिक भू-दृश्य उत्पन्न होता है जिसमें अधिकतम संख्या में अवस्थितियाँ होती हैं, साथ ही सभी वस्तुओं के मध्य की कुल दूरी न्यूनतम होती है। अतः वस्तुओं की स्थानीय आपूर्ति अधिकतम संख्या में न्यूनतम लागत में होती है।

5 लॉश और क्रिस्टालर के अध्ययन की तुलना

- [1] क्रिस्टालर का केन्द्रस्थल सिद्धान्त उच्च श्रेणी के नगरों से प्रारम्भ होकर निम्न श्रेणी के नगरों की ओर आगे बढ़ता है, जबकि लॉश छोटे केन्द्र से बड़े केन्द्र की ओर बढ़ते हैं।
- [2] क्रिस्टालर का सिद्धान्त तृतीयक कार्यों या सेवाओं की व्याख्या अधिक उपयुक्त ढंग से करता है, जबकि लॉश का मॉडल द्वितीयक कार्यों हेतु अधिक उपयुक्त है।
- [3] क्रिस्टालर के सिद्धान्त में एक प्रदेश के पदानुक्रम हेतु जहाँ 'K' का मान स्थिर रहता है, वही लॉश का पदानुक्रम काफी लचीला एवं परिवर्तनशील है।

इस प्रकार लॉश एवं क्रिस्टालर के सिद्धान्तों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वे दोनों ही वस्तुओं के लिए एक रूप तथा समान माँग को प्रारम्भिक बिन्दु मानते हैं। लेकिन लॉश गौण प्रकार्यों तथा भूवैय्यासिक अर्थव्यवस्था के लघुस्तर पर क्रियान्वयन से अधिक सम्बन्धित है जबकि क्रिस्टालर वृहद स्तर से नीचे की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों के प्रतिरूप कृषि निवेश तथा उसके उत्पादन की माँग-पूर्ति के प्रति उपेक्षा करते हैं। लॉश के प्रतिरूप में केन्द्रस्थलों का पदानुक्रमिक होना आवश्यक नहीं है तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि आकार से समानता रखने वाले केन्द्र

वस्तुओं के परिसर में भी समानता रखे। इन दोनों के षटभुजाकार योजना में भी पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है। लॉश की योजना क्रिस्टालर की योजना की तरह योजनाबद्ध नहीं है।

क्रिस्टालर ने केन्द्रस्थलों को स्थायी माना जबकि अध्ययन क्षेत्र जैसे विकासशील क्षेत्रों में केन्द्रीय क्रियाकलाप आवर्ती विपणन केन्द्रों के द्वारा सम्पादित होते हैं। क्रिस्टालर ने इन्हें अपने सिद्धान्त में स्थान नहीं दिया है। स्किनर²² ने ऐसे आवर्ती केन्द्रस्थलों का केन्द्रस्थल सिद्धान्त में समावेश किया है। इस परिमार्जन से केन्द्रस्थल सिद्धान्त की सरचनात्मक अपेक्षाओं में कुछ अन्तर आया है (चित्र 12C)।

क्रिस्टालर, लॉश के पश्चात् अनेक विद्वानों ने पदानुक्रम निर्धारण में केन्द्रीय कार्यों को आधार माना जिसमें— उलमैन²³ स्मेल्ट्स²⁴ डिकिन्सन²⁵ ब्रश²⁶ कार्टर²⁷ आदि विद्वानों का अध्ययन प्रमुख है। सिडाल²⁸ ने थोक व्यापार ब्रेशी²⁹ गोडलुण्ड³⁰ ने जनसंख्या ग्रीन³¹ कैरुथर्स³² ने बस सेवकों लोमश³³ ने प्रकीर्णन आरेख तथा ग्रीस्टन³⁴ बेकमैन³⁵ एव डेकी³⁶ ने गणितीय मॉडल का प्रयोग केन्द्रस्थलों के पदानुक्रम निर्धारण में किया।

इन विद्वानों के अतिरिक्त हैरिश³⁷ इशार्ड³⁸ फिलब्रिक³⁹ बेरी एव गैरीशन⁴⁰ मेयर⁴¹ किंग⁴² जॉनसन⁴³ डेविस⁴⁴ पार⁴⁵ फिशर⁴⁶ थामस⁴⁷ आदि का नाम प्रमुख है, जिन्होंने केन्द्रस्थलों से सम्बन्धित अध्ययन करके नगरीय भूगोल में नये आयाम जोड़ने के प्रयास किये।

1.4 भारत में सेवाकेन्द्रों से संबंधित अध्ययन

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक सेवाकेन्द्रों का अध्ययन पाश्चात्य देशों तक सीमित रहा। पर युद्धोपरान्त भारत में भी इसका अध्ययन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से होने लगा। यद्यपि भारत में व्यक्तिगत नगरों का अध्ययन 1950 ई. से ही प्रारम्भ हो गया था परन्तु सेवाकेन्द्रों से सम्बन्धित सर्वप्रथम अध्ययन, कर⁴⁸ द्वारा 1960 ई० में 'कलकत्ता प्रदेश के केन्द्रस्थलीय पदानुक्रम' में किया गया।

काशीनाथ सिंह⁴⁹ ने मध्य गंगाघाटी के सेवाकेन्द्रों का अध्ययन कर भारत में नगरीय भूगोल के नींव को सबलता प्रदान किया परन्तु सेवाकेन्द्रों के विविध पहलुओं का सर्वप्रथम विशद अध्ययन ओमप्रकाश सिंह⁵⁰ द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'उत्तर प्रदेश के केन्द्रस्थलों का अध्ययन', के माध्यम से हुआ।

केन्द्रस्थलों एवं विकास केन्द्रों के माध्यम से बनमाली⁵¹ एवं सेन⁵² द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित विकास हेतु नियोजन के प्रयास किये गए। सेवाकेन्द्रों को विकास ध्रुवों के रूप में देखते हुए मिश्रा⁵³, प्रकाशराव⁵⁴ एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रादेशिक नियोजन के तर्कसंगत प्रयास हुए

जिससे प्रादेशिक नियोजन में सेवाकेन्द्रों की भूमिका की सकल्पना स्पष्ट रूप से उजागर हुई।

इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्वानों द्वारा सेवाकेन्द्रों से सम्बन्धित अनेक अध्ययन प्रस्तुत किये गये इनमें *सिंह*⁵⁵ *तिवारी*⁵⁶ *मिश्रा*⁵⁷ *रवान*⁵⁸ *मूर्ति*⁵⁹ *पाण्डेय*⁶⁰ आदि के अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण हैं।

(ख) विकास की संकल्पना

1.5 विकास, प्रगति एवं सवृद्धि की अवधारणा

विकास प्रगति एवं *सवृद्धि* शब्दों का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है परन्तु तीनों शब्द भिन्न हैं। *डडले सियर्स* ने करीब 30 वर्ष पूर्व संभवतः लैटिन अमेरिकी देशों के सन्दर्भ में लिखा था *ग्रोथ विदाउट डेवलपमेन्ट* अर्थात् बिना विकास के वृद्धि। इस प्रकार सामान्य अर्थ में *विकास* से आशय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि से है जबकि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कई और तत्वों पर भी आधारित है। *प्रगति* का क्षेत्र और भी व्यापक एवं विस्तृत है। इसमें विकास के साथ-साथ अन्य सामाजिक पहलू भी समाहित हैं। *सवृद्धि* का अर्थ है आकलन किए जा सकने वाले तत्वों में बढ़ोतरी। इस प्रकार विकास से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन से है तो प्रगति से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन से।⁶¹

(अ) प्रगति और विकास

प्रगति का अभिप्राय वाछनीय परिवर्तन से है, जिसमें इष्ट मूल्यों की पूर्ति होती है। प्रगति का सदर्भ उद्देश्यपरक दिशा की ओर धनात्मक परिवर्तन होता है। यदि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन वाछित तरीके से होता है तो उसे *प्रगति* समझा जा सकता है। इस प्रकार प्रगति एक सापेक्षिक धारणा है जिसमें वर्तमान का मूल्यांकन भूतकाल को आधार बनाकर किया जाता है। इसमें मूल्यांकन एक सामान्य किन्तु निश्चित पैमाने पर किया जाता है। मूल्यांकन की कसौटिया आर्थिक, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक लक्षण गुण और मानसिक विकास है। तकनीकी प्रगति सरलतम कसौटी है, इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से निकट का सम्बन्ध है। वास्तव में किसी क्षेत्र में परिवर्तन या प्रगति दूसरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और उस पर निर्भर भी है। अतः प्रगति एक जटिल परिघटना है।⁶²

प्रगति की अवधारणा की तरह विकास की अवधारणा में भी वाछित दिशा में परिवर्तन की ओर संकेत है। इस प्रकार विकास की अवधारणा एक नूतन परिघटना है। जबकि प्रगति की अवधारणा प्रबोध और औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है। विकास की प्रकृति सदर्भात्मक और सापेक्षिक है। इस प्रकार वाछनीय दिशा में नियोजित गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय को *विकास* कहते हैं। विकास की धारणा सामाजिक—सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक और

भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पायी जाती है।

विकास एक सम्मिश्र अवधारणा है। किसी क्षेत्र के विकास में कृषि उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन एवं संचार आदि विभिन्न क्षेत्र में प्रगति को शामिल किया जाता है। विकास में समाज के निम्नतम उपेक्षित लोगों के कल्याण को भी सम्मिलित करते हैं और तत्संबधित कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करते हैं। अतः विकास एक मूल्य-भारित अवधारणा है। यह किसी समाज क्षेत्र और जनता की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक व भौगोलिक आवश्यकताओं से सम्बद्ध है।⁶³ विकास का अभिप्राय एक परिघटना के पूर्णतर वृद्धि रूपी उद्विकास से है। मनुष्य का अपने पर्यावरण पर नियंत्रण विकास का ही उदाहरण है।

(ब) सवृद्धि और विकास

आर्थिक सवृद्धि को हम एक ऐसी वृद्धि दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अत्यन्त निम्न जीवन स्तर में फँसी हुई किसी अल्पविकसित अर्थ व्यवस्था को अल्पावधि में ही ऊँचे जीवन स्तर तक पहुँचा सके।⁶⁴ कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक सवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का कुल राष्ट्रीय उत्पादन लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है⁶⁵। आर्थिक सवृद्धि से प्रायः यह अर्थ निकाला जाता है कि उत्पादन में समय के साथ कितनी वृद्धि हुई? दूसरी ओर आर्थिक विकास की संकल्पना में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढाँचे में क्या परिवर्तन हुए? इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के हिस्से के सापेक्ष उद्योगों सेवाओं व्यापार बैंकिंग व विनिर्माण का हिस्सा बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया में श्रम शक्ति की व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन होता है तथा उसके कार्य कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि होती है। अतः सवृद्धि परिवर्तन के मात्रात्मक पहलू की ओर संकेत करती है जबकि विकास में मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रश्रय मिलता है।⁶⁶

किडलबर्गर के अनुसार जहाँ आर्थिक सवृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है वही आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन की तकनीक, संस्थागत व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। आर्थिक सवृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके उसकी उत्पादकता व उत्पादन बढ़ाकर आर्थिक सवृद्धि की जा सकती है किन्तु आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन लाना अनिवार्य होता है साथ ही उसके आवंटन में भी परिवर्तन लाना होता है, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार जहाँ आर्थिक सवृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय पर ध्यान देना पड़ता है, वही आर्थिक विकास का अनुमान मुख्यतः संरचनात्मक परिवर्तनों के आधार पर लगाया जाता है।

(स) क्रांति और विकास

किसी भी क्षेत्र में त्वरित आकस्मिक धनात्मक परिवर्तन को ही *क्रान्ति* कहते हैं। क्रांतियों क्षेत्रों के अनुसार अनेक प्रकार की होती हैं यथा— राजनैतिक क्रांति सामाजिक क्रांति औद्योगिक क्रांति कृषि क्रांति आदि। यहाँ क्रांति का तात्पर्य विकास के सन्दर्भ में है। क्रांतिकारी विकास से अप्रत्यासित विकास होता है जबकि साधारण विकास सतत गतिशील होता है। इस प्रकार क्रांति का अर्थ परिवर्तन के चरम स्वरूप से है।⁶⁷ यदि किसी समाज या क्षेत्र में इस तीव्र परिवर्तन से सामाजिक करने की क्षमता नहीं है तो उसके नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। जहाँ विकास से धीमे एवं सतत परिवर्तन का बोध होता है वहीं इससे सतुलित विकास का भी बोध होता है। जबकि क्रांति का अर्थ तीव्र और आमूल परिवर्तन होता है।⁶⁸ किसी समाज या क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्रांतिकारी विकास की आवश्यकता होती है, वस्तुतः ये विकास प्रक्रिया की कुजी होते हैं जिन्हें तीव्र किये बिना अन्य विकास कार्य सम्पादित ही नहीं हो सकते। भारत के सन्दर्भ में हरित क्रांति के बाद कृषि आधारित उद्योगों का विकास स्वतः स्फूर्त था। मानव समाज के विकास में क्रांतियों ने एक आवश्यक भूमिका अदा की है।⁶⁹

1.6 विकास की भौगोलिक अवधारणा

मनुष्य अपने चेतन व गतिशील स्वभाव के कारण सभी प्राणियों से अलग है। वह अपने वर्तमान वस्तु-स्थिति से सन्तुष्ट न रहकर उसमें मनोवांछित परिवर्तन लाकर विकसित स्वरूप देखना चाहता है। वस्तुओं एवं घटनाओं का स्वरूप परिवर्तन ही विकास होता है।⁷⁰ परिवर्तन दो तरह का होता है— ऋणात्मक एवं धनात्मक। विकास का सम्बन्ध धनात्मक परिवर्तन से होता है।⁷¹ यह परिवर्तन भूतल पर अवस्थित किसी भी वस्तु-स्थिति से हो सकता है। अतः तथ्यात्मक सन्दर्भ में विकास की परिभाषाओं का स्वरूप बदलता रहता है। विकास के अतर्गत भू-तल पर अवस्थित सम्पूर्ण तथ्यों में धनात्मक परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य ही सभी अध्ययनों का केन्द्र-बिन्दु होता है और मानव कल्पना में वृद्धि ही भूगोल का मूल उद्देश्य रहा है।⁷² अतः मानव के क्रिया-कलापों के विकास को ही विकास की परिधि में सम्मिलित करना चाहिए। ये क्रिया-कलाप सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों से सम्बन्धित हो सकते हैं। इन समस्त क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं का स्थान सर्वोपरि है किन्तु विकास का सम्बन्ध केवल आर्थिक क्रियाओं से ही नहीं है, इसमें वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति के आधारभूत कारक संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन को भी विकास के अतर्गत समाहित किया जाता है। वस्तुतः विकास एक व्यावहारिक संकल्पना है जिसका अभिप्राय प्रगति, उत्थान एवं वांछित परिवर्तन से है। विगत वर्षों में विकास से तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति और सुधार से समझा जाता था, किन्तु आजकल इसका आशय जीवन के विविध क्षेत्रों में हुए वांछित गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से किया जाता है।⁷³ इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर *ब्रह्मप्रकाश* एवं

मुनीस रजा ⁷⁴ ने विकास को कार्य अथवा कार्यों की एक श्रृंखला या प्रक्रम माना है जो जीवन की दशाओं में शीघ्र ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय सुधार करता है अथवा भविष्य में जीवन की सम्भावना में वृद्धि करता है या दोनों ही कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं।

गुलतुग ⁷⁵ ने विकास की नयी परिभाषा देते हुए बताया कि विकास का सिद्धान्त सामाजिक विषयों का वह क्षेत्र है जहाँ भूतकाल का अध्ययन इतिहास वर्तमान का अध्ययन समाजशास्त्र अर्थशास्त्र एवं भूगोल आदि तथा भविष्य का अध्ययन भविष्यशास्त्र एक साथ करते हैं। आर पी मिश्र ⁷⁶ ने विकास का विश्लेषण करते हुए कहा है कि विकास समाज एवं अर्थ व्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार के अतिरिक्त उनमें वांछित गति से वांछित दिशा में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ-साथ मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से सम्बद्ध है। इसमें सामयिक क्षेत्रीय तथा स्थानीय पहलुओं के साथ नियोजन का समन्वय देखा जाता है। विकास के विविध पहलुओं को देखते हुए आर एन सिंह ⁷⁷ ने लिखा है कि— *विकास एक आदर्शोन्मुखी सकल्पना है जिसमें सकारात्मक, प्रयोजनात्मक एवं वांछित सतत उर्ध्वोन्मुख परिवर्तन समाहित है।*

1.7 आर्थिक विकास की अवधारणा

यह विकास की अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो आर्थिक सवृद्धि की अवधारणा से अधिक व्यापक है परन्तु आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सवृद्धि की पूर्व दशा का होना अनिवार्य है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विकास की प्रमुख समस्या गरीबी, सवृद्धि होने के बावजूद बढ़ती गयी जिससे शताब्दी के मध्य के बाद से आर्थिक विकास की सकल्पनाओं को आर्थिक सवृद्धि से भिन्न माना जाने लगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब— उल— हक ⁷⁸ का कहना है कि विकास की सर्वप्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

आर्थिक विकास से सम्बन्धित दो मुख्य विचारधाराएँ हैं—

प्रथम परम्परागत विचारधारा है— जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में 5-7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एवं उत्पादन तथा रोजगार में परिवर्तन का स्वरूप इस प्रकार हो कि तृतीयक व विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा कृषि की अपेक्षा बढ़ता जाय को शामिल किया जाता है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि द्वारा विकास के शेष उद्देश्यों (गरीबी निवारण आर्थिक असमानता में कमी और रोजगार अवसरों में वृद्धि आदि) को स्वतः धीरे-धीरे प्राप्य मान लिया जाता है।

व्यवहारिक रूप में देखने से पता चलता है कि जनसंख्या के अधिकांश भाग को आर्थिक

संवृद्धि से कोई लाभ नहीं मिला और उनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। अतः बहुत से विद्वानों ने इस परम्परागत विचारधारा को सशोधित करके आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी असमानता और बेरोजगारी का निवारण रखा है। इसके अंतर्गत पुनर्वितरण के साथ संवृद्धि (*Redistribution with Growth*) का नाम दिया है। इस सम्बन्ध में चार्ल्स पी० किन्डलबर्गर और ब्रूस हैरिक⁷⁹ का कहना है आर्थिक विकास की परिभाषा प्रायः लोगों के भौतिक कल्याण में सुधार के रूप में आँकी जाती है। जब किसी देश में खासकर निम्न आय वाले लोगों के भौतिक कल्याण में बढ़ोत्तरी होती है जनसंख्या को अशिक्षा बीमारी और छोटी उम्र में मृत्यु के साथ-साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय न रहकर औद्योगिकरण होता है जिससे उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले कारकों के स्वरूप में परिवर्तन होता है कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है और आर्थिक तथा दूसरे प्रकार के निर्णयों में लोगों की साझेदारी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है। इस प्रकार के परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं।

ब्रोगर⁸⁰ ने आर्थिक विकास का अर्थ बताते हुए कहा है कि इसके अंतर्गत सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के संयुक्त प्रभाव को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माइकल पी० टोडेरो⁸¹ विकास के स्वरूप को सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना एवं विचारों के बाह्य परिवर्तन में बताते हैं। विकास में न केवल आर्थिक पक्ष बल्कि सामाजिक कल्याणकारी, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पक्ष भी आते हैं। इसीलिए स्मिथ⁸² ने लिखा है कि मानव के कल्याण में वृद्धि ही विकास है। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए निम्न उद्देश्यों का पूरा होना अनिवार्य है—

- (1) आर्थिक विकास निर्धन जनसंख्या के लिए अर्थपूर्ण हो
- (2) निर्धनता में कमी हो,
- (3) वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि हो
- (4) आर्थिक असमानता में कमी हो
- (5) क्षेत्रीय असमानता में कमी हो,
- (6) विकास और समृद्धि की दरों में क्षेत्रीय अंतर में कमी हो।

उपरोक्त में से एक या दो अथवा सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम असफल रहते हैं तो आर्थिक विकास कहना अनुपयुक्त होगा चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी ही क्यों न हो जाय।⁸³

18 विकास (इकोडेवलपमेंट) की अवधारणा

यह विकास की नवीनतम अवधारणा है। प्रारंभिक वर्षों में पर्यावरण की भारी कीमत पर हुए भौतिक विकास के कारण उत्पन्न पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय समस्याओं में इस अवधारणा का

बीज निहित है। इसके अतर्गत वर्तमान में पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए विकास करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य है।

प्रारम्भिक विचारधारा कि मानवीय क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है के बाद जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने मानव को प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रभावित सीमाओं को पार करने में सक्षमता का एहसास दिलाया तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए मानव ने विकास के अनेक द्वार खोल दिए। इस क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होने लगा जो आज विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं (*वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण ओजोन आवरण क्षय हरित गृह प्रभाव जल संकट सूखा जलवायु परिवर्तन आदि*) के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं एवं जिसका दुष्प्रभाव मानव सहित समस्त जीवन-जगत पर पड़ रहा है।

वातावरण का विनाश सिर्फ आर्थिक विकास के कारण ही नहीं बल्कि अत्यधिक निर्धनता का भी प्रतिफल है।⁸⁴ भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आने वाली समस्याएँ गरीबी व विकास के निम्न स्तर से जुड़ी हुयी हैं हमारी विशाल आबादी और उसमें हो रही निरन्तर वृद्धि तथा अनियमित विकास गतिविधियों के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुँच रही है वह इतनी अधिक है कि इसके लिए सीधे आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रबन्ध को अब भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए मार्ग निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आज गरीबी बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास की तीव्र दर के रूप में देखा जा रहा है। परन्तु इस प्रक्रिया ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को त्वरित किया है, जो स्वयं विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का अनचाहा परिणाम है, ये समस्याएँ हैं— प्राकृतिक ससाधनों का कुप्रबन्ध, वनों का विनाश, कूड़े-कचरे और अवाछित पदार्थों का अनियोजित ढग से फेंका जाना विषैले रसायनों का अधार्धुध प्रयोग, अति नगरीकरण आदि।⁸⁵

उपर्युक्त विवरण से लग सकता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी हैं पर ऐसा नहीं है। प्रारम्भ में ये माना जाता था कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुँचाये विकास नहीं हो सकता। जहाँ विकसित देशों में पर्यावरण ह्रास का कारण विकास है वही विकासशील देशों में इसका प्रधान कारण गरीबी है। आज इन पर्यावरणीय समस्याओं के सन्दर्भ में विकास का अर्थ पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए तथा उनके अनुकूलतम उपयोग से विकास करना हो गया है। क्योंकि विकास का केन्द्र मानव होता है तथा मानव के सर्वांगीण और स्थायी विकास के लिए प्रकृति का अक्षुण्ण रहना भी अनिवार्य है। इस प्रकार प्रकृति की इस अक्षुण्णता को बनाये रखते हुए विकास करना ही *सविकास* की अवधारणा है। अर्थात् विकास और पर्यावरण परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, प्रतिलोम नहीं। इस प्रकार सविकास का सामान्य अर्थ है, बिना विनाश के विकास, इसे *संयुक्त विकास* (*सस्टेनेबल डेवेलपमेन्ट*) अथवा *ठोस विकास* (*साउण्ड डेवलेपमेन्ट*) की संज्ञा दी जाती है। *संयुक्त विकास* का उद्देश्य है— मानव समाज की विद्यमान भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को,

बिना भावी पीढ़ियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार नुकसान पहुँचाए सुनिश्चित करना। संक्षेप में *सविकास ऐसा विकास है, जो सामाजिक दृष्टि से वांछित आर्थिक दृष्टि से सतोषप्रद एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से पुष्ट हो।*⁸⁶

1.9 विकास के निर्धारक तत्व

प्राकृतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सस्थाये आर्थिक विकास के तीन आधारभूत प्राचल हैं जिनके द्वारा विकास की दिशा तथा स्तर निर्धारित होता है⁸⁷ किन्तु विकास की सकलपना तथा विकास को निर्धारित करने वाले सूचको के सम्बन्ध में मतभेद है। ये सूचक एक स्थान से दूसरे स्थान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। विकास स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित *एडेलमैन* तथा *मेरिस*⁸⁸ ने राजनैतिक तथा सामाजिक विषयो से सम्बन्धित 41 सूचको का प्रयोग किया है। वर्तमान समय में विकास का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिस्थिति में निरन्तर वृद्धि करना है। इस वृद्धि को किसी समाज की आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग तथा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर से ज्ञात किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर *हेगल*⁸⁹ ने समाज एवं व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित 12 सूचको का प्रयोग विकास के स्तर को निर्धारित करने में किया है। *सयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध सस्थान*⁹⁰ (UNRISD) ने 16 सूचको को विकास के स्तर निर्धारण में उचित बताया है। *बेरी*⁹¹ ने 1960 में आर्थिक विकास के विश्लेषण में परिवहन ऊर्जा का प्रयोग कृषि उत्पाद संचार, व्यापार, जनसंख्या तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्रमुख सूचको के रूप में प्रयुक्त किया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक सूचक प्रयुक्त हुए हैं किन्तु अधिकांश विद्वानों ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरीकरण, रोजगार, संचार, परिवहन तथा जनसंख्या संरचना औद्योगिकरण आदि सूचको का प्रयोग किया है।

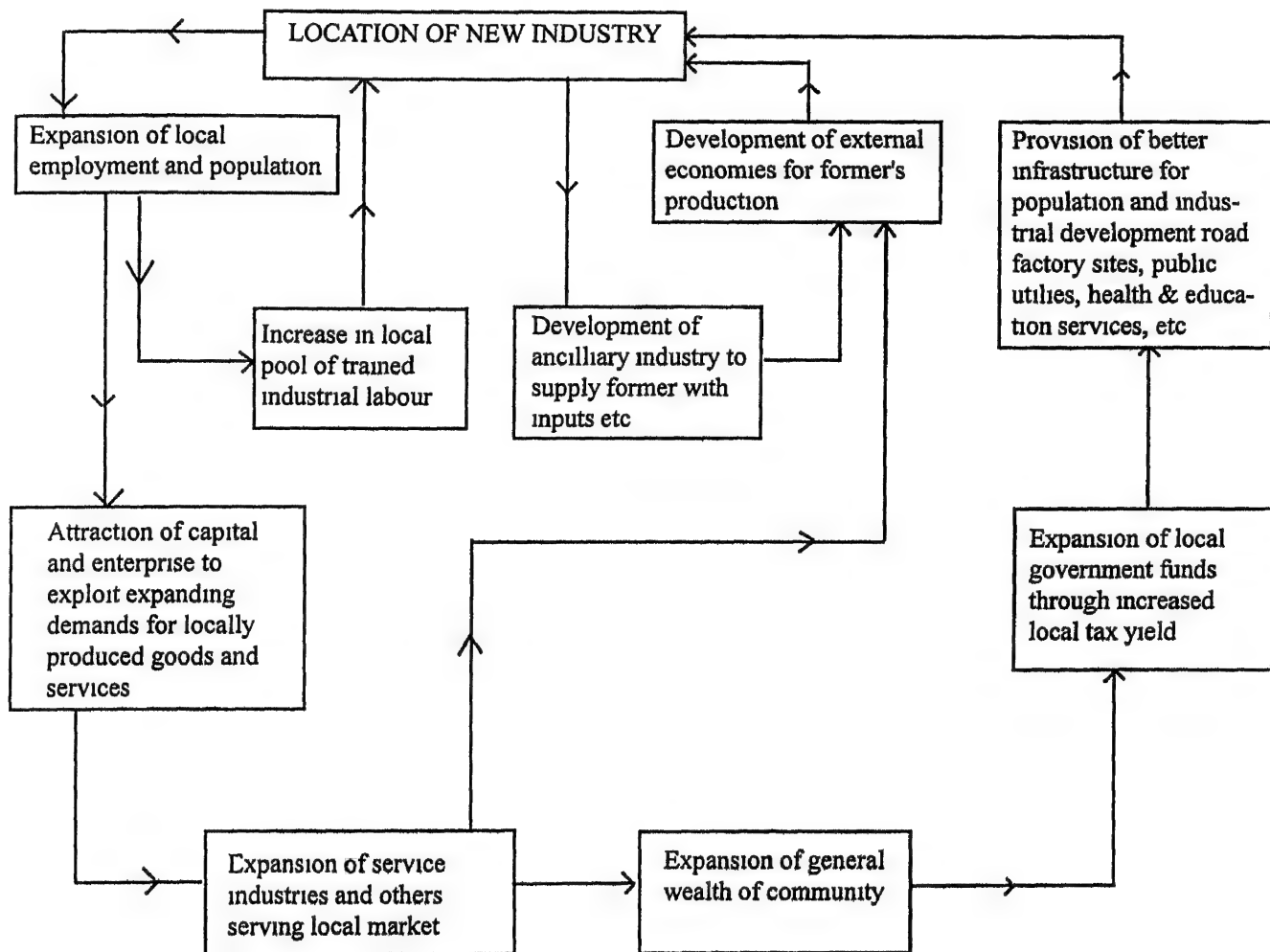
1.10 विकास के सिद्धान्त

समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों अर्थशास्त्रियों तथा जीव विज्ञानियों ने विकास से सम्बन्धित अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उनमें से भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त कुछ प्रमुख सिद्धान्तों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नवत है—

(अ) मिरडल का 'क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल'

मिरडल महोदय⁹² ने 1956 में विकास सम्बन्धी 'क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल' प्रस्तुत किया (चित्र-1.3)। इसके माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रादेशिक विभेदशीलता आर्थिक विकास का स्वाभाविक प्रतिफल होती है, क्योंकि एक प्रदेश बिना दूसरे को क्षति पहुँचाये कभी भी विकास नहीं कर सकता। इनके मॉडल से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित होता है जहाँ कच्चा माल एवं शक्ति के साधनों की उपलब्धता आसानी से होती

MYRDAL'S PROCESS OF CUMULATIVE CAUSATION



Source : R J, Chorly and P Haggett
'Models in Geography' Methuen

हैं। उनके अनुसार किसी स्थान पर एक बार विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यों के सचयी प्रभाव केन्द्राभिमुखी शक्ति एवं गुणक प्रभाव के कारण सतत बढ़ती जाती है। फलतः बढ़ती हुई औद्योगिक इकाइयों द्वितीयक प्रकार की औद्योगिक स्थापना को जन्म देती हैं जिससे केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है। सामाजिक इकाइयों इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं जिससे स्वयंपोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है। केन्द्रीय प्रदेशों की ओर अपेक्षतया निर्धन क्षेत्रों से ससाधनों का आकर्षण बढ़ता जाता है जिसे *मिरडल* ने *बैकवास इफेक्ट* कहा तथा इसके परिणाम स्वरूप अभिवर्धित केन्द्रीय प्रदेश से फैलने वाले सम्भावित विकास को *स्प्रेड इफेक्ट* की संज्ञा दी जिसके माध्यम से अतत सम्पूर्ण प्रदेश का विकास होता है।

इस प्रकार उन्होंने विकास की तीन अवस्थाओं का निरूपण किया। *प्रथम अवस्था* को प्रारम्भिक औद्योगिक स्थिति कहा जब प्रादेशिक असमानताएँ न्यूनतम होती हैं। *द्वितीय अवस्था* में सचयी कारक सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जिससे प्रदेश विशेष अन्य प्रदेशों की तुलना में तीव्रगति से विकसित होता है तथा ससाधनों के वितरण में असंतुलन बढ़ने लगता है। *तृतीय अवस्था* में निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताएँ कम होने लगती हैं।

मिरडल महोदय के इस मॉडल की आलोचना इसके अत्यधिक गुणात्मकता को लेकर हुई जिसके कारण यह मॉडल वास्तविकता से परे हो जाता है। इसके बावजूद विकसित एवं विकासशील राष्ट्र तथा किसी देश के विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों के अन्तर को स्पष्ट करने में यह मॉडल काफी सक्षम है।⁹³

(ब) फ्रीडमैन का 'केन्द्र-परिधि मॉडल'

फ्रीडमैन ने *मिरडल* के दो प्रदेशों की आर्थिक विषमताओं के स्थान पर स्थानिक रूप से विषमताओं का वर्णन किया है तथा विश्व को *गतिशील प्रदेश*, द्रुतगति से बढ़ने वाले *केन्द्रीय प्रदेश* तथा अल्पगति से बढ़ने वाले या *स्थैतिक प्रदेश* में विभक्त किया है। *फ्रीडमैन* के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार में विकास के स्तर के परिप्रेक्ष्य में चार सकेन्द्रीय कटिबंध देखे जा सकते हैं।⁹⁴

पहला प्रदेश— जिसकी अवस्थिति केन्द्रीय होती है को उन्होंने केन्द्रीय प्रदेश कहा है। यह प्रदेश का वह क्षेत्र होता है, जहाँ नगरीय औद्योगीकरण उच्चस्तरीय तकनीक विविध ससाधन तथा जटिल आर्थिक संरचना के साथ वृद्धिदर उच्च होती है। इस प्रदेश के परिधीय क्षेत्र में विस्तृत केन्द्रीय प्रदेश से प्रभावित ऊर्ध्वोन्मुख मध्यम प्रदेश होता है। जहाँ ससाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है, जन प्रवास वृहद् पैमाने पर होता है तथा आर्थिक वृद्धि स्थिर होती है। तत्पश्चात् परिधीय विस्तार में ससाधन युक्त सीमान्त प्रदेश होता है, जहाँ नूतन खनिजों के खोज एवं विदोहन हेतु नवीन अधिवासों का विकास होता है तथा उसकी सीमा में सवृद्धि की संभावनाएँ विद्यमान होती हैं। केन्द्रीय प्रदेश से सुदूरतम प्रदेश को उन्होंने अधोन्मुख प्रदेश कहा है, जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है तथा कृषि उत्पादन न्यूनतम होता है, जो प्राथमिक

ससाधनो की समाप्ति तथा औद्योगिक संस्थानों की क्षीणता के कारण सम्पन्न होता है। 'क्यूमूलेटिव कॉंजेशन मॉडल' की ही भाँति इस मॉडल का भी प्रयोग आर्थिक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु किया जा सकता है।

(स) रोस्टोव का 'आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सिद्धान्त'

यह सिद्धान्त विशेषतः तकनीकी नवीनताओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रदेश में सामयिक आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करता है। रोस्टोव ने किसी क्षेत्र के विकास की निम्न पाँच अवस्थाओं का निरूपण किया है—⁹⁵ (चित्र-14)

(क) रूढ़िवादी समाज

(ख) ऊपर उठने की पूर्व अवस्था

(ग) ऊपर उठने की अवस्था

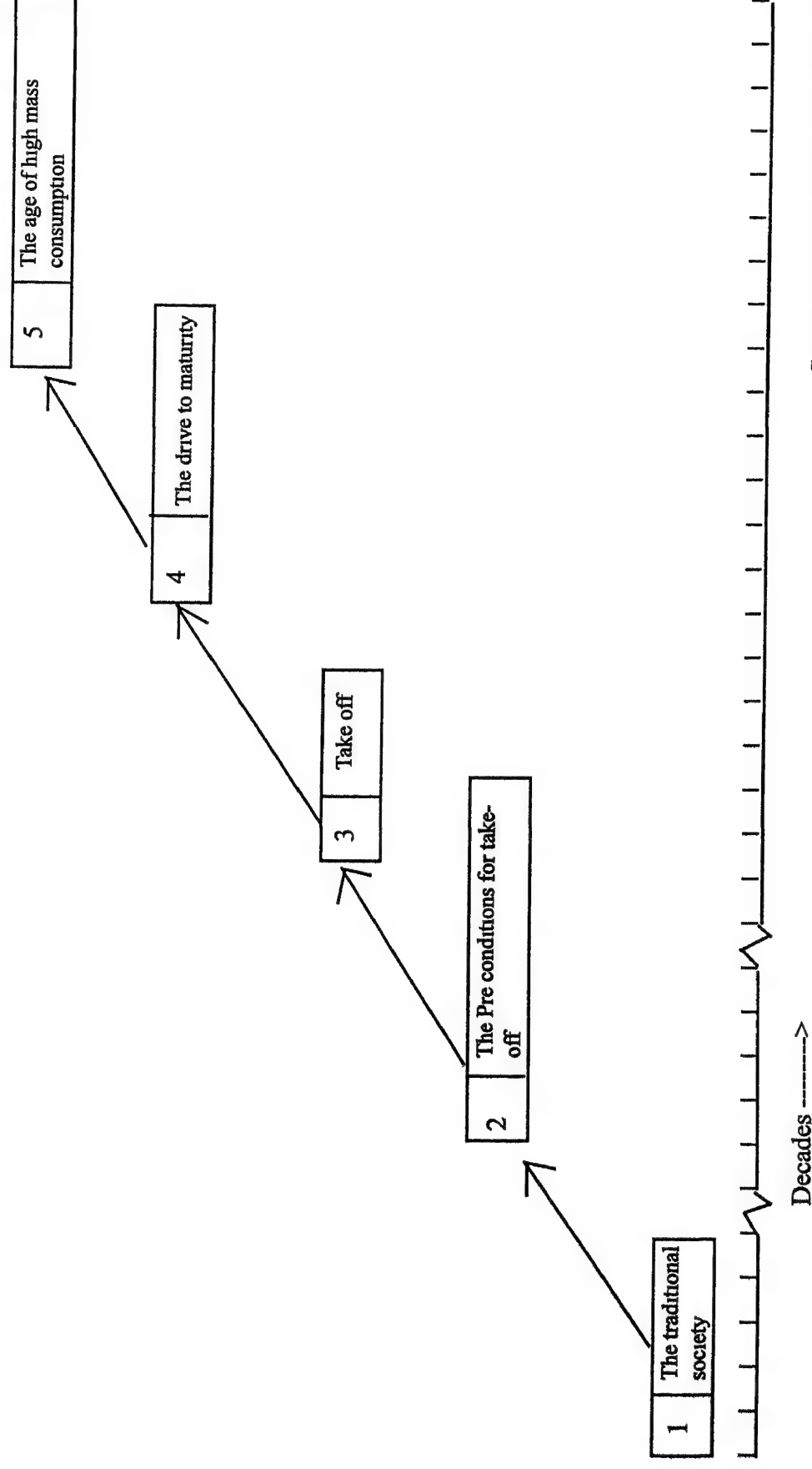
(घ) चरमोत्कर्ष प्राप्त करने की अवस्था तथा

(ङ) अधिकतम उपभोग की अवस्था

पहली अवस्था में इन्होंने रूढ़िवादी समाज की कल्पना की है जिसका प्रधान व्यवसाय निर्वाहन कृषि है तथा सभाव्य ससाधनों की खोज नहीं हो पायी है। कुछ दशकों के बाद ऊपर उठने के पूर्व की अवस्था (द्वितीय अवस्था) आती है जबकि आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है और व्यापार विस्तृत होता है। वाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीकों के प्रयोग के साथ-साथ नवीन तकनीकों का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है। तृतीय अवस्था ऊपर उठने की अवस्था आती है जब प्राचीनता का प्रतिस्थापन नवीनता द्वारा हो जाता है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त समाज का जन्म होता है, जिससे अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है। राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है तथा स्वयंपोषी एवं स्वयं-सेवी वृद्धि आरम्भ हो जाती है। चतुर्थ अवस्था में समाज अत्यधिक सुसंगठित हो जाता है तथा पूँजी बढ़ने लगती है। कुछ पुरानी औद्योगिक इकाइयों का समापन नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण होने लगता है। वृहद् नगरीय क्षेत्र विकसित होने लगते हैं तथा यातायात-संचार व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो जाता है। चौथी अवस्था का चरमोत्कर्ष पाँचवी अवस्था है, उत्पादकता प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है, तकनीकी व्यवस्था में वृद्धि होने लगती है तथा भौतिकता में वृद्धि के साथ ससाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण हेतु होने लगता है।

इस सिद्धान्त में पूँजी निर्माण की विधि की व्यवस्था की गयी है, किन्तु पाँच अवस्थाओं के अर्तसम्बन्ध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं की गयी है। इसके बावजूद साधारण तथा विकसित देशों के विश्लेषण में यह प्रक्रिया सदिग्ध है। तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं।

THE ROSTOW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT



Source R J Chorley and P Haggett,
'Models in Geography', Methuen

(द) विकासध्रुव एव विकास केन्द्र सिद्धांत

विकास ध्रुव सकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1955 में *पेरॉक्स*⁸⁶ महोदय ने किया। चूँकि *पेरॉक्स* एक अर्थशास्त्री थे इसलिए इन्होंने केवल आर्थिक तत्वों पर ही ध्यान केन्द्रित किया भौगोलिक तत्वों की ओर इनका ध्यान नहीं गया। इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय *बोडविले*⁸⁷ को है। *पेरॉक्स* की मान्यता है कि किसी क्षेत्र में विकास एकाएक प्रकट नहीं होता है अपितु वह कुछ सीमित केन्द्रों पर विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होता है तथा उसका प्रभाव अनेक रूपों में अनेक माध्यमों द्वारा फैलता है। विकास की इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय ससाधनों के समुचित प्रयोग तथा क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकताएँ पूरी होने की क्षमता छिपी होती है।

पेरॉक्स के अनुसार '*वृद्धिध्रुव*' से तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है जिससे अपकेन्द्रीय शक्तियाँ बाहर की ओर फैलती हैं तथा जिसकी ओर अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक केन्द्र आकर्षण और विकर्षण के केन्द्र के रूप में अपना निजी क्षेत्र रखता है जो अन्य केन्द्रों के क्षेत्र में सम्बद्ध होता है। इनके अनुसार प्रत्येक केन्द्र में कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग या आर्थिक कार्य स्थित होते हैं जो नवीनीकरण एवं वृद्धि के जनक होते हैं। ये उद्योग एवं आर्थिक कार्य बड़े अपेक्षाकृत प्रगतिशील प्रविधियों से युक्त तथा तीव्र वृद्धि की विशेषताओं वाले होते हैं। इन्हीं औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ये केन्द्र सम्बन्धित प्रदेशों में अग्रगामी तथा पृष्ठगामी सम्बन्धों को स्थगित करने के द्वारा विकास की उत्पत्ति करते हैं। चूँकि प्रादेशिक आर्थिक विकास ऐसे ही केन्द्रों के माध्यम से होता है अतः इन्हें *वृद्धिजनक ध्रुव* कहते हैं। इन केन्द्रों से बाहर की ओर फैलने वाला प्रभाव समस्त क्षेत्र के विकास में सहायक होता है, किन्तु केन्द्र से बाहर की ओर फैलने वाले प्रभावों पर यदि अन्दर की ओर आने वाले प्रभाव अधिक प्रभावी होते हैं तो केन्द्र के समीपवर्ती क्षेत्रों के ससाधन, पूँजी निवेश एवं मानव क्षमताएँ केन्द्र की ओर खिंचती चली जाती हैं, जिससे क्षेत्रीय विषमता का जन्म होने लगता है अर्थात् केन्द्र विकसित होता है और प्राश्ववर्ती क्षेत्र पिछड़ जाता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त का सबसे प्रबल तर्क यह है कि केन्द्र में विभिन्न सुविधाओं के पूँजीभूत होने से वहाँ स्वतः स्फूर्त विकास उत्पन्न हो जाता है जिससे अवस्थापनात्मक कारक यथा—सड़के शक्ति जल स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का विकास हो जाता है।

विकास ध्रुव शब्द के प्रयोग के सन्दर्भ में *डारवेण्ट*⁸⁸ का विचार है कि प्रकार्यात्मक एवं भौगोलिक दोनों क्षेत्रों के लिए इस शब्द के प्रयोग से संभव की स्थिति असम्भव हो जाती है। अतएव इसके निराकरण हेतु भौगोलिक केन्द्र के क्षेत्रों के लिए '*विकास केन्द्र*' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारत जैसे विकासशील देश के सदर्भ में विकास केन्द्र सकल्पना को प्रयोज्य बनाने हेतु *आर पी मिश्र*⁸⁹ ने इन विकासकेन्द्रों में तीन आधारभूत प्रकार्यों का पाया जाना आवश्यक माना है, जिसके अनुसार ये केन्द्र सेवाकेन्द्र, विकास उत्प्रेरक केन्द्र एवं सामाजिक रूपान्तरण केन्द्र के रूप

मे कार्य करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों में विविध योगदान के आधार पर *आर पी मिश्र* तथा कुछ अन्य लोगो ने वृद्धि जनक केन्द्रों को पाँच पदानुक्रमीय वर्गों में रखा है—

- (1) राष्ट्रीय स्तर पर 'वृद्धि ध्रुव' (*Growth Poles*)
- (2) प्रादेशिक स्तर पर 'वृद्धि केन्द्र' (*Growth Centres*)
- (3) उप-प्रादेशिक स्तर पर 'वृद्धि बिन्दु' (*Growth Points*)
- (4) लघु-प्रादेशिक स्तर पर 'सेवाकेन्द्र' (*Service Centres*)
- (5) स्थानीय स्तर पर 'केन्द्रीय ग्राम' (*Central Village*)

विकास ध्रुव सिद्धान्त में दो प्रमुख कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम विकास ध्रुवों का चयन कठिन है तथा द्वितीय राजनीतिक दबाव के कारण चयन प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। *बोदविले* ने इन विकास ध्रुवों की पहचान प्रमुख केन्द्रीय बस्तियों के रूप में किया है जिनमें दूसरे बस्तियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उनके अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की संख्या और क्षेत्रीय आकार में इन केन्द्रों के विभिन्न स्तर होंगे। इनमें सबसे बड़ा केन्द्र क्रमशः अपने छोटे केन्द्रों को प्रभावित करेगा तथा अविकसित क्षेत्र इन केन्द्रों से लाभ उठा सकेंगे। फलतः सम्पूर्ण क्षेत्र विकास परिधि में आ जाएगा। विकास की यह प्रक्रिया 'ट्रिकल डाउन' तथा 'टॉप डाउन' के नाम से भी जानी जाती है। विकास ध्रुवों से विकास की ऐसी क्रमबद्ध श्रृंखला बन जाती है, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में सतुलित विकास की गति मिलती है। इसके इन्हीं विशेषताओं के कारण नियोजकों में यह सिद्धान्त काफी लोकप्रिय है। विकास ध्रुवों की अवस्थापना में स्थान का चयन तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराने में धन की आवश्यकता कभी-कभी इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। वास्तव में विकास ध्रुवों की उत्पत्ति का सहसम्बन्ध उस क्षेत्र के मॉग व पूर्ति पर निर्भर करता है।

इस प्रकार प्रगतिशील उद्योग औद्योगिकरण तथा उनका प्रभाव विस्तार ही इस सिद्धान्त का मूलाधार एवं प्रमुख तत्व है।¹⁰⁰ समय-समय पर *मृदाल*,¹⁰¹ *हैन्सन*,¹⁰² *हारमेनसन* आदि द्वारा इसमें अनेक सुधार किए गए हैं। *हर्षमैन*, *मृदाल* तथा *फ्रीडमैन*¹⁰³ ने इसमें सचयी कार्यकारण तथ्यों पर तथा प्राथमिक असमानताओं के सकेन्द्रण की प्रवृत्ति सम्बन्धी विचार जोड़े। इस सन्दर्भ में *मृदाल* का मत है कि विकास की प्रक्रिया इस प्रकार संचालित होती है कि उसका पश्चगामी प्रवाह अग्रगामी प्रवाह की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है और इससे आर्थिक प्रवाह का फैलाव स्वतः अवरोद्ध हो जाता है। जबकि *हर्षमैन* की मान्यता है कि किसी निश्चित अवधि में अग्रगामी प्रवाह का धीरे-धीरे प्रवाह होना अपरिहार्य है। *फ्रीडमैन* ने अपने अध्ययन में किसी केन्द्र की नव्यताओं को उत्पन्न करने या उसे अपनाने की क्षमता को अधिक महत्व प्रदान किया है।



References

- 1 Yeates and Garner 'The North American City', *Op cit*, P 160
- 2 Christaller, W (1933) 'Central place in Southern Germany', Translated by C W Baskin, New Jersey
- 3 Berry's 'Geography of market Centres', *op (fn 4)*, pp 1-3
- 4 Christaller, W (1933), 'Central Place in Southern Germany', Translated by C W Baskin New Jersey
- 5 सिंह ओम प्रकाश 'नगरीय भूगोल प्रथम संस्करण 1979 पृष्ठ- 320
- 6 Singh, O P (1973) 'Central Places their Origin and Evolution' *U B B P Vol 9, Pt 1*, pp 30-34
- 7 सिंह ओम प्रकाश 'नगरीय भूगोल प्रथम संस्करण 1979 पृष्ठ-323-324
- 8 Yeates and Garner, 'The North American City', *op cit*, P 160
- 9 Von, Thunen, J N (1910), 'Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationale Ökonomie, Jena'
- 10 Kohl, J C (1850), 'Der Verkehr und die Ansiedlung der Menschen in ihrer Abhängigkeit, Von der Gestaltung der Erdoberfläche', 2nd ed Leipzig
- 11 Lalanne, L (1863), 'An essay of theory of Railway system based on observation of facts and basic laws governing population distribution', *Academia Des Sciences, Vol 57*, pp 206-10
- 12 Golpin, G J (1915), 'Social Anatomy of an Agricultural Community', *Res Bull, 34, Univ Of Wisconsin*
- 13 Cooley, C H (1889), 'The theory of Transportation' Publication of the American Economic Association, May, 1889 p 148
- 14 Haggett, P and Clift, A D and Prey, A (1979), 'Locational Analysis in Human Geography', Vol 1, Arnold, Heinemann
- 15 Christaller's original work 'Die Zentralen' (Fn 4), p 72 and Baskin, C W, *Op cit (Fn 4)*, P 67
- 16 Brush, J E (1953), 'The Hierarchy of Central Places in S W Wisconsin' *Geog Rev, Vol 1-43, PP 380-402*
- 17 Winning R (1955), 'A Description of, Certain Spatial Aspects of Economic System, Economic development of cultural change', Vol-3, pp 147-75
- 18 Thomas, E N (1961), 'Toward an Expanded Central Place Model', *Geog, Rev, Vol.51*, pp 400-411
- 19 Berry, B J L and Garrison, W L (1958), 'The Functional bases of Central place Hierarchy and note on the central place Theory and Range of good', *Eco-Geog 34*, pp 145-154
- Berry, B J L and Garrison, W L (1958), 'Recent development of Central Place theory', *proc of the Reg Science*
- 20 Loesh, A (1954), 'The Economics of Location', Yale University press, New Haven.
- 21 Mishra, R.P et al, 'The Economics of Location', Yale University Press New Haven

- 22 Skinner, G W (1954) 'Marketing and Social Structure in Rural China', *Jl As Stud* Vol 35, pp 445-53
- 23 Ullman, E L (1941), 'A Theory of Location of Cities', *American Journal of Sociology*, XI VI, No-2, pp 853-68
- 24 Smailes A E (1944), 'The Urban Hierarchy in England and Wales', *Geography*, 29, pp 41-51
- 25 Dickinson R E (1951) 'The wets European city', *A Geographical Integration* London
- 26 Brush, J E (1953) *op cit*
- 27 Carter, H C (1955) 'Urban Graded and Spheres of Influence in South-West Wales', *Scot Geog Mag*', 71, p 43-56
- 28 Siddol, W R (1961), 'Wholesale Retail Trade Relations as Indices of Urban Centrality', *Econ Geog* , 37
- 29 Bracey, H E (1956), 'A Rural Component of Centrality applied to six southern Countries, the U K ', *Econ Geog* , 32, pp 38-50
- 30 Godlund, S (1956), 'The Functions and Growth of Bus Traffic with the sphere of Urban Influence', *Lung Stud in Geog*, Ser B No 18
- 31 Green, F H W (1948) 'Motor Bus Service in West England', *Trans Inst of British Geog* , 14, pp 59 -68
- 32 Carruthers, W I (1953), 'The Classification of Service centres in England and Wales', *Geog JI* 123, pp 371-285
- 33 Lomas, G M (1964) 'Retail Trade Centres in the Midlands', *Town Plan Inst Soc*
- 34 Preston, R E (1971), 'The Structure of Central Place System', *Econ Geog Vol* 47
- 35 Beckmann, M J (1958), 'City Hierarchies and the distributoin of city size', *Eco Devel Cul Change*, No -6
- 36 Dacey, M F (1962), 'Analysis of Central Place and point Pattern by Nearest-Neighbour Analysis', *Lund Std in Geog Series B*, 4
- 37 Harris, C D (1953), 'A Functional classification of the Cities in the United State', *Geog Rev Vol* 53
- 38 Isard, W (1956), 'Mitod for Bestamning evtatorters centralitetagrade', *Vensk Geog Arsback*, Vol 34
- 39 Philbrick A K (1957), 'Areal Functional Organization in Regiond Human Geog ', *Eco Geog* 33
- 40 Berry, B J L & Garrison, W L (1958), *op cit*
- 41 Mayor, H M & Cohn C F (1959), 'The Economic Bese of cities', in *Readings in the Urban Geography Chicago*
- 42 King, L C (1962), 'Central Place Theory and the spacing of Town in the United States', in M M caskil (Ed) *Land and Livelihood*', *Newzeeland Geog Soc*
- 43 Johnson, R J (1966), 'Central Places and the Settlement Pattern', *A A A G Vol* 56

- 44 Davies, W K D (1967) 'Centrality and Central place Hierarchy' *Urban Studies*, 4
- 45 Parr J B (1977), 'Growth Poles Regional Development and Ceneral Place Theory' *Pap Reg Assn* 31
- 46 Fisher, H B (1975) 'Rural Growth Centres, experience in the Pilot Research Project, Sanfrancisco' 26
- 47 Thomas E N (1961) *op cit*
- 48 Kar, N R (1960) 'Urban Hierarchy and Contral function around Calcutta in lower West-Bengal and their Significance', *Proc of the I G U Symp in Urban Geog, Lund 'Swden*
- 49 Singh, K N (1966), 'Spatial Pattern of Central Places in Middle Ganga Valley,' *N G J I Vol 12, No 4*
- 50 Singh O P (1969), 'The Study of Central Placel in U P', *Unpub Ph D thesis, B H U , Varanasi*
- 51 Wanmali, S (1972), 'Regional planning for Social Facilities An Examination of Central Place concept and their Application'
- 52 Sen , L K et al (1971) 'Planning Rural Growth Centres for Integrated Development, study of Miryalguda Taluka' *N I C D , Hyderabad*
- 53 Mishra, R P (1972), 'Growth-Poles and Growth Centres in the context of India's Urban and Regional Development Problems' in Kullinski (Ed)
- 54 Rao, V L S P (1974), 'Planning for an Agricultural region' in Mishra, R P et al, 'Reginal Development Planning in India' New Delhi
- 55 Singh, J (1979), 'Central Places and Spatial organization in a Backward Economy Gorakhpur Region- A study in Intergrated Regional Development, Gorakhpur
- 56 Tiwari, R C (1980), 'Spatial organization of Service Centres in the lower Ganga- Yamuna Doab', *Nat Geog Val XV, No 2, pp 103-124*
- 57 Mishra, H N (1984), 'Urban Systems of a Developing Economy, A study of Allahabad City Region', *I I D R , Allahabad*
- 58 Khan, Z T (1992), 'Spatial Distribution of Central Place in Sheonath Basin', *Paper presented in XIII th Annual meet of N G Gorakhpur*
- 59 Murthy K L N (1993), 'Identification of Central place Hierarchy A case Study form flood prone Environment', *paper Presented in XVth I G C, Bhubaneswar*
- 60 Pandey, J N & Mishra, P (1989), 'Environment and spatial Distribution of settlement in Deoria Distriet U P', in Mishra, B N (ed), 'Rural Development in India', Allahabad, PP 225-231
- 61 दत्त भवतोष वृद्धि विकास और प्रगति 'योजना' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली 15 अगस्त 1987 पृष्ठ 6
- 62- शर्मा के एल भारतीय समाज एन सी ई आर टी नई दिल्ली 1991 पृष्ठ 153
- 63- वही पृष्ठ 154
- 64- मिश्र एस0के0 एव पुरी वी0के0 भारतीय अर्थव्यवस्था' टिमनकला पब्लिशिंग हाउस मुम्बई 2000 पृ 3

- 65 Meir G M and Balduin, R E , 'Economic Development Theory, History and Policy' New York, 1957, P 2
- 66 Drewnowski, J , 'On Measuring and Planning the quality of Life, Mounon', The Hague, 1974, p 95 s
- 67- पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 62 पृष्ठ 151
- 68- देव उपर्जन सभ्यता की कहानी (2) एन सी ई आर टी नई दिल्ली 1987 पृ 178
- 69- वही पृष्ठ 179
- 70- मिश्रा बी एन 'विकास एक वैज्ञानिक-धार्मिक सन्दर्भ' भू-सगम 2 (1) इलाहाबाद ज्योग्राफिक्स सोसायटी इलाहाबाद 1984 पृ 1-16
- 71 Qureshi, M H , 'India Resources and Regional Development', NCERT, New Delhi, 1990, p 81
- 72 Smith, D M Human Geography A welfare Approach, Arnold Heine Mann, London, 1984
- 73 सिंह आर एन एव कुमार ए० भारतीय नियोजन प्रणाली एव ग्रामीण विकास एक समीक्षा भू-सगम 2 (1) इलाहाबाद ज्योग्राफिक्स सोसायटी इलाहाबाद 1984 पृष्ठ 17-24
- 74- Prakash, B and Raza M , 'Rural Development Issues to Ponder', Kurukshetra, 32(4), 1984, PP 4-10
- 75 तिवारी आर सी तथा त्रिपाठी एस 'समन्वित ग्रामीण विकास भौगोलिक दृष्टिकोण' 'ग्रामीण विकास सकल्पना उपागम एव मूल्यांकन (स) सिंह पी एव तिवारी ए पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र इलाहाबाद 1989 पृ 48-64
- 76 Mishra, R P Sundaram, K P and Prakash Rao, V L S, 'Regional Development Planning in India A New Stretegy', Vikas Publishing House New Delhi, 1974, p 189
- 77 Singh, R N and Kumar, A, 'Spatial Reorganisation Concept & Approaches', National Geographer, 18 (2), 1983, p 215-226
- 78 Haque, Mahbub-ul, "Employment and Income Distribution in the 1970s A New Perspective", Pakistan Economic and Social Review, June- Dec 1971 p 6
- 79 Kindleberger C P and Herrick, B , 'Economic Development' (New York, 1977) p 1
- 80 Broger, D , 'Central Palace System, Regional Planning Development in Developing Countries Case of India'
- 81 Todaro, M P, 'Economic Development', in the Third World', New York, Long man Inc 1983
- 82 पूर्वोक्त संदर्भ - स 72
- 83 Seers, Dubley, 'The Meaning of Development', 11th world conference of the Society for International Development (New Delhi-1989) p 3
- 84 सिंह जगदीश, 'वातावरण नियोजन एव सविकास' ग्रामोदय प्रकाशन गोरखपुर 1988 पृ० 242
- 85- 'भारत' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, 2000 पृ० 140-142
- 86- पूर्वोक्त संदर्भ सं०- 84 पृ० 242-246
- 87 Qureshi, M H , 'India Resources and Regional Development', NCERT, New Delhi 1996. p 81

- 88 *Adelmn, I and Herris C T , 'Society, Politics and Economic Development' Baltimore, The Jon Hopkins, 1967*
- 89 *Hagen, E E , 'A framework for Analysing Economic and Political Development', Booking Institution, 1962, pp- 1-38*
- 90 *'United Nations Research Institute for Social Development Contents and Measurements of Social Economic Development', Geneva, Report No 70, 10, 1970*
- 91 *Berry, B J L , 'An Inductive Approach to the Regionalization of Economic Development', 1960*
- 92 *Myrdal, G 'Economic Theory and Underdevelopment', London 1957*
- 93 *Keeble, D , 'Models of Economic Development', in R J Chorley and P Haggette, 'Models in Geography', London, Methuen, 1967*
- 94 *Friedman, J , 'The Urban Regional Frame for National Development, International Development Review, 1966*
- 95 *Rostow, W W , 'The Stage of Economioc Growth', London, Cambridge University press, 1962 p 2*
- 96 *Persons, F, 'La Nation De Croissance', Economique Applique, Nos 1 & 2, 1955*
- 97 *Boudeville, T R , 'Problem of Regional Economic Planning', Edinburgh University Press, 1966*
- 98 *Darwent, D F 1969, 'Growth Poles and Growth Centres Regional Planning-A Review Environment and Planning' Vol I pp- 5-32*
- 99 *Mishra, R P (1979), 'Central Places and Spatial Centres in the context of India's Urban & Regional Development', in Kulklinski, A (ed)*
- 100 *Glasson, J (1978), 'An Introduction to Regional Planning, Concept, Theory and Practice', London pp 146-148*
- 101 *Myrdol, G M (1975), 'Economic Theory and Under-development Regions, London*
- 102 *Hanson, N M (1972), 'Growth Centres in Regional Economic Development', New York*
- 103 *Freidmann, J R (1969), 'A General Theory of Polarised Development', School of Architecture and Urban Planning, Los Angles*





अध्याय-दो



अध्ययन क्षेत्र का महत्व एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि

नामकरण— देवरिया' का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मंदिर स्थिति हो।¹ इस प्रकार देवरिया की उत्पत्ति देवरही से मानी जाती है जो करना नदी (Karna river) तट पर स्थित चतुर्भुजी भगवती के मंदिर हेतु विख्यात है। देवरिया का वर्तमान प्रदेश प्राचीन काल में घने जंगलो (अरण्य) से आवृत था। अतः इसे देवारण्य प्रदेश या देवारण्य भी कहा जाता था क्योंकि इस अरण्य प्रदेश में देवों एवं ऋषियों की तपोस्थली थी। इस प्रकार देवरिया शब्द की व्युत्पत्ति देवारण्य से देवरिया भी मानी जाती है।

अध्ययन क्षेत्र का महत्व

1 अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) का पौराणिक महत्व

इस जनपद के पौराणिक आख्यानो पर दृष्टिपात करे तो विदित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के प्रथम पुत्र कुश की राजधानी कुशीनगर में थी जो कभी इसी जनपद में था अब स्वयं जनपद हो चुका है। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर हरिहर क्षेत्र की ओर जाते समय इस जिले के दक्षिण पश्चिम कोण पर सरयू के सगम पर उन्होंने एक कुटी की स्थापना की थी। इस जनपद के अहिल्यापुर नामक स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के शाप से जब पत्थर रूप में हो गयी थी तो वन गमन के समय भगवान श्रीराम के चरण स्पर्श से उसने पुनः सजीव होकर स्त्री रूप धारण कर लिया था। इस जनपद का वर्तमान 'भागलपुर' भागवपुर का विकृत रूप है। यह भार्गव या भृगु शब्द से बना है। यहाँ पर भृगु तथा उनके शिष्यों के आश्रम के होने की बात कही जाती है। इस बात की सत्यता इससे भी जान पड़ती है कि इस क्षेत्र के दक्षिण में सरयूपार बलिया जनपद में महर्षि भृगु का प्राधान्य क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर अनेकानेक ऋषियों की परिपूरित धर्मारण्य क्षेत्र पाया जाता है।

मार्टिन मॉन्ट गोमरी ने अपनी पुस्तक 'इस्टर्न इण्डिया' में लिखा है कि प्रारम्भ में भागलपुर और खैराडीह दोनों एक ही नगर थे जो संयुक्त रूप से भार्गवपुर कहलाते थे तथा बाद में अपभ्रंश होकर भागलपुर हो गये। कहा जाता है कि यह भृगुवशीयो का बसाया हुआ नगर था। जन श्रुतको के अनुसार यहाँ भृगुवशीय ऋषि यमदग्नि का आश्रम था। 'मार्टिन' ने यह भी लिखा है कि संयुक्त नगर भार्गवपुर घाघरा के एक ही ओर दक्षिण में स्थित था। कालान्तर में इस नदी की धारा में परिवर्तन हुआ और यहाँ के लोगो ने नदी के उस पार उत्तर की ओर जाकर

भागलपुर नामक नया नगर बसा लिया।

भागलपुर के प्राचीन नगर के पास पीपल के वृक्ष बहुत मात्रा में विद्यमान थे। जो सरयू की कटान के कारण धराशायी हो गये। पीपल का वृक्ष *बोधिवृक्ष* के रूप में बौद्ध संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। पीपल वृक्षों की बहुलता से यह इंगित होता है कि यह स्थान कभी बौद्ध केन्द्र के रूप में विकसित रहा होगा। *प्रो सिन्हा* को *खैराडीह* की खुदाई में जो कमरे तथा अन्य सामग्रियाँ मिली हैं। उनसे स्पष्ट संकेत मिलता है कि यहाँ कभी बौद्ध विहार विद्यमान थे। बौद्धकाल के बाद इस क्षेत्र पर *भर* राजाओं का शासन रहा जो भवन निर्माण कला में बड़ी रुचि लेते थे और इसके जानकार भी थे। इस क्षेत्र के *इन्दौली* में भरो की गढ़ी थी जहाँ खुदाई करने पर उस काल की ईंटे आदि मिलती हैं।

इस जनपद में भगवान् शिव की अराधना के प्रसिद्ध केन्द्र *रुद्रनाथ रुद्रपुर* तथा *दीर्घेश्वर नाथ* स्थित हैं जिनसे *अश्वत्थामा* का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। *दुग्धेश्वर नाथ महेन्द्र नाथ शैवनाथ सोमनाथ* आदि के प्राचीन स्थल आज भी हैं। *रुद्रपुर* में सहनकोट के पास स्थित *दुग्धेश्वर नाथ* का मंदिर एकादश रुद्रों की कोटि में आता है। कहा जाता है कि कामधेनु ने जब इन्द्र के वज्र के लिए महर्षि दधीचि की हड्डी के लिए उनका मांस चाटा था तो स्वतः स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उसी से इस शिवलिंग का उदय हुआ तथा इसका नाम *दुग्धेश्वर नाथ* पड़ा।

मझौली राज के दक्षिण में एक मंदिर है जिसका नाम *दीर्घेश्वर नाथ* है। कहा जाता है कि *अश्वत्थामा* ने दीर्घ जीवन के लिए यही तपस्या की थी इसलिए इस मंदिर का नाम दीर्घेश्वर नाथ है। सलेमपुर के पास *सोहनाग परशुराम धाम* के रूप में जाना जाता है कहा जाता है कि परशुराम ने यहाँ साधना की थी। देवरिया जनपद के भू-भाग को महान सन्तो ने भी अपनी साधना हेतु चुना था क्योंकि एक तो घने अरण्य दूसरे भगवती सरयू का पवित्र किनारा तीसरे पर्वतराज हिमालय की सन्निकटता ने इस क्षेत्र में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि यहाँ आकर चंचल मन स्वतः शान्त हो जाता था। इस जनपद के लार कस्बे में स्थित *मठलार आश्रम* एक सिद्धपीठ है।

2 अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) का ऐतिहासिक महत्व

जब दुनियाँ की अधिकांश जातियाँ निर्वस्त्र होकर घूम-घूम कर भोजन तलाश रही थी राजनैतिक चिंतन का स्वरूप शैशवावस्था में था उस समय देवरिया जनपद की उर्वरक मिट्टी में स्वतंत्र *मल्ल गणराज्य* का अस्तित्व था।

मल्ल गणराज्य को महाभारत में '*मल्लराष्ट्र*' तथा जातक कथाओं में '*मल्लरक्ष*' कहा गया है। यह राज्य दो राज्यों में विभक्त था। इन्हीं दोनों राज्यों का जिक्र महाभारत में *मल्ल एवं दक्षिण*

मल्ल के नाम से किया गया है। बौद्ध धर्म का इतिहास देवरिया जनपद के कण-कण में समाया हुआ है।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आते आते राजनैतिक चेतना बलवती होने लगी थी और उनके छोटे-छोटे कबीले बड़े-बड़े राज्यों में समाहित होने लगे थे। इस तरह धीरे-धीरे सोलह महाजनपदों का युग प्रारम्भ हुआ उस समय देवरिया जनपद का भू-भाग कोशल जनपद का एक अंग था जहाँ के मल्ल वीरों को कोशल राज्य में विशेष स्थान प्राप्त था। वे लोग उस समय सेना में भर्ती होने के लिए देवरिया में राप्ती नदी द्वारा नावों से कोशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती जाया करते थे। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने भी इस तथ्य को अपनी पुस्तक 'बोल्गा से गंगा' में बन्धुत्व मल्ल निकन्ध में उल्लेख किया है। कालान्तर में जब गणराज्यों का परिवर्तन हुआ तो महावीर मल्ल अपना अलग गणराज्य कायम करके उसका विस्तार गोरखपुर से देवरिया तक किये। महापद्मनन्द के युग में यह जनपद नन्द राजाओं के अधीन था। कालान्तर में जब मगध पर ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में मौर्य राजाओं का वर्चस्व हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य राजा बना तो देवरिया का भू-भाग मौर्य राजाओं के अधीन हो गया।

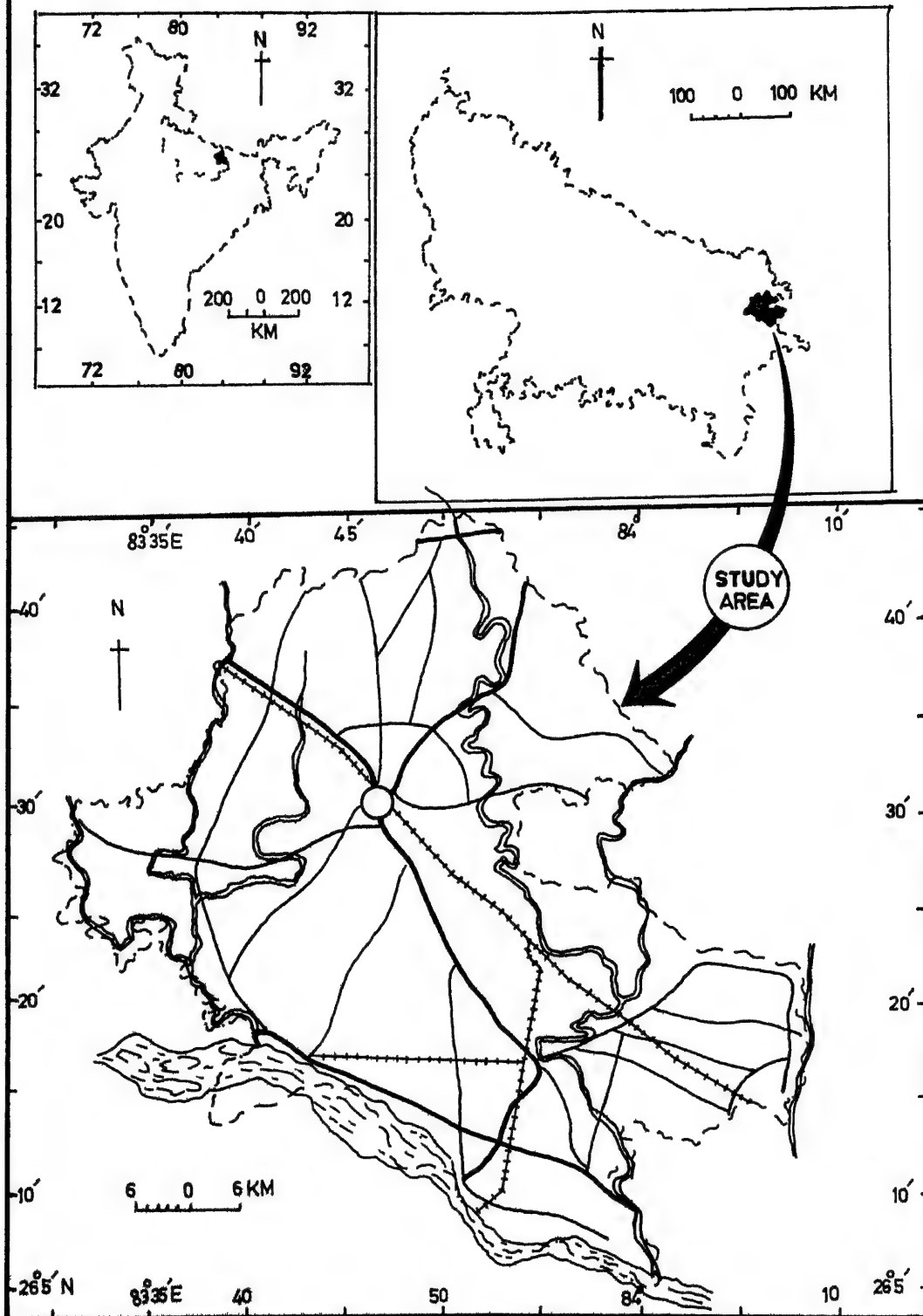
देवरिया जनपद के भू-भाग को महान सन्तों ने भी अपनी साधना हेतु चुना था। सिद्ध सन्त अनन्त महाप्रभु का आश्रम इसी जनपद के बरहज बाजार में स्थित है। महान सत देवरहा बाबा का आश्रम भी इसी जनपद के सरयू नदी के तट पर मड़ल कस्बे के निकट स्थित है। राष्ट्रीय स्तर के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा राघवदास का भी पवित्र आश्रम बरहज बाजार में है। इस प्रकार उपर्युक्त विकिरणों से स्पष्ट है कि देवरिया जनपद आज से ही नहीं अपितु अतीत काल से ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत में अत्यन्त गौरवशाली रहा है। ससार में चाहे शील क्षमा एवं करुणा का उपदेश देने वाले देवदूतों की परम्परा रही हो या सत्य अहिंसा जैसे सतत मानवीय मूल्यों के उपदेशकों की बात रही हो अथवा अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य जैसे सामाजिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार रहा हो महान सन्त परम्परा एवं गरिमामयी ऐतिहासिक धरोहरों हेतु यह पावन धरती सदैव से ही नितान्त वैभवशाली रही है।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

किसी भी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों के उद्भव विकास तथा उस क्षेत्र के विकास में भौगोलिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ भौतिक कारक सेवाकेन्द्रों के उद्भव हेतु उपयुक्त स्थल एवं परिस्थिति का निर्माण करते हैं वही सामाजिक और आर्थिक कारक उसके उद्भव एवं विकास को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का उद्भव एवं विकास भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का प्रतिफल होता है।

अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) में सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास के निरूपण हेतु

FIG 2.1 LOCATION MAP OF STUDY AREA (DEORIA DIST)



भौगोलिक कारको का ज्ञान अपेक्षित है। अतः जनपद के भौगोलिक स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत है।

2.1 भौतिक पृष्ठभूमि

प्रकृति द्वारा नैसर्गिक रूप में प्रदत्त समस्त अवयवों (वायु, जल, मृदा, वनस्पति आदि) जो किसी भी सेवाकेन्द्र के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं भौतिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इनका विवेचन निम्नवत् है—

[1] अवस्थिति

अध्ययन क्षेत्र देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी छोर पर अवस्थित है। जहाँ उत्तर में इसकी सीमा कुशीनगर जनपद से मिलती है पश्चिम में गोरखपुर जनपद अवस्थित है तथा दक्षिण में मऊ एवं बलिया जनपद अवस्थित हैं वही पूर्व में यह बिहार राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है।

स्थिति एवं विस्तार

देवरिया जनपद $26^{\circ} 6'$ और $27^{\circ} 18'$ उत्तरी आक्षांशों एवं $83^{\circ} 29'$ से $84^{\circ} 26'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य वर्तमान में 2389 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 1 प्रतिशत (0.99 प्रतिशत) है। वर्तमान देवरिया जनपद सन् 1801 से 1946 ई तक गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत सम्मिलित था। 1946 में गोरखपुर जनपद से हाटा, पडरौना, देवरिया और सलेमपुर तहसील को अलग कर देवरिया नामक एक नये जनपद की निर्माण किया गया। पुनः 1994 में देवरिया के लगभग 54.6 प्रतिशत क्षेत्रफल को इससे अलग कर कुशीनगर नामक नये जनपद का निर्माण किया गया³। इसी के बाद इसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है।

प्रशासनिक दृष्टि से देवरिया जनपद वर्तमान में पाँच तहसील एवं पन्द्रह विकासखण्डों में विभक्त है।⁴ पाँचों तहसील हैं— देवरिया, सदर, रुद्रपुर, सलेमपुर, बरहज, भाटपाररानी। दो नगर पालिका परिषद देवरिया तथा गौराबरहज में हैं।

[2] उच्चावच

अध्ययन क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल मैदान है। जिसकी सागर तल से औसत ऊँचाई 72 मीटर है। क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उच्चावच के आधार पर इसे भाट प्रदेश, बागर प्रदेश तथा खादर प्रदेश में बाँटा जा सकता है। इसमें खादर क्षेत्र का धरातल बागर प्रदेश से नीचा है तथा बागर प्रदेश का धरातल भाट प्रदेश से नीचा है। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में इस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण घाघरा एवं राप्ती नदियों द्वारा होता है।⁵ इस मैदानी क्षेत्र की औसत ऊँचाई उत्तर-पश्चिम में बढ़कर 74 मीटर तक हो जाती है। जलोढ़ संरचना के इस समतल क्षेत्र के निर्माण में गण्डक, घाघरा एवं

राप्ती नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके प्रवाह मार्गों के परिवर्तन के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में अनेक नदी छाड़न बड़ी झीले तथा छोटे-छोटे जलाशय निर्मित हो गये हैं। इसके कारण मैदान में कुछ हद तक व्यतिक्रम आ गया है परन्तु अपरदन एवं निक्षेपण क्रियाओं की सक्रियता से यह व्यतिक्रम क्रमशः कम होता गया है।

[3] भू-आकृति प्रदेश

उच्चावच ढाल प्रवणता, मृदा प्रकार जल प्रवाह आदि के आधार पर इस मैदान को तीन भूआकृति प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जो निम्नवत हैं ०

(क) उत्तरी-पूर्वी भाट क्षेत्र

(ख) बांगर क्षेत्र

(ग) कछारी क्षेत्र

(क) उत्तरी भाट क्षेत्र

यह क्षेत्र इस मैदान में कुशीनगर जनपद के पडरौना तहसील के तराई भाग से लगा हुआ है। इसमें भाट मृदा की प्रधानता है जो इस मैदानी भाग में नवीनतम जमाव के फलस्वरूप निर्मित हुई है। इस जमाव का विकास गडक नदी एवं खनुआ नाला द्वारा हुआ है। आज भी इस क्षेत्र के ऊपरी भाग में सीपे, घोघे आदि जलीय जीवों के अवशेष विशेष रूप से मिलते हैं जो नये जमावों के घोटक हैं। इसी कारण यह एक चूना प्रधान क्षेत्र बन गया है [सीप घोघा आदि जलीय जीवों के बाह्य आवरण में कैल्शियम की प्रधानता होती है जो चूना (कैल्शियम कार्बोनेट— $CaCO_3$) का एक प्रधान घटक है]। जलोढ़ संरचना के कारण इस क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर काफी ऊँचा है परन्तु इसमें पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर गहराई बढ़ती जाती है। भूमिगत जल स्तर के ऊँचा होने से इस क्षेत्र में नमी सदा बनी रहती है। विकासखण्ड पथरदेवा पूर्णतः तथा देसही देवरिया रामपुर कारखाना एवं देवरिया सदर अंशतः इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। गन्ना एवं चावल की कृषि के लिए यह भाट क्षेत्र विशेष उपयुक्त है।

(ख) बांगर क्षेत्र

प्राचीनतम जलोढ़ द्वारा निर्मित यह क्षेत्र जनपद के पश्चिमी तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अंतर्गत देवरिया तहसील का कुछ पश्चिमी भाग तथा सलेमपुर तहसील का अधिकांश शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र पूरे जनपद का सर्वाधिक उर्वर एवं उपजाऊ भू-भाग है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। इसे दो उपविभागों में बाँटा जा सकता है—

(1) उत्तरी बांगर क्षेत्र

यह बांगर क्षेत्र के उत्तर से उत्तर-पूर्व में विस्तृत है जो बहुत ही उपजाऊ भू-भाग है। यह क्षेत्र देवरिया तहसील तक ही सीमित है, जो इसके 29.94 प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है। इसके

अतर्गत देवरिया तहसील के विकासखण्ड *देसही देवरिया रामपुर कारखाना* का अधिकांश क्षेत्र *गौरीबाजार* एवं *बैतालपुर* का कुछ उत्तरी भाग तथा विकासखण्ड *देवरिया सदर* का उत्तरी भाग शामिल है। इन क्षेत्रों में उत्तरी बागर क्षेत्र एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है।

(2) दक्षिणी बागर क्षेत्र

इसका विस्तार *देवरिया-गोरखपुर रेललाइन* के दक्षिण में देवरिया गौरीबाजार बैतालपुर विकासखण्डों के दक्षिणी भाग एवं रुद्रपुर के उत्तरी भाग में है। बाढ़-पकोप से वंचित यह क्षेत्र बलुई दोमट मिट्टी का क्षेत्र है जिसमें गेहूँ की प्रधानता है। यह क्षेत्र *मझनान व कर्नाला* के प्रवाह क्षेत्र के अतर्गत आता है जो ग्रीष्मकाल में सूख जाते हैं। इस भाग में सिंचाई साधनों का अभाव है क्योंकि नहरीक्षेत्र का विस्तार रेललाइन के उत्तर ही हुआ है।

(ग) कछारी क्षेत्र

जनपद का सबसे दक्षिणी भाग जो *राप्ती* और *घाघरा* नदियों के सामानान्तर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है इसे कछारी क्षेत्र कहते हैं। यह सामान्यतः निम्न भू-भाग है जहाँ *राप्ती* एवं *घाघरा* नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ प्रतिवर्ष बाढ़ लाती हैं। इससे इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष नवीन कॉप मिट्टी का फैलाव हो जाता है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है फलतः इस समस्त भाग पर कृषि की जाती है। जहाँ *राप्ती* के किनारे कछारी पट्टी सकीर्ण है वही *घाघरा* के किनारे यह प्राकृतिक तटबन्धों द्वारा अवरोधित है। पर इन तटबन्धों को तोड़कर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में फैल जाता है। खरीफ के समय बाढ़ग्रस्त हो जाने से इस क्षेत्र में कृषि नहीं हो पाती होती भी है तो प्रायः नष्ट हो जाती है। परन्तु रबी की फसल यहाँ उच्च उत्पादकता के साथ कम लागत पर उगायी जाती है।

[4] अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप

किसी भी भू-भाग के प्रतिरूप का सीधा सम्बन्ध उसके धरातल के स्वरूप एवं संरचना से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि उस पर धरातल की ऊपरी सतह के व्यतिक्रमों और अधोभौमिक तत्वों की विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में *प्रो. स्टाम्प* का यह कथन बहुत ही प्रामाणिक और अनुकूल प्रतीत होता है कि *धरातल की संरचना और उसके स्वरूप में अत्यन्त निकट का संबंध होता है और वे धरातल के अपवाह को पूर्णतः प्रभावित करते हैं।*

वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप के विकास में मृदा संरचना का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। क्षेत्र की मृदा प्रधानतः दोमट या बलुई दोमट है, जो जल में शीघ्र घुलनशील है। अतः इसका अपरदन सरलता से और शीघ्र होता रहता है। इसी कारण जितनी सरलता से अपवाह मार्ग बनते हैं, उतनी ही शीघ्रता और सरलता से अवरोध मिलने पर परिवर्तित भी होते रहते हैं। *राप्ती* एवं *छोटी गण्डक* नदियों के मार्ग परिवर्तन का यही प्रमुख कारण है। इसके

DRAINAGE PATTERN
OF DEORIA DISTRICT

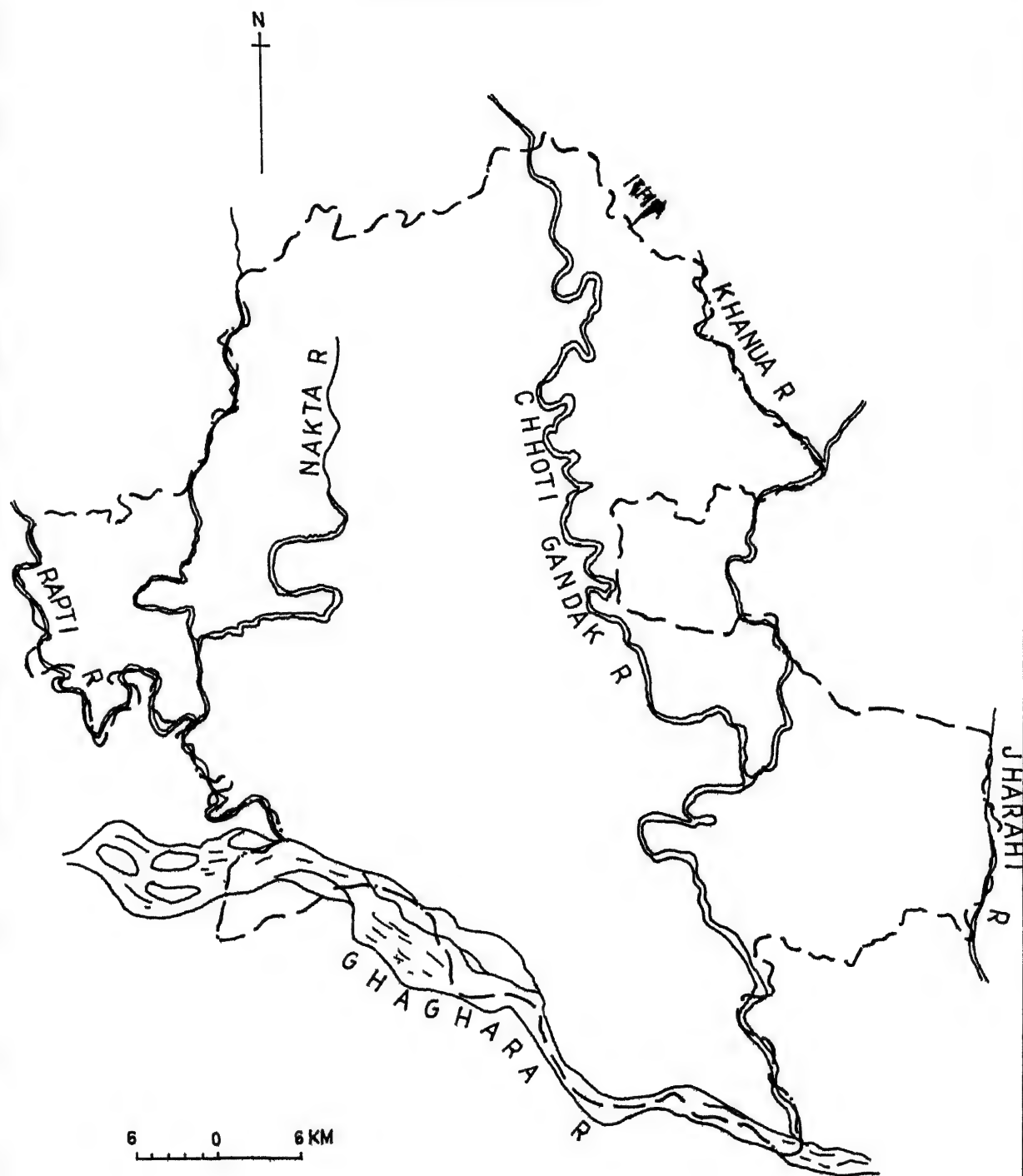


FIG 2 2

विपरीत चिकनी मिट्टी और भाट मिट्टी चिपचिपी एव कम घुलनशील होती है जिससे अपवाह के मार्ग परिवर्तन में अवरोध उत्पन्न होता है परन्तु जहाँ भाट मिट्टी के साथ बालू का अंश अधिक होता है वहाँ नदियों द्वारा अपरदन एव मार्ग परिवर्तन अधिक होता है।

नदियों में जल की बहुलता के आधार पर इस क्षेत्र के अपवाह को मौसमी और स्थायी दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। क्षेत्र का सम्पूर्ण जल छोटी गण्डक नदी प्रणाली या राप्ती घाघरा नदी प्रणाली में सन्निहित है। इनमें शुष्क मौसम में प्राकृतिक अपवाह केवल बड़ी नदियों में ही दिखाई देता है। जबकि छोटी नदियाँ प्रायः सूखी रहती हैं परन्तु वर्षा के दिनों में छोटी नदियाँ भी अपने उफान पर आ जाती हैं।

शोध क्षेत्र का सामान्य अपवाह प्रतिरूप उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में पाया जाता है जो क्षेत्र के सामान्य ढाल का ही अनुसरण करता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण अपवाह तंत्र का जल अतः घाघरा में मिल जाता है क्योंकि सभी नदियाँ इसी में आकर मिल जाती हैं। क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले अपवाह को निम्न तीन तन्त्रों में विभाजित किया जा सकता है—

क— राप्ती नदी तंत्र पश्चिम में

ख— छोटी गण्डक नदी तंत्र मध्य में

ग— घाघरा नदी तंत्र दक्षिण-पूर्व में

(क) राप्ती नदी तंत्र

1 राप्ती नदी

राप्ती नदी देवरिया जनपद के दक्षिणी-पश्चिमी सीमान्त पर प्रवाहित होती है। इसका प्रारम्भिक नाम 'इरावती' था। जो कालान्तर में क्रमशः 'राप्ती' एव पुनः 'राप्ती' हो गया। नदी का उद्गम शिवालिक पर्वत में होता है और यह बहराइच, गोण्डा, बस्ती एव गोरखपुर जनपदों में बहती हुई 'तिघरा खैरवा' के पास देवरिया जनपद को स्पर्श करती है। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर यह 'परसियाकान्त' के पास घाघरा नदी से मिल जाती है।

2 गउरा (Gaura) नदी

यह राप्ती की सहायक नदी है जिसका उद्गम गोरखपुर जनपद के 'कुडाघाट ताल' से हुआ है। राप्ती के सामानान्तर ही यह दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर समोहर के निकट राप्ती में मिल जाती है। निचले भागों में इसे 'कटना' नाम से जाना जाता है।

3 मझनान नदी

यह गउरा (कटना) की ही एक सहायक नदी है जो मसूरगज (हाटा तहसील जनपद कुशीनगर) से उत्पन्न होती है तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर गोरखपुर और देवरिया जनपद की सीमा बनाते हुए खानदौली (Khandauli) के पास देवरिया में प्रविष्ट होती है। दक्षिण में और

प्रवाहित होने पर इसमें बॉयी ओर से *बरहरी नदी* मिलती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक *करना (Karna) नदी* है। जो रुद्रपुर में *सरया* के पास मिलती है। ये संयुक्त नदी दक्षिण में बहकर आगे *राप्ती* में मिल जाती है।

4 करना नदी

इसे अध्ययन क्षेत्र में नाला के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह नाला '*बालकुआँ*' (विकासखण्ड गौरीबाजार जनपद देवरिया) के पास उद्भूत होकर देवरिया नगर के उत्तर-पश्चिम में प्रवाहित होकर रुद्रपुर के पास *मझना नाले* में मिल जाता है। अध्ययन क्षेत्र में इसके प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पूर्णतः वर्षाकालीन नाला है। जो ग्रीष्मकाल में सूख जाता है।

5 नकटा नाला (Nakta)

यह *करना नाला* की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। जो देवरिया तहसील में *कटउरा (Katura)* से उत्पन्न होकर दक्षिण दिशा में बहते हुए *टिवार (Tewar)* के पास *करना* में मिल जाता है। यह भी प्रमुखतः बरसाती नाला है।

(ख) छोटी गण्डक नदी तंत्र

1 छोटी गण्डक नदी

यह नेपाल के '*बाघवन*' क्षेत्र से उत्पन्न होकर '*पूरनहवा नाला*' के रूप में *बड़ी गण्डक* के एक पुराने मार्ग का अनुसरण कर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुयी भारत में '*शीतलपुर गाँव*' में नेपाल की सीमा पार करती है यहाँ से लगभग 16 किमी प्रवाहित होने पर यह दो शाखाओं (*चन्दन नाला* एवं *छोटी गण्डक*) में विभक्त हो जाती है। *चन्दन नाला* उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। जबकि *छोटी गण्डक* दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत यह नदी *हेतिमपुर ग्राम* के पास प्रवेश करती है और अध्ययन क्षेत्र के लगभग मध्य से प्रवाहित होती हुई दक्षिण-दक्षिण पूर्व में घाघरा में मिल जाती है।

2 ऊँची नदी

यह *छोटी गण्डक* की सहायक नदी है जो देसही देवरिया से उत्पन्न होकर देवरिया तहसील में दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर *बैकुण्ठपुर* के पास *छोटी गण्डक* में मिल जाती है।

3 कोइलर नदी (Koilar)

यह भी *छोटी गण्डक* की ही सहायक है जो '*ताल*' से उत्पन्न होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती हुए *बरसीपार गाँव* के पास *छोटी गण्डक* में मिल जाती है।

4 खनुआ नदी

छोटी गण्डक की यह सहायक नदी कुशीनगर जनपद में हाटा तहसील में स्थित '*सिरसिया*' में उत्पन्न होती है। *डुमारी* एवं *सोनबरसा* गाँवों के निकट यह अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करती है तथा

देवरिया एव कुशीनगर जनपद की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर बहती हुई आगे जाकर उत्तर प्रदेश (देवरिया) एव बिहार (सीवान) की भी सीमा निर्धारित करती है। भाटपार रानी से 4 किमी उत्तर-पश्चिम में यह छोटी गण्डक से मिल जाती है।

(ग) घाघरा नदी तंत्र

1 घाघरा नदी

घाघरा नदी अध्ययन क्षेत्र में नहीं प्रवाहित होती है पर इसकी कुछ सहायक नदियाँ अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग में बहती हैं। घाघरा नदी अध्ययन क्षेत्र के सलेमपुर तहसील को दक्षिण-पूर्व में स्पर्शकरती है और बलिया के साथ देवरिया की सीमा बनाती है। घाघरा का उद्गम हिमालय में मापचाचुगो ग्लेशियर से होती है।

2 झरही नदी

यह कुशीनगर जनपद के पडरौना तहसील के बोंसगाँव नामक गाँव के पास से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। प्रारम्भ में यह गण्डक नदीतंत्र का भाग थी पर वर्तमान में घाघरा की सहायक है। यह अध्ययन क्षेत्र में सलेमपुर तहसील में प्रवेश करती है तथा दक्षिण दिशा में बहती हुई देवरिया और सीवान (बिहार) की सीमा निर्धारित करती है।

[5] भौमिकीय संरचना

भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र सरयूपार मैदान का ही एक भाग है जिसे मध्यवर्ती गंगा मैदान के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। मैदान का निर्माण एक बड़े अवतलित गर्त में मलवे के गहरे एव विस्तृत निक्षेप के द्वारा हुआ है। जिसका जमाव प्लीस्टोसीन काल से वर्तमान समय तक हो रहा है।

इस प्रकार भूगर्भिक कालक्रम के अनुसार इस मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग के चतुर्थ कल्प से लेकर आधुनिक काल तक माना जाता है। जो 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10 हजार वर्ष पूर्व तक मानी जा सकती है। इस मैदान की संरचना एवं निर्माण काल के विवेचन में पर्याप्त अन्तरो के साथ ही साथ इसकी गहराई के सम्बन्ध में भी भूगोलवेत्ताओं में मतभेद नहीं है।⁹

मैदान के विभिन्न भागों में गहराई के अनुसार जलोढ़ की संरचना में बालू कणों सिल्ट, क्ले और ककड़ों का विभिन्न अनुपात पाया जाता है। संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है— (1) पुरानी जलोढ़— इसे बांगर (Bangar) कहते हैं। जो अपेक्षकृत काले रंग की मृदा है। जिसमें ककड़ीट और चूने की प्रचुरता पायी जाती है, जिसे 'ककड़' कहते हैं। ये बाढ़ क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाया जाता है, जिसका निक्षेप मध्य से ऊपरी प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है। (2) नवीन जलोढ़— इसे स्थानीय रूप में कछार (Kachhar) या खादर (Khadar) कहते हैं। यह हल्के भूरे रंग की होती है तथा क्लियम का इसमें अभाव होता है। इसका निक्षेप काल होलोसीन काल

अथवा ऊपरी प्लिस्टोसीन से वर्तमान समय तक है। इस जनपद में खनिजों का प्रायः अभाव है पर जो खनिज प्राप्य हैं। वे निम्नवत् हैं—

साल्टपीटर (Saltpetre) — यह प्रमुख रूप से सलेमपुर तहसील में गौरा बरहज के समीप प्राप्य है।

रेह (Reh) — यह नमकीन पदार्थ है जो सतह के ऊपर पाया जाता है जिसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। अध्ययन क्षेत्र में इसकी प्राप्ति सलेमपुर तहसील के उत्तरी भाग में होती है।

बालू (Sand) — इसकी प्राप्ति देवरिया-कसया रोड पर छोटी गण्डक कटक के पूर्व में सिरसीघाट के निकट और सलेमपुर तहसील में बड़वारघाट से होती है।

क्ले (Clay) — इसकी प्राप्ति जनपद में लगभग हर जगह से होती है। इसका उपयोग ईंट बनाने, खिलौने बनाने, बर्तन बनाने आदि में होता है।

[6] भूकम्पीय स्थिति

अध्ययन क्षेत्र भारत के सामान्य क्षति वाले भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यद्यपि अभी तक कोई बड़ा भूकम्प इस क्षेत्र में नहीं आया है। पर हल्के से सामान्य भूकम्प आ चुके हैं जिससे कुछ क्षति हुई है। सबसे पहले 4 जनवरी, 1994 में उसके बाद 1934 में पुनः 1988 में हल्के भूकम्प आ चुके हैं। चूँकि अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति 'ग्रेट हिमालयन बाउण्ड्री फाल्ट' से दूर नहीं है अतः यहाँ हल्के भूकम्प आते रहते हैं। इण्डियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्मित भारत के भूकम्प मानचित्र में अध्ययन क्षेत्र को जोन IV के अन्तर्गत रखा गया है जहाँ भूकम्प तीव्रता की संभावना VIII तक (परिष्कृत मरकली इन्टेन्सिटी स्केल 1931) हो सकती है। मरकली स्केल के अन्तर्गत तीव्रता का विस्तार I से XII तक है जिसमें I का अर्थ है *महसूस न होने वाला कम्पन* तथा XII का अर्थ है— *सम्पूर्ण विनाश*।¹⁰

[7] जलवायु

भूमि उपयोग को प्रभावित करने तथा सेवाकेन्द्र के विकास को प्रेरित करने वाले भौतिक कारकों में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मध्य गंगा मैदान में स्थित अध्ययन क्षेत्र की जलवायु आर्द्र उष्ण मानसूनी है। इसके पश्चिम में शुष्क तर जलवायु, पूर्व में आर्द्रतर जलवायु, उत्तर में तराई मैदान की उमस भरी उष्णार्द्र जलवायु एवं दक्षिण में शुष्कार्द्र जलवायु पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में जलवायु के विभिन्न तत्वों यथा तापमान, वायुदाब, वर्षा आर्द्रता का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।¹¹

DEORIA DISTRICT CLIMATIC CONDITIONS- 2001

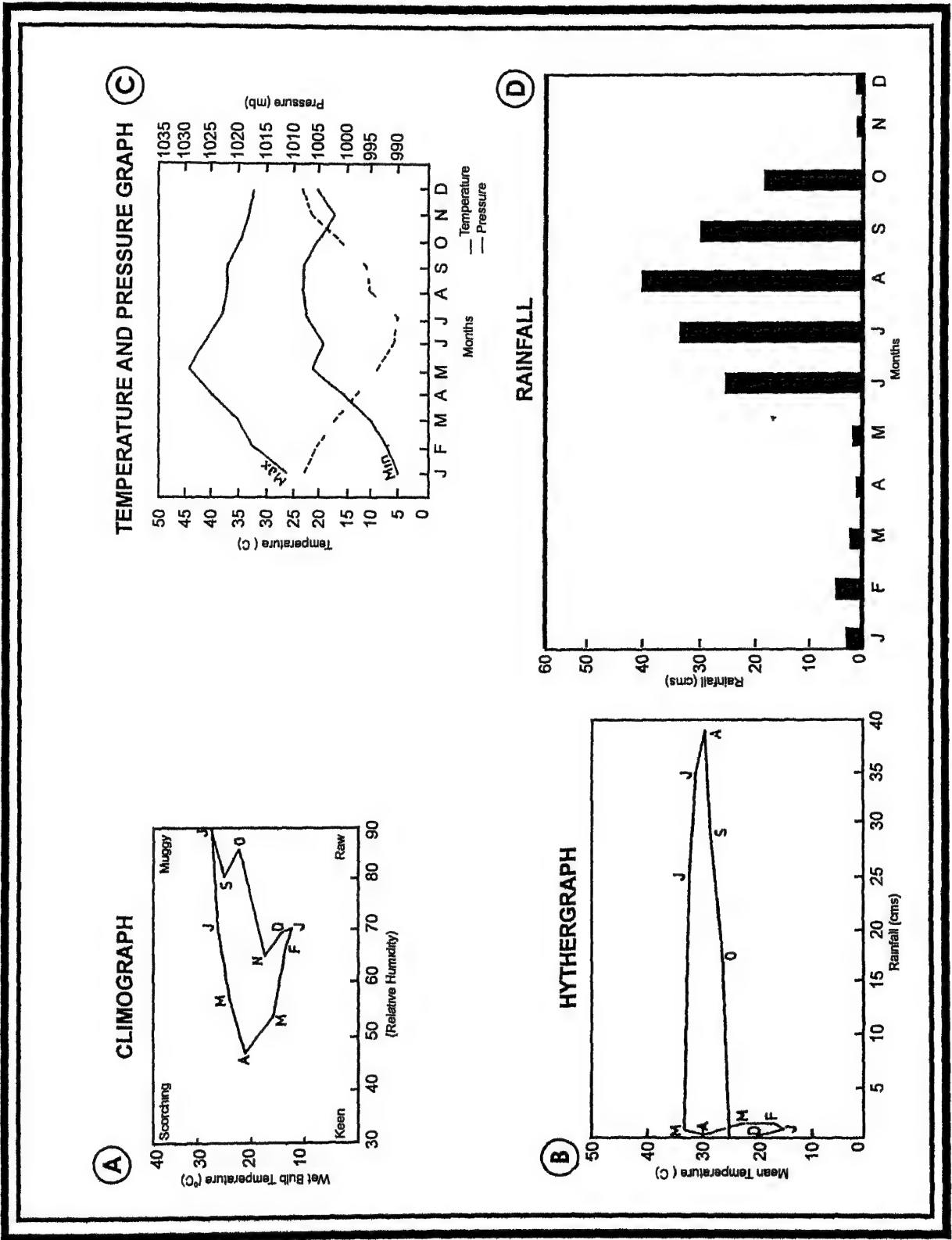


Fig 2 3

(क) तापमान

तापमान किसी भी क्षेत्र की जलवायु सम्बन्धी विशेषताओं को निर्धारित करने में विशेष महत्व रखता है। उपोष्ण कटिबन्ध में स्थित होने के कारण क्षेत्र में मई में अधिकतम औसत तापमान 44.0° से न्यूनतम औसत तापमान जनवरी में 15.2° से रहता है। जनवरी में न्यूनतम तापमान 4.8° से तक हो जाता है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 26.4° से एव औसत वार्षिक तापान्तर लगभग 11.8° से है। सर्वाधिक औसत दैनिक तापान्तर दिसम्बर माह में पाया जाता है जो 17.3° से के लगभग होता है।

(ख) वायुदाब

वायुदाब तापक्रम से निर्धारित होता है। तापक्रम और वायुदाब में सामान्यतः उलटा सम्बन्ध पाया जाता है। क्षेत्र में बसंत विषुव (Equinox) (21 मार्च) के पश्चात तापक्रम में वृद्धि के परिणामस्वरूप वायुदाब घटना प्रारम्भ हो जाता है और क्रमशः मई में 994.5 मिलीबार जून-जुलाई में औसतन 990.9 मिलीबार एव 990.7 मिलीबार हो जाता है। इस प्रकार जुलाई में वायुदाब न्यूनतम (990.7 मि.बार) होता है। पुनः शरद विषुव (21 सितम्बर) के पश्चात तापक्रम में निरन्तर ह्रास के कारण वायुदाब बढ़ते-बढ़ते नवम्बर में 1002.3 मिलीबार, दिसम्बर में 1008.2 मिलीबार तथा जनवरी में 1008.4 मिलीबार हो जाता है।

(ग) वायुवेग

अध्ययन क्षेत्र में औसत वायुगति 4.47 किमी प्रति घण्टा है। वायुगति नवम्बर माह में न्यूनतम (2.0 किमी/घण्टा) होती है तथा मई माह में अधिकतम (7.1 किमी/घण्टा) होती है तथा मई माह में अधिकतम (7.1 किमी/घण्टा) हो जाती है। स्पष्ट है वायु वेग पर वायुदाब का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में औसत वायुवेग 2.4 किमी/घण्टा होती है तथा ग्रीष्म ऋतु में औसत वायुगति 6.6 किमी/घण्टा रहती है। कभी-कभी यहाँ पर झझावातों के आने पर वायु वेग अत्यधिक बढ़कर 50 किमी प्रति घण्टा तक पहुँच जाता है।

(घ) वायु दिशा

हिमालय के निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में लगभग वर्ष के 45 प्रतिशत दिनों में हवाएँ शांत रहती हैं 55 प्रतिशत दिनों में हवाओं की दिशा अधिकांशतः पूरुवा एव कुछ पछुआ होती है। वर्ष में पूरुवा हवाओं की दिन संख्या 80 दिन से कम नहीं होता है इनमें अधिकांश दिन जुलाई महीने में होता है। वर्ष में पश्चिम से प्रवाहित होने वाली हवा के दिनों की संख्या 47 है जिसमें ये अप्रैल माह में सर्वाधिक दिन प्रवाहित होती हैं।

विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि शीत काल (अक्टूबर से फरवरी) में तापमान कम रहने से हवाएँ प्रायः शान्त रहती हैं। किन्तु ग्रीष्म काल (अप्रैल से जुलाई) में तापमान बढ़ने से हवाएँ अधिक सक्रिय होने लगती हैं।

DEORIA DISTRICT WEATHER CONDITIONS- 2001

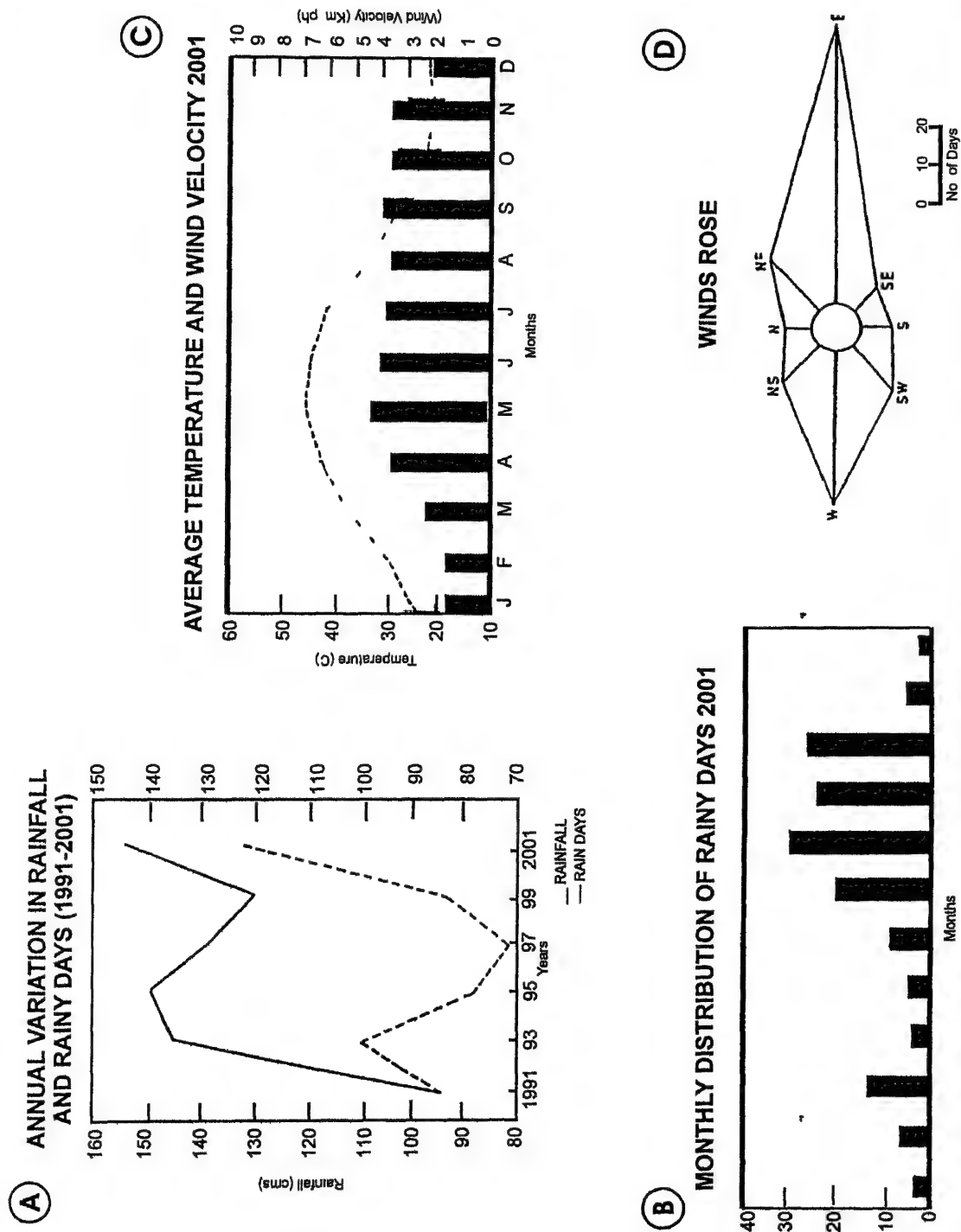


Fig 2 4

(ड) वर्षा

अध्ययन क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 153 सेमी है एवं वर्ष में वर्षा के दिनों की कुल संख्या लगभग 122 है। वार्षिक वर्षा का लगभग 85.90 प्रतिशत भाग जून से अक्टूबर के मध्य ग्रीष्म कालीन मानसून से प्राप्त होता है। 7 प्रतिशत वर्षा शीतकालीन चक्रवातों से नवम्बर से फरवरी माह के मध्य तथा शेष 3 प्रतिशत वर्षा मार्च से मई माह के मध्य मानसून पूर्व होती है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वर्षा की मात्रा (401.8 मिमी) एवं वर्षा के दिनों की अधिकतम संख्या (26 दिन) अगस्त माह में पायी जाती है। दिसम्बर में वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों की संख्या न्यूनतम (21 मिमी एवं 2 दिन) होती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के मासिक वितरण एवं वर्षा के दिनों की मासिक संख्या में बहुत अधिक विषमता है। यहाँ की वर्षा मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता से प्रभावित होती है।

(च) सापेक्षिक आर्द्रता

सापेक्षिक आर्द्रता का तापमान एवं वर्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सापेक्षिक आर्द्रता के मासिक वितरण में भिन्नता मिलती है। सबसे कम सापेक्षिक आर्द्रता गर्म शुष्क माह अप्रैल में (12 प्रतिशत) पाई जाती है जबकि अक्टूबर माह में सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक (130 प्रतिशत) तक हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक आर्द्रता का औसत 86.2 प्रतिशत एवं न्यूनतम वार्षिक आर्द्रता का औसत 50.46 प्रतिशत पाया जाता है। इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता का वार्षिक औसत 68.37 प्रतिशत है।

(छ) ऋतुएँ

क्षेत्र में तीन प्रमुख ऋतुएँ पायी जाती हैं। जो जलवायु सम्बन्धी विशेषताओं के आधार पर निश्चित की गयी हैं।

1 वर्षा ऋतु

वर्षा ऋतु का आगमन जून के मध्य से प्रारम्भ होता है और अक्टूबर तक रहता है। वर्षा ऋतु के आरम्भ होने पर ग्रीष्म ऋतु के शुष्क एवं तर वातावरण में सुहावनापन आ जाता है। घनघोर घन गर्जन, विद्युत चमक से युक्त मेघाच्छादन आदि वर्षा ऋतु की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वार्षिक वर्षा का लगभग 92 प्रतिशत भाग अध्ययन क्षेत्र में इसी ऋतु में प्राप्त होता है। अधिकतम वर्षा अगस्त माह में (40.18 सेमी) प्राप्त होती है। वर्षा की अधिकता के कारण क्षेत्र की नदियों एवं नालों के समीपस्थ निम्न भू-भाग जलाप्लावित हो जाते हैं।

2 शीत ऋतु

यह ऋतु नवम्बर से फरवरी तक चलती है। नवम्बर के पश्चात् शीतलता में वृद्धि होने लगती है तथा दैनिक तापान्तर भी बढ़ता है। जनवरी का महीना सबसे शीतल होता है जिसमें औसत न्यूनतम तापमान 7.9° से एवं औसत अधिकतम तापमान 20° से तक पाया जाता है। इस ऋतु

मे शीत लहर का प्रकोप होता रहता है तथा भूमध्य सागरीय अवदाबो से अल्प मात्रा मे वर्षा भी होती है। शीतलहर के समय तापमान 48° से तक नीचे उतर जाता है। इस ऋतु की प्रमुख विशेषताओ मे शात मौसम मेघरहित आकाश तथा कभी-कभी शीतलहर का प्रकोप प्रमुख है।

3 ग्रीष्म ऋतु

यह ऋतु मार्च से जून तक रहती है। फरवरी के पश्चात तापक्रम मे वृद्धि होती है। मई माह सर्वाधिक गर्म रहता है। मई एव जून के महीने मे उष्ण-शुष्क वायु चलने लगती है। धूल भरी ओंधी तथा यदा-कदा 'लू' भी इस ऋतु मे चला करती है। इन दिनो क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान लगभग 39.7° से एव औसत न्यूनतम तापमान 25.8° से रहता है। औसत तापान्तर 13.6 से रहता है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे हिमालय की तराई होने से एव नहरों के अधिक होने के कारण 'लू' का प्रभाव कम पडता है। फिर भी इस क्षेत्र मे इस ऋतु मे गर्मी के कारण दिन कष्टमय तथा राते अपेक्षाकृत कम कष्टकारी होती है।

[8] मृदा

मृदा आधारभूत ससाधन है। जनपद की मृदा जलोढ़ है। प्राचीन जलोढ़ बागर क्षेत्र मे तथा नूतन जलोढ़ खादर क्षेत्र मे पायी जाती है। सरचना एव उर्वरता के आधार पर क्षेत्र की मृदा को निम्न वर्गों मे वर्गीकृत किया जा सकता है—¹²

(1) बालूकणों की मात्रा के आधार पर

1 बलुई मिट्टी

यह नदियों की तलहटियों एव रेतीली भूमि मे पायी जाती है। इसमे बालू का अंश अधिक होता है।

2 दोमट मिट्टी

यह अपेक्षाकृत उच्च बागर क्षेत्रों मे मिलती है। इसमे बालू और मिट्टी का अंश बराबर होता है।

3 मटियार मिट्टी

यह निम्न भू-भागों मे पायी जाने वाली बालू रहित मृदा है। धान की कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।

(2) उर्वरता के आधार पर

1 गोयड़ मिट्टी

आबादी के नजदीक अधिक उर्वर मिट्टी।

2 मझार मिट्टी

गोयड़ मिट्टी क्षेत्र से दूर एव अपेक्षाकृत कम उर्वर मृदा।

3 पाली मिट्टी

गाँव से अधिक दूर एव कम उर्वर मृदा।

(3) उत्तरप्रदेश का *चकबन्दी विभाग* मृदा का एक नया वर्गीकरण प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार वर्गीकरण निम्नवत् है—

1 बागर मिट्टी

आर्द्रता एव कणों के आकार के आधार पर इसके निम्न उपविभाग हैं—

- (i) — **दोमट मिट्टी**— क्षेत्र के आंतरिक भागों में मिलती है।
- (ii) — **मटियार दोमट मिट्टी**— भूरे रंग की तथा धान की खेती के लिए अनुकूल एव जल धारण क्षमता अधिक।
- (iii) — **मटियार मिट्टी**— भूरी हल्की काली चिपचिपी मृदा जल धारण क्षमता अधिक।
- (iv) — **करैल मिट्टी**— चीका प्रधान अपेक्षाकृत नीची भूमि में पायी जाने वाली गाढ़े भूरे रंग की चिपकदार मिट्टी।
- (v) — **बलुई दोमट मिट्टी**— बाँगर मृदा के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत मृदा जल धारण क्षमता कम।

2 भाट मिट्टी

इस का क्षेत्र बागर मिट्टी क्षेत्र से ठीक उत्तर—पूर्व में स्थित है। यद्यपि यह भी जलोढ मृदा ही है पर इसमें चूना प्रधान पदार्थों की अधिकता है।¹³ इसके निम्न उपविभाग हैं—

- (i) — **चउर भाट मिट्टी**— अत्यधिक उर्वर मृदा,
- (ii) — **चेंवर भाट मिट्टी**— निम्न कोटि की दलदली मिट्टी,
- (iii) — **धूसी भाट मिट्टी**— हल्के लाल रंग की शुष्क मिट्टी जो छोटी *गण्डक नदी* के पूर्वी भाग में छोटे—छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है।

3 कछारी मिट्टी

इस का विस्तार अध्ययन क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी एव दक्षिण—पूर्वी भागों में है। यह मिट्टी मुख्यतः उर्वर बलुई मिट्टी है। कछारी नदियों का विस्तृत निक्षेपण *राप्ती* एव *छोटी गण्डक* नदियों द्वारा हुआ है।

क्षेत्र के कुछ भागों में क्षारीय अनुर्वर मृदा जिसे क्षेत्र में 'ऊसर' कहा जाता है, प्राप्त होती है। यह बागर क्षेत्र में यत्र—तत्र पायी जाती है। इस मृदा में क्षारीय एव लवणीय तत्वों की प्रधानता होती है। इसके धूसरित भाग को क्षेत्र में 'रेह' के नाम से जाना जाता है। नदियों के किनारे की मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। क्षेत्र की मृदा सामान्य रूप से उर्वर है जो फसलोत्पादन

के लिए उपयुक्त है।

[9] प्राकृतिक वनस्पति

सन् 1840 के पूर्व सरयूपार मैदान में *राप्ती घाघरा* तथा अन्य नदियों के तटों पर घने जंगल थे।¹⁴ मध्यम वर्षा एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वृक्षों की अधिकता थी। परन्तु बाढ़ में कृषि भूमि के विस्तार के साथ वनों की अधार्ध कटाई होने लगी। जिससे वर्तमान में वन अध्ययन क्षेत्र के 329 प्रतिशत भूमि पर ही बाग-बगीचों के रूप में रह गये हैं। वनों के अतर्गत सबसे कम क्षेत्र *रुद्रपुर विकासखण्ड* में (181 प्रतिशत) है। अध्ययन क्षेत्र के भाट मृदा क्षेत्र वाले उत्तरी भाग में *शीशम* वृक्ष की बहुतायत है जबकि मध्यवर्तीय उच्च भूमि में एवं नदियों के किनारे तट बन्धों पर स्थित *धूस* क्षेत्रों पर *आम जामुन महुआ* आदि के वृक्ष मिलते हैं। दक्षिण में *राप्ती* एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे तट बन्धों पर स्थित *धूस* क्षेत्रों पर *आम जामुन महुआ* आदि के वृक्ष मिलते हैं। दक्षिण में *राप्ती* एवं उसकी सहायक नदियों के अचल में *बेर* एवं *बबूल* के वृक्षों की अधिकता है।

वर्तमान समय में सड़कों एवं नहरों के किनारे वृक्षारोपण तीव्र गति से किया जा रहा है।

2.2 सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

क्षेत्र की उर्वर मृदा, अनुकूल जलवायु तथा सतत प्रवाही नदियों प्राचीन काल से ही मानव बसाव की केन्द्र रही है। *मुकर्जी*¹⁵ के अनुसार 15 हजार वर्ष ई पूर्व इस क्षेत्र में मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था तथा उसकी कृषि का ढग प्रारम्भिक अवस्था में था। आर्यों के आगमन के साथ विकसित कृषि कार्य प्रारम्भ हुआ एवं सुव्यवस्थित अधिवास विकसित हुए। बौद्धकालीन युग तक यहाँ पर सभ्यता का पूर्ण विकास हो चुका था।

[1] जनाकिकीय वैशिष्ट्य

मनुष्य न केवल प्राकृतिक परिवेश का अंग है, अपितु वह परिवेश निर्माता और सम्पूर्ण मानवीय चिन्तन का केन्द्र भी है अतः सम्पूर्ण जनसंख्या तथा उनकी विशिष्टताये चिन्तन का ऐसा आधार प्रस्तुत करती है, जहाँ से मानव हित की योजनाएँ बनायी जाती हैं। जनसंख्या एवं उसकी विशेषताएँ स्वयं में एक महत्वपूर्ण ससाधन हैं क्योंकि इसकी संरचना वितरण प्रतिरूप एवं जनाकिकीय वैशिष्ट्य पर ही विभिन्न ससाधनों का वर्तमान आर्थिक उपयोग, संरक्षण एवं समुचित नियोजन आधारित होता है तथा उसी के सन्दर्भ में विकास स्तर का निर्धारण एवं मापन किया जाता है। जनसंख्या के सम्यक अध्ययन हेतु उसके विभिन्न पक्षों का ज्ञान अपरिहार्य है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व एवं क्षेत्रीय वितरण के साथ ही आयु संरचना लिंगानुपात, साक्षरता, क्रियाशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक संरचना आदि का समुचित विश्लेषण आवश्यक

सारणी 21
देश, प्रदेश एवं जनपद में जनसंख्या वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति

जनगणना वर्ष	जनपद जनसंख्या (लाख में)	दशकीय वृद्धि		
		जनपद	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	14.84	—	—	—
1911	16.20	8.90	(-) 0.9	5.75
1921	16.53	2.08	(-) 3.08	(-) 0.31
1931	17.66	6.78	6.6	11.00
1941	19.70	11.53	13.5	14.22
1951	21.02	6.74	21.8	13.31
1961	23.75	12.96	16.7	21.51
1971	28.12	18.41	19.8	24.80
1981	34.97	24.30	25.6	24.60
1991	44.40	27.00	25.4	23.86
2001*	27.30	(-) 38.5	25.8	21.34

स्रोत— गजेटियर जिला देवरिया-1988 जनगणना हस्तपुस्तिका-1981 भारत की जनगणना 2001

* कुशीनगर जनपद के सृजन के कारण जनसंख्या कम हो गई

ऑकडे एवं तथ्य— उपकार प्रकाशन, भारत-2001

सारणी 22

जनपद एवं प्रदेश का जनसंख्या घनत्व

वर्ष	जनसंख्या घनत्व (देवरिया)	जन घनत्व (उत्तर प्रदेश) (व्यक्ति/वर्ग किमी)
1971	595 व्यक्ति/वर्ग किमी	300
1981	734 '	377
1991	872 ''	583
2001	1077 ''	689

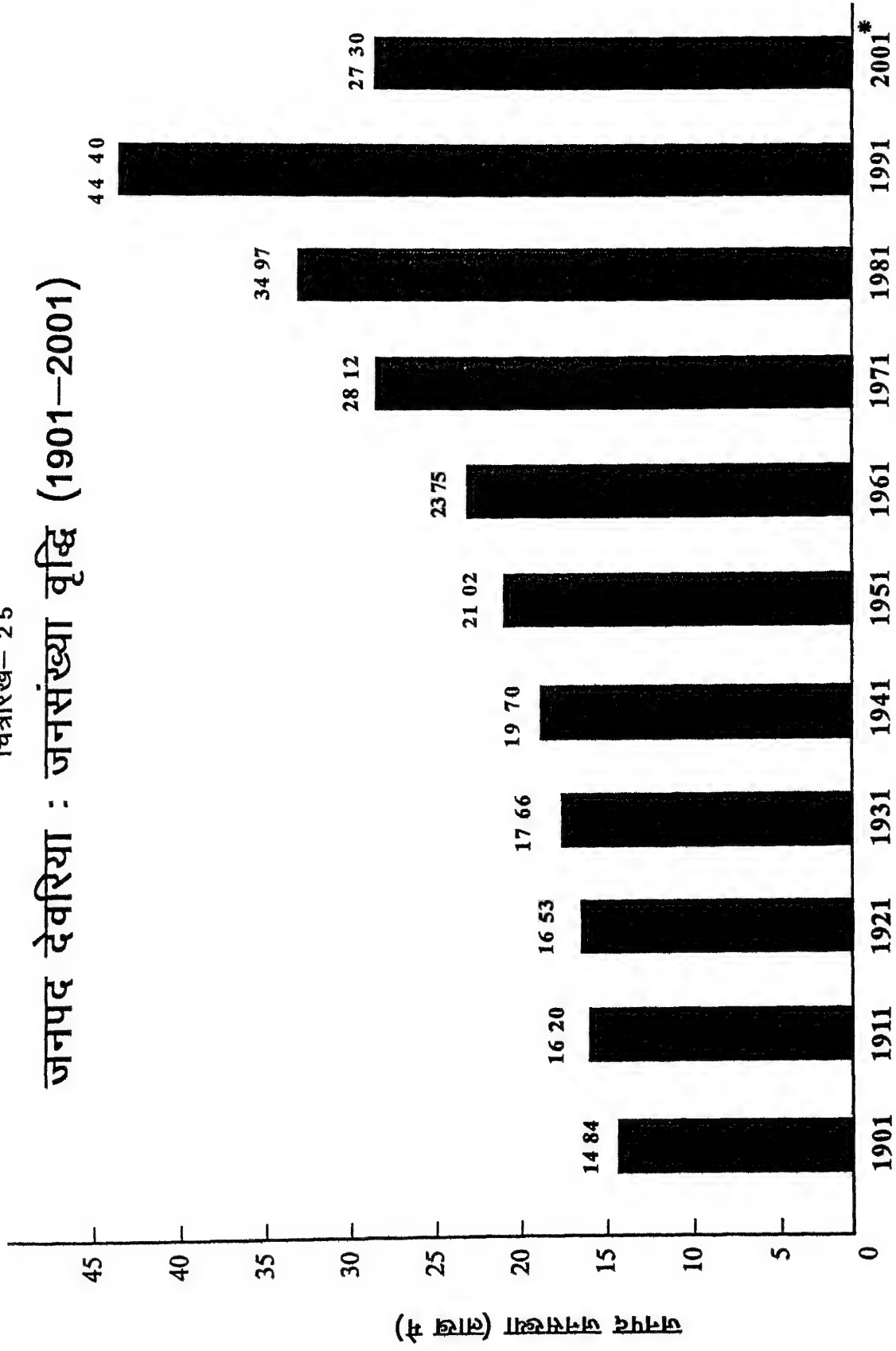
स्रोत— भारत की जनसंख्या- 2001 आकडे एवं तथ्य

है।

(क) जनसंख्या वृद्धि

सन 1901 में देवरिया जनपद की जनसंख्या 7.4 लाख थी जो क्रमशः बढ़ते हुए 1991 में 44.40 लाख हो गयी। इस दौरान सर्वाधिक तीव्र वृद्धि की दर 1981 से 1991 के दशक में 27.0 प्रतिशत रही। जबकि 1971-1981 के मध्य यह वृद्धि 24.3 प्रतिशत रही थी। मई 1994 में जनपद कुशीनगर के सृजन के फलस्वरूप इस जनपद की जनसंख्या घटकर 22.04 लाख रह गयी। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की वर्तमान जनसंख्या बढ़कर 27.30 लाख हो गयी है जो कि गत दशक की अपेक्षा लगभग 17.1 लाख कम हो गयी। इस दौरान जनसंख्या की वृद्धिदर (- 38.5) ऋणात्मक रही। जनपद की जनसंख्या वृद्धि की तुलना यदि

जनपद देवरिया : जनसंख्या वृद्धि (1901-2001)



* (वर्ष 1994 में देवरिया से कुशीनगर जनपद के सृजन के कारण 2001 की जनसंख्या कम हो गई है।)

प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि से करे तो स्पष्ट होता है कि 1931 के बाद 1991 के जनगणना वर्ष के अलावे कभी भी जनपद की वृद्धिदर प्रदेश की वृद्धिदर से अधिक नहीं रही।¹⁶

(ख) जनसंख्या घनत्व

देवरिया का जनसंख्या घनत्व विगत पॉच दशको में 1971 से 2001 के दौरान निरन्तर बढ़ता रहा है। 1971 में यहाँ एक वर्ग किमी क्षेत्र में 595 व्यक्ति रहते थे। जो 2001 में बढ़कर 1077 हो गये जो प्रदेश और देश के घनत्व से बहुत अधिक है 1991 में उ.प्र. का जनसंख्या घनत्व 548 था जो 2001 में 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। इन्हीं वर्षों में भारत का घनत्व 267 से बढ़कर 324 (2001) व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हुआ। अतः यदि देवरिया के जनसंख्या घनत्व की तुलना प्रदेश (2001 वर्ष) से करे तो यह प्रदेश का 1.56 गुना है तथा देश का 3.32 गुना है। वर्तमान में घनत्व की दृष्टि से जनपद का प्रदेश में 9वाँ स्थान है।¹⁷

(ग) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद देवरिया की जनसंख्या के 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। नगरीय जनसंख्या (217363) में 52 प्रतिशत लोग गौरा बरहज एवं देवरिया के दो नगर परिषदों तथा 48 प्रतिशत लोग 8 नगर पंचायतों में निवास करते हैं। रोजगार पाने के इच्छुक लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में पलायन होने के कारण नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही है। 2001 में प्रदेश की 20.8 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी। जबकि देश की 28 प्रतिशत जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय थी।¹⁸

सारणी 2.3

जनपद, प्रदेश, देश की नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में) की तुलनात्मक स्थिति

जनगणना वर्ष	जनपद	प्रदेश	देश
1951	3.46	13.64	17.30
1961	2.42	12.85	18.83
1971	2.96	14.02	19.90
1981	6.63	17.95	23.32
1991	10.00	-	25.70
2001		20.8	27.78

स्रोत— जिला गजेटियर, देवरिया, जनगणना हस्त पुस्तिका—1981, भारत की जनसंख्या—2001, आकड़े एवं तथ्य।

(घ) लिंग अनुपात

देवरिया में 1901 में लिंगानुपात 1,011 था जो क्रमशः कम होते 1931 में 944 हो गया। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद इसमें वृद्धि होती रही और यह 2001 में बढ़कर 1003 हो गया।¹⁹ इस

सारणी 24
जनपद, प्रदेश एवं देश का लिंगानुपात

जनगणना वर्ष	दशकीय वृद्धि		
	जनपद	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	1011	942	972
1911	995	916	964
1921	966	908	955
1931	944	903	950
1941	988	907	945
1951	1003	908	946
1961	1002	907	941
1971	958	876	930
1981	988	882	935
1991	995	876	927
2001	1003	898	933

स्रोत— जिला गजेटियर देवरिया जनगणना हस्त पुस्तिका—1981, भारत की जनसंख्या 2001

ऑफ़डे एव तथ्य— उपकार प्रकाशन

दृष्टि से वर्तमान में यह प्रदेश का तीसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है [क्रमशः प्रथम— आजमगढ़, (1026), द्वितीय जौनपुर (1021) है]। परन्तु देश में हो रही भ्रूण कन्याओं की मृत्यु में वृद्धि का प्रभाव यहां भी दिखने लगा है। 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 964 है²⁰ जो एक चिन्तनीय प्रवृत्ति है।

(ड) साक्षरता

साक्षरता अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रतिबिम्बित करती है।²¹ साक्षरता की दृष्टि से जनपद में साक्षरता उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। जनपद में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 61.4 प्रतिशत पुरुष तथा 23.4 प्रतिशत स्त्री साक्षर रही है। जनपद में स्त्री एवं पुरुष को मिलाकर साक्षरता का कुल प्रतिशत 42.3 था परन्तु वर्तमान समय में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत के सापेक्ष इस जनपद की साक्षरता दर 59.84 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.31 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 43.56 प्रतिशत है। इस प्रकार से इस जनपद की साक्षरता दर में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें स्त्रियों की साक्षरता दर में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान जनगणना के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता दर में ज्यादा वृद्धि हुई है।

इस जनपद में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 'दीप शिक्षा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम'

चलाया जा रहा है। जनपद के उन नवसाक्षरो के लिए जिन्होंने सम्पूर्ण साक्षरता अभियान अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ शिक्षा प्राथमिक विद्यालय या अन्य माध्यमों से प्राथमिक स्तर तक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उनके लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।²²

(च) अधिवास

क्षेत्र में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के अधिवास पाये जाते हैं। यहाँ पर 1991 की जनगणना के अनुसार आवासीय मकानों की संख्या 3,11,951 है जिसमें 91 प्रतिशत आवासीय मकान ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9 प्रतिशत आवासीय मकान नगरीय क्षेत्रों में है। इसी प्रकार जनपद के 91 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 9 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं²³।

(छ) जनसंख्या वितरण

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण मूलतः क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं आर्थिक क्रियाओं सामान्य आवासीय सुविधाओं एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि द्वारा नियंत्रित होता है। 1991 में देवरिया जनपद का जनसंख्या घनत्व 972 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। जो 2001 में बढ़कर 1077 हो गया। परन्तु जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में इसका वितरण समान नहीं है। अपेक्षाकृत अनुकूल क्षेत्रों में ये सघनता अत्यधिक उच्च है तथा कुछ प्रतिकूल क्षेत्रों में कम। इस दृष्टि से जनसंख्या सान्द्रण को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। उच्च जनसंख्या सान्द्रण के क्षेत्र जनपद के उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र हैं। मध्यम उच्च जनसंख्या का सान्द्रण क्षेत्र पश्चिमी तथा मध्यवर्ती पूर्वी भाग में केन्द्रित है। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या का सांद्रण क्षेत्र के दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एवं मध्य भागों में क्रमशः राप्ती, घाघरा एवं छोटी गण्डक नदियों के खादर प्रदेश में हुआ है।

(ज) नगरीकरण

देवरिया जनपद नगरीकरण की दृष्टि से एक पिछड़ा जनपद है। पिछले 50 वर्षों में जनपद की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पहली बार दो अंकों में पहुँचकर 1991 में 10.00 हुई जबकि उस दौरान प्रदेश का नगरीकरण स्तर लगभग 18—19 प्रतिशत के बीच था। जनपद की सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या में से आधे से अधिक (52 प्रतिशत) लोग क्रमशः देवरिया तथा गौरा बरहज में सग्रहित हैं। तीसरा स्थान लार तथा चौथा स्थान रुद्रपुर का है।²⁴

(झ) जनसंख्या का स्थानान्तरण

अध्ययन क्षेत्र एक पिछड़ा जनपद है जहाँ रोजगार के अवसर कम हैं। अतः इस क्षेत्र से प्रदेश तथा देश के नगरों में रोजगार की तलाश में अधिक संख्या में व्यक्ति स्थानान्तरित हुए हैं। यहाँ के स्थानान्तरण की प्रवृत्ति को तीन वर्गों— स्थायी स्थानान्तरण आकस्मिक स्थानान्तरण एवं मौसमी स्थानान्तरण में विभक्त किया जा सकता है। क्षेत्र में पुरुष एवं स्त्री दोनों का ही

स्थानान्तरण अन्तर्क्षेत्रीय एव अन्तर्प्रान्तीय हुआ है। विवाह के कारण स्त्रियों का स्थानान्तरण पुरुषों की अपेक्षा अधिक हुआ है। क्षेत्र की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या स्थानान्तरित होती रहती है। स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण आब्रजन की अपेक्षा प्रवजन अधिक हुआ है। क्षेत्र में ग्राम से नगरोन्मुख स्थानान्तरण अधिक हुआ है।

[2] सामाजिक संरचना

इस मैदानी जनपद की सामाजिक संरचना में उच्च मध्य एवं निम्न वर्ग के लोग हैं। यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या में विभिन्न धर्मों वर्गों और वर्णों के लोग हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या में हिन्दू लगभग 83.7 प्रतिशत मुस्लिम लगभग 16.5 प्रतिशत सिक्ख ईसाई जैन और बौद्ध मिलकर लगभग 0.2 प्रतिशत हैं। शहरी अंचल में यह प्रतिशत क्रमशः 84.7 14.7 और 0.6 प्रतिशत हैं। इस जनपद में ग्रामीण अंचल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत शहरी अंचल की तुलना में अधिक होना एक विचित्रता है।

हिन्दुओं में वर्ण तो केवल चार ही हैं— ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र किन्तु इनकी अनेक जातियाँ और उपजातियाँ मिलती हैं। विशेषकर ब्राह्मणों की प्रमुख शाखाएँ यही से उद्भूत हैं। धतुरा सिरजम श्रीमुख शण्डिल्य ब्राह्मणों के उद्गम स्थल हैं तथा धतुरा उधोपुर बेलही सिरजम बरपार पटनी बुढियाबारी एवं देवरिया खास इनके प्रमुख गाँव हैं। सरयू और छोटी गण्डक के सन्धिस्थल के समीप स्थिति पिण्डी और नदौली नामक ग्राम गर्दभमुख गोत्रीय शण्डिल्य ब्राह्मणों के उद्गम स्थल हैं। इसी तरह पयासी गौतम गोत्रीय मिश्र ब्राह्मणों का उद्गम स्थल है। बरहज के पास स्थित बारा दीक्षित ब्राह्मणों का आरम्भिक स्थल है। भेडी, बकरुआ सराव बसडीला कश्यप गर्ग गोत्रीय शुक्ल ब्राह्मणों के प्रमुख गाँव हैं। ब्राह्मणों की सभी शाखाएँ संयुक्त रूप से सरयूपारीय ब्राह्मण वर्ग में आती हैं। सरयूपारीय 'सर्वाय' शब्द का अपभ्रंश है जिसका आशय सरयू के उत्तरी भाग में रहने वाले लोगों से है।²⁵ साथ ही शाकल्यद्वीपी और कनौजिया ब्राह्मणों का निवास भी इस जनपद में है।

इस जनपद में चारों तरफ फैले हुए क्षत्रियों की भी अच्छी संख्या है तथा इनकी भी कई उपशाखाएँ हैं। नकटा नाला और मझना के बीच में श्रीनेत वशीय क्षत्रियों के प्रमुख स्थल हैं— सौंडा इन्द्रपुर असनहर वर्दगोनिया इत्यादि। मझौली मल्ल क्षत्रियों तथा पैकौली, गडेर और बौरोना शाही क्षत्रियों के प्रमुख स्थान हैं। इनके अतिरिक्त कौशिक सूर्यवंशी चन्देल पँवार अमेठिया, बघेल और चौहान जैसी क्षत्रिय उपजातियाँ भी इस जनपद में हैं। इस जनपद में भूमिहारों की भी महत्वपूर्ण स्थिति है और इनकी प्रमुख उपशाखाएँ हैं— गौतम किवर और गौर तथा शाही। इस जनपद के उत्तरी क्षेत्र में इनका बाहुल्य है। ये मूलतः खेतिहर लोग हैं।²⁶

वैश्य भी इस जनपद में सर्वत्र फैले हुए हैं, यद्यपि इनकी संख्या बहुत नहीं है। जनपद के

व्यापार— वाणिज्य का अधिकांश इनके नियंत्रण में है।

इस जनपद में अहीरो की संख्या भी बहुत है। ये अधिकांशतः कृषि कार्य और दुग्ध उत्पादन में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे राजपूतों के साथ यहाँ आए।²⁷

कोइरी कुर्मी और कँहार भी इस जनपद में हैं। कोइरी लोग कुशल कृषक हैं और शाक सब्जी उत्पादन में बेजोड़ हैं। इनकी प्रमुख शाखाएँ हैं— कनौजिया भगतिया कटियों और जुरीहार।

जहाँ तक व्यावसायिक समूहों— जातियों का प्रश्न है— इनमें प्रमुख हैं— बढई लोहार भडभूज छिप्पी दर्जी कोरी कुम्भकार नाई सोनार मल्लाह और पटहेरा।

अनुसूचित जाति जिनकी प्रभावी संख्या इस जनपद में है की लगभग 40 उपशाखाएँ हैं। इनमें से अधिकांश अब भी मजदूर वर्ग के लोग हैं तथा स्वतंत्रता के बाद भी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जीवन स्तर में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है।²⁸

2.3 आर्थिक एवं वाणिज्यिक पृष्ठभूमि

(अ) कृषि (Agriculture)

[1] भूमि उपयोग प्रतिरूप

भू-लेख से प्राप्त वर्ष 2001-02 के ऑकड़ों के आधार पर जनपद देवरिया का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2,52,370 हे है।²⁹ भूमि उपयोग सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है—

सारणी— 2.5

भूमि उपयोग प्रतिरूप, देवरिया जनपद— 2000-01

क्रमांक	मद	क्षेत्रफल (हे)	प्रतिशत
1	वन	260	0.1
2	उसर एवं खेती के अयोग्य भूमि	3,692	1.46
3	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि	26,877	10.65
4	कृषि अयोग्य भूमि (बजर)	2,359	0.94
5	स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई गई भूमि	65	0.03
6	अन्य वृक्षों झाड़ियों बागों आदि के क्षेत्र	3,919	1.55
7	वर्तमान परती भूमि	7,172	2.84
8	अन्य परती भूमि	3,851	1.53
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	2,04,175	80.90

स्रोत— सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया 2001 पृष्ठ 41

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि कृषि कार्य में लगी है। इसके पश्चात् कृष्येतर भूमि वर्तमान परती वृक्षो झाड़ियो बागो आदि के क्षेत्र तथा उसर भूमि आदि का स्थान है।

उपर्युक्त भूमि उपयोग के विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान परती भूमि एवं उसर भूमि में सुधार एवं सिंचाई साधनों के विकास द्वारा कृषि भूमि के क्षेत्र में विस्तार की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इससे न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सुधार होगा।

[2] कृषि जोत का आकार

कृषि गणना वर्ष 2001-02 के अनुसार जनपद में कुल जोतो की संख्या 3,46,411 है एवं जोतो का कुल क्षेत्रफल 2,10,618 हेक्टेयर है जबकि प्रदेश की कुल जोतो की संख्या 2,00,74,032 है एवं क्षेत्रफल 1,79,85,932 हे है। इस प्रकार जनपद की जोतो की संख्या प्रदेश की जोतो की संख्या का 1.83 प्रतिशत है। जनपद में प्रति जोत औसत क्षेत्र 0.61 हे है।

सारणी 26

देवरिया जनपद के क्रियात्मक जोतो का आकार के अनुसार विवरण ³⁰

क्रमांक	जोत सीमा	प्रतिशत कुल जोत स	प्रतिशत कुल क्षेत्र स
1	10 हे से कम	85.11	50.37
2	10 हे से 20 हे	9.91	21.65
3	20 हे से 40 हे	3.94	59.48
4	40 हे से 100 हे	0.96	8.04
5	10 हे से ऊपर	0.08	1.89
	योग	100.00	100.00

स्रोत- सामाजार्थिक समीक्षा जनपद-देवरिया (2001-2002)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में छोटे जोतो का आकार एवं क्षेत्र का प्रतिशत काफी ज्यादा है।

सारणी 27

प्रदेश में क्रियात्मक जोतो का आकार के अनुसार विवरण (2001-2002)³¹

क्रमांक	जोत सीमा	प्रतिशत कुल जोत स	प्रतिशत
1	10 हे से कम	72.82	31.43
2	10 हे से 20 हे	15.54	24.41
3	20 हे से 30 हे	5.28	14.21
4	30 हे से 50 हे	3.69	15.52
5	50 हे से अधिक	2.67	14.43
	योग	100.00	100.00

स्रोत- सामाजार्थिक समीक्षा जनपद-देवरिया (2001-2002)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में 10 हे से कम क्षेत्रफल वाली जोतो का प्रतिशत 85.11 है जबकि प्रदेश में यह प्रतिशत 72.82 है। इसी प्रकार जनपद में जातो के अंतर्गत क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 50.37 है जबकि प्रदेश में यह प्रतिशत 31.43 है। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद में छोटी जोतो की संख्या प्रदेश की तुलना में अधिक है। इसके अनुकूल ही जनपद में कृषि विकास की योजनाएँ बनाने की नितान्त आवश्यकता है।

[3] कृषि-भूमि उपयोग प्रतिरूप एवं शस्य साहचर्य

अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसके कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (252370 हे) का 84.6 प्रतिशत भू-भाग कृषि जोत के अंतर्गत है परन्तु 2001-02 में 80.90 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि की गयी जो जनपद का शुद्ध कृषित क्षेत्रफल है। जनपद का सकल कृषित क्षेत्र 3,17,759 हेक्टेयर है। जिसमें खरीफ़ रबी एवं जायद की फसलें होती हैं। सर्वाधिक कृषित भूमि खरीफ़ (50.46 प्रतिशत) शस्यान्तर्गत है। इसमें प्रमुख फसल धान है जो कछारी भू-भाग तथा सिंचित भू-भागों में अधिकांशतः की जाती है। रबी शस्यान्तर्गत 47.55 प्रतिशत क्षेत्र है। इसमें गेहूँ, प्रधान फसल एवं सरसो, चना, मटर, आदि अन्य फसलें उगाई जाती हैं। सिंचित भू-भागों में गेहूँ की प्रमुखता है। जायद के अंतर्गत 1.81 प्रतिशत क्षेत्र पर सब्जियों की कृषि की जाती है। 0.15 प्रतिशत क्षेत्र गन्ना के अंतर्गत है।³² इसे निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है—

सारणी 28

देवरिया जनपद में विभिन्न शस्यान्तर्गत क्षेत्र का विवरण

शस्य	क्षेत्रफल हे में	क्षेत्रफल प्रतिशत में
खरीफ़	160366	50.46
रबी	151114	47.55
जायद	5778	1.81
गन्ना	501	0.15
सकल बोया गया क्षेत्र	3,17,759	100

स्रोत— सामाजार्थिक समीक्षा जनपद—देवरिया (2001-2002)

[4] शुद्ध कृषित क्षेत्र एवं सकल कृषित क्षेत्र

वर्ष 2001-02 में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2,04,175 हे है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 80.90 प्रतिशत है। एक बार से अधिक बोये गये फसल का क्षेत्र 1,13,584 हे है। जिसका तहसीलवार वर्गीकरण एवं जनपद में प्रतिशत निम्न सारणी से प्रदर्शित किया जा सकता है।

सारणी 29

शुद्ध एव सकल कृषित क्षेत्र का तहसीलवार विवरण³³

क्रमांक	तहसील	शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रति (जनपद के क्षेत्रफल से)	1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र प्रतिशत
1	देवरिया	36 02	39 36
2	रुद्रपुर	12 27	19 23
3	सलेमपुर	18 64	17 03
4	बरहज	15 13	11 18
5	भाटपार रानी	13 94	13 20
	योग	100 00	100 00

स्रोत— सामाजार्थिक समीक्षा जनपद—देवरिया (2001-2002)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देवरिया तहसील में एक बार से अधिक बाए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है उसके बाद क्रमश रुद्रपुर सलेमपुर भाटपाररानी एव बरहज का स्थान है। एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत उन्ही भागो में अधिक है जो बागर क्षेत्र के अतर्गत है तथा जहाँ सिचाई सुविधाओं का विकास समुचित मात्रा में हुआ है।

[5] फसलचक्र एव फसल सघनता ³⁴

अध्ययन क्षेत्र में खरीफ एव रबी प्रधान फसले हैं। रबी की प्रमुख फसले गेहूँ जौ चना एव लाही सरसो तथा खरीफ की फसलो में प्रमुखत धान मक्का अरहर है। इसके साथ ही गन्ना चना एव सावा की फसले भी बोयी जाती हैं। वर्ष 2000-2001 में जनपद की फसल सघनता 155 63 रही है। वर्ष 2000-01 में रबी में बोयी गयी फसलो के क्षेत्र का 91 1 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ 1 82 प्रतिशत मटर 1 40 प्रतिशत आलू 1 00 प्रतिशत जौ, 0 52 प्रतिशत चना तथा 4 16 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य फसले बायी गयी है। वर्ष 2001-01 में 151114 हे क्षेत्र में रबी की फसल बोयी गयी थी जिसमें देवरिया सदर तहसील में गेहूँ का क्षेत्र सबसे ज्यादा है एव सबसे कम क्षेत्र भाटपाररानी तहसील का है। अधिक उपज वाले गेहूँ की खेती का अधिक प्रचलन होने के कारण जौ का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है।³⁴

खरीफ की फसल में कुल बोया गया क्षेत्र 1 60,366 हेक्टेयर था जिसमें धान का क्षेत्र देवरिया सदर तहसील में सबसे अधिक एव भाटपाररानी तहसील में सबसे कम रहा है। मक्का का क्षेत्र भाटपाररानी तहसील में सबसे अधिक (2 553 हे) एव सबसे कम बरहज तहसील का (399 हे) है।

वर्ष 2000-01 में जनपद में 2 080 हे में लाही एव अन्य खाने योग्य तिलहनी फसलो को बोया गया है जिसमें देवरिया तहसील में सबसे अधिक क्षेत्र (816 हे) एव बरहज तहसील में सबसे कम क्षेत्र (221 हे) है।

जनपद में गन्ने की खेती का महत्वपूर्ण स्थान था परन्तु विगत कई वर्षों से कई चीनी मिलों की दशा जर्जर होने के कारण एव कई बन्द होने के कारण गन्ने का उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बाये गये क्षेत्र में भी कमी होती जा रही है। वर्ष 2000-01

मे गन्ना कुल 18227 हे भूमि मे बोया गया था जिसमे देवरिया सदर मे सबसे ज्यादा क्षेत्र एवं सबसे कम क्षेत्र तहसील बरहज का रहा है।

[6] कृषि उत्पादकता

देवरिया जनपद कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भू-भाग है। यहाँ कृषि के क्षेत्र में आधारभूत ढाँचा के विकास का प्रभाव उत्पादकता पर परिलक्षित होने लगा है। 1995 से 1998 के वर्षों के दौरान मक्का की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई इसके बाद क्रमशः चना अरहर जौ चावल मटर मूँगफली गेहूँ लाही-सरसो का स्थान रहा। क्षेत्र में चावल एवं गेहूँ जो प्रधान खाद्यान्न फसले हैं इनमें चावल उत्पादकता थम सी गयी है एवं गेहूँ की उत्पादकता में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।³⁵ इसे निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है—

सारणी 2 10
देवरिया जनपद में औसत कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, कु/हे (1995-1998)

मुख्य फसले	औसत उपज		उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत
	1995	1998	
1 मक्का	8 51	15 24	79 0
2 चना	4 53	6 74	48 78
3 अरहर	6 99	9 38	34 19
4 जौ	19 32	25 03	29 55
5 चावल	17 40	19 35	11 2
6 मटर	12 21	12 99	6 38
7 मूँगफली	7 75	8 01	3 35
8 गेहूँ	23 22	23 04	(-) 0 77
9 लाही सरसो	6 63	6 43	(-) 3 0

स्रोत— सामाजार्थिक समीक्षा जनपद देवरिया (2001-2002)

[7] सिंचाई एवं बाढ़

सिंचाई— कृषि के लिए जल अनिवार्य है जिसकी पूर्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों द्वारा होती है। सिंचाई का प्राकृतिक साधन वर्षा है। वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता के कारण कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, असामयिकता तथा विषमता सिंचाई की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्रोत नहर राजकीय नलकूप निजी नलकूप एवं पम्प सेट हैं। जनपद में नहरों की कुल लम्बाई 401 कि मी है। जिससे 30 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। राजकीय नलकूपों की संख्या 854 है जिसमें 39,552 हेक्टेयर तथा निजी नलकूपों द्वारा 87351 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गयी है। इसी प्रकार कुएँ 639 हेक्टेयर तथा तालाब एवं झील 1017

हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों से 158 हे क्षेत्र में सिंचाई होती है। जनपद में वर्ष 2000-01 के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1 58 937 हेक्टेयर रहा है एवं सकल सिंचित क्षेत्रफल 1 77,819 हे था जो सकल बोए गये क्षेत्रफल का 55.76 प्रतिशत था। जनपद में वर्ष 1999-2000 के अनुसार सकल बोया गया क्षेत्रफल 3 17 759 हेक्टेयर था। जनपद में सिंचाई के प्रधान स्रोत नलकूप हैं। कुल सिंचाई का 79.85 प्रतिशत भाग इनसे सींचा जाता है। उसके बाद नहरों से 19.01 प्रतिशत भाग की सिंचाई होती है। तालाब एवं झील से सिंचाई बहुत कम क्षेत्रों में होती है। झील तालाब वर्षा पर निर्भर स्रोत है।³⁶

सारणी- 211

जनपद में स्रोतवार सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचाई का विवरण (2000-2001)

सिंचाई स्रोत	सिंचित क्षेत्रफल (हे मे)	सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
नलकूप	1 26 903	79.85
नहर	30 220	19.01
तालाब-झील	1 017	0.64
कुँए	639	0.40
अन्य	158	0.09
योग	1 58 937	100.00

स्रोत- सामाजार्थिक समीक्षा जनपद-देवरिया (2001-2002)

बाढ़- यह जनपद बाढ़ की दृष्टि से काफी सवेदनशील है। इस जनपद का रुद्रपुर तहसील का अधिकांश भाग नदियों से आच्छादित रहने के कारण साथ ही राप्ती एवं घाघरा नदी के बीच पतला कछारक्षेत्र है, जो प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष कृषि एवं पशुओं के साथ-साथ जनजीवन को गम्भीर खतरा बना रहता है। इस जनपद में छोटी गण्डक, राप्ती, गोर्रा, घाघरा नदियों के अलावा मझना नाला, नकटा नाला तथा कुर्ना एवं खनुआ नाला जो प्रायः वर्षा के दिनों में नदी का रूप ले लेते हैं, इनसे भी काफी क्षति होती है। बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु बाढ़ खण्ड विभाग देवरिया उत्तरदायी है जिसके द्वारा रुद्रपुर एवं सलेमपुर तहसील के अतर्गत पड़ने वाली राप्ती गोर्रा, घाघरा नदियों से बचाव कार्य हेतु इस जनपद में निम्न रणनीति अपनायी गयी है।

(1) बाढ़ खण्ड द्वारा जनपद में घाघरा राप्ती गोर्रा नदियों एवं कतुआ नाला के किनारे बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबन्ध निर्मित कराया गया है। वर्ष 1998 में आयी प्रलयकारी बाढ़ के फलस्वरूप गोर्रा नदी के दोनों किनारे पर स्थिति जमींदारी बंध को लेकर जितने कटाव हुए थे उनके पुनर्निर्माण का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

(2) विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तीन गेज स्थल क्रमशः पिडरा, मेड़ी, बरहज में

स्थापित किये गये हैं, जिसके प्रभारी बाढ़ खण्ड के सहायक अभियन्ता बनाये गए हैं तथा उनके साथ तीन या चार अवर अभियन्ता सम्बद्ध कराये गये हैं जो उनकी देखरेख में बाढ़ सुरक्षा कार्यों में सलग्न रहते हैं।

इस जनपद में गण्डक नहर-3 एवं बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा बाढ़ सुरक्षा हेतु 34 बन्धे निर्मित किये गये हैं जिसकी कुल लम्बाई 223.43 किमी है एवं इससे 46 083 हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से सुरक्षित किया गया है।

वर्ष 1998 में आयी प्रलयकारी बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बाढ़ काल में तटबधों तथा उसके किनारे स्थित ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामवार बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन वर्ष 1999 में किया गया है।

[8] जल एवं मृदा संबंधित पर्यावरणीय समस्याएँ एवं उनका संरक्षण

जल एवं मृदा पृथ्वी पर जीवन के आधारभूत संसाधन हैं। इनके बिना कृषि कार्य की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसको केवल अक्षुण्ण रूप में ही नहीं बल्कि सुधरे हुए रूप में आगामी पीढ़ियों के लिए सौंपें। इसके लिए कृषि विकास की प्रक्रिया में भूमि संसाधन की वहन क्षमता तथा जल संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता तथा इसके सामर्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओं की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। भूमि तथा जल चक्रों के बीच तालमेल का सम्बन्ध बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की उपलब्ध भूमि की उपलब्धता बढ़ाने उत्पादकता फिर से प्राप्त करने भूमि का फिर से सुधार करने और कम उपजाऊ भूमि का विकास करने व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता को लेकर कृषि तथा इसके अन्य आनुषंगिक माध्यमों से अध्ययन क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि लायी जा सकती है।

अध्ययन क्षेत्र नेपाल से लगे तराई क्षेत्र के समीप स्थित है, जहाँ नेपाल से निकलने वाली अनेक नदियाँ जनपद से होकर गुजरती हैं तथा अपने रास्ते में पानी के तेज बहाव एवं आयतन के कारण कटाव तथा बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती हैं। साथ ही तराई क्षेत्र होने के कारण जनपद में भूमिगत जल स्तर अन्य जनपदों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। जनपद में भूमि एवं जल संरक्षण सम्बन्धी मुख्य समस्याओं में जल भराव (वाटर लॉजिंग) मृदा के उपरी परत का क्षरण, नदियों के तेज बहाव से इसके किनारे स्थित कृषि एवं अकृष्य भूमि का कटाव बढ़ती जनसंख्या के कारण अत्यधिक पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का नाश, उसर भूमि तथा समुचित भू-संरक्षण तकनीक न अपनाये जाने के कारण उबड़-खाबड़ भूमि तथा परती भूमि का होना है। जनपद में मुख्यतः घाघरा, छोटी गण्डक, राप्ती, गोर्रा, आदि नदियाँ अपने बहाव में किनारे स्थित

उपयोगी भूमि का कटाव करती है तथा वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के कारण बाढ़ की समस्या पैदा करती है जो बाढ़ में पक सिल्ट छोड़ जाती है। इससे बहुमूल्य कृषि भूमि का काफी क्षेत्र प्रभावित होता है तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता कम हो जाती है।³⁷

सरक्षण के उपाय

इन समस्याओं के निदान हेतु यह आवश्यक है कि जनपद में भूमि एवं जल सरक्षण तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय जिससे इन समस्याओं का यथा सम्भव निदान हो सके। इन उन्नतशील तकनीकों में मृदा के ऊपरी परत के कटाव को रोकने हेतु *फिल्ड बन्ड* *कन्टूर बन्ड* *चकरोड* आदि का निर्माण आवश्यक है। जलभराव की समस्या के निदान हेतु उपर्युक्त नियोजन कर *ड्रेन* आदि का निर्माण उपयोगी होगा। इसी प्रकार जल सरक्षण तथा मतस्य पालन आदि हेतु अधिकाधिक तालाब एवं पोखरो का निर्माण उपयोगी होगा। मृदा कटाव की रोकथाम हेतु नदियों नालों के किनारे तथा कृषि एवं अकृष्य भूमि में उपयुक्त प्रजाति के घास झाड़ी तथा पेड़ों का रोपण आवश्यक है। नदियों से आने वाली बाढ़ की रोकथाम हेतु नदियों का गहरा किया जाना तथा उससे निकली मिट्टी का उपयोग इसके दोनों तरफ बाँध बनाने में किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त समस्याओं तथा उसके सुझाये गए निदान को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में वर्तमान भूमि सरक्षण इकाई की स्थापना वर्ष 1993 में की गयी। *भूमि सरक्षण इकाई देवरिया* द्वारा विगत वर्षों में जनपद के विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों में ड्रेन निर्माण तालाब निर्माण नाला स्थिरीकरण, जलबाँध निर्माण मेडबन्दी समतलीकरण घास रोपण, पौध रोपण, तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बोरिंग एवं पुल निर्माण आदि कार्यों का निष्पादन किया गया है। इन कार्यों के निष्पादन हेतु विगत वर्षों में *सुनिश्चित रोजगार योजना* *जवाहर रोजगार योजना* *दस लाख कूप योजना*, *विधायक निधि*, *राष्ट्रीय जलागम एवं जलमग्न योजना* आदि योजनाओं में प्राप्त धनराशि से उपरोक्तानुसार कार्यों का निष्पादन किया गया। परन्तु वर्तमान में *राष्ट्रीय जलागम योजना* के अंतर्गत *बैतालपुर* विकासखण्ड तथा *राष्ट्रीय जलमग्न योजना* के अन्तर्गत विकासखण्ड *गौरीबाजार* में ही धनराशि प्राप्त होने के कारण कार्यों का निष्पादन हो पा रहा है।

[9] कृषि वैशिष्ट्य

अध्ययन क्षेत्र का मुख्य आर्थिक क्रिया-कलाप कृषि है। प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ पर कृषि कार्य प्रारम्भ हो गया था। इस क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। वैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का प्रभाव क्षेत्र में भी पड़ रहा है फिर भी पशुपालन की महत्ता कायम है।

[10] पशुपालन

जनपद आरम्भिक काल में पशुधन सम्पन्न था परन्तु अब बढ़ते यंत्रीकरण के फलस्वरूप इसकी संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। अब कृषि कार्य का ये पूरक नहीं रहा बल्कि केवल दुधारू पशुओं का ही महत्व रह गया है। जनपद में पशुधन की विभिन्न नस्लों में चौपाए ही अधिक प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1993 की पशुगणना के अनुसार पशुओं की कुल संख्या 7 98 121 थी जिसमें प्रतिशत संख्या क्रमानुसार *गौजातीय महिषवशीय भेड़ बकरा—बकरी घोड़े एवं टटटू एवं सुअर* का है।

1997 के पशुगणना के समय ये पशुसंख्या घटकर 6 08 971 हो गयी। इसमें मात्र 4 वर्षों में 1 89 150 पशुओं की कमी हो गयी। सर्वाधिक कमी *भेड़ों* और *गौजातीय* पशुओं में हुयी।

[11] मत्स्य पालन

जनपद के ग्रामीण अंचल में तालाब पोखर के रूप में ग्रामपंचायत के स्वामित्व के अंतर्गत विभिन्न आकार के कुल 1 835 तालाब (*जलक्षेत्र 866 हे*) उपलब्ध हैं। इनमें 1 521 तालाब विकसित जलक्षेत्र के रूप में उपलब्ध हैं जिसमें तकनीकी विधि से मत्स्य पालन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। मत्स्य बीज उपलब्ध कराने हेतु *खुखुन्दू* में *हैंचरी* की स्थापना की गयी है।

[ब] ऊर्जा (Energy)

1 ऊर्जा उपभोग

ऊर्जा प्रत्येक आर्थिक गतिविधि को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती है और इसकी उपलब्धता तथा लागत पर राष्ट्र का आर्थिक भविष्य प्रगति तथा जनता का जीवन स्तर निर्भर करता है। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी ऊर्जा की आवश्यकता गैर वाणिज्यिक स्रोतों जैसे लकड़ी, उपले, बेकार कृषि पदार्थों आदि और वाणिज्यिक स्रोतों जैसे बिजली, कोयला, तेल तथा परमाणु ईंधन से पूरी होती है। विद्युत ऊर्जा की सबसे सुविधाजनक और उपयोगी किस्म है। इसलिए अन्य ऊर्जा साधनों की तुलना में इसकी माँग बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है।³⁸ उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः बिजली की खपत की मात्रा देश में उत्पादकता और विकास दर की सूचक होती है। इसे देखते हुए विकास कार्यक्रमों में विद्युत—विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। विद्युत सविधान की *समवर्ती सूची* में सम्मिलित है, इसलिए इसके विकास की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्यों दोनों पर है।³⁹ इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। केन्द्र में विद्युत विभाग विद्युत ऊर्जा के विकास और इसके उत्पादन, संरक्षण, वितरण एवं संरक्षण का कार्य देखता है।

अध्ययन क्षेत्र विद्युत उत्पादन की दृष्टि से निर्धन है। यहाँ कोई भी विद्युत उत्पादन गृह नहीं है वरन् बाहर से प्रेषित विद्युत पर ही जनपद का सम्पूर्ण विकास कार्य अवलम्बित है।

वर्ष 1999-2000 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 4 737 ग्रामो तथा 10 नगरो को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युतीकृत गाँवों की संख्या कुल आबाद ग्रामो की 72.2 प्रतिशत है। वर्ष 1998-2000 में 18 ग्रामो को विद्युतीकृत एवं 26 पम्पसेट/नलकूपों का ऊर्जन किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक ग्रामो को विद्युत सुविधा पूर्ण करने हेतु योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

सारणी- 2.12

जनपद में विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग (ह कि वा घ)

क्रम सं	मद	1997-98	1999-2000	कुल उपभोग में प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5
1	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	46563	87839	87.3
2	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	4381	4568	4.54
3	औद्योगिक विद्युत शक्ति	12182	1715	1.70
4	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	604	17	0.016
5	रेल / ट्रेक्शन	—	—	
6	कृषि विद्युत शक्ति	76251	6065	6.03
7	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्ध्वन व्यवस्था	849	30	0.03
	योग	140830	100534	100.00

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका- 2001 पृष्ठ- 63-64

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में विद्युत की सर्वाधिक खपत घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति में हो रही है। कृषि में 6.03 प्रतिशत एवं उद्योग में 1.70 प्रतिशत की बिजली खपत, उद्योग एवं कृषि विकास की दयनीय स्थिति को ही सूचित करते हैं। यदि इस खपत की तुलना 1997-98 के आँकड़ों से करे तो विगत तीन-चार वर्षों में जहाँ घरेलू प्रकाश वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति की खपत में भारी वृद्धि हुई है वही कृषि एवं उद्योग में क्रमशः 92 प्रतिशत एवं 86 प्रतिशत की कमी हुयी, जो एक चिन्तनीय प्रवृत्ति है। ये क्षेत्र में विकास की अधःप्रवृत्ति को ही सूचित करता है।

1980-81 से 1999-2000 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य में तीव्र वृद्धि हुयी है। 1980-81 में जनपद में जहाँ मात्र 32 प्रतिशत गाँवों में ही विद्युत पहुँची थी वही 1999-2000 तक यह प्रतिशत बढ़कर 72.2 के आंक तक पहुँच गया।

[स] औद्योगिक स्थिति

उद्योग को मानव जाति के विकास की कुजी कहा जाता है परन्तु अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग के विकास की पर्याप्त सभावनाएँ हैं और उद्योगों का विकास भी इसी आधार पर हुआ भी है पर वर्तमान में उनकी स्थिति भी बहुत ही निराशाजनक है।

क्षेत्र में वृहद् उद्योग के अतर्गत गन्ना पर आधारित चीनी उद्योग का विकास हुआ। प्राचीन काल में भी खाडसारी उद्योग के रूप में यह विकसित था, परन्तु वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ वे विनष्ट हो गये। चीनी उद्योग की वर्तमान इकाइयों—प्रतापपुर गौरीबाजार भटनी देवरिया एवं बैतालपुर में स्थापित हैं।

जनपद लघु उद्योग के विकास में भी काफी पिछड़ा हुआ है। इसके अतर्गत यहाँ मुख्य रूप से इजीनियरिंग वर्क्स फूड स्टफ्स ऑयल इण्डस्ट्रीज गुड उद्योग विद्युत बल्ब प्लास्टिक उद्योग पिंटिंग प्रेस आदि विकसित हैं। कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास की यहाँ पर्याप्त सभावनाएँ हैं। कुटीर उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है।

[द] परिवहन व्यवस्था

परिवहन तन्त्र आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। किसी क्षेत्र में परिवहन साधनों का वैसा ही महत्व है जैसा कि मानव शरीर में रक्त वाहिनी धमनियों का होता है। देश में कृषीय और औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रम परिवहन व्यवस्था के विकास से सम्बद्ध हैं। विकसित परिवहन व्यवस्था से कृषि—विकास और औद्योगिकीकरण में सहायता मिलती है। परिवहन साधनों के पर्याप्त विकास होने पर देश के सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिनसे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।⁴⁰ किसी भी देश—प्रदेश या क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए एकीकृत परिवहन तन्त्र की आवश्यकता होती है। परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का लाभ पिछड़े क्षेत्रों को भी मिल जाता है। इस प्रकार परिवहन जाल पिछड़े क्षेत्रों में भी ससाधनों के उपयोग को बल देकर वृद्धि एवं विकास की स्थिति उत्पन्न करेगा।⁴¹ आर्थिक विगलन राजनैतिक विखण्डन और सामाजिक दूरियों को, एकीकृत एवं समन्वित परिवहन जाल से ही खत्म किया जा सकता है। उपभोग एवं उत्पादन बिन्दुओं में संयोजन गाँव एवं शहर से सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्राकृतिक आपदा के समय ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। परिवहन तन्त्र न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है, वरन् स्थानीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजार से और राष्ट्रीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है।⁴² कैन्नन महोदय के अनुसार “परिवहन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है जो किसी भी अविकसित क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तीव्र विकास ला सके।”⁴³ क्षेत्रीय विकास के

विभिन्न स्तरों एवं परिवहन साधनों के विकास में गहन अंतर्सम्बन्ध मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तो परिवहन साधनों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है।

परिवहन तन्त्र क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। देवरिया जनपद एक समतल भू-भाग है जहाँ पर सड़क एवं रेल परिवहन का विकास सुगमतापूर्वक हुआ है। प्राचीन काल में नदियाँ एवं सड़कें प्रमुख परिवहन का साधन रही हैं परन्तु वर्तमान समय में परिवहन के प्रमुख साधन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग हैं।

अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक परिवहन मार्गों (मुख्यतः सड़क एवं रेल) का विकास अंग्रेजी शासन काल में प्रारम्भ हुआ था। इससे पूर्व इस क्षेत्र में जल परिवहन अधिक महत्वपूर्ण था। जल मार्ग पर स्थित हेतिमपुर, रुद्रपुर गौराबरहज तरकुलवा, भागलपुर मुख्य व्यापारिक सेवाकेन्द्र थे। ये केन्द्र छोटी गण्डक राप्ती, घाघरा— गंगा जलमार्ग द्वारा व्यापार के लिए देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए थे। किन्तु रेल परिवहन के विकास तथा सड़कों के निर्माण के कारण जल परिवहन का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा और अब लगभग समाप्त हो गया है।

(क) रेल परिवहन

अध्ययन क्षेत्र में रेल मार्ग निर्माण का कार्य बंगाल और उत्तरी-पश्चिमी रेलवे (बी एन डब्ल्यू आर) के अंतर्गत मई 1882 से प्रारम्भ हुआ। 15 जनवरी 1885 को इसे परिवहन के लिए खोल दिया गया। 14 मई 1952 को जब भारतीय रेलवे को जोन में विभाजित किया गया तब यह उत्तरी-पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया जिसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया।

जनपद के रेल मार्ग को निम्न भाग में बाँटा जा सकता है।

[i] गोरखपुर—सोनपुर—जक्शन ट्रक लाइन— यह लाइन गोरखपुर से मझना नाला को पार करते ही जनपद में प्रवेश करती है। देवरिया—सलेमपुर—भाटपाररानी तहसील होते हुए दक्षिण—पूर्व दिशा में बिहार के सोनपुर को चली गयी है। यह बड़ी लाइन है तथा इस पर निम्न प्रमुख रेलवे स्टेशन स्थित हैं— गौरी बाजार बैतालपुर, देवरिया सदर, अहिल्यापुर, नूनखार भटनी जक्शन नोनापार, भाटपार रानी बनकटा।

[ii] भटनी— औरिहार—इलाहाबाद मुख्य लाइन— यह लाइन जनपद में मात्र 27 किलोमीटर की दूरी तक ही विस्तृत है। इस जनपद में इस पर निम्न स्टेशन हैं— पेड़कोल, सलेमपुर, लार रोड, तुर्तीपार।

[iii] भटनी— बरहजबाजार ब्रान्च लाइन— यह लाइन जनपद में मात्र 20 किमी तक

TRANSPORT NETWORK OF DEORIA DIST (2002)

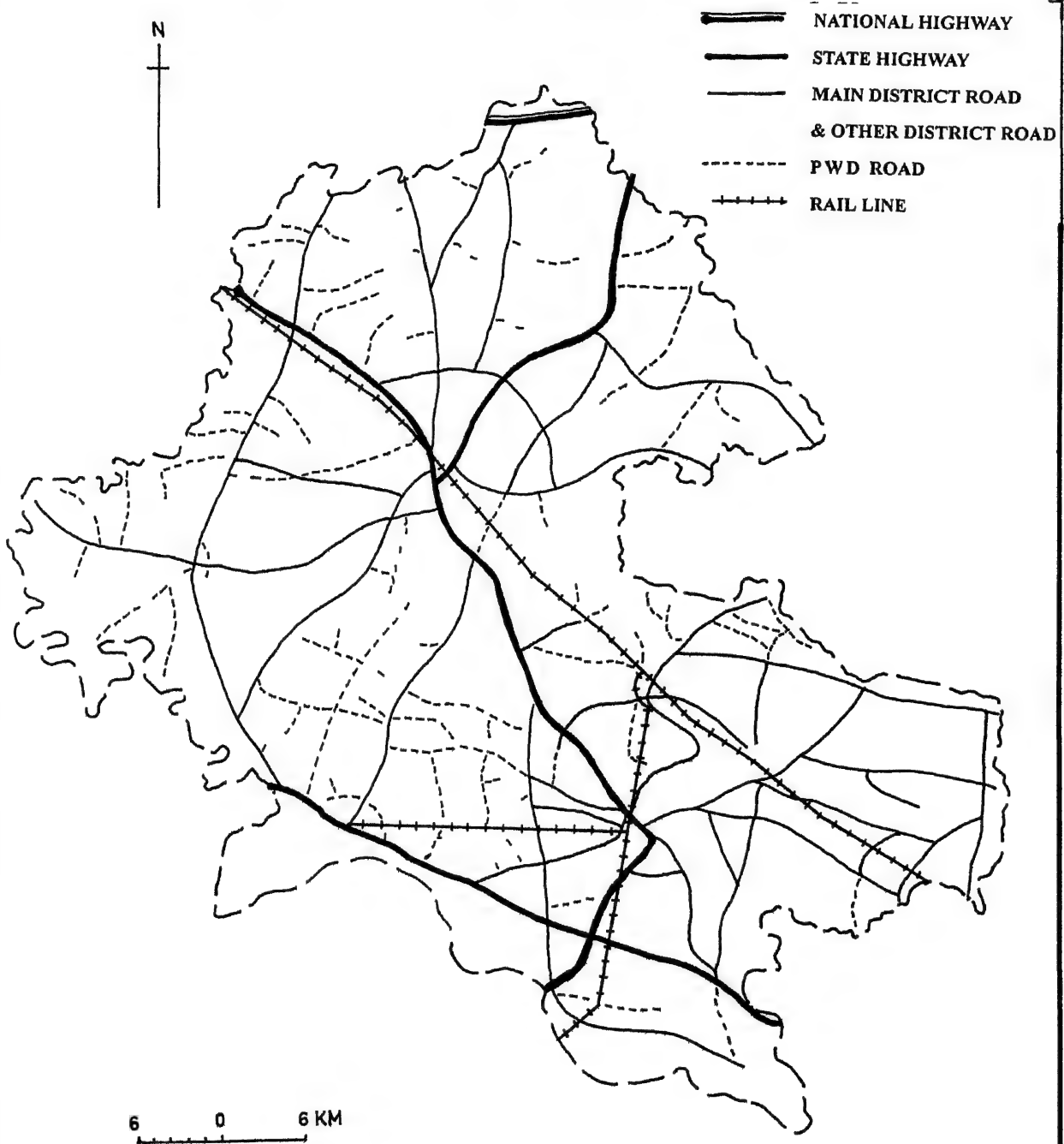


FIG 2 6

ही विस्तृत है। इस लाइन को 1 दिसम्बर 1897 को यातायात के लिए खोला गया। इस पर मुख्य स्टेशन हैं— सतराँव और बरहज बाजार।

इस प्रकार उपरोक्त रेल लाइनो के साथ जनपद में रेल लाइनो की कुल लम्बाई 111 किमी है जिनमें सभी लाइनें बड़ी लाइन ही हैं।

(ख) सड़क परिवहन

सड़क क्षेत्र का सबसे प्राचीन परिवहन मार्ग है। अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेल मार्गों की तुलना में सड़को का अधिक विकास हुआ है। सड़को पर परिवहन साधनों की विविधता तथा मात्रा के कारण सड़को के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर मिलता है। सड़को का आधुनिक महत्व इसी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों से बढ़ा जब मोटर गाड़ियों के अत्यधिक प्रचलन से द्रुत सड़क परिवहन रेल परिवहन की बराबरी करने में समर्थ हुआ। अब दोनों परिवहन माध्यम एक-दूसरे के पूरक हो गए हैं। प्रत्येक सेवाकेन्द्रों को रेलमार्गों से जोड़ना असंभव है किन्तु प्रत्येक सेवाकेन्द्र को सड़को से जोड़ा जा सकता है। रेलमार्गों को सड़को से जोड़कर अभिगम्यता और बढ़ायी जा सकती है। इसलिए लोच विश्वसनीयता एवं गति को सड़क परिवहन की मुख्य विशेषता बताया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न नदियों पर पुलों का निर्माण सड़को का निर्माण तथा उनको पक्का करने की गति में तीव्रता आयी जिससे क्षेत्र में सड़को का जाल बिछ गया है चित्र (26)। अध्ययन क्षेत्र में सड़को का जाल बिछ गया है। बाढ़ का प्रभाव सड़को के विकास में बाधक रहा है। सम्प्रति क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग तथा अन्य सड़कें हैं।

[य] संचार

पिछड़े क्षेत्रों के विकास में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार माध्यमों से नवीनताओं का प्रसारण होता है जो पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होता है। विकसित संचार सेवाएँ आधुनिक समय की अनिवार्य आवश्यकता हैं। संदेश विचार एवं सूचनाओं इत्यादि के आदान-प्रदान को संचार कहते हैं। संचार माध्यमों को *व्यक्तिगत संचार माध्यम* तथा *जनसंचार माध्यम* में विभक्त किया जा सकता है। *व्यक्तिगत संचार माध्यम* के अंतर्गत डाक तार तथा दूरभाष आदि आते हैं। ये वैयक्तिक सेवाएँ प्रदान कर विकास को बढ़ावा देते हैं। रेडियो, दूरदर्शन पत्र-पत्रिकाएँ तथा सिनेमा आदि *जनसंचार* के माध्यम हैं।

जनपद में 276 डाकघर 21 तारघर 668 पी सी ओ तथा 5,931 टेलीफोन हैं।

[र] श्रम एवं रोजगार

31 मार्च 2001 को जनपद के सार्वजनिक क्षेत्र में 17,419 तथा निजी क्षेत्र में 4,831 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोजगार में लगे हुए थे। इस प्रकार कुल 22,250 व्यक्तियों में से *निजी क्षेत्र* का

प्रतिशत 217 एव सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिशत 783 है। जनपद में एक सेवायोजन कार्यालय स्थित है जिसमें वर्ष 2000-01 में 30782 बेरोजगारों ने प्रतीक्षारत व्यक्तियों के रूप में नामांकन कराया है।

इस जनपद में वर्ष 2000-01 में कुल 61 पंजीकृत कारखानों में से 29 कारखाने कार्यरत हैं जिनमें 8696 श्रमिक कार्यरत हैं। जनपद में विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत श्रमिकों का विवरण निम्नवत है—

सारणी- 213

विभिन्न सेक्टरों में कार्यरत श्रमिकों का विवरण 2001

विभिन्न सेक्टर	कार्यरत श्रमिक संख्या
कृषक	3 47,089
कृषि श्रमिक	1 69 406
पशुपालन एवं बागवानी	2 255
खान खोदना	338
कुटीर उद्योग	858
अन्य उद्योग	22 176
निर्माण	4 084
व्यापार-वाणिज्य	34 949
यातायात-संचार	6 385
अन्य कर्मकार	57 575

★★★★★

References

- 1 Varun, D P, 'Gazetteers of Deoria, Govt Press Allahabad P 1
- 2 I bid p 1
- 3 सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद-देवरिया (2001-2002) पृ 4
- 4 वही पृष्ठ-5
- 5 संदर्भ संख्या 1 पृष्ठ-3
- 6 संदर्भ संख्या- 1 पृष्ठ 3
- 7 संदर्भ संख्या 1 पृ 5
- 8 वही
- 9 वही पृष्ठ 9
- 10 संदर्भ- 1 पृष्ठ 10
- 11 वही, पृष्ठ 11-13
- 12 बसु, जे के कैथ डी सी रामाराव एम एस बी भारत में मृदा संरक्षण उग्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (लखनऊ) हिन्दी संस्करण।

- 13 Singh M, 'Land Utilization in North-Eastern Uttar-Pradesh an unpublished thesis, 1960, Agra pp 79-80
- 14 Singh R L 'India- A Regional Geography'- 1971, p-204
- 15 Mukerji, R K (1938) 'The Changing face of the Bengal, Calcutta, pp 33-34
- 16 सामाजार्थिक समीक्षा जनपद देवरिया 2001-2002 कार्यालय अर्थ एव सख्याधिकारी देवरिया अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान उत्तर प्रदेश पृष्ठ 6
- 17 सदर्थ 16 पृष्ठ 7
- 18 सदर्थ 16 पृष्ठ 7
- 19 सदर्थ-वही पृष्ठ-7
- 20 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन-2003 प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पृ-32
- 21 Tripathi, R S , 'History of Kannauj to the Muslim conquest', pp 302-324
- 22 सदर्थ 16 पृष्ठ 9
- 23 वही पृष्ठ 8
- 24 वही पृष्ठ-7
- 25 उप्र डिस्ट्रिक्ट गजेटियर देवरिया 1988 पृष्ठ-52
- 26 पार्श्वोद्धृत पृष्ठ-53
- 27 पार्श्वोद्धृत पृष्ठ-53
- 28 उप्र डिस्ट्रिक्ट गजेटियर देवरिया 1988 पृष्ठ-55
- 29 विकास के बढ़ते कदम जनपद देवरिया सूचना एव जनसंपर्क विभाग देवरिया- पृष्ठ-46
- 30 वही पृष्ठ- 46
- 31 वही पृष्ठ- 46
- 32 सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-देवरिया 2001-02 अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान उत्तर प्रदेश पृष्ठ- 14-15
- 33 सदर्थ- 32 पृष्ठ-15
- 34 सदर्थ 32 पृष्ठ- 15-16
- 35 सदर्थ-32 पृष्ठ-16
- 36 सदर्थ 32 पृष्ठ-22-24
- 37 वही पृष्ठ 17
- 38 भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग नई दिल्ली- 1986 पृ 457
- 39 वही पृष्ठ- 458
- 40 मिश्र एस के व पुरी, वी के भारतीय अर्थव्यवस्था' 1991 पृ 867।
- 41 कुरैशी एम एच, 'भारत ससाधन और आर्थिक विकास, एन सी ई आर टी 1998 पृ 102
- 42 वही पृ 101
- 43 Cannon, A M , 'New Railway Construction and the Pattern of Economic Development of East Africa, Transactions', I B C No -36, June 1965 pp 21





अध्याय-तीन

सेवाकेन्द्रों का उद्भव—विकास

3.1 सेवाकेन्द्रों के उद्भव विकास को प्रभावित करने वाले कारक

किसी भी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास में वहाँ की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सेवाकेन्द्र किसी क्षेत्र में अकस्मात् प्रकट नहीं होते बल्कि उस क्षेत्र के भौतिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सम्मिलित रूप में इसके उद्भव एवं विकास को सम्पन्न करते हैं। सेवाकेन्द्र मानव अधिवासों के अभिन्न अंग होते हैं। अतः इनका उद्भव एवं विकास मानव अधिवासों की स्थापना से सम्बन्धित होता है। उपर्युक्त कारकों के बदलते समीकरणों के कारण अधिवासों के महत्व एवं आकार में वृद्धि होती है अथवा वे ह्रास को प्राप्त होते हैं।¹

प्रत्येक पूर्ण विकसित केन्द्र या बड़ा नगर एक छोटी बस्ती या स्थान के रूप में प्रारम्भ होता है जिनका अस्तित्व भिन्न-भिन्न जटिल भौतिक एवं मानवीय कारकों पर आश्रित रहता है। एक बार किसी स्थान पर सेवाकेन्द्र के जन्म ले लेने पर तथा उसके कार्य करने पर अनेक राजनैतिक-ऐतिहासिक तत्व उसकी विकास की अवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए प्रभावित करते रहते हैं।²

इस प्रकार सेवाकेन्द्रों के उद्भव, विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है— **भौतिक** एवं **मानवीय**।

(अ) भौतिक कारक

सेवाकेन्द्र अवश्यमेव एक मानवीय रचना है परन्तु **भौतिक कारक** ही इसके प्रारम्भिक आधार के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतर्गत धरातल का स्वरूप, जल की उपलब्धता परिवहन मार्ग आदि प्रमुख हैं। भौतिक कारक सेवाकेन्द्रों के आधार को निर्धारित करते हैं। इनमें जल की उपलब्धि एक प्रमुख कारक है। जलमार्गों द्वारा स्थानीय यातायात की सुविधा भी मिलती रही है। विशेषकर प्राचीन काल में जब परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं हुआ था। यही कारण है कि, प्राचीन काल में जब वर्तमान बड़े-बड़े केन्द्रों की आधार स्थापना हुयी तो उनको एक छोटी बस्ती या निर्माण के रूप में बहुसुरक्षित प्राकृतिक आधार धरातलों पर बसाया गया और आज भी अधिकांश केन्द्र भिन्न-भिन्न नदियों के किनारे ही प्रायः स्थित पाये जाते हैं।

(ब) मानवीय कारक

धरातल का स्वरूप मृदा जल की उपलब्धि एवं विकास आदि भौतिक कारकों के द्वारा प्राप्त

सुविधाओं या सीमाओं के मूल आधार पर मानवीय कारक प्रतिक्रिया करना प्रारम्भ करते हैं। प्रशासकीय कारक यातायात मार्ग तथा आर्थिक विकास का स्वरूप एवं अवस्था— ये अत्यन्त शक्तिशाली मानवीय कारक हैं। जो केन्द्रों के उद्भव एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। अतएव भौतिक तथा मानवीय दोनों कारक एक दूसरे के पूरक रहे हैं तथा परस्पर समन्वित रूप से कभी पूर्वगामी तथा कभी अनुगामी होकर कार्य करते हैं। सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास के लिए इन कारकों के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ भी उत्तरदायी होती हैं जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

प्रथम— कृत्रिम या प्रशासकीय शक्तियाँ

द्वितीय— प्राकृतिक रूप से क्षेत्र की सामाजिक— आर्थिक आवश्यकताओं के द्वारा स्वतः प्रेरित होकर उत्पन्न शक्तियाँ।

विश्लेषण

प्रशासकीय मुख्यालय या केन्द्र सुरक्षा केन्द्र या स्थल, किले क्षेत्रीय राजधानियाँ महल औद्योगिक आवास स्थल आदि कृत्रिम शक्तियों के परिणाम हैं। दूसरी ओर भिन्न—भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए सेवाकेन्द्रों की स्वाभाविक आवश्यकता भी होती है। ऐसा स्थान सामान्यतया क्षेत्र के केन्द्र में स्थित होता है और उस क्षेत्र के लिए जिसकी आवश्यकताएँ केन्द्र से पूरी होती हैं का मुख्य केन्द्र भी होता है। इन केन्द्रों का जन्म सामान्यतया मेले के स्थान, साप्ताहिक बाजार मंदिर या धर्मस्थल मार्ग केन्द्र इत्यादि के रूप में होता है। इन स्थानों की स्थिति मध्यवर्ती होनी चाहिए तथा परिवहन मार्गों द्वारा सेवाक्षेत्रों से सबद्धता भी होनी चाहिए। जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र को सेवाएँ प्राप्त हो सकें।

सेवाकेन्द्रों के विकास के निम्न प्रेरक तत्व हैं—

(क) विनिमय प्रक्रिया

वस्तुओं एवं आवश्यकताओं का विनिमय एक प्राथमिक आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति के लिए सेवाकेन्द्रों का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त कोई नई बस्ती भी सेवाकेन्द्र के रूप में विकसित हो सकती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जनसंख्या वैयक्तिक रूप से अपनी प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो। इसके लिए बहुगम्य केन्द्र स्थान की आवश्यकता होती है और इस प्रकार एक स्थानीय बाजार की उत्पत्ति हो सकती है। विशेषतः मध्यवर्ती सगम स्थलों पर। एक बड़े प्रदेश में जहाँ सेवाकेन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हों, नये केन्द्र उन्हीं मध्यवर्ती बिन्दुओं पर जन्म ले सकते हैं जो वर्तमान केन्द्रों से काफी दूर सेवा पूर्ति की प्रभावकारी सीमा से बाहर स्थित होते हैं।

(ख) क्षेत्रीय आवश्यकता

क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि या परिवर्तन के साथ-साथ केन्द्र में भी परिणामतः परिवर्तन होना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोणों से अधिक सम्पन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग अधिक तथा ऊँचे किस्म की होती है। इसलिए क्षेत्रीय केन्द्र अधिक सम्पन्नता को प्राप्त होते हैं। जैसे-जैसे केन्द्रीय वस्तुओं की माँग बढ़ती जाती है वैसे-वैसे पुराने केन्द्रों की सेवा क्षमता बढ़ती जाती है या सीमावर्ती बिन्दुओं पर नये केन्द्रों का विकास होता है।

(ग) प्रशासकीय क्रियाएँ

कृत्रिम या प्रशासकीय कारकों का भी कम महत्व नहीं है। ये कारक न केवल कुछ केन्द्रों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं अपितु ये केन्द्रस्थलों के भावी विकास में भी सहायक होते हैं। पहले की प्रशासकीय बस्तियाँ इस समय बड़े केन्द्रों के रूप में विकसित हो गयी हैं। कुछ अन्य केन्द्र राजधानी या मुख्यालय होने के कारण ही समृद्ध हो गये हैं।

(घ) परिवहन सबद्धता

सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास में परिवहन मार्ग (नदी मार्गों को लेकर) एक महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन मार्गों के केन्द्रों पर ही प्रायः वाणिज्य या बाजार केन्द्रों का जन्म होता है। यदि किसी वर्तमान केन्द्र में परिवहन अथवा गमनागमन की सुविधा बढ़ा दी जाती है तो उसकी सेवा क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्र भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं और सेवा प्रदेश का विस्तार हो जाता है। यदि परिवहन के साधन तीव्रतर हैं तो यह दूरी और भी कम हो जायेगी (समय के सदर्भ में)। परिवहन मार्गों एवं साधनों के अभाव में सेवाकेन्द्र और उनके प्रभाव क्षेत्र प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हो सकते।

(ङ) कार्यात्मक आधार

कार्यात्मक आधार भी सेवाकेन्द्रों के विकास का एक प्रेरक तत्व है जो प्रायः सेवाकेन्द्रों के उद्भव के लिए भी उत्तरदायी होता है। प्राचीनकाल के बहुत से केन्द्रों का ह्रास इसलिए हो गया क्योंकि उनकी कार्यात्मक प्रेरणा समाप्त हो गयी। सेवाकेन्द्रों के वृद्धि और उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि वह अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवाएँ प्रदान करता रहे। यदि कोई केन्द्रीय कार्य कृत्रिम या प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा सेवाकेन्द्र में जोड़ा जाता है तब उसका विकास और अधिक तीव्रतर होगा। सेवाकेन्द्रों के विकास के आर्थिक कारकों (मानवीय कारकों सहित) की संख्या दो है—

प्रथम— सेवाकेन्द्रों में वस्तुओं एवं सेवाओं की सेवा पूर्ति की मात्रा तथा क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएँ।

द्वितीय— केन्द्रों और क्षेत्र के बीच की आर्थिक दूरी।

प्राचीनकाल में अधिकांश केन्द्रों का जन्म प्रशासकीय प्रभाव केन्द्रों, धार्मिक स्थानों क्षेत्रीय केन्द्रों तथा राजनैतिक राजधानियों के रूप में हुआ है तथा केन्द्रों को सामाजिक—आर्थिक आधार बाद में प्रदान किये गये। इन केन्द्रों के निर्धारण में मुख्यतः आधार—धरातल और अवस्थिति की भौतिक सीमाओं का प्रभाव रहा है। आधुनिक एवं मध्यकालीन नगरों में से कुछ का जन्म एक विशेष प्रकार की बस्ती निर्माण से हुआ तथा वहाँ पर केन्द्रीय कार्यों का विकास बाद में हुआ।

3.2 अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) में सेवाकेन्द्रों के पुरातात्विक स्थल

पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल से ही मानव अधिवासों का विकास हुआ। आर्यावर्त में स्थित उस क्षेत्र में आर्यकालीन सभ्यता पल्लवित एवं विकसित हुई। प्राचीन काल में यहाँ नदियों के किनारों पर तथा वनाच्छादित भू-भाग के अतर्गत मानव बस्तियाँ बसीं और कालान्तर में सेवाकेन्द्रों के रूप में रूपान्तरित हो गयीं।

ऐतिहासिक काल में अध्ययन क्षेत्र आर्य सभ्यता के *कोशल राज्य* के अतर्गत समाहित था। पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों से सम्बन्धित अनेक पुरातात्विक स्थल मूर्तियों प्रतिमाओं, सिक्कों, ईंटों मंदिरों—मठों के अवशेषों एवं स्तूपों आदि के रूप में पूरे जनपद में बिखरे हुए हैं। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि अपने आरम्भिक काल में यह क्षेत्र सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कर्ष पर था।

कालायिल ने देवरिया गोरखपुर संयुक्त जनपद के सर्वेक्षण के उपरान्त यह मत प्रकट किया था कि इस जनपद में जितने प्राचीन स्थल हैं, उतने इस देश के किसी भी जनपद में नहीं तथापि इसे जनपद का दुर्भाग्य कहे या पुरातत्व के संयोग तत्व की प्रबलता कि यहाँ का पूर्ण ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है।

इस जनपद के निकटवर्ती क्षेत्रों से *नवपाषाणकाल* के अवशेष, लघु पाषाणिक प्रस्तर उपकरण तथा चटाईदार मृदभाण्डों के अवशेषों की प्राप्ति *ताम्राशय संस्कृतियों* से इस क्षेत्र का सम्बन्ध प्रमाणित करते हैं। समीपवर्ती जनपदों से अन्न के जले हुए दानों तथा भूसी युक्त मृदभाण्डों के अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि इस क्षेत्र की संस्कृति का सम्बन्ध लगभग 8000 ई० पूर्व की *विन्ध्य गागेय धान्य संस्कृति* से था और सर्वप्रथम धान की खेती *विन्ध्य क्षेत्र गंगा घाटी एवं सरयूपार* में आरम्भ हुई थी। जनपद के *मदनपुर* से चित्रित धूसर पात्र के अवशेष मिले हैं। *मदनपुर रुद्रपुर तहसील* में *राप्ती नदी* से थोड़ी दूर पर स्थित है। यहाँ *एन वी पी, मृण्मूर्तियाँ* तथा *एक सिली* के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं³। *सलेमपुर तहसील* में *भागलपुर* से 4 किमी पूरब *घाघरा* से थोड़ी दूर पर ग्राम *सहिया* के पास *हन्द पोखर* से *काले लाल मृदभाण्ड* के अवशेष मिले हैं⁴। इसमें सन्देह नहीं है कि पुरास्थलों की दृष्टि से जनपद समृद्ध है लेकिन *मदनपुर* और *हन्द पोखर*

के अतिरिक्त अन्य स्थलो का सम्बन्ध ऐतिहासिक काल की सस्कृतियों से है। रुद्रपुर तहसील मुख्यालय के पास *सहनकोट* या *नाथनगर* में पुरावशेषों का विशाल टीला है, जिसके पूर्वी छोर पर स्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर एवं परिसर में ब्राह्मण धर्म की विभिन्न देव प्रतिमाएँ तथा जैन प्रतिमा हैं⁵। *दयाराम साहनी* ने 1906-7 में यहाँ काले पत्थर की जिस विष्णु प्रतिमा की खोज की⁶ वह गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। इसके अतिरिक्त *फ्यूरर* को यहाँ जैन महावीर एवं गणेश की नृत्य-मूर्ति की सूचना मिली थी।⁷ रुद्रपुर के आस-पास 25 अन्य दैव मंदिरों के ध्वसावशेष भी दृष्टिगोचर हुए थे जिनपर शिवलिंग स्थापित थे।⁸ रुद्रपुर से सटे पश्चिम एक टीले से *कालायिल* को एक खण्डित जैन प्रतिमा मिली थी जिसकी चरण चौकी पर *कुटिल लिपि* में क्षतिग्रस्त एक अभिलेख (तिथ्यांकित स०- 1161) अंकित था।⁹ वहाँ से लगभग 9 किमी दक्षिण-पूरब *बराव* और *समोगर* में भी ध्वसावशेष देखे गये थे।¹⁰ इसी तहसील में *राप्ती- सरयू (घाघरा)* के प्रवाह क्षेत्र में अन्य पुरास्थल भी हैं जहाँ के पुरावशेष धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आज भी *घाघरा* के बाँये किनारे पर *बरहज* के आस-पास *सुरैनाडीह* *सोनवाडीह* तथा *देईडीहा* में प्राक्कुषाण कुषाण मध्यकालीन अवशेष दृष्टव्य हैं। इनमें लाल काले तथा लाल मृदभाण्ड बाउल्स उन्नत गर्दन के पात्र मानव मूर्तियाँ दोंवेदार ईंटे एवं मोटे-भट्टे मृदभाण्ड उल्लेखनीय हैं। स्वयं *बरहज* भी एक पूर्व मध्यकालीन नगर है जहाँ के नीलकण्ड मंदिर में शिव का मुख भाग या लिंग नन्दी तथा नृवराह पूजक की मूर्तियाँ एवं समीप के गेट पर बने मन्दिर में एक विष्णु प्रतिमा के होने की सूचना है। एक लेखक ने यहाँ की नृवराह पूजक प्रतिमा का मूल्यांकन करते हुए यह अनुमान व्यक्त किया है कि *गुर्जर-प्रतिहार* शासक *मिहिरभोज (836-885 ई.)* के *कलचुरि सामंत गुणाम्बोधि देव* ने पहले *बरहज* में अपनी राजधानी बनायी।¹¹ यह भी कल्पना की गयी कि उस कलचुरि सामंत ने अपने स्वामी की उपाधि *आदि बराह* के अनुरूप स्थान का नामकरण *बरहज* किया होगा। लेकिन इस धारणा की अभी अन्यथा पुष्टि नहीं हो पायी है।

जनपद की सलेमपुर तहसील में सलेमपुर से लगभग 4.5 किमी दक्षिण-पश्चिम स्थित *सोहनाग* एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। वर्तमान सदी के आरम्भ में यहाँ जो सर्वेक्षण किये गये उनमें यहाँ के जलाशय के तटवर्ती टीले को स्तूप एवं विहार ध्वसावशेष बताया गया। किन्तु वे पुरातत्वविद् सर्वेक्षण कर्ता बौद्धधर्म एवं साहित्य तथा पूर्वी उत्तर-प्रदेश में स्थित उसके पुरास्थलों की व्यापकता से इतने अभिभूत थे कि उन्हें प्रदेश के अधिकांश ध्वसावशेषों में स्तूप और विहार ही दृष्टिगोचर होते थे। जबकि वास्तविकता उससे परे होती थी। उस समय टीले पर परशुराम मन्दिर शिव मंदिर तथा बौद्ध मूर्तियाँ दृष्टिगोचर हुईं। शिवमन्दिर के काले पत्थर की लिंग प्रतिमा तथा गौरीशंकर की युगल मूर्ति प्रतिष्ठित थी। टीले के निचले भाग में झारखण्डी महादेव के मन्दिर में शिवलिंग व बौद्ध प्रतिमाएँ थी। *फ्यूरर* ने *सोहनाग* को एक रोचक स्थल बताते हुए कहा था कि वहाँ पुरातात्विक खोज की अच्छी संभावनाएँ हैं।¹² *घाघरा* के तट पर स्थित इसी तहसील के *भागलपुर* में लगभग 17' ऊँचे एवं 5' की परिधि वाले गोल एकांशक स्तम्भ पर 10 वीं शताब्दी

की कुटिल लिपि में 21 पक्तियों का एक लेख है जिसकी आरम्भिक तीन पक्तियाँ इस प्रकार हैं।

भुजगागक नाम भूषित विष्णु

वक्ष () स्थलराजि कोस्तुभो विमर्ति रम्योरसि।

सूर्यान्वये दशरथ प्रयितो वभूव ।¹³

इससे मात्र इतनी ही सूचना मिल पाती है कि इस स्तम्भ की स्थापना किसी सूर्यवंशी वैष्णव मतानुगामी राजा ने की थी।

सलेमपुर एव देवरिया के बीच स्थित खुखुन्दू में महत्वपूर्ण प्राचीन नगर के ध्वसावशेष हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं कनिष्क के सर्वेक्षण एव उत्खनन के समय वहाँ कुल 30 टीले थे जिनपर मन्दिर दीवार खचित ईंटों के अवशेष शिव पार्वती— नन्दी गणेश की प्रतिमाएँ लिग—विग्रह विष्णु मूर्तियाँ नवग्रह प्रस्तर खण्ड तीर्थंकर प्रतिमाएँ स्तूप आदि के अवशेष विद्यमान थे। इन्हें देखकर कनिष्क ने कहा था कि नालन्दा को छोड़कर अन्यत्र इतनी पुरासम्पदा नहीं है। उत्खनन में यहाँ से ऐसे अवशेष व अभिलेख मिल सकते हैं जिनसे ब्रह्मण धर्म के विकास पर नया प्रकाश पड़ सकता है। यह वही विशाल ग्राम हो सकता है जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने कसया से बनारस के मार्ग में कसया से 200 ली० (30 मील) दक्षिण—पश्चिम की ओर किया है जहाँ के एक धनी ब्राह्मण ने अपना सारा धन एक बौद्ध सक्षराम के अलकरण में व्यय कर दिया था। चीनी यात्री खुखुन्दू कहाँव भागलपुर होकर घाघरा पारकर बनारस पहुँचा होगा¹⁴ लेकिन कार्लायल ने चीनी यात्री द्वारा वर्णित विशाल ग्राम का समीकरण रुद्रपुर के साथ किया है।¹⁵ जो सही नहीं जान पड़ता। फ्यूरर ने भी प्रकारान्तर से इन पुरावशेषों का उल्लेख किया है यथा— नीले पत्थर की चतुर्भुज विष्णु मूर्तियाँ तथा पाँच अवतार मूर्तियाँ लिग—विग्रह शिव—पार्वती व गणेश की मूर्तियाँ मन्दिरों के प्रस्तर न्यास पुष्पालकृत घुमावदार ईंटों के टुकड़े, आदिनाथ शातिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियाँ आदि।¹⁶ वहाँ फ्यूरर को मूर्ति शिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना भी मिला जिसमें दो नग्न परन्तु विरल आभूषण पहने पुरुष—स्त्री की आसनमुद्रा की युगल मूर्ति थी। स्त्री की बाहों में एक शिशु था। यह युगल मूर्ति वर्धमान महावीर के पिता और माता— नाथ एव त्रिशला की थी।¹⁷ एक विद्वान ने खुखुन्दू को रघुवंशी राजा ककुत्स्थ अथवा पुष्पदन्त नाथ (काकुत्स्थ) की जन्मभूमि एव राजधानी (काकुत्स्थ नगरी—काकन्दी) बताया है और खुखुन्दू के आस—पास पड़लहो, जैतपुरा, मेहजा, दानवपुर, भीष्म नरौली सग्राम नरौली, खेम नरौली महाराजपुर पड़ौली अटहर महवार शुकरीली सुरहा, खीरसर, अवदालपुर मटहर व कुलहा आदि ग्रामों को पौराणिक एव जैन परम्परा का स्मृतिशेष निरूपित किया है।¹⁸ भट्टदोजि दीक्षित के समय भी काकन्दी जनपद प्रसिद्ध था।¹⁹

खुखुन्दू से 11 किमी दक्षिण ग्राम कहाँव से उत्तरी छोर पर एक 34'—3" ऊँचा एकात्मक स्तम्भ तथा कुछ अन्य अवशेष सुविदित हैं। स्तम्भ के आधार एव शीर्ष पर जैन आकृतियाँ तथा मध्य भाग पर गुप्तकालीन ब्राह्मी में 12 पक्तियों का अभिलेख उत्कीर्ण है जिसका प्रयोजन गुप्त सम्राट

स्कन्दगुप्त के शासन काल (स०—141) में मद द्वारा पोंच तीर्थकर प्रतिमाओं के दान का अकन है।²⁰ इस समय इस ग्राम का नाम 'ककुम' था। अन्य पुरावशेषों में कूप ध्वस्त जैन मन्दिर तथा अनेक जलाशय भी उल्लेखनीय हैं। स्वयं गाँव भी विशाल टीले पर स्थित है। कनिष्क के अनुसार कभी यहाँ बोध गया के मन्दिर की शैली के लगभग 30 ऊँचे मन्दिर थे जिनमें तीर्थकरों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित थीं।²¹ यहाँ का उक्त स्तम्भ सिंह शीर्ष से युक्त था। यह वर्गाकार वर्तुलाकार बहुकोणीय आदि विभिन्न ज्यामितीय आकारों में तराशा गया है। इसका निम्नतर भाग अशोक के स्तम्भों की तरह उलटे घटे या कमल पुष्प की तरह है जिसके ऊपर बने वर्गों में दिगम्बर प्रतिमाएँ हैं। इसमें एक ताखे में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है।²² वर्तमान समय में कहाँवाँ गाँव का क्षेत्रफल 244 84 हेक्टेयर है जिसमें 131 परिवार निवासित हैं। इसकी जनसंख्या 845 है।²³ इस प्रकार इतनी कम जनसंख्या घनत्व से विदित होता है कि यह ऐतिहासिक गाँव पुनर्निवासित हो रहा है। इस गाँव को वर्तमान समय में गौरा बरहज तहसील मुख्यालय से पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है जिससे विकास की गति तीव्र हो रही है।

सलेमपुर में ही छोटी गण्डक है बाँए तट पर स्थित मझौली में फ्यूरर ने चार शैव मन्दिर एक गढ़ी तथा राजप्रसाद देखा था।²⁴ जैसा कि स० 1892 के एक दस्तावेज से प्रमाणित होता है। औरंगजेब के समकालीन राजा बोध मल्क के समय में मझौली राज्य की स्थापना हुई थी। मझौली का उल्लेख पटना की एक पत्थर की मस्जिद में लगे एक फारसी अभिलेख में भी हुआ है जिसके अनुसार उस मस्जिद के निर्माण की सामग्री मझौली के एक मन्दिर को ध्वस्त कर उससे तथा एक किले से प्राप्त कर ले जायी गयी थी।²⁵ यहाँ के अन्य पुरावशेषों में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की एक मूर्ति तथा दीर्घेश्वरनाथ महादेव मन्दिर के ध्वसावशेष भी उल्लेखनीय हैं।²⁶

इसी तहसील में जनपद के पूर्वोत्तर छोर पर मैरवा रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किमी उत्तर स्थित दोन बुजुर्ग गाँव के पूर्वी छोर पर जो ध्वसावशेष है उन्हें स्थानीय लोग 'द्रोण का घर' कहते हैं। यहाँ के बहुत से पुरावशेष खोद कर निकाल लिये गए हैं और अब देखने को नहीं मिलते। यहाँ ईंटों की मोटी फर्श भी थी। गाँव भी पूरब की ओर पसरे हुए ध्वसावशेषों के टीले पर बसा है। यहाँ से प्राप्त ईंटों का औसत आकार है। यहाँ से ताम्र और स्वर्णमुद्राओं के मिलने की सूचना भी मिली है। लेकिन वे किसी पुरातत्वेत्ता को देखने को नहीं मिली।²⁷ दोन एव मठिया गाँव के बीच एक खेत से गाहड़वाल नरेश गोविन्द चन्द्र का (वि० 1176—1120) दो ताम्रफलकों पर उत्कीर्ण दान शासन प्राप्त हुआ है।²⁸ जिसका प्रयोजन गोविन्दचन्द्र द्वारा द्रोणायण पड के वत्सगोत्रीय ब्राह्मण दुल्लाइच शर्मा को अलापवत्तल के बड़ग्राम के दान का अकन करना है।²⁹ पालि साहित्य के विभिन्न संस्करणों में उल्लिखित द्रोणग्राम के धूसत्र गोत्रीय ब्राह्मणों³⁰ तथा उक्त अभिलेख में सदर्भित वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के द्रोणायण पड की पहचान इस दोन बुजुर्ग के साथ की जा सकती है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को विभक्त करने वाला द्रोण ब्राह्मण भी इसी ग्राम का

निवासी रहा होगा।

सदर तहसील में देवरिया से लगभग 15 किमी उत्तर *करुना नाले* के पास *भरोली* तथा *बभनी* में ध्वसावशेष मन्दिरों के अवशेष एवं शैव मूर्तियाँ देखी जा चुकी हैं। यहाँ मृत्तिका दुर्ग की प्रतिमा स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई³¹

देवरिया से 7 किमी दक्षिण दक्षिण-पश्चिम स्थित *सुरौली ग्राम* में काफी विस्तार में फैले हुए ध्वसावशेषों का टीला देखा गया। जिसके चतुर्दिक *परिया* को *लक्षित* करते हुए *फ्यूरर* ने यहाँ किसी दुर्ग के अस्तित्व का अनुमान किया था।³²

उपर्युक्त स्थलों के विवेचन से जनपद के अतीत का जो चित्र उभरता है उसमें विभिन्न धर्मों की झोंकी दिखाई पड़ती है। यहाँ *ब्राह्मण बौद्ध* एवं *जैन* तीनों धर्मों का सुन्दर समागम था और उनके प्रभाव से समिश्र समन्वयकारी संस्कृति का विकास हुआ। पूर्व मध्यकाल में यहाँ *शैव धर्म* का प्रभाव बढ़ा जिसका कारण *बौद्ध धर्म* के पतनमुख काल में इस क्षेत्र पर *काशी* की *शैव परम्परा* का प्रभाव रहा होगा। इस दृष्टि से *रुद्रपुर* को *छोटी काशी* भी कहा जा सकता है।

3.3 अध्ययन क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(अ) प्राचीनकाल

अध्ययन क्षेत्र का इतिहास आर्य सभ्यता से प्रारम्भ होता है। *महाराजा मनु* ने मध्य देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके बड़े पुत्र *इक्ष्वाकु* इस क्षेत्र के प्रथम शासक बने तथा *कोशल* राज्य में *इक्ष्वाकु वंश* की स्थापना हुई। इस वंश के विभिन्न पराक्रमी राजाओं यथा— *मान्धाता हरिश्चन्द्र सगर, भगीरथ, दीलीप रघु दशरथ* और *राम* तथा उनके पुत्रों ने इस क्षेत्र पर राज्य किया। *महाभारत काल* में यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के राजा राज्य करते थे जिन्हें *भीम* ने अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। प्राचीन नगर *काहोन* के भग्न अवशेष तथा एक प्रस्तर पर *भीमसेन की लात* की आकृति जनपद से प्राप्त हुयी है। कालान्तर में यह क्षेत्र *मल्लो* के अधीन आ गया। जो *पावा (फाजिलनगर)* एवं *कुशीनारा (कुशीनगर)* से शासन करते थे। *मल्लो* का राज्य गणतन्त्रात्मक था।

ईसा पूर्व छठी शताब्दी में यह *मल्ल* शासित राज्य *कोशल* के सोलह महाजनपदों³³ में से एक हो गया। जिसमें *बुद्ध* के समकालीन *प्रसेनजित* का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व था। *कुशीनगर* एवं *पावा* के *मल्ल भगवान बुद्ध* और *महावीर* के अनुयायी थे।³⁴ *महावीर* यहाँ अक्सर आते रहते थे। कैवल्य प्राप्ति से पूर्व उन्होंने यहाँ अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया था³⁵, जिसे *काशी* और *कोशल* राज्य के अठारह सघटनों (*नौ मल्ल एवं नौ लिच्छवियों*) ने सुना था।³⁶ *भगवान बुद्ध* का इस क्षेत्र पर प्रमुख धार्मिक प्रभाव था जो इस क्षेत्र के *सोहनाग, साहिया, भागलपुर, खुखुन्दू* आदि क्षेत्र में पाए जाने वाले बुद्ध की प्रतिमाओं, मूर्तियों, स्तूपों मठों, टीलों आदि के अवशेषों से स्पष्ट है। *भगवान बुद्ध*

महापरिनिर्वाण के पूर्व बसाढ(बिहार) से कुशीनारा के लिए आते समय पावा मे रुके थे तथा वही पर उन्होंने एक सुनार जाति के चन्द नामक व्यक्ति के यहाँ अपना अंतिम भोजन ग्रहण किया था।³⁷ बुद्ध के निर्वाण के पश्चात यहाँ उनके अस्थियों को लेकर अनेक राज्यों एवं मल्ल शासकों के बीच गभीर विवाद उत्पन्न हो गया। परन्तु द्रोण की मध्यस्थता से सघर्ष टला और अस्थियों को आठ भागों में विभाजित कर प्रत्येक राज्यों को दे दिया गया। इन्हीं अस्थियों के अवशेष पर आठ स्तूपों का निर्माण हुआ जिसमें से दो स्तूप इस जनपद में निर्मित हुए एक कुशीनगर (कुशीनगर जनपद) एवं दूसरा पावा में।

पाँचवीं शताब्दी ई० पूर्व के आरम्भ में मगध के उत्कर्ष के साथ अजातशत्रु के समय में इस क्षेत्र के मल्लों का राजनीतिक ³⁸ महत्त्व कम हो गया। इस समय यह क्षेत्र कोसल और मगध के मध्य एक तटस्थ क्षेत्र (Buffer) के रूप में ही रह गया। चौथी शताब्दी ईसापूर्व में इसपर मगध के शासक महापद्मनन्द के अधीन रहा। इस दौरान मल्ल शासकों ने नन्द की अधीनता स्वीकार कर अपने अस्तित्व को बनाये रखा। 321 ई० पूर्व में चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा नदवश के विनाश और मौर्य वंश की स्थापना के साथ यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन आया। इस समय यहाँ के मल्ल शासकों का सम्बन्ध मौर्य शासकों से मित्रतापूर्ण एवं सम्मानपूर्ण बने रहे। मौर्यवंश के प्रतापी शासक सम्राट अशोक ने उपगुप्त के साथ कुशीनगर की यात्रा की और यहाँ पर दो स्तूपों का निर्माण कराया।

185 ई० पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ मौर्य वंश तथा कुशीनगर एवं पावा के मल्ल शासकों का भी अस्तित्व समाप्त हो गया।³⁹ इसके पश्चात यह क्षेत्र क्रमशः शक और कुषाणों के आधिपत्य में रहा। अध्ययन क्षेत्र में अनेक स्थानों से प्राप्त कुषाण शासकों विम कडफिसस और कनिष्क के सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं।⁴⁰ कनिष्क (78 से 120 ई०) तक इसके क्षेत्र के इतिहास पर परदा पड़ा रहा।

चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना (320 ई०) के साथ यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया। चन्द्रगुप्त द्वितीय (380—415 ई०) के काल में चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान (400—411) इस क्षेत्र में भ्रमण करने आया और कुशीनगर रूका⁴¹। मौर्य शासक कुमारगुप्त ने यहाँ के स्तूपों की मरम्मत कराई इस क्षेत्र से कुमारगुप्त के 16 चोँदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शासन काल में निर्मित काहोन के प्रस्तर स्तम्भ क्षेत्र में दृष्टव्य है।

510 ई० में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् इस क्षेत्र पर भर शासकों का आधिपत्य हो गया। छठी शताब्दी में कनौज के माखिरी शासकों का इस क्षेत्र पर आधिपत्य रहा। माखिरी शासक हर्षवर्धन (606—647 ई०)⁴² के समय यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रही तथा इसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भी देवरिया आया। इसने कुशीनगर का नाम 'कौ-सुल्ह-ना-का' (Kou-Sulh-Na-Ka)⁴³ रखा। हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र विशेषकर कुशीनगर के विकास के लिए

काफी धन देकर विकास किया।⁴⁴ हर्ष की मृत्यु के पश्चात् पुनः केन्द्रीय शक्तियों का हास हुआ और क्षेत्र का इतिहास पुनः **नौवीं** शताब्दी तक अधरे में रहा। इस बीच का क्षेत्रीय इतिहास स्पष्ट नहीं है।

नौवीं शताब्दी में यह क्षेत्र *कन्नौज* के आधिपत्य में चला गया जिस पर *राजा भोज* के शासन काल में इस क्षेत्र पर कल्चुरी राजा *गुनामबोधिदेव* का शासन स्थापित हुआ।⁴⁵

11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के पूर्वी भाग *नवापार (सलेमपुर)* में *बिसेन* का शासन स्थापित हुआ।⁴⁶ बाद में सम्पूर्ण जनपद पर गहडवाल राजा *गोविन्द चन्द्र (1114-1154 ई०)* का आधिपत्य हो गया। इनके नाती *जयचन्द्र* को (1194 ई० में)⁴⁷ *सिहाबुद्दीन गोरी* ने परास्त किया जिससे गहडवाल शक्ति समाप्त हो गयी। इस समय इस क्षेत्र के बिसेन क्षत्रियों ने अपने को सलेमपुर मझौली में स्वतंत्र घोषित कर लिया। परन्तु शेष भाग पर भरो का शासन कायम रहा।

(ब) मध्यकाल

दिल्ली सल्तनत के काल में *सुल्तान दास वंश* और *खिलजी वंश* के शासन काल में इस क्षेत्र पर इनका मामूली नियंत्रण रहा। 1353 में तुगलक शासक *फिरोज तुगलक* के बगाल अभियान (*हाजी इलियास साह के विरुद्ध*) के समय यहाँ के स्थानीय शासकों मझौली के *बिसेन* और गोरखपुर के *उदयसिंह* ने उसे अपना सहयोग प्रदान किया। कालान्तर में यह क्षेत्र *शर्की* शासकों के अधीन रहा पर इस क्षेत्र पर इनका प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रहा। यहाँ तक कि *शेरशाह* तक के काल का भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि उसका इस क्षेत्र पर पूरा नियन्त्रण रहा हो। इस प्रकार **14वीं** शताब्दी तक इस क्षेत्र पर मझौली के *बिसेनो* का प्रभुत्व बना रहा। इसके पश्चिम में इस समय *डोमवारो* का भी अस्तित्व बना रहा। पर **14वीं** शताब्दी के मध्य में *चन्द्रसेन* ने *डोमवारो* को परास्त कर *सतासी राज* की स्थापना की। प्रारम्भ में इनका *बिसेनो* से अच्छा सम्बन्ध बना रहा।⁴⁸ परन्तु बाद में दक्षिण में रुद्रपुर के क्षेत्र को लेकर दोनों में संघर्ष होने लगा जो लगभग एक शताब्दी तक चला।

1556 ई. में *अकबर* के राज्यारोहण के साथ इस क्षेत्र का इतिहास स्पष्ट होने लगता है। इस समय यह सम्पूर्ण क्षेत्र मुगल सत्ता के अधीन था। कालान्तर में *अकबर* के *जनरल फिदाई खान* एवं *राजा मझौली* के बीच संघर्ष हुआ। राजा परास्त हुए। *अकबर* ने इस क्षेत्र *नेवापार* की भूमि को *शेख सलीम चिस्ती* को दान में दे दिया तथा *सलीम चिस्ती* के नाम पर इस क्षेत्र का नाम *सलेमपुर* रखा।⁴⁹ बाद में *अकबर* ने *राजा सतासी* को भी परास्त कर सम्पूर्ण राप्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1572 ई. के आस-पास इस क्षेत्र पर *पयिण्डा मुहम्मद बगश* शासक नियुक्त हुए।

1596 ई. में जब *अकबर* ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से सूबों में विभाजित किया। तो यह क्षेत्र *अवध सूबा* के अंतर्गत *गोरखपुर सरकार* के अंतर्गत आया। इस समय *सिधुआ जोबना*, *सलेमपुर* और *शाहजहाँपुर* इसके परगना बनाए गए। उत्तर-पश्चिम में एक छोटा क्षेत्र *हवेली*

परगना के अधीन लाया गया।

1625 ई में सतासी के राजा बसंत सिंह ने मुगल गवर्नर पर हमला कर के गोरखपुर का स्वतंत्र शासक अपने आपको घोषित किया। यह स्थिति औरगजेब के पूर्व तक बनी रही। इस बीच दिल्ली को कोई राजस्व अदा नहीं किया गया। 1680 ई में काजी खलिल-उल-रहमान गोरखपुर का कलक्टर नियुक्त हुआ। इन्होंने सतासी के राजा को पदच्युत कर सिलहट परगना के रुद्रपुर गाँव में रुद्रपुर नगर की स्थापना किया। 1690 ई में राजकुमार मुअज्जम (बहादुर साह) गोरखपुर आए। इनके सम्मान में एक और परगना मुअज्जमाबाद की स्थापना की गयी।

पुन मुगल शासकों के कमजोर होने एवं पतन होने के साथ क्षेत्रीय सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता बहाल कर ली।

(स) आधुनिक काल

1707 ई में औरगजेब के मृत्यु के समय यह क्षेत्र अवध के अर्तगत गोरखपुर सरकार में सम्मिलित था जिसके अर्तगत वर्तमान के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और बस्ती जिले समाहित थे। जून 1707 ई में जब बहादुरसाह बादशाह बना तब उसने चिनकिलीच खान को गोरखपुर का फौजदार नियुक्त किया जो 1710 ई तक बना रहा⁶⁰। इस दौरान वास्तविक शक्ति स्थानीय राजपूत शासकों के हाथों में ही रही।

सितम्बर 1722 ई में शियाधर्मावलम्बी सहादत खान अवध का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह एक तरह से नाम मात्र का ही सूबेदार था। वास्तव में यह एक स्वतंत्र शासक था। इसके समय में चारों ओर अशांति और अराजकता व्याप्त थी। परन्तु इस दौरान मझौली के राजा ने अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बरकरार रखी।⁶¹ बाद में सुजाउदौला और आसफुदौला के शासनकाल में अवध की शासन व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ।

बाद में अवध के नवाब को कुशासन के आरोप में पदच्युत कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। 1857 ई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भ के साथ ही इस क्षेत्र के विभिन्न तालुकेदार तथा राजाओं ने अंग्रेज सत्ता के विरोध में विद्रोह किया। विद्रोह आरम्भ होने के साथ ही देवरिया तहसील के पैना गांव के जमींदारों ने घाघरा नदी में अनाजों से लदे हुए नावों को घेरना आरम्भ कर दिया। बरहज के थानेदार इसे रोकने में असफल रहे। 5 जून को क्षेत्र में जैसे ही सूचना मिली कि आजमगढ़ में भारतीय फौजे स्वाधीनता सेनानियों के साथ मिल गयी है गोरखपुर के फौजी जवानों ने आजमगढ़ विद्रोह को दबाने के लिए जाने से इकार कर दिया। इस दौरान सतासी और नरहरपुर के राजाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। पैना एवं घाघरा के तटवर्ती गाँवों के जमींदार, नरहरपुर, नगर और सत्तासी के राज्य एवं पाण्डेयपुर के बाबू ने मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ सहयोग का वचन लिया। इस बीच नेपाल के शासक जगबहादुर ने विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को अपनी गोरखा सेना उपलब्ध करा दी। 29 जुलाई

को 3000 गोरखा गोरखपुर में पहुँच गए। हालाँकि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। पर इसके बाद अंग्रेज इस क्षेत्र पर पुनः अपनी शक्ति और शासन नहीं स्थापित कर सके। गोरखा सेनाएँ अनेक बिमारियों से ग्रसित होकर कमजोर होने लगी जिससे स्थानीय प्रतिरोध करने की क्षमता उनमें नहीं थी। जब गोरखा सेनाएँ वापस जाने लगी तो अंग्रेजों ने शासन की बागडोर पुनः *मझौली सतासी बॉसी गोपालपुर तमकुही* के राजाओं को सुपूर्द कर दी और इन्हीं के माध्यम से शासन चलाने लगे।

1887 ई के विद्रोह के पश्चात् शासन की बागडोर ईट इंडिया कम्पनी के हाथ से *ब्रिटिश क्राउन* के हाथ में चली गयी। इसी के साथ गोरखपुर के प्रशासित क्षेत्र को गोरखपुर-देवरिया समेत बनारस डिविजन में शामिल कर दिया गया। 1871 ई में *पडरौना* के शहरी क्षेत्र की स्थापना की गयी तथा *देवरिया शहर* की स्थापना 1892 ई में की गयी।

1885 ई में *भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस* की स्थापना के साथ इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी। देवरिया की जनता ने कांग्रेस के आह्वान पर 1914-1918 ई के प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का भरपूर सहयोग किया।

1920 ई में जब *महात्मा गांधी* ने *असहयोग आंदोलन* आरम्भ किया। देवरिया की जनता ने इसे हृदय से समर्थन दिया। 8 फरवरी 1921⁵² ई को *महात्मा गाँधी* गोरखपुर आए। अगस्त 1921 ई को *लार* में कांग्रेस की एक बड़ी सभा आयोजित की गयी। 17 सितम्बर को *जवाहरलाल नेहरू* देवरिया पहुँचे जहाँ विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस समय सरकार ने धारा 144 को पूरे क्षेत्र में बढा दिया पर सब निस्प्रभावी रहा। इस दौरान विदेशी कपड़ों एवं विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा तथा खादी और गाँधी टोपी लोकप्रिय होने लगा।

13 अप्रैल 1924 ई को *जवाहरलाल नेहरू* दूसरी बार देवरिया आए और लोगों से कांग्रेस के फंड में चढ़ा देने का आह्वान किया।

4 अक्टूबर, 1929 ई को *महात्मा गाँधी* पत्नी *कस्तूरबा* और *जे बी कृपलानी श्री प्रकाश (बनारस)* के साथ देवरिया आये और उन्होंने नागपुर के *झंडा सत्याग्रह* (1923) में लोगों के भारी संख्या में भाग लेने पर उनका धन्यवाद किया।

1930 ई के *नमक सत्याग्रह* के समय देवरिया जनपद में भी *गाँधीजी* के आह्वान पर नमक कानून तोड़ा गया। 13 अप्रैल 1930 को *बाबा राघवदास* के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया।

11, मई 1935 ई को राष्ट्रीय नेता *रफी अहमद किदवई* देवरिया पहुँचे और कांग्रेस की दो दिवसीय सम्मेलन की।

1935 ई के *इंडियन एक्ट* के अनुसार जब कांग्रेस ने विधान सभा के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया तब देवरिया के सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गये।

इसी प्रकार 1940 ई में गॉंधीजी के व्यक्तिगत सत्याग्रह एव 1942 ई के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवरिया की जनता ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। 21 अगस्त को गौरी बाजार सलेमपुर और देवरिया में आन्दोलनकारियों ने टेलीफोन लाइनो को काटकर रेलों की पटरियों को उखाड़कर सड़कों को क्षतिग्रस्त कर एव पुलों आदि को तोड़कर अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए।

1945 ई में जब द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने लगा। तब ब्रिटिश जनता का विचार भी भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने का बनने लगा।

1946 ई में देवरिया गोरखपुर से अलग होकर स्वतंत्र जनपद का अस्तित्व प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 ई को देश वर्षों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया। पर इसी के साथ देश को विभाजन की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। करीब 533 विस्थापित पाकिस्तानी जनपद में आए और बसे।

30 जनवरी 1948 ई को जनपद में जैसे ही ये खबर आयी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गयी है देश के साथ सारा जनपद स्तब्ध और शोकाकुल हो गया।

स्वतंत्रता के पश्चात विकास की गति तीव्र हुई जिससे अनेक सेवाकेन्द्रों का विकास होता गया।

3.4 ऐतिहासिक कालक्रम में देवरिया जनपद में सेवाकेन्द्रों का उद्भव विकास

अध्ययन क्षेत्रों में विद्यमान सेवाकेन्द्रों का उद्भव एव विकास विभिन्न काल क्रमों में हुआ जिसे निम्नलिखित चार प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है (चित्र- 3.1)।

- 1 प्राचीन काल
- 2 मध्य काल
- 3 आधुनिक काल
- 4 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्।

(अ) प्राचीन काल

ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित था। भरत के प्राचीनतम राज्य कोशल का एक भाग होने के कारण यहाँ पर कई सेवाकेन्द्र विकसित हुए जिनके अब मात्र भग्नावशेष ही दृष्टव्य हैं। इन प्राचीनतम केन्द्रों⁵³ में लार सोहनाग खुखुन्दू साहिया भागलपुर बैरौनाखास (चित्र 3.1A) आदि प्रमुख हैं। खुखुन्दू प्राचीनतम सेवाकेन्द्र है जिसका विकास ऐतिहासिक काल में हुआ यहाँ पर उत्खनन से बौद्ध, जैन एव हिन्दू मंदिरों, मूर्तियों एव प्रतिमाओं के भग्नावशेष, स्तूप, टीले आदि प्राप्त हुए हैं।

इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने राज्य के सुचारु संचालन व्यवस्था हेतु अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न

ORGIN & EVOLUTION OF SERVICE CENTRE IN DEORIA DIST

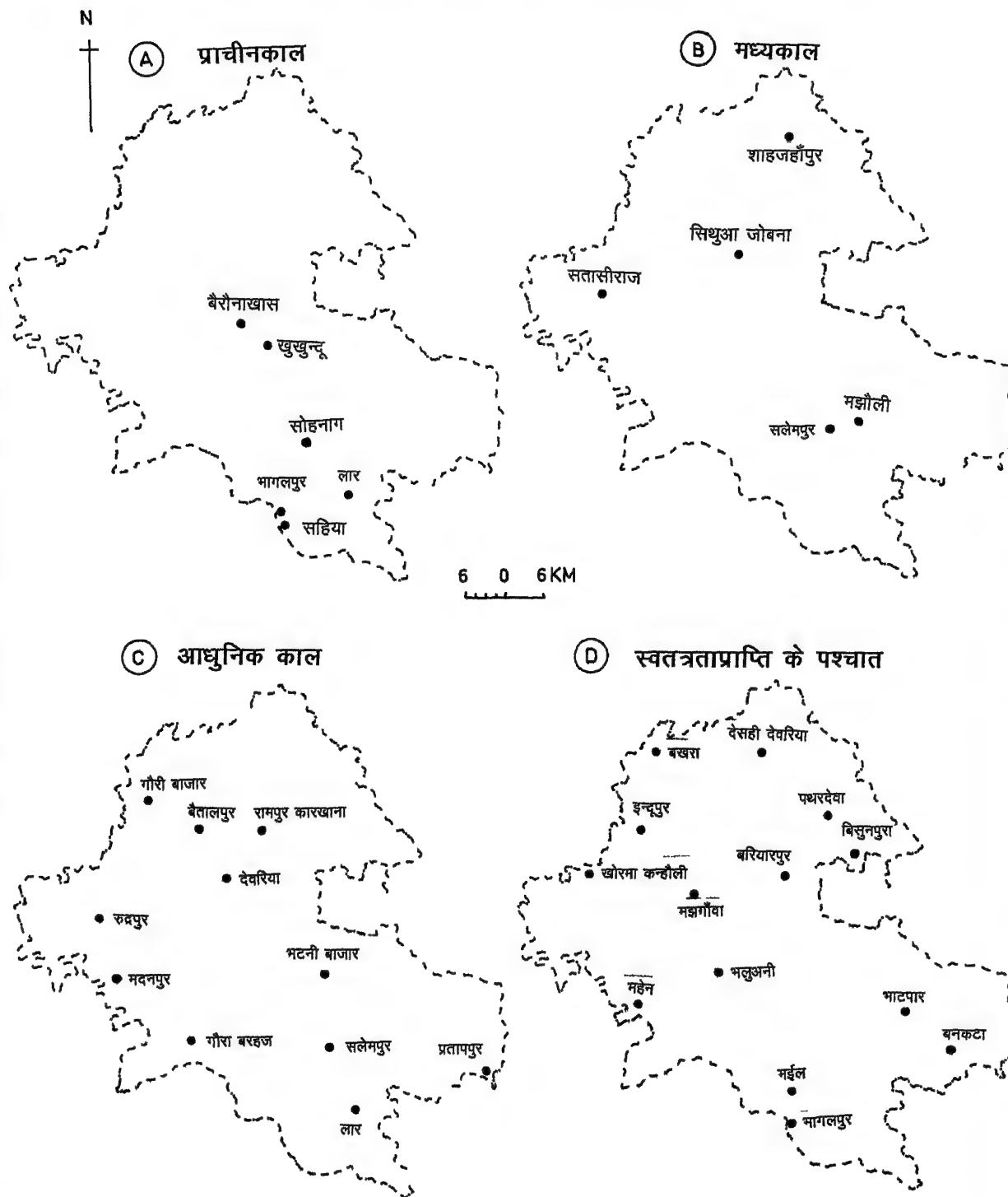


FIG 31

प्रकार के प्रशासनिक केन्द्र स्थापित किये जिनके भग्नावशेष विद्यमान हैं। इस सबध में विभिन्न किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। *भगवान राम* ने अपने राज्य का विभाजन पुत्रों में किया तो *कुश* ने *कुशीनगर* को अपनी राजधानी बनायी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम *कुशीनगर* पड़ा। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इन्होंने विभिन्न सेवाकेन्द्रों का निर्माण किया।

अध्ययन क्षेत्र में स्थित *काहोन* का उद्भव *महाभारत काल* में हुआ था। यहाँ के भग्नावशेषों में प्राचीन तथ्य छिपे हुए हैं। यह प्राचीन काल का एक समृद्ध केन्द्र रहा है। *महाभारत काल* में *युद्धिष्ठिर* ने राजसूय यज्ञ के दौरान इस केन्द्र को अपने अधीन किया और अनुज *भीम* को सौंप दिया। *भीम* ने इसे अपनी राजधानी बनाया।

वर्तमान *रुद्रपुर* की स्थापना भी प्राचीन काल में ही हुई थी। यहाँ प्राचीन सेवाकेन्द्र के अवशेष भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस केन्द्र का विकास *राप्ती नदी* के किनारे जल की उपलब्धता के कारण हुआ था। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग एवं काले पत्थर पर बनी भगवान विष्णु की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में यह धार्मिक दृष्टि से समृद्धतम सेवाकेन्द्रों में एक था।

(ब) मध्यकाल

अध्ययन क्षेत्र में मध्यकाल *दिल्ली सल्तनत* के साथ 11वीं शताब्दी से माना गया है। इस काल में यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा जिससे आवश्यकता तथा सुविधानुसार सेवाकेन्द्रों का विकास एवं महत्व बदलता रहा (चित्र 3 1B)। मध्यकाल में इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों का प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रहा क्योंकि यह क्षेत्र घना वनावरण होने के कारण इसके अनुकूल नहीं था। फलतः यहाँ विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जल सुविधा जो *राप्ती* एवं *घाघरा* नदियों द्वारा उपलब्ध था तथा इन्हीं नदियों द्वारा परिवहन एवं व्यापार की सुविधा के कारण इन नदी तटों के किनारे विभिन्न सेवाकेन्द्रों का उद्भव एवं विकास हुआ। इनमें *बिसेन* राजाओं द्वारा *घाघरा नदी* के किनारे *मझौली राज* की स्थापना तथा पश्चिम में *रुद्रपुर* में *राप्ती* के किनारे *सतासी राज* की स्थापना प्रमुख सेवाकेन्द्र थे। उपर्युक्त नदियों के किनारे अधिवासों का विकास हुआ। मध्यकाल में *सिधुआ जोबना सलेमपुर शहजहाँपुर* प्रमुख सेवाकेन्द्र रहे हैं। ये तीनों ही प्रशासनिक एवं व्यापारिक सेवाकेन्द्र थे। *सिधुआजोबना*, *सलेमपुर* और *शाहजहाँपुर* का विकास *अकबर* के काल में परगना के मुख्यालय के कारण हुआ। इसमें *सलेमपुर* *मझौली* के *बिसेन* राजाओं का प्रशासनिक केन्द्र रहा है। *रुद्रपुर* का विकास एक धार्मिक प्रशासनिक एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में हुआ। अध्ययन क्षेत्र का *रुद्रपुर* नगर अपने आरंभिक काल से ही प्रशासनिक धार्मिक एवं व्यापारिक दृष्टि से एक सम्पन्न क्षेत्र एवं केन्द्र रहा है। यहाँ *सतासी राज* के राजाओं का प्रशासनिक मुख्यालय था। *औरंगजेब* की मृत्यु के पूर्व (1690 ई.) जब *मुअज्जम (बहादुर शाह)* अध्ययन क्षेत्र में आए तो उनके सम्मान में एक और परगना *मुअज्जमाबाद*

की स्थापना की गई।

(स) आधुनिक काल

अध्ययन क्षेत्र में इस काल का आरम्भ 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के साथ हुआ। अपने आरम्भिक काल में यह क्षेत्र *मराठों* के प्रभाव में रहा। 1761 ई में *पानीपत युद्ध* में मराठों की पराजय के पश्चात् *अवध के नबाबों* के अधीन यह क्षेत्र आ गया। नवाबों एवं क्षेत्र के स्थानीय राजपूत राजाओं में विभिन्न समयों में युद्ध चलता रहा। इसके पश्चात् क्षेत्र *अंग्रेजी शासकों* के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता सुविधानुसार कलकटरी कचहरी जेल कोतवाली नगरपालिका तहसील मुख्यालय अस्पताल शिक्षण संस्थाओं आदि को निर्मित कराया। अनेक व्यापारिक केन्द्रों का उद्भव इस काल में हुआ जिससे विकास की गति मिली (चित्र— 31 C,D,)।

इस समय *देवरिया शहर* की स्थापना एक प्रशासनिक केन्द्र के रूप में 1892 ई में की गयी। इसके साथ ही यहाँ पर कचहरी कोतवाली शिक्षण केन्द्रों आदि की भी स्थापना हुई। स्वतंत्रता काल में यह क्षेत्र विशेषकर देवरिया आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र रहा। यहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं का आगमन बराबर होता रहा। *महात्मा गांधी कस्तुरबा गोंधी, जे बी कृपलानी, श्रीप्रकाश रफी अहमद किदवई जवाहर लाल नेहरू* आदि नेताओं का आगमन देवरिया में कई बार हुआ।

1946 ई में जब *देवरिया* को गोरखपुर से अलग कर एक स्वतंत्र जनपद का स्वरूप प्रदान किया गया तो तत्कालीन समय में इसमें *हाटा पडरौना देवरिया* एवं *सलेमपुर* चार तहसील थीं। ये तहसील मुख्यालय प्रमुख प्रशासनिक एवं व्यापारिक सेवाकेन्द्रों के रूप में विकसित हो गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारत सरकार का ध्यान पिछड़े क्षेत्रों के विकास की तरफ गया तो अध्ययन क्षेत्र में स्थित कई बड़े-बड़े ग्राम जहाँ साप्ताहिक बाजार और मेले लगते थे तथा रेलवे लाइन एवं सड़क मार्ग के करीब थे सेवाकेन्द्र के रूप में विकसित हुए। सेवाकेन्द्रों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना, सड़कों का विकास तथा वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना रही है जिससे विभिन्न प्रशासनिक, व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्धित केन्द्र प्रकाश में आए (चित्र 31 C,D)।

1951 ई में तत्कालीन देवरिया जनपद के चारों तहसीलों (देवरिया, सलेमपुर हाटा पडरौना) में 29 प्रखण्ड विकास केन्द्रों की स्थिति थी, जिसमें से बाद में हाटा एवं पडरौना तहसीलों को मिलाकर *कुशीनगर जनपद* की स्थापना की गई यदि इनके प्रखण्डों को अलग कर दिया जाय तो वर्तमान देवरिया जनपद में 1951ई में 15 प्रखण्ड विकास केन्द्र थे। ये निम्नवत् थे—

- | | |
|------------------|---------------|
| 1— देवरिया | 8 सलेमपुर |
| 2 बैतालपुर | 9 भागलपुर |
| 3 गौरीबाजार | 10 भाटपाररानी |
| 4 रुद्रपुर | 11 बरहज |
| 5 देसही देवरिया | 12 भलुअनी |
| 6 पथरदेवा | 13 भटनी |
| 7 रामपुर कारखाना | 14 बनकटा, और |
| | 15 लार |

(क) प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना

स्वतंत्रता पश्चात् वर्तमान अध्ययन क्षेत्र में 15 विकास खण्डों की स्थापना की गई जिसका प्रभाव सेवाकेन्द्रों के विकास पर पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सेवाकेन्द्रों की स्थापना करनी थी जो उस क्षेत्र की सेवा करने में तत्पर हों।¹⁴ इसलिए अधिकांश विकासखण्ड मुख्यालय नगरीय क्रियाकलापों से कुछ दूर स्थापित किये गये। इस प्रकार इन प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना से उस स्थान के विकास में सहायता मिली।

(ख) पक्की सड़कों का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तीव्रगति से पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। इससे ऐसे केन्द्र जो समुचित परिवहन अभाव के कारण सुसुप्त पड़े थे वे इन सड़कों के विकास से जागृत होकर विकसित हुये। इससे नये केन्द्रों की भी उत्पत्ति हुई। चूँकि यहाँ का धरातलीय स्वरूप समतल है अतः सड़क मार्ग के निर्माण के लिए उपयुक्त है। क्षेत्र के दक्षिणी भाग राष्ट्रीय धाधरा तथा उसकी सहायक नदियों से उत्पन्न बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसी के साथ अध्ययन क्षेत्र के मध्य का भाग भी छोटी गण्डक एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्पन्न बाढ़ से प्रभावित रहता है। अतः इन क्षेत्रों में पक्की सड़कों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् छोटी नदियों पर पुल निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिला तथा बसों, ट्रकों, टैक्सियों के गमनागमन से इन सड़कों पर नये सेवाकेन्द्रों के उद्भव के साथ ही पूर्व स्थित सेवाकेन्द्रों का विकास भी हुआ।

(ग) वस्तु निर्माण उद्योग एवं व्यापार का विकास

रेल एवं सड़क मार्ग के विकास के साथ-साथ व्यापार एवं वाणिज्य केन्द्रों का विकास द्रुतगति से हुआ। देवरिया जनपद की समतल एवं उर्वर भूमि गन्ना की कृषि के लिए विशेष उपयुक्त है, जिससे यहाँ के फसल संयोजन में गन्ना की प्रमुखता है। स्वतंत्रता पूर्व सड़कों एवं रेल लाइनों के विकास के साथ यहाँ पर गन्ना पर आधारित चीनी मिलों का संकेन्द्रण आरम्भ हुआ और स्वतंत्रता पश्चात् आधारभूत सेवाओं के विस्तार के साथ इसकी गहनता बढ़ती गयी। फलस्वरूप चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से यह जनपद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ गया। इन चीनी मिलों की स्थापना के स्थल सेवाकेन्द्र के रूप में विकसित हो गये। वर्तमान समय में इस जनपद के अंतर्गत गौरीबाजार बैतालपुर देवरिया, भटनी तथा प्रतापपुर, सेवाकेन्द्रों का विकास चीनी मिलों की स्थापना के कारण ही हुआ है। यहाँ ये उल्लेख करना समीचीन होगा कि देवरिया नगर की स्थापना अन्य चारों सेवाकेन्द्रों के पूर्व हो चुका था। देवरिया नगर के विकास में चीनी मिल के साथ प्रशासनिक कारण भी उत्तरदायी हैं।

अपने चतुर्दिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु सेवाकेन्द्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना, सेवाकेन्द्रों के विकास का प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि अपने क्षेत्र की सेवावृत्ति के अभाव में कोई भी केन्द्र सेवाकेन्द्र की परिसीमा में नहीं आ सकता।¹⁵ अतः वस्तु-विनिमय एवं व्यापार ने

सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास में सबसे शक्तिशाली कारक के रूप में कार्य किया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देवरिया जनपद प्राचीनकाल से ही मानव बसाव का केन्द्र रहा है। कोशल राज्य के प्रभाव में होने के कारण यहाँ पर प्राचीन नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। क्षेत्र में बहने वाली घाघरा राप्ती एवं छोटी गण्डक नदियों जल के साथ-साथ व्यापार के लिए परिवहन मार्ग भी प्रदान करती थी। अतः इनके किनारे ही क्रम से अधिवास एवं कस्बों का विकास हुआ जिसमें अधिकांश कालान्तर में सेवाकेन्द्रों का रूप ले लिए। बौद्धकाल के स्तूप मठ एवं मूर्तियाँ भग्नावशेष के रूप में आज भी दृष्टव्य हैं। अंग्रेजों के अधीन आने पर यहाँ *म्युनिसिपल बोर्ड* की स्थापना हुई जिससे सामाजिक ढाँचे में तेजी से परिवर्तन होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ढाँचागत विकास के कारण सेवाकेन्द्रों का तीव्रगति से विकास हुआ तथा कुछ नवीन सेवाकेन्द्र भी अस्तित्व में आये।

3.5 ऐतिहासिक कालावधि में उत्पन्न सेवाकेन्द्रों के प्रकार

ऐतिहासिक कालावधि में कालक्रम के विकास के साथ विभिन्न प्रकार के सेवाकेन्द्रों का उद्गम एवं विकास हुआ। उनमें से कुछ समय के साथ ही विलीन हो गये तथा कुछ आज भी जिंदा हैं। इन सेवाकेन्द्रों को निम्न प्रकारों में बाँटा जा सकता है—

- (क) प्रशासनिक सेवाकेन्द्र
- (ख) व्यापारिक एवं यातायात सम्बन्धी सेवाकेन्द्र
- (ग) धार्मिक सेवाकेन्द्र

(क) प्रशासनिक सेवाकेन्द्र

अध्ययन क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का श्रीगणेश हुआ था तथा मध्य काल में अनेक प्रशासनिक केन्द्रों का उद्भव एवं विकास हुआ, जो विभिन्न राजवंशों द्वारा स्थापित किये गये। ये प्रशासनिक केन्द्र निम्न थे (चित्र 3.2 A)।

(i) सहनकोट

यह रुद्रपुर के समीप स्थित है जो कभी *नाथनगर* के नाम से जाना जाता था। यह अत्यन्त समृद्धिशाली नगर था। सहनकोट नामक किला तथा नाथ नगर वर्तमान रुद्रपुर से पौन मील उत्तर है। किला सहनकोट की उत्तरी सीमा दो हजार फीट से दो हजार पॉंच सौ फीट तक है। किले के किनारे की दीवारें 15 से 25 फीट तक ऊँची हैं। सहनकोट नामक इस गढ़ को *काशीराज ब्रह्मा* ने बनवाया था। रुद्रपुर के लोग इस जगह को '*हसतीर्थ*' कहते हैं। चीनी यात्री *ह्वेनसांग* यहाँ आया था और इस स्थान को *हसतीर्थ* बताया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सहनकोट का शुद्ध नाम *शकुनकोट* है जिसे *राजा शकुनदेव* ने बनवाया था। परन्तु राजा शकुनदेव के राज्यकाल के

विषय में इतिहासवेत्ता एकमत नहीं हैं।

(II) सुरौली

यह वर्तमान में एक गाँव के रूप में है जो देवरिया से 7 किमी दक्षिण दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यहाँ फ्यूरेर ने काफी विस्तार में फैले हुए टीला का ध्वसावशेष खोजा है जो कभी प्रशासनिक केन्द्र रहा होगा। यहाँ किसी दुर्ग के अस्तित्व का भी अनुमान किया था।

(III) मझौली

यह मध्यकाल में एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था। सलेमपुर तहसील में छोटी गडक के बाँए तट पर स्थित इस केन्द्र की स्थापना सन् 1100 ई में बिसेन सिंह ने नवापार के पास की। 1114 ई से 1154 ई तक इस जनपद पर गहडवाल शासक गोविन्द चन्द्र का नियंत्रण था। 1194 ई में गहडवाल शासन के पराभव के बाद बिसेन क्षत्रियो ने सलेमपुर मझौली में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली।

(IV) रुद्रपुर

यह सतासी राज की राजधानी के रूप में एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था जो आज तहसील मुख्यालय के रूप में विद्यमान है। देवरिया जनपद के दक्षिण-पश्चिमांचल में स्थित रुद्रपुर का इतिहास बहुत पुराना और गौरवपूर्ण है। ऐतिहासिक शोधों के अनुसार रुद्रपुर का उद्भव ईसा के 17वीं शताब्दी के पूर्व माना जाता है। लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराज मझौली ने अपनी पुत्री दिगराज कुँवरी का विवाह कश्मीर के राजघराने के किसी राजकुमार से कर दी। कश्मीर के राजघराने द्वारा इस सम्बन्ध को मान्यता न मिलने के कारण राजकुमार और कुवरी वापस लौट आये। महाराजा मझौली ने अपने ही राज्य में सतासी ग्राम देकर उन्हें राजा बना दिया। यही रियासत 'सतासी राज्य' के नाम से प्रसिद्ध हुयी जो वर्तमान में रुद्रपुर की सज्ञा धारण किए हुए है। आरम्भ में अयोध्या से आए हुए राजपूत वशिष्ठ सेन ने इस स्थान पर एक किले का निर्माण कराया और नामीकाशी नाम दिया। सन् 1605 ई में श्रीनेत् वशीय राजा रुद्रसेन ने पुराने किले के स्थान पर नया किला बनवाया। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम रुद्रपुर पड़ा।

(V) सलेमपुर

मध्यकाल में यह भी एक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र था। इसके विषय में दो मत लोक में प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार मझौली राज की शूरता और स्वत्व की गाथा के कारण तत्कालीन मुगल शासक ने मझौली के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने तथा नाम बदलने को मजबूर किया और इनका नाम 'सलीम' रखा। जब रानी को ये बात मालूम हुयी तो उन्होंने सलीम को अपनाने से इनकार कर दिया। क्षोभवश राजा छोटी गण्डक के किनारे एक नगर बसाकर रह गये जो बाद में सलेमपुर के नाम से मशहूर हुआ। दूसरे मत के अनुसार शेख सलीम चिस्ती के नाम पर इसका नाम पड़ा, जिसे मुगल बादशाह ने चिस्ती को दान में दिया था।

MAIN SERVICE CENTRE OF HISTORICAL PERIOD

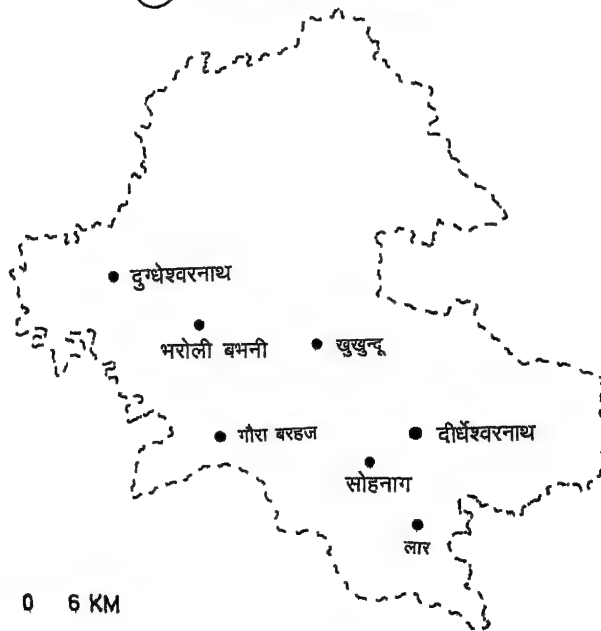
(A) प्रशासनिक सेवाकेन्द्र



(B) व्यापारिक एव यातायात सम्बन्धी सेवाकेन्द्र



(C) धार्मिक सेवाकेन्द्र



6 0 6 KM



FIG 3 2

(VI) काहोन

यह एक अत्यन्त प्राचीन महाभारतकालीन नगर है जो आज भी गौराबरहज तहसील मुख्यालय के नजदीक खुरबुन्दू से 11 किमी दक्षिण में स्थित है। आज यह एक पुनर्जीवित गाव के रूप में है जिसकी जनसंख्या घनत्व अत्यल्प है। इसका उद्भव महाभारत काल में हुआ था। यहाँ के भग्नावशेषों में प्राचीन तथ्य छुपे हुए हैं। यह प्राचीन काल का एक समृद्ध प्रशासनिक केन्द्र रहा है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान इस केन्द्र को अपने अधीन किया और अनुज भीम को सौंप दिया। भीम ने इसे अपनी राजधानी बनाया।

(ख) व्यापारिक एवं यातायात सम्बन्धी सेवाकेन्द्र

प्राचीन एवं मध्यकाल में जलपरिवहन यातायात के प्रमुख साधन के रूप में थे। इस समय नदी मार्गों से ही यातायात एवं व्यापारिक कार्य सम्पन्न किये जाते थे। फलतः नदियों के किनारे अनेक सेवाकेन्द्रों का उद्भव एवं विकास हुआ। अध्ययन क्षेत्र में मध्य भाग में छोटी गण्डक के किनारे तथा दक्षिण में राप्ती एवं घाघरा नदियों के तटों पर इस प्रकार के अनेक सेवाकेन्द्रों का विकास हुआ। इनमें निम्न प्रमुख हैं— (चित्र 32 B)।

(I) सहिया

सलेमपुर तहसील में भागलपुर से 4 किमी पूरब घाघरा से थोड़ी दूरी पर यह एक गाँव के रूप में स्थित है। यहाँ से प्राचीन काल के काले लाल मृद भाण्ड हिन्द पोखर से प्राप्त हुए हैं जिससे अनुमान है कि अति प्राचीन काल में यहाँ कोई नगर था जो व्यापारिक केन्द्र रहा होगा।

(II) बैकुण्ठपुर

जनपद के पूर्वी छोर पर बिहार की सीमा के अति निकट छोटी-गण्डक के तट पर नितान्त ग्रामीण अंचल में बैकुण्ठपुर गाँव अवस्थित है। नूनखार रेलवे स्टेशन से तीन किलोमीटर उत्तर एवं देवरिया जनपद मुख्यालय से पूरब इसकी दूरी 15 किमी है। प्राचीन समय में यह गाँव खाद्यान्नों का व्यावसायिक केन्द्र रहा। उस समय यातायात के समुचित साधन पर्याप्त उपलब्ध न होने के कारण अनाजों का आयात नदियों के मार्ग से बड़ी नावों द्वारा होता था। व्यापार में तिलहन की प्रमुखता थी।

(III) कहाँव

यह प्रशासनिक के साथ-साथ एक प्रमुख व्यापारिक सेवाकेन्द्र भी रहा है। सलेमपुर शहर से दक्षिण-पश्चिम स्थित इस स्थल में गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त के शासनकाल का एक स्तम्भ खड़ा है। इस पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि जैन धर्मानुयायी मद्र नामक व्यापारी ने यहाँ पोंच जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्तम्भ के निचले भाग में निर्मित करायी थी। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में यह स्थल व्यापार का केन्द्र था अथवा व्यापारिक मार्ग पर स्थित था।

(IV) खुखुन्दू

कहाँव से उत्तर देवरिया मुख्यालय से दक्षिण-पूर्व में 16 किमी की दूरी पर यह स्थल स्थित

है। प्राचीन काल में यह स्थल मार्ग द्वारा कहोंव और भागलपुर से जुड़ा था जिस कारण व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग खुखुन्दू कहोंव भागलपुर होकर ही घाघरा पारकर बनारस पहुँचा था।

(v) भागलपुर

कहोंव से दक्षिण थोड़ा पूरब हटकर भागलपुर सरयू नदी (घाघरा) के तट पर स्थित है। प्राचीन समय में नदी परिवहन की प्रमुखता के समय नदी तट पर यह प्रमुख यातायात एवं व्यापारिक केन्द्र था। सड़क मार्ग द्वारा यह कहोंव और खुखुन्दू से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ एक खण्डित स्तम्भ पाया गया है जिसे आज भी लोग भीम की छड़ी कहते हैं। वस्तुतः वह गुप्तों के प्रशासन काल में हूणों शकों के आक्रमण पर बिजय प्राप्ति के स्मारक के रूप में गुप्तों के विजयी सेनापति भीमसेन द्वारा बनवाया गया था। क्षेत्रीय किवदंतियों ने स्तम्भ के नाम को दूसरे रूप में उजागर किया।

(vi) बरहज

घाघरा के तट पर स्थित बरहज एक पूर्व मध्यकालीन नगर है। नदी मार्ग से यातायात के समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहा है।

(ग) धार्मिक सेवाकेन्द्र

‘देवरिया’ नाम से ही स्पष्ट है कि यह जनपद अपने अति प्राचीन काल से ही धार्मिक सेवाकेन्द्रों का सर्वप्रमुख स्थल रहा है। ‘देवरिया’ नाम स्वयं में ही आध्यात्मिक है क्योंकि इस भू-भाग पर विद्यमान ‘देवरही शक्ति पीठ’ के कारण ही इस जिले का नाम ‘देवरिया’ रखा गया। यहाँ पर हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का समन्वय देखने को मिलता है। ऐतिहासिक कालक्रम में इन धर्मों से सम्बन्धित विभिन्न स्थल रहे हैं। जिनमें निम्न प्रमुख हैं— (चित्र-32 C)।

(i) खुखुन्दू

देवरिया मुख्यालय से दक्षिण-पूर्व में 16 किमी की दूरी पर स्थित खुखुन्दू में ब्राह्मण व्यवस्था के अनेक अवशेष होने के साथ ही साथ एक प्रमुख जैन तीर्थकर उषोदन्त का जन्म स्थल भी है। इस स्थान के पास अनेक ब्राह्मण मन्दिरों के अवशेष मिले हैं। ब्राह्मण मन्दिरों में शिव-पार्वती, गणेश और चतुर्भुज विष्णु की नीले पत्थरों की मूर्तियाँ मिली हैं। इन सबसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में यह स्थल प्रमुख धार्मिक सेवाकेन्द्र रहा है।

(ii) सोहनाग

सलेमपुर तहसील में सलेमपुर से 4.5 किमी दक्षिण-पश्चिम में सोहनाग स्थित है। इसका सम्बन्ध भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है। यहाँ एक बड़ा पोखरा है जिसके सम्बन्ध में लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से चर्मरोग दूर हो जाते हैं। इस पोखरे के पश्चिम में एक टीला है। टीले पर परशुराम मन्दिर, शिव मन्दिर तथा बौद्ध मूर्तियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं। नाम के विषय में ये मत लोक में प्रचलित है कि कभी नेपाल के राजा सोहन अपने लश्कर के साथ देशाटन पर

यहाँ आए थे। यहाँ के पोखर में स्नान करने पर उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उन्हीं के नाम पर स्थान का नाम *सोहनाग* हो गया।

(III) लार

वर्तमान समय में यह जनपद के दक्षिणी-पूर्वी छोर पर स्थित है। यह एक प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार *महर्षि वशिष्ठ* की एक गाय को लेकर एक बाध यहाँ चला आया था जो *लार* में मिली और जिसकी पहचान उसके द्वारा गिराए हुए लार से हुई थी। इसी कारण इस स्थान विशेष का नाम *लार* पड़ा।

(IV) बरहज

सरयू तट पर स्थित बरहज आरम्भ से ही एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्र रहा है। यह एक पूर्व मध्यकालीन नगर है जहाँ के नीलकण्ठ मन्दिर में शिव का लिंग नन्दी तथा नृवराह पूजक की मूर्तियाँ एवं समीप के गेट पर बने मन्दिर में एक विष्णु प्रतिमा के होने की सूचना है। इस नगर को *अनन्त महाप्रभु* की साधना स्थली माना जाता है। जिन्हें *ओकार सिद्धी* प्राप्त थी। *बरहज* के चार अक्षर क्रमशः *बद्रीनाथ रामेश्वरम हरिद्वार* और *जगन्नाथपुरी* का कुछ-कुछ बोध कराते हैं ऐसी मान्यता है।

(V) भरोली-तथा बमनी

सदर तहसील में देवरिया से लगभग 15 किमी उत्तर *करुना नाले* के पास स्थित इस स्थल से ध्वसावशेष मन्दिरों के अवशेष एवं शैव मूर्तियाँ देखी जा चुकी हैं। जिससे प्राचीन काल में इसके धार्मिक सेवाकेन्द्र के रूप में होने का आभास मिलता है।

(VI) दीर्घेश्वरनाथ

हिरण्यावती (छोटी गण्डक) के बाँए किनारे पर स्थित विश्वसेवो का राज्य केन्द्र *मध्यपल्ली (मझौली)* के पूर्वी हिस्से पर अवस्थित दीर्घेश्वर नाथ मंदिर आज भी अपने अतीत के गौरव को अपने पार्श्व में समेटे पूर्वांचल को शिव का सन्देश सुना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे *पर्यटन केन्द्र* के रूप में घोषित किया है।

(VII) दुग्धेश्वरनाथ

श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर जिसे *हसतीर्थ* की सजा दी जाती है पूर्वांचल के प्रमुख तीर्थों में एक है। यह मंदिर वर्तमान रुद्रपुर कस्बे से लगभग 2 किमी उत्तर में स्थित है। श्री दुग्धेश्वरनाथ उपज्योतिर्लिंग के विषय में अनेक किवदंतियाँ लोक में प्रचलित हैं। बौद्ध धर्म के अवसान के समय *जगद्गुरु शंकराचार्य* द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी, उसके बाद द्वादश उपज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई जिसमें दुग्धेश्वरनाथ का अतिमहत्वपूर्ण स्थान है।



References

- 1 तिवारी रामचन्द्र अधिवास भूगोल (1997) पृ०- 17
- 2 Singh, O P (1973) 'Central Place and their Origin and Evolution', U B B P, Vol IX Pt I pp 30-35
- 3 इण्डियन आर्कियोलॉजी 1969-70 पृ० 62
- 4 वही 1963-64 पृ०-45
- 5 कनिघम आ० रि० खण्ड-18 पृ० 41-52 खण्ड-22 पृ० 9-13 फ्यूरर आ० रि० पृ०- 249
- 6 आ० स० रि० 1906-7 पृ० 193-95
- 7 वही पृष्ठ- 195-96
- 8 वही पृ० 249
- 9 वही उद्धृत युग वातायन (पाक्षिक) देवरिया फरवरी-प्रथम पृ०-1-2 4-5 मार्च 1995
- 10 वही
- 11 गुप्त हीरालाल बरहज की पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाये युग-युगीन सरयूपार वाराणसी 1987 पृष्ठ 104-5
- 12 फ्यूरर पूर्वोक्त पृष्ठ 250-51 आ० स० रि० 1906-7 पृ० 193
- 13 वही पृष्ठ 237 उद्धृत- कनिघम आ० रि० खण्ड-16 पृष्ठ 130 खण्ड-22 पृष्ठ 60 जे० ए० एस० बी० भाग-7 पृष्ठ-24
- 14 कनिघम आ० रि० खण्ड-1 पृष्ठ 85-91 खण्ड-16 पृष्ठ 127-29 खण्ड-2 पृष्ठ-42
- 15 वही आ० रि० खण्ड-18 पृष्ठ-41
- 16 पूर्वोक्त पृष्ठ 248
- 17 वही
- 18 पाण्डेय रामपूजन अथ कुकुत्स्य चरित्र देवरिया, 1975, पृष्ठ 1-19
- 19 'काकन्दी नर्या जात' काकन्दक वही पृष्ठ 30-31 विश्वनाथ शास्त्री द्वारा उद्धृत
- 20 फ्यूरर आ० रि० 1891 पृष्ठ 234
- 21 कनिघम आ० रि० खण्ड-1 पृष्ठ 91-95 खण्ड-16 पृष्ठ-129
- 22 फ्यूरर पूर्वोक्त
- 23 जिला जनगणना हस्त-पुस्तिका जिला देवरिया पृ०-466
- 24 वही पृष्ठ 248
- 25 आ० रि० 1906-7 पृ०- 196
- 26 वही
- 27 वही पृष्ठ- 199
- 28 वही
- 29 साहनी श्याम एई जि 18 (1925-26) पृष्ठ 218 एव आगे
- 30 शर्मा जे० पी०, 'रिपब्लिक्स इन एन्सिएन्ट इण्डिया' लीडेन 1968 परिशिष्ट ई पृष्ठ- 248
- 31 फ्यूरर पूर्वोक्त पृष्ठ 240-41
- 32 वही
- 33 Raychandhuri, H C , 'Political Hoistory of Ancient India' P 95

- 34 *Datt & Bajpai, op cit pp 347-48*
- 35 *Pathak, op cit , p 281, 283 421*
- 36 *Majumdar and Pusalker op cit vol II p 415*
- 37 *Malalasekera, G R 'Dictionary of Pali Proper Names' Part II, p 653*
- 38 *सदर्भ 17 पृष्ठ— 221-287*
- 39 *Pandey, op cit pp 126-127*
- 40 *Srivastava, A K 'Find Spots of Kusana Coins in U P' p 39*
- 41 *Giles, H A 'The Travels of Fa-Hsin' pp 40-41*
- 42 *Tripathi R S , 'History of Kanauj to the Moslem Conquest', p 75*
- 43 *Watters, T , 'On Yuan Chwang's Travels in India Vol, II, p 25*
- 44 *Bajpai and Dikshit, op cit p 18*
- 45 *Puri, B N 'The History of the Gurjara- Pratiharas' pp 63-64*
- 46 *Alexander op cit , p 439*
- 47 *Pandey op cit, p 228*
- 48 *Nevill H R , op cit p 110*
- 49 *I bid*
- 50 *Chandra, Satish, 'Parties and Politics at the Mughal Court', 1707-1740 p 27-28, Irvine, Welliam 'Later Mughals' vol I pp-40-41*
- 51 *Nevill- op- cit p 182*
- 52 *Hallowes, B J K, 'District Gazatteers of the United Provinees of Agra and Audh Supplementary Notes and Statistics up to 1931-32 vol XXXI (D) Gorakhpur District, P 24*
- 53 *'Uttar Pradesh District Gazatteers' Deoria-1988 pp-20*
- 54 *Mishra, R P , Sunadaram, K P and Prakash Rao, V L S, (Ed) 1974, 'Regional Development Planning in India, A New Strategy', Vikash Publishing House India pp 180-218*
- 55 *Jefferson, M (1931) 'Distribution of world's city Folk', Geographical Review, XXI, p 453*





अध्याय-चार



सेवाकेन्द्रों का स्थानिक कार्यात्मक संगठन

4.1 सेवाकेन्द्रों का स्थानिक-कार्यात्मक संगठन

प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसका निर्माण न केवल वहाँ प्राप्त ससाधनों द्वारा अपितु वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा भी होता है।¹ ससाधनों तथा आर्थिक क्रियाओं के असमानता के कारण ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय सेवाकेन्द्रों का अभ्युदय एवं विकास होता है। इन सेवाकेन्द्रों का अधिवास प्रतिरूपों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी विभिन्न भौगोलिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सुसहज एवं व्यासृत दोनों ही प्रकार के अधिवास प्रतिरूपों का विकास हुआ है। इन दोनों प्रतिरूपों के अतिरिक्त दोनों के मध्य अनेक प्रतिरूपों जैसे विसरित पल्लियों आदि का भी विकास स्थान विशेष की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मिलता है।² कृषि आधारित बड़े पैमाने पर सहज बस्तियाँ भारतीय बस्ती प्रतिरूप की प्रमुख विशेषता है।³ अध्ययन क्षेत्र समतल उपजाऊ भू-भाग है जहाँ गहन कृषि की जाती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 2001 के जनगणना के अनुसार 1077 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो प्रदेश के औसत घनत्व (689) से काफी अधिक है। इस प्रकार घनत्व की दृष्टि से इसका प्रदेश में नौवाँ स्थान है। अतः स्पष्ट है कि यह क्षेत्र सहज अधिवास का क्षेत्र है। इस जनपद में बागल क्षेत्र में सहज अधिवास प्रमुख विशेषता है जबकि छोटी गडक, सप्ती एवं घाघरा के खादर प्रदेश में अर्द्धसघन ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। ये प्रदेश जनपद के दक्षिण में स्थित हैं। इसमें रुद्रपुर, गौराबरहज एवं सलेमपुर तहसीलों के दक्षिणी भाग के गाँव शामिल किये जा सकते हैं। माइत्सेन⁴ ने सहज ग्रामीण अधिवास को सामुदायिक कृषि व्यवस्था से और व्यासृत आवास गृहों को व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित बताया है।

नगरों का विकास गाँवों से होता है और नगरवासी निरंतर ग्रामवासियों के परिश्रम पर ही पनपते हैं।⁵ सामाजिक आर्थिक अधःसंरचना की दृष्टि से ये ग्रामीण बस्तियाँ नगरी बस्तियों की अपेक्षा पर्याप्त रूप से पिछड़ी हैं। इनके पिछड़ेपन के कारण ही बड़े पैमाने पर कार्यशील जनसंख्या का स्थानान्तरण गाँवों से नगरों की ओर हो रहा है जो भारतीय जनसंख्या की प्रमुख समस्या है। गाँवों से नगरों की स्थानान्तरण की समस्या का समाधान, ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक-आर्थिक अधःसंरचना के विकास में निहित है।⁶ इस समस्या का समाधान क्षेत्र के विकास द्वारा ही सम्भव है और उस क्षेत्र का विकास ऐसे अनेक सेवाकेन्द्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जहाँ लगभग सभी आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाओं का केन्द्रीकरण हो। यदि ये सेवाकेन्द्र अपने सेवा

क्षेत्रों एवं अन्य सेवाकेन्द्रों से आवागमन एवं संचार माध्यमों से आपस में सुसम्बद्ध हो जाय तो विकास की गति और तेज हो सकती है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र 'कृषि प्रधान पिछड़ी अर्थव्यवस्था' का प्रतिरूप है। जो उद्योग भी विकसित हुए हैं वे भी कृषि पर आधारित उद्योग ही हैं जिनमें **पीनी उद्योग** सर्वप्रमुख है। इस उद्योग ने इस क्षेत्र के विकास में भरपूर योगदान दिया है। परन्तु वर्तमान समय में अधिकांश मिलें या तो बंद पड़ी हैं या बीमार चल रही हैं या फिर किसानों को समय से गन्नों के पैसों का भुगतान नहीं कर रही हैं जिससे क्षेत्र के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों को पहचानने का प्रयास किया है जो सख्या में अल्प है। साथ ही उनके पदानुक्रम एवं क्षेत्रीय वितरण को भी स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के ऐसे सभी प्रकार के विकास जनक केन्द्रों को सेवाकेन्द्र कहा गया है। जिनका अभिनिर्धारण उनकी विशिष्ट स्थिति एवं कार्यों के केन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप सेवाकेन्द्रों के रूप में स्वयमेव हो जाता है। ऐसे सेवाकेन्द्र ही सम्बन्धित कार्यों द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करते हैं जिससे उन्हें *सेवाकेन्द्र* के रूप में अभिहित किया जाता है।¹⁷ सेवाकेन्द्रों का आधार छोटे गाँव से लेकर बृहद् नगरों तक होता है। ये केन्द्र विकास तथा नवाचार के जनक होते हैं। इन सेवाकेन्द्रों के आधार पर *पेरॉक्स*¹⁸ महोदय ने जो एक अर्थशास्त्री थे *विकास ध्रुव सिद्धान्त* का प्रतिपादन किया। *बोडविले*¹⁹ ने इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में नया आयाम दिया।

4.2 सेवाकेन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

कोई भी सेवाकेन्द्र चाहे जिस आकार-प्रकार का हो वह सामाजिक आर्थिक कार्यों का सग्रह केन्द्र होता है तथा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है। बड़े सेवाकेन्द्रों में सेवा कार्यों की सख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसी भी सेवाकेन्द्र की स्थापना एवं स्थायित्व उन सामाजिक आर्थिक कार्यों पर निर्भर करता है जिसके द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अतः ये केन्द्र परिधीय क्षेत्र से इष्टतम रूप में जुड़े होते हैं। इन केन्द्रों के सेवाओं का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे इसके लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न स्तर के सेवाकेन्द्रों का जाल होना चाहिए। वास्तव में ये केन्द्र सामाजिक-आर्थिक कार्यों के क्रीडा स्थल के रूप में होते हैं। इन सेवाकेन्द्रों का स्वरूप स्थानीय इकाई के समान होता है जिनके द्वारा अधिकांश सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रमुख निश्चित क्षेत्र के लोगों को दिये जाते हैं।

सेवाकेन्द्रों पर अनेक कार्यों का सकेन्द्रण होता है, किन्तु इनमें से कुछ कार्य सेवाकेन्द्र की जनसख्या के लिए तथा कुछ कार्य समीपवर्ती क्षेत्र (सेवित क्षेत्र) की जनसख्या के लिए होते हैं। स्वयं सेवाकेन्द्र की जनसख्या को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को *सामान्य कार्य (Non Basic Function)* तथा समीपवर्ती क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाले कार्यों को *आधारभूत कार्य (Basic Function)* कहा जाता है, जिस पर ही उनकी अवस्थिति होती है। सामान्यतः सामान्य कार्य सभी

बस्तियों द्वारा किये जाते हैं किन्तु आधारभूत कार्य कुछ विशिष्ट बस्तियों (सेवाकेन्द्र) द्वारा ही सम्पादित होते हैं। क्रिस्टालर¹⁰ ने इन आधारभूत कार्यों को *केन्द्रीय कार्य (Central Function)* कहा है। भट्ट¹¹ ने तकनीकी आर्थिक एवं सस्थागत कारणों से असर्वगत (NonUbiquites) तथा कुछ निश्चित क्षेत्रों की सेवा के लिए निश्चित स्थानों पर अवस्थित सेवाओं को 'केन्द्रीय कार्य' के रूप में माना है। राजकुमार पाठक¹² के अनुसार जिन कार्यों से लोगों का स्थानान्तरण संभव होता है उसे *केन्द्रीय कार्य* कहते हैं। यह स्थानान्तरण दैनिक मासिक वार्षिक स्थायी अस्थायी आदि अनेक रूपों में हो सकता है। किन्तु किसी भी कार्य का केन्द्रीय कार्य होना इस बात पर निर्भर है कि उसका उस क्षेत्र में क्या महत्व है? किसी विकास केन्द्र के केन्द्रीय कार्यों का महत्व स्वयं उस केन्द्र एवं सम्बन्धित क्षेत्र के विकास में योगदान से है। सम्बन्धित केन्द्र एवं क्षेत्र का विकास केन्द्रीय कार्यों का प्रतिफल होता है। इन सेवाकेन्द्रों का विकास परिधीय क्षेत्रों के योगदान का भी परिणाम है। वास्तव में केन्द्रीय कार्यों का सम्बन्ध सम्बन्धित सेवाकेन्द्र एवं क्षेत्र का विकास करने से है। अतः ऐसे कार्यों को *केन्द्रीय विकास कार्य (Central Growth Function)* कहना अधिक उपयुक्त है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासनिक कृषि एवं पशुपालन शिक्षा एवं मनोरंजन परिवहन एवं संचार चिकित्सा वित्तीय तथा व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित 51 कार्यों को केन्द्रीय विकास कार्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है सारणी – (41)।

4.3 सेवाकेन्द्रों का निर्धारण

सेवाकेन्द्रों के निर्धारण से तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित बस्तियों में से उन बस्तियों का चयन करना है जो वितरित बस्तियों का सेवाकेन्द्र के रूप में सेवा कर रहा है। सेवाकेन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया सिद्धान्त रूप में जितनी आसान लगती है, व्यावहारिक रूप में उतनी ही जटिल प्रक्रिया है। अध्ययन क्षेत्र के विपुल बस्तियों (2004) में से किन-किन बस्तियों को किस मात्रा में तथा किस आधार पर सेवाकेन्द्र का अभिनिर्धारण किया जाय? वांछित ऑकड़ों की अनुपलब्धता के कारण परिमाणात्मक मानदण्डों का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। फलतः वास्तविक विकासकेन्द्रों का सुनिश्चयन नहीं हो पाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजित एवं परिभाषित बस्तियाँ कभी-कभी समस्या खड़ी कर देती हैं। कुछ गाँवों में कुछ पुरवें अनेक केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं तथा कभी-कभी राजस्व गाँव वास्तविक बस्ती की इकाइयों से मेल नहीं खाते। कभी-कभी एक ही सातत्य की बस्ती कई राजस्व गाँवों में बटी होती है। कभी-कभी कुछ चौराहे, मोड़ या मुख्य सड़क की अवस्थितियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि मात्र एक या दो कार्यों के सम्पादन के बावजूद व्यावहारिक रूप में कई बड़े सेवाकेन्द्रों से महत्वपूर्ण होते हैं। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि केन्द्रीय कार्यों की अवस्थिति सरकारी ऑकड़ों में वस्तुतः प्रदर्शित नहीं होती है। अतः सेवाकेन्द्र के केन्द्रीय कार्यों की गणना में प्रायः कठिनाई होती है।

सामान्यतः सेवाकेन्द्रों का निर्धारण *केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, केन्द्रीयता तथा केन्द्रीयता*

सूचकांक जनसंख्या आकार कार्यशील व कुल जनसंख्या के अनुपात केन्द्रीय कार्यों के कार्याधार जनसंख्या तथा बस्तियों के सेवा क्षेत्र के आधार पर या उपर्युक्त आधारों में से एकाधिक आधारों पर किया जा सकता है। विगत कुछ वर्षों में भारत में सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। सुधीर वनमाली¹³ सेन¹⁴ नित्यानन्द,¹⁵ कुमार एव शर्मा,¹⁶ एस0बी0सिंह¹⁷ तथा खान¹⁸ आदि विद्वानों ने कार्यों के सकेन्द्रण के आधार पर सेवाकेन्द्रों का निर्धारण किया है जिसमें कार्यों के औसत कार्याधार जनसंख्या को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दत्ता¹⁹ ने परिवहन सूचकांक के आधार पर आलम²⁰ ने जनसंख्या के आधार पर जी0के0मिश्र²¹ जनसंख्या के आकार और कार्यों की उपस्थिति के आधार पर तथा भट्ट²³ एव पाठक²⁴ आदि विद्वानों ने बस्तियों की केन्द्रीयता को सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में आधार माना है। बी0एन0 मिश्र²⁵ ने इसके लिए औसत कार्याधार जनसंख्या उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप और सेवाकेन्द्र एव सेवा क्षेत्र के मध्य क्षेत्रीय अतिक्रिया के लिए परिवहनीय सम्बद्धता को आधार माना है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सेवाकेन्द्रों के निर्धारण की अनेक प्रक्रियाएँ हैं। सभी प्रक्रियाएँ व्यक्तिनिष्ठ हैं क्योंकि सेवाकेन्द्रों का चयन केन्द्रीय कार्यों का चयन तथा सतृप्त जनसंख्या बिन्दु का चयन जिसके ऊपर ही सम्पूर्ण विश्लेषण सम्भव है, अध्ययन कर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के 2004 बस्तियों में से बी0एन0मिश्र (1980) द्वारा प्रयुक्त विधि का उपयोग करते हुए कार्यों की औसत कार्याधार जनसंख्या उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप और बस्तियों की सम्बद्धता के माध्यम से सेवाकेन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यों के क्षेत्रीय महत्व औसत कार्याधार मूल्य और उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप के आधार पर 51 केन्द्रीय कार्यों एव सेवाओं का चयन किया गया है जो अध्ययन क्षेत्र में वितरित बस्तियों द्वारा सम्पादित होते हैं सारणी— (4 1)।

(क) औसत कार्याधार जनसंख्या

‘कार्याधार जनसंख्या’ किसी भी प्रदेश में किसी भी कार्य को उपयुक्त ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक जनसंख्या होती है। यह प्रदेश से सम्बन्धित कार्य की प्रवेशी और संपृक्त जनसंख्या के बीच की स्थिति होती है। प्रवेशी जनसंख्या से तात्पर्य किसी कार्य को सम्पादित करने से सम्बन्धित उस निम्नतम जनसंख्या से है जिस पर किसी बस्ती में किसी कार्य की अवस्थापना हो। प्रस्तुत अध्ययन में प्रवेशी जनसंख्या की गणना सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के बस्तियों में से की गयी है। संपृक्त जनसंख्या वह जनसंख्या आकार है जिसके ऊपर किसी प्रदेश में कोई कार्य (यूबीक्वीटस) हो जाता है।²⁶ प्रस्तुत अध्ययन में संपृक्त जनसंख्या निर्धारण में सम्बन्धित कार्य को करने वाले सबसे बड़े केन्द्र की जनसंख्या की गणना रीड मुच²⁷ विधि द्वारा की गयी है। इसके बाद सबसे कम कार्याधार जनसंख्या वाले कार्य की जनसंख्या से सभी कार्यों की कार्याधार

जनसख्या मे भाग देकर कार्याधार जनसख्या सूचकांक की गणना की गयी है। पुन कार्याधार जनसख्या सूचकांक के निरीक्षण के बाद कार्यों के 4 पदानुक्रम निर्धारित किये गये हैं। सारणी (4 1) मे कार्य उनकी प्रवेशी जनसख्या संपृक्त जनसख्या तथा उनकी कार्याधार जनसख्या को प्रस्तुत किया गया है। सारणी (4 2) मे कार्याधार जनसख्या सूचकांक तथा कार्यों के पदानुक्रम का विवरण दिया गया है।

सारणी-4 1

केन्द्रीय कार्य एव सेवाएँ

कार्य	अध्ययन क्षेत्र मे कुल सख्या	प्रवेशी जनसख्या	संपृक्त जनसख्या	कार्याधार जनसख्या
1	2	3	4	5
(क) प्रशासनिक कार्य				
1 जनपद मुख्यालय	1	82168	82168	82168
2 तहसील मुख्यालय	5	9827	82168	45997
3 विकासखण्ड केन्द्र	15	5027	82168	43597
4 जनपद पचायत केन्द्र	1	82168	82168	82168
5 न्यायपचायत केन्द्र	176	2260	21550	11905
6 थाना	18	3676	82168	42927
(ख) उद्योग एव औद्योगिक आस्थान				
7 बडे उद्योग	6	6326	82168	42247
8 बडे औद्योगिक आस्थान	2	12705	82168	47436
9 लघु औद्योगिक आस्थान	5	5027	29793	17410
10 औद्योगिक क्षेत्र	1	1348	1348	1348
(ग) कृषि एव पशुपालन				
11 शीत गृह	3	5027	82168	43597
12 बीज गोदाम एव उर्वरक केन्द्र	299	459	5027	2743
13 कीटनाशक डीपो	17	5027	8268	6647
14 क्रय-विक्रय सहकारी समिति	5	9827	82168	45997
15 कृषि सेवाकेन्द्र	16	4025	82168	43096
16 पशु चिकित्सालय	25	5522	10270	7896
17 पशु सेवाकेन्द्र	37	735	5522	3128
(घ) परिवहन एव सचार				
18 रेलवे स्टेशन/हाल्ट	19	2120	29793	15956
19 बस स्टेशन/स्टाप	142	222	5522	2872
20 टेलीफोन एक्सचेंज	35	2250	22334	12292
21 तारघर	21	2250	22344	12297

22	डाकघर	376	316	2245	1280
23	पी सी ओ	668	100	22400	11250
(ड) शिक्षा एव मनोरजन					
26	महाविद्यालय	12	5027	82168	43597
25	तकनीकी एव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	4	82168	82168	82168
26	इण्टर कॉलेज	115	1213	29793	15513
27	हाई स्कूल	121	953	22334	11643
28	सीनियर बेसिक स्कूल	413	540	5522	3033
29	जूनियर बेसिक स्कूल	1813	316	5527	2921
30	छवि गृह	16	5027	82168	43597
(च) चिकित्सा सेवा					
31	जिला अस्पताल	1	82168	82168	82168
32	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	5027	29793	17410
33	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16	3676	29793	16734
34	नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	64	450	22400	11425
35	आयुर्वेदिक एव यूनानी चिकित्सालय	46	450	13698	7074
36	होम्योपैथिक चिकित्सालय	25	450	13696	7074
37	परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र	20	3026	29793	16409
(छ) वित्तीय कार्य					
38	राष्ट्रीय बैंक	53	2025	82168	42096
39	भूमि विकास बैंक	3	22344	82168	52256
40	जिला सहकारी बैंक	19	2903	82168	42535
41	नाबार्ड' इकाई	1	82168	82168	82168
42	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	53	1248	3549	2398
43	भारतीय जीवन बीमा निगम	1	82168	82168	82168
(ज) व्यापार एव वाणिज्य					
44	वार्षिक मेला	17	2025	29793	15909
45	थोक बाजार	15	2025	82168	42096
46	फुटकर बाजार	45	1225	3549	2387
47	साप्ताहिक बाजार	36	1009	2245	1627
48	कृषि उपकरण यत्र विक्रय केन्द्र	20	2903	29793	16348
49	हार्डवेयर शॉप	102	1248	5522	3385
50	ऑटो रिपेयर शॉप	106	1440	5522	3481
51	दवाखाना	185	450	5500	2975

सारणी-4 2

कार्य, कार्याधार जनसंख्या सूचकांक एवं कार्य अनुक्रम

क्रम	केन्द्रीय कार्य एवं सेवाएँ	कार्याधार जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
1	2	3	4
प्रथम क्रम के कार्य			
1	जनपद मुख्यालय	82168	64 20
2	जनपद पंचायत केन्द्र	82168	64 20
3	तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	82168	64 20
4	जिला अस्पताल	82168	64 20
5	नाबार्ड की इकाई	82168	64 20
6	भारतीय जीवन बीमा निगम	82168	64 20
द्वितीय क्रम के कार्य			
7	भूमि विकास बैंक	52256	40 82
8	बड़े औद्योगिक आस्थान	47436	37 05
9	तहसील मुख्यालय	45997	36 00
10	क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ	45997	36 00
11	बड़े उद्योग	44247	34 56
12	महाविद्यालय	43597	34 06
13	शीत गृह	43597	34 06
14	छवि गृह	43597	34 06
15	विकासखण्ड केन्द्र	43597	34 06
16	कृषि सेवाकेन्द्र	43096	33 66
17	थाना	42927	33 53
18	जिला सहकारी बैंक	42535	33 23
19	थोक बाजार	42096	32 88
20	राष्ट्रीयकृत बैंक	42096	32 88
तृतीय क्रम के कार्य			
21	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	17410	13 60
22	लघु औद्योगिक आस्थान	17410	13 60
23	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	167734	13 07
24	परिवार एवं मातृ-शिशु-कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र	16409	12 82
25	कृषि उपकरण यन्त्र विक्रय केन्द्र	16734	12 77
26	रेलवे स्टेशन/हाल्ट	15956	12 46
27	वार्षिक मेला	15909	12 42
28	इण्टर कॉलेज	15513	12 12
29	तारघर	12297	9 60

30	टेलीफोन एक्सचेंज	12292	9 60
31	न्याय पचायत केन्द्र	11905	9 30
32	हाई स्कूल	11643	9 10
33	नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11425	9 00
34	पी सी ओ	11250	8 78
35	पशु चिकित्सालय	7896	6 16
36	आयुर्वेदिक एव यूनानी चिकित्सालय	7074	5 52
37	होमियोपैथिक चिकित्सालय	7073	5 52
38	कीटनाशक डीपो	6647	5 20
चतुर्थ क्रम के कार्य			
39	ऑटो रिपेयर शॉप	3481	2 72
40	हार्डवेयर शॉप	3385	2 64
41	पशुसेवा केन्द्र	3128	2 44
42	सीनियर बेसिक स्कूल	30 33	2 37
43	दवाखाना	2975	2 32
44	जूनियर बेसिक स्कूल	2921	2 28
45	बसस्टेशन/स्टॉप	2872	2 24
46	बीज गोदाम एव उर्वरक केन्द्र	2743	2 14
47	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2398	1 87
48	फुटकर बाजार	2387	1 86
49	साप्ताहिक बाजार	1627	1 27
50	औद्योगिक क्षेत्र	1348	1 05
51	डाकघर	1280	1 00

अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियों में उन्हीं का चयन करने का प्रयास किया गया है जो कम से कम 5 केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करती हो। इसमें चतुर्थ क्रम के अधिकांश कार्यों के मूल्य को अभिनिर्धारण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत अधिक है तथा अधिकांश बस्तियाँ ऐसे कार्यों को सम्पादित करती हैं चतुर्थ क्रम के कार्यों— औद्योगिक क्षेत्र बस स्टेशन, साप्ताहिक बाजार पशुसेवाकेन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डाकघर के मूल्य को सेवाकेन्द्र के निर्धारण में जोड़ा गया है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र के कम केन्द्रों पर ही ये सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार तृतीय क्रम के कार्य पी सी ओ का उच्च मूल्य होने के बावजूद अत्यधिक संख्या के कारण अभिनिर्धारण में इसके मूल्य को नहीं जोड़ा गया है। उक्त मानदण्डों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में कुल 47 सेवाकेन्द्रों को मान्यता प्रदान की गयी है। इन 47 सेवाकेन्द्रों की जनसंख्या, तथा सम्पादित होने वाले कार्यों की संख्या सारणी (4.3) में प्रदर्शित है। इन सेवाकेन्द्रों की स्थानिक अवस्थितियाँ मानचित्र (4.1) में प्रदर्शित हैं।

SPATIAL DISTRIBUTION OF SERVICE CENTRE IN DEORIA DISTRICT (2002)

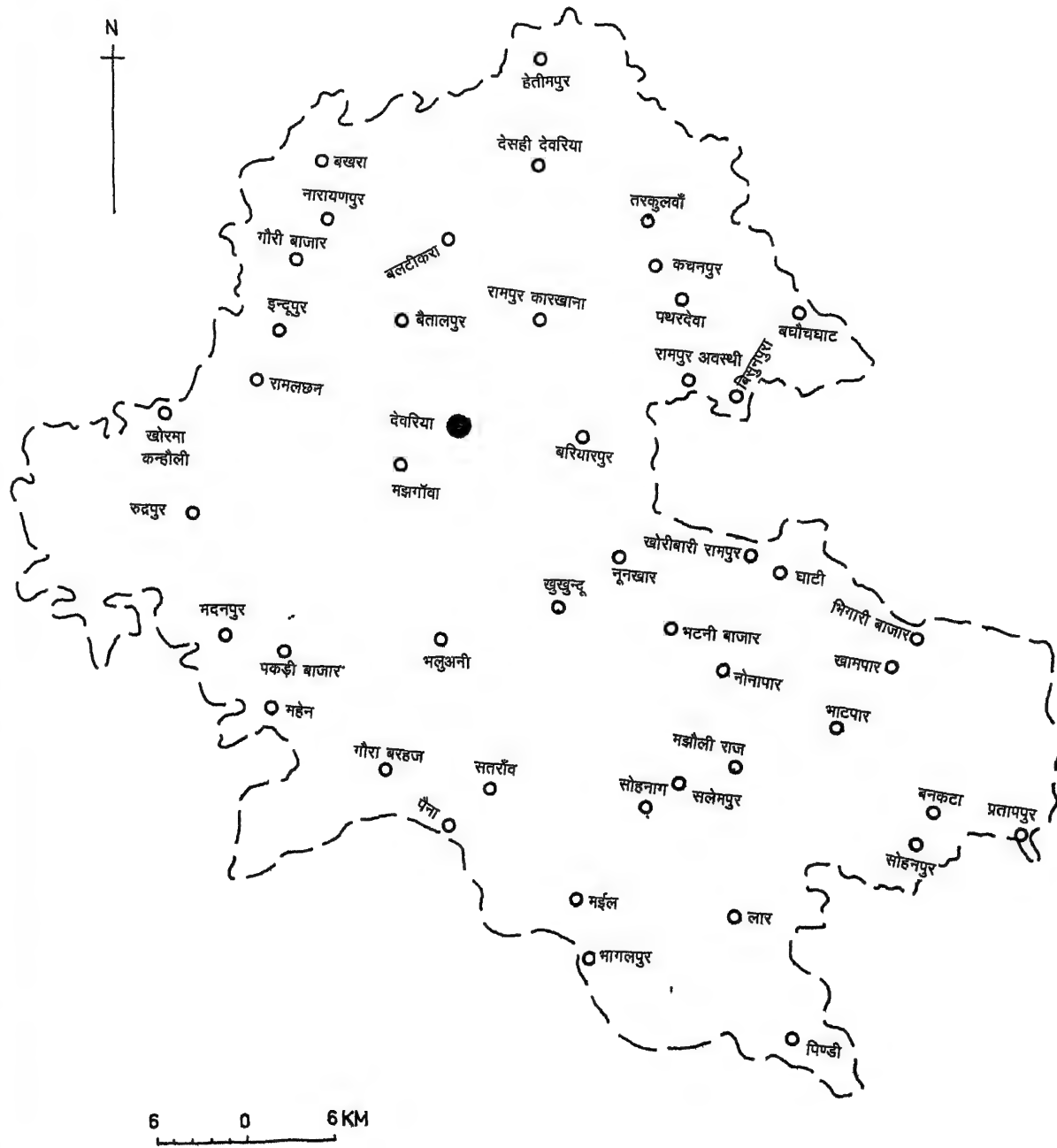


FIG 4 1

सारणी 43
जनपद मे निर्धारित सेवाकेन्द्र

क्रम	सेवाकेन्द्रो का नाम	जनसंख्या (2001)	सम्पादित कार्यो की संख्या
1	2	3	4
1	देवरिया	82168	40
2	रुद्रपुर	22344	23
3	भाटपार	9827	22
4	सलेमपुर	12705	26
5	लार	22400	20
6	गौरीबाजार	5027	22
7	पथरदेवा	6214	16
8	गौरा बरहज	29793	21
9	महेन	4505	6
10	रामपुर कारखाना	9061	16
11	देसही देवरिया	1840	12
12	भटनी बाजार	11549	18
13	भलुअनी	3518	15
14	बनकटा	4507	16
15	भागलपुर	4936	11
16	मझगँव	2705	9
17	बैतालपुर	2082	20
18	खुखुन्दू	5292	10
19	मईल	3174	7
20	भिगारी बाजार	4047	5
21	खामपार	6335	7
22	सोहनपुर	6618	7
23	पिण्डी	5996	6
24	रामलछन	2134	6
25	बखरा	3868	9
26	बिसुनपुरा	4548	6
27	पकडी बाजार	3825	8
28	मझौली राज	13698	12
29	पैना	12592	5
30	बघौचघाट	3354	6
31	रामपुर अवस्थी	1546	5
32	तरकुलवाँ	5482	9
33	कचनपुर	2480	5
34	हेतिमपुर	1951	7
35	नूनखार	4274	5

36	घाटी	3081	5
37	मदनपुर	3847	7
38	खोरमा कन्हौली	2250	5
39	बरियारपुर	1385	5
40	बलटीकरा	1260	6
41	इन्दूपुर	2875	6
42	सतराव	2416	5
43	नोनापार	3370	5
44	सोहनाग	575	5
45	प्रतापपुर	3796	6
46	नारायणपुर	2175	5
47	खोरीबारी रामपुर	4870	5

(ख) उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप

उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप सेवाकेन्द्रों के मध्य लम्बवत् अन्योन्य क्रिया है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं के द्वारा उनके आवश्यक सामानों के क्रय—विक्रय हेतु सेवाकेन्द्रों तक सचरण के स्वरूप एवं उनकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे *उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप* कहते हैं। उपभोक्ताओं के सचरण प्रतिरूप के अध्ययन से किसी क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों की कार्यात्मक महत्ता का पता चलता है। साथ ही किसी क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों के विभिन्न स्तरों (पदानुक्रम) के मध्य *क्षेत्रीय अन्तर्प्रक्रिया* के अध्ययन द्वारा वहाँ पर सेवाकेन्द्रों के क्षमता निर्धारण एवं चयन में सहायता मिलती है।²⁸ इसके अध्ययन से क्षेत्र के भावी विकास हेतु योजना प्रस्तुत करने में सहयोग मिलता है। अतः सेवाकेन्द्रों का चयन एवं पुष्टि उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप द्वारा होना अपरिहार्य है। अध्ययन क्षेत्र में उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप के अध्ययन के लिए उपभोक्ता सचरण सर्वेक्षण को आधार बनाया गया है।

(i) उपभोक्ता सचरण सर्वेक्षण

अध्ययन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के सचरण प्रतिरूप के अध्ययन हेतु 150 ग्रामों का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किया गया। इन ग्रामों के प्रतिचयन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि प्रतिचयनित ग्राम लगभग पूरे जनपद का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए कुछ ग्राम परिवहन भागों के निकट के लिए गए हैं, तो कुछ परिवहन मार्गों से दूर आंतरिक क्षेत्रों से। कुछ ऐसे ग्रामों का चयन किया गया है, जहाँ सप्ताह में एक या दो दिन बाजार लगता है, तो कुछ ग्राम केन्द्रस्थलों के समीपवर्ती हैं। इस प्रकार प्रतिचयनित ग्राम अध्ययन क्षेत्र के भौतिक और सांस्कृतिक भू-दृश्यों के अनुरूप चुने गये हैं।

प्रतिचयनित ग्रामों के अंतर्गत आर्थिक स्तर के आधार पर (धनी निर्धन एवं मध्यम), 5 या 6

परिवारों का चयन किया गया। जैसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर एक एकड़ जोत वाले कृषक 10 एकड़ या इससे अधिक जोत वाले कृषक एवं नौकरी पेशा या व्यापार में कार्यरत। परिवार के मुखिया से तीन स्तर के आवश्यक सामानों के क्रय-विक्रय हेतु प्रश्न पूछे गये। *प्रथम स्तर* में प्रतिदिन उपभोग में आने वाले सामान जैसे—नमक तेल मसाला सब्जी मॉस मछली आदि *द्वितीय स्तर* के सामानों में सप्ताह या एक माह तक खर्च के लिए खरीदे जाने वाले सामान जैसे कपड़ा रेडीमेड बर्तन दवा स्टेशनरी जूता चप्पल सौन्दर्य प्रसाधन आदि। *तृतीय स्तर* के अंतर्गत खरीदे जाने वाले सामान जैसे घड़ी रेडियो आभूषण ऊनी कपड़े कृषि यन्त्र भवन निर्माण सामग्री शादी-विवाह के अवसरों पर उपहार के सामान आदि जो कभी-कभी क्रय किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके बाजार जाने के साधन बाजार जाने की आवृत्ति (प्रतिदिन साप्ताहिक या मासिक) निकटतम बाजार आसपास के अन्य बाजारों में गमनागमन की प्रवृत्ति तथा सामानों के विक्रय हेतु गन्तव्य स्थान के विषय में साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी।

(ii) उपभोक्ता संचरण सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम

सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के बाजार संचरण का प्रतिरूप उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों के प्रकार तथा उनकी आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित होता है। जैसे प्रतिदिन काम आने वाला सामान अधिक से अधिक 5 किमी की दूरी पर अवस्थित बाजार से चाहे वह आवर्ती बाजार ही क्यों न हो हर स्तर के उपभोक्ताओं द्वारा पैदल चलकर या साइकिल अथवा स्कूटर-मोटर साइकिल द्वारा चलकर क्रय किया जाता है।





द्वितीय वर्ग की वस्तुओं को क्रय करने के लिए निर्धन उपभोक्ता निकट के बाजार केन्द्र तक ही जाते हैं अथवा ग्राम के आवर्ती बाजारों में ही क्रय कर लेते हैं क्योंकि दूर के बड़े केन्द्रों तक जाने के लिए इनके पास पैसा एवं समय दोनों का अभाव रहता है। मध्यम एवं उच्च स्तर के उपभोक्ता इन वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने पास के प्रमुख सेवाकेन्द्र तक 15 से 20 किमी की दूरी तय कर जाते हैं।

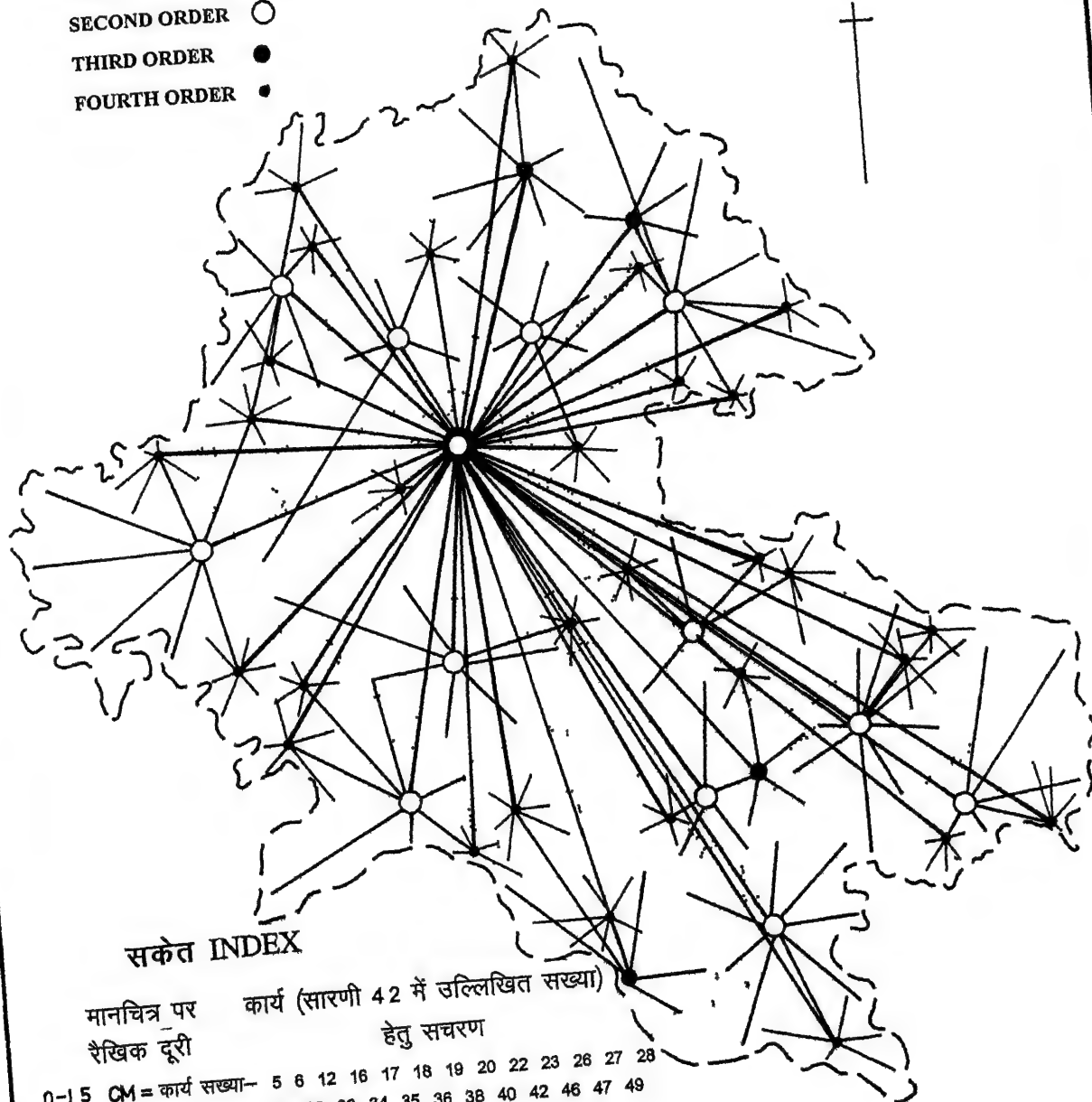
तृतीय वर्ग के बहुमूल्य सामग्री एक तो उच्चस्तर के उपभोक्ता ही अधिकतर क्रय करते हैं, दूसरे वे उसे प्राप्त करने के लिए या तो दूसरे क्षेत्र के सेवाकेन्द्र कसया गोरखपुर को जाते हैं या देवरिया से क्रय करते हैं। भवन-निर्माण सामग्री खाद इत्यादि भारी सामान सभी स्तर के उपभोक्ता निकटवर्ती बाजार से ही क्रय करते हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा सामानों के क्रय हेतु तय की गयी दूरी के आकलन से स्पष्ट है कि अधिकतम संचरण 45 किमी के लगभग है। शादी विवाह के अवसरों पर खरीदे जाने वाले सामान सभी स्तर के उपभोक्ता अपने-अपने आर्थिक स्तर के अनुरूप समीप के बाजार से लेकर देवरिया से या फिर दूसरे क्षेत्र के पड़ोसी सेवाकेन्द्रों— कसया, गोरखपुर से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न सामानों के क्रय हेतु तय की जाने वाली दूरी का प्रदर्शन चित्र (4.2) में है। जिससे

SPATIAL PREFERENCE OF CONSUMERS IN DEORIA DISTRICT

ORDER OF CENTRES

- FIRST ORDER 
- SECOND ORDER 
- THIRD ORDER 
- FOURTH ORDER 



सकेत INDEX

मानचित्र पर कार्य (सारणी 4.2 में उल्लिखित संख्या) हेतु सचरण
 रेखिक दूरी

0-15 CM = कार्य संख्या— 5 6 12 16 17 18 19 20 22 23 26 27 28
 29 30 33 34 35 36 38 40 42 46 47 49
 50 51 हेतु सचरण।

0-35 CM = कार्य संख्या— 2 3 5 6 9 10 13 14 15 16 17 18 20 21
 26 27 30 32 33 35 36 37 38 39 40 44 47
 50 51 हेतु सचरण।

0-13 CM = कार्य संख्या— 1 2 4 7 8 11 24 25 31 32 38 39 40 41 43 45
 46 48 51 हेतु सचरण।

6 0 6 KM

FIG 4.2

स्पष्ट है कि निकटवर्ती बाजारों का महत्व उपभोक्ताओं के लिए अधिक है क्योंकि आकस्मिक या अतिशीघ्र सामानों की प्राप्ति अथवा मनोरंजन हेतु प्राप्त या सायं टहलते हुए जाने का कार्य इन्हीं बाजार केन्द्रों द्वारा सम्पादित होता है।

उपभोक्ता संचरण का एक महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा वांछित सेवाकेन्द्रों तक पहुँचने के लिए प्रयोग में लाये गये साधन है। निकट के बाजार तक उपभोक्ता प्रायः पैदल साइकिल अथवा मोटर-साइकिल का प्रयोग करते हैं। 5 से 10 किमी तक की दूरी पर स्थित सेवाकेन्द्रों को जाने के लिए बहुधा रिक्शा साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूर स्थित बड़े केन्द्रों तक जाने के लिए बसों टैक्सियों इत्यादि का माध्यम लिया जाता है। रेल सेवा का माध्यम उन्हीं स्थलों पर जाने हेतु लिया जाता है जहाँ समय से उसकी उपलब्धि है जैसे— सलेमपुर माटपार भटनी बनकटा गौरी बाजार इत्यादि।

चित्र (4 2) में उपभोक्ताओं के संचरण प्रतिरूप से स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं के संचरण की दृष्टि से देवरिया मुख्यालय **सबसे बड़ा (प्रथम क्रम)** सेवाकेन्द्र है। जनपद की लगभग सभी जनसंख्या तथा सभी सेवाकेन्द्रों को यह सेवाएँ प्रदान करता है। इसके लिए इसकी केन्द्रीय अवस्थिति बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। सुदूर सेवाकेन्द्र एवं जनसंख्या का संचरण देवरिया के लिए प्रधानतः सारिणी (4 2) में उल्लिखित कार्य संख्या — 1 2 4 7 8 11 24 25 31 32 38 39 40, 41 43 45 46 48 51 — के लिए होता है। उपभोक्ता संचरण की दृष्टि से **दूसरे क्रम** के सेवाकेन्द्र सलेमपुर रुद्रपुर गौरीबाजार पथरदेवा गौरा बरहज, लार भाटपार भटनीबाजार रामपुर कारखाना भलुअनी बैतालपुर, और बनकटा हैं। ये सभी प्रखण्ड विकास केन्द्र के मुख्यालय हैं जिसमें सलेमपुर रुद्रपुर गौराबरहज और भाटपार तहसील मुख्यालय भी हैं। अतः इन केन्द्रों द्वारा अन्य कार्यों के अलावा प्रशासनिक कार्य भी सम्पादित होता है। यहाँ प्रमुख संचरण कार्य संख्या— 2 3 5, 6 9 10 13 14 15 16 17 18 20, 21 26 27 30 32 33 35 36 37 38 39, 40 44 47 50 51 के लिए होता है। इस दृष्टि से देसही देवरिया भागलपुर, मझौली राज एवं तरकुलवाँ को **तीसरे क्रम** के सेवाकेन्द्र में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि देसही देवरिया और भागलपुर में प्रखण्ड कार्यालय होने के बावजूद अन्य सेवाओं की केन्द्रीयता अपेक्षाकृत कम है। दूसरी ओर तरकुलवाँ और मझौली राज प्रशासनिक केन्द्र न होते हुए भी अन्य कार्यों के कारण प्रचुर सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों पर प्रशासनिक कार्य संख्या 1 2 3 4 के अलावे द्वितीय क्रम के केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी कार्यों के लिए संचरण होता है। **चतुर्थ क्रम** के सेवाकेन्द्र का उपभोक्ता संचरण की दृष्टि से स्थानीय महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इन केन्द्रों की संख्या अध्ययन क्षेत्र में 30 है। इन पर केन्द्र से लगभग 4—5 किमी अर्द्धव्यास तक की जनसंख्या कार्य संख्या— 5 6 12 16 17 18 19, 20 22 23 26 27 28, 29 30 33 34 35, 36, 38 40 42 46 47 49 50 51 के लिए संचरण करती है।

(ग) परिवहनीय सम्बद्धता

सेवाकेन्द्रों का उद्भव—विकास तथा अस्तित्व परिवहनीय सम्बद्धता पर ही निर्भर करता है क्योंकि कार्यों एवं सेवाओं के लिए संचरण परिवहन मार्गों द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो क्षेत्र परिवहनीय दृष्टि से जितना अधिक सुसम्बद्ध होता वह उतना ही अधिक क्षेत्र के लोगों को सवाएँ उपलब्ध करायेगा। फलतः उसका सेवाक्षेत्र भी विस्तृत होगा। इस प्रकार परिवहनीय सम्बद्धता सम्बद्धता सूचकांक के द्वारा आँका जा सकता है। सम्बद्धता सूचकांक सेवाकेन्द्र एवं उसके आवृत सेवा क्षेत्र के मध्य क्षेत्रीय अन्तर्प्रक्रिया के स्तर को व्यक्त करता है। निम्न सम्बद्धता सूचकांक निम्न स्तर तथा उच्च सूचकांक सम्बद्धता के उच्च स्तर को व्यक्त करता है।

अध्ययन क्षेत्र में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क एवं रेलमार्ग हैं। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़को तक के सभी प्रकार पाये जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई अध्ययन क्षेत्र में 4 किमी राज्य उच्च पथ— 68 किमी मुख्य जिला सड़के— 134 किमी तथा अन्य जिलामार्ग 335 एवं ग्रामीण मार्गों की लम्बाई 1272 किमी है। अध्ययन क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन 111 किमी की लम्बाई तक विस्तृत है। इस प्रकार परिवहन मार्गों के सभी प्रकारों सहित अध्ययन क्षेत्र में इसकी कुल लम्बाई 1924 किमी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्षेत्रीय अन्तर्प्रक्रिया के लिए केवल उन्हीं सड़को को लिया गया है जो पक्की हैं और सम्पूर्ण वर्ष उन पर परिवहन सम्भव होता है। यद्यपि क्षेत्रीय अन्तर्प्रक्रिया में कच्ची सड़के भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। परन्तु इनकी उपलब्धता ऋत्विक होती है अतः इन्हें गणना में नहीं लिया गया है। ग्रामीण मार्ग का महत्व स्थानीय होता है। परन्तु क्षेत्र की जनसंख्या को सेवाये इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को ये सेवाकेन्द्र से जोड़ते हैं। जिला मार्ग तथा इस स्तर की अन्य सड़के सभी ग्रामीण मार्गों को एक—दूसरे से सम्बद्ध कर सेवाक्षेत्र का विस्तार करती हैं। परिवहन के साधन भी इन्हीं पर उपलब्ध होते हैं अतः क्षेत्र में इनकी लम्बाई ग्रामीण मार्गों से कम होने के बावजूद क्षेत्रीय सम्बद्धता की दृष्टि से इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। जनपद में राज्य उच्च मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई क्रमशः 68 किमी एवं 5 किमी है। कम लम्बाई के बावजूद परिवहन के सभी साधनों की इनपर उपलब्धता तथा सभी बड़े सेवाकेन्द्रों से सुसम्बद्धता के कारण इन मार्गों का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन्हीं मार्गों के सहारे अपेक्षाकृत उच्च स्तर के कार्य एवं सेवाये सूदूर क्षेत्रों तक सेवा प्रदान कर पाती हैं। फलतः सेवाक्षेत्र का व्यापक विस्तार होता है। इस प्रकार जो सेवाकेन्द्र केवल ग्रामीण स्तर के मार्ग द्वारा जुड़ा होगा उसका मूल्य अपेक्षाकृत जिलामार्ग से सम्बद्ध सेवाकेन्द्र से कम होगा तथा जो केन्द्र जिला मार्ग से केवल सम्बद्ध होगा उसका मूल्य राज्य स्तरीय सम्बद्धता वाले सेवाकेन्द्र से कम होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन मार्गों को उनके महत्व के अनुसार मूल्य प्रदान करने के लिए जनपद में परिवहन मार्गों की सकल लम्बाई में परिवहन मार्ग विशेष की लम्बाई से भाग देकर प्रत्येक प्रकार के परिवहन मार्ग का मूल्य ज्ञात किया गया है। इस विधि से अपेक्षाकृत कम लम्बाई वाले

राज्य उच्चपथ एव जिलामार्ग का मूल्य ग्रामीण मार्गों से उच्च प्राप्त हुआ है। जो क्रमशः निम्नवत् है—

मार्ग प्रकार	—	सम्बद्धता मूल्य
1— राष्ट्रीय एव राज्य उच्चमार्ग	—	26
2— रेलमार्ग	—	17
3— मुख्य जिला मार्ग	—	14
4— अन्य जिला मार्ग	—	6
5— ग्रामीण मार्ग	—	15

उपर्युक्त मूल्यों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों का सम्बद्धता मूल्य ज्ञात किया गया। इसमें अधिकतम मूल्य 166 तथा न्यूनतम मूल्य 1 प्राप्त हुआ। अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में न्यूनतम मूल्य 3 से ऊपर के सेवा केन्द्रों का चयन किया गया। सर्वाधिक सम्बद्धता मूल्य देवरिया मुख्यालय का 166 प्राप्त हुआ है। पुनः इन मूल्यों के आधार पर सेवाकेन्द्रों के सम्बद्धता मूल्य सूचकांक की गणना की गयी है। सेवाकेन्द्रों के सम्बद्धता मूल्य एव सम्बद्धता मूल्य सूचकांक को सारणी (44) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-44

परिवहनीय सम्बद्धता सूचकांक जनपद देवरिया

क्रम	सेवाकेन्द्र	सम्बद्धता मूल्य	सम्बद्धता मूल्य सूचकांक
1	2	3	4
1	देवरिया	166	55 33
2	सलेमपुर	139	46 00
3	गौरीबाजार	114	38 00
4	बैतालपुर	93 5	31 16
5	भटनी बाजार	79 5	26 50
6	गौरा बरहज	78 0	26 00
7	हेतिमपुर	78 0	26 00
8	लार	65 5	21 83
9	रामपुर कारखाना	65 5	21 83
10	मईल	65 5	21 83
11	भाटपार	64 0	21 33
12	रुद्रपुर	62 0	20 66
13	खुखुन्दू	59 5	19 83
14	बनकटा	58 0	19 33
15	सतरौव	58 0	19 33
16	तरकुलवाँ	53 5	17 83
17	पैना	53 5	17 83
18	नौनापार	46 0	15 33

19	मझगौंव	41 5	13 83
20	नूनखार	41 5	13 83
21	भागलपुर	39 5	13 16
22	महेन	29 5	9 83
23	बखरा	29 5	9 83
24	नारायणपुर	29 5	9 83
25	इन्दूपुर	29 5	9 83
26	रामलछन	29 5	9 83
27	मदनपुर	28 0	9 33
28	बलटीकरा	28 0	9 33
29	मझौलीराज	24 0	8 00
30	सोहनपुर	19 5	6 50
31	बरियारपुर	19 5	6 50
32	भिगारीबाजार	18 0	6 00
33	कचनपुर	18 0	6 00
34	पथरदेवा	15 0	5 00
35	भलुअनी	15 0	5 00
36	खोरीबारी रामपुर	15 0	5 00
37	देसही देवरिया	13 5	4 50
38	रामपुर अवस्थी	13 5	4 50
39	प्रतापपुर	12 0	4 00
40	बघउचघाट	12 0	4 00
41	सोहनाग	12 0	4 00
42	खोरमा कन्हौली	12 0	4 00
43	बिसुनपुरा	12 0	4 00
44	खामपार	12 0	4 00
45	पिण्डी	7 5	2 5
46	पकडी बाजार	3 0	1 00
47	घाटी	3 0	1 00





स्रोत- चित्र 43 से परिकलित

सारणी से स्पष्ट है कि सम्बद्धता सूचकांक और सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता में घनात्मक सम्बन्ध है। प्रायः वे सेवाकेन्द्र उच्च सेवा वाले हैं जिनका सम्बद्धता सूचकांक भी उच्च है। जनपद के सभी सेवाकेन्द्रों को परिवहन मार्गों के साथ चित्र स (43) में दर्शाया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त **तीनों आधारों—औसत कार्याधार जनसंख्या उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप एवं परिवहनीय सम्बद्धता** के आधार पर जनपद में 47 केन्द्रों को **सेवाकेन्द्र** के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है चित्र (41)। तीनों ही आधारों से इस बात की पुष्टि होती है कि उच्च सूचकांक उच्च सेवाकेन्द्र एवं निम्न सूचकांक निम्न सेवाकेन्द्र को प्रदर्शित करते हैं। इस आधार

CONNECTIVITY OF SERVICE CENTRES IN DEORIA DISTRICT (2002)

ORDER OF CENTRES

- FIRST ORDER 
- SECOND ORDER 
- THIRD ORDER 
- FOURTH ORDER 

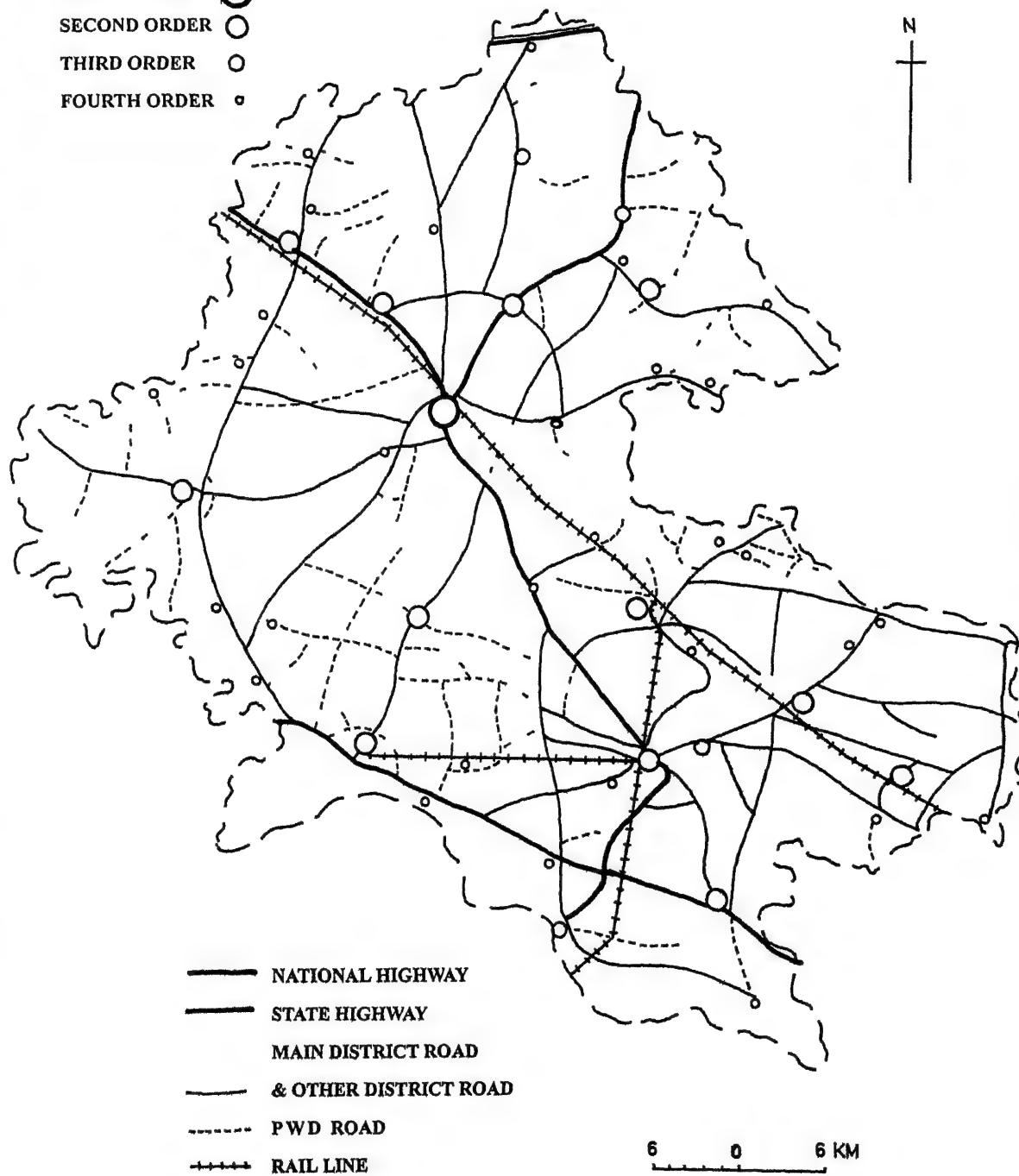


FIG 4.3

पर *देवरिया* सबसे बड़ा सेवाकेन्द्र है। जो औसत कार्याधार जनसंख्या उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप और परिवहनीय सम्बद्धता तीनों ही दृष्टियों से उच्च सूचकांक रखता है।

4.4 सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता

किसी केन्द्र की केन्द्रीयता उसके द्वारा सम्पादित कार्यों के गुण और उनकी मात्रा का द्योतक है।²⁹ केन्द्रीयता से सेवाकेन्द्रों के महत्व का आकलन तथा सापेक्षिक महत्व का पता चलता है। इससे सेवाकेन्द्रों का निर्धारण भी किया जाता है। भट्ट³⁰ ने कार्यों की मात्रा एवं गुण के साथ-साथ कार्यों की सम्भाव्यता को केन्द्रीयता कहा है। यद्यपि किसी केन्द्र की केन्द्रीयता का उसके जनसंख्या आकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी जनसंख्या आकार तथा केन्द्रीयता में ऋणात्मक सम्बन्ध भी दृष्टिगत होता है।

केन्द्रीयता का निर्धारण एक जटिल एवं व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका निर्धारण एक या एक से अधिक आधारों पर किया जा सकता है। क्रिस्टालर (1933)³¹ ने दक्षिणी जर्मनी में टेलीफोन कनेक्शन के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। उनकन³² ब्रश³³ स्मेल्स³⁴ कार्टर³⁵ उलमैन³⁶ हार्टले एवं स्मेल्स³⁷ तथा कार³⁸ आदि विद्वानों ने किसी केन्द्र पर पाए जाने वाले सभी चयनित कार्यों के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। ब्रेसी³⁹ ने केन्द्र के आकर्षण शक्ति के आधार पर तथा ग्रीन⁴⁰ कारुथर्स⁴¹ ने आकर्षण शक्ति के साथ-साथ केन्द्रों की विभिन्न केन्द्रों से परिवहन सम्बद्धता को भी ध्यान में रखा है। सिद्दाल⁴² ने फुटकर और थोक व्यापार अनुपात तथा एबियादेन⁴³ ने 1967 में बहु-विचर विश्लेषण (मल्टी वेरीएट एनालिसिस) के द्वारा केन्द्रीयता का निर्धारण किया। 1971 में प्रेस्टन⁴⁴ ने फुटकर व्यापार तथा औसत परिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मॉडल प्रस्तुत किया। किन्तु ऑकडो पर अत्यधिक निर्भरता इसके व्यावहारिक प्रयोग को सीमित कर देती है। वाशिंगटन के स्नोहिमश काउण्टी के अध्ययन में बेरी और गैरिशन⁴⁵ ने 1958 में केन्द्र की केन्द्रीयता निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों व उसकी कार्याधार जनसंख्या और पदानुक्रम का उपयोग किया।

भारतीय विद्वानों ने भी केन्द्रीय स्थलों की केन्द्रीयता का निर्धारण अधिकांशतः केन्द्रीय कार्यों के संख्या के आधार पर किया है। कार्यों के आधार पर विश्वनाथ (1967)⁴⁶ ओपी सिंह (1971)⁴⁷ प्रकाशराव (1974)⁴⁸, जगदीश सिंह (1976)⁴⁹ आदि विद्वानों ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यों की परस्पर यातायात सम्बद्धता के आधार पर बहुत कम कार्य हुआ है, फिर भी जैन (1971)⁵⁰ तथा ओपी सिंह ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों के केन्द्रीयता निर्धारण में *कार्यों* को आधार बनाया गया है। कार्यों के महत्व एवं मूल्य की गणना प्रत्येक कार्य के औसत कार्याधार जनसंख्या सूचकांक के द्वारा की गयी है। इस क्रम में कार्यों के मूल्य की गणना हेतु प्रत्येक कार्य के कार्याधार जनसंख्या में

क्षेत्र में सम्पादित न्यूनतम कार्याधार जनसंख्या वाले कार्य की कार्याधार जनसंख्या से भाग दिया गया है। इससे प्राप्त कार्यों के मूल्य को सारणी (4 2) में प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीयता निर्धारण में कार्यों के मूल्य के अनुसार ही केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व को भी आँकने का प्रयास किया जाता है। अतः केन्द्रों के महत्व की गणना के लिए सेवाकेन्द्रों के सेवित जनसंख्या को भी गणना में शामिल किया गया है क्योंकि सेवित जनसंख्या से भी केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व का ज्ञान होता है। सामान्यतया उच्च स्तरीय कार्यों और केन्द्रों द्वारा सेवित क्षेत्र एवं जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। कार्यों के महत्व की तीव्रता का अनुमान किसी केन्द्र द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यों के मूल्य को जोड़कर किया गया है तथा इसे *कार्यात्मक अंक (फ़ंक्शनल स्कोर)* की सजा प्रदान की गयी है। अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित सेवाकेन्द्रों में से सबसे कम कार्यात्मक अंक से सभी सेवाकेन्द्रों के कार्यात्मक अंकों को भाग देकर *कार्यात्मक सूचकांक* प्राप्त किया गया है। प्रत्येक केन्द्र का कार्यात्मक अंक एवं सूचकांक सारणी (4 5) में प्रदर्शित है। प्रत्येक केन्द्र की कुल सेवित जनसंख्या को न्यूनतम जनसंख्या वाले केन्द्र की जनसंख्या से विभाजित करके *सेवित जनसंख्या सूचकांक* प्राप्त किया गया है। कार्यात्मक सूचकांक की ही भाँति सेवित जनसंख्या सूचकांक भी सापेक्षिक महत्व को उपयुक्त ढंग से व्यक्त करता है। प्रत्येक केन्द्र के कार्यात्मक सूचकांक और सेवित जनसंख्या सूचकांक को जोड़कर उनके *केन्द्रीयता अंक* निर्धारित किए गए हैं। इस केन्द्रीयता अंक से उपर्युक्त विधि द्वारा *केन्द्रीयता सूचकांक* परिकलित की गयी है। केन्द्रीयता अंक की अपेक्षा केन्द्रीयता सूचकांक केन्द्रों की सापेक्षिक केन्द्रीयता को व्यक्त करने में अधिक समर्थ है। सारणी (4 5) में विभिन्न केन्द्रों के केन्द्रीयता सूचकांक प्रदर्शित हैं।

सारणी 4 5
सेवाकेन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

क्र.स.	सेवाकेन्द्र का नाम	कार्यात्मक अंक	कार्यात्मक सूचकांक	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता सूचकांक
1	देवरिया	1655 79	100 29	2730376	76 89	177 18	68 67
2	रुद्रपुर	495 86	30 03	149894	42 16	72 19	27 98
3	भाटपार	402 04	24 35	130166	36 61	60 96	23 62
4	सलेमपुर	582 93	35 30	155812	43 82	79 12	30 66
5	लार	346 14	20 96	142900	40 19	61 15	23 70
6	गौरी बाजार	401 98	24 34	168959	47 52	71 86	27 85
7	पथरदेवा	259 08	15 69	190227	53 50	69 19	26 81
8	गौरा बरहज	511 24	30 96	126603	35 61	66 57	25 80
9	महेन	73 43	4 44	18020	5 06	9 50	3 68
10	रामपुर कारखाना	330 62	20 02	130341	36 66	56 68	21 96
11	देसही देवरिया	107 08	6 48	112219	31 56	38 04	14 74
12	भटनी बाजार	356 52	21 59	134042	37 70	59 29	22 98

13	भलुअनी	238 91	14 47	140643	39 56	54 05	20 94
14	बनकटा	256 06	15 50	116683	32 82	48 32	18 72
15	भागलपुर	125 56	7 60	105645	29 71	37 31	14 46
16	मझगाँवा	86 59	5 24	13525	3 80	9 04	3 50
17	बैतालपुर	211 21	12 79	144957	40 77	53 56	20 75
18	खुखुन्दू	89 19	5 40	23214	6 69	12 09	4 68
19	मईल	94 11	5 70	7348	2 06	7 76	3 00
20	भिगारी बाजार	21 47	1 30	8094	2 27	3 57	1 38
21	खामपार	67 49	4 08	16471	4 63	8 71	3 37
22	सोहनपुर	35 83	2 17	17206	4 83	7 00	2 71
23	पिण्डी	30 15	1 82	29980	8 43	10 25	3 97
24	रामलछन	27 63	1 67	8536	2 40	4 07	1 57
25	बखरा	71 46	4 32	19340	5 44	9 76	3 78
26	बिसुनपुरा	65 25	3 95	23695	6 66	10 61	4 11
27	पकडी बाजार	93 74	5 67	19584	5 50	11 17	4 32
28	मझौली राज	290 88	17 61	45614	12 83	30 44	11 79
29	पैना	54 72	3 31	25104	7 06	10 37	4 01
30	बघौचघाट	26 11	1 58	7714	2 16	3 74	1 44
31	रामपुर अवस्थी	26 23	1 58	3555	1 00	2 58	1 00
32	तरकुलवों	129 51	7 84	55829	15 70	23 54	9 12
33	कचनपुर	26 23	1 58	5456	1 53	3 11	1 20
34	हेतीमपुर	35 83	2 17	4487	1 26	3 43	1 32
35	नूनखार	57 58	3 48	9830	2 76	6 24	2 41
36	घाटी	16 51	1 00	6165	1 73	2 73	1 05
37	मदनपुर	68 71	4 16	26929	7 57	11 73	4 54
38	खोरमा कन्हौली	26 23	1 58	6750	1 89	3 47	1 34
39	बरियारपुर	26 83	1 62	8185	2 30	3 92	1 52
40	बलटीकरा	29 23	1 77	4095	1 15	2 92	1 13
41	इन्दूपुर	60 66	3 67	20125	5 66	9 33	3 61
42	सतराँव	41 81	2 53	9648	2 71	5 24	2 03
43	नोनापार	60 7	3 60	13480	3 79	7 46	2 89
44	सोहनाग	54 7	3 31	5602	1 57	4 88	1 89
45	प्रतापपुर	82 15	4 97	17203	4 83	9 80	3 79
46	नारायणपुर	103 56	6 27	11745	3 30	9 57	3 70
47	खोरीबारी रामपुर	47 39	2 87	16022	4 50	7 37	2 85

4.5 सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रम

सेवाकेन्द्र का महत्व क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए आर्थिक सतुलन सामाजिक कल्याण आर्थिक विकास एवं वृद्धि की अवधारणा को मौलिक आधार प्रदान करता है। सेवाकेन्द्र न केवल अपनी सेवा— परिधिगत ग्रामीण भू-भाग के जन समुदाय की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की ही पूर्ति करता है वरन् अपने प्रदेश में स्थित अन्य छोटे सेवाकेन्द्रों को भी सेवाएँ प्रदान करता है। इस प्रकार इन सेवाकेन्द्रों को उनकी सेवा के महत्व क्रम या कार्यात्मक शृंखलाबद्धता के आधार पर श्रेणीबद्ध करने को 'सेवाकेन्द्र-पदानुक्रम' कहते हैं।

सेवाकेन्द्र समूह कार्यात्मक रूप से एक गुफन प्रतिरूप (Nesting Pattern) में सगठित पाये जाते हैं। इस गुफन प्रक्रिया में छोटे- बड़े केन्द्र इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि छोटे क्रम के केन्द्र बड़े केन्द्र के प्रभाव क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं फिर भी अपना स्वतन्त्र सेवाक्षेत्र बनाये रखते हैं। वस्तुतः पदानुक्रम की सकल्पना सेवाकेन्द्रों के आकार कार्य एवं सेवाओं के वितरण की तारतम्यता का प्रतिपादन करती है तथा इसके अनुसार केन्द्रों की सातत्य प्रवृत्ति भी प्रदर्शित होती है। पदानुक्रम किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक विकास प्रक्रिया के लिये सरचनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रेरक अभिज्ञानों का प्रचार एवं प्रसार सेवाकेन्द्र- पदानुक्रम के माध्यम से ही होता है।

सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता सेवित क्षेत्र प्रदत्त सेवाओं की महत्ता तथा उनकी क्षेत्रीय एवं जनाकिकीय आकार के आधार पर विभिन्न कर्मिक वर्गों में व्यवस्थित करने को ही *पदानुक्रम* कहते हैं। किसी क्षेत्र के सेवाकेन्द्र- पदानुक्रम व्यवस्था के अध्ययन से ही यह पता लगाया जा सकता है कि सेवाकेन्द्रों में अभिज्ञानों को आत्मसात् एवं प्रसारित करने की कितनी क्षमता है। इसके लिए आवश्यक है, सेवाकेन्द्रों के वितरण प्रतिरूप का ज्ञान क्योंकि सभी सेवाकेन्द्र एक से नहीं होते।

सेवाकेन्द्र पदानुक्रम से ही ज्ञात होता है कि ये कितने महत्व के हैं? उनका पदानुक्रमिक सगठन कैसा है? उनमें अवस्थापनात्मक कमियाँ कितनी हैं? तथा उनमें अन्तर्सम्बन्ध कितना गहन एवं सुदृढ़ है? इत्यादि। सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रम व्यवस्था का अध्ययन विविध पदानुक्रमीय श्रेणी के केन्द्रों के अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन हेतु आवश्यक है साथ ही सेवाकेन्द्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों के अध्ययन हेतु भी अपरिहार्य है।

पदानुक्रम निर्धारण के लिए मुख्य रूप से केन्द्रीयता को आधार माना जाता है। केन्द्रीयता निर्धारण हेतु विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों एवं विधि तन्त्रों का प्रयोग किया है। *अध्ययन क्षेत्र* में सेवाकेन्द्रों को विभिन्न पदानुक्रम में विभक्त करने के लिए *केन्द्रीयता* को आधार बनाया गया है। केन्द्रीयता का निर्धारण विभिन्न *कार्यों के मूल्य* एवं *सेवित जनसंख्या* के आधार पर निम्न सूत्र की सहायता से किया गया है—

$$Wfi = \frac{Mti}{Wtl}$$

जहाँ Wfi = कार्य (i) का कार्यात्मक मूल्य

Mti = (i) कार्य का औसत कार्याधार मूल्य

Wtl = शृंखला में निम्नतम औसत कार्याधार मूल्य

इसके बाद प्रत्येक सेवाकेन्द्र के कार्यात्मक अंक की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की गयी—

$$Fv(i) = (Fui \times Wfi)$$

Fvi = सेवाकेन्द्र (i) का कार्यात्मक मूल्य

Fvi = कार्य एवं सेवाओं की संख्या (1 2 3 n)

Wfi = प्रत्येक कार्य (1 2 3 n) का कार्यात्मक मूल्य

पुन कार्यात्मक सूचकांक निम्न सूत्र से निकाला गया—

$$Fci = \frac{Fv(i)}{Fvl}$$

जहाँ— Fci = कार्यात्मक सूचकांक

$Fv(i)$ = सेवाकेन्द्र का कार्यात्मक मूल्य

Fvl = शृंखला में निम्नतम कार्यात्मक मूल्य

इसी प्रकार सेवित जनसंख्या की गणना सेवाकेन्द्र के चतुर्दिक जनसंख्या जहाँ तक सेवाएँ प्रत्यक्षत पहुँचती हैं को जोड़कर की गई। पुन उपर्युक्त सूत्रों की तरह ही सेवित जनसंख्या सूचकांक की गणना की गई। सेवाकेन्द्र की केन्द्रीयता के लिए कार्यात्मक सूचकांक और सेवित जनसंख्या सूचकांक के मूल्यों को जोड़ दिया गया पुन निम्न सूत्र से सेवाकेन्द्र के केन्द्रीयता सूचकांक को प्राप्त किया गया—

$$Ci = \frac{Cv}{Cvl}$$

जहाँ— Ci = केन्द्रीयता सूचकांक

Cv = केन्द्रीयता मूल्य

Cvl = शृंखला में न्यूनतम केन्द्रीयता मूल्य,

इस प्रकार उपर्युक्त सूत्रों की सहायता से अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों की केन्द्रीयता ज्ञात की गयी और इनमें चार पदानुक्रम विनिश्चित किए गये। कार्यों के कार्याधार मूल्य को सारणी (4 2) में तथा केन्द्रीयता सूचकांक के परिकलन को सारणी (4 5) में दर्शाया गया है। केन्द्रीयता सूचकांक के आधार पर सेवाकेन्द्र पदानुक्रम सारणी (4 6) में प्रदर्शित है।

सारणी- 4 6
सेवाकेन्द्र पदानुक्रम

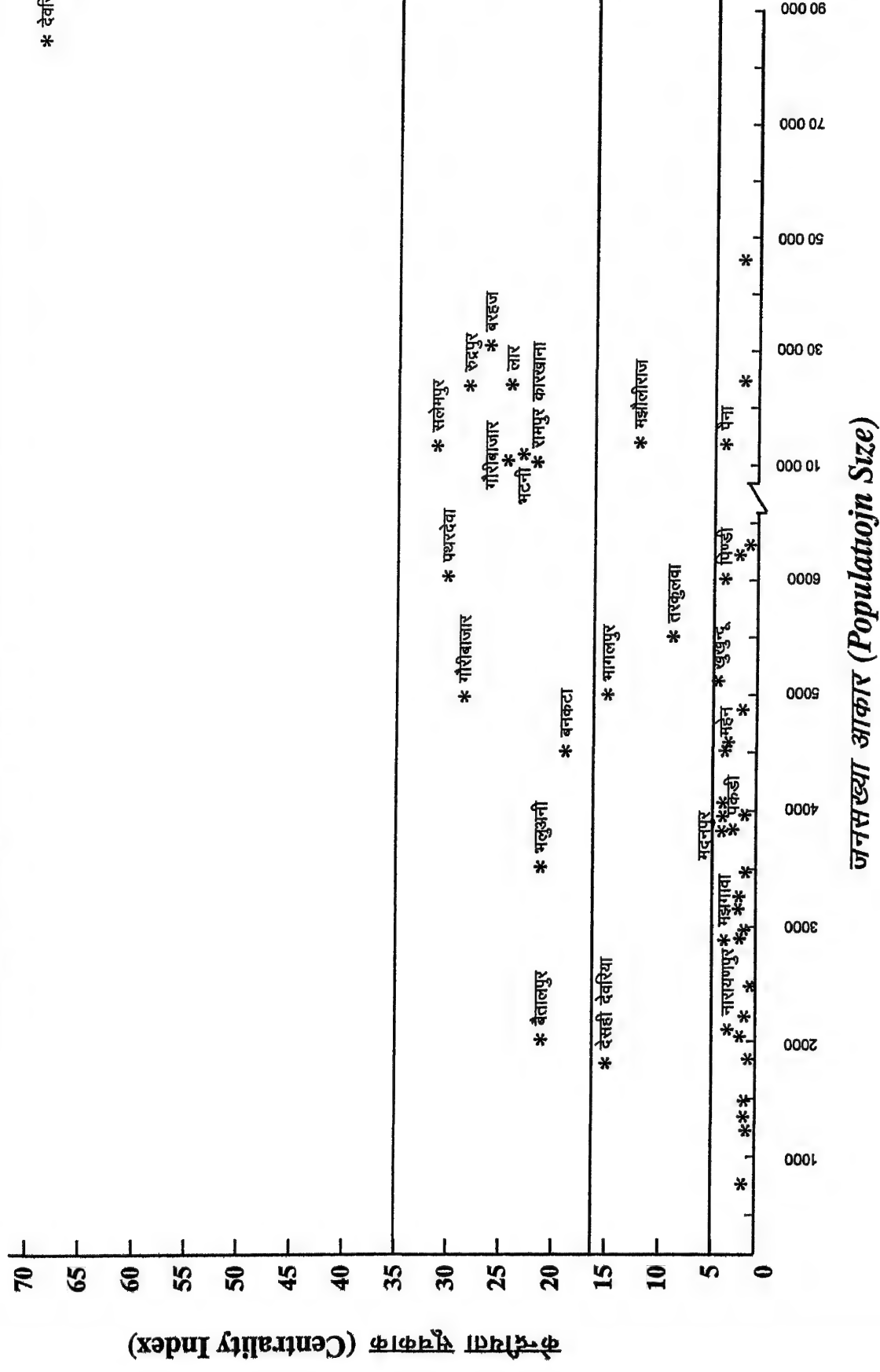
क्रम स	सेवाकेन्द्र	केन्द्रीयता
<i>प्रथम अनुक्रम</i>		
1	देवरिया	68 67
<i>द्वितीय अनुक्रम</i>		
2	सलेमपुर	30 66
3	रुद्रपुर	27 98
4	गौरी बाजार	27 85
5	पथरदेवा	26 81
6	गौराबरहज	25 80
7	लार	23 70
8	भाटपार	23 62
9	भटनी बाजार	22 98
10	रामपुर कारखाना	21 96
11	भलुअनी	20 94
12	बैतालपुर	20 75
13	बनकटा	18 72
<i>तृतीय अनुक्रम</i>		
14	देसही देवरिया	14 74
15	भागलपुर	14 46
16	मझाली राज	11 79
17	तरकुलवों	9 12
<i>चतुर्थ अनुक्रम</i>		
18	खुखुन्दू	4 68
19	मदनपुर	4 54
20	पकडी बाजार	4 32
21	बिसुनपुरा	4 11
22	पैना	4 01
23	पिण्डी	3 97
24	प्रतापपुर	3 79
25	बखरा	3 78
26	नारायणपुर	3.70

27	महेन	3 68
28	इन्दूपुर	3 61
29	मझगौवा	3 50
30	खामपार	3 37
31	मईल	3 00
32	नोनापार	2 89
33	खोरीबारी रामपुर	2 85
34	सोहनपुर	2 71
35	नूनखार	2 41
36	सतराँव	2 03
37	सोहनाग	1 89
38	रामलछन	1 57
39	बरियारपुर	1 52
40	बघउचघाट	1 44
41	भिगारी बाजार	1 38
42	खोरमा कन्हौली	1 34
43	हेतिमपुर	1 32
44	कचनपुर	1 20
45	बलटीकरा	1 13
46	घाटी	1 05
47	रामपुर अवस्थी	1 00

सारणी 47
सेवाकेन्द्रों की पदानुक्रमीय व्यवस्था

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता सूचकांक वर्ग	केन्द्रों की संख्या
1	68 67 से अधिक	1
2	18 72 से 30 66	12
3	9 12 से 14 74	4
4	1 00 से 4 68	30

सारणी (4 6) में प्रस्तुत सेवाकेन्द्रों की पदानुक्रमीय व्यवस्था में केन्द्रीयता की असमानता को ध्यान में रखकर केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। सेवाकेन्द्रों के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के निर्धारण के लिए उनके केन्द्रीयता सूचकांक के सातत्य को भग करने वाले अलगाव बिन्दुओं को सीमा माना गया है। सारणी (4 6) तथा रेखाचित्र (4 4) से स्पष्टतः **तीन** अलगाव बिन्दु दृष्टिगत होते हैं जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों के चार पदानुक्रम निश्चित किए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र में प्रथम स्तर का एक केन्द्र मात्र देवरिया है जो जनपद मुख्यालय भी है। द्वितीय स्तर के 12 केन्द्र हैं जो सभी प्रखण्ड विकास केन्द्र हैं। इनमें पाँच तहसील मुख्यालय भी शामिल हैं। तृतीय स्तर के सेवाकेन्द्रों की संख्या 4 है, जिसमें देसही देवरिया और भागलपुर दो



HIERARCHICAL DISTRIBUTION OF SERVICE CENTRE DISTRICT DEORIA

ORDER OF CENTRES

FIRST ORDR

SLCOND ORDLR

THIRD ORDER

FOURTH ORDER

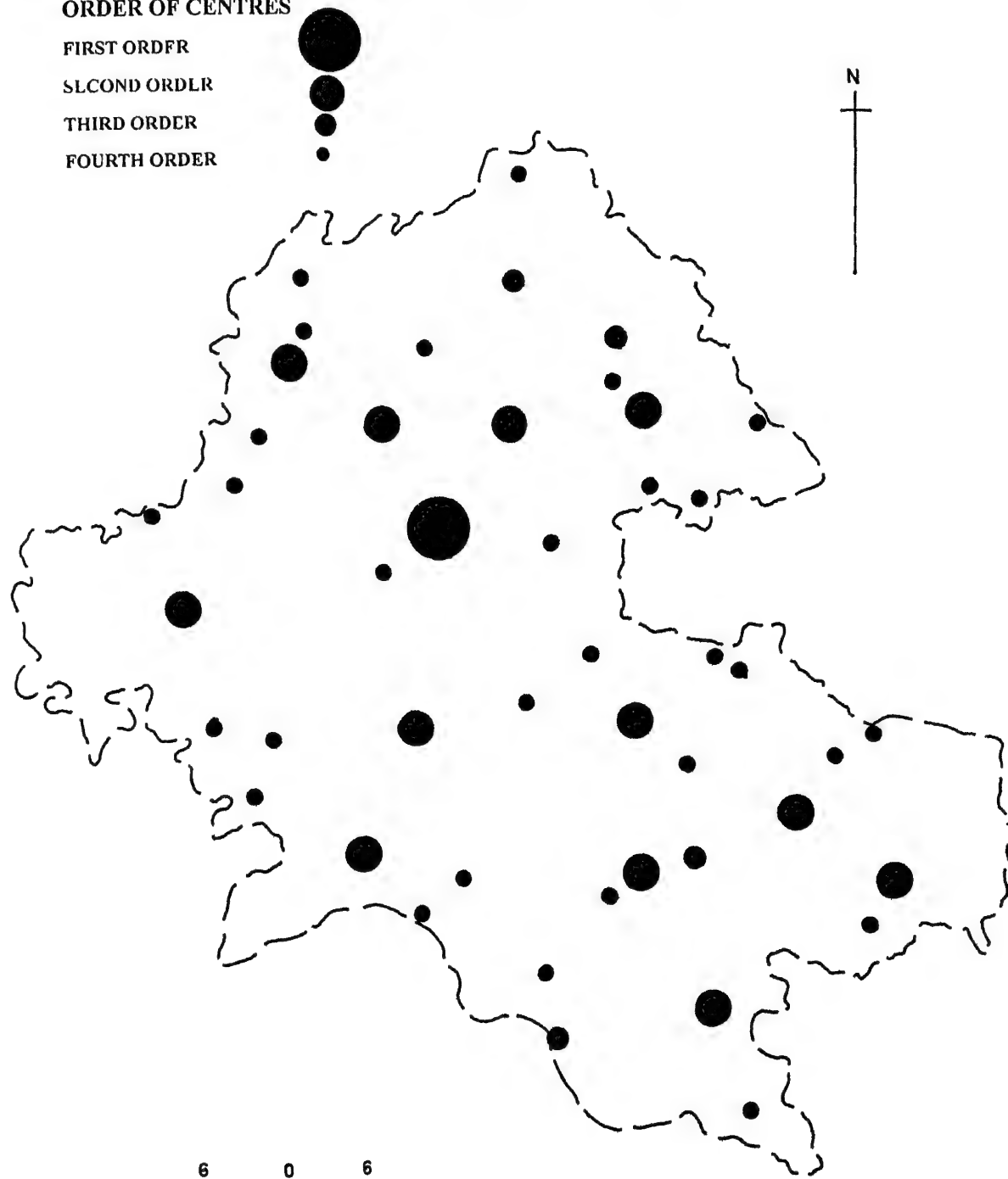


FIG 4 5

प्रखण्ड विकास केन्द्र मुख्यालय है। चतुर्थ स्तर के केन्द्रों की संख्या सर्वाधिक 30 है।

प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीयता के आधार पर प्रस्तुत सेवाकेन्द्र पदानुक्रम को *कार्याधार जनसंख्या उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप* और *परिवहनीय सम्बद्धता* के साथ देखने पर सभी से उसकी पुष्टि होती है। रेखाचित्र (4.4) में सेवाकेन्द्रों को उनकी केन्द्रीयता एवं उनके जनसंख्या आकार के साथ प्रदर्शित किया गया है। चित्र (4.5) में सेवाकेन्द्रों का पदानुक्रमिक वितरण प्रदर्शित है।

4.6 सेवाकेन्द्रों का सेवाक्षेत्र

सेवाक्षेत्र सेवाकेन्द्र के चतुर्दिक स्थित वह क्षेत्र होता है जो सेवाकेन्द्र की विभिन्न सेवाओं द्वारा लाभान्वित होता है तथा जो सेवाकेन्द्र को विभिन्न ससाधनों की आपूर्ति करता है। यह अभिकेन्द्रीय (Centrifugal) उभय बलों से प्रभावित होता है। इसमें प्रथम द्वारा संगृहीत तथा द्वितीय द्वारा वितरक सेवाओं को पोषण मिलता है। इस प्रकार सेवाकेन्द्र क्षेत्रीय वस्तुओं के संग्रह एवं केन्द्रीय वस्तुओं के वितरण का कार्य करता है। जहाँ यह अपने अस्तित्व हेतु प्रभाव क्षेत्र के ससाधनों पर निर्भर रहता है वही सेवाक्षेत्र के निवासी अपनी बहुत सी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सेवाकेन्द्र पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक सेवाकेन्द्र अपने पृष्ठ प्रदेश से कुछ लेता है और बदले में उसे कुछ देता है। इस आदान-प्रदान की क्रिया पर ही सेवाकेन्द्र और उसके सेवाक्षेत्र की समृद्धि एवं प्रत्याशंसा निर्भर करती है।

इस सेवाक्षेत्र के परिसीमन हेतु कई गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों का उपयोग किया गया है। *क्रिस्टालर* एवं *लॉश* ने सेवाकेन्द्रों के सौपानिक सम्बन्ध पर आधारित आगमनिक उपागम का प्रयोग किया है। *गोडलुण्ड* (1956) और *ग्रीन* (1952) ने बस सेवाओं के ऑकड़ों का इस परिसीमन में प्रयोग किया है। *स्मेल्स* (1944) *डिकिन्सन* (1964) प्रभृति ने निगमनिक प्रक्रमों द्वारा इस सीमा क्षेत्र के निर्धारण का प्रयास किया है, जबकि *ब्रेसी* (1953 एवं 1956) ने एतदर्थ केन्द्रीयता के ग्रामीण उपादान का प्रयोग किया है। हाल में *बेरी* (1967)⁵¹ ने *रीले* (1931) के 'फुटकर केन्द्राकर्षण नियम' (Law of retail gravitation) एवं 'फुटकर केन्द्राकर्षण नियम' (Breaking point equation) का प्रयोग कर इस कार्य को आसान बना दिया है। उनके द्वारा प्रयुक्त सूत्र का विवरण निम्नवत् है—

$$L_s = \frac{D}{1 + \sqrt{\frac{A_c}{B_c}}}$$

जहाँ	D	=	दो (A और B) सेवाकेन्द्रों के मध्य दूरी
	A _c	=	केन्द्र A का केन्द्रीयता गणन
	B _c	=	केन्द्र B का केन्द्रीयता गणन, एवं
	L _s	=	A केन्द्र के सेवाक्षेत्र का B से विस्तार, (किमी या मील में)

उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए अध्ययन क्षेत्र के चार सोपानिक सेवाकेन्द्रों के सेवाक्षेत्रों को चित्र (46) में प्रदर्शित किया गया है। जहाँ प्रथम सेवाकेन्द्र देवरिया का प्रभाव समूचे जनपद पर फैला है वहीं सलेमपुर रुद्रपुर गौरीबाजार पथरदेवा गौरा बरहज लार भाटपार भटनीबाजार रामपुर कारखाना भलुअनी बैतालपुर बनकटा द्वितीय स्तर के प्रभावशाली सेवाकेन्द्र हैं जिनका विवरण निम्नवत है— (चित्र— 46)।

(1) सलेमपुर सेवाक्षेत्र

इस क्षेत्र का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण—मध्य पूरब में है। इसके अतर्गत तृतीय स्तर का सेवाकेन्द्र मझौली राज तथा चतुर्थ स्तर का सेवाकेन्द्र सोहनाग स्थित है। यह क्षेत्र परिवहन मार्गों से सुसम्बद्ध है और यह सम्पूर्ण दक्षिणी—पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दैनिक बाजार डिस्पेन्सरी उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय इण्टर कॉलेज पोस्ट एव टेलीग्राफ कार्यालय बैंकिंग आदि की सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं। यह सेवाक्षेत्र देवरिया के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेवाक्षेत्र है। सलेमपुर तहसील मुख्यालय एव प्रखण्ड विकास केन्द्र भी है।

(2) रुद्रपुर सेवाक्षेत्र

इस सेवाक्षेत्र का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के सबसे पश्चिमी भाग में है। इसके अतर्गत चतुर्थ स्तर के तीन सेवाकेन्द्र मदनपुर पकड़ी बाजार और खोरमा कन्हौली प्रखण्ड विकास केन्द्र का मुख्यालय भी है। यह क्षेत्र सड़क मार्ग द्वारा देवरिया से अच्छी तरह सम्बद्ध है। इस क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र इण्टर और डिग्री कॉलेज बैंकिंग, टेलीफोन पुलिस स्टेशन आदि सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं।

(3) गौरीबाजार सेवाक्षेत्र

यह सेवाक्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के उत्तर—पूर्व में विस्तृत है। इसके अतर्गत चतुर्थ स्तर के चार सेवाकेन्द्र स्थित हैं— बखरा नारायणपुर इन्द्रपुर एव रामलछन ये सभी केन्द्र सड़क मार्ग से सीधे जुड़े हुए हैं तथा गौरीबाजार तहसील एव प्रखण्ड मुख्यालय होने के कारण सभी कार्यों एव सेवाओं का प्रमुख केन्द्र है। यह रेलमार्ग से भी सम्बद्ध है।

(4) पथरदेवा सेवाक्षेत्र

यह क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के उत्तर—पूर्व में अवस्थित एक प्रमुख सेवाक्षेत्र है। जिसमें तृतीय स्तर का एक सेवाकेन्द्र तरकुलवाँ एव चतुर्थ स्तर के चार सेवाकेन्द्र क्रमशः कचनपुर बघउच घाट बिसुनपुरा एव रामपुरअवस्थी स्थित है। पथरदेवा प्रखण्ड विकास केन्द्र मुख्यालय होने के कारण प्रशासनिक एव वित्तीय सेवाओं का केन्द्र है। यह क्षेत्र सड़क मार्ग से पूरी तरह सम्बद्ध है।

(5) गौरा बरहज सेवाक्षेत्र

सुदूर दक्षिण में घाघरा की गोदी में विस्तृत यह क्षेत्र खादर प्रदेश का एक प्रमुख सेवाक्षेत्र है। यह अपने पश्चिम में स्थित रुद्रपुर सेवा केन्द्र एव पूर्व स्थित लार सेवाकेन्द्र से सड़क मार्ग से तथा सलेमपुर से रेलमार्ग से प्रत्यक्षत जुड़ा हुआ है। देवरिया से यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह सम्बद्ध है। इस सेवाक्षेत्र में चतुर्थ स्तरीय तीन सेवाकेन्द्र— महेन सतराँव एव पैना स्थित हैं। गौरा बरहज तहसील एव प्रखण्ड मुख्यालय का केन्द्र है इसके अलावे यह शैक्षणिक, वित्तीय व्यापारिक एव चिकित्सा का भी प्रमुख केन्द्र है।

SERVICE AREAS OF SERVICE CENTRE, DISTRICT DEORA

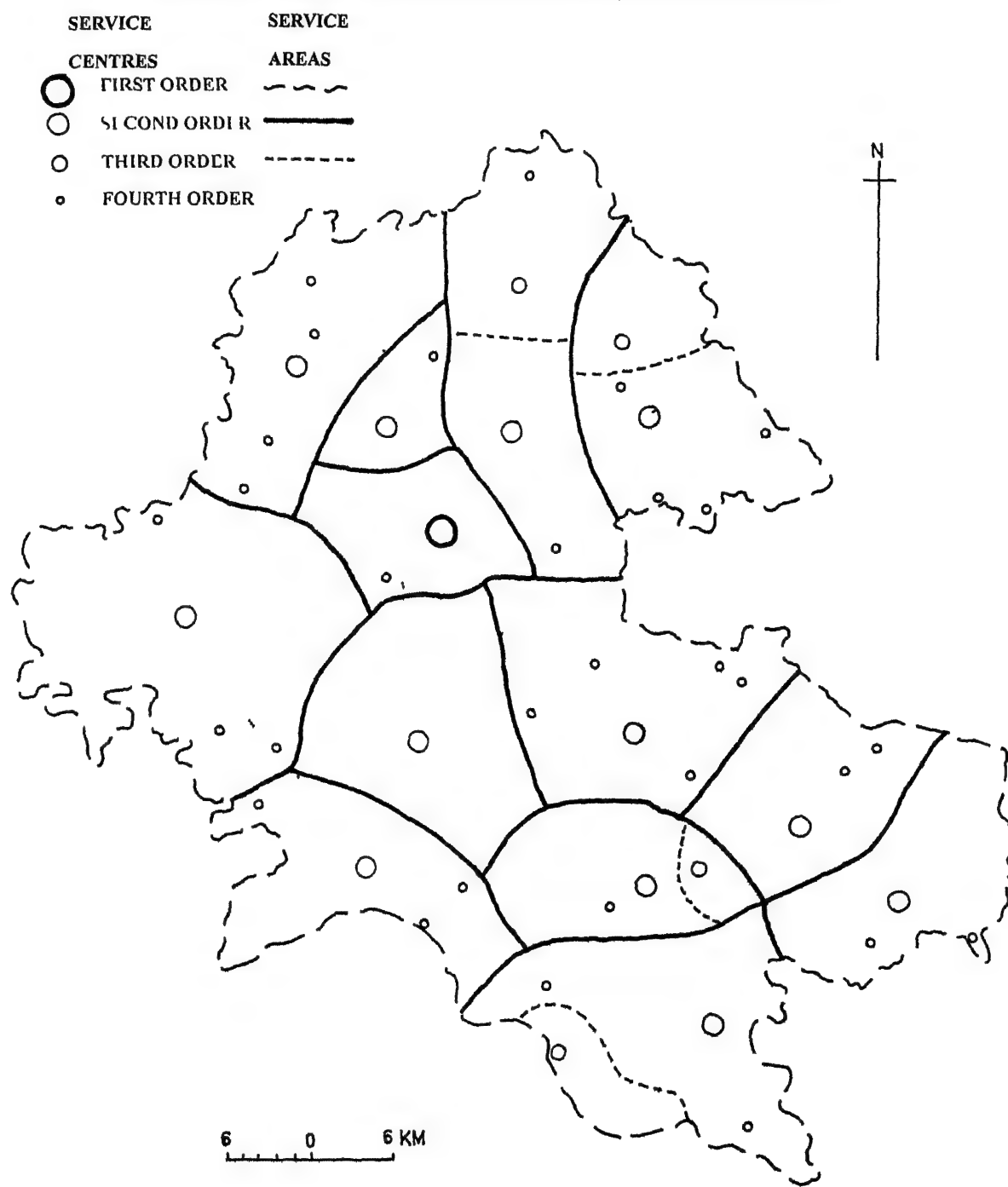


FIG 46

(6) लार सेवाक्षेत्र

जनपद के दक्षिणी-पूर्वी कोने पर अवस्थित यह प्रमुख सेवाक्षेत्र है। इसमें तृतीय स्तर का एक सेवाकेन्द्र भागलपुर एवं चतुर्थस्तरीय दो सेवाकेन्द्र मईल एवं पिण्डी स्थित हैं। लार सेवाकेन्द्र सभी कार्यों एवं सेवाओं का केन्द्र है तथा देवरिया से यह सड़क मार्ग से सम्बद्ध है।

(7) भाटपार सेवाक्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग का यह प्रमुख सेवाक्षेत्र है। इसके अतर्गत दो सेवाकेन्द्र भिगारी बाजार एवं खामपार समाहित हैं। भाटपार सभी कार्यों एवं सेवाओं का केन्द्र है तथा देवरिया से रेलमार्ग से जुड़ा है।

(8) भटनीबाजार सेवाक्षेत्र

भाटपार सेवाकेन्द्र के पश्चिम में अवस्थित यह सेवाक्षेत्र अपने अन्तर्गत चतुर्थ स्तरीय सर्वाधिक पाँच सेवाकेन्द्रों—खुखुन्द, नूनखार खोरीबारी रामपुर घाटी नोनापार, को समाहित किए है। भटनी सेवाकेन्द्र देवरिया से सीधे रेलमार्ग से जुड़ा है। यह सेवाक्षेत्र भी सभी तरह के कार्यों एवं सेवाओं से सम्पन्न है। भटनी प्रखण्ड विकास केन्द्र का मुख्यालय भी है।

(9) रामपुर कारखाना सेवाक्षेत्र

देवरिया के उत्तर में यह अपेक्षाकृत छोटा सेवाक्षेत्र विस्तृत है जिसमें चतुर्थ स्तरीय एक मात्र सेवाकेन्द्र बरियारपुर स्थित है। यह सेवाक्षेत्र सड़क मार्ग से पूरी तरह सम्बद्ध है। रामपुर कारखाना प्रखण्ड विकास केन्द्र मुख्यालय होने के साथ सभी प्रमुख—कार्यों—सेवाओं का केन्द्र है। देवरिया की सन्निकटता के कारण इस सेवा केन्द्र का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है।

(10) भलुअनी सेवाक्षेत्र

यह सेवाक्षेत्र दक्षिण मध्य में विस्तृत है। अपेक्षाकृत क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद इस सेवा क्षेत्र में कोई अन्य सेवाकेन्द्र नहीं है। सड़क मार्ग द्वारा यह अपन क्षेत्र से पूरी तरह जुड़ा है। जिसका केन्द्र भलुअनी प्रखण्ड मुख्यालय है। यह अन्य सेवाओं का केन्द्र भी है।

(11) बैतालपुर सेवाक्षेत्र

देवरिया मुख्यालय के सटे पश्चिमोत्तर में विस्तृत यह अध्ययन क्षेत्र का सबसे छोटा सेवाक्षेत्र है। इसमें चतुर्थ स्तरीय एक सेवाकेन्द्र बलटीकरा अवस्थित है। बैतालपुर, प्रखण्ड मुख्यालय औद्योगिक केन्द्र एवं अन्य कार्यों एवं सेवाओं का प्रमुख केन्द्र है। यह रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग से देवरिया से सम्बद्ध है।

(12) बनकटा सेवाक्षेत्र

यह अध्ययन क्षेत्र का सुदूर पूर्वी एवं सबसे कम सम्पन्न सेवाक्षेत्र है। देवरिया से रेलमार्ग से प्रत्यक्षता जुड़े होने एवं सड़क मार्गों की अच्छी क्षेत्रीय सम्बद्धता के बावजूद कार्यों एवं सेवाओं की सम्पन्नता अपेक्षाकृत कम है। बनकटा प्रखण्ड मुख्यालय है तथा क्षेत्र का केन्द्र है। इसमें चतुर्थस्तरीय सेवाकेन्द्र प्रतापपुर एवं सोहनपुर अवस्थित हैं।



References

- 1 पदमनाभन् अनन्त 'मनुष्य व वातावरण' एन सी ई आर टी नई दिल्ली पृ 79
- 2 शर्मा लक्ष्मी नारायण अधिवास भूगोल राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 1983 पृ 70
- 3 Thaha, A, *Identification of Hierarchical Growth Centres and Delineating of their Hinterlands'* 10th course of IRD, NICD, Hyderabad, Sept Oct 1977 P 1 (Cyclostyled paper)
- 4 Meitzen, R , '*Siedlung and Agrarwesen der westgermanen und obstgermanen der Kelten, Romer Finnen und slaven*' (3 Vol and Atlas) (Berlin W Herty, 1895)
- 5 सिंह इकबाल भारत में ग्रामीण विकास एन सी ई आर टी 1986 पृ 1
- 6 Pathak R K '*Environmental Planning Resources and Development*' Chugh Publication Allahabad, 1990 p 54
- 7 Babu, R , '*Micro Level Planning A case study of Chhikramau Tahsil*' (Farrukhabad District, U P) Unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981
- 8 Perroux, F, '*La notion de Croissance, Economique Applique*', Nos 1 & 2 , 1955
- 9 Bondeville, T R , '*Problems of Regional Economic planning*', Edinburgh University Press, 1966
- 10 Christaller, W , '*Die Zentralen orte in Sudent Schland, Jena*', G Fisher, 1933, Translated by C W Baskin, Englewood cliffs, N J 1966
- 11 Bhatt, L S , '*Micro-Level Planning-A case study of Karanal Area, Haryana, India*,' Vikas, New Delhi 1976, p 45
- 12 op cit fn 6 p 55
- 13 Wanmali, S , '*Regional Planning for social Facilities- A case study of Eastern Maharashtra*', NICD, Hyderabad 1970 P 45
- 14 Sen L K , '*Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development A study in Miryalguda Taluka*', NICD Hyderabad, 1971, p 92
- 15 Nytyanand, P and Bose, S , '*An Integrated Tribal Development Plan for Keonjhar District Orissa*', NICD Hyderabad, 1976
- 16 Kumar A and Sharma, N , '*Rural Centres of Services, Geographical Review of India*', Vol 39, No 1, 1977, pp 19-29
- 17 Singh, S B, '*Spatial Organisation of Settlement systems*' National Geographer, Vol XI No 2, 1976, pp 130 140
- 18 Khan, W etal, '*Plan for Integrated Development in Pauri Garhwal*', NICD, Hyderabad, 1976 pp 15-21
- 19 Dutta, A K , '*Transportation Index in West Bengal- A means to Determine Central Place Hierchy*', National Geographical Journal of India, Vol 16 No 3 & 4, 1970, pp 199-207

- 20 Alam, A M , Gopi, K N and Khan, W A , 'Planning for Metropolitan Region of Hyderabad'- A case study in S P Chatterjee, etal (ed), proceedings of Symposium on Regional Planning, National Committee of Geography Calcutta, 1971
- 21 Mishra G K 'A Methodology for Identifying Service centres in Rural Area' Behavioural Sciences and Community Development, Vol 6 No 1, 1972 pp 48-63.
- 22 Singh J 'Central places and spatial organisation in a Backward Economy-Gorakhpur Region-A case study integrated Regional Development,' Uttar Bharat Bhoogol Parishad, Gorakhpur, 1979
- 23 op cit , fn 11
- 24 op cit , fn 6
- 25 Mishra, B N (1980), 'The Spatial Pattern of Service Centres in Mirzapur District U P', Unpublished D Phil Thesis Univerity of Allahabad Allahabad p 372
- 26 Pathak, R K 'Environmental Planning Resources and Development', Chugh Publication, Allahabad, 1990, p 6
- 27 Haggett, p etal., 'Determination of Population Threshold for settlement Functions by Read Muench Method', Professional Geographer, Vol 16, 1964, pp 6-9
- 28 Mishra, R P (1972), 'Growth poles and Growth centres in the context of India's Urban and Regional Development problems in Kulklinski', A (ed)
- 29 Prakasha Rao, V L S, 'Problems of Micro-Level Planning', Behavioural Sciences and Community Development, Vol 6, No 1, 1972, p 151
- 30 op cit , fn 11 p 45
- 31 op cit, fn-10
- 32 Duncun, J S , 'New-Zealand Towns as Service Centres', N Z G , Vol 11, 1955, pp 119-38
- 33 Brush, J E, 'The Hierarchy of Central Places in South-Western Wis Conssin', Geographical Review, Vol Xliii, No 3, 1953, pp 380-402
- 34 Smailes, A E , 'The Urban Hierarchy in England and Wales', Geography, 1944, Vol 29
- 35 Carter, H , 'Urban Grades and Spheres of Influence in South-West Wales', Scot Geography Mag , Vol 71, 1955, pp 43-58
- 36 Ullman, E L , 'Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines', Geographical Review Vol 50, 1960, pp 203-218.
- 37 Hartley, G and A E Smailes, 'Shopping centres in Greater London Areas', Trans Inst Br Geog , 29, 1961, pp 201-213.
- 38 Kar, N R , 'Urban Hierarchy and Central Functions Around the City of Calcutta and its significance', in L Norgery (ed , proceeding of the I G II

Symposium in Urban Geography, Lund 1962

- 39 *Bracey, H E , 'Town as Rural Services Centres', Trans Inst Br Geog , 19, 1962 pp 95-105*
- 40 *Green, F H W 'Motor Bus Centres in South-West England Considered in Relation to Population and Shopping Facilities', Trans, Inst Br Geo Vol 14 1948 pp-57-69*
- 41 *Carruthers, W I , 'A Classification of Service Centres in England and Wales' Geographical Journal Vol 123, 1957 pp 371-85*
- 42 *Siddal, W R , 'Wholesale Retail Trade Ratios as Indices of Urban Centrality' Economic Geography, Vol 37, 1961*
- 43 *Abiodeen J O 'Urban Hierarchy in a developing country', Economic Geography, Vol 43(4), 1967 pp 347-367*
- 44 *Preston R E , 'The structure of Central Place systems, Economic Geography', Vol 47 (2), 1971, pp 136-55*
- 45 *Berry, B J L and Garrison, W L , 'The Functional Bases of the Central Places Hierarchy' Eco Geog Vol 34(2), 1958, pp 145-54*
- 46 *Vishwnath, M S , 'A Geographical Analysis of Rural Markets and Urban Centres in Mysore', Ph D Thesis, B H U Varanasi*
- 47 *Singh, O P , 'Towards Determining Hierarchy of service centres- A Methodology for Central Place Studies', N G J I Vol XVII (4), 1971, pp 165-177*
- 48 *Rao, V L S P , 'Planning for An Agricultural Region, in New Strategy', Vikas, New Delhi, 1974*
- 49 *Singh, J , 'Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy A case study in Gorakhpur Region', pp 101-112*
- 50 *Jain, N G , 'Urban Hierarchy and Telephone Services in Vidarbha (Maharashtra)', N G J I , Vol 17 (2 & 3), 1971, pp 134-37*
- 51 *Berry, B J L , 1967, 'Geography of Market centres and Retail Distribution', Prentice-Hall, I N C Englewood, Cliffs, N J , New York, p 40*





अध्याय-पाँच



सेवाकेन्द्र और कृषि-औद्योगिक विकास

अध्ययन क्षेत्र मूलतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या का 78.76 प्रतिशत भाग कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यों में लगी हुई है। यहाँ सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 80.90 प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। इस प्रकार कृषि कार्य तथा कृषि क्षेत्र के आधार पर यह क्षेत्र निःसन्देह कृषि प्रधान क्षेत्र है। कुछ वृहद् उद्योगों (गन्ना पेपर) की स्थापना भी क्षेत्र में हुई है पर वे भी कृषि पर ही आधारित हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ एवं संस्कृति का आधार कृषि ही है। कृषि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं बल्कि जीवन शैली भी है। प्रस्तुत अध्याय में वर्तमान कृषि एवं औद्योगिक स्वरूप का विश्लेषण कर क्षेत्र के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए भावी विकास हेतु एक संतुलित नियोजन भी प्रस्तुत है। अध्ययन की स्पष्टता के लिए अध्ययन दो खण्डों में विभक्त है। **प्रथम भाग** में कृषि विकास एवं **द्वितीय भाग** में औद्योगिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत है।

कृषि विकास

5.1 कृषि सम्प्रत्यय एवं विकास

कृषि का प्रारम्भ, नवपाषाण युग में हुआ। हिन्दी के 'कृषि' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कृष् धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है 'जोतना' या 'खीचना'। इसके अंग्रेजी पर्याय 'Agriculture' शब्द की स्थापना लैटिन भाषा के दो शब्दों 'Agre' अर्थात् 'Land' या 'Field' तथा 'Cultura' अर्थात् 'The care of cultivation' से हुई है। जिसका अर्थ हुआ 'भूमि को जोतकर फसल पैदा करना'।

चैम्बर शब्दकोष में वाटसन ने कृषि शब्द से आशय 'मृदा संस्कृति' से लगाया है जबकि जिम्मेरमैन (1951) के अनुसार कृषि के अन्तर्गत भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य— खेत निर्माण जुताई बुआई, फसल उगाना, सिंचाई करना पशुपालन, मत्स्यपालन तथा अन्य जीवों का पालन आदि सम्मिलित हैं।

इस प्रकार कृषि का अर्थ व्यापक है। इसके अन्तर्गत मानव की उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए मिट्टी का उपयोग होता है। इसके अन्तर्गत भूमि की जुताई से लेकर कृत्रिम साधनों से सिंचाई उर्वरकों की आपूर्ति, मृदा संरक्षण, हानिकारक तत्वों से पौधों की रक्षा आदि अनेक विस्तृत कार्यक्रमों को

अपनाया जाता है जिनका उद्देश्य मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि करना है तथा जिससे न केवल खाद्य सामग्री की प्राप्ति होती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल और पशुओं के लिए चारा मिलता है। कृषि इस बात का भी सबसे उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य ने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। वस्तुतः मनुष्य के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तब जुड़ी जब उसने पौधों एवं पशुओं को पालतू बनाना सीखा। इससे उसके जीवन में स्थायित्व आया प्राकृतिक नियन्त्रण में कमी आयी और भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों के संचयन की प्रवृत्ति का विकास हुआ।²

5.2 कृषि-विकास

प्रायः कृषि-विकास से तात्पर्य कृषि उत्पादकता वृद्धि से लिया जाता रहा है। कृषि उत्पादकता में यह वृद्धि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों के समावेश के फलस्वरूप सम्भव हुआ है। यहाँ पर कृषि-वृद्धि और कृषि-विकास में विभेद का ज्ञान आवश्यक है। यात्रिक क्रांति से पूर्व 'कृषि-विकास' को 'उत्पादकता में वृद्धि' का स्थानापन्न माना जाता रहा। परन्तु आज उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के अपेक्षाकृत कृषि विकास को अधिक विस्तृत अर्थों में प्रयोग करते हैं। विकास वृद्धि का पर्याय नहीं अपितु इसमें उत्पादकता वृद्धि के साथ ही उत्पादों का समान सामाजिक वितरण तथा परिस्थितिकीय सतुलन बनाये रखने पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार कृषि विकास का अभिप्राय उस उत्पादकता की वृद्धि से है जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप में प्राप्त हो और पर्यावरण का स्वरूप भी विकृत न हो। कृषि-भूदृश्य में विकास तभी सम्भव हो सकता है जब कृषि के स्वरूप को निर्धारित करने वाले सभी कारकों को योजना-बद्ध ढंग से प्रयोग किया जाय।³ अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास का विश्लेषण इसी आशय के सन्दर्भ में किया गया है।

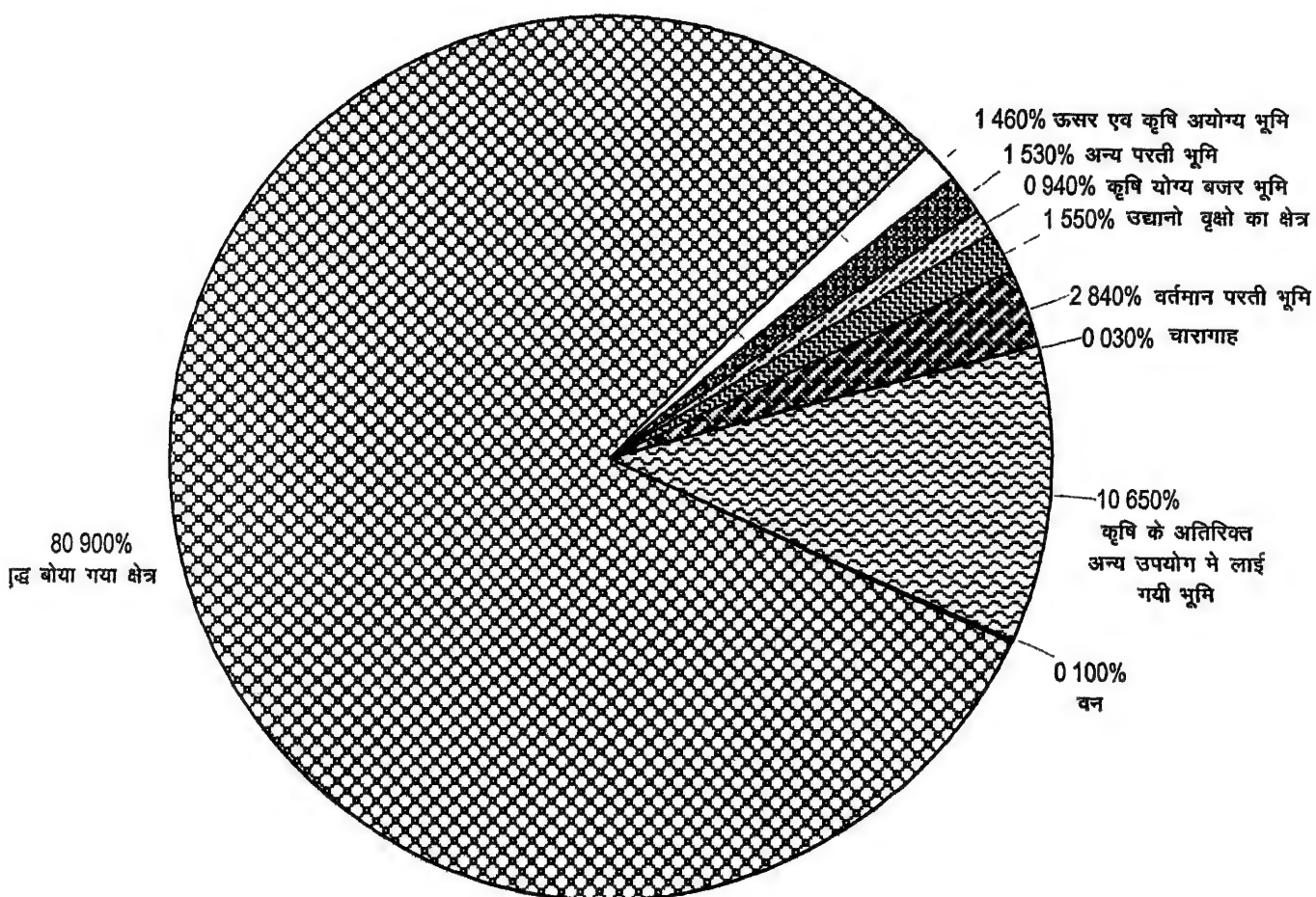
5.3 भूमि-उपयोग प्रतिरूप

भूमि उपयोग से आशय भूमि का विभिन्न कार्यों— यथा— कृषि एवं कृष्येत्तर में उपयोग के विवेचन से है। देवरिया जनपद सरयूपार का एक समतल उपजाऊ भू-भाग वाला क्षेत्र है। इसका कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 252370 हेक्टेयर है। इसका सर्वाधिक भू-भाग (80.90 प्रतिशत) कृषि कार्यों में सलग्न है। इसके बाद क्रमशः कृष्येत्तर कार्यों, परतीभूमि, बाग-बगीचों, उसर भूमि, कृषि योग्य बजर भूमि वन, एवं चारागाह में भूमि का उपयोग है। आरेख (5.1) से जनपद के भूमि उपयोग को स्पष्ट किया गया है।

आरेख (5.1) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभी भी जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्र की 6.77 प्रतिशत भूमि— कृषि योग्य बजरभूमि, परती भूमि, उसर भूमि के रूप में पड़ी हुई है जिन्हें उसर सुधार एवं सिंचाई की व्यवस्था द्वारा कृषि भूमि में तब्दील किया जा सकता है। अर्थात् जनपद में

जनपद देवरिया भूमि उपयोग 2001
(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

District Deoria Land Use 2001



कुल उपलब्ध भूमि 252370
(लाख हेक्टेयर)

कृषि योग्य क्षेत्र को 87.67 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात् कृषि उत्पादन में बढोत्तरी की पर्याप्त सभावना है जिससे अतः क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। अध्ययन क्षेत्र में विकास खण्डकार भूमि उपयोग को सारणी (5.1) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी- 5.1

जनपद में विकास खण्डवार भूमि उपयोग (हे में)

विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषियोग्य बजर भूमि	परती भूमि	उसर एव कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	चारागाह	उद्यानो बागो वृक्षो एव झाड़ियाँ	शुद्ध बोया गया क्षेत्र
1 गौरी बाजार	18575	0.05	1.02	3.44	0.17	7.61	0.01	2.49	85.17
2 बैतालपुर	16505	0.09	1.13	2.69	0.28	7.02	0.01	1.52	87.22
3 देसही देवरिया	13204	0.04	2.19	1.98	0.10	10.53	0.06	1.87	83.19
4 पथरदेवा	22866	0.16	1.07	6.29	0.41	11.29	0.03	1.87	78.85
5 रामपुर कारखाना	14375	0.45	1.42	4.61	0.25	9.80	0.01	2.46	80.97
6 देवरिया सदर	17317	0.06	1.57	4.19	0.08	8.27	0.02	1.73	84.04
7 रुद्रपुर	20739	0.04	0.85	5.47	0.54	1.29	0.04	0.60	79.42
8 भलुअनी	18549	0.05	0.48	4.75	0.57	9.17	0.01	0.69	84.26
9 बरहज	15885	0.11	0.21	5.65	3.92	15.64	0.01	0.84	73.59
10 भटनी	14156	0.18	0.96	4.37	0.86	10.25	0.02	0.86	82.46
11 भाटपार रानी	13319	0.06	0.45	2.47	0.66	9.69	0.04	1.73	84.87
12 बनकटा	14228	0.14	0.78	3.09	0.57	9.24	0.02	1.48	84.64
13 सलेमपुर	15469	0.03	0.58	4.02	0.89	10.92	0.01	0.85	82.66
14 भागलपुर	14637	0.02	0.48	2.28	0.70	11.50	0.04	1.52	83.42
15 लार	18198	0.04	0.37	7.83	11.04	10.08	0.01	3.07	68.27
नगरीय क्षेत्र	4348		2.96	6.94	1.49	30.72		0.16	57.70

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया 2001 से परिकलित पृष्ठ स 41-42

सारणी- 5.1 से स्पष्ट है कि जनपद में कृषि योग्य बजर भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक देसही देवरिया विकासखण्ड में है। परती भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत लार विकासखण्ड में एव उसर भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक बरहज में है। अतः इन विकासखण्डों में सिचाई एव उसर सुधार के द्वारा कृषिक्षेत्र में विस्तार की पर्याप्त सभावना है।

5.4 कृषि के आधारभूत सघटक

(अ) मृदा

मृदा कृषि का आधारभूत ससाधन है। जनपद की मृदा उपजाऊ जलोढ़ है। प्राचीन जलोढ़ बागर क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत है तथा नूतन जलोढ़ खादर क्षेत्र में पायी जाती है। सरचना एव उर्वरता के आधार पर क्षेत्र की मृदा को बलुई, दोमट, मटियार, गोयड़ मझार

बलुई दोमट भाट कछारी आदि भागो मे बँटा जा सकता है। मृदा का विस्तृत वर्गीकरण अध्याय दो (2 1—8) मे किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र की 90 14 प्रतिशत जनसंख्या गँवो मे रहती है जहाँ उत्पादन का मुख्य स्रोत भूमि है। भूमि पर अधिकार आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक स्तर को व्यक्त करता है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के लिए किए गए पुनर्वितरण ने सार्वजनिक पद्धति मे विशेष स्थान ले लिया है। जैसे ग्रामीण उत्पादन पद्धति कृषि पर ही केन्द्रीत थी भूमि सुधार भी कृषि से ही सम्बन्धित था। भूमि पर कृषि कार्य किया जाना भूमि उपयोग का एक माध्यम है। फाक्स⁴ ने भूमि उपयोग के प्रारम्भिक अवस्था को *भूमि प्रयोग (Land use)* तथा द्वितीय सोदेश्य उपयोग को *भूमि उपयोग (Land utilisation)* बताया। चौहान⁵ वैनजेटी⁶ तथा बुड⁷ ने भी सूक्ष्म अन्तर के साथ यही विचार व्यक्त किया है।

भूमि का अपना कोई महत्व नहीं है इसका मूल्यांकन मानवीय प्रयासो से आका जाता है—भूमि का उपजाऊ और बजर रूप मे वर्गीकरण उसके सम्भावित सामाजिक उपयोग पर निर्भर करता है। पारम्परिक रूप मे कृषि ही भूमि का सबसे उपयुक्त उपयोग है। इसलिए कृषि उत्पादकता ही भूमि वर्गीकरण का आधार रहा है। भूमि की उपयोगिता की धारणा स्थिर न होकर आर्थिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। पारम्परिक रूप मे कृषि ही भूमि का सबसे उपयोगी प्रयोग रहा है। फिर भी अध्ययन क्षेत्र मे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का एक बड़ा हिस्सा है जिसके सुनिश्चित उपयोग की आवश्यकता है।

कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल के अतिरिक्त वन, कृषि योग्य बजर भूमि परती भूमि उसर एव कृषि के अयोग्य भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि, चारागाह बाग—बगीचो, को सम्मिलित किया गया है (सारणी—5 1)। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता पथरदेवा विकास खण्ड मे है। परन्तु शुद्ध बोये गये क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत (87 22) बैतालपुर विकास खण्ड मे है। सबसे कम प्रतिवेदित क्षेत्र देसही देवरिया मे (13204 हे) है तथा सबसे कम शुद्ध बोया गया प्रतिशत क्षेत्र (68 27) लार विकास खण्ड मे है।

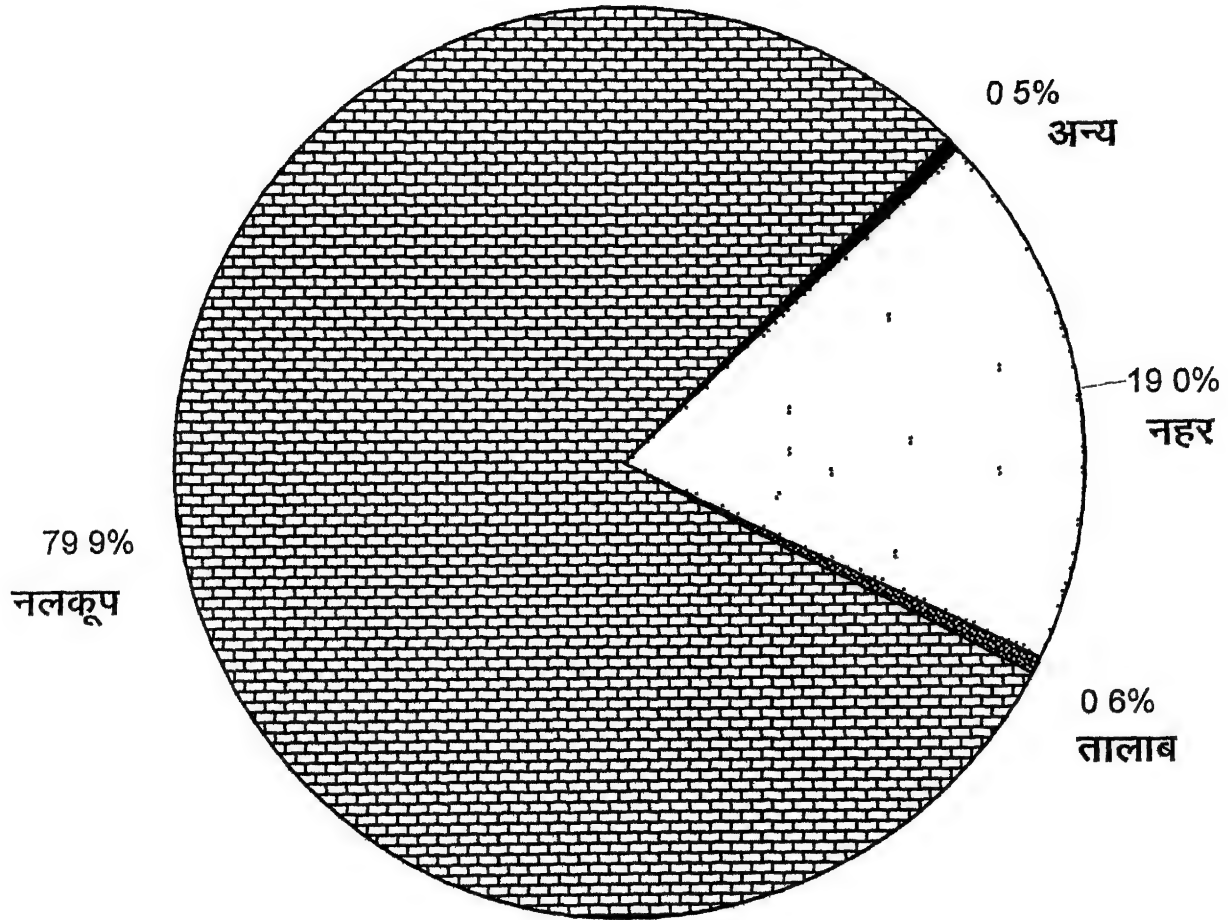
(ब) जल की उपलब्धता

मृदा के बाद जल की उपलब्धता कृषि के लिए एक अनिवार्य शर्त है। जल की पूर्ति प्राकृतिक या कृत्रिम साधनो द्वारा होती है। सिचाई का प्राकृतिक साधन वर्षा है। वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता के कारण कृत्रिम साधनो द्वारा जल उपलब्ध कराना ही *सिचाई* कहलाता है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, असामयिकता तथा विषमता अध्ययन क्षेत्र मे सिचाई की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है।

अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषित भूमि 204175 हेक्टेयर है। इसके 77 84 प्रतिशत भाग (158937 हे) पर सिचाई के विभिन्न साधनो द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। विकासखण्ड वार सर्वाधिक

जनपद देवरिया विभिन्न साधनो द्वारा स्रोतवार
सिंचित क्षेत्रफल (हे० मे) 2001

Means of Irrigation & Irrigated Area 2001



शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल - 158937 [100%]

स्रोत. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद देवरिया 2001

सिंचित क्षेत्र प्रतिशत पथरदेवा का है जहाँ कृषित क्षेत्र के 97 प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो चुका है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र प्रतिशत भलुअनी (57.61 प्रतिशत) का है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कृत्रिम ससाधन है परन्तु फिर भी वर्षा पर निर्भरता विशेषकर खरीफ की कृषि के लिए बनी हुयी है। यही कारण है कि उच्च सिंचाई क्षमता के बावजूद वर्तमान वर्ष (2002) में मानसून के समय पर न आ पाने के कारण पूरा क्षेत्र सूखा की चपेट में आ गया और खरीफ की फसल बुरी तरह प्रभावित हुयी। सिंचाई के कृत्रिम साधनों में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र नलकूप का (79.85 प्रतिशत) उसके बाद नहर (19.01 प्रतिशत) तथा उसके बाद तालाब (0.64 प्रतिशत) का स्थान आता है (आरेख 5.2)। नलकूप भी अधिकांश निजी क्षेत्र में है। नलकूप के लिए उर्जा की उपलब्धता विद्युत द्वारा की जाती है जिसकी उपलब्धता पर्याप्त न होने से इसका परेक्ष प्रभाव सिंचाई पर पड़ता है।

सारणी- 5.2

सिंचाई के विभिन्न साधनों की स्थिति

विकास खण्ड	नहरों की लम्बाई (किमी)	राजकीय नलकूप (संख्या)	निजी नलकूप संख्या	कुँए (संख्या)
1 गौरी बाजार	47	70	533	409
2 बैतालपुर	59	62	315	518
3 देसही देवरिया	81	14	90	267
4 पथरदेवा	100	30	124	255
5 रामपुर कारखाना	59	18	112	307
6 देवरिया सदर	40	71	552	370
7 रुद्रपुर		30	154	100
8 भलुअनी		108	271	286
9 बरहज		52	218	160
10 भटनी	15	42	281	254
11 भाटपार रानी		69	229	210
12 बनकटा		55	188	301
13 सलेमपुर		101	464	408
14 भागलपुर		77	279	407
15 लार		55	412	400

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका- 2001, पृष्ठ- 63-64

जनपद में नहरी सिंचित क्षेत्र देवरिया से उत्तर स्थित क्षेत्रों में ही सीमित है। इसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र देसही देवरिया में है उसके बाद क्रमशः रामपुर कारखाना पथरदेवा, बैतालपुर, गौरी बाजार, एवं देवरिया सदर का स्थान है। इन्हीं क्षेत्रों में नहरों की कुल लम्बाई (401 किमी) में 386 किमी का विस्तार है। 15 किमी लम्बी नहर भटनी में विस्तृत है जिससे 73 हेक्टेयर

क्षेत्र में सिंचाई होती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र क्रमशः सलेमपुर भलुअनी भागलपुर और भाटपार रानी विकास खण्डों में है। इन क्षेत्रों में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 99 प्रतिशत से अधिक भाग नलकूपों द्वारा सिंचित है। कुँआ द्वारा सिंचाई प्रमुखतः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः बनकटा और बरहज विकास खण्डों में होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भी इन्हीं क्षेत्रों में क्रमशः लार और बरहज में है। जनपद में विकास खण्डवार सिंचाई के विभिन्न साधनों का विस्तृत विवरण सारणी (52) में तथा विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत सारणी (53) में प्रदर्शित है।

(स) श्रम एवं तकनीक

कृषि कार्य के आधारभूत सघटकों में श्रम की अपनी अलग भूमिका है क्योंकि भूमि जल की उपलब्धता के बावजूद श्रम की अनुपलब्धता से कृषि-कार्य सम्भव नहीं है। कृषि-कार्य चूँकि प्राथमिक कार्य है अतः इसके लिए अधिकाधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। श्रम की दृष्टि से भारत सम्पन्न देश है। इसी अनुरूप देवरिया जनपद भी अत्यधिक घनी आबादी के कारण श्रम ससाधन सम्पन्न क्षेत्र है। वर्ष 2001 के आँकड़ों के अनुसार यहाँ जनसंख्या घनत्व 1077

सारणी- 53

विकास खण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

विकास खण्ड	शुद्धकृषित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत	नहर सिंचित क्षेत्र प्रतिशत	नलकूप सिंचित क्षेत्र प्रतिशत	कुँए सिंचित क्षेत्र प्रतिशत	तालाब सिंचित क्षेत्र प्रतिशत
1 गौरी बाजार	15822	74.65	33.76	66.19	0.04	
2 बैतालपुर	14339	78.75	34.78	65.12	0.04	
3 देसही देवरिया	10985	77.57	79.05	21.03		
4 पथरदेवा	18030	96.99	42.34	57.65		
5 रामपुर कारखाना	11640	94.49	58.18	41.81		
6 देवरिया सदर	14554	82.05	13.23	86.75		
7 रुद्रपुर	16471	69.03		99.34	0.52	
8 भलुअनी	15631	57.61		99.97		
9 बरहज	11690	66.86		93.46	1.66	4.35
10 भटनी	11674	73.36	0.85	99.14		
11 भाटपार रानी	11305	70.88		99.37	0.37	
12 बनकटा	12044	68.92		94.38	4.89	
13 सलेमपुर	12787	85.20		99.99		
14 भागलपुर	12211	94.06		99.67		0.32
15 लार	12425	76.00		93.07	0.02	6.77

व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो प्रदेश और देश के घनत्व से बहुत अधिक है। वर्तमान में घनत्व की दृष्टि से जनपद का प्रदेश में 9 वाँ स्थान है। जनपद में कुल आबादी का 90.14 प्रतिशत (2001) गाँवों में रहती है तथा इनका सर्वप्रमुख कार्य कृषि है। इस प्रकार यहाँ कृषि कार्य के लिए श्रम की समस्या नहीं है। जनपद के कुल कर्मकारों में कृषकों का प्रतिशत 55.75 है तथा कृषक मजदूरों का प्रतिशत— 23.01 है। इस प्रकार कुल कर्मकारों में 78.76 प्रतिशत केवल कृषि कार्य से सम्बद्ध है।

तकनीक से श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है जिससे अतः उत्पादकता बढ़ती है और कृषक के लाभ में वृद्धि होती है जिससे उसका आर्थिक स्तर सुदृढ़ होता है। कृषि कार्य में तकनीक या मशीनीकरण का अर्थ जमीन पर उन कार्यों के लिए मशीनों के इस्तेमाल से है जो परम्परागत खेती में बैल, घोड़े और दूसरे भारवाही पशुओं या मनुष्यों के श्रम द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।⁹ अध्ययन क्षेत्र इस दृष्टि से अभी भी पारंपरिक ढंग से ही कृषि कार्य करता है। पर 5-7 वर्षों में कृषि तकनीक की दृष्टि से इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग बढ़ने लगा है। वर्तमान समय में सभी सम्पन्न किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, कम्बाइन, हार्वेस्टर इत्यादि यंत्रों का उपयोग कृषि कार्य में करने लगे हैं वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत भाग में गेहूँ फसल की कटाई एवं धान की फसल की कटाई में मजदूरों के स्थान पर हार्वेस्टर का उपयोग किया जाने लगा है। इन सबके बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर परम्परागत यंत्रों का प्रयोग इस क्षेत्र के कृषि कार्य में हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र में ट्रैक्टरों की कुल संख्या 4,705 है उन्नत बोआई यंत्र— 1,817 स्प्रेयर संख्या— 1,475, उन्नत थ्रेसिंग मशीन 24,133 उन्नत हल एवं कल्टीवेटर— 49,385 एवं 26,487 है। उपर्युक्त तथ्यों से कृषि में यन्त्रीकरण के अभाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है।

(द) उर्वरक प्रयोग

उत्पादन वृद्धि में सतुलित उर्वरकों के प्रयोग का विशेष महत्व है। नवीनतम अनुसंधानों से प्राप्त परिणाम के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश का अनुपात कृषि में 4:2:1 होना चाहिए। जबकि जनपद में अब तक नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश का अनुपात 22:5:1 है। अतः आवश्यकता है कि सतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग हेतु फास्फोरस एवं पोटाश के प्रयोग पर बल दिया जाय। विशेषकर दलहनी एवं तिलहनी फसलों में फास्फोरस एवं पोटाश के प्रयोग पर अवश्य ही बल दिया जाय। वर्षवार उर्वरक खपत का विवरण सारणी (5.4) में प्रस्तुत है।

सारणी— 5.4

जनपद में वर्षवार उर्वरक खपत का विवरण (के जी / हे)

क्र.सं.	उर्वरक	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	नाइट्रोजन	19.52	21.50	24.00	21.83
2	फास्फोरस	4.02	3.98	5.00	4.72
3	पोटाश	1.00	1.00	1.00	1.00

सारणी 54 से स्पष्ट है कि जनपद में उर्वरक का उपयोग सस्तुत अनुपात में नहीं हो रहा है। अभी भी फास्फोरस और पोटाश की खपत बहुत कम है तथा नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत अधिक। इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। लगभग सभी विकास खण्डों में उर्वरक खपत का यही प्रतिरूप देखने को मिलता है। सारणी (55) में प्रत्येक विकास खण्ड में उर्वरक खपत का विवरण प्रस्तुत है। सारणी (56) में प्रति हेक्टेयर बोये गये क्षेत्र पर उर्वरक उपभोग प्रस्तुत है। जिसमें उपभोग में क्षेत्रीय स्तर पर भारी असंतुलन दृष्टिगत होता है।

सारणी-55

जनपद में विकास खण्डवार उर्वरक खपत (मी टन) एव एन पी के अनुपात

विकास खण्ड	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	एन पी के अनुपात	जिक
1 गौरीबाजार	3281	700	151	22.5:1	19
2 बैतालपुर	3271	711	150	22.5:1	15
3 देसही देवरिया	3211	702	148	22.5:1	15
4 पथरदेवा	3201	712	146	22.5:1	15
5 रामपुर कारखाना	3662	728	151	24.5:1	15
6 देवरिया सदर	3663	726	167	22.6:1	19
7 रुद्रपुर	2951	704	152	19.5:1	15
8 भलुआनी	3261	708	151	22.5:1	15
9 बरहज	3131	700	150	21.5:1	19
10 भटनी	3311	694	148	22.5:1	15
11 भाटपार रानी	3351	704	150	22.5:1	15
12 बनकटा	3202	708	151	21.5:1	15
13 सलेमपुर	3251	707	150	22.5:1	18
14 भागलपुर	3031	709	136	22.5:1	15
15 लार	3271	702	147	22.5:1	15

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका- 2001, पृष्ठ- 69 एव खरीफ उत्पादन कार्यक्रम (2000-01) कृषि विभाग देवरिया पृ 27

5.5 कृषि विकास के उत्प्रेरक एवं सहायक तत्व

कृषि कार्य में उपर्युक्त आधारभूत तत्वों के अलावे कई ऐसे तत्वों का भी समावेश होता है जो कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में जिनकी स्थापना से विकास तीव्र होता है। अर्थात् ये कृषि विकास को उत्प्रेरित करते हैं। जहाँ कृषि के आधारभूत घटक (मृदा, जल, श्रम) प्रकृति प्रदत्त है, वही उत्प्रेरक तत्व पूर्णतः मानवीय हैं तथा इनकी उपलब्धता देश और राज्य के आर्थिक विकास से निर्धारित और नियंत्रित होती है। कृषि विकास के इन उत्प्रेरक तत्वों की स्थापना सेवाकेन्द्रों पर ही होती है और इन्हीं इकाइयों के माध्यम से सेवाकेन्द्र सेवाक्षेत्र को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। कृषि विकास के इन उत्प्रेरक तत्वों में बीज गोदाम/उर्वरक डिपो, ग्रामीण गोदाम, कीटनाशक डिपो, शीत भण्डार, कृषि सेवाकेन्द्र, मण्डी समिति, पशु चिकित्सालय,

सारणी- 56

जनपद मे विकास खण्डवार प्रति हे सकल बोये गये क्षेत्र पर उर्वरक उपभोग (एन पी के)

क्रम सख्या	विकास खण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र
1	गौरीबाजार	315 3
2	बैतालपुर	249 5
3	देसही देवरिया	239 2
4	पथरदेवा	235 0
5	रामपुर कारखाना	224 0
6	देवरिया सदर	222 1
7	रुद्रपुर	220 1
8	भलुअनी	215 2
9	बरहज	185 8
10	भटनी	179 7
11	भाटपार रानी	176 0
12	बनकटा	169 2
13	सलेमपुर	161 7
14	भागलपुर	154 0
15	लार	135 9

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका- 2001, पृष्ठ- 165

पशु सेवाकेन्द्र कृतिम गर्भाधान केन्द्र सहकारी समितियों एवं वित्तीय संस्थाएँ प्रमुख हैं। अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों पर इनकी उपलब्धता तथा क्षेत्र के कृषि विकास में इनकी भूमिका का विवेचन निम्नवत् है।

(1) बीज गोदाम, उर्वरक डिपो

कृषि के सहयोगी तत्वों में बीज गोदाम एवं उर्वरक डिपो की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। देश में 60 के दशक में आयी हरितक्रांति 70 के दशक के मध्य तक देश के कई अन्य भागों में प्रसारित होते हुए देवरिया तक पहुँची। हरितक्रांति का चूँकि एक प्रमुख पहलू उन्नतशील बीज एवं रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से सम्बन्धित था। अतः देवरिया में 1981 तक इसके अनेक केन्द्रों की स्थापना सेवाकेन्द्रों पर हो चुकी थी। 1981 में बीज गोदाम एवं उर्वरक डिपो की कुल संख्या 254 थी। इनमें सर्वाधिक केन्द्र देवरिया सदर में तथा सबसे कम संख्या देसही देवरिया और भटनी विकास खण्डों में थी। सन् 2001 तक ये संख्या बढ़कर 299 हो गयी। इस समय बीज गोदाम एवं उर्वरक डिपो की सर्वाधिक संख्या देवरिया सदर विकास खण्ड में (31) एवं न्यूनतम संख्या देसही देवरिया में (13) है। इन केन्द्रों की सेवाकेन्द्रों पर स्थापना से कृषि में उन्नतशील बीजों एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे कृषि में इनका प्रयोग बढ़ा।

(2) ग्रामीण गोदाम

ग्रामीण गोदामों की स्थापना अन्न को सुरक्षित संचित रखने के उद्देश्य से की जाती है। सेवाकेन्द्रों पर इनकी स्थापना का कृषि विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 1981 तक कृषि उपज के अतिरिक्त को सुरक्षित संग्रह कर रखने हेतु जनपद में 149 ग्रामीण गोदाम थे। जिसमें सर्वाधिक गोदाम क्रमशः सलेमपुर (14) एवं देवरिया सदर (12) में स्थापित थे। 2001 में जनपद में इनकी संख्या बढ़कर 174 हो गयी। वर्तमान में सर्वाधिक गोदामों की संख्या सलेमपुर प्रखण्ड में (17) तथा सबसे कम पथरदेवा एवं रामपुर कारखाना विकास खण्डों में क्रमशः 99 हैं।

(3) कीटनाशक डिपो

हरित क्रांति के बाद के वर्षों में कृषि में उन्नतशील बीज सिंचाई के समुचित प्रबन्ध एवं उर्वरकों के प्रयोग के साथ कीटनाशकों का प्रयोग अपरिहार्य हो गया। जनपद की कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों के लाभ वृद्धि हेतु 1981 तक जनपद में मात्र 5 कीटनाशक डिपो थे। ये सभी गौरी बाजार देवरिया सदर रुद्रपुर बरहज एवं सलेमपुर में केन्द्रीत थे। कृषि विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 2001 तक जनपद के विभिन्न सेवाकेन्द्रों पर इनकी स्थापना की गयी जिससे वर्तमान में संख्या बढ़कर 17 हो गयी है। इसमें सलेमपुर एवं देवरिया सदर में दो केन्द्र हैं तथा बाकी सभी विकास खण्डों में एक-एक केन्द्र स्थित है।

(4) शीत भण्डार

1981 में देवरिया जनपद में कुल मात्र 2 शीत भण्डार थे जिसमें सबसे पुराना एक शीत भण्डार गौरीबाजार में तथा दूसरा देवरिया सदर में मुख्यालय पर स्थापित था। देवरिया मुख्यालय के उत्तर-उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आलू की बढ़ती पैदावार को संचित रखने के लिए बाद में देवरिया में ही एक और शीत भण्डार की स्थापना की गयी। इससे संख्या बढ़कर तीन हो गयी है। परन्तु ये पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी-कभी किसानों को शीत भण्डार की कमी की वजह से अपने उपज को या तो औने-पौने कीमत पर बेचना पड़ता है या वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। शीत भण्डार की स्थापना से कृषि प्रतिरूप पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(5) कृषि सेवाकेन्द्र

कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि सेवाकेन्द्रों की स्थापना की जाती है। इस निमित्त 1981 तक देवरिया में इनकी स्थापित संख्या मात्र 6 थी जो 2001 तक बढ़कर 16 हो गयी। अर्थात् इसमें 10 इकाइयों की वृद्धि हुयी। कृषि सेवाकेन्द्रों से कृषकों को कृषि सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाती है।

(6) कृषि उत्पादन मण्डी समिति

यदि कृषक को उसके उपज का उचित मूल्य न मिले तो कृषक उस फसल विशेष के प्रति अरुचि दिखाने लगता है। कृषकों के उपज को उचित मूल्य पर क्रय-विक्रय करने के लिए

विकास खण्डवार कृषि से सम्बन्धित मुख्य सुविधाएँ (वर्ष 1981-2001)

विकास खण्ड	बीज गोदाम उर्वरक डिपो स 1981-2001	ग्रामीण गोदाम 1981-2001	क्रीटनाशक डिपो 1981-2001	शीत मण्डार 1981-2001	कृषि सेवाकेन्द्र 1981-2001	कृषि उत्पादन मण्डी समिति 1981-2001	पशु चिकित्सालय 1981-2001
1 गौरीबाजार	23 26	10 12	1 1	1 1	1 3	- -	- 1
2 बैतालपुर	24 25	11 12	- 1	- -	- -	- -	1 2
3 देसही देवरिया	10 13	9 10	- 1	- -	- -	- -	- 1
4 पथरदेवा	17 19	9 9	- 1	- -	- -	- -	1 2
5 रामपुर कारखाना	14 18	7 9	- 1	- -	- 1	- -	- 1
6 देवरिया सदर	27 31	12 13	1 2	1 2	2 4	1 1	1 2
7 रुद्रपुर	16 19	10 11	1 1	- -	- -	- -	1 2
8 मलुअनी	14 15	10 12	- 1	- -	1 4	- -	1 3
9 बरहज	17 21	10 12	1 1	- -	- -	- -	- 1
10 भटनी	10 14	11 12	- 1	- -	- -	- -	- 1
11 भाटपारसानी	12 15	9 10	- 1	- -	- -	- -	1 2
12 बनकटा	14 15	10 11	- 1	- -	- 2	- -	- 1
13 सलेमपुर	22 29	14 17	1 2	- -	1 1	- -	1 2
14 भागलपुर	17 19	8 12	- 1	- -	- -	- -	1 2
15 लार	17 20	9 12	- 1	- -	1 1	- -	1 2
योग जनपद	254 299	149 174	5 17	2 3	6 16	1 1	9 25

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 70-71 78-79 81-82 106 एव जिला गजेटियर देवरिया- 1988 पृष्ठ 78-131 तथा जिला जनगणना हस्त
पुस्तिका देवरिया- 1981 से संगणित पृष्ठ- 7-19 495-500 640-661

विकास खण्डवार कृषि से सम्बन्धित मुख्य सुविधाएँ (वर्ष 1981-2001)

विकास खण्ड	पशु सेवाकेन्द्र 1981 — 2001	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 1981 — 2001	कृषि ऋण सहकारी समितियाँ 1981 — 2001	जिला सहकारी बैंक 1981 — 2001	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1981 — 2001
1 गौरीबाजार	1 2	- -	8 13	1 2	2 3
2 बैतालपुर	- 3	- -	3 11	- 1	3 4
3 चेसही देवरिया	- 3	- -	3 8	1 1	3 3
4 पथरदेवा	1 3	- 1	5 13	1 2	5 8
5 रामपुर कारखाना	- 2	- -	2 9	- 1	3 5
6 देवरिया सदर	2 4	1 1	7 15	2 2	3 3
7 रुद्रपुर	1 2	- 1	8 13	1 2	1 3
8 भलुआनी	1 2	- -	9 14	1 3	2 3
9 बरहज	1 3	- 1	9 13	- 1	1 1
10 भटनी	- 3	- -	10 13	- 1	1 2
11 भाटपारसानी	- 2	- 1	8 12	- 1	1 2
12 बनकटा	- 2	- -	7 11	- 1	4 4
13 सलेमपुर	- 1	- 1	8 18	1 1	- 1
14 भागलपुर	- 2	- -	9 12	- 1	2 4
15 लार	1 3	- 1	7 13	- 1	3 3
योग जनपद	8 37	1 7	103 184	8 21	34 59

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 70-71 78-79 81-82 106 एव जिला गजेटियर देवरिया- 1988 पृष्ठ 78-131 तथा जिला जनगणना

हस्त पुस्तिका देवरिया- 1981 से संगणित पृष्ठ- 7-19 495-500 640-661

देवरिया में एक मात्र मण्डी समिति है। इनकी स्थापना तहसील स्तर पर करते हुए सख्या बढ़ाना चाहिए।

(7) पशुचिकित्सालय पशु सेवाकेन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

पशुपालन को जनपद में कृषि के पूरक कार्य के रूप में तथा दूध उत्पादन हेतु किया जाता है। पहले जब कृषि में यंत्रीकरण का प्रयोग सीमित था तब यह कृषि कार्य का प्रमुख आधार हुआ करता था। पर अब जैसे-जैसे कृषि में ट्रैक्टर हारवेस्टर थ्रेसर इत्यादि यंत्रों का प्रयोग बढ़ने लगा है वैसे-वैसे कृषि में पशुपालन की भूमिका सिमटते हुए केवल दूध उत्पादन तक रह गयी है। एक ओर जहाँ कृषि में यंत्रीकरण के कुछ लाभ हुए हैं वही फसल और पशुपालन साहचर्य के बिगड़ने से कृषि उत्पादकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि पशुधन के गोबर से प्राप्त होने वाले खाद की मात्रा कम हो गयी है जिससे भूमि की उर्वरता प्रभावित हुयी है।

पशुओं को उचित चिकित्सासुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके गर्भाधान के लिए जनपद में अनेक चिकित्सालय पशु सेवाकेन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना की गयी। जहाँ 1981 में पशु चिकित्सालय पशुसेवाकेन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की सख्या क्रमश 9 8 और 1 थी वही 2001 तक इनकी सख्या बढ़कर क्रमश 25 37 और 7 हो गयी है। ये केन्द्र जनपद के विभिन्न सेवाकेन्द्रों पर स्थापित हैं। पशु सेवाकेन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सा के साथ ये सुविधा भी उपलब्ध है। जनपद के सभी विकास खण्डों में पशु चिकित्सालय स्थापित हैं,— ये हैं— देवरिया सदर बैरौना गौरी बाजार देसही देवरिया बैतालपुर, पहाड़पुर भटनी बनकटा, रामपुर कारखाना भलुअनी खुखुन्दू, पकड़ी बाजार नोनार पाण्डे तरकुलवाँ सलेमपुर सोहनाग लार पिण्डी भागलपुर मईल रुद्रपुर बरहज पथरदेवा भाटपार एवं पचलडी (रुद्रपुर)। इन सेवाकेन्द्रों से सेवाकेन्द्र पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाये सेवाक्षेत्र को प्रदान करते हैं।

(8) सहकारी समितियाँ एवं बैंकिंग

जनपद के प्रगति में सहकारी क्षेत्र एवं बैंकिंग का विशेष योगदान रहा है। ये वित्तीय सस्थाये कृषकों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान कर उन्हें कृषि कार्य में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। 1981 में इन समितियों में कृषि ऋण सहकारी समितियाँ जिला सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सर्वप्रमुख थे, जिनकी सख्या क्रमश 103, 8 और 34 थी। वर्तमान समय (2002) में प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों की सख्या बढ़कर 184 हो गयी है, जिसमें सदस्यों की सख्या 3 52 लाख है। इसके अतिरिक्त 21 संयुक्त कृषि समितियाँ 289 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ 31 मत्स्य सहकारी समितियाँ, 5 क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ तथा 11 गन्ना सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिसमें सदस्य के रूप में जनपद के विभिन्न व्यक्ति कृषि कार्य हेतु सहयोग प्राप्त करते हैं। सहकारी विभाग का एक शीतगृह तथा 5000 मी क्षमता का एक गोदाम भी जनपद में स्थित है।

वर्तमान समय में जनपद में सहकारी बैंकों की कुल 21 शाखाएँ कार्यरत हैं जो अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। तीन कृषि ग्रामीण सहकारी बैंक तीन तहसीलों क्रमशः देवरिया, रुद्रपुर तथा सलेमपुर में स्थित हैं। वर्तमान समय में जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल 59 शाखाएँ कार्यरत हैं। ये सभी बैंक कृषि एवं गैर कृषि कार्यों हेतु मध्य कालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं कृषि से संबंधित उपरोक्त मुख्य सुविधाओं को सख्या एवं वर्ष के साथ सारणी (57) में प्रस्तुत किया गया है।

5.6 कृषि विकास की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप

कृषि कार्य के सहायक इकाइयों की विभिन्न केन्द्रों पर स्थापना का कृषि विकास पर प्रभाव—कृषि प्रतिरूप उत्पादन उत्पादकता गहनता शस्य साहचर्य फसल—चक्र पशुपालन—मत्स्यपालन का कृषि के साथ संयोजन आदि के रूप में परिलक्षित होने लगता है। अतः इनकी प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के विश्लेषण से कृषि विकास को स्पष्ट किया जा सकता है।

(क) फसल प्रतिरूप

फसल प्रतिरूप के अन्तर्गत फसलों के स्थानिक एवं कालिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अनेक फसलों के स्थानिक और कालिक वितरण से बने स्वरूप को फसल प्रतिरूप कहते हैं।¹⁰ फसल प्रतिरूप पर भौतिक, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक तथा सस्थागत कारकों का प्रभाव पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप वितरण के लिए कालिक पक्ष को अपनाया गया है। क्योंकि इसमें स्थानिक प्रतिरूप का स्वतः समावेश हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ़ रबी दो मुख्य फसलें हैं। इसके अलावे गन्ना की फसल भी ली जाती है। जायद की फसल सबसे कम क्षेत्र में बोयी जाती है। जायद में केवल कुछ सब्जियों एवं उड़द की फसल ही उगायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र के खरीफ़ रबी एवं जायद फसलों के अन्तर्गत समाहित कृषि क्षेत्र को सारणी (58) एवं चित्र— 53 में प्रदर्शित किया गया है।

(अ) खरीफ़—फसल

जून—जुलाई में मानसून के आगमन के समय बोई जाने वाली फसल को खरीफ़ फसल कहते हैं। धान, गन्ना, कपास, ज्वार बाजरा मक्का, जूट मूँगफली, तिल तम्बाकू, मूँग, अरहर, उड़द तथा मोठ आदि खरीफ़ की फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक क्षेत्रफल (160366 हे.) पर खरीफ़ की कृषि की जाती है, जो सकल बोये गए क्षेत्र का 50.46 प्रतिशत है। विकास खण्डवार सकल कृषित क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में विकास खण्ड बनकटा में खरीफ़ की कृषि की जाती है सारणी (58)। खरीफ़ फसल के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल धान की कृषि का (38.03 प्रतिशत) है। धान के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्रमशः पथरदेवा गौरी बाजार, भलुअनी, देवरिया सदर रुद्रपुर विकास खण्ड में हैं। खरीफ़ की दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है जो सकल कृषित क्षेत्र के 5.73 प्रतिशत भू-भाग पर की जाती है। अरहर 3.45 प्रतिशत तथा मक्का 1.91 प्रतिशत सकल कृषि

DISTRICT DEORIA CROPPING PATTERN 2001

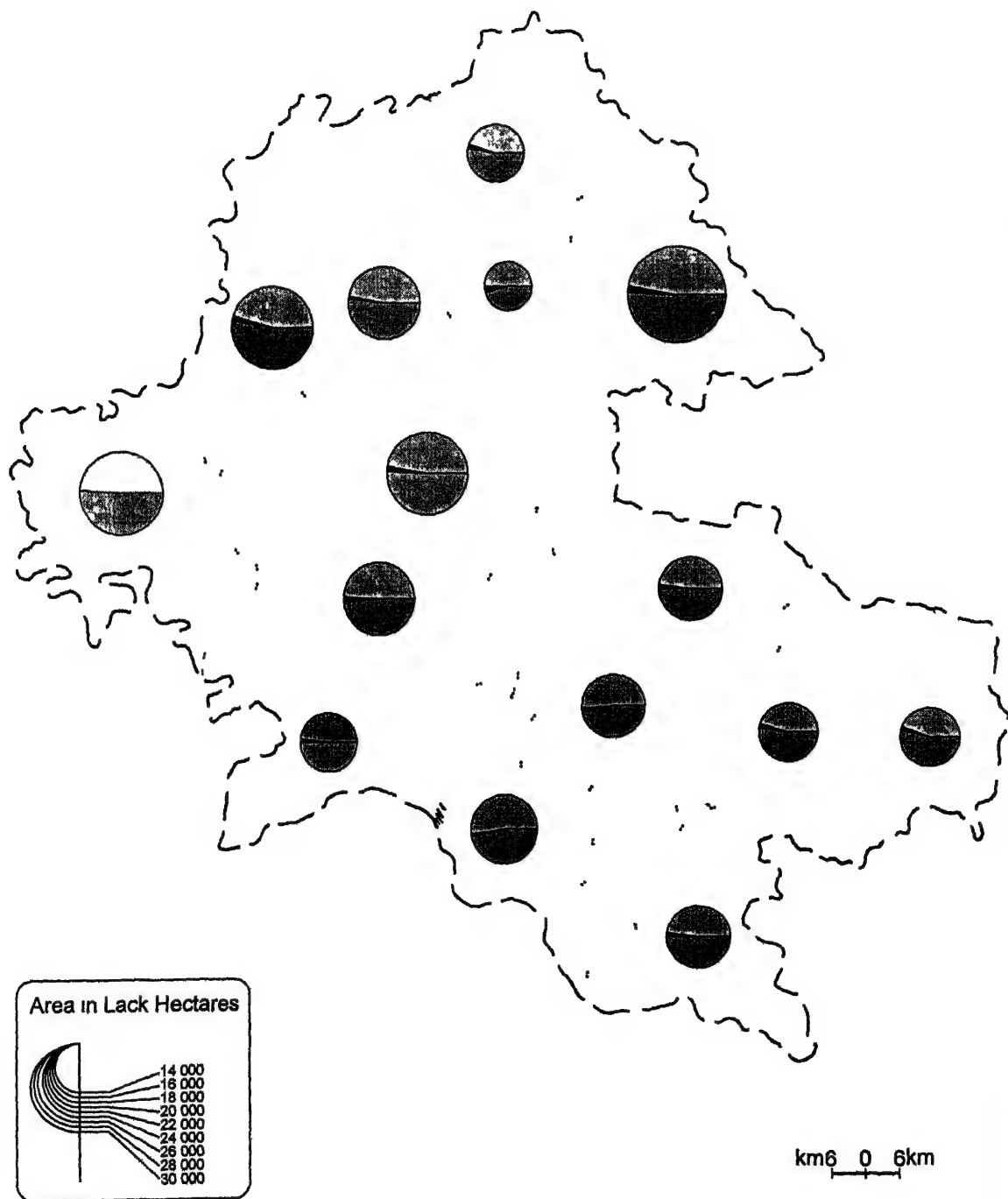


Fig. 5 : 3

क्षेत्र के भाग पर की जाती है। सकल कृषित क्षेत्र की सर्वाधिक भूमि *मक्का* के अन्तर्गत क्रमश—*भटनी रुद्रपुर रामपुर कारखाना लार पथरदेवा* विकास खण्डों में तथा *गन्ना* के अन्तर्गत क्रमश *पथरदेवा देसही देवरिया बैतालपुर गौरीबाजार बनकटा रामपुर कारखाना, एव देवरिया* सदर विकास खण्डों में है। *अरहर* के अन्तर्गत *रुद्रपुर लार* एव *भलुअनी* विकास खण्डों में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एव सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत सारणी 59 एव आरेख (54) में प्रदर्शित है।

(ब) रबी—फसल

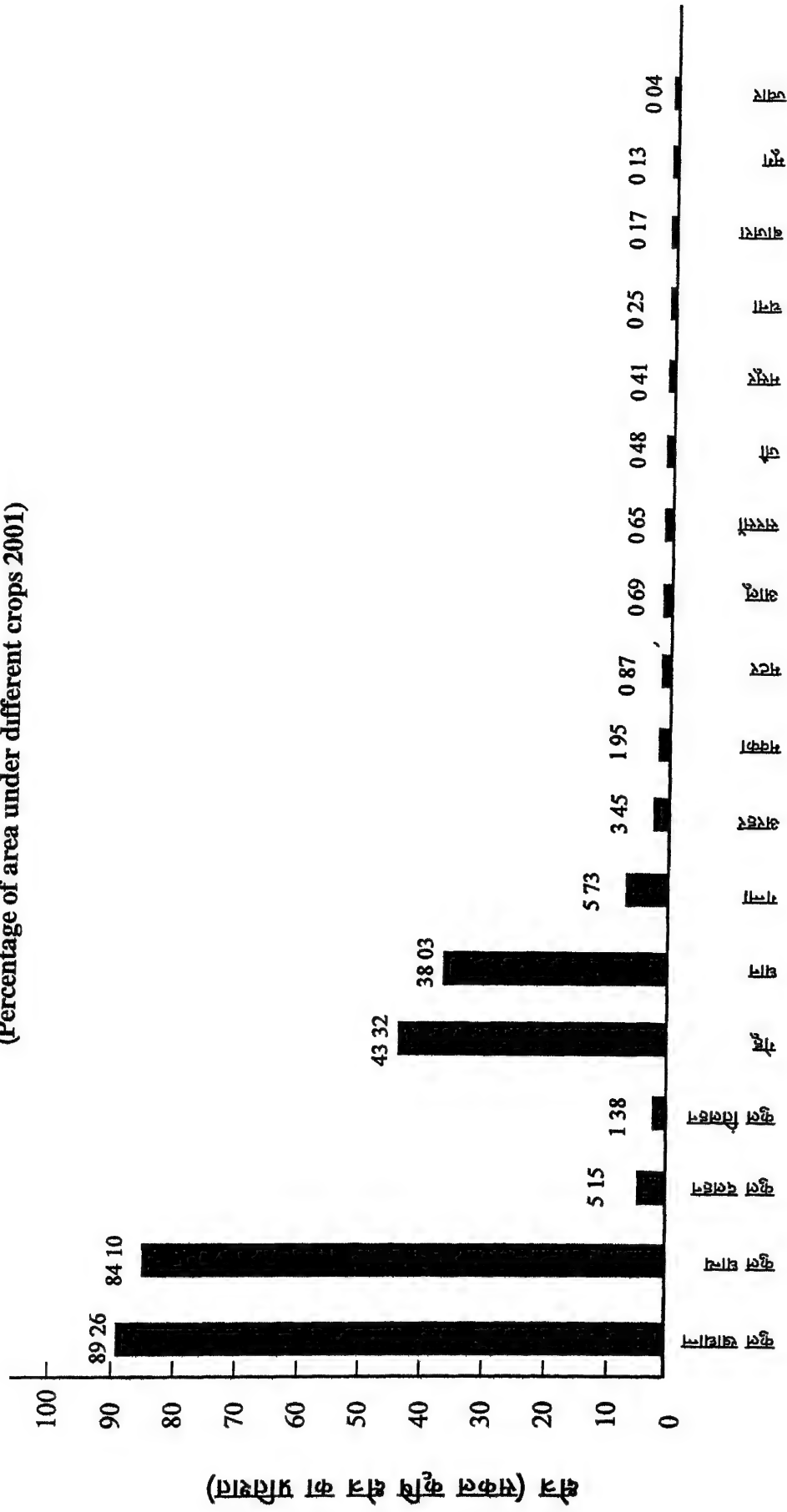
रबी के फसलों की बुवाई अक्टूबर से दिसम्बर माह तक होती है तथा कटाई मार्च—अप्रैल माह में होती है। इन फसलों की उत्पादकता प्रमुखतः सिचाई पर निर्भर करती है। गेहूँ जौ चना मटर सरसो आलू मसूर अलसी तथा बरसीम आदि मुख्य रबी की फसलें हैं। अध्ययन क्षेत्र में खरीफ फसलों की तुलना में रबी की फसलों के अन्तर्गत कम क्षेत्र (151114 हे) 47.55 प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण है इसकी सिचाई पर निर्भरता सारणी—(58)। सकल बोए गए क्षेत्र का विकास खण्ड वार रबी फसल में बोए गए क्षेत्र का क्रम सारणी (58) में प्रस्तुत है।

रबी की प्रमुख फसलें क्रमश गेहूँ, मटर सरसो, जौ मसूर, चना हैं। जिनका सकल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत क्रमश—43.32, 0.87, 0.65, 0.48, 0.41, 0.25 है। गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्रमश *भलुअनी, पथरदेवा, देवरिया सदर गौरीबाजार रुद्रपुर* में है। मटर के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्रमश *सलेमपुर भलुअनी, रुद्रपुर* विकासखण्डों में तथा *सरसो* के अन्तर्गत *पथरदेवा बैतालपुर, देवरिया सदर रुद्रपुर* विकासखण्डों में सर्वाधिक क्षेत्र है। जौ की कृषि प्रमुख रूप से *रुद्रपुर लार बरहज एव भलुअनी* विकास खण्डों में तथा *मसूर* की कृषि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्रमश *रुद्रपुर लार, पथरदेवा, देसही देवरिया* विकासखण्डों में है। चना के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र—*भलुअनी* एव *रुद्रपुर* में है।

(स) जायद—फसल

खरीफ तथा रबी के ग्रीष्मकालीन सक्रमण कालावधि में जायद की कृषि की जाती है जिसमें उड़द मूँग, मक्का, खरबूज तरबूज ककड़ी तथा सब्जियों का उत्पादन होता है। इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में मात्र 5778 हे क्षेत्र ही समाहित है। जो सकल कृषित भूमि का 1.81 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र में जायद के अन्तर्गत खाद्यान्न में *मक्का* की कृषि सकल कृषित क्षेत्र के 0.04 प्रतिशत भाग में की जाती है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र *पथरदेवा, रामपुर कारखाना भटपाररानी बैतालपुर, देसही देवरिया* विकासखण्डों में पाया जाता है। मूँग जायद की सर्वप्रमुख फसल है जो सकल कृषित क्षेत्र के 0.13 प्रतिशत भाग पर की जाती है। इसके अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र *पथरदेवा रामपुर कारखाना, बैतालपुर, देसही देवरिया, गौरीबाजार* विकासखण्डों में पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में जायद फसल के अन्तर्गत सब्जियों का उत्पादन भी प्रमुख रूप से किया जाता है। सिचाई

जनपद देवरिया
विभिन्न फसलो के अतर्गत क्षेत्र प्रतिशत- 2001
(Percentage of area under different crops 2001)



विभिन्न फसले

सारणी 58
विभिन्न फसलों के अतर्गत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) -2001

विकास खण्ड	सकल कृषित क्षेत्र	रबी के अतर्गत क्षेत्र	प्रतिशत	खरीफ के अतर्गत क्षेत्र	प्रतिशत	जायद के अतर्गत क्षेत्र	प्रतिशत	गन्ना के अतर्गत तैयार क्षेत्र	प्रतिशत
1 गौरीबाजार	25604	11591	45.27	13557	52.94	398	1.55	58	0.22
2 चैतालपुर	22988	10701	46.55	11901	51.77	346	1.50	40	0.17
3 देसही देवरिया	18453	8249	44.70	9936	53.84	261	1.41	7	0.03
4 पथरदेवा	29875	13960	46.72	15270	51.11	582	1.94	63	0.21
5 रामपुर कारखाना	14403	7180	49.85	6688	46.43	464	3.22	71	0.49
6 देवरिया सदर	24520	11617	47.37	12442	50.74	381	1.55	80	0.32
7 रुद्रपुर	24718	12081	48.87	12357	49.99	265	1.07	15	0.06
8 मलुअनी	24352	11829	48.57	11998	49.26	500	2.05	25	0.10
9 बरहज	16937	8077	47.68	8457	49.93	381	2.24	22	0.12
10 भटनी	17362	8261	47.58	8733	50.29	350	2.01	18	0.10
11 भाटपाररानी	16852	7642	45.25	8917	52.91	269	1.59	24	0.14
12 बनकटा	18128	7898	43.56	9835	54.25	373	2.05	22	0.12
13 सलेमपुर	18493	9481	51.26	8626	46.64	374	2.02	12	0.06
14 भागलपुर	22198	11493	51.77	10337	46.56	329	1.48	39	0.17
15 लार	19142	9253	48.33	9524	49.75	360	1.88	5	0.02
योग जनपद	317759	151114	47.55	160366	50.46	5778	1.81	501	0.15

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 42-43 से संगठित।

सारणी 59

खरीफ, रबी एव जायद फसलो के अतर्गत प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत विवरण (2001-02)

फसल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल कृषित क्षेत्र (317759 हे०) का प्रतिशत
कुल खाद्यान्न	283641	89 26
कुल धान्य	267245	84 10
कुल दलहन	16396	5 15
कुल तिलहन	4405	1 38
गेहूँ	137653	43 32
धान	120846	38 03
गन्ना	18227	5 73
अरहर	10982	3 45
मक्का	6242	1 95
मटर	2767	0 87
आलू	2221	0 69
सरसो	2080	0 65
जौ	1537	0 48
मसूर	1326	0 41
चना	797	0 25
बाजरा	542	0 17
मूँग	419	0 13
ज्वार	133	0 04

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया- 2001 पृष्ठ- 42-56

सुविधा की कमी इस फसल को निरुत्साहित करती है। कुछ नगरीय क्षेत्रों के आस-पास सब्जियों का उत्पादन होता है।

आलू की कृषि-अध्ययन क्षेत्र में सकल कृषित क्षेत्र के 0 69 प्रतिशत भाग (2221 हे) पर आलू की कृषि की जाती है इसके अतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र क्रमशः रुद्रपुर, भलुअनी भटनी, गौरीबाजार सलेमपुर विकासखण्डों में पाया जाता है।

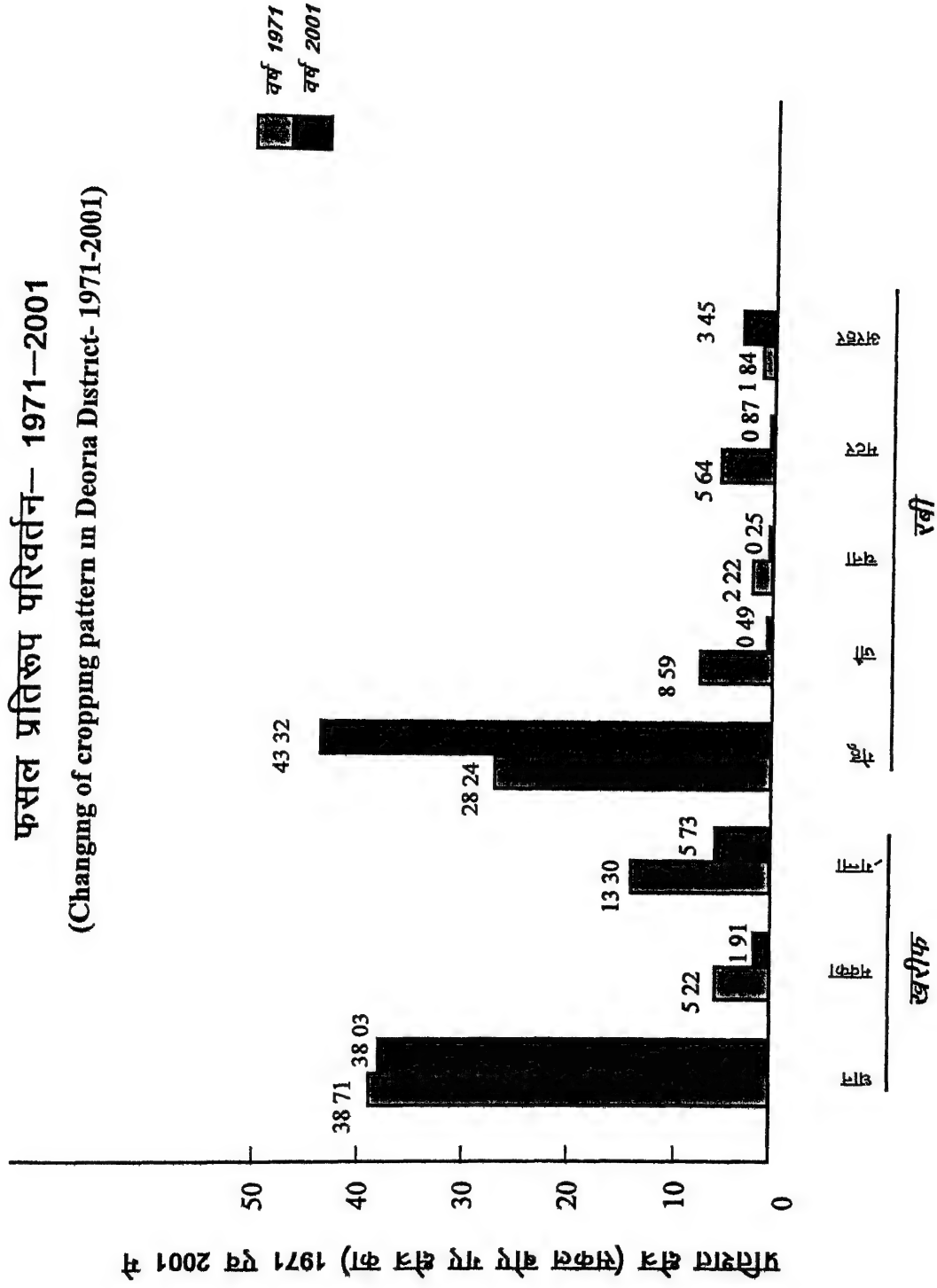
(ख) फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

सारणी (5 10) में 1971-72 तथा 2001 का फसल प्रतिरूप परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। इसे आरेख स (5 5) में भी प्रस्तुत किया गया है। सारणी एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप में विगत तीस वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में शुद्ध बोए गये क्षेत्र में विस्तार सिचाई सुविधाओं में वृद्धि तथा अन्य कृषि निष्ठियों (सहायक एवं उत्प्रेरक तत्वों) एवं विधियों के विकास तथा कृषकों द्वारा उन्हें अपनाया जाना शामिल है। सारणी से स्पष्ट है कि 1971-72 में जहाँ खरीफ सर्वप्रमुख फसल थी और इसमें धान

जनपद देवरिया

फसल प्रतारूप परवर्तन- 1971-2001

(Changing of cropping pattern in Deoria District- 1971-2001)



प्रमुख फसले

एव गन्ना की सर्वप्रथम भूमिका थी वही 2001 में सम्पूर्ण खरीफ फसलों के प्रतिशत क्षेत्र में गिरावट हुयी। परन्तु धान के अतर्गत प्रतिशत क्षेत्र लगभग समान बना रहा। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि 1971-72 में जहाँ धान प्रमुख फसल थी और यह सकल कृषित क्षेत्र के 38.71 प्रतिशत भाग पर बोयी जाती थी तथा गेहूँ का प्रतिशत क्षेत्र 28.24 था वही 2001 में ये स्वरूप उलट गया और गेहूँ प्रमुख फसल हो गयी। इस वर्ष गेहूँ सकल कृषित क्षेत्र के 43.32 प्रतिशत भाग पर बोयी गयी। सर्वाधिक परिवर्तन भी गेहूँ के फसल क्षेत्र में ही हुआ। खरीफ के अतर्गत गन्ना का प्रतिशत क्षेत्र कम हुआ है। जिसका प्रमुख कारण मिलो का बीमार होना और गन्ने के पैसे का किसानों को समय से भुगतान न हो पाना है। 1971-72 में जायद फसल के अतर्गत कोई क्षेत्र नहीं था पर 2001 में जायद के अतर्गत सकल कृषित क्षेत्र का 1.81 प्रतिशत क्षेत्र समाहित हो गया जिसे सारणी (5.8) में देखा जा सकता है। सारणी (5.10) से एक बात और स्पष्ट होती है कि 1971-72 से 2001 तक के कृषि विकास कालावधि में फसल प्रतिरूप *विविधीकरण* से *विशेषीकरण* की ओर उन्मुख हुआ है। 1971-72 में जहाँ सभी फसल कमोबेश मात्रा में बोए जाते थे वही 2001 में उनके क्षेत्र धान एव गेहूँ की फसल के अतर्गत समाहित हो गये।

सारणी 5.10

जनपद में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन (1971 एव 2001)

फसल	सकल बोये गए क्षेत्र का प्रतिशत		परिवर्तन
	1971-72	2001-00	
खरीफ	53.50	50.46	- 3.04
धान	38.71	38.03	- 0.68
मक्का	5.22	1.91	- 3.31
ज्वार	0.08	0.04	- 0.04
बाजरा	0.30	0.17	- 0.13
गन्ना	13.30	5.73	- 7.57
रबी	46.49	47.55	+ 1.06
गेहूँ	28.24	43.32	+ 15.08
जौ	8.59	0.48	- 8.11
चना	2.22	0.25	- 1.97
मटर	5.64	0.87	- 4.77
अरहर	1.84	3.45	+ 1.61
मसूर	0.74	0.41	- 0.33

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका, जनपद देवरिया- 2001 एव जिला गजेटियर जनपद देवरिया, 1988 से संगणित।
क्रमशः पृ- 45 से 56 एव गजेटियर पृ0 87-91

(ग) उत्पादकता

कृषि विकास के उत्प्रेरक एव सहायक तत्वों का सीधा प्रभाव उत्पादकता पर परिलक्षित होता है। अतः उत्पादकता में परिवर्तन को ज्ञात कर हम सेवाकेन्द्रों पर स्थापित सहायक तत्वों के

कृषि विकास पर पडने वाले प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। उत्पादकता कृषि क्षमता का मापक है। इसके आकलन का प्राथमिक सम्बन्ध इकाई क्षेत्र में प्रति हे उत्पादन से है जो सभी भौतिक एवं मानवीय कारकों के सम्बन्धों एवं अंतःसम्बन्धों की देन है। पोप स्टैम्य ¹¹ के अनुसार किसी इकाई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक अनुकूलित तत्वों तथा कृषि सक्षमता की देन है। प्रो शफी ¹² ने कृषि उत्पादकता को किसी विशिष्ट इकाई क्षेत्र की कृषि क्षमता का ही मापक के रूप में बताया है। किसी भी क्षेत्र की कृषि उत्पादकता उस क्षेत्र विशेष की कृषि सक्रियता कृषि गहनता और कृषि कुशलता पर निर्भर करती है। यदि इनमें कमी आती है तो उत्पादकता कम हो जाती है। इस प्रकार कृषि उत्पादकता इकाई क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से सम्बन्धित है जिसमें भौतिक मानवीय आर्थिक सांस्कृतिक तकनीकी और सस्थागत कारकों का योग रहता है।

सारणी 5 11 में प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के उत्पादकता परिवर्तन को देखने से स्पष्ट होता है कि विगत 30 वर्षों में कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है। इन वर्षों में कुछ विशेष फसलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई जैसे— मक्का में 1561 प्रतिशत ज्वार में 718 बाजरा में 380 प्रतिशत। अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख फसलों जैसे धान गेहूँ एवं गन्ना में ये वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई। ये वृद्धि मक्का ज्वार एवं बाजरा की तुलना में क्रमशः 267 प्रतिशत, 169 प्रतिशत एवं 44.7 प्रतिशत रही। परन्तु इनके अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के कारण उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी हुई। आरेख (5 6) के माध्यम से उत्पादकता पर कृषि निष्ठियों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है।

सारणी 5 11
विभिन्न फसलों का उत्पादकता परिवर्तन (कुन्तल/हे)

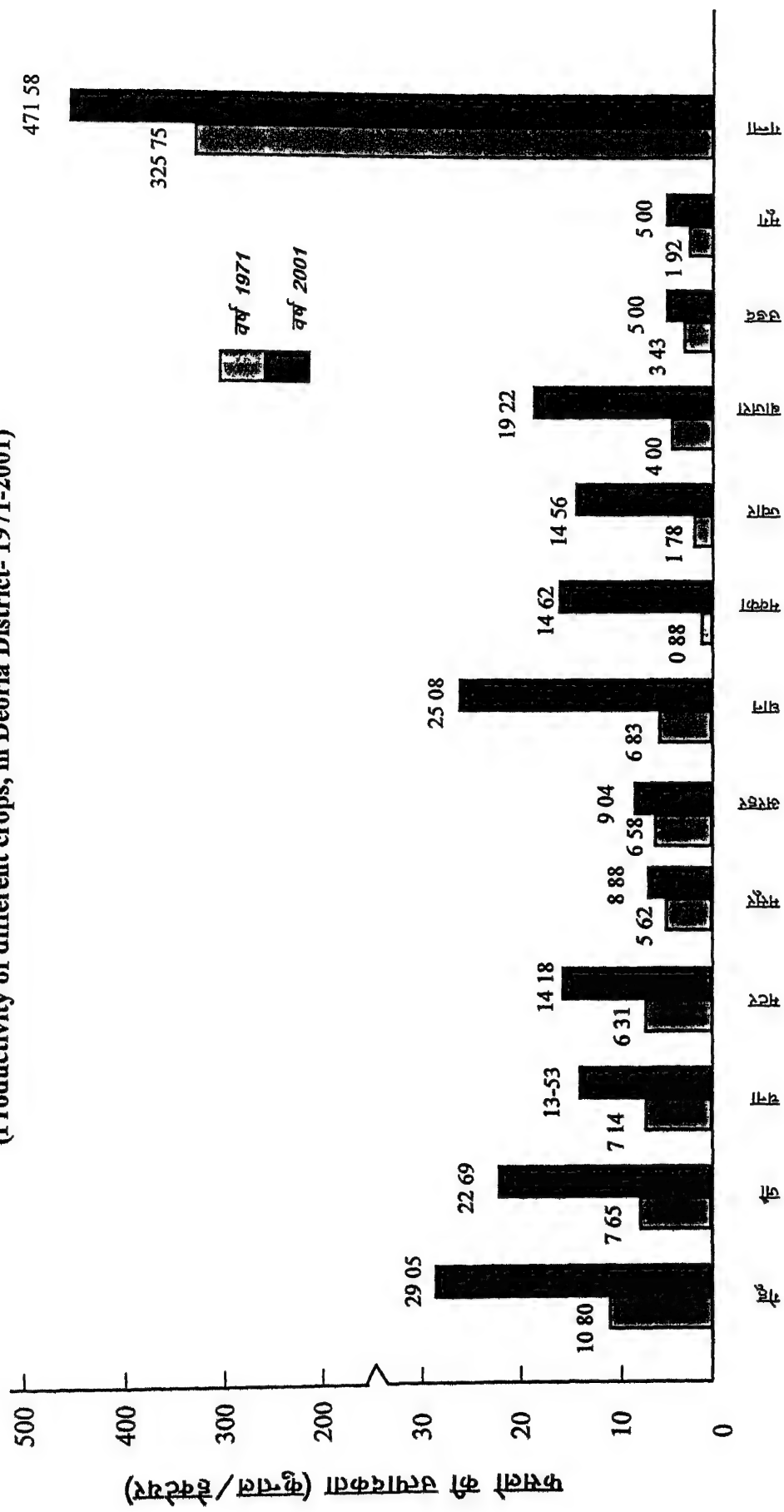
फसल	विभिन्न फसलों का उत्पादकता (कुन्तल/हे)		परिवर्तन	
	1971-72	2001		
गेहूँ	10.80	29.05	18.25	168.98 %
जौ	7.65	22.69	15.04	196.60 %
चना	7.14	13.53	6.39	89.49 %
मटर	6.31	14.18	7.87	124.7 %
मसूर	5.62	8.88	3.26	58.0 %
अरहर	6.58	9.04	2.46	37.3 %
धान	6.83	25.08	18.25	267.2 %
मक्का	0.88	14.62	13.74	1561.3 %
ज्वार	1.78	14.56	12.78	717.9 %
बाजरा	4.00	19.22	15.22	380.5 %
उड़द	3.45	5.00	1.55	44.9 %
भूँग	1.92	5.00	3.08	160.4 %
गन्ना	325.75	471.58	145.83	44.76 %

स्रोत— गजेटियर, देवरिया जनपद 1988 पृष्ठ-90 एवं सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद देवरिया-2000-2001 पृष्ठ- 19-20, गन्ना के लिए— सांख्यिकी पत्रिका 2001— पृ 28

जनपद देवसिया

विभिन्न फसलों की उत्पादकता- 1971-2001

(Productivity of different crops, in Deoria District- 1971-2001)



विभिन्न फसले

(घ) शस्य-गहनता

शस्य गहनता से अभिप्राय कृषि क्षेत्र में फसलो की आवृत्ति से है अर्थात् एक निश्चित कृषि क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसले उत्पन्न की जाती हैं अर्थात् फसलो की आवृत्ति उस क्षेत्र विशेष की गहनता कहलाती है। यह एक प्रकार से किसी भू-भाग में शुद्ध बोये गये क्षेत्र तथा सफल कृषित क्षेत्र का आनुपातिक सम्बन्ध है। किसी प्रदेश में शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा सकल कृषित क्षेत्र का अधिक होना गहन शस्य-क्रम का परिचायक है। यह (शस्यक्रम गहनता) वह सामयिक बिन्दु है जहाँ भूमि श्रम पूँजी प्रभुत्व तथा प्रबन्धन का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद होता है।¹³ इस प्रकार शस्य-क्रम गहनता प्राकृतिक दशाओ सामाजिक-आर्थिक एवं सस्थागत तथ्यो से प्रभावित होता है। इस आधार पर हम शस्य-क्रम गहनता के आकलन से 1971-72 से 2001 के मध्य कृषि विकास के स्वरूप को समझ सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शस्य गहनता सूचकाको की गणना निम्न सूत्र के माध्यम से की गयी है-

$$\text{शस्य गहनता सूचकांक} = \frac{\text{सकल कृषित क्षेत्र}}{\text{शुद्ध कृषित क्षेत्र}} \times 100$$

सारणी 5 12

शस्य गहनता सूचकांक (2001)

क्रम संख्या	प्रखण्ड विकास खण्ड	शस्य गहनता
1	भागलपुर	181 8
2	देवरिया	168 5
3	देसही देवरिया	168 0
4	पथरदेवा	165 7
5	गौरीबाजार	161 8
6	बैतालपुर	159 7
7	भलुअनी	155 8
8	लार	154 1
9	बनकटा	150 5
10	रुद्रपुर	150 1
11	भाटपारसानी	149 1
12	भटनी	148 7
13	बरहज	144 9
14	सलेमपुर	144 6
15	रामपुर कारखाना	123 7
योग जनपद		155 63

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ 165

1971-72 में अध्ययन क्षेत्र में शस्य गहनता 116 98 थी। उस समय एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र शुद्ध कृषित क्षेत्र का 31% था। इसके अतर्गत केवल वही क्षेत्र शामिल थे जिनपर गन्ना अरहर और धान की फसले बोयी गयी थी।¹⁴

2001 में अध्ययन क्षेत्र में शस्य गहनता बढ़कर 155 63 हो गयी। इस समय एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्र से प्रतिशत 55 63 था। इस समय कृषि की प्रवृत्ति में सबसे बड़ा अंतर ये आया कि जहाँ 1971-72 में एक बार से अधिक बोए गए फसल क्षेत्र में केवल गन्ना और अरहर ही शामिल थी वही अब जायद फसल के अतर्गत क्षेत्र विस्तार हुआ तथा गन्ना अरहर के अलावे सब्जी मक्का मूँग आदि फसलो सहित सरसो लाही फसले भी उगाही जाने लगी। 2001 में सर्वाधिक शस्य गहनता भागलपुर में तथा न्यूनतम शस्य गहनता रामपुर कारखाना में पायी जाती है। जनपद के सभी विकासखण्डों में फसल गहनता को सारणी 5 12 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

(ड) शस्य-विविधता

शस्य विविधता से आशय एक समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोयी जाने वाली फसल सख्या से है। इससे विभिन्न फसलों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा का पता चलता है। यह प्रतिस्पर्धा जितनी तीव्र होती है शस्य विविधता का परिणाम उतना ही अधिक होता है इसके विपरीत अल्प प्रतिस्पर्धा से विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। शस्य विशेषीकरण आज स्थिर कृषि एवं आधुनिक कृषि पद्धति की प्रमुख विशेषता है जिसके प्रोत्साहन में सिचाई उर्वरकों उन्नतशील बीजों कीटनाशकों और कृषि के आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग आदि का विशेष योगदान है। इसके विपरीत मौसम की अनिश्चितता तथा पारम्परिक कृषि व्यवस्था से शस्य विविधता में सदैव वृद्धि देखी जाती रही है। वास्तव में भौतिक-सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं से प्रेरित होकर कृषक कृषि प्रतिरूप में विविधता को अपनाता है। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में शस्य प्रतिरूप के अध्ययन में शस्य विविधता की जानकारी विभिन्न प्रकार से सहायक होती है।

शस्य विविधता के आकलन के लिए भाटिया (1965) महोदय ने निम्न सूत्र बताया है—

$$\text{शस्य विविधता सूचकांक} = \frac{\text{फसलों के अतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत}}{\text{फसलों की सख्या}}$$

उपर्युक्त सूत्र के प्रयोग द्वारा अध्ययन क्षेत्र में 1971-72 एवं 2001 के शस्य विविधता क्रम की गणना करने पर स्पष्ट होता है कि 1971-72 में जहाँ अध्ययन क्षेत्र में शस्य विविधता उच्च थी, वही 2001 में ये कम हुयी, अर्थात् 1971-72 से 2001 की कालावधि में कृषि प्रतिरूप शस्य विविधता से विशेषीकरण की ओर प्रवृत्त हुआ है। 1971-72 में किसान एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को बोते थे। इसके पीछे प्रमुख कारण था प्रतिकूल मौसम में भी उत्पादन प्राप्त

करना तथा कीटो और बिमारियो से बचाव। उस समय अरहर के साथ ज्वार उडद तिल मूँगफली बोयी जाती थी बाजरा के साथ उडद अरहर या मूँगफली चना और गेहूँ मटर और सरसो जौ और चना या मटर मक्का और उडद मूँगफली और ज्वार सामान्यत एक साथ बोये जाते थे। आलू के साथ प्याज एव मेथी तथा गन्ना के साथ मूँग बोया जाता था।

वर्तमान समय में यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में विशेषीकरण की प्रवृत्ति मिलती है परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर ये उन्ही जगहों पर दृष्टिगोचर होती हैं जहाँ धरातल समतल है मृदा उर्वर है सिचाई के उत्तम साधन हैं तथा परिवहन एवं बाजार की सुगमता है। जहाँ सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं साथ ही भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं वहाँ फसल विविधता का स्तर मध्य एवं उच्च काटि का है।

(च) शस्य-संयोजन

कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन में शस्य संयोजन सम्बन्धी अध्ययन कृषि प्रादेशीकरण हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली फसलों का अध्ययन होता है। किसी इकाई क्षेत्र में एक प्रमुख फसल के साथ अनेक गौण फसलें भी पैदा की जाती हैं। प्रायः कृषक खाद्यान्न दलहन तिलहन मुद्रादायिनी एवं सब्जी आदि फसलों की खेती करते हैं। इस प्रकार किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहते हैं। इसकी सहायता से फसलों के प्रतिरूप तथा कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को सुगमता पूर्वक पहचाना जा सकता है साथ ही कृषि की प्रकृति पद्धति एवं उनकी विशेषताओं के आधार पर कृषि प्रादेशीकरण हेतु उपागम प्राप्त किया जा सकता है जिसके आधार पर वर्तमान कृषि समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव दिए जा सकते हैं।¹⁵ शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण उन फसलों के स्थानिक वर्चस्व के आधार पर किया जाता है जिनमें क्षेत्रीय सहसम्बन्ध पाया जाता है एवं जो साथ-साथ विभिन्न रूपों में उगायी जाती हैं।¹⁶ किसी भी क्षेत्र के शस्य संयोजन का स्वरूप मुख्यतः उस क्षेत्र विशेष के भौतिक (धरातलीय स्वरूप जलवायु जलप्रवाह ढाल एवं मृदा) तथा सांस्कृतिक (आर्थिक सामाजिक एवं सस्थागत) वातावरण की देन होता है। इस प्रकार किसी भी प्रदेश का शस्य संयोजन मानव की क्रियाशीलता तथा भौतिक वातावरण के सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है।¹⁷

फसल संयोजन तथा फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण हेतु अनेक विद्वानों ने अनेक सांख्यिकीय विधियों को प्रस्तुत किया है। इनमें जानसन¹⁸ थामस,¹⁹ वीवर,²⁰ तथा अय्यर²¹ द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संरचना के विश्लेषण में दोई²² द्वारा अपनायी गयी विधि काफी महत्वपूर्ण है। इनमें वीवर तथा दोई द्वारा अपनायी गयी सांख्यिकीय विधियाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा कुछ सुधारों के साथ अनेक विद्वानों द्वारा अपनायी जा रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में दोई की विधि के आधार पर जनपद स्तर पर एवं प्रखण्ड

स्तर पर शस्य सयोजन का निर्धारण किया गया है।

दोई ने भी वीवर की भाँति यह माना है कि कृषित भूमि सभी फसलों में समान रूप से वितरित है। सैद्धान्तिक एवं वास्तविक प्रतिशतों का अंतर भी उसी तरह ज्ञात किया जाता है। इन दोनों प्रविधियों में अंतर सिर्फ इतना है कि वीवर के प्रसरण सूत्र $\Sigma d^2/N$ के स्थान पर दोई महोदय ने अंतरों के वर्ग अर्थात् Σd^2 को ही शस्य सयोजन का आधार माना है।

दोई के उपरोक्त सूत्र के आधार पर सर्वप्रथम 1971-72 एवं 2001 में जनपद स्तर पर शस्य सयोजन ज्ञात किया गया है ताकि इन तीस वर्षों में शस्य सयोजन पर कृषि विकास के उत्प्रेरक तत्वों के प्रभाव को स्पष्ट किया जा सके। इस क्रम में 1971-72 एवं 2001 में फसल प्रतिरूप सारणी- 5 13 में प्रस्तुत है।

सारणी- 5 13
फसल प्रतिरूप (1971-72—2001)

फसल	1971-72	फसल	2001
धान	38 71	गेहूँ	43 32
गेहूँ	28 24	धान	38 03
गन्ना	13 30	गन्ना	5 73
जौ	8 59	अरहर	3 45
मटर	5 64	मक्का	1 95
मक्का	5 22	मटर	0 87
चना	2 22	आलू	0 69
अरहर	1 84	सरसो	0 65
मसूर	0 74	जौ	0 48
बाजार	0 30	मसूर	0 41
ज्वार	0 08	चना	0 25
		बाजरा	0 17
		मूँग	0 13
		ज्वार	0 04

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका देवरिया-2001 एवं गजेटियर जनपद देवरिया- 1988 से संगणित

शस्य सयोजन परिकलन- 1971-72

$$\text{एक फसल} = (100-39)^2 = 3721$$

$$\text{दो फसल} = (50-39)^2 + (50-28)^2 = 605$$

$$\text{* तीन फसल} = (33\ 3-39)^2 + (33\ 3-28)^2 + (33\ 3-13)^2 = 472\ 67$$

$$\text{चार फसल} = (25-39)^2 + (25-28)^2 + (25-13)^2 + (25-9)^2 = 605$$

$$\text{पाँच फसल} = (20-39)^2 + (20-28)^2 + (20-13)^2 + (20-9)^2 + (20-6)^2 = 814$$

इस प्रकार 1971-72 में तीन फसलों का शस्य संयोजन—धान गेहूँ गन्ना (RWS) प्राप्त हुआ।

शस्य संयोजन परिकलन— 2000-2001

$$\text{एक फसल} = (100-43)^2 = 3249$$

$$* \text{दो फसल} = (50-43)^2 + (50-38)^2 = 193$$

$$\text{तीन फसल} = (33.3-43)^2 + (33.3-38)^2 + (33.3-6)^2 = 861$$

$$\text{चार फसल} = (25-43)^2 + (25-38)^2 + (25-6)^2 + (25-3)^2 = 1338$$

$$\text{पाँच फसल} = (20-43)^2 + (20-38)^2 + (20-6)^2 + (20-3)^2 + (20-2)^2 = 1662$$

वर्ष 2001 में उपर्युक्त परिकलन द्वारा दो फसलों का शस्य संयोजन प्राप्त हुआ। ये हैं गेहूँ धान (WR)

उपर्युक्त दोनों समय के शस्य संयोजन परिणामों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 1971-72 में जहाँ चावल सर्वप्रमुख फसल थी वही गेहूँ और गन्ना का प्रतिशत भी अधिक था। पूरे क्षेत्र में तीनों ही फसलों का साहचर्य था। 2001 तक आते आते ये साहचर्य परिवर्तित होकर मात्र गेहूँ और धान का (दोफसली) रह गया। ये कृषि विशिष्टीकरण की ओर संकेत करता है। चूँकि दोनों वर्षों में धान का प्रतिशत क्षेत्र अपरिवर्तित रहा है और गेहूँ का प्रतिशत क्षेत्र बढ़ा है अतः स्पष्ट है कि पहले जहाँ खरीफ फसल केवल मानसून पर निर्भर थी धीरे-धीरे सिंचाई साधनों तथा अन्य सहयोगी तत्वों के विकास के कारण रबी का प्रतिशत क्षेत्र बढ़ा। इसी कारण गेहूँ 2001 में सर्वप्रमुख फसल हो गई। गन्ना प्रारम्भ में तीसरी प्रमुख फसल थी, परन्तु चीनी मिलों की जर्जर स्थितियों मूल्य भुगतान में अनियमितता एवं अनिश्चिता आदि का प्रभाव गन्ना के कृषि प्रतिरूप पर पड़ा है। इन्हीं कारणों से गन्ना के लिए कृषि क्षेत्र के अनुकूल भौतिक दशाओं सिंचाई साधनों के पर्याप्त विकास एवं स्वयं एक नकदी फसल होने के बावजूद न सिर्फ इसका कृषि प्रतिशत क्षेत्र घटा है बल्कि 2001 के शस्य साहचर्य से भी ये गायब हो गया है।

दोई की उपर्युक्त सांख्यिकी विधि का उपयोग करते हुए अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड के फसल प्रतिरूप एवं शस्य साहचर्य का परिकलन किया गया है जो सारणी (5 14) में प्रस्तुत है।

उपर्युक्त परिकलन में उन्ही फसलों को सम्मिलित किया गया है जिनका विकासखण्ड स्तर पर सकल कृषि क्षेत्र से प्रतिशत न्यूनतम 2 तक है। इससे नीचे के अंक क्रम वाले फसलों को छोड़ दिया गया है। विकासखण्ड के कृषि प्रतिरूप के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों के शस्य साहचर्य को दोई की सांख्यिकी विधि का उपयोग करते हुए ज्ञात किया गया है। इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे हैं— **तीन फसली साहचर्य** वर्तमान में केवल देसही देवरिया और रामपुर

विकास खण्डवार शस्य प्रतिरूप एव शस्य संयोजन (2000-01)

विकास खण्ड	1	2	3	4	5	6	शस्य संयोजन
1 गौरीबाजार	चा 43	गे 42	ग 8	अ 2	-	-	चा गे [RW]
2 बैतालपुर	गे 44	चा 35	ग 9	मू 4	अ 3	-	गे चा [WR]
3 देसही देवरिया	गे 42	चा 40	ग 12	-	-	-	गे चा ग [WRS]
4 पथरदेवा	चा 43	गे 39	ग 10	-	-	-	चा गे [RW]
5 रामपुर कारखाना	गे 49	चा 34	ग 10	म 4	-	-	गे चा ग [WRS]
6 देवरिया सदर	गे 45	चा 40	ग 4	अ 2	मू 2	-	चा गे [WR]
7 रुद्रपुर	गे 43	चा 38	अ 6	म 4	मसूर 3	जौ 2	चा गे [WR]
8 भलुअनी	गे 49	चा 43	ग 4	अ 4	-	-	चा गे [WR]
9 बरहज	गे 40	चा 35	अ 6	ग 3	म 2	-	चा गे [WR]
10 मटनी	गे 43	चा 35	म 6	ग 5	अ 5	-	चा गे [WR]
11 भाटपासरानी	गे 43	चा 36	ग 6	म 6	अ 5	-	चा गे [WR]
12 बनकटा	गे 40	चा 31	ग 9	अ 3	-	-	चा गे [WR]
13 सलेमपुर	गे 46	चा 36	अ 5	ग 3	मट 2	-	चा गे [WR]
14 भागलपुर	गे 40	चा 30	अ 3	-	-	-	चा गे [WR]
15 लार	गे 43	चा 33	अ 7	ग 2	म 2	-	चा गे [WR]

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 42-54 से संगणित

संकेत-

चा - चावल अ - अरहर मसू - मसूर

गे - गेहूँ

जौ - जौ

मट - मटर

ग - गन्ना

म - मक्का

मू - मूँगफली

BLOCK WISE CROP-COMBINATION PATTERN IN DEORIA DISTRICT
2000-01



INDEX

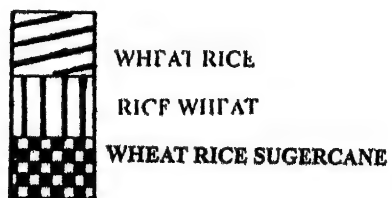


FIG 57

6 0 6 KM

कारखाना में ही पाया जाता है। बाकी सभी विकासखण्डों में **दो फसली साहचर्य** है। इसमें गौरी बाजार और पथरदेवा में ये साहचर्य चावल और गेहूँ के रूप में है तथा शेष सभी में गेहूँ की प्रधानता के साथ चावल के साथ। उपर्युक्त आधार पर *शस्य संयोजन प्रदेश* चित्र (5 6) में प्रदर्शित है।

(छ) फसल-चक्र

फसल चक्र से आशय फसलों का एक वर्ष दो वर्ष या तीन वर्ष में किसी क्षेत्र में क्रम बदलने से है। इससे उत्पादकता और उत्पादन के साथ-साथ मृदा उर्वरता का सकारात्मक सम्बन्ध होता है। किसी भी क्षेत्र का सम्बन्ध मूलतः कृषक की पारम्परिकता अनुभव ज्ञान वैज्ञानिकता एवं कृषि-जलवायु बोध द्वारा एवं आर्थिक-सामाजिक स्तर द्वारा निर्धारित होता है और गौणतः क्षेत्र की भौतिक दशा द्वारा नियंत्रित होता है। अतः विभिन्न कालों-1971-72 एवं 2001 में क्षेत्र के फसल चक्र के अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा कृषि के प्रति किसानों की जागरूकता वैज्ञानिकता व्यावसायिकता एवं कृषि बोध को जाना जा सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में हुए उनके अनुभव एवं विकास के साथ कृषि-सहायक तत्वों का पश्चप्रभाव भी ज्ञात हो जाएगा जो क्षेत्र विकास के नियोजन में प्रभावी भूमिका निभाएगा।

1971-72 में अध्ययन क्षेत्र में फसल चक्र के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसान अपने खेतों में चक्रण के रूप में विभिन्न फसलों को उगाते थे। इसके पीछे उनकी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं थी बल्कि परंपरा और अनुभवाधारित थी। उस समय क्षेत्र के विभिन्न भागों में ये चक्र मृदा प्रकार और सिंचाई सुविधा से नियंत्रित था। उस समय मूलतः धान, गेहूँ एवं गन्ना ही बोयी जाती थी। इस समय सामान्य रूप से रबी और खरीफ का चक्र निम्न रूप में था-

सारणी- 5 15
फसल चक्र- 1971-72

खरीफ	रबी	वर्ष क्रम
अगाती धान या मक्का	आलू/गेहूँ	एक वर्षीय
मक्का	आलू/गेहूँ/टमाटर	एक वर्षीय
भिण्डी	गेहूँ/सरसो/मटर	एक वर्षीय
पटुआ	गेहूँ / चना / जौ	एक वर्षीय
भिण्डी / तराई	गेहूँ / जौ	एक वर्षीय

स्रोत - *Uttar Pradesh District Gazetteers, Deoria- 1988, P-95*

वर्तमान समय में क्षेत्र के अधिकांश कृषक परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिकता एवं लाभ को ध्यान में रखकर फसल चक्र को अपना रहे हैं। वैसे यह प्रवृत्ति अभी भी शिक्षित और जागरूक किसानों में ही पायी जाती है। फिर भी कृषि में विशिष्टीकरण के प्रभाव के कारण ये फसल चक्र कुछ सीमित फसलों तक ही सिमट कर रह गया है। वर्तमान में निम्न फसल चक्र प्राये

जाते हैं यद्यपि इनमें क्षेत्रीय भिन्नता दृष्टव्य है जो सिचाई सुविधाओं के विकास तथा मृदा की प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं—

सारणी- 5 16
जनपद में फसल चक्र— 2001

क्रम	फसल चक्र	वर्ष क्रम
1	धान—गेहूँ	एक वर्षीय
2	मक्का—आलू	एक वर्षीय
3	मक्का—तोरिया—गेहूँ	एक वर्षीय
4	धान—गेहूँ—गन्ना	दो वर्षीय
5	धान—मक्का (रबी) उड़द/मूँग	एक वर्षीय
6	धान—मटर	एक वर्षीय
7	धान—जौ	एक वर्षीय
8	मक्का—राई	एक वर्षीय
9	मक्का—आलू	एक वर्षीय
10	धान—गेहूँ—हरी खाद (ढैचा/सनई)	एक वर्षीय
11	धान—गेहूँ—उड़द/मूँग	एक वर्षीय

स्रोत— खरीफ फसलों की सघन पद्धतियाँ— 2001 कृषि विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ पृ 132

(ज) पशुपालन

पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है। पशुधन की संख्या का प्रभाव न सिर्फ फसल के कुल उत्पादन पर पड़ता है, अपितु मृदा संरचना एवं उर्वरता भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। पशुधन की विभिन्न नस्लों में चौपाए ही अधिक प्रमुख हैं। केवल इसलिए नहीं कि इनकी संख्या अधिक है बल्कि इसलिए भी कि ये पशु कृषि कार्यों और किसान की सम्पन्नता में अधिक सहयोग देते हैं। कृषि के लगभग सभी कार्यों यथा— खेत जोतना, खाद लादना पानी प्राप्त करना, फसल मड़ाई और यातायात आदि में पशुशक्ति प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में यंत्रीकरण के फलस्वरूप अब इनका महत्व निरन्तर कम हुआ है। मॉस खाल ऊन बाल और मुर्गीपालन को छोड़कर पशुधन के अन्य सभी कामों में चौपायों का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के गोबर से बने कम्पोस्ट खाद में मृदा के मूल पोषक तत्वों (फास्फोरस पोटैश, नाइट्रोजन) के साथ सभी सूक्ष्म तत्व भी एक आदर्श अनुपात में पाए जाते हैं। जो रासायनिक उर्वरक (डीएपी) में नहीं पाए जाते हैं। इस दृष्टि से पशुओं का गोबर कृषि क्षेत्र की खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है। अध्ययन क्षेत्र में ईंधन के अन्य साधन न होने के कारण उपलब्ध गोबर का दो-तिहाई भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। पशुओं से कृषि कार्य में सहयोग के साथ ही साथ दूध की भी प्राप्ति होती है।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1993 की पशुगणना के अनुसार जिले में कुल पशुओं की संख्या

7 98 121 थी जिसमे कुल पशु आबादी का गौजातीय-38 4 प्रतिशत महिषवशीय- 17 91 प्रतिशत भेड- 1 62 प्रतिशत बकरा-बकरी- 29 2 प्रतिशत घोडे एव टट्टू- 0 04 प्रतिशत सुअर- 6 36 प्रतिशत एव अन्य पशु- 6 44 प्रतिशत थे। पशुगणना 1993 के अनुसार जनपद मे प्रति 100 हेक्टेयर क्षेत्र पर कुल पशुधन सख्या-316 थी। प्रति 1000 जनसख्या पर पशुधन सख्या-362 प्रति 100 जनसख्या पर दुधारु पशुओ की सख्या 7 एव प्रति 1000 जनसख्या पर कुक्कुटो की सख्या-80 रही है।

वर्ष 1997 की पशुगणना के अनुसार जनपद मे कुल पशुओ की सख्या 6,08 971 है

जो वर्ष- 1993 की अपेक्षा काफी कम है। इन चार वर्षो मे सभी प्रकार के पशुओ की सख्या मे भारी कमी हुयी है। सर्वाधिक कमी भेडो एव गौजातीय पशुओ की सख्या मे हुयी है। इनमे कमी का प्रतिशत क्रमश 42 68 एव 42 15 है। उसके बाद घोडे एव टट्टू मे 10 2 प्रतिशत तथा महिषवशीय एव बकरा-बकरियो की सख्या मे क्रमश 2 55 एव 2 35 प्रतिशत कमी हुयी है। इसे सारणी- 5 17 मे देखा जा सकता है।

सारणी- 5 17

पशुधन सख्या परिवर्तन- (1993-1997), जनपद देवरिया

मद	पशुप्रजाति	सख्या (1993)	प्रतिशत	सख्या (1997)	प्रतिशत	प्रतिशत कमी (1993-1997)
1	2	3	4	5	6	7
1	गौजातीय	306834	38 4	177474	29 10	42 15
2	महिषवशीय	142877	17 9	139222	22 90	2 55
3	भेड	12973	1 6	7436	1 22	42 68
4	बकरा-बकरियो	232874	29 2	227382	37 34	2 35
5	घोडे-टट्टू	372	0 04	334	0 05	10 20
6	सुअर	50781	6 36	50769	8 34	0 02
7	अन्य पशु	51410	6 44	6354	1 04	87 64

स्रोत- सामाजार्थिक समीक्षा जनपद देवरिया (200-2001) पृ- 28

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1993 के पशुगणना के अनुसार वर्ष 1997 की पशुगणना मे दर्शायी गयी प्राय सभी पशुओ की सख्या मे कमी आयी है। इसका प्रमुख कारण पशुओ के महत्व की उपेक्षा करना है। 1993 से 1997 मे मध्य भेड एव गौजातीय पशुओ की सख्या मे भारी कमी के बावजूद 1997 तक गौजातीय पशुओ का महत्व बकरा एव बकरियो के बाद बना हुआ है। अभी भी कुल पशुओ की सख्या मे बकरा-बकरी के बाद गौजातीय (29 प्रतिशत) एव महिषवशीय (23 प्रतिशत) पशुओ की ही सख्या है।

जनपद में पशुधन विकास हेतु वर्ष 2000-2001 के अन्त तक 25 पशु चिकित्सालय, 37

पशुधन विकास केन्द्र 32 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8 सुअर विकास केन्द्र 22 17 पिंगरी यूनिट तथा 298 पोल्ट्री यूनिट स्थापित हैं। खराब नस्ल के साढ़ों के स्थान पर उन्नत नस्ल के साढ़ों को कम दर पर वितरण कर कृत्रिम गर्भाधान माध्यम की क्रिया से मादा पशुओं को गर्भित कर नस्ल सुधार कार्य को सफल बनाया जा रहा है। पशुओं को उत्तम स्वास्थ्य हेतु चारा उत्पादन कार्यक्रम जनपद में पूरे जोर के साथ चलाया जा रहा है। कुक्कुट विकास कार्यक्रम का जनपद में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1993 में जहाँ कुल कुक्कुटों की संख्या 178057 थी वही वर्ष 1997 में कुल संख्या बढ़कर 283512 हो गयी।

जनपद के आर्थिक समस्या के समाधान में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूध उत्पादन घी एवं खाद उत्पादन में जनपद के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में पशुधन का सक्रिय सहयोग रहा है। 31 मार्च 2001 तक जनपद में 289 दूध उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

(झ) मत्स्यपालन

मानव शरीर के पोषण एवं विकास के लिए सतुलित आहार की आवश्यकता होती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में मिलाकर सतुलित आहार की पूर्ति करके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। सामान्यतया शरीर को स्वस्थ रखने हेतु विभिन्न पोषक तत्व जैसे— प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन खनिज और लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है किन्तु स्वस्थ शरीर के निर्माण में प्रोटीन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है क्योंकि यह हमारी मॉसपेशियों तन्तुओं तथा शरीर के द्रव्य तत्वों की संरचना करती है और प्रोटीन मुख्य रूप से मछली मॉस, अण्डे, दूध दाल इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। मछली के मांस में उच्च कोटि के प्रोटीन के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेड खनिज लवण तथा विभिन्न तत्व जैसे— कैल्शियम फास्फोरस, लोहा आदि भी सामान्य रूप से पाया जाता है। इस दृष्टि से मछली एक प्रोटीन युक्त सुपाच्य आहार है। जलीय खेती अर्थात् 'एक्वाकल्चर' एवं 'पीसीकल्चर' को अपनाकर जहाँ एक ओर जनसामान्य को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त एवं सुपाच्य मछली उपलब्ध कराया जा सकता है वही दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में उपलब्ध अकृष्य एवं जलमग्न भूमि के सदुपयोग के साथ-साथ इसे एक व्यवसाय के रूप में विकसित करके इस व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इस जनपद में मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत वर्ष 1982 से भारत सरकार—राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है। इसके मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल क्षेत्र का विकास तथा मत्स्य पालकों का ज्ञानवर्धन कर अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन सुनिश्चित करना है।

इस जनपद के ग्रामीण अंचल में तालाब, पोखर के रूप में ग्राम पंचायत के स्वामित्व के

अन्तर्गत विभिन्न आकार के कुल 1835 तालाब (जलक्षेत्र 866 हे) उपलब्ध है जिन्हे शासन द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में मछुआ समुदाय को पट्टे पर आवंटित कर इनके विकास यथा-गहरा करने बंधों की मरम्मत एवं जल आवागमन द्वार के निर्माण व्यावसायिक बैकों से ऋण तथा अभिकरण की ओर से रु 18000/- से 22500/- प्रति हे की दर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ वर्ष 1982 से अब तक कुल 802 तालाबों (जल क्षेत्र 508406 हेक्टेयर) का सुधार कार्य पूर्ण कराया गया है तथा अभिकरण के सौजन्य से निजी क्षेत्र में अकृषक भूमि पर कुल 285 तालाब (जलक्षेत्र 161769 हेक्टेयर) का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील मत्स्य पालकों द्वारा अपने स्वयं ससाधनों से 434 तालाबों (जलक्षेत्र 216918 हेक्टेयर) का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार इस जनपद में कुल 1521 तालाबों (जल क्षेत्र 887093 हेक्टेयर) विकसित जलक्षेत्र के रूप में उपलब्ध हैं जिसमें तकनीकी विधि से मत्स्य पालन कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

मत्स्य पालकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उपलब्ध कराने के दृष्टिगत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र खुखुन्दू पर मिनी हैचरी की स्थापना के साथ-साथ निजी क्षेत्र में शासकीय सहायता एवं स्वयं ससाधनों से 4 मिनी हैचारियों की स्थापना की गई है जिससे वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 13008 लाख मत्स्य बीज उत्पादित एवं वितरित किया जा चुका है।

मत्स्य पालकों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र खुखुन्दू पर निर्मित प्रसार प्रशिक्षण भवन में 10 दिवसीय अल्पकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार इस योजना के संचालन के फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन का स्तर 600 किग्रा से बढ़कर 2800 किग्रा प्रति हेक्टेयर के स्तर पर पहुँच चुका है।

औद्योगिक विकास

5.7 सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास मुख्यतः औद्योगिक विकास पर ही निर्भर है। इसलिए इसे मानव जाति के विकास की कुजी भी कहा जाता है। सभ्यता के आरम्भ से ही उद्योग मानव का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। प्रगति के अनेक सोपानों का निर्माण करते हुए इसने मानव को आदिम गुफाओं से चन्द्रमा तक पहुँचाया। उद्योग मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव प्रयासों के जिन-जिन क्षेत्रों की ओर हम दृष्टि करते हैं हमें औद्योगिक गतिविधियों की अमिट छाप देखने को मिलती है। गत पाँच दशकों में हुई औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से द्रुत गति से विकास हुआ है तथा औद्योगिक आधार में काफी विविधता आयी है।¹² साधारणतः आर्थिक भूगोल में 'उद्योग' शब्द का व्यवहार वस्तु निर्माण के लिए किया जाता है।

शब्दिक अर्थ में 'उद्योग' किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को कहते हैं।²⁴ कच्ची सामग्री को सशोधित और परिवर्द्धित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना उद्योग कहलाता है।²⁵ विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते हैं। जिनके द्वारा मानव कच्चे माल का स्वरूप परिवर्तित करके उसको अधिक उपयोगी बनाता है। ऐसे परिवर्तन कार्य कारखानों में होते हैं जहाँ अनेक स्थानों से कच्चा माल लाकर एकत्र किया जाता है।²⁶ मिलर²⁷ तथा एलेक्जेंडर²⁸ ने वस्तुओं को अधिक मूल्यवान् स्वरूप में परिवर्तन को ही विनिर्माण उद्योग कहा है। उनके अनुसार विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य उन विभिन्न प्रक्रियाओं से है जिनकी सहायता से व्यापार में बिकने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

5.8 औद्योगिक स्वरूप

आज के युग में किसी भी समाज की औद्योगिकरण की स्थिति का सीधा सम्बन्ध उसकी अर्थव्यवस्था से है। वास्तव में औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। यही नहीं औद्योगिकरण से कृषि के क्षेत्र में भी अभिवृद्धि हुई है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और विकास स्तर को बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के साथ-साथ प्राथमिकता भी दी जाये।³⁰ औद्योगिकरण के महत्व को सभी स्वीकारते हैं किन्तु इसके स्वरूप के बारे में एक मत नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक स्वरूप तीन अवस्थाओं से गुजरा है। प्रथम अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार करना है। द्वितीय अवस्था का सम्बन्ध कच्चे माल के रूप परिवर्तन से है तथा तृतीय अवस्था में उन मशीनों तथा पूँजी यन्त्रों का निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी तात्कालिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि नहीं करती वरन् भावी उत्पादन क्रिया को सुविधाजनक बनाती है।

औद्योगिक विकास के रूसी सरचना में सीधे प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में प्रवेश किया गया किन्तु ब्रिटिश ढाँचे में धीरे-धीरे विकास किया गया। इसी प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार औद्योगिकरण के विभिन्न स्वरूप विकसित किए जा सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों एवं देशों के औद्योगिकरण के स्वरूप में पूँजी अभाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रम की अधिकता को देखते हुए श्रम प्रधान औद्योगिक स्वरूप अधिक उपयुक्त होता है। अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से चयनित उद्योग ही लगाना चाहिए जिससे वास्तविक रूप में क्षेत्र विकास हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर आयात-प्रतिस्थापक एवं निर्यात सवर्धन उद्योग में सतुलन स्थापित करना चाहिए। वास्तव में किसी भी देश या क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप नियोजकों के नियोजन व प्राथमिकता तथा ससाधनों पर आश्रित है।

अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर गिनी-चुनी मात्र कुछ औद्योगिक ईकाइयाँ हैं। ये भी कृषि आधारित उद्योग ही हैं। चूँकि जनपद सिन्धु-गंगा मैदान के जलोढ़ निक्षेपों तथा राप्ती, घोटी गण्डक एवं इनकी शाखाओं द्वारा निर्मित कृषि प्रधान मैदानी क्षेत्र है अतः यहाँ कृषि प्रधान उद्योग ही विकसित हुए।

किसी भी क्षेत्र का औद्योगिकरण मुख्यतः वहाँ प्राप्त प्राकृतिक ससाधनो एवं ऊर्जा उपलब्धता पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र प्राकृतिक ससाधन की दृष्टि से निर्धन है परन्तु कृषि क्षेत्र में समृद्ध है। अतः मूलतः यहाँ कृषि आधारित उद्योग ही प्रोत्साहित हुए। औद्योगिक पिछड़ेपन की दृष्टि से शासन द्वारा इस जनपद को सी श्रेणी में रखा गया है।

5.9 उद्योगों का वर्गीकरण

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों सीमित है तथा उनमें विविधता का अभाव है। प्रायः सभी इकाइयों कृषि आधारित उद्योग ही हैं। अतः आकार के अनुसार इन्हें तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) वृहद् उद्योग

(ब) लघु उद्योग

(स) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग

(अ) वृहद् उद्योग

इस प्रकार के उद्योगों में उर्जा चालित मशीनों का प्रयोग होता है तथा श्रमिक व पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र में वृहद् उद्योग के अंतर्गत चीनी मिलों एवं पेपर मिल को रखा जा सकता है। देश स्तर पर वृहद् उद्योगों के अंतर्गत जिन इकाइयों को रखा जाता है उस दृष्टि से इन इकाइयों को वृहद्-मध्यम वर्गीय उद्योग की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। सारणी- 5.18 एवं चित्र (5.8) में इनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।

(क) चीनी उद्योग का विकास

जनपद में गुड तथा खाडसारी उद्योग 18वीं शताब्दी में विकसित थे। इसका केन्द्र रामपुर कारखाना था। इस स्थान पर प्राचीन समय में 500 कारखाने खाडसारी उद्योग के रूप में विकसित थे। यहाँ के जमींदारों ने चीनी निर्माण हेतु बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ आदि स्थानों के कारीगरों को लाकर यहाँ बसाया था। उस समय देवरिया (सम्प्रति मुख्यालय) चीनी रखने के गोदाम के रूप में ही जाना जाता था। देवरिया शहर से 40 किमी दूर बरहज शहर भी चीनी के गोदामों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से नावों द्वारा चीनी विदेशों में निर्यात की जाती थी।

20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जनपद में चीनी उद्योग के लिए बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना की गयी। अंग्रेजी शासन के समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। धीरे-धीरे ये चीनी उद्योग के कारखाने जनपद में महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में बदल गये पर इसके विकास के साथ ही खाडसारी उद्योग नष्ट हो गया।

पूरे अध्ययन क्षेत्र में चीनी उद्योग हेतु अनुकूल स्थितियाँ सुलभ हैं। क्षेत्र में गन्ना की उच्चतम

सारणी 518
वृहद् एव मध्यम वर्गीय उद्योग देवरिया- 2001

इकाई का नाम व पता	अवस्थिति	उत्पादित वस्तु एवं उत्पादन क्षमता	विद्युत खपत	पूँजी विनियोजन (करोड़ रु में)	रोजगार	स्थापना वर्ष
सार्वजनिक क्षेत्रक						
1 दी यूपी स्टेट सुगर कारपोरेशन लि देवरिया	देवरिया	चीनी 914 TCD	1054 KVA	2 20	861	1932
2 दी यूपी स्टेट सुगर कारपोरेशन लि बैतालपुर	बैतालपुर	चीनी 914 TCD	900 KW 500 KVA	5 70	735	1929
3 दी यूपी स्टेट सुगर कारपोरेशन लि भटनी देवरिया	भटनी	चीनी 1016 TCD	816 KVA	3 66	870	1932
निजी क्षेत्रक						
4 मे कानपुर सुगर मिल्स लि गौरीबाजार देवरिया	गौरीबाजार	चीनी 950 TCD	1080 KW	5 00	744	1932
5 दी प्रतापपुर सुगर मिल्स प्रतापपुर देवरिया	प्रतापपुर	चीनी 1500 TCD	432 VHP	10 97	783	1932
6 मे देवरिया पेपर मिल्स लि हाटारोड नरायनपुर देवरिया	हाटा रोड नरायनपुर	पेपर 4000 MTA	750 KVA	1 26	73	1995

स्रोत- निर्देशिका जनपद देवरिया में स्थापित लघु/मध्यम/वृहदस्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ जिला उद्योग केन्द्र देवरिया- 2000-2001 पृ-5

पैदावार हैं घनी जनसंख्या सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराती है तथा ईंधन के रूप में खोइया का प्रयोग होता है। स्थानीय क्षेत्रों से लकड़ियाँ भी उपलब्ध हो जाती हैं। कोयला झारखण्ड से प्राप्त किया जाता है तथा रिहन्द बॉध योजना से जल-विद्युत सुलभ हो जाता है। जनपद की सभी मिलें या तो नदियों के किनारे या नालों के किनारे स्थित हैं जिससे शुद्ध जल की प्राप्ति हो जाती है। चूना गन्धक आदि की प्राप्ति नजदीकी स्थानों से हो जाती है। देवरिया मुख्यालय की उत्तर-पूर्व रेलवे पर अवस्थिति तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 से निकटता के कारण चीनी के निर्यात एवं व्यापार के लिए इसे एक आदर्श परिवहन जाल प्राप्त है। अतः इन सभी अवस्थापन तत्वों की उपलब्धता के कारण जनपद में चीनी उद्योग का विकास हुआ।

वर्तमान समय में यहाँ का चीनी उद्योग सकट के दौर से गुजर रहा है। चीनी उद्योग को सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग से मुक्त करने (1998), तथा जनवरी 2000 से लेवी व खुली बिक्री अनुपात 40/60 से घटाकर 30/70 किए जाने के बावजूद इस उद्योग की समस्या बढ़ती ही जा रही है। चीनी गोदामों में ही पड़ा हुआ है तथा किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। चीनी उद्योग की समस्या को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका सरकार की आयात नीति की भी रही। इधर के वर्षों में देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धि के बावजूद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी का आयात किया, जिससे घरेलू चीनी अपेक्षाकृत महगी हो गयी। इन सब का प्रभाव घरेलू चीनी के व्यापार पर पड़ा।

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है जिसकी प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। इसी आधार पर यहाँ का औद्योगिकरण भी चीनी उद्योग के रूप में हुआ। इस प्रकार कृषि स्तर पर गन्ना से एवं औद्योगिक स्तर पर चीनी उद्योग से क्षेत्र के कृषकों की आय मूलतः निर्धारित एवं प्रभावित होती है। *कृषि-कृषक एवं उद्योग* की इस परस्पर सम्बद्धता के कारण चीनी उद्योग की इस समस्या का दुष्प्रभाव समूचे कृषि प्रतिरूप में गन्ना क्षेत्र का ह्रास कृषक का गिरता आय स्तर एवं अतत ह्रासोन्मुख आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रूप में दिख रहा है। क्षेत्र की चीनी मिलों का विवेचन निम्नवत् प्रस्तुत है—

(1) प्रतापपुर सुगर मिल, प्रतापपुर

यह मिल बनकटा विकासखण्ड के प्रतापपुर स्थान पर 1932 में स्थापित हुआ। यह जनपद का सबसे बड़ा चीनी मिल है। यह गोरखपुर-छपरा रेल लाइन पर बिहार सीमा पर स्थित है। इस मिल में चीनी तथा शीरा का उत्पादन होता है।

(2) कानपुर सुगर मिल गौरीबाजार

इसकी स्थापना 1932 में गौरीबाजार विकासखण्ड के मुख्यालय पर हुयी। यह जनपद के बागर क्षेत्र में अवस्थित है तथा सड़क एवं रेल लाइन से जुड़ा है। इसमें चीनी तथा शीरा का उत्पादन होता है।

MAJOR INDUSTRIES OF DEORIA, 2001-02

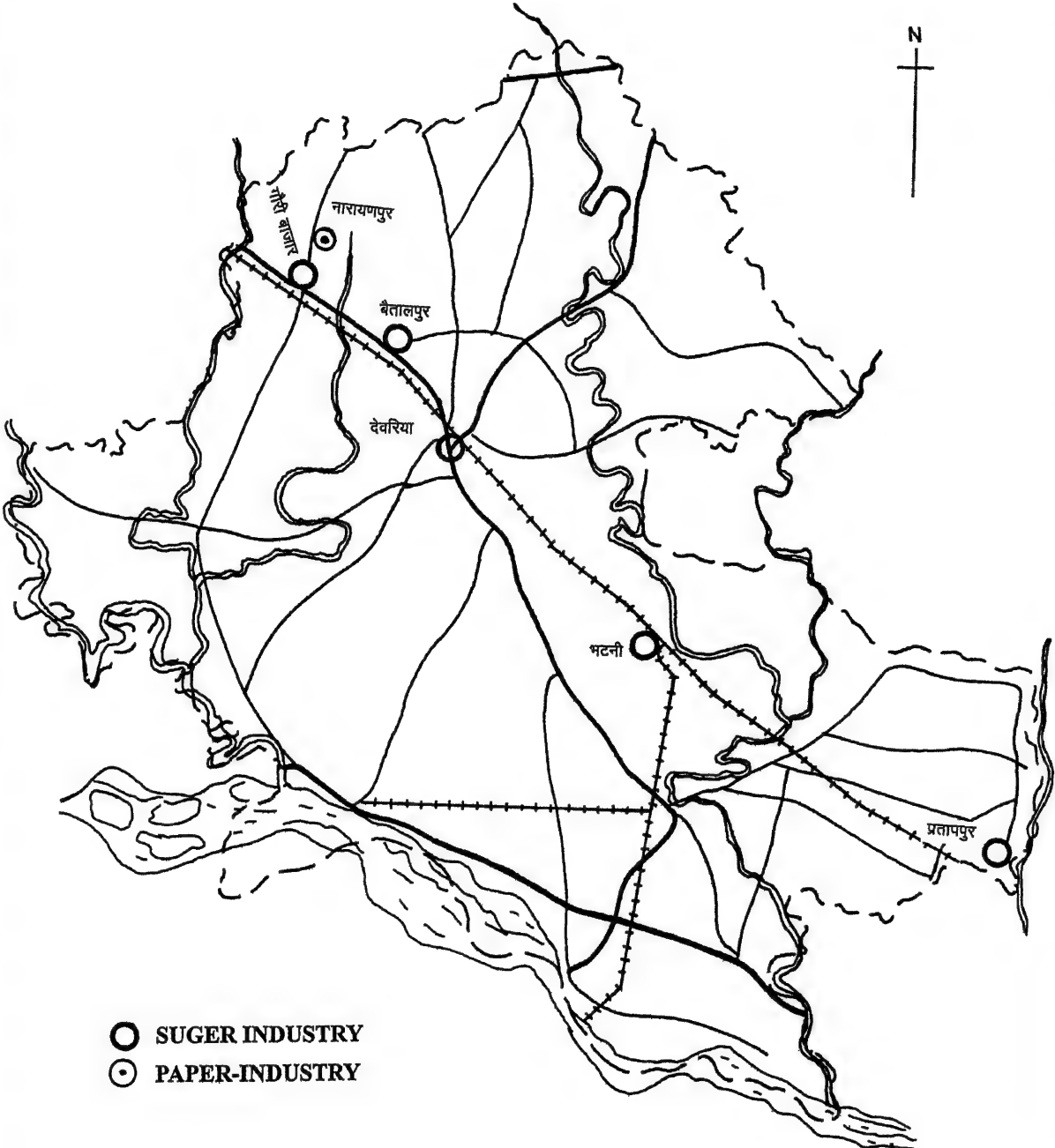


FIG 5 8 6 0 6 KM

(3) यू पी स्टेट सुगर कारपोरेशन भटनी

इस चीनी मिल की स्थापना 1932 में भटनी विकासखण्ड में की गयी। यह रेललाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ मुख्यतः चीनी और शीरा पैदा होता है।

(4) यू पी स्टेट सुगर कारपोरेशन देवरिया

इस चीनी मिल की स्थापना जनपद मुख्यालय पर 1932 में की गयी। यह भी सड़क और रेल मार्ग से सम्बद्ध है तथा चीनी और शीरा का उत्पादन होता है।

(5) यू पी स्टेट सुगर कारपोरेशन, बैतालपुर

यह मिल 1929 में बैतालपुर विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित हुयी। यह भी सड़क और रेलमार्ग से सम्बद्ध है तथा चीनी के साथ शीरा का उत्पादन होता है।

(ब) लघु उद्योग

लघु उद्योग की परिभाषा विभिन्न औद्योगिक नीति में भिन्न-भिन्न रही है। फरवरी 1999 में लघु क्षेत्र में निवेश की सीमा को 1 करोड़ रुपया किया गया। लघु उद्योग किसी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए बेरोजगारी की समस्या को हल करने में योगदान करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार के उद्योग में भी पिछड़ा हुआ है। इसके अतर्गत धान की उपलब्धता की दृष्टि से जनपद में बहुत अधिक मात्रा में *मिनी राइस मिले* ही स्थापित हैं। इसके अलावे इजीनियरिंग वर्क्स, फूड स्टाफ्स ऑयल इण्डस्ट्रीज गुड़ उद्योग विद्युत वल्ब प्लास्टिक उद्योग प्रिंटिंग प्रेस आदि विकसित हैं। लघु उद्योग के विकास के लिए पूँजी एवं तकनीकी ज्ञान दिए जा रहे हैं। जनपद में लघु पैमाने के निम्नलिखित उद्योग विकसित हैं—

(क) कृषि पर आधारित उद्योग

जनपद में कृषि पर आधारित उद्योग ही मुख्य रूप से विकसित हैं। इनमें चावल और आटा मिल सर्वप्रमुख हैं। जनपद में बड़े पैमाने की दो चावल की मिलें हैं। एक *सलेमपुर* में तो दूसरी जनपद मुख्यालय से 5 किमी दूर कसया रोड पर *गौरा* ग्राम में— *मार्डर्न राइस मिल गौरा*। इस मिल की धान कूटने की क्षमता 20 क्विंटल प्रति घण्टा है। कच्चे माल के रूप में धान स्थानीय क्षेत्रों से तथा गोरखपुर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ जनपद आदि स्थानों से ट्रक द्वारा मगाया जाता है। सम्प्रति यह मिल कुछ कारणों से बंद है। *लक्ष्मी फ्लोर मिल* जनपद मुख्यालय पर 1989 में स्थापित की गयी। इसमें सूजी तैयार करने की आधुनिक मशीनें लगी हैं। इसके अलावे कृषि पर आधारित फ्लोर मिल गुड़ और खाडसारी जनपद के मुख्य उद्योग हैं जो नगरीय केन्द्रों चौराहों, बड़े ग्रामों में विकसित हैं।

(ख) दफती एवं कागज उद्योग

कृषि पर आधारित इस उद्योग की दो इकाइयाँ *गौरी बाजार* विकासखण्ड में तथा

एक—एक इकाइयों *देवरिया* एव *लार* में स्थापित है। गन्ने की खोई एव पुआल इसके प्रमुख कच्चा माल है। चीनी उद्योग के समस्याग्रस्त होने एव बढ़ होने से ये उद्योग भी प्रभावित हो रहा है।

(ग) लकड़ी पर आधारित उद्योग

जनपद के प्रमुख सेवाकेन्द्रों— *देवरिया*, *रुद्रपुर*, *बरहज*, *सलेमपुर*, *भाटपार*, *गौरीबाजार* आदि स्थानों पर यह उद्योग विकसित है। इन केन्द्रों पर फर्नीचर हेतु बाहर से लकड़ी मगायी जाती है।

(घ) पशुओं पर आधारित उद्योग

जनपद के *गौरीबाजार*, *बरहज*, *सलेमपुर*, *लार* आदि सेवाकेन्द्रों तथा विकासखण्डों के प्रमुख सेवाकेन्द्रों पर यह उद्योग विकसित है। इसमें *बरहज* तथा *गौरीबाजार* बोन फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है। पशु सम्पदा में सम्पन्न जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल (हड्डी) की प्राप्ति हो जाती है। *बरहज* एव *गौरीबाजार* में बूचडखाना भी है। बोन फर्टिलाइजर में 25 प्रतिशत खाद तथा 75 प्रतिशत चूना पैदा किया जाता है।

(ङ) हैण्डलूम उद्योग

जनपद के *भाटपाररानी*, *कपरवार*, *घाट लार*, *रुद्रपुर*, *मदनपुर*, *भलुअनी*, *बरहरा* आदि स्थानों पर यह उद्योग विकसित है।

(च) रसायन उद्योग

जनपद में प्लास्टिक, चाक, स्याही आदि उद्योग जनपद मुख्यालय पर विकसित हैं। *बरहज*, *लार*, *भाटपाररानी* आदि स्थानों पर रसायन उद्योग के केन्द्र हैं।

(छ) इजीनियरिंग उद्योग

जनपद मुख्यालय, *बरहज*, *भाटपार रानी लार*, *गौरी बाजार*, *रामपुर कारखाना* आदि स्थानों पर इजीनियरिंग विकसित है। यहाँ मशीनों के औजार, कृषि यन्त्र आलमारी बाक्स लोहे के दरवाजे आदि निर्मित किये जाते हैं।

(ज) रेशम उद्योग

कुशीनगर के जनपद बन जाने से रेशम उद्योग अब नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि रेशम उद्योग के अधिकांश केन्द्र कुशीनगर में जा चुके हैं। जनपद में देसही *देवरिया* विकास खण्ड में *बराव सेमरा* (1982) में रेशम उद्योग विकसित है।

(झ) ईट उद्योग

समस्त जनपद मैदानी क्षेत्र है, अतः ईट उद्योग जनपद के सभी विकासखण्डों में विकसित है। व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण श्रमिकों और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। प्रत्येक मट्ठे

पर झारखण्ड राज्य के रॉन्ची से श्रमिक आकर यहाँ कार्य करते हैं जिनमें महिलाएँ अधिक हैं।

(ज) प्रिंटिंग प्रेस

जनपद मुख्यालय में प्रिंटिंग प्रेस की बहुलता है। यहाँ से छ दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं— *दैनिक ग्राम स्वराज हिन्दुस्थान का स्वरूप आकाशमार्ग जगत आशा सीमा रेखा*। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं।

(स) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को साधारणतया एक समान माना जाता है। यद्यपि काल एवं स्थान के अनुसार इनमें सूक्ष्म भेद बताया जाता है। कुटीर उद्योग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक निर्माण उद्योग का आधार है। इसके अन्तर्गत दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से घर में ही वस्तुएँ बनाता है। इस उद्योग की प्रमुख विशेषता स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग है। इसके उत्पादों की उपादेयता स्थानीय लोगों के लिए अधिक होती है। इन उद्योगों का उत्पादन छोटे स्तर पर होता है तथा बहुत साधारण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।³¹ विस्तृत अर्थों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में उन सभी उद्योगों को सम्मिलित किया जा सकता है जो ग्रामीणों द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में किये जाते हैं। ये उद्योग जातिगत या परम्परागत उद्योग के रूप में हो सकते हैं।³²

1997 से कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग में निवेश की उच्चतम सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है। भारतीय प्रशुल्क कमीशन ने इन उद्योगों को दो वर्गों में रखा है— 1 *ग्रामीण कुटीर उद्योग*
2 *नगरीय कुटीर उद्योग*।

जनपद के लगभग सभी सेवाकेन्द्रों पर ग्रामीण बाजारों में तथा बड़े ग्रामों में यह उद्योग विकसित है। **साबुन उद्योग**— लार देवरिया में विकसित है। **तेल उद्योग**, गुड उद्योग भुजिया चावल उद्योग जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में विकसित है।

चमड़े का उद्योग—भलुअनी कोइलगडहा सलेमपुर लार आदि स्थानों पर विकसित है।

इसी प्रकार लकड़ी पर आधारित उद्योग कुर्सी मेज स्टूल, कृषि औजारों में प्रयुक्त होने वाले सामानों के उद्योग भाटपार रानी, सलेमपुर बरहज रुद्रपुर लार आदि स्थानों पर विकसित है।

मिट्टी के बर्तनों के उद्योग प्रत्येक बाजार केन्द्रों बड़े ग्रामों और नगरीय केन्द्रों पर विकसित है।

खादी उद्योग— लार, बडहरा गरेड आदि ग्रामों में विकसित है। रस्सी उद्योग पटसन और मूँज पर आधारित है। डलिया मुनिया दौरा आदि ग्रामीण औरते अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करती हैं।

मत्स्य पालन उद्योग अनेक विकास खण्डों में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा नदी तालाबों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का महत्व

निरन्तर बढ़ती जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाली जनसंख्या का जीवन—स्तर उठाने आर्थिक विषमता को कम करने एवं बढ़ती शहरीकरण की समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प है— ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग का विकास। तेजी से बढ़ती हुई ग्रामीण जनसंख्या को कृषि क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर को देखते हुए सबको काम नहीं दिया जा सकता। अतः इन उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि प्राकृतिक रूप से श्रमिकों को अपने अनुकूल वातावरण में कार्य मिल जाता है। इससे उनके सामर्थ्य इच्छा और रुचि के अनुरूप तथा व्यक्तिगत योग्यता एवं प्रवृत्ति के अनुसार व्यवसाय चलाने की सम्भावना भी बन जाती है। अध्ययन क्षेत्र में कच्चा माल स्थानीय योग्यता और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र में श्रम के बाहुल्य तथा पूँजी के अभाव को देखते हुए कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न तथ्यों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है।

- (1) गाँव के कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त हैं।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर अर्द्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- (3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आय—स्तर को सुधारने हेतु क्षेत्रीय—प्राकृतिक और मानवीय ससाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है।
- (4) इन उद्योगों की स्थापना से बहुसंख्यक ग्रामीणों की क्रय—शक्ति में सुधार होगा फलस्वरूप उद्योगों पर आधारित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होगी और उनके जीवन—स्तर में सुधार होगा।
- (5) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करके गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोका जा सकता है।
- (6) इन उद्योगों की स्थापना से कृषि एवं उद्योगों के समन्वित सहयोग से सतुलित विकास की प्राप्ति हो सकेगी।
- (7) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना से कुछ सीमा तक उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

किया जा सकता है।

(8) धन एवं आय की विषमता को कम किया जा सकता है।

(9) चूँकि इनकी अवस्थापना में कम-पूँजी एवं कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रारम्भ कर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

5 10 औद्योगिक अवस्थापन सुविधायें

अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में कुछ सुविधाओं की स्थापना एवं विकास किया गया है। इनमें प्रमुख हैं— औद्योगिक आस्थान औद्योगिक क्षेत्र मनी औद्योगिक आस्थान एवं प्राविधिक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सारणी-5 19)। ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की गयी है तथा वित्तीय सहायता जनपद के बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

5 11 समस्या एवं विकास नियोजन

कृषि प्रधान अध्ययन क्षेत्र में तथा उस पर आधारित औद्योगिकीकरण के तमाम प्रयासों के फलस्वरूप निःसन्देह क्षेत्र का विकास गतिमान हुआ है। परन्तु विकास की दशा और दिशा के क्षेत्रीय संसाधन आवश्यकता से मेल न होने से न सिर्फ विकास को अनुकूल गति नहीं मिल पायी बल्कि कई नवीन समस्याओं का उद्भव हो गया। अतः इन समस्याओं का समाधान करने तथा क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु क्षेत्रीय संसाधनों के आधार पर नियोजित विकास रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। ताकि विकास को सही दिशा और गति मिल सके। इन समस्याओं को कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विभक्त कर इनका विकास नियोजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

(अ) कृषि समस्या एवं विकास नियोजन

कृषि क्षेत्र का विकास एवं सेवाकेन्द्रों के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विकास के लिए विकास पूँज सेवाकेन्द्रों से ही प्रस्फुटित होकर क्षेत्र में प्रसारित होती हैं और सेवाकेन्द्रों पर ये विकास ऊर्जा या तो सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है या विकास क्रम में स्वतः इनका केन्द्रों पर जनन और प्रस्फुटन हो जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास कृषि विकास में गति प्राप्त किए बिना सम्भव ही नहीं है। अतः कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि उसके विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न अवयवों को नियोजित ढंग से विकसित किया जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति सुसंगठित प्रयासों से ही सम्भव है जिसमें प्रशासक और योजना निर्माता शोध करने वाले वैज्ञानिकों प्रसार कार्यकर्ताओं, वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने वाली

औद्योगिक अवस्थापन सुविधाएँ देवरिया जनपद- 2001

अवस्थापन सुविधा का नाम	क्षेत्रफल (एकड़)	शेड स	विकसित प्लॉट स	आवटन की स्थिति
(क) औद्योगिक आस्थान				
1 औद्योगिक आस्थान देवरिया	15 08	19	39	39
2 औद्योगिक आस्थान, सलेमपुर	5 00	5	16	16
(ख) औद्योगिक क्षेत्र				
1 औद्योगिक क्षेत्र- उसरा बाजार	147 00		55	38
(ग) मिनी औद्योगिक आस्थान,				
1 मिनी औद्योगिक आस्थान गौरी बाजार	2 29		32	32
2 मिनी औद्योगिक आस्थान रुद्रपुर	2 50		36	19
3 मिनी औद्योगिक आस्थान बरहज	2 34		29	
4 मिनी औद्योगिक आस्थान पथरदेवा	2 50	—	44	44
5 मिनी औद्योगिक आस्थान भाटपार रानी	4 66	—	52	—
(घ) प्राविधिक / औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान एवं अन्य				संख्या
1 प्राविधिक शिक्षण सस्थान ..				1
2 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान				1
3 ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र				1
4 राज्य निर्यात निगम एवं अखिल भारतीय हस्तकला मण्डल द्वारा संचालित कालीन प्रशिक्षण केंद्र				1

स्रोत- निर्देशिका जनपद देवरिया में स्थापित लघु/मध्यम/वृहदस्तरीय औद्योगिक इकाइयों जिला उद्योग केंद्र देवरिया- 2000-2001 पृ-2-4

एजेसियो जनसंचार माध्यमों तथा कृषकों के सहयोग की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के कृषकों की सहनशीलता उल्लेखनीय तथ्य है। लगातार बाढ़— सूखा का शिकार होने के बावजूद कृषक देव—अधीन कृषि कार्य करने में लगे हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए समन्वित फसल पशुधन मत्स्यपालन तथा बागवानी जैसे उद्यमों के जरिये कृषि में विभिन्नता लाकर कृषि आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। कृषि के क्षेत्र में सामान्य वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी पर सीधे आक्रमण करने की नीति अपनाकर एक सचेष्ट परिवर्तन लाना होगा क्योंकि कृषि विकास के बिना अध्ययन क्षेत्र की गरीबी को दूर करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमें कृषि विकास को केवल और अधिक अनाज उपजाने के साधन के रूप में ही नहीं लेना है बल्कि गाँवों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में भी लेना है। कृषि विकास नियोजन के लिए भूमि—सुधार कृषि—यन्त्रीकरण पशुधन एवं डेयरी विकास दलहन एवं तिलहन विकास औद्योगिक फसलों का विकास मिश्रित खेती शुष्क भूमि कृषि खरपतवार नियन्त्रण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि रसायनों एवं उर्वरकों के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने बचत को प्रोत्साहन देने तथा महाजनी ऋण जाल से मुक्ति प्रदान करने के लिए बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है। क्षेत्र की कृषीय समस्याओं एवं उनका विकास नियोजन निम्नवत प्रस्तावित है—

(1) भूमि/मृदा एवं सिंचाई सम्बन्धित

भूमि ससाधन विकास का मूलधार है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसको केवल अक्षुण्ण रूप में ही नहीं बल्कि सुधरे हुए रूप में आगामी पीढ़ियों को सौंपें। इसके लिए कृषि विकास की प्रक्रिया में भूमि ससाधन की वहन क्षमता तथा इसके सामर्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओं की ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। भूमि तथा जल—चक्रों के बीच ताल—मेल बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की, उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढ़ाने उत्पादकता पुन प्राप्त करने, भूमि का सुधार करने और कम उपजाऊ भूमि का विकास करने व ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है। भूमि ससाधन के अनुकूलतम उपयोग तथा सामाजिक—आर्थिक उद्देश्यों के संरक्षण आवश्यकताओं को लेकर कृषि तथा इसके अन्य आनुषंगिक माध्यमों से अध्ययन क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि लायी जा सकती है।

(क) उसर भूमि की समस्या

अध्ययन क्षेत्र में 3,692 हे भूमि उसर एवं कृषि के अयोग्य है। अतः उसर सुधार द्वारा कृषि क्षेत्र में 1.46 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। उसर सुधार हेतु क्षेत्र के लिए सस्तुत जिप्सम (25 प्रतिशत जीआर + एफवाईएम 10 टन/हे) की आधी मात्रा तथा 10 टन प्रति हे गोबर की खाद अथवा 10 टन प्रेसमड (सल्फाटेशन प्लान्ट) अथवा 10 टन प्लाईऐश प्रति हेक्टेयर की

दर से किया जाय। यदि गोबर की खाद प्रेसमड तथा फलाईऐश उपलब्ध न हो तो जिप्सम की सस्तुत पुरी मात्रा का प्रयोग किया जाय। इसके बाद प्रथम फसल धान की ली जाय। धान क्षारीयता के प्रति सहनशील है अतः दो तीन वर्षों तक खरीफ में धान की अनवरत फसल ही ली जाय क्योंकि यह जैविक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रकार का जैविक अम्ल उत्पन्न करता है साथ ही भूमि में सोडियम तत्व का अवशोषण अधिक मात्रा में होने से भूमि में विनिमयशील सोडियम की मात्रा कम हो जाती है और भूमि की भौतिक तथा रासायनिक गुणवत्ता में धीरे-धीरे सुधार हो जाता है। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र के लिए धान-गेहूँ-हरी खाद का फसल चक्र सस्तुत किया गया है।

(ख) सिचाई समस्या

जनपद का कुल सिंचित क्षेत्रफल वर्तमान में 158937 हे है। वर्तमान सिचाई क्षेत्र का 80 प्रतिशत क्षेत्र केवल नलकूपों द्वारा सींचा जाता है जो विद्युत आपूर्ति पर निर्भर है। इसके अलावे सिचाई साधनों के अभाव में अभी-भी 2359 हे भूमि बजर भूमि के रूप में पड़ी हुयी है। अतः बन्द नलकूपों को ठीक कर तथा विद्युत आपूर्ति को नियमित कर सिचाई क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। रबी के फसलों के उत्पादन में सिचाई का विशेष महत्व है। अतः समय से सभी नलकूप चलाए जाय साथ ही नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया जाय।

(ग) बाढ़ की समस्या

अध्ययन क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इसमें जनपद का रुद्रपुर तहसील का अधिकांश भाग नदियों से आच्छादित रहने के कारण साथ ही राप्ती एवं घाघरा नदी के बीच पतला कच्चा क्षेत्र है। यह प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है जिससे प्रत्येक वर्ष कृषि एवं पशुओं की क्षति के साथ-साथ जनजीवन को गम्भीर खतरा बना रहता है। इस जनपद में छोटी गण्डक राप्ती गोर्रा घाघरा नदियों के अलावा मझना नाला नकटा नाला तथा कुर्ना एवं खनुआ, बथुआ नाला जो प्रायः वर्षा के दिनों में नदी का रूप ले लेते हैं इनसे भी काफी क्षति होती है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु बाढ़ खण्ड विभाग देवरिया उत्तरदायी है। जिसके द्वारा रुद्रपुर एवं सलेमपुर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली राप्ती, गोर्रा, घाघरा नदियों से बचाव कार्य किया जाता है। बाढ़ सुरक्षा हेतु गण्डक नहर-3 एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु 34 बन्धों का निर्माण किया गया है परन्तु इससे बाढ़ की आवृत्ति में कोई उल्लेखनीय सुधार अभी तक नहीं हुआ है। अतः आवश्यकता है बाँधों की मरम्मत तथा पक्के बाँध निर्मित किए जाय।

(घ) मृदा-उर्वरक साहचर्य एवं मृदा परीक्षण

मृदा ही कृषि का मूलाधार है, जिसमें प्रत्येक फसल के लिए पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

इन पोषक तत्वों में मृदा की प्रकृति और प्रकार के अनुसार स्थानिक भिन्नता पायी जाती है। साथ ही प्रत्येक फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता में भी फसली स्तर पर भिन्नता होती है। मृदा में पोषक तत्वों की इस कमी को कृत्रिम रूप से उर्वरकों के सहारे पूरा किया जाता है। अतः यदि किसान को अपने भूमि के पोषक तत्वों का ज्ञान नहीं है तथा तत्त्व विशेष का फसल के लिए आवश्यकता का बोध नहीं है तो कृत्रिम रूप से डाले गये उर्वरक का फसल एवं उत्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा और वह लागत ही बढ़ायेगा। इस प्रकार मृदा-उर्वरक के साहचर्य का ज्ञान किसान को होना चाहिए तथा उनकी भूमि में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटैश की कितनी मात्रा है उसी के अनुसार उर्वरक प्रयोग करें। इसके लिए मृदा परीक्षण अनिवार्य है। वर्तमान समय में मात्र देवरिया मुख्यालय पर ही परीक्षण केन्द्र मौजूद है। इसे प्रत्येक प्रखण्ड पर स्थापित कर किसानों को इसके प्रति जागरूक बनाया जाय।

(ड) मृदा-क्षरण एवं संरक्षण

जनपद की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भू-भाग प्रतिवर्ष बाढ़ सिंचाई अतिरेक एवं मृदा अपरदन से ग्रस्त होता है। जिसका कृषि-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः मृदा संरक्षण हेतु 1993-94 से 'राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम' की शुरुआत हुयी। यह योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है जिसमें केन्द्र एवं राज्य भार अनुपात 3:1 है। योजना के अन्तर्गत एकीकृत जलागम पबन्धन के आधार पर कृषि-भूमि संरक्षण उद्यान पशुपालन वानिकी आदि कार्य समेकित रूप से सम्पादित किये जाते हैं। यह कार्यक्रम वर्तमान में बैतालपुर एवं गौरी बाजार विकासखण्डों तक ही सीमित है। इसका विस्तार सभी विकासखण्डों तक होना चाहिए।

(2) उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयोग सम्बन्धित

हरितक्रांति के प्रमुख आधारों में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कृषि क्षेत्र में प्रयोग शामिल है। परन्तु वर्तमान में इसका उपयोग बिना समुचित ज्ञान के धड़ले से हो रहा है। किस मृदा एवं फसल के लिए कौन सा उर्वरक दिया जाय तथा कितनी मात्रा में दिया जाय साथ ही कीटनाशकों के प्रयोग की समय और विधि कौन सी उपयुक्त है? इसके ज्ञान के अभाव में ये सारे कार्य न सिर्फ लागत बढ़ा रहे हैं। वरन् ये प्राकृतिक पर्यावरण को भी विभिन्न रूपों में क्षति पहुँचा रहे हैं। अनियमित और अनियंत्रित रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। वर्तमान समय में आवश्यकता है न्यूनतम लागत में मृदा उर्वरता गुणों को अक्षुण्ण रखते हुए उत्पादकता वृद्धि की।

(क) उर्वरकों की पहचान

खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगी सामग्री रासायनिक उर्वरक है। उर्वरकों के शीर्ष उपयोग की अवधि हेतु खरीफ एवं रबी के पूर्व उर्वरक विनिर्माता फैक्ट्रियो

तथा विक्रेताओं द्वारा नकली एव मिलावटी उर्वरक बनाने एव बाजार में उतारने की कोशिश होती है। इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन और किसानों पर पड़ता है। नकली एव मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए यद्यपि सरकार प्रतिबद्ध है फिर भी यह आवश्यक है कि किसान अपने स्तर पर भी उर्वरकों की शुद्धता को परखें। इसकी शुद्धता की जाँच हेतु *कृषक सेवाकेन्द्रों पर टेस्टिंग किट* उपलब्ध है। परन्तु जनपद में मात्र 16 ही कृषक सेवाकेन्द्र हैं। अभी भी बैतालपुर देसही देवरिया पथरदेवा रुद्रपुर बरहज भटनी भाटपाररानी एव भागलपुर विकासखण्डों में कोई कृषि सेवाकेन्द्र नहीं है। अतः सभी विकास खण्ड मुख्यालयों पर इसकी सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

(ख) सस्तुत उर्वरक उपयोग

उत्पादन एव उत्पादकता की दृष्टि से सतुलित उर्वरकों के प्रयोग का विशेष महत्व है। नवीनतम अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों के अनुसार *नाइट्रोजन फास्फोरस एव पोटाश* का अनुपात 4 3 1 होना चाहिए। जबकि जनपद में ये अनुपात 22 5 1 में हैं। अतः आवश्यकता है कि सस्तुत भाग में उर्वरकों के प्रयोग हेतु फास्फोरस एव पोटाश के प्रयोग पर बल दिया जाय। दलहनी एव तिलहनी फसलों में फास्फेट एव पोटाश के प्रयोग पर अवश्य ही बल दिया जाय।

(ग) जैव उर्वरक, हरित खाद एव कम्पोस्ट प्रयोग

हमारा उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा उत्पादन वृद्धि प्राप्त करना है। परन्तु यह वृद्धि *मृदा उर्वरता पर्यावरण एव परिस्थितिकी* की कीमत पर नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे अक्षुण्ण रखते हुए होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कृषिक्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर *जैव उर्वरक हरीखाद एव गोबर की खाद* के प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए *मुख्यतः 16 तत्वों* की आवश्यकता होती है जिनमें *नाइट्रोजन फास्फोरस एव पोटाश* अति आवश्यक तथा प्रमुख पोषक तत्व हैं। ये पौधों में चार प्रकार से उपलब्ध होती हैं—

- 1 रासायनिक खाद द्वारा
- 2 गोबर की खाद/कम्पोस्ट द्वारा
- 3 नाइट्रोजन स्थिरीकरण एव फास्फोरस घुलनशील जीवाणु द्वारा एव
- 4 हरी खाद द्वारा

जैव उर्वरक

भूमि मात्र एक भौतिक माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक *जीवित क्रियाशील तन्त्र* है। इसमें

सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया फफूँदी शैवाल प्रोटोजोआ आदि पाये जाते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव वायुमण्डल में स्वतंत्र रूप से पायी जाने वाली 78 प्रतिशत नाइट्रोजन जिन्हे पौधे सीधे उपयोग करने में अक्षम होते हैं को *अमोनिया* एवं *नाइट्रेट* तथा फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जैव उर्वरक इन्ही सूक्ष्म जीवों का पीट लिग्नाइट या कोयले के चूर्ण में मिश्रण है जो पौधों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरक पौधों के लिए वृद्धि कारक पदार्थ भी देते हैं पादप रोगों की रोकथाम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हैं। ये भूमि जल एवं वायु को प्रदूषित किये बिना उत्पादन स्तर में स्थायित्व लाते हैं। इन्हें *जैव कल्चर जीवाणु खाद इनाकुलेन्ट* आदि कहते हैं।

जैव उर्वरक निम्न प्रकार के उपलब्ध हैं—

(1) राइजोबियम कल्चर (2) एजेटोबेक्टर कल्चर (3) एजोस्पाइरिलम कल्चर (4) नील हरित शैवाल (वी जी ए) (5) फास्फेटिका कल्चर (6) एजोला फर्न (7) माइकोराइजा।

गोबर की खाद/कम्पोस्ट

अध्ययन क्षेत्र पशु ससाधन की दृष्टि से सम्पन्न है। परन्तु पशुओं के गोबर का अधिकांश ईंधन पूर्ति में जला दिया जाता है। अतः ईंधन के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कर गोबर से खाद बनाना ज्यादा लाभकर होगा, साथ ही कूड़ा-कचड़ा को गढों में सड़ा-गलाकर कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण धान के पुआल गोहूँ के भूसे गन्ना खोई आदि के रूप में कम्पोस्ट निर्माण हेतु पर्याप्त सामग्री सम्पन्न है। इन खादों में कृषि के प्रमुख पोषक तत्वों के साथ-साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी एक निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। अतः यह कृषि की दृष्टि से फायदेमन्द है।

हरीखाद

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरे पौधों को अथवा उनके किसी भाग को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है, इससे हरी खाद बनती है। यह दो प्रकार से तैयार की जाती है—

(क) खेत में हरी खाद उगाकर पलटना

(ख) अन्यत्र उगाये गये पेड़ पौधों की हरी पत्तियाँ तथा मुलायम शाखाएँ काटकर उन्हें खेत में डालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है।

हरीखाद के लिए प्रयुक्त होने वाली फसले निम्न सारणी (5 20) में प्रस्तुत हैं।

सारणी- 5 20
हरी खाद विवरण

क्रम संख्या	फसल	बीज की मात्रा (किग्रा / हे)	पलटाई का समय	प्रति हे० सस्थापित (नाइट्रोजन (किग्रा)
1	सनई	90—100	42 दिन पर	82
2	ढैचा	25—30	42 दिन पर	76
3	मूँग	20—25	फली तोड़ने के बाद 65 दिन पर	38
4	उडद	25—30	85—90 दिन पर फली तोड़ने के बाद	42
5	लोबिया	35—40	60 दिन पर	55

स्रोत-विकास के बढ़ते कदम देवरिया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग-2002 पृ०- 50

हरी खाद के लाभ

- 1 भूमि को जीवाश्म पदार्थ मिलता है।
- 2 भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशा सुधरती है।
- 3 हरी खाद से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।
- 4 दलहनी वर्ग के हरी खाद के पौधों की जड़ों में पायी जाने वाली राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण से भूमि में नाइट्रोजन इकट्ठा करती हैं।

(घ) एकीकृत नाशीजीव प्रबन्ध (इटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट)

प्रदेश में कृषि के प्रति वांछित आकर्षण पैदा करने एवं उसको कम खर्चीला और अधिक लाभकारी बनाने के लिए जिन उपायों पर गौर किया जा रहा है उनमें प्रमाणित एवं उपचारित बीजों की उपलब्धि, उर्वरकों का सतुलित उपयोग, अच्छा जल प्रबन्धन एवं 'इटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट' मुख्य हैं।

कृषि में कीटों, रोगों, चूहों एवं खरपतवारों से फसलों की उपज प्रभावित होती है। अभी तक इनके समाधान हेतु केवल रसायनों का ही सहारा लिया जाता रहा है जो खर्चीला होने के साथ-साथ पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारक हैं। इनसे कई प्रकार की दुर्घटनाएँ घटती हैं तथा इनका दुष्प्रभाव खाद्य-शृंखला के माध्यम से मानव सहित सम्पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। इनके निरंतर प्रयोग से कई कीटों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है जो एक नई समस्या खड़ा कर रहे हैं। अतः उक्त समस्याओं के प्रभावी निदान एवं उपर्युक्त खतरों से बचने के लिए अब जिस पद्धति पर जोर दिया जा रहा है उसे 'इटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट' या एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन कहा जाता है। इस पद्धति में कीटों, रोगों और खरपतवारों आदि के उन्मूलन के बजाय उनके प्रबन्धन की बात की जाती है। इसके अंतर्गत- समुचित फसल चक्र अपनाना, फसल के

प्रतिरोधी प्रजातियों को बोना शोधित बीज ही बोना समय से बुआई एवं पौधों के बीच वाछित दूरी रखना सतुलित उर्वरक प्रयोग समुचित जल प्रबन्ध निराई—गुड़ाई कीड़ों के अण्डों इल्लियों को नष्ट करना तथा मित्र कीटों को बाहर से लाकर खेतों में छोड़ना आदि सम्मिलित हैं।

(3) कृषि प्रविधि प्रशिक्षण एवं ज्ञान से सबधित

कृषि प्रविधि का कृषि लागत और उत्पादकता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। नवीन तकनीक और वैज्ञानिक प्रविधि न सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि करती है बल्कि ये भूमि की गुणवत्ता में भी ह्रास नहीं आने देती है। इस प्रविधि का किसानों तक प्रसार विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों एवं अनुभवों से होता है। अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान है पर यहाँ कृषि प्रशिक्षण संस्थानों का नितान्त अभाव है जो कम से कम सभी प्रखण्ड मुख्यालयों पर अवश्य स्थापित होने चाहिए। उपयुक्त ज्ञान के अभाव में किसान असतुलित कृषि करते हैं जो लागत बढ़ाने के साथ पर्यावरण की भी क्षति करती है। इसके लिए निम्न उपाय प्रस्तावित हैं—

(i) बीज शोधन

फसलों को रोग से बचाने हेतु बीज शोधन अति आवश्यक है। ये उन बीजों के लिए आवश्यक है जो किसान घर का बीज बोते हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर संयुक्त रसायन थीरम कैप्टान एग्रोसेन जी एन आदि की आवश्यकता का परीक्षण विकास खण्डवार कराया जाय तथा आवश्यक रसायन की समय से उपलब्धता भी सुनिश्चित कर किसानों को प्रेरित कर बीज शोधित कराकर ही बुआई कराई जाय।

(ii) वैज्ञानिक कृषि, फसलचक्र

कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु वैज्ञानिक कृषि द्वारा तकनीक हस्तान्तरण कार्यक्रम 1995—96 से जनपद में चलाया जा रहा है। प्रत्येक तहसील के एक ग्राम का चयन कर कृषि की दृष्टि से उसे विकसित किया जा रहा है। उक्त ग्राम में मृदा परीक्षण के आधार पर सतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग एवं सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसे प्रखण्ड स्तर पर किया जाय।

अध्ययन क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा की उर्वरता बनाये रखने के लिए सही फसल चक्र का ज्ञान कृषकों के लिए लाभदायक होता है परन्तु निरक्षरता, आर्थिक विपन्नता सिचाई एवं परिवहन की असुविधा तथा परम्परागत कृषि पद्धति के कारण आज भी अध्ययन क्षेत्र के कृषक खाद्यान्न प्रधान पारम्परिक फसल चक्र को ही अपना रहे हैं। यद्यपि हाल के वर्षों में फसल चक्र में कुछ नवीनता आयी है, परन्तु उसमें अभी—भी शस्य सतुलन एवं कृषि—पद्धति की वैज्ञानिकता में अभाव मिलता है। अध्ययन क्षेत्र की भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित फसल चक्र सस्तुत किया जा सकता है—

1	धान-गेहूँ	एक वर्षीय
2	मक्का-आलू-सूरज मुखी	एक वर्षीय
3	मक्का-तोरिया-गेहूँ	एक वर्षीय
4	धान-गेहूँ-गन्ना	दो वर्षीय
5	धान-मक्का (रबी) उडद / मूँग	एक वर्षीय
6	धान-मटर	एक वर्षीय
7	धान-जौ	एक वर्षीय
8	मक्का-राई	एक वर्षीय
9	मक्का-आलू	एक वर्षीय
10	धान-गेहूँ-हरीखाद (ढैचा / सनई)	एक वर्षीय
11	धान-गेहूँ-उडद / मूँग	एक वर्षीय

(iii) पारम्परिक अनुभवों उक्तियों का उपयोग

प्राचीन काल से कुछ ऐसी उक्तियाँ लोक प्रचलन में रही हैं जिनके आधार पर किसान मौसम की सूचना पाते थे और कृषि करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मौलिकता तथा सत्य के करीब होने के कारण ये प्रासंगिक बनी हुयी हैं। अतः उन उक्तियों का कृषि कार्य में उपयोग अपेक्षित है। उदाहरण स्वरूप कृषि पंडित 'घाघ' की उक्ति बहुत ही वैज्ञानिक लगती है—

- (i) दिन में गर्मी रात में ओस। कहे घाघ वर्षा सौ कोस।
- (ii) नीचे ओद ऊपर बदराई कहे घाघ तब गेरुई आई।
- (iii) गोबर मैला नीम की खली। इससे खेती दूनी फली।
- (iv) जेकरे खेत परै ना गोबर। उहि किसान को जानो दूबर।
- (v) धान गिरै सुभागे का। जौ गेहूँ गिरै अभागे का।
- (vi) चित्रा गेहूँ आद्रा धान न ओ के गेरुई न ओके घाम।
- (vii) गेरुई-गेहूँ गधी-धान । बिना अन्न के मरे किसान।
- (viii) पूसै-माघ बहे पुरवाई तब सरसो को माहो खाई।

(iv) कृषि-पशु साहचर्य विकास

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय कृषि में प्रारम्भ से ही पशुश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि कृषि यंत्रीकरण की अभिनव प्रवृत्ति के बावजूद पशुधन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब कभी इनकी संख्या में ह्रास हुआ है कृषिगत अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अध्ययन क्षेत्र यद्यपि पशुधन सम्पन्न है पर इसमें निरन्तर ह्रास हो रहा है। अतः क्षेत्र में किसानों को कृषि-पशु साहचर्य के लाभ को बताने की आवश्यकता

हैं क्योंकि पशुओं से दूध मॉस चमड़े अण्डे आदि सुलभ होते हैं। साथ ही पशुओं से प्राप्त होने वाली खाद खेत के लिए काफी लाभकारी होती है। गोबर से किसान कम्पोस्ट खाद तैयार कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं।

(4) कृषि-वित्त एवं सुरक्षा संबंधित

अध्ययन क्षेत्र पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला कृषिक्षेत्र है। सिंचाई उर्वरक डीजल बिजली आदि के निरन्तर महंगे होते जाने से कृषि लागत बढ़ती जा रही है। पूँजी के अभाव में किसान नयी तकनीक को नहीं अपना पा रहे हैं। लागत प्रधान इस कृषि में किसानों को फसल की क्षति होने पर भारी क्षति होती है। अतः फसल सुरक्षा तथा कृषि कार्य के लिए पूँजी उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही नवीन कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए तरह-तरह से किसानों को सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसमें सरकार द्वारा कुछ प्रयास हो रहे हैं पर वह पर्याप्त नहीं हैं।

(i) किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को समय से पर्याप्त वित्तीय सुविधा पहुँचाने के लिए *क्रेडिट कार्ड योजना* 1997 से सारे देश में प्रारम्भ की गयी। इस योजना में किसानों को समस्त कृषि एवं पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु 5000 रुपये या उससे अधिक के ऋण बैंकों से उपलब्ध कराये जाते हैं।

जनपद में ये कार्ड सरकारी बैंकों एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से बनाये जा रहे हैं। ये एक सराहनीय प्रयास है। इसे और तीव्र और व्यापक करने तथा इसमें छोटे-बड़े सभी किसानों को समाहित करने से इसकी उपादेयता और बढ़ जायेगी।

(ii) बीमा योजनाएँ

किसानों को फसल क्षति से राहत प्रदान करने के लिए जनपद में *खलिहान दुर्घटना बीमा योजना* तथा कृषि विभाग की *राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना* चलाई जा रही है। यद्यपि इन योजनाओं के आकर्षक लाभ हैं परन्तु दुर्भाग्य से इसका लाभ बहुत ही थोड़े किसानों को मिल पाता है। इसका प्रमुख कारण है लोगों में इसकी जानकारी का अभाव और बीमा के भुगतान के समय अनावश्यक देरी। अतः बीच के इन व्यवधानों को दूर करने तथा इसके अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को समाहित करने का प्रयास होना चाहिए।

(iii) किसान मित्र योजना

किसानों को कृषि सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन्नतशील बीज के लिए अनुदान देने के लिए जनपद में *किसान मित्र योजना* चलाई जा रही है। जिसमें दो मदे हैं—

1— *कृषक मित्र प्रशिक्षण* और 2— *उन्नतशील बीज व्यवस्था*। इसमें कृषक मित्र प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका प्रसार समूचे जनपद में तथा सभी किसानों तक होना चाहिए। इसके माध्यम से कृषि सम्बन्धित सभी जानकारीयों (नवीन तकनीक, सतुलित उर्वरक

उपयोग जैव उर्वरक के लाभ समन्वित कीट प्रबन्धन) से किसानों को अवगत कराने का उद्देश्य होना चाहिए। उन्नतशील बीज व्यवस्था में 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर धान गेहूँ के बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है पर अभी भी इसका लाभ मात्र कुछ कृषकों तक ही सीमित है। इसका प्रसार होना चाहिए।

(ब) औद्योगिक समस्याएँ, संभावनाएँ एवं विकास नियोजन

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान है। इसलिए यहाँ जो थोड़ा बहुत औद्योगिकरण हुआ वे सभी कृषि पर ही आधारित हैं। परन्तु ये उद्योग भी कई समस्याओं का शिकार हो गये और सकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। प्राचीन समय में यहाँ गन्ना पर आधारित खाडसारी उद्योग संपन्न अवस्था में था। बाद में चीनी मिलों की स्थापना ने इन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और आज यहाँ चीनी उद्योग भी सकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग ही है जिसकी पाँच मिलें हैं परन्तु इसमें से मात्र तीन मिलें ही चल रही हैं। गन्ना किसानों का बकाया सभी मिलों पर है और ये मिलें गन्ना के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही हैं।

परन्तु अभी भी इस क्षेत्र में औद्योगिक दृष्टि से पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। यदि इनका सुनियोजित रणनीति के द्वारा विकास किया जाय तो यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न हो सकता है। कृषि सम्पन्न क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि उपजों को संशोधित करने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की भी पर्याप्त संभावना है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि संसाधनों को देखते हुए यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं। परन्तु क्षेत्र में वित्तीय अनुपलब्धता की समस्या है। अतः समुचित वित्त प्रबन्धन द्वारा औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(1) कृषि आधारित उद्योग

जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ मुख्य मुद्रादायिनी फसल गन्ना है। धान गेहूँ की अच्छी फसल होती है। अतः जनपद में गन्ने की खेई, धान का पुआल गेहूँ के भूसा पर आधारित उद्योग विकसित हो सकते हैं। खाडसारी उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं।

(2) फलाधारित उद्योग

जनपद में केला आम पपीता जामुन अमरुद के फल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। देवरिया तथा सलेमपुर में फल संरक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन पर आधारित फलों से जूस निकालने के उद्योग तथा अचार बनाने के उद्योग विकसित हो सकते हैं।

(3) पशुधन आधारित उद्योग

पशुधन में जनपद धनी है। ग्रामीण जनता पशुपालन करती है। पशुओं से प्राप्त दूध पर आधारित मिठाई उद्योग विकसित किया जा सकता है। भेड़-बकरी के बालों पर आधारित वस्तु

उद्योगों का विकास हो सकता है। जनपद में दूध एकीकरण केन्द्र का अभाव है अतः प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालयों पर इसकी स्थापना कर प्रत्येक सेवाकेन्द्र पर दूध वितरण कार्य किया जा सकता है। पशुओं के मृत्यु के बाद हड्डी व चमड़े पर आधारित उद्योग के विकास की भी पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

(4) पर्यटन उद्योग

जनपद प्राचीन काल से ही एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र रहा है। धार्मिक केन्द्र आज भी जनपद में पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं। इन केन्द्रों पर अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास कर जनपद पर्यटन उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल हैं— खुखुन्दु, सोहनाग लार बरहज, दीर्घेश्वरनाथ दुग्धेश्वरनाथ आदि। इनमें से मात्र दीर्घेश्वरनाथ को ही उत्तर-प्रदेश सरकार ने पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित किया है। अतः बाकी सभी स्थलों को पर्यटन के रूप में घोषित कर यहाँ पर्यटन उद्योग को विकसित किया जा सकता है।



References

- 1 सिंह बी एन 'कृषि भूगोल' (2000) प्रयाग पुस्तक भवन पृ-1
- 2 वही पृष्ठ- 1-2
- 3 वही पृष्ठ- 35
- 4 Fox, K and Tanber, R, 'Spatial Equilibrium Models of the Livestock feed Economy', *American Economic Review*, as, 1955 pp 801-802
- 5 Chandan, D S , 'Studies in Utilization of Agriculture Land', 1966, p 171
- 6 Venzetti, C , 'Land use and Natural Vegetation in International Geography', edited by W Peter Adams and Frederick, M Helleiener, Toronto University, 1972, pp 1105-1106
- 7 Wood, H,A , 'A Classification of Agricultural Land use for Development planning', *International Geogr* (22, I G U, Canada), Univ of Toronto Press 1972, p 1106
- 8 मिश्र एस के—पुरी वी के, 'भारतीय अर्थव्यवस्था' (2000) हिमालय पब्लिशिंग हाऊस— पृष्ठ— 315
- 9 रबी उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2000—2001 कृषि विभाग देवरिया पृष्ठ—4
- 10 सिंह ब्रज भूषण 'कृषि भूगोल' ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988 पृष्ठ 165
- 11 Stamp, L D, 'Our Developing world', Faber & Faber, London, 1968, pp 105-125

- 12 Shafi, M 'Perspective on the Measurement of Agricultural Productivity' *The Geographer*, 1974 Vol 30, No -1 pp 15-23
- 13 Tandon, R K and Dhondyal, S P 'Principles and Methods of Farm Management, 1967 p 60
- 14 Uttar Pradesh District Gazetteers Deoria, 1988 p 87
- 15 Hussain M 'Crop Combination in India', 1982, p 61
- 16 Dayal, E , 'Crop Combination Region A study of the Punjab plain' *Tej dschrift voor Economical social Geography* 1967, Vol 58 p 39
- 17 Ahmad, A and Sidhiqui M F 'Crop Associations Pattern in the Luni Basin', *The Geographer*- 1967, Vol XIV, p 68
- 18 Johnson, B L C 'Crop Combination Region in East Pakistan', *Geography* 43, 1958, pp 86-103
- 19 Thomas, D , 'Agriculture in works during the Neopleanic war' *Cradiff* 1963 pp- 80-81
- 20 Weaver, J C , 'Crop Combination Regions in the Middle west', *Geographical Review*, 44 1954, p 175
- 21 Ayyar, N P , 'Crop Regions of Madhya Pradesh A Study in Methodology', *Geographical Review of India*, 31 1 1969, pp 1-19
- 22 Doi, K , 'The Industrial Structure of Japanese prefecture', *Proceedings of I G U Regional conference in Japan*, 1957-59, pp 310-316
- 23 भारत प्रकाशन विभाग नई दिल्ली 2000-01 पृष्ठ 388
- 24 सिंह काशीनाथ एव सिंह जगदीश आर्थिक भूगोल के मूल तत्व वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर (1984) पृ-296
- 25 कौशिक एस डी आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धांत रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ 1980-81 पृष्ठ-188
- 26 Richards, T , 'The Geography of Economic Activity', *Mc Graw Hill Book Co, Inc* 1962, P 456
- 27 Miller, E Willard, 'A Geography of Manufacturing', *prentice Hall, Inc Englewood Cliffs, N J* 1962 p 1
- 28 Alexander, J W , 'Economic Geography', p 288
- 29 Jarret, N R., 'A Geography of Manufacturing' (Second edition), *Macdonald and Erans Estover Plymouth*, 1977, p 7
- 30 'उत्तर प्रदेश वार्षिकी' सूचना एव जनसंपर्क विभाग उत्तर-प्रदेश 2000-01 पृष्ठ-109
- 31 कुरैशी एम एच, भुगोल के सिद्धान्त भाग-2 एन सी ई आर टी नई दिल्ली 1989 पृ 78-79
- 32 सिंह इकबाल 'भारत में ग्रामीण विकास' एन सी ई आर टी नई दिल्ली 1986 पृ 75





अध्याय-छः

सेवाकेन्द्र परिवहन-संचार एवं विकास

(क) परिवहन व्यवस्था

6.1 सेवाकेन्द्र-परिवहन सम्बद्धता एवं विकास

परिवहन तत्र आर्थिक विकास की रीढ़ है। सेवाकेन्द्रों पर क्षेत्रीय जनसंख्या को विभिन्न प्रकार के कार्य एवं सेवाएँ प्रदान करने वाली इकाइयों केन्द्रीभूत रहती हैं। इनसे सेवाओं एवं कार्यों का संचरण परिवहन मार्गों के सहारे ही चतुर्दिक क्षेत्र में संचरित हो पाती है। सेवाक्षेत्र से सेवाकेन्द्र के मध्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान परिवहन साधनों की सुलभता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का उद्भव विकास एवं अस्तित्व परिवहनीय सम्बद्धता पर ही निर्भर करता है। परिवहनीय दृष्टि से जिस सेवाकेन्द्र की सम्बद्धता जितनी ही अच्छी होती है उसका सेवाक्षेत्र तथा पदानुक्रम उतना ही ऊँचा होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवहन तत्र वह मार्ग जाल है जिससे होकर विकास प्रवाहित होता है।

देश में लगभग 6 लाख गाँव हैं। इनके विकास के लिए इनकी अच्छी परिवहन प्रणाली से सम्बद्धता आवश्यक है परन्तु अभी तक देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की लम्बाई पाँच लाख किलोमीटर ही है। जो गाँव सड़कों से जुड़े हैं उनकी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियाँ इन्हीं सड़कों के सहारे चलती हैं। आज शहरी और 'ग्रामीण भारत' के बीच भारी अंतर का प्रमुख कारण सड़कों की सम्बद्धता ही है। प्रगति की राह में शहर के साथ गाँव साथ-साथ कदम इसीलिए नहीं उठा सके, क्योंकि वे शहरों की भोंति सड़कों से सम्बद्ध नहीं थे। यही कारण है कि व्यापार रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे राज्य काफी पिछड़े हुए हैं जहाँ ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के कम हैं। कहना न होगा कि इसमें उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, झारखण्ड, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमबंगाल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं।¹ परिवहन स्वयं उत्पादन प्रक्रिया का एक चरण है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देश भर में फैले हुए उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है जो कि परिवहन के साधनों से ही सम्भव है।² विकसित परिवहन व्यवस्था से कृषि विकास और औद्योगिकरण में भी सहायता मिलती है। प्रायः परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास होने पर देश के सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे आर्थिक वातावरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।³ इस प्रकार किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए एकीकृत परिवहन तन्त्र की आवश्यकता होती है। परिवहन एवं संचार माध्यमों से 'क्षेत्रीय विशिष्टीकरण' का लाभ पिछड़े क्षेत्रों को भी मिल जाता है। इस प्रकार परिवहन जाल,

पिछडे क्षेत्रो मे भी ससाधनो के उपयोग को बल देकर वृद्धि एव विकास की स्थिति उत्पन्न करेगा।¹⁴ आर्थिक विलगन राजनैतिक विखण्डन और सामाजिक दूरियो को एकीकृत एव समन्वित परिवहन—संचार माध्यमो से खत्म किया जा सकता है। उपभोग एव उत्पादन बिन्दुओ मे सयोजन गाँव एव शहर से सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्राकृतिक आपदा के समय ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं। परिवहन तन्त्र न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है वरन् स्थानीय बाजारो को राष्ट्रीय बाजार से और राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोडता है।¹⁵ सडके ग्रामीण क्षेत्र मे हो या शहरी क्षेत्र मे उन पर विकास का सारा दारोमदार रहता है। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विश्व स्तर पर आर्थिक विकास एव परिवहन साधनो के विकास मे समानता मिलती है।¹⁶ यही कारण है कि बुनियादी ढाँचे मे सुधार के लिए सडको पर अब विकासशील देश जोर देने लगे हैं। विकसित देशो मे 'एक्सप्रेस हाइवे' ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी 'एक्सप्रेस वे' दिया है। इसे हमने देर से स्वीकार किया लेकिन उसमे अब अपेक्षित गति व प्रगति दिखाई देने लगी है। यद्यपि उसकी गति धीमी ही है क्योकि ठेकेदार सरकारी अधिकारी व स्थानीय राजनीति के त्रिकोण मे अपेक्षित लक्ष्य पाना कठिन होता जा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र देवरिया जनपद विकास की दृष्टि से पिछडा क्षेत्र है किन्तु विकास के लिए उत्तरदायी ससाधनो की प्रचुरता है। अन्य स्थितियो के अलावे विकास के मुख्य प्रेरक तथा ससाधनो के प्रमुख सयोजक तत्व परिवहन एव संचार का अपेक्षाकृत अभाव है। प्राय अध्ययन क्षेत्र के जिन भागो मे सडको एव रेलमार्गो का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है वे आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं अध्ययन क्षेत्र मे जल परिवहन की पर्याप्त सभावना है विशेषकर मध्यवर्ती क्षेत्र मे छोटी गण्डक नदी के माध्यम से तथा दक्षिणी भागो मे राप्ती एव घाघरा नदियो के माध्यम से। प्राचीन काल मे क्षेत्र मे व्यापार का प्रमुख माध्यम जल—परिवहन मार्ग ही था। बरहज प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। वायु परिवहन के माध्यम नहीं हैं। रेलमार्ग कुछ विकसित है पर लाइन इकहरी है। समतल मैदान होने के कारण विकसित—अविकसित सडके ही परिवहन के मुख्य साधन हैं।

6.2 परिवहन माध्यम—प्रतिरूप

'माध्यम' का अर्थ 'मार्ग' जैसे सडक, रेल समुद्र नदी, वायु मार्ग माना गया है, जबकि साधन का प्रयोग यातायात हेतु प्रयुक्त विविध वाहनो यथा— बस ट्रक कार रेलगाडी नाव जलयान, ट्रैक्टर आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक युग मे तीनो मण्डलो (स्थल जल एव वायुमण्डल) का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है। स्थल मण्डल मे रेलमार्ग सडकमार्ग रज्जुमार्ग तथा भूमिगत नलिकाएँ (टनेल पाइप लाइन्स) परिवहन के माध्यम हैं। जल मण्डल मे समुद्र के साथ नौगम्य नदियो तथा नहरो का प्रयोग परिवहन माध्यम के रूप मे होता है तो वायुमण्डल मात्र वायुयान परिवहन तक ही सीमित है। स्थानीय यातायात के लिए इन माध्यमो में रेलमार्ग एव

सड़को का विशेष महत्व है। इनके द्वारा ही क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं को पहुँचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है।¹⁷ जनपद देवरिया में परिवहन माध्यमों का विवरण इस प्रकार है—

(अ) जल परिवहन

जल परिवहन एक सस्ता परिवहन माध्यम है जो भारी सामान ढोने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।¹⁸ समतल क्षेत्र तथा जनपद के मध्य में बहने वाली छोटी गण्डक नदी तथा दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली राप्ती एवं घाघरा नदियों में जल परिवहन की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। इन मार्गों का उपयोग छोटी दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है। प्राचीनकाल में व्यापार का प्रमुख माध्यम ये जलमार्ग ही थे। दक्षिणी भाग में स्थित सेवाकेन्द्र क्रमशः बरहज एवं भागलपुर के विकास में इन मार्गों की विशेष भूमिका है। ये ही प्राचीन काल के प्रमुख व्यापारिक स्थल थे क्योंकि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख पतन थे। बरसात के दिनों में जब इन नदियों के बाढ़ का विस्तार पास के विस्तृत कृषि क्षेत्र पर हो जाता है उस समय सड़क मार्ग जल समाधि ले लेता है वैसे में जलमार्ग क्षेत्रीय सम्बद्धता में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनसे होकर वस्तुओं एवं यात्रियों का परिवहन होता है।

(ब) रेल-परिवहन

जनपद में रेल परिवहन मार्ग का निर्माण एवं विकास अंग्रेजी काल में हुआ। यहाँ 1882 से रेलमार्ग का निर्माण आरम्भ हुआ जिसे 15, जनवरी 1885 को परिवहन के लिए खोल दिया गया। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में 111 किमी लम्बी इकहरी ब्राडगेज की रेलवे लाइन है। ये सभी उत्तरी-पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत सम्मिलित है जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। जनपद के औद्योगिक विकास में रेलमार्ग की विशेष भूमिका है। प्रमुख उद्योग (चीनी उद्योग) की सभी इकाइयों रेलमार्गों के किनारे ही स्थापित हैं। इनके माध्यम से इन्हें गन्ने की प्राप्ति होती है। देवरिया जनपद में 15 विकासखण्ड हैं। इनमें गौरीबाजार, बैतालपुर, देवरिया सदर, भटनी, भाटपार, बनकटा, सलेमपुर, लार, भागलपुर और गौराबरहज विकासखण्डों में रेलमार्गों का विस्तार है। रेलमार्ग का सर्वाधिक विस्तार सलेमपुर एवं भटनी विकासखण्ड में है। भटनी एवं सलेमपुर रेलवे जंक्शन हैं। जनपद में सर्वाधिक विस्तार गोरखपुर-सोनपुर रेललाइन का है। यह मार्ग सबसे व्यस्त भी रहता है। इस पर जनपद में गौरीबाजार, बैतालपुर, देवरिया सदर, अहिल्यापुर, नूनखार, भटनी जंक्शन, नोनापार, भाटपार, रानी, बनकटा रेलवे स्टेशन हैं। भटनी जंक्शन पर औरिहार-इलाहाबाद मुख्य लाइन आकर गोरखपुर-सोनपुर लाइन से मिलती है। सलेमपुर जंक्शन भटनी-औरिहार-इलाहाबाद लाइन पर स्थित है। यहाँ से बरहज बाजार के लिए बान्ध लाइन निकली है। बरहज बाजार पर रेललाइन समाप्त हो जाती है जिससे इसकी सम्बद्धता सीमित हो जाती है। इस प्रकार रेल मार्ग जनपद के 10 विकासखण्डों में विस्तृत है। क्षेत्रीय विकास में अपना योगदान कर रेलवे ने सराहनीय कार्य किया है।

(स) सडक—परिवहन

अध्ययन क्षेत्र के समतल भू-भाग के कारण सडके सबसे प्राचीन परिवहन मार्ग है। अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेलमार्गों की तुलना में सडको का अधिक विकास हुआ है। साथ ही रेलमार्ग से सभी सेवाकेन्द्रों को सम्बद्ध करना कठिन है किन्तु प्रत्येक सेवाकेन्द्र को सडको से जोड़ा जा सकता है। अतः स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न नदियों पर पुलों का निर्माण सडको का निर्माण तथा उनको पक्का करने की गति में तीव्रता आयी जिससे क्षेत्र में सडको का जाल बिछ गया है। यद्यपि क्षेत्र में नदी-नालों की अधिकता तथा बाढ़ के प्रभाव के कारण इसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर राज्य उच्च मार्ग मुख्य जिला मार्ग अन्य जिलामार्ग तथा पीण्डब्लूण्डी की सडके विकसित हैं। अध्ययन क्षेत्र में पक्की सडको की कुल लम्बाई 1940 किमी है। इसमें 1813 किमी में राष्ट्रीय राजमार्ग (4 किमी) राज्य उच्चपथ (68 किमी) मुख्य जिला सडके (134 किमी) अन्य जिला मार्ग (335 किमी) एवं ग्रामीण सडके (1272 किमी) हैं। शेष में जिला पंचायत नगरपालिका सिचाई विभाग एवं गन्ना विभाग की सडके विस्तृत हैं। सभी प्रकार की सडको सहित पक्की सडको की विकास खण्डवार लम्बाई सारणी 61 में प्रस्तुत है। चित्र 61 में देवरिया जनपद के परिवहन प्रतिरूप को प्रस्तुत किया गया है।

6.3 सडक परिवहन—महत्व

किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन मार्गों का महत्व रेखांकित हो चुका है। इसमें सडक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सडको का अपेक्षाकृत अधिक महत्व निम्न कारणों से है—

- 1 अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेलमार्गों की तुलना में सडक का विकास सुगमता पूर्वक किया जा सकता है
- 2 प्रत्येक सेवाकेन्द्र रेलमार्ग से नहीं जुड़ सकते, पर सडको द्वारा सभी को सम्बद्ध किया जा सकता है।
- 3 रेलमार्गों की तुलना में सडको के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सेवाकेन्द्रों पर तथा सेवाकेन्द्रों से सेवाक्षेत्रों में सुगमता पूर्वक की जा सकती है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अलावे सडके सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन क्षेत्रों में सडक अभिगम्यता पर्याप्त है वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक और सामाजिक सुविधाओं का प्रसरण होने लगता है जिससे क्षेत्र विकासशील हो उठता है। किसी भी क्षेत्र में सिर्फ सडको का होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि सडके अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इसका दुष्प्रभाव श्रृंखलाबद्ध रूप में क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में सडके टूटी-फुटी और बुरी स्थिति में होती हैं, वहाँ वाहनो की दुर्गति होती है जिससे उनकी

TRANSPORT NETWORK OF DEORIA DIST (2002)

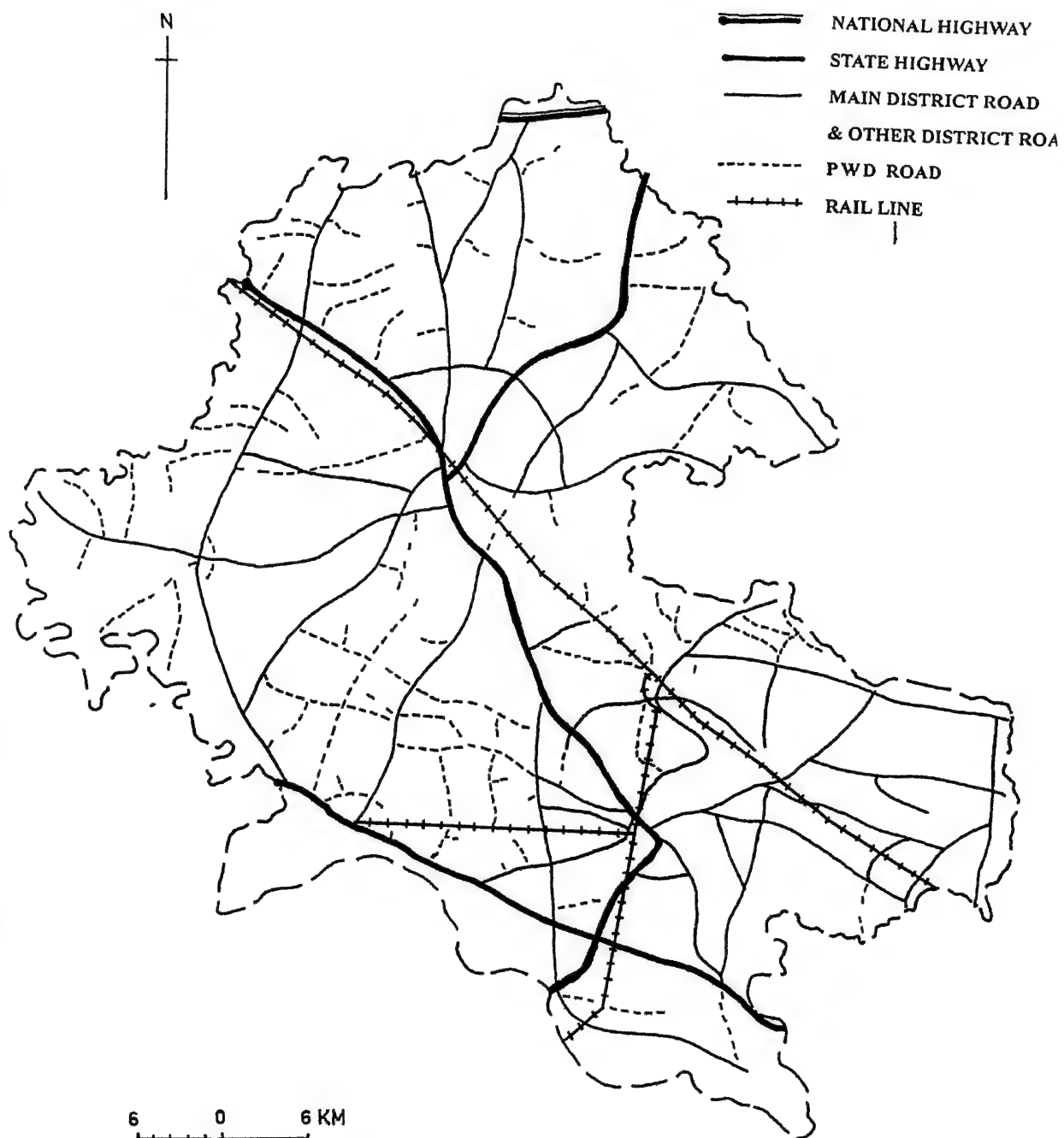


FIG 61

जनपद मे विकासखण्डवार पक्की सडको की लम्बाई (किमी) (2000-01)

विकास खण्ड	पक्की सडको की लम्बाई	सडको से जुड़े ग्रामो की सख्या (जनसख्यावार)		
		1000 से कम वाले ग्राम	1000 से 1499 वाले ग्राम	1500 से अधिक वाले ग्राम
1 गौरीबाजार	168	36	13	7
2 बैतालपुर	137	17	22	9
3 देसही देवरिया	120	14	31	13
4 पथरदेवा	160	33	14	17
5 रामपुर कारखाना	109	40	12	13
6 देवरिया सदर	182	43	28	19
7 रुद्रपुर	94	57	17	14
8 भलुअनी	99	24	15	11
9 बरहज	102	20	18	9
10 भटनी	101	23	15	12
11 भाटपाररानी	107	61	21	16
12 बनकटा	112	29	21	12
13 सलेमपुर	134	51	34	20
14 भागलपुर	99	43	14	21
15 लार	110	23	29	14
योग ग्रामीण	1834	514	299	207
नगरीय	106			
कुल जनपद	1940	514	299	207

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका- 2001,

आयु कम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों के अभाव में डीजल-पेट्रोल की औसत से ज्यादा खपत होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार खराब सड़कों की वजह से वाहन पचास फीसदी तक ज्यादा डीजल खपत करते हैं। यह राष्ट्रीय क्षति है। भारत जैसे देश के लिए जो ऊर्जा सकट की समस्या से जूझ रहा है यह और भी गंभीर समस्या है। इन्हीं कारणों से ग्रामीण परिवहन तथा यातायात की स्थिति आज भी दयनीय है। भारत में भी सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद यूरो-// मॉडल के वाहन चलने लगे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी सारी उच्च गुणवत्ता सड़कों की खराब स्थिति के कारण धरी की धरी रह जाएगी। चूंकि सड़कें अच्छी नहीं हैं, इसलिए सब्जियाँ अनाज, दस्तकारी के सामान गाँवों से उचित समय पर बाजार तक नहीं पहुँच पाते। विपणन की दयनीय स्थिति के कारण ही आज ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास उतना नहीं हो सका है, जितना हमारे बाद आजाद हुए चीन में हुआ है।

देवरिया की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है यहाँ का छोटा-बड़ा उद्योग भी कृषि

आधारित ही है। अतः समतल भू-क्षेत्र वाले इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सड़कें विशेष लाभदायी हैं। विकास में सड़क की भूमिका यहाँ के अधिक सड़क घनत्व वाले क्षेत्रों में देखने से स्पष्ट हो जाती है। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित हैं।

6.4 सड़क घनत्व

सड़क परिवहन का अधिकाधिक प्रयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के यातायात के लिए किया जाता है। पिछड़े क्षेत्र के आर्थिक तन्त्र के प्रादेशिक सन्तुलन के लक्ष्यपूर्ति में रेल की अपेक्षा सड़क अधिक उपादेय सिद्ध होती है। किन्तु सड़कों की उपादेयता की विश्लेषण में उनकी लम्बाई की अपेक्षा सघनता का प्रयोग अधिक समीचीन प्रतीत होता है। सड़कों की स्थिति (टूटी-फूटी या अच्छी स्थिति) एवं चौड़ाई भी उपादेयता के प्रमुख निर्धारक तत्वों में शामिल हैं परन्तु प्रस्तुत विश्लेषण में इन्हें स्थिर मानकर घनत्व के आधार पर उपादेयता का विश्लेषण किया गया है। सड़कों के घनत्व का आर्थिक विकास क्षेत्रीय विस्तार जनसंख्या तथा आर्थिक कार्यकलापों के वितरण प्रतिरूप एवं वैकल्पिक परिवहन साधनों के विकास से घनिष्ठ अंतर्सम्बन्ध है। अध्ययन क्षेत्र में सड़क घनत्व अत्यधिक न्यून है। सापेक्षिक दृष्टि से सड़क घनत्व उन्हीं भागों में अधिक है जहाँ जनसंख्या एवं आर्थिक कार्यकलाप की सघनता है।

प्रस्तुत अध्ययन में सड़क घनत्व की गणना दो प्रकार से की गयी है। प्रथम विकासखण्ड स्तर पर प्रति 1,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर तथा द्वितीय 1,00,000 की मानक जनसंख्या पर (विकासखण्ड स्तर पर)। इसे सारणी (6.2) एवं चित्र (6.2) में प्रस्तुत किया गया है। इनसे सड़क घनत्व को आसानी से प्रत्यक्षीकृत किया जा सकता है।

सारणी 6.2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रति 1,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक देवरिया सदर विकास खण्ड में तथा न्यूनतम भलुअनी विकास खण्ड में है। विकास खण्ड स्तर पर सड़कों का घनत्व अवरोही क्रम में क्रमशः— देवरिया सदर गौरीबाजार देसही देवरिया, सलेमपुर बनकटा लार भाटपाररानी बैतालपुर, रामपुर कारखाना बरहज पथरदेवा भटनी भागलपुर रुद्रपुर और भलुअनी में हैं। मानचित्र से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र सड़क घनत्व में सम्पन्न क्षेत्र है जबकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम घनत्व के क्षेत्र हैं। शेष भागों में सड़क घनत्व अपेक्षाकृत औसत है।

प्रतिलाख जनसंख्या के आधार पर भी सड़क घनत्व का लगभग यही प्रतिरूप उभरता है। देवरिया सदर सर्वाधिक घनत्व वाला विकासखण्ड है। जनसंख्या के आधार पर सड़क घनत्व का विकास खण्डवार अवरोही क्रम निम्नवत् है— देवरियासदर, देसही देवरिया बरहज, गौरीबाजार बनकटा, बैतालपुर, भागलपुर, सलेमपुर लार रामपुर कारखाना, भाटपाररानी पथरदेवा, भटनी रुद्रपुर, भलुअनी।

जनपद देवरिया का सडक घनत्व 2001

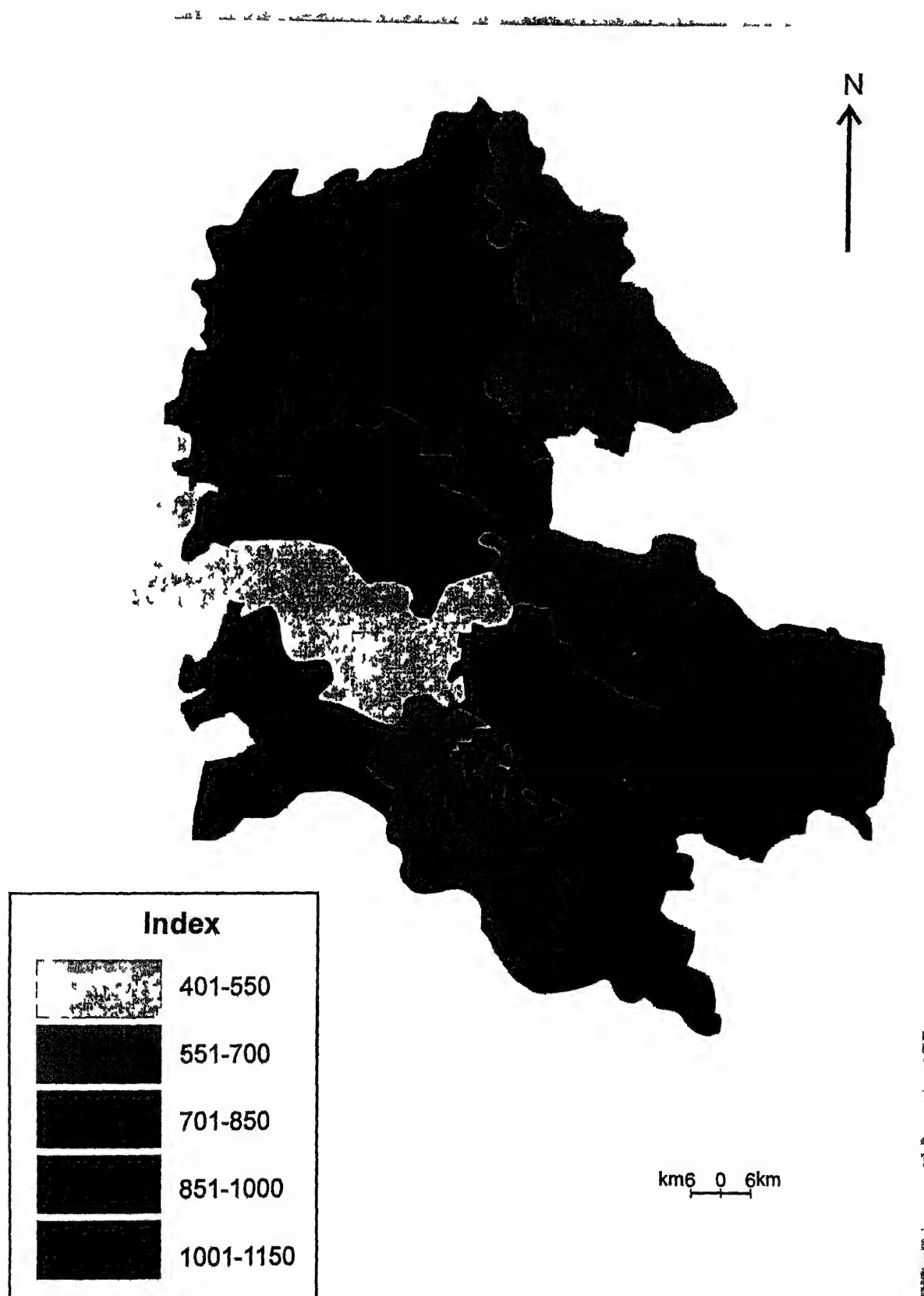


Fig 6 2

सारणी- 62

जनपद मे विकासखण्डवार सडको का घनत्व (क्षेत्रफल एव जनसख्या के आधार पर (2000-01)

विकास खण्ड	पक्की सडको की लम्बाई	प्रतिलाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई (किमी)-2000	प्रतिलाख जनसख्या पर लो नि वि द्वारा सघृत सडको की लम्बाई (किमी)-2000	प्रतिहजार वर्ग किमी पर कुल पक्की सडको की लम्बाई (किमी)-2000
1 गौरीबाजार	168	102.5	67.7	915.5
2 बैतालपुर	137	94.5	62.8	767.1
3 देसही देवरिया	120	106.9	69.5	904.3
4 पथरदेवा	160	84.1	63.1	695.3
5 रामपुर कारखाना	109	89.0	59.6	765.4
6 देवरिया सदर	182	113.8	61.9	1011.7
7 रुद्रपुर	94	73.7	56.4	489.8
8 भलुअनी	99	70.4	48.3	411.6
9 बरहज	102	105.4	78.5	744.5
10 भटनी	101	82.5	51.4	685.7
11 भाटपाररानी	107	88.9	77.3	795.5
12 बनकटा	112	96.0	60.8	821.7
13 सलेमपुर	134	93.6	73.4	897.5
14 भागलपुर	99	93.7	89.0	664.0
15 लार	110	91.3	56.4	814.8

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया - 2001 पृ- 104, 167, 168 से संगणित

सारणी 62 को देखने से एक बात और स्पष्ट होती है, कि जिन विकासखण्डों में सडक घनत्व अपेक्षाकृत कम है वे कम विकसित विकासखण्ड हैं। इनमें क्रमशः बरहज (744.5) भटनी (685.7) भागलपुर (664), रुद्रपुर (489.8) और भलुअनी (411.6) विकासखण्ड शामिल हैं। इनमें प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपेक्षाकृत कम सडके हैं। ये सभी विकासखण्ड अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। यह क्षेत्र राप्ती और घाघरा नदियों के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। जिससे बरसात के दिनों में इसका सडक सम्पर्क अन्य भागों से कट जाता है। बाढ़ के कारण खरीफ की फसलें नहीं हो पाती हैं। रबी इन क्षेत्रों की प्रधान फसल है। अतः इन क्षेत्रों में पक्की सडकों के विकास से क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

6.5 सडक अभिगम्यता

प्रायः मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कम से कम समय तथा शक्ति का उपयोग करना चाहता है। लेकिन इसकी सम्भाव्यता सडकों की अभिगम्यता की तीव्रता पर निर्भर है। सडक

अभिगम्यता का तात्पर्य यथा सम्भव कम समय तथा कम शक्ति के व्यय पर निर्वाध गति से सुगमता पूर्वक किसी सड़क या सेवाकेन्द्र पर पहुँचने से है। सड़को की अभिगम्यता से सड़को की सघनता तथा गमनागमन की सुविधा का ज्ञान होता है। साथ ही इसकी तीव्रता से किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एवं सड़क जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है। सामान्यतया मार्ग जाल की गम्यता परिवहन मार्गों से एक विशेष दूरी द्वारा प्रकट की जाती है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक ही दूरी को अभिगम्यता का मानक मापदण्ड नहीं माना जा सकता। अभिगम्यता का मापदण्ड साधारणतया व्यक्तिनिष्ठ होता है। अभिगम्यता बहुत कुछ सड़क की स्थिति पर भी निर्भर करती है क्योंकि यदि सड़क रहे और टूटी-फूटी हालत में हो तो अभिगम्यता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सड़क तन्त्र के विकसित होने से अगम्य क्षेत्र लुप्त प्राय हो जाता है। भारत में सड़को के विकास के लिए अभिगम्यता मानदण्ड सर्वप्रथम 1943 में 'नागपुर योजना' के अन्तर्गत निर्धारित की गयी। उसके बाद 'बम्बई योजना' के रूप में इसे सशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया। इन दोनों योजनाओं द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्डों को सारणी 63 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी- 63

नागपुर तथा बम्बई योजनाओं द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड

क्रम सं०	क्षेत्र विवरण	किसी भी गाँव की अधिकतम दूरी (किमी)	
		किसी भी सड़क से	मुख्य सड़क से
1	नागपुर योजना		
	1 कृषि क्षेत्र	3 22	8 05
	2 कृष्येत्तर क्षेत्र	8 05	32 10
2	बम्बई योजना		
	1 विकसित कृषि क्षेत्र	2 41	6 44
	2 अविकसित कृषि क्षेत्र	8 05	19 31

राष्ट्रीय स्तर पर सड़क परिवहन के विश्लेषण में अधिकांशतया इसी मानदण्डों को ही अपनाया जाता रहा है। किन्तु कृषि प्रधान तथा दक्षिणी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इस जनपद के लिए उक्त मानदण्ड उपयुक्त नहीं है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम- यह मानदण्ड आर्थिक विकास के स्तर से सम्बन्धित है, जबकि अध्ययन क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर आर्थिक विकास के स्तर के अतिरिक्त भौतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विभिन्नता पायी जाती है। द्वितीय- यह मापदण्ड अत्यधिक प्राचीन है। अतः आज के बदले हुए परिवेश में देवरिया जनपद में सड़को की अभिगम्यता मापन के लिए उपर्युक्त मापदण्ड उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। अतः व्यावहारिक अभिगम्यता को देखते हुए इस भाग में सड़क अभिगम्यता के मापन के लिए निम्नलिखित को अभिगम्य माना जा सकता है-

- 1 मुख्य पक्की सड़को से 3 किमी दूर तक स्थित बस्तियाँ,

सारणी- 64
देवरिया जनपद मे सडकमार्ग द्वारा अभिगम्य बस्तियाँ

विकास खण्ड	कुल आबाद ग्राम	बारहमासी सडको से सबद्ध ग्राम	कुल ग्राम से सबद्ध ग्राम का प्रतिशत	कुल ग्राम से असम्बद्ध ग्राम का प्रतिशत
1 गौरीबाजार	114	56	49 12	50 88
2 बैतालपुर	127	48	37 79	62 21
3 देसही देवरिया	86	58	67 44	32 56
4 पथरदेवा	150	64	42 66	57 34
5 रामपुर कारखाना	113	65	57 52	42 48
6 देवरिया सदर	155	80	51 61	48 39
7 रुद्रपुर	159	88	55 34	44 66
8 भलुअनी	171	50	29 23	70 77
9 बरहज	94	47	50 00	50 00
10 भटनी	107	50	46 72	53 28
11 भाटपाररानी	117	98	83 76	16 24
12 बनकटा	148	62	41 89	50 11
13 सलेमपुर	203	105	51 72	48 28
14 भागलपुर	122	78	63 93	36 07
15 लार	124	66	53 22	46 78
योग जनपद			52 13	47 87

स्रोत-सांख्यिकी पत्रिका- 2001 पृ- 24, 104 से परिकलित

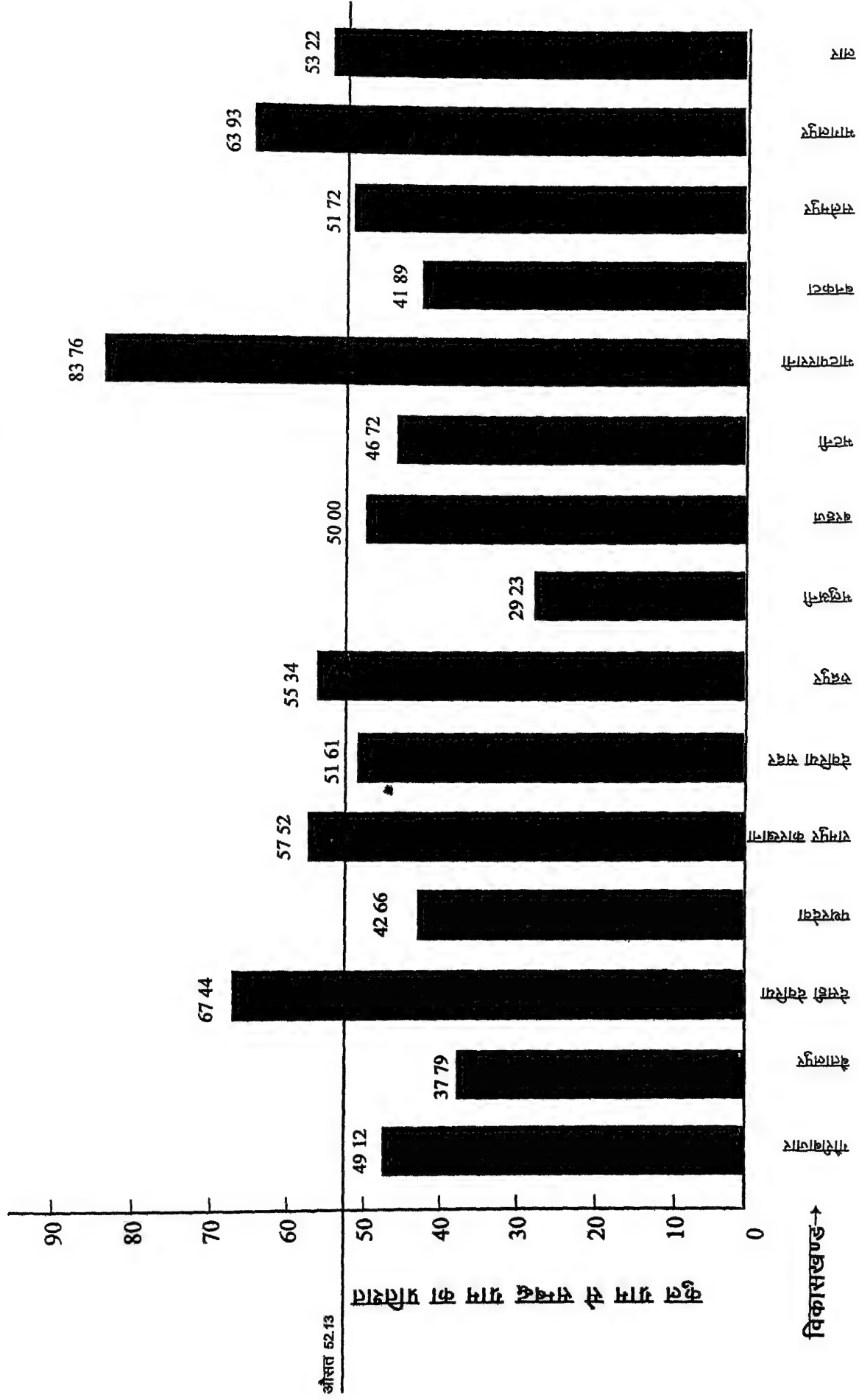
2 अन्य पक्की सडको से 2 किमी दूरस्थ तक की बस्तिया तथा

3 किसी भी खडन्जा मार्ग या कच्चे मार्ग से सम्बद्ध बस्तियाँ,

परन्तु ये मार्ग बारहमासी होने चाहिए।

उपर्युक्त मानदण्डो के आधार पर जनपद मे वर्षभर परिवहन योग्य सडको से सम्बद्ध एव अभिगम्य बस्तियो को सारणी 64 मे प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त आधार पर अभिगम्यता मानचित्र (63) मे प्रदर्शित है। सारणी एव मानचित्र से स्पष्ट है कि जनपद की अभिगम्यता औसत है। उच्च जनघनत्व वाले इस क्षेत्र के लिए इस अभिगम्यता को सतोषजनक नही कहा जा सकता। जनपद का औसत 52 13 प्रतिशत क्षेत्र सडक मार्ग द्वारा अभिगम्य है जबकि शेष 47 87 प्रतिशत भाग आज भी सडक मार्ग से कटा हुआ है। अतः क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनपद के प्रत्येक बस्ती को सडक से सम्बद्ध होना आवश्यक है। जनपद मे सर्वाधिक अभिगम्यता भाटपाररानी विकास खण्ड मे (83 76) है। उसके बाद क्रमशः देसही देवरिया भागलपुर रामपुर कारखाना रुद्रपुर, लार, सलेमपुर देवरिया सदर, बरहज, गौरीबाजार भटनी, पथरदेवा, बनकटा बैतालपुर एव भलुअनी का स्थान है। भलुअनी में निम्नतम मात्र 29 23 गाँव ही सडको द्वारा अभिगम्य हैं। इनमे से क्रमशः भाटपार रानी देसही देवरिया, भागलपुर रामपुर कारखाना रुद्रपुर

जनपद देवरिया सडक मार्ग द्वारा अभिगम्य बस्तियाँ- 2001



METALLED ROAD CONNECTIVITY MATRIX (Dist Deoria 2001)

SC	DR	SL	GB	BP	BT	BR	LR	RK	BP	RP	BK	TK	BH	IP	RL	MP	BL	MR	SP	BG	KP	BY	PD	BN	DD	SC	
देवरिया	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	DR	
सलेमपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SL	
गौरीबाजार	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	GB	
बैतालपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BP	
मटनी	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BT	
बरहज	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BR	
लार	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	LR	
रामपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	RK	
भाटपार	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BP	
रुद्रपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	RP	
बनकटा	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BK	
तरकुलवाँ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	TK	
भागलपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BH	
इन्दूपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	IP	
रामलछन	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	RL	
मदनपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	MP	
बलटीकरा	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BL	
मझौलीराज	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	MR	
सोहनपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	SP	
मिगारी	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BG	
कचनपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	KP	
बरियारपुर	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BY	
पथरदेवा	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PD	
मलुआनी	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	BN	
देसही देवरिया	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	DD	
T	13	8	5	5	1	5	5	5	7	3	6	1	3	3	3	2	3	3	5	3	3	4	2	1	2	2	98

सेवाकेन्द्र

देवरिया

सलेमपुर

गौरीबाजार

बैतालपुर

मटनी

बरहज

लार

रामपुर

भाटपार

रुद्रपुर

बनकटा

तरकुलवाँ

भागलपुर

इन्दूपुर

रामलछन

मदनपुर

बलटीकरा

मझौलीराज

सोहनपुर

मिगारी

कचनपुर

बरियारपुर

पथरदेवा

मलुआनी

देसही देवरिया

SERVICE CENTRE

DEORIA

SALEMPUR

GAURI BAJAR

BAITAL PUR

BHATNI

BARHAJ

LAR

RAMPUR KARKHANA

BHATPAR

RUDRA PUR

BANKATA

TARKULWA

BHAGAL PUR

INDU PUR

RAMLACHHAN

MADANPUR

BALTIKRA

MAJHAULIRAJ

SOHAN PUR

BHINGARI

KANCHAN PUR

BARIYAR PUR

PATHAR DEVA

BHALUANI

DESAI DEORIA

और लार विकास खण्डो मे ही अभिगम्यता *जनपद औसत* (52 13) से ऊँची है। शेष सभी विकास खण्डो की अभिगम्यता औसत से निम्न है।

6 6 सडक सम्बद्धता

सडको की आपस मे सम्बद्धता सडक परिवहन के विश्लेषण का एक अद्वितीय माध्यम है। परिवहन व्यवस्था की सुगमता सडक तन्त्र के विकास का स्तर तथा सघनता का बोध सडक सम्बद्धता से ही स्पष्ट होता है। जिन क्षेत्रो मे सम्बद्धता अधिक होती है उन क्षेत्रो मे सडको की सघनता तथा गम्यता अधिक होती है। पिछडी अर्थव्यवस्था के सडक जाल प्राय सुसम्बद्ध नही होते है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रो मे सडक सम्बद्धता अधिक पायी जाती है। जहाँ सडके इस प्रकार वितरित हो कि कोई भी सडक किसी आतरिक बिन्दु पर जाकर अकस्मात् समाप्त नही होती है वरन् उसके दोनो छोर अन्य सडको से सम्बन्धित हो तो उसे *सुसम्बद्ध सडक जाल* कहा जाता है। दूसरी ओर जहाँ प्रमुख सडको से आबद्ध क्षेत्र के मध्य अन्य सडके अकस्मात् किसी बिन्दु पर समाप्त हो जाती है अर्थात् उनके द्वारा हर दिशा मे यात्रा बिना वापस लौटे नही की जा सकती तो उसे *असम्बद्ध सडक जाल* कहा गया है। इन दोनो के बीच की स्थिति को सामान्य सम्बद्धता की दशा मानी गयी है। जो सडक जाल जितना ही सुसम्बद्ध होगा उसमे परिक्रमता उतनी ही कम होगी।¹⁰ अध्ययन क्षेत्र मे सम्बद्धता को तीन माध्यमो से तीन स्तरों पर ज्ञात किया गया है। *प्रथम— परिवहनीय सम्बद्धता* *द्वितीय—सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता* तथा *तृतीय— मार्ग जाल की सम्बद्धता*।

(अ)— परिवहनीय सम्बद्धता

इसके अतर्गत सडक मार्गों के दूसरे सडको से सम्बद्धता एव प्रत्येक सडक की अभिगम्यता को संयुक्त कर पहले जनपद मे पायी जाने वाली प्रत्येक सडक का मूल्य ज्ञात किया गया है। चूँकि जनपद मे राष्ट्रीय राजमार्ग राजकीय राजमार्ग, जिला मार्ग अन्यजिलामार्ग तथा ग्रामीण मार्ग मिलकर एक सडक जाल का निर्माण करती है। अत इस सडक संरचना मे स्थित प्रत्येक प्रकार का सेवाकेन्द्र सडक अभिगम्यता के मूल्य के अनुसार ही लाभ प्राप्त करेगा। राजकीय सडके एव जिला मार्ग ज्यादा अभिगम्य होती है, जबकि ग्रामीण मार्ग कम। इसी भाँति इनसे जुड़े सेवाकेन्द्रों का सेवाक्षेत्र भी कम या ज्यादा विस्तृत होता है। अत उक्त आधार पर चतुर्थ अध्याय मे परिवहनीय सम्बद्धता एव सेवाकेन्द्रों के सन्दर्भ मे परिवहनीय सम्बद्धता सूचकांक की गणना की गयी है। इसे सारणी 4 4 मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त सारणी के आधार पर देवरिया सेवाकेन्द्र का सबसे अधिक सम्बद्धता मूल्य (55 33) है। इसके बाद क्रमश सलेमपुर (46 00), गौरी बाजार (38 0), बैतालपुर (31 16) आदि सेवाकेन्द्रों का स्थान है। सबसे कम मूल्य घाटी का (1 00) है।

(ब) सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता

सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि जनपद देवरिया के प्रमुख सेवाकेन्द्र आपस में कितने सेवाकेन्द्रों से जुड़े हुए हैं। इस सड़क सम्बद्धता को ज्ञात करने में केवल पक्की सड़कों को ही आधार बनाया गया है। यद्यपि कच्ची सड़कों द्वारा भी सेवाकेन्द्रों में सम्बद्धता पायी जाती है किन्तु जनपद के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग के बाढ़गस्त क्षेत्र होने के कारण तथा क्षेत्र में अत्यधिक नालों के होने के कारण एवं समुचित पुलों के अभाव के कारण वर्षा के दिनों में सम्बद्धता भग्न हो जाती है। अस्तु सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता विश्लेषण में समरूपता लाने के लिए कच्ची सड़क एवं खडजा मार्गों को छोड़ दिया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता ज्ञात करने के लिए मानचित्र 61 के आधार पर *कनेक्टिविटी मैट्रिक्स* बनाया गया है। जिसे सारणी 65 के रूप में देखा जा सकता है। जनपद का सबसे सम्बद्ध सेवाकेन्द्र *देवरिया* है। यह प्रत्यक्षतः 13 सेवाकेन्द्रों से जुड़ा है। इसके बाद *सलेमपुर* 8 सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध है। *रामपुर कारखाना* की सम्बद्धता 7 तथा *रुद्रपुर* की सम्बद्धता 6 है। इसके बाद *गौरीबाजार*, *बैतालपुर*, *बरहज*, *लार* और *मझौलीराज* सभी 5 सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध हैं। *कचनपुर* की सम्बद्धता 4 तथा *भाटपार*, *तरकुलवा*, *भागलपुर*, *इन्द्रपुर*, *रामलछन*, *बलटीकरा*, *सोहनपुर*, *भिगारी* 3 सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध है। *मदनपुर*, *बरियारपुर*, *भलुअनी* और *देसही देवरिया* की सम्बद्धता 2 है। सबसे कम सम्बद्धता *भटनी*, *बनकटा* और *पथरदेवा* सेवाकेन्द्र की मात्र एक सेवाकेन्द्र से है।

(स) मार्ग-जाल की सम्बद्धता

मार्ग जालों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कई मापकों का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण विधि में किसी भी मार्ग जाल को एक ग्राफ के रूप में माना गया है। जिसमें *बिन्दु (वर्टिक्स)* तथा *बाहु (एजेंज)* दो मुख्य तत्व होते हैं। किसी भी परिवहन माध्यम के मार्ग जाल में जितने भी उद्गम, सगम तथा अंतिम या प्रमुख विकास केन्द्र होते हैं उन्हें *बिन्दु* तथा इनको सीधे सम्बन्धित करने वाले मार्गों को *बाहु* के रूप में माना जाता है। इसमें दो बिन्दुओं के बीच की दूरी अर्थात् बाहुओं की लम्बाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़कों के जाल के सन्दर्भ में प्रमुख *बिन्दुओं (v)* की संख्या— 43, *बाहुओं (e)* की संख्या 115 तथा *असम्बद्ध ग्राफ (g)* की संख्या 16 है। इन बिन्दुओं एवं बाहुओं के माध्यम से सड़क जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले *अल्फा (α)*, *बीटा (β)* तथा *गामा (γ)* निर्देशांकों की गणना की गयी है।

(i) अल्फा निर्देशांक (α)

इससे मार्ग जाल के सम्बद्धता स्तर का बोध होता है। इस निर्देशांक का मान 0—1.00 के मध्य होता है। पूर्णतः असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 0 होता है। पूर्णतः सुसम्बद्ध मार्ग जाल का निर्देशांक 1.00 होता है। इस निर्देशांक की गणना निम्न सूत्र से की गयी है—

$$\alpha = \frac{e-v+g}{2v-5}$$

जहाँ—

- α = अल्फा निर्देशांक
 e = बाहुओं की संख्या
 v = बिन्दुओं की संख्या तथा
 g = असम्बद्ध ग्राफों की संख्या

अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल का यह निर्देशांक 0.69 है। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद की सड़क जाल सम्बद्धता औसत से कुछ अच्छी है। इस निर्देशांक (0.69) में 100 से गुणा करके इस सम्बद्धता को प्रतिशत में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद का मार्ग जाल 69 प्रतिशत सम्बद्ध है, जो एक अच्छी स्थिति है।

(ii) बीटा निर्देशांक (β)

बीटा निर्देशांक से किसी मार्ग-जाल के बाहुओं एवं बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है। इस निर्देशांक के अनुसार असम्बद्ध मार्ग जालों का मान 1.00 से कम होता है। एक ही चक्र में विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं को मिलाने वाले मार्ग जाल का मान 1.00 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान 1.00 से अधिक होता है। इस निर्देशांक की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है¹²—

$$\beta = \frac{e}{v}$$

जहाँ —

- β = बीटा निर्देशांक
 e = बाहुओं की संख्या तथा
 v = बिन्दुओं की संख्या।

अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल के इस निर्देशांक का मान 2.67 है, जिससे स्पष्ट है कि सड़क जाल उत्तम ढंग से सबद्ध है।

(iii) गामा निर्देशांक (γ)

इससे किसी मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है किन्तु यह बीटा निर्देशांक से भिन्न है। यह निर्देशांक विद्यमान बाहुओं का अधिकतम बाहुओं के गुणांक का घातक है। इस निर्देशांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है—¹³

$$\gamma = \frac{e}{3(v-2)}$$

जहाँ —

$$\begin{aligned}\gamma &= \text{गामा निर्देशांक} \\ e &= \text{बाहुओं की संख्या तथा} \\ v &= \text{बिन्दुओं की संख्या।}\end{aligned}$$

इस निर्देशांक का मान 0—1 00 के मध्य होता है। पूर्ण सम्बद्ध मार्ग जालों का मान 1 00 तथा अपूर्ण सम्बद्धता वाले मार्ग जालों का मान 1 00 से कम आता है। जनपद में सड़क जाल का गामा निर्देशांक 0 93 है। इसमें 100 का गुणा करने पर सम्बद्धता प्रतिशत में ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार सड़क जाल सम्बद्धता 93 प्रतिशत है। जो अच्छी सम्बद्धता का द्योतक है। गामा निर्देशांक तथा अल्फा निर्देशांक के सम्बद्धता प्रतिशत में अन्तर का कारण है अल्फा निर्देशांक उन्हीं सड़क जालों के लिए उपयुक्त है जिनमें कई असम्बद्ध ग्राफ हो।

इस प्रकार सड़क सम्बद्धता के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सड़क सम्बद्धता तथा अभिगम्यता औसत से अच्छी है। परन्तु चूँकि इसमें केवल उन्हीं मार्गों को आधार बनाया गया है, जो पक्की हैं, ग्रामीण सड़कों की उपेक्षा की गयी है, जबकि सेवाकेन्द्रों से सेवाक्षेत्रों को ग्रामीण सड़कों ही जोड़ती हैं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता के बिना सेवाकेन्द्रों के इस सम्बद्धता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अतः आवश्यकता है प्रत्येक ग्राम को पक्की सड़कों द्वारा सेवा केन्द्रों से सम्बद्ध किया जाय, तभी क्षेत्र का समुचित विकास सम्भव है। अध्ययन क्षेत्र में इस सम्बद्धता में क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नता मिलती है। भटनी पथरदेवा बनकटा, बैतालपुर और भलुअनी विकास खण्डों में सम्बद्धता बहुत ही निम्न स्तर की है। दक्षिणी भाग राप्ती और घाघरा के बाढ़ के कारण बरसात भर शेष क्षेत्र से असम्बद्ध हो जाता है। यहाँ बाढ़ सबसे बड़ा विकास में बाधक है।

6 7 यातायात प्रवाह

यातायात प्रवाह से न केवल परिवहन की कार्यात्मक विशिष्टताएँ स्पष्ट होती हैं अपितु क्षेत्रीय आर्थिक कार्यकलाप आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूप एवं आर्थिक विकास का स्तर भी ज्ञात होता है। साधारणतः यातायात प्रवाह के अन्तर्गत वस्तुओं एवं यात्रियों के आवागमन प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत तीन बातों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम वस्तुओं के उद्गम—गन्तव्य स्थलों पर आने—जाने से व्यापारिक स्वरूप का बोध होता है, द्वितीय, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रतिमाह परिवहन मार्ग पर कुल यातायात घनत्व का पता चलता है, तथा तृतीय परिवहन के साधनों तथा परिवहित वस्तुओं की संरचना में परिवर्तन का प्रभाव परिवहन साधनों पर पड़ता है।

यातायात प्रवाह के उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से इस क्षेत्र के वर्तमान यातायात प्रवाह के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। परन्तु किसी निर्धारित मापदण्ड के अभाव में यह निश्चित कर पाना कठिन है कि विद्यमान यातायात प्रवाह घनत्व की स्थिति पिछड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है अथवा विकसित अर्थव्यवस्था का दूसरे ससाधनों की कमी के कारण समय के साथ वस्तुओं के प्रवाह के आकड़ों का संग्रहण भी संभव नहीं हो सका।

अध्ययन क्षेत्र के कृषि प्रधान होने कृषि आधारित उद्योग के विकास एवं घनी जनसंख्या बसाव के कारण यातायात प्रवाह का विशेष महत्व है। यहाँ खाद्यान्नों गन्ना सब्जियों तथा दूध आदि की आपूर्ति विभिन्न शहरों एवं औद्योगिक केन्द्रों पर सड़क मार्ग से ही होता है। विभिन्न सेवाओं कार्यों एवं वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए यात्रियों के परिवहन का सर्वप्रमुख माध्यम सड़कमार्ग ही है। जनपद से बाहर जाने वाली वस्तुओं तथा बाहर से जनपद में आने वाली वस्तुओं के लिए ट्रकों एवं रेल गाड़ियों का उपयोग होता है। इनमें प्रमुखतः चूना सीमेंट पेट रसायन रासायनिक उर्वरक आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सामानों की आपूर्ति ट्रैक्टर द्वारा पूरी की जाती है। इसके आलावे यात्रियों के आवागमन के लिए बसों ट्रैक्टरों जीप टैक्सी बैलगाड़ी रिक्शा स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा साइकिल आदि का उपयोग होता है। मौसम के अनुसार यातायात में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः शादी-विवाह के अवसरों (मार्च अप्रैल से जून) पर इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है।

यातायात प्रवाह के उपर्युक्त आँकड़ों का एकत्रीकरण निश्चित समय के अन्दर संभव नहीं है दूसरे यातायात प्रवाह में परिवर्तन बहुत अधिक होता है क्योंकि यातायात प्रवाह में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। क्योंकि यातायात प्रवाह अनेक परिवर्त्यों पर निर्भर करता है। इसलिए अध्ययन क्षेत्र के यातायात प्रवाह का विश्लेषण यात्रियों के आवागमन के आधार पर किया गया है। यात्रियों के इस प्रवाह का मापन सड़कों पर चलने वाले व्यक्तिगत तथा सरकारी बसों के माध्यम से किया गया है। सड़कों पर चलने वाली सरकारी बसों की गणना देवरिया रोडवेज डिपो, तथा रुद्रपुर लार सलेमपुर, बरहज एवं गौरीबाजार बस स्टैंड से एवं निजी बसों की गणना विभिन्न सेवाकेन्द्रों पर व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर की गयी है। बसों की सम्पूर्ण संख्याओं का योग उनके (बसों के) आने व जाने के सन्दर्भ में किया गया है। देवरिया में बसों का प्रवाह मानचित्र (6.4) में प्रदर्शित है।

देवरिया से प्रतिदिन लगभग 176 यात्री बसों का आवागमन होता है। इनमें 158 बसे विभिन्न मार्गों से देवरिया जनपद से बाहर की ओर जाती हैं। इनमें से गौरीबाजार-गोरखपुर रूट से 110 बसे, गौरीबाजार-हाटा रूट से 12 बसे, हेतिमपुर रूट से 2 बसे तरकुलवाँ-पड़रौना की ओर 16 बसे तथा लार से बिहार की ओर 10 यात्री बसों का आवागमन प्रतिदिन होता है। लम्बी दूरी की बसों में देवरिया से दिल्ली 16 बसे, देवरिया-कानपुर 8 बसे, देवरिया-लखनऊ 8 बसे देवरिया-

DISTRICT DEORIA FREQUENCY OF BUSES 2002

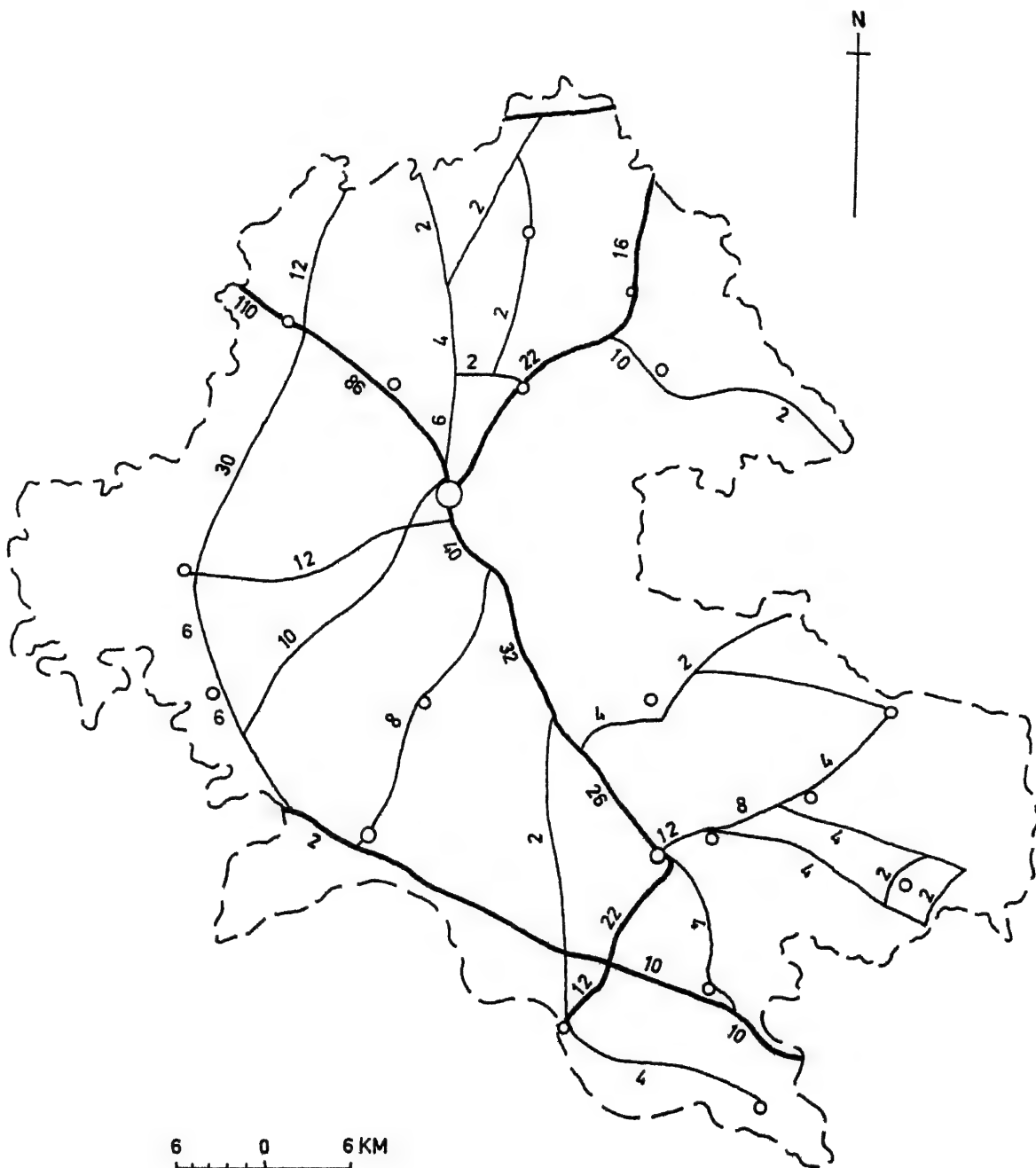


FIG 6 4

FLOW MAP OF BUSES, DISTRICT DEORIA

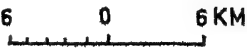
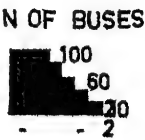
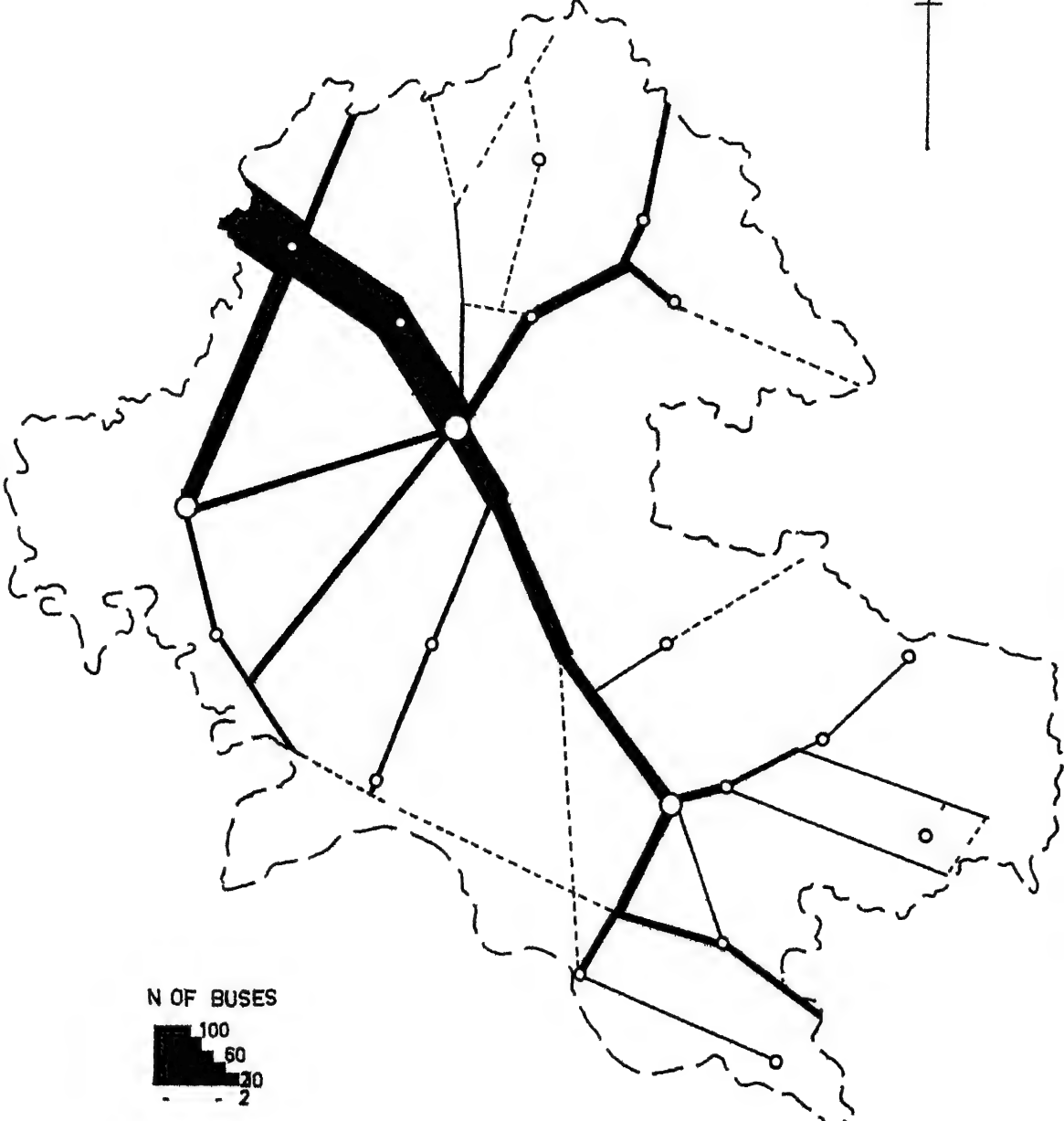


FIG 65

बलिया— 8 बसे, लार—कानपुर 8 बसे तथा रुद्रपुर से गोरखपुर लखनऊ कानपुर एव दिल्ली के लिए प्रतिदिन 16 बसों का आवागमन होता है। जनपद का सबसे व्यस्ततम मार्ग सलेमपुर—देवरिया—गौरीबाजार मार्ग है। यह मार्ग राजकीय राजमार्ग स०-1 (एस एच 1) है जो देवरिया को गोरखपुर से सम्बद्ध करता है। इस पर देवरिया से गोरखपुर की ओर बसों की सर्वाधिक आवृत्ति प्रतिदिन 110 तक पायी जाती है। गौरीबाजार और देवरिया के मध्य आवृत्ति 86 तथा देवरिया—सलेमपुर के मध्य 40—32 एव 26 पायी जाती है। रुद्रपुर से देवरिया के बीच 12 बसे तथा गौरीबाजार के बीच प्रतिदिन 30 बसे गुजरती हैं। बरहज से भलुअनी होते हुए देवरिया तक प्रतिदिन 8 बसे गुजरती है। जबकि देवरिया से कसया की ओर राजकीय उच्चपथ 79 (एस एच 79) से होते हुए 16 बसे गुजरती है। प्रमुख मार्गों से बसों के प्रवाह को चित्र (65) में दिखाया गया है तथा उक्त पर आधारित आरेख चित्र (65) में प्रदर्शित है।

(ख) संचार और सूचना प्रसार

6.8 महत्व एवं विकास

संचार से आशय सदेश, विचार एवं सूचनाओं इत्यादि के आदान—प्रदान से है। विकास के लिए संचार अपरिहार्य है पिछले एक दशक से विकास विश्व राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था की एक गभीर चिन्ता बनकर उभरा है। वैसे विश्व के समक्ष विकास की चिन्ता पहले भी रही परन्तु जिस शिद्दत से पिछले दस वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सभ की विकास योजना और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने विकास के सवाल को उठाया है वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था।

विकास में सूचना के प्रचार—प्रसार की आवश्यकता पहले भी महत्वपूर्ण मानी गयी थी लेकिन वैश्वीकरण के दौर में सूचना का प्रचार—प्रसार स्वयं एक बड़ा एजेन्डा बनकर उभरा है। यह माना गया कि विश्व तभी एक बड़ा बाजार बन सकता है जब दुनिया का छोटे से छोटा गाँव एक दूसरे से जुड़ा हो और उपभोक्ता वस्तुओं की जानकारी व्यापक तौर पर उपलब्ध हो। संभवत यही वजह थी कि पिछले तीन दशकों में एक ऐसी प्रौद्योगिकी क्रांति हुई जिसने दुनिया की शक्ति काफी हद तक बदल दी। इस क्रांति को हमने 'सूचना क्रांति' कहा।

सूचना क्रांति के केन्द्र में दूरसंचार प्रौद्योगिकी रही है भले ही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर उपयोग जनसंचार के लिए ही हुआ। उपग्रह संचार का प्रयोग सम्प्रेषण के दो महत्वपूर्ण तरीकों के लिए किया जा सकता था। पहला प्रयोग तो दूरदराज के क्षेत्रों तक टेलीफोन की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर और दूसरा उसका प्रयोग दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारणों को व्यापक बनाकर। 1982 में एशियाई खेलों के दौरान दूरदर्शन के लिए तकरीबन हर रोज एक ट्रांसमीटर लगाने का जो सिलसिला आरम्भ हुआ उसने जल्दी ही टेलीविजन प्रसारणों की पहुँच

देश के लगभग 98 प्रतिशत क्षेत्र तक कर दी।

1984 में राजीव गान्धी के नेतृत्व में जो टेक्नोलॉजी मिशन बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण मिशन टेलीफोन सुविधा से संबद्ध था। जिसने अपना लक्ष्य हर गाँव तक टेलीफोन पहुँचाना रखा था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'सी-डॉट' नामक संस्था ने देश में ही आधुनिकतम टेलीफोन एक्सचेंज बनाने की जिम्मेदारी ली थी। इस मिशन के प्रयासों से आज देशभर में टेलीफोन के 'सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों' (पीसीओ) का जाल फैल गया है। वर्ष 1996 तक प्रति हजार व्यक्ति 26 केन्द्रों तक पहुँचने का अनुमान है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी पीसीओ केवल महानगरों और बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि आज देश के कोने-कोने में, गाँव-गाँव में पीसीओ दिखाई पड़ते हैं।

इसी दौरान योजना आयोग का एक कार्यालय 'राष्ट्रीय सूचना केन्द्र' (नेशनल इफोर्मेटिक सेंटर) देश के हर जिले को उपग्रह आधारित कंप्यूटर सजाल से जोड़ने में लगा हुआ है।

सन् 2001 की *विश्व विकास रिपोर्ट* से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि हम अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद विश्व के विकसित देशों से कहीं पीछे हैं। टेलीफोन के क्षेत्र में अमरीका के पास सन् 2000 तक प्रति हजार व्यक्ति 700 टेलीफोन लाइनें थी, जर्मनी में 619 आस्ट्रेलिया में 525 और जापान में 586 लाइनें थी, वही भारत में इस शताब्दी के आरम्भ तक प्रतिहजार व्यक्ति कुल 32 लाइनें ही थी।

दूर संचार विभाग के अनुसार सितम्बर 2001 से सितम्बर 2002 के बीच भारत सरकार ने लगभग 90 626 ग्राम पंचायत टेलीफोन लगाए। मोबाइल फोन के करीब 32.5 लाख नये उपभोक्ता बने और सीमित मोबाइल सेवा लगभग 5 लाख नए उपभोक्ताओं तक पहुँची। पिछले एक वर्ष में 1 लाख 22 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर तार बिछाई गई। पिछले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन दरों में भारी कमी की गई है जिससे लोगों के बीच बेहतर सम्प्रेषण की संभावना बढ़ी है।

जनसंचार के क्षेत्र में एक अन्य क्रांतिकारी परिवर्तन तब हुआ जब खाड़ी युद्ध के दौरान भारत में केबल टेलीविजन का अचानक प्रसार हुआ। उपग्रह और केबल के उस मेल के चमत्कार ने केवल शहरों को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें उलटी छतरीयों के समूह दिखने लगे। उपग्रह और केबल टेलीविजन के इस विस्तार से जहाँ एक ओर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का एक साथ प्रचार आरम्भ हुआ वहीं दूसरी ओर हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को ऐसी तमाम सूचनाएँ और जानकारीयों भी मिलने लगी जिन पर पहले केवल शहरी सम्राट वर्गों की ही पकड़ थी। इस अर्थ में आजादी के बाद से ही पहले रेडियो और फिर टेलीविजन के प्रसार से सूचनाओं का जनतंत्रीकरण हुआ।

सम्प्रेषण और संचार के लिए प्रौद्योगिकी की मौजूदगी के अलावा साक्षरता की भी आवश्यकता होती है। भारत में आजादी के बाद शिक्षा और साक्षरता में काफी सुधार हुआ है। हालाँकि देश की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस क्षेत्र में होने वाला विकास बहुत कम लगता है। साक्षरता के इस व्यापक प्रचार-प्रसार की वजह से जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है वह है भारतीय भाषा की पत्रकारिता में तेजी से हुआ विकास।

सूचना प्रौद्योगिकी आज समाज की विभिन्न आवश्यकताओं का आधार बनती जा रही है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भले ही भारत में वर्ष 1998 तक प्रतिहजार व्यक्ति 27 कंप्यूटर एवं वर्ष 2000 तक प्रति दस हजार लोगों के बीच 0.23 इंटरनेट कनेक्शन ही थे परन्तु इस सबके बावजूद देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसकी भूमिका की अनिवार्यता से देश का हर व्यक्ति परिचित हो चुका है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजादी के समय के गाँवों और आज के गाँवों में सुविधाओं के नजरिये से जमीन-आसमान का अंतर है लेकिन आज भी संचार और जनसंचार की स्थितियों ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी नहीं है। वही दूसरी ओर महानगरों और शहरों में टेलीविजन दूरभाष मोबाइल-टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रसार गाँवों की तुलना में कहीं ज्यादा हुआ है। यही वजह है कि न केवल अमीर-गरीब के बीच की खाई बड़ी है बल्कि सुविधा सम्पन्न और सुविधा विहीन, विकास सम्पन्न और विकास रहित समाजों का अंतर भी भारत में स्पष्ट दिखाई देता है।

6.9 अध्ययन क्षेत्र में संचार एवं सूचना प्रसार

संचार माध्यमों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है *प्रथम- व्यक्तिगत संचार माध्यम* तथा *द्वितीय जनसंचार माध्यम*। व्यक्तिगत संचार माध्यम के अन्तर्गत डाक तार तथा दूरभाष आदि आते हैं। ये वैयक्तिक सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार से कृषि कार्यों एवं उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। रेडियो, टेलीविजन पत्र-पत्रिकाएँ तथा सिनेमा आदि जनसंचार के माध्यम हैं जो सूचना, ज्ञान विचारों भावनाओं तथा शिल्प आदि का संकेत-चिन्हों शब्दों चित्रों तथा आरेखों द्वारा प्रभावशाली प्रसारण करते हैं।¹⁴

(अ) व्यक्तिगत संचार

सम्प्रति जनपद में 276 डाकघर (ग्रामीण क्षेत्र में- 258 एवं नगरीय क्षेत्र में 18) 21 तारघर (ग्रामीण क्षेत्र- 11 नगरीय क्षेत्र-10) 35- टेलीफोन एक्सचेंज 668 पी सी ओ (ग्रामीण क्षेत्र- 407 एवं नगरीय क्षेत्र-261) तथा 5931 टेलीफोन कनेक्शन हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 615 एवं नगरीय क्षेत्र में 5316 कनेक्शन हैं। इसे सारणी 6.6 में विकास खण्ड स्तर पर प्रस्तुत किया गया है।

सारणी- 66
देवरिया जनपद में उपलब्ध संचार सेवाएँ

वर्ष	डाकघर	तारघर	पी सी ओ	टेलीफोन
1997 98	276	21	657	5901
1998 99	276	21	668	5931
1999 00	276	21	668	5931
विकासखण्ड वार (1999-2000)				
1 गौरीबाजार	17		25	8
2 बैतालपुर	16	1	4	43
3 देसही देवरिया	16	1	10	22
4 पथरदेवा	20	1	74	76
5 रामपुर कारखाना	10		6	25
6 देवरिया सदर	23		65	45
7 रुद्रपुर	20	2	17	12
8 भलुअनी	20	1	6	5
9 बरहज	17	1	51	42
10 भटनी	13		32	38
11 भाटपाररानी	12		30	69
12 बनकटा	14	1	38	100
13 सलेमपुर	22		26	72
14 भागलपुर	17	1	3	5
15 लार	21	2	20	53
योग ग्रामीण	258	11	407	615
नगरीय	18	10	261	5316
कुल जनपद	276	21	668	5931

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया- 2001 पृष्ठ 105

(1) डाक सेवा

भारत में आधुनिक डाक प्रणाली सर्वप्रथम 1837 में प्रारम्भ हुई। 1854 में डाक विभाग तथा 1880 में मनीआर्डर प्रणाली प्रारम्भ हुई। रेलवे डाक सेवा 1907 तथा हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारम्भ हुई। फलस्वरूप द्रुत डाक सेवा रिकार्डेड डिलीवरी और द्रुतगामी डाक सेवा (स्पीड पोस्ट) जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देवरिया जनपद इस विकास से अछूता नहीं है। जनपद में कुल डाकघरों की संख्या 276 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 258 डाकघर स्थित हैं। भारत में एक डाकघर से जहाँ औसतन 4731 लोगो को सेवाएँ प्राप्त होती हैं वही जनपद में 2001 की जनगणना के आधार पर प्रति 9892 लोगो पर एक डाकघर है, अर्थात् एक डाकघर राष्ट्रीय औसत से लगभग दूनी जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है, जो बहुत ही निम्न स्तर है। इस दृष्टि से देवरिया जनपद पिछड़ा हुआ है।

डाकघर खोलने के लिए गाँवों के एक समूह को चुना जाता है और इस समूह में से डाकघर की स्थापना के लिए उपयुक्त गाँव का चयन किया जाता है। गाँवों के समूह की कुल आबादी पहाड़ी पिछड़े हुए और जनजातीय क्षेत्रों में 1 500 या इससे अधिक तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3 000 या इससे अधिक होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में इस मानक के अतर्गत बहुत कम गाँव सम्मिलित हैं।

1995 से 2002 तक अध्ययन क्षेत्र में डाकघरों की संख्या यथावत (276) बनी हुई है जबकि आबादी लगातार बढ़ रही है। अध्ययन क्षेत्र में विकास खण्डवार बरहज की स्थिति सबसे अच्छी है यहाँ एक डाकघर 5 695 लोगों को सेवाएँ प्रदान करता है। परन्तु राष्ट्रीय औसत (4731) से यह भी काफी अधिक है। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर विकास खण्डों का क्रम क्रमशः निम्नवत है— लार भागलपुर सलेमपुर, देवरिया सदर देसही देवरिया, भलुअनी रुद्रपुर बनकटा बैतालपुर भटनी पथरदेवा गौरीबाजार भाटपाररानी और रामपुर कारखाना। रामपुर कारखाना में प्रति 12 248 लोगों पर एक डाकघर है जो सबसे बुरी स्थिति है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में डाकघर की सुविधा बहुत ही निम्न स्तर की है। जनसंख्या साक्षरता कृषि उद्योग आदि में निरन्तर वृद्धि हो रही है पर डाकघर में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव विकास पर पड़ता है। ये सब सेवाएँ विकास के प्रेरक हैं। अतः इन के पिछड़ने से क्षेत्रीय विकास अधोगामी हो जाएगा।

(2) तारसेवा

अध्ययन क्षेत्र में कुल तारघर की संख्या 21 है। इसमें 11 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10 नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रमशः रुद्रपुर एव लार में दो-दो तथा बैतालपुर देसही देवरिया, पथरदेवा, भलुअनी बरहज, बनकटा और भागलपुर में एक-एक तारघर है। नगरीय क्षेत्रों में— देवरिया गौराबरहज, लार रुद्रपुर मझौलीराज, भटनी बाजार, सलेमपुर भाटपाररानी रामपुर कारखाना और गौरीबाजार टाउनएरिया में एक-एक तार घर हैं। उपर्युक्त तथ्य से तार सेवा की अभावग्रस्तता एवं पिछड़ेपन का ज्ञान होता है।

(3) टेलीफोन सेवा

संचार के क्षेत्र में हुए तीव्र विकास से देवरिया जनपद भी अछूता नहीं है पर विकास अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। राष्ट्रीय औसत से यहाँ वर्तमान विकासदर बहुत दूर है। वर्तमान समय में जनपद में 5931 टेलीफोन कनेक्शन हैं। इसमें 5316 नगरीय क्षेत्र में तथा मात्र 615 ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ प्रति हजार व्यक्तियों पर 32 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है वही जिले में ये उपलब्धता मात्र 2.17 प्रति हजार ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कनेक्शन (100) बनकटा विकास खण्ड में है जबकि भागलपुर, भलुअनी में न्यूनतम पाँच-पाँच कनेक्शन ही उपलब्ध हैं। जनपद में वर्तमान में 35 टेलीफोन एक्सचेंज विभिन्न क्षमता के स्थापित हैं। इनकी

कुल कनेक्शन क्षमता 31 832 है। अतः वर्तमान क्षमता का यदि सम्पूर्ण विकास कर लिया जाय तब भी प्रति हजार व्यक्ति पर उपलब्धता 11 65 ही हो पायेगी, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 20 35 कम है। अतः इस क्षेत्र में तीव्र विकास की आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक कनेक्शन देवरिया में (4367) है जो कुल नगरीय क्षेत्र उपलब्धता का 82 14 प्रतिशत है।

(4) पी सी ओ

जनपद में सबसे कम विकास पी सी ओ का हुआ है। यहाँ कुल 668 पी सी ओ केन्द्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ प्रति हजार जनसंख्या पर केन्द्र की उपलब्धता 26 है वही जनपद में एक हजार जनसंख्या पर मात्र 0 24 प्रतिशत सेन्टर है। परन्तु नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से देखा जाय तो जहाँ नगरीय क्षेत्र में 261 पी सी ओ केन्द्र हैं वही ग्रामीण क्षेत्र में 407 केन्द्र स्थापित है। अर्थात् कुल स्थापित केन्द्र को 60 9 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति ग्रामीण रुझान व्यक्त होती है। जनपद में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज को उनकी क्षमता के साथ सारणी 67 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी- 67
जनपद में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज एवं उनकी क्षमता (2002)

क	एक्सचेंज का नाम	तहसील	पैरेंट एक्सचेंज क्षेत्र	संस्थापित क्षमता	
1	2	3	4	5	6
1	अहिरौली बघेल	सलेमपुर	सलेमपुर	R	184
2	बघउच	देवरिया	देवरिया	R	512
3	बैतालपुर	देवरिया	देवरिया	R	1000
4	बखरा	देवरिया	देवरिया	R	256
5	बलटीकरा	देवरिया	देवरिया	R	184
6	बगरा	भाटपाररानी	भाटपार	R	184
7	बरहज बाजार	बरहज बाजार	देवरिया	U	1400
8	बरियापुर	देवरिया	देवरिया	R	256
9	भागलपुर	सलेमपुर	सलेमपुर	R	184
10	भलुअनी	देवरिया	देवरिया	R	512
11	भटनी	भाटपाररानी	सलेमपुर	R	184
12	भाटपाररानी	भाटपाररानी	सलेमपुर	U	1000
13	भिगारीबाजार	भाटपाररानी	सलेमपुर	R	184
14	बिशुनपुरा	देवरिया	देवरिया	R	184
15	देवरिया	देवरिया	गोरखपुर	U	14000
16	देसही देवरिया	देवरिया	देवरिया	R	256
17	गौरीबाजार	देवरिया	देवरिया	U	1000
18	हेतिमपुर	देवरिया	देवरिया	R	256

19	खोराराम	देवरिया	देवरिया	R	256
20	खुखुन्दू	सलेमपुर	देवरिया	R	184
21	लार	सलेमपुर	सलेमपुर	U	1400
22	लार रोड	सलेमपुर	सलेमपुर	R	184
23	मदनपुर	रुद्रपुर	देवरिया	R	512
24	मईल	सलेमपुर	बरहजबाजार	R	256
25	ओलीपटी	देवरिया	देवरिया	R	184
26	पैना	बरहज	बरहज	R	256
27	पकडी बाजार	देवरिया	देवरिया	R	256
28	पथरदेवा	देवरिया	देवरिया	R	1000
29	प्रतापपुर	भाटपाररानी	सलेमपुर	R	184
30	रामलछन	रुद्रपुर	देवरिया	R	256
31	रामपुर कारखाना	देवरिया	देवरिया	R	512
32	रुद्रपुर	रुद्रपुर	देवरिया	U	1000
33	सलेमपुर	सलेमपुर	देवरिया	U	2400
34	सराव	देवरिया	देवरिया	R	256
35	सोनहुला रामनगर	देवरिया	देवरिया	R	1000

योग— 31832

स्रोत— जिला प्रबन्धक दूरभाष जनपद देवरिया के कार्यालय से प्राप्त

(ब) जनसंचार

इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इलेक्ट्रानिक्स के अन्तर्गत रेडियो दूरदर्शन तथा चलचित्र प्रमुख हैं। संगीत मनोरंजन शिक्षा समाचार विज्ञापन, सवाद सूचना आदि के प्रसारण के लिए रेडियो एक सस्ता और सशक्त माध्यम है। खेलो स्वतंत्रता दिवस गणतन्त्र दिवस व अन्य प्रमुख घटनाओं के आँखों-देखा हाल का प्रसारण रेडियो को और जीवन्त बना देता है। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम बम्बई और कलकत्ता के दो निजी स्वामित्व वाले ट्रांसमीटरों की सहायता से 1927 में हुआ। 1930 में सरकार ने इसे अपने हाथ में लेकर 'भारतीय प्रसारण सेवा' प्रारम्भ किया। 1936 में इसका नाम बदलकर 'ऑल इण्डिया रेडियो' रखा गया और 1957 के बाद से इसे 'आकाशवाणी' कहा जाता है। देवरिया जनपद के सम्पूर्ण भाग पर रेडियो प्रसारण पहुँचता है। जनपद के पश्चिम में स्थित गोरखपुर जनपद मुख्यालय पर आकाशवाणी का क्षेत्रीय केन्द्र है। यहाँ से तमाम सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसका आधार क्षेत्रीय सामाजिक संस्कृति ही होती है। अतः जनपद के लोग ऐसे कार्यक्रमों में विशेष रुचि लेते हैं। जनपद के प्रायः सभी परिवार रेडियो का लाभ लेते हैं। गोरखपुर आकाशवाणी केन्द्र से कृषि से सम्बन्धित तमाम जानकारियाँ समय-समय पर प्रसारित होती हैं। इससे किसान अपनी कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान पाते हैं। इसने परोक्ष रूप से कृषि विकास में बड़ा लाभ पहुँचाया है।

(1) दूरदर्शन

दूरदर्शन जनसंचार का एक सशक्त दृश्य-श्रव्य माध्यम है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत सितम्बर 1959 में हुई जब एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्र खोला गया। अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत आता है। जनपद के समीपस्थ गोरखपुर में दूरदर्शन का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित हो जाने से अब दूरदर्शन प्रसारण में क्षेत्रीय प्रसारणों को भी प्रमुखता मिलने लगी है जिनका आधार क्षेत्रीय समस्याएँ होती हैं। कृषि-दर्शन कार्यक्रम कृषकों के लिए विशेष लाभकारी है। चूँकि दूरदर्शन सेट अपेक्षाकृत महंगे हैं साथ ही अध्ययन क्षेत्र में विद्युत का भी अभाव है। अतः कुछ सम्पन्न वर्ग ही इस सुविधा का उपयोग कर पा रहे हैं।

(2) चलचित्र

चलचित्र भी जनसंचार का सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक राजनीतिक व धार्मिक समस्याओं तथा निदान के अभिप्रेरण हेतु उसका चित्रण लोगों तक पहुँचाया जाता है। जनपद में वर्तमान में 16 चलचित्र गृह स्थापित हैं जिसमें सीटों की कुल संख्या 8338 है।

(3) समाचार पत्र

जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम मुद्रण भी है। हाल के वर्षों में साक्षरता में सुधार के कारण लोगों में ये माध्यम काफी लोकप्रिय होने लगा है। क्षेत्र के लोगों में राजनीति के प्रति दिलचस्पी के कारण इस माध्यम को और लोकप्रियता हासिल हुयी है। जनपद में राष्ट्रीय स्तर का कोई भी समाचार पत्र उसी दिन या एक दिन बाद प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः प्रत्येक चाय की दुकानों, होटलों आदि में समाचार पत्रों के उपलब्धता से वहाँ आने जाने वाले लोग इसे पढ़ लेते हैं। फिर भी क्षेत्र की आर्थिक बदहाली और निम्न शैक्षणिक स्तर के कारण अपेक्षाकृत निम्न आयवर्ग के लोग एवं श्रमिक वर्ग तक इसका लाभ नहीं पहुँच सका है। वर्तमान समय में जनपद में मुद्रणालयों की संख्या 48 है। ये सभी निजी क्षेत्र में हैं।

6.10 परिवहन एवं संचार का नियोजन

क्षेत्र के विकास में परिवहन के विभिन्न साधनों तथा संचार के विभिन्न माध्यमों के विश्लेषण के उपरान्त विश्लेषण क्रम के अनुरूप ही क्रमशः परिवहन एवं संचार माध्यम प्रतिरूप के लिए नियोजन की परिकल्पना अपेक्षित है। वैसे इस दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही हैं परन्तु अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन तक योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। अतः उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए नियोजन निम्नवत् प्रस्तुत है।

(क) परिवहन तंत्र का नियोजन

अध्ययन क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय परिवहन में सर्वप्रमुख सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग ही है। इन दोनों में सड़क मार्ग की भूमिका क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण है। अध्ययन क्षेत्र के समतल होने तथा सड़को के पर्याप्त विकास के बावजूद अभी भी अनेक ऐसे सेवाकेन्द्र हैं जो पक्की सड़को से सम्बद्ध नहीं हैं। 1999-2000 तक जनपद में 101 ग्राम ऐसे थे जो पक्की सड़को से 5 किमी की दूर पर स्थित हैं जिस कारण यातायात एवं विपणन सम्बन्धी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जहाँ तक कच्ची-पक्की सड़को से ग्रामों की सम्बद्धता का प्रश्न है तो जनपद के 47.87 प्रतिशत गाँव अभी भी असम्बद्ध हैं। सबसे अधिक असम्बद्धता भलुअनी (70.77 प्रतिशत) एवं बैतालपुर (62.21 प्रतिशत) विकास खण्डों में पायी जाती हैं। जहाँ तक मार्ग-जाल की सम्बद्धता का सवाल है तो ग्रामीण मार्गों के स्तर पर यह बहुत ही निम्न है। जबकि सेवाकेन्द्रों का ग्रामीण विकास में लाभ ग्रामीण सड़को के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यातायात प्रवाह सड़क सम्बद्धता पर ही निर्भर करता है। सड़क सम्बद्धता के अभाव में यातायात प्रवाह भी निम्न स्तर का है। अतः जनपद के समाकलित विकास के लिए परिवहन सुविधाओं का बढ़ाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एक समन्वित कार्य योजना अपेक्षित है।

(अ) रेलमार्ग नियोजन

अध्ययन क्षेत्र समतल भू-भाग तथा घना बसाव का क्षेत्र है। इसके बावजूद रेलमार्ग की जनपद में लम्बाई मात्र 111 किमी ही है। ये रेललाइन भी इकहरी है। अतः अध्ययन क्षेत्र में अवस्थित सम्पूर्ण रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ यात्री परिवहन एवं मालगाड़ी की परिचालन क्षमता बढ़ेगी बल्कि सुदूर राज्यों में स्थित कोयला खनिज आदि को जनपद में मगाना भी सुगम हो जाएगा जिनमें यह क्षेत्र निर्धन है। फलतः कई नये उद्योग अवस्थापन प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावे सलेमपुर से बरहज वाली लाइन का विस्तार रुद्रपुर तक करना अपेक्षित है। इससे क्षेत्र का विकास प्रोत्साहित होगा।

(ब) सड़क मार्ग नियोजन

अध्ययन क्षेत्र में सड़क मार्ग परिवहनतंत्र का आधार है। सर्वप्रथम वर्तमान पक्की सड़को में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही व्यस्त सड़को को चौड़ा करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत देवरिया-तरकुलवा मार्ग (एसएच 79) एवं राज्य उच्चपथ सख्या-1 जो गौरी बाजार-देवरिया-सलेमपुर से होकर गयी है को दोहरी करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में सलेमपुर से लार के मध्य अन्य जिलामार्ग को राज्य उच्चपथ जितनी ही चौड़ाई और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर बनाना अपेक्षित है। रुद्रपुर से गौरीबाजार तथा रुद्रपुर-देवरिया मार्ग भी चौड़ा करने की जरूरत है।

जनपद के बनकटा विकास खण्ड का पूर्वी क्षेत्र बरहज भागलपुर लार एवं रुद्रपुर

विकास खण्डवार विभिन्न प्रकार के सडको की लम्बाई

विकास खण्ड	सडक की कुल लम्बाई (किमी)				कुल
	ऊपरी काली सतह (B-T)	पत्थर-बैसाल्ट कुटाई की सतह (WBM)	खडजा (Gravel)	कच्ची सतह (Track)	
1 बैतालपुर	128 50	17 70	50 45	70 53	267 18
2 बनकटा	103 60	11 70	45 50	38 50	199 30
3 बरहज	69 80	4 30	19 70	19 50	113 30
4 भागलपुर	130 50	10 00	72 80	10 00	223 30
5 भलुअनी	85 29	9 40	53 00	26 25	173 94
6 भटनी	107 80	7 70	25 60	22 50	163 60
7 भाटपाररानी	100 74	9 76	60 75	40 55	211 79
8 देवरिया	124 50	6 20	39 80	22 60	193 10
9 देसही देवरिया	70 20	6 10	25 90	21 20	123 40
10 गौरीबाजार	119 25	25 80	28 50	22 00	195 55
11 लार	95 00	7 95	52 90	30 00	185 85
12 पथरदेवा	143 75	4 40	59 10	9 90	217 12
13 रामपुर कारखाना	122 17	8 00	23 80	36 15	190 12
14 रुद्रपुर	73 50	17 63	35 45	41 01	167 59
15 सलेमपुर	132 50	10 10	53 20	35 00	230 80
कुल योग	1607 07	156 74	646 45	445 69	2855 94

स्रोत- पीडब्लूडी विभाग देवरिया से प्राप्त

विकासखण्ड का दक्षिणी भाग घाघरा एव राप्ती के बाढ़ से बरसात में काफी समस्याग्रस्त हो जाता है। जनपद के शेष भाग से इसका सडक सम्पर्क खडजा सडको एव कच्ची सडको के जल समाधि के कारण टूट जाता है। पूरे जनपद में पत्थर और बैसाल्ट कुटाई वाली सडको की लम्बाई 156 45 किमी है। खडजा सडको की लम्बाई 646 45 किमी है। अतः इन सभी सडको को पक्की सडको में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि बरसात के दिनों में अपरदन से बस्तियों की सडको से अभिगम्यता और कम हो जाती है। विगत वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अनेक गाँवों को खडजा मार्ग से पक्की सडको से जोड़ा गया। किन्तु मार्गों पर जैविक अपरदन (पशुओं से) व यात्रिक अपरदन (ट्रैक्टर व बैलगाड़ी से) होने से उद्देश्यों को पूरा करने में असफल है। अतः इन सभी लघु सम्पर्क मार्गों को पक्की सडक में बदलने की जरूरत है। अध्ययन क्षेत्र की पक्की सडको खडजा सडको एव कच्ची सडको की विकास खण्डवार लम्बाई सारणी 68 में प्रस्तुत है।

(स) ग्रामीण सड़क मार्ग

ग्रामीण सड़क ग्रामीण विकास का आधार है। अध्ययन क्षेत्र की 90 14 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को नगरी औद्योगिक केन्द्रों विकास केन्द्रों तथा मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल होना आवश्यक है। कृषि उपज तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों की विपणनीय सुविधाएँ ग्रामीण सड़कों पर बहुत निर्भर करती हैं। गाँवों को सड़कों द्वारा मण्डियों से जोड़कर गाँवों का बहुमुखी विकास किया जा सकता है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के पिछड़ेपन को ग्रामीण सड़कों के अभाव ने और पिछड़ा बना दिया है।

ग्रामीण बस्तियों की सेवाकेन्द्रों एवं पक्की सड़कों से सम्बद्धता की विकास के लिए अनिवार्यता महसूस करते हुए जनपद में सरकारी स्तर पर अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इनमें 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु जिला योजना *पूर्वांचल विकास निधि* के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार की एक योजना— *पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग* के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न भागों में 19 10 किलोमीटर मार्गनिर्माण का कार्य चल रहा है।¹⁵ इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाकेन्द्रों एवं पक्की सड़कों से सम्बद्ध कर सड़कों की अभिगम्यता एवं सबद्धता वृद्धि द्वारा गाँवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार की *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* जनपद में क्रियान्वित हो रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

यद्यपि पिछले पॉच दशकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क हेतु सड़कों का लगातार विकास हुआ है। इसके बावजूद खुद सरकार ने माना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों की कमी देश के वास्तविक विकास में बड़ी बाधा है। आजादी के 54 वर्षों बाद भी देश के 40 फीसदी गाँव अभी भी बारहमासी सड़क सम्पर्क से कटे हैं। बारहमासी सड़क सम्पर्क से वंचित गाँवों की संख्या 2 5 लाख से ज्यादा है। इनको सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए ही 25 अक्टूबर 1999 को *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है।¹⁶

इसके लिए धन जुटाने के उद्देश्य से सरकार ने अप्रैल-2000 में कैबिनेट के फैसले के अनुरूप डीजल की बिक्री पर 1 रुपये का अधिभार लगाया जिसका 50 प्रतिशत *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के लिए रखा जाना तय था। इस प्रकार 2000-2001 के वित्तीय बजट में इस मद में 60 हजार करोड़ रुपये की रकम रखी गयी। इस रकम को केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को देकर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की निगरानी में योजना को कार्यान्वित करा रही है। इसके लिए आरम्भ हुए सड़क-निर्माण कार्य को 9 से 12 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित समय सीमा में पूरा न करने वाले राज्यों पर अनुदान में कटौती के रूप में दण्डात्मक प्रावधान भी किया गया है।¹⁷

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2002) (स्वीकृत/मार्गों की सूची)

क्र	पैकेज स संख्या	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी)	स्वीकृत लागत (लाख रु)	ब्लाक का नाम
1	2603	जमुआ मगहरा से मधवापुर	2 400	52 61	सलेमपुर
2	2603	आनन्दनगर देसही देवरिया से कवलाछापर मार्ग	2 000	47 96	देसही देवरिया
3	स्पे पै 26	मदनपुर देवकली जयराम से सेहुदामानस	6 300	121 84	रुद्रपुर/भलुअनी
4	स्पे पै 26	देवरिया पकडी से सिसवा मार्ग	2 500	45 69	भलुअनी
5	2604	हेतिमपुर रम्हौली-सहोदरपटी-रामपुर जगदीश मार्ग	3 100	87 50	देसही देवरिया
6	2604	गोरखपुर देवरिया से कालाबवन मार्ग	2 100	47 75	गौरीबाजार
7	2604	बाबा मोहन से समोगर	1 000	18 63	बरहज
8	2604	पकडी बगरा-मिश्रौली-नोनार कपरवार मार्ग	1 600	43 96	बनकटा
9	2604	पुरुषोत्तमा करमेल से बर्दगोनिया मार्ग	2 606	47 70	गौरीबाजार
10	2605	मदनपुर से केवटलिया मार्ग	2 700	67 21	रुद्रपुर
11	2605	बगरा महुआरी से शाहपुर पुरैनी मार्ग	2 000	39 48	पथरदेवा
12	2605	बघौचघाट सेमरी से बसडीला जदूघोडी मार्ग	2 000	48 03	पथरदेवा
13	2605	अमारी गोठा से रसूलपुर सुरचक मार्ग	2 000	45 05	बैतालपुर/देसही
14	2605	बारीहपुर शिवाजी चौराहा-आमघाट चौहान टोला मार्ग	2 600	54 91	देवरिया रामपुर कारखाना

स्रोत- पी डब्ल्यू डी विभाग जनपद देवरिया से प्राप्त सितम्बर 2002

इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश को सर्वाधिक 315 करोड़ रुपये की राशि 2000-2001 के दौरान प्राप्त हुयी है।¹⁸ इस योजना के अतर्गत जनपद के विभिन्न भागों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान में 14 मार्गों (34 90 किमी) पर मार्ग निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। ये निम्न हैं- (सारणी न 69 में)।

ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की इस महत्वपूर्ण योजना को पंचायतो के माध्यम से लागू किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक लालफीताशाही स्थानीय राजनीतिक गुटबाजी और बदहाल ठेकेदारी से इस योजना का पूरा लाभ मिल पाने में सन्देह है। पिछले दिनों इसी योजना के तहत झारखण्ड प्रदेश के गोड्डा जिले में बनी ग्राम सड़क बरसात में एक भी मौसम नहीं झेल पायी और आठ लाख रुपये की लागत से बनी यह सड़क एक झटके में 'परनाला' में तब्दील हो गयी। पिछड़े और आदिवासी बहुल ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली के किस्से प्रशासन तक पहुँचाने के लिए सड़क पर ही धान के पौधे रोप दिए। यदि जनपद में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की समीक्षा करें तो यह प्रवृत्ति यहाँ भी दिखायी देती है। बाढ़ की आवृत्ति वाले क्षेत्रों में बनी सड़कों में घोर घोंघली होती है। बाढ़ के बाद जब सड़क का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे आसानी से बाढ़ का ग्रास साबित कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ के अधिकारी,

इन्जीनियर और ठेकेदार योजनाओं के लिए आवंटित पैसे से लाल हो रहे हैं तथा विकास ठूँठ बना हुआ है।

इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है कि कैसे इस योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाया जाय। गोडडा जिले की एक घटना तो वहाँ के ग्रामीणों के चलते उजागर हो गयी पर यह महत्वपूर्ण है कि गोडडा की तरह कितने गाँवों के लोग अपना मामला उठाएंगे? इसके लिए जागरूकता एवं नीतिगत उपाय करने होंगे। इस योजना के अंतर्गत 2003 तक 1000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव को तथा 2007 तक 500 की जनसंख्या वाले गाँवों को बारहमासी अच्छी सड़कों से जोड़ने की योजना है। ग्रामीण सड़कों से सम्बन्धित निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं—

- 1— जो भी सड़कें बने उन्हें परिवहन मानकों के अनुसार बनाया जाय।
- 2— गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सभी सहायक खडजा सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाय।
- 3— गाँवों में परिवहन के साधनों में मोटर परिवहन का तेजी से विकास हो रहा है अतः सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था नियमित होनी चाहिए।
- 4— सड़क जाल इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी गाँवों का सम्पर्क सेवाकेन्द्रों से हो जाय।
- 5— सड़कों के विकास के लिए ऐच्छिक श्रम अर्थात् श्रमदान को प्रोत्साहित किया जाय।
- 6— राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय तथा रखरखाव की नियमित जिम्मेदारी बाँट दी जाय। इस कार्य में ग्राम पंचायतों एवं सहकारी संस्थाओं का व्यापक सहयोग लिया जा सकता है।
- 7— सड़क निर्माण की लागत गुणवत्ता और कार्य के प्रति ठेकेदार समेत अधिकारी और अभियन्ता को जवाबदेह बनाया जाय, ताकि उसका वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक पहुँच सके।

(ख) संचार तंत्र का नियोजन

किसी भी क्षेत्र के विकास की संकल्पना में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनपद में संचार माध्यमों की उपलब्धता बहुत ही निम्न स्तर की है। अतः क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथमतः सुनियोजित संचार तंत्र की स्थापना अनिवार्य है। इसमें संचार के प्राचीनतम माध्यम (डाक तार आदि) एवं नवीनतम तकनीकी माध्यमों (टेलीफोन, कंप्यूटर, इन्टरनेट दूरदर्शन रेडियो) का इस प्रकार समन्वय हो कि ये परस्पर एक दूसरे को पूरक बन सकें,

क्योंकि विकास में सबके लिए एक सुनिश्चित भूमिका है। इन सभी माध्यमों का विकास कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारकों से अंतर्सम्बन्धित है। जैसे— शिक्षा—साक्षरता का विकास सुसम्बद्ध एवं अभिगम्य परिवहन तंत्र एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता। अतः प्रथमतः उपर्युक्त सुविधाओं का जनपद में विकास किया जाय तथा उसके बाद जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सुविधाओं की क्षेत्र में स्थापना की जाय। जैसे— अध्ययन क्षेत्र में डाकघरों एवं तारघरों की संख्या अपेक्षित स्तर तक नहीं है। अतः प्रत्येक ग्राम को सड़कों से सम्बद्ध कर अपेक्षित स्तर तक डाकघरों की स्थापना की जाय साथ ही पत्रों का नियमित वितरण सुनिश्चित की जाय। इसमें ग्रामप्रधान का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि टेलीफोन पीसीओ की सुविधा नगरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक है फिर भी इनकी संख्या कम है। अतः प्रत्येक ग्राम में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय इसके लिए जनपद में अपेक्षित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कर क्षमता में वृद्धि अपेक्षित है। टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या जनसंख्या के अधिकांश भागों तक पहुँचे इसके लिए केन्द्रीय स्तर भी आयोजना में सुधार की आवश्यकता है। प्रायः टेलीफोन प्रसार का ठेका किसी व्यावसायिक कम्पनी को ही दिया जाता है। अतः जहाँ सरकार की प्राथमिकता अधिकतर लोगों तक टेलीफोन की सुविधा पहुँचाना होता है वही कम्पनियों की प्राथमिकता अधिकतम लाभ कमाना होता है जिस कारण वह शहरों में व्यवसाय करने में दिलचस्पी लेती है। फलतः गाँव सुविधा से वंचित रह जाता है। अतः किसी भी कम्पनी को बड़े शहरों में दूरसंचार का ठेका इस शर्त के साथ दिया जाय कि वह आस-पास के गाँवों के एक निश्चित क्षेत्रफल को भी अपनी सेवाएँ मुहैया कराएँगे। सूचना के आधुनिकतम प्रौद्योगिकी माध्यम विद्युत सुलभता एवं शिक्षा के विकास पर भी अवलम्बित है, अतः जनपद में शिक्षा एवं विद्युत उपलब्धता की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इसके लिए प्रत्येक गाँव तक पहले बिजली को पहुँचाया जाय। वर्तमान में कुल आबाद गाँवों (1990) में से 1437 गाँवों तक ही बिजली पहुँची है। अर्थात् अभी भी 27.78 प्रतिशत गाँव अधरे में जी रहे हैं।

शिक्षा के विकास से ही सम्बन्धित एक और सूचना माध्यम है वह है *समाचार पत्र*। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के बावजूद आज भी वास्तविक *देवरिया* गाँवों में ही बसा है। शिक्षा के अभाव में समाचार पत्र सूचना का सशक्त—माध्यम नहीं बन पाया है। इसके पीछे अन्य कारणों के अलावा एक कारक सीधे समाचार पत्र के उद्देश्य एवं गुणवत्ता से ही सम्बन्धित है। आज समाचार पत्रों का उद्देश्य लोकहित तथा लोक कल्याण से सम्बन्धित समस्याओं को उजागर करना न होकर व्यावसायिक होता जा रहा है। इसके पीछे रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रायः सभी पत्रों में चुनाव किसान रेलियों एवं राजनीतिक समाचारों को ही प्रमुखता मिलती है। इनके साथ-साथ गाँव के लोगों विशेषकर वहाँ के कमजोर वर्गों की वास्तविक सामाजिक—आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना तथा उन उपायों का मूल्यांकन करना ग्रामीण रिपोर्टिंग का मुख्य

उद्देश्य होना चाहिए जो इन समस्याओं को हल करने और कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए किये जा रहे हैं।

संचार आयोजना के लिए जरूरी है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत विशिष्टता और प्रभुसत्ता का सदा भान रहे। इसमें आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन की ग्राह्यता के साथ-साथ परम्परा की निरन्तरता को जीवन्त बनाए रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। यद्यपि रेडियो दूरदर्शन और फिल्म के विपरीत प्रेस जैसे सशक्त माध्यम को स्थापित होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि आधारभूत ढाँचे का विस्तार मात्र ही इसके विकास के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रकाशित सामग्री को पढ़ने के लिए क्षमता और रुचि का विकास करना। इसके लिए प्रथमतः साक्षरता को उच्च स्तर तक विकसित करना होगा। इस प्रकार जनसम्पर्क माध्यम और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी प्रासंगिक और लचीली गैर विशिष्ट वर्गीय और सहभागिता के दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्र के लोगों को सहभागी लोकतन्त्र के लिए सक्षम बनाने तथा विकासोन्मुखी समाज की शुरुआत करने के लिए संचार नियोजन और जनसम्पर्क माध्यमों की नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

★★★★★

References

- 1 कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2002 पृष्ठ 36
- 2 कुरैशी एमएच भारत का भूगोल ससाधन तथा प्रादेशिक विकास एन सी ई आर टी 1978 पृ 100
- 3 मिश्र एस के व पुरी वी के भारतीय अर्थव्यवस्था 2000 पृ 867
- 4 कुरैशी एमएच भारत ससाधन और प्रादेशिक विकास एन सी ई आर टी 1990 पृ 102
- 5 वही पृ 101
- 6 सिंह जगदीश परिवहन तथा व्यापार भूगोल 1977 पृ 4
- 7 Thomas, R L 'Transporation and Development of Malaya', A A A G Vol 65, No 2, p 67
- 8 Qureshi M H , 'India Reources and Regional Development', N C E R T, New Delhi, 1990, p-67
- 9 'कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2002 पृ 38
- 10 Singh, J 'Parivahan and Vyapar Bhoogol', Uttar Pradesh Hindi Sansthan Lucknow 1977, p-149
- 11 Babu, R , 'Micro-level Planning- A case study of chhibramu Thasil', Unpublished Ph D Thesis, Geography Deptt , Allahabad University, 1981, p 244
- 12 Ibid, p 245
- 13 Ibid, p 246
- 14 Parakh, Bhalchandra Sadashive, 'India Economic Geography', N C E R T, New Delhi, p 151
- 15 मुख्यमंत्री की साप्ताहिक समीक्षा से सम्बन्धित 33- बिन्दुओं का प्रगति विवरण जनपद- देवरिया फरवरी- 2002
- 16 'कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2002 पृष्ठ- 36
- 17 वही- पृष्ठ- 37
- 18 वही- पृष्ठ- 37





अध्याय-सात



सेवाकेन्द्र तथा सामाजिक सुविधाओं का विकास

7.1 सेवाकेन्द्र एवं सामाजिक बुनियादी क्षेत्र

किसी भी क्षेत्र का विकास दो स्तरों पर प्रतिबिंबित होता है— प्रथम मानवीय विकास स्तर पर तथा द्वितीय क्षेत्रीय विकास के स्तर पर। दोनों क्षेत्रों के विकास स्तर मापन के अपने-अपने प्राचल हैं परन्तु सर्वांगीण विकास दोनों के सतुलित विकसित स्वरूप से ही झलकता है। मानवीय विकास के बिना क्षेत्रीय विकास विरोधाभास पैदा करता है जिससे विकास बाधित होता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी क्षेत्र में निवेश अनिवार्य होता है। उपर्युक्त आधार पर इसे दो क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है— आर्थिक बुनियादी क्षेत्र और सामाजिक बुनियादी क्षेत्र। आर्थिक बुनियादी क्षेत्र में निवेश मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को समर्थन और बढ़ावा देता है। इसके घटक बिजली, दूरसंचार, सड़क, बदरगाह, परिवहन, जलापूर्ति तथा स्वच्छता हैं। जबकि सामाजिक बुनियादी क्षेत्र में स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक, वैधानिक और प्रशासनिक प्रणाली तथा वाणिज्यिक एवं सस्थागत ढाँचा शामिल है। ये दोनों क्षेत्र न सिर्फ एक-दूसरे के पूरक हैं। बल्कि कृषि और खनन जैसे बुनियादी क्षेत्र और उत्पादन जैसे द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक-दूसरे पर निर्भर हैं। चूँकि बुनियादी क्षेत्र आम आदमी को सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसलिए जीवन-स्तर के निर्धारण में इसका सीधा हस्तक्षेप है। इस तरह बुनियादी क्षेत्र किसी राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का स्तर तथा प्रकृति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ ऐसे मुद्दे जो बुनियादी क्षेत्र के उपर्युक्त समर्थन के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं निम्न हैं—¹

- 1 उत्पादन में विविधता और व्यापार का विस्तार।
- 2 जनसंख्या नियन्त्रण और निर्धनता में कमी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- 3 संसाधनों का प्रभावी आबंटन और
- 4 पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाना।

पिछले अध्याय के अंतर्गत विकास में आर्थिक बुनियादी क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में विकास में सामाजिक बुनियादी क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत है। मानवीय विकास के बिना क्षेत्रीय विकास अधूरा है, अतः मानवीय विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र में निवेश तथा स्थितियों की पड़ताल अपेक्षित है।

सामाजिक क्षेत्र में निवेश का लाभ प्रत्यक्ष नहीं मिलता है इसीलिए इसे प्रायः अनुत्पादक विनियोग भी कह दिया जाता है। यह अप्रत्यक्ष विनियोग ही विकास का आधार स्तम्भ है तथा विकास की दीर्घकालीन रणनीति इन्हीं विनियोगों पर आश्रित होती है। प्रधान रूप में इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन जैसी सामाजिक सुविधाओं को ही शामिल किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में विकास का विश्लेषण इन्हीं प्रमुख सुविधाओं के सन्दर्भ में किया गया है। इनमें विनियोग मनुष्य की कार्यकुशलता की वृद्धि में अभिप्रेरण होने के कारण इस महत्वपूर्ण तथा उत्पादक विनियोग के अन्तर्गत गिना जाने लगा है।¹² इन सामाजिक सुविधाओं को विकास का सूचक माना गया है। इसलिए सामाजिक सुविधाओं के विकास को सम्पूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मानव का सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं से प्रभावित होता रहता है। ये सुविधाएँ सेवाकेन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि इनकी इकाइयों सेवाकेन्द्रों पर ही स्थापित होती हैं। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सविधान निर्माताओं ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित तथ्यों को *मौलिक अधिकारों* एवं *राज्य की नीति निर्देशक तत्वों* के अन्तर्गत समाहित किया है।¹³

मनुष्य की मूल आवश्यकताओं— भोजन, कपड़ा और मकान— के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान है। उत्तम स्वास्थ्य व शिक्षा से ससाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। सीमित ससाधनों को विकसित किया जा सकता है तथा नये ससाधनों को खोजा जा सकता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं दो तथ्यों (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) को अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में विश्लेषित किया गया है।

(क) शिक्षा विकास

7.2 शिक्षा—महत्व एवं विकास

शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक और भावात्मक विकास का एक अनवरत प्रयास है जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़े, दृष्टिकोण समतुलित और सकारात्मक बने और वह एक उपयोगी एवं उत्तरदायी व्यक्ति बनकर परिवार, समाज और देश के जीवन में अपनी भूमिका निभा सके। महात्मा गाँधी ने इसी उद्देश्य से कहा— *शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।*¹⁴

शिक्षा विकसित समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। विश्व के लगभग सभी समाजों और सभी कालों में शिक्षा का महत्व स्वीकार किया गया न केवल स्वीकार ही किया गया बल्कि उसके प्रसार के लिए समुचित और वास्तविक व्यवस्था भी की गई। जिन समाजों में शिक्षा का आलोक नहीं फैला वे कूप—मडूक और अतीत जीवी बने रहे।

वस्तुतः शिक्षा हमें आधुनिक सभ्यता की उपलब्धियों को जानने समझने और उन्हें आत्मसात् करने के योग्य बनाती है अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों से जोड़ती है। और चाहे हम किसी भी कार्य व्यापार से सम्बद्ध क्यों न हों— उनसे जुड़ी उपयोगी तकनीक के दैनिक जीवन में प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। यह हमारी विश्लेषण क्षमता और तर्क बुद्धि का विकास करती है और सही-गलत का निर्णय कर पाने का विवेक पैदा करती है।

55 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। 1951 में देश की मात्र 18.33 प्रतिशत आबादी साक्षर थी लेकिन विगत आधी शताब्दी के सुनियोजित प्रयास से इस स्थिति में काफी बदलाव आया है। संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 से अर्जित शक्ति और प्रेरणा से अनुप्राणित सर्वशिक्षा की 93 वें संविधान संशोधन तक की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जहाँ ठहर कर हमारे नीति-निर्माताओं ने हासिल उपलब्धियों और शेष लक्ष्य का मुआयना किया अनुभवजनित संशोधन किए और पुनः लक्ष्योन्मुख हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1976 का संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 93 वें संविधान संशोधन 2001 जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना माता-पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व बना दिया गया है ⁵— ये इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। अब शिक्षा प्राप्त करना न केवल सरकार की वरन् माता-पिता और सरकार दोनों की सम्मिलित जिम्मेदारी है।

इन प्रयासों का ही परिणाम है कि 1991 से 2001 के दशक में साक्षर नागरिकों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है और 1991 के 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में साक्षरों की कुल आबादी 65.38 प्रतिशत हो गई है। मात्र एक दशक में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि बीती सदी के अन्य किसी भी दशक की तुलना में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि पहली बार देश के कुल निरक्षर लोगों की संख्या में कमी आयी है अन्यथा अब तक निरक्षर लोगों के प्रतिशत में तो कमी आती थी लेकिन आबादी बढ़ने के साथ-साथ प्रत्येक दशक में निरक्षरों की कुल संख्या बढ़ती ही जाती थी। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। शिक्षा और साक्षरता के प्रसार की यह गति पूरे देश में एक जैसी अग्रगामी नहीं है। 1991-2001 के दौरान जहाँ राजस्थान तथा दादरा और नागर हवेली में साक्षरों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है, वहीं अनेक राज्यों की प्रगति अधोगामी रही है। उत्तरप्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

7.3 साक्षरता—परिभाषा एवं प्रयास

न्यूनतम शैक्षिक निपुणता को साक्षरता कहते हैं। साक्षरता के आधार एवं परिभाषा भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न अपनायी गयी है किन्तु सर्वत्र निम्न दो तथ्यों में से किसी न किसी को अवश्य स्वीकार किया गया है। *प्रथम*— विद्यालयी शिक्षा अवधि तथा *द्वितीय*—किसी भी प्रचलित भाषा में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की योग्यता। 'संयुक्त राष्ट्र सघ जनसंख्या आयोग' ने किसी भी भाषा में साधारण सदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है।⁶ भारतीय जनगणना में लगभग इसी परिभाषा को स्वीकारोक्ति के साथ कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा में लिखना पढ़ना और गणित की दृष्टि से 1 से 100 तक गिनना और सरल जोड़ घटाव गुणा और भाग जानता हो वह साक्षर है।⁷ इस प्रकार वह व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लिख नहीं सकता साक्षर नहीं है। 1981 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार 0—4 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया था। किन्तु 1991 और 2001 की जनगणना में 0—6 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना गया है। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों के लिए सन् 2005 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। केन्द्रीय योजनाओं में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988 से आरम्भ) मध्याह्न भोजन योजना (1995 से आरम्भ) तथा प्राथमिक विद्यालय को साधन सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से 1987—88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारम्भ की गयी। इनके अतिरिक्त हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्रदेश में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है।

साक्षरता में वृद्धि के लिए प्रदेश स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश भर के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल लाने का अभियान जुलाई 2001 से 'स्कूल चलो अभियान' के नाम से आरम्भ की गयी है। इस अभियान की सफलता से प्रेरित होकर राज्य सरकार इसे सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित कर रही है। 'सभी के लिए शिक्षा परियोजना' के अन्तर्गत प्रदेश में 49 जिलों में विभिन्न प्रकार की बाह्य सहायता योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं में बेसिक शिक्षा परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख हैं। 'शिक्षा गारंटी योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक प्राथमिक विद्यालय से वंचित प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रयास किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'शिक्षा मित्र योजना' भी संचालित की गई है। इस वर्ष (2002) प्रदेश सरकार द्वारा 'प्रदेश शिक्षा नीति' तैयार की जा रही है। प्रदेश की अपनी शिक्षा नीति बन जाने से प्रदेश में समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों एवं वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी योजनाएँ, गुणात्मक शिक्षा के लिए

समुचित प्रयास समुचित शैक्षिक विकास हेतु उपयुक्त प्रकार से शैक्षिक नियोजन उत्तरदायित्वपूर्ण शैक्षिक प्रबंधन एवं परीक्षा पद्धति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किया जाना संभव हो सकेगा।

7.4 अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा एवं साक्षरता विकास

जनपद में 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का 59.7 प्रतिशत पुरुष तथा 20.9 प्रतिशत स्त्री एवं नगरीय जनसंख्या का 75.1 प्रतिशत पुरुष तथा 48.5 प्रतिशत स्त्री साक्षर रही है। इस प्रकार 1991 में जनपद में कुल जनसंख्या का 61.4 प्रतिशत तथा 23.4 प्रतिशत स्त्री साक्षर थी। कुल साक्षरता का प्रतिशत 42.3 था जबकि उस समय प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 42.42 था परन्तु वर्तमान समय में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जहाँ प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है वही जनपद की साक्षरता दर 59.84 प्रतिशत हो गयी है। वर्तमान में प्रदेश में पुरुष और स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 70.23 और 42.98 है जबकि ये प्रतिशत जनपद में क्रमशः 76.31 और 43.56 है। इस प्रकार 1991 से 2001 के मध्य जनपद की साक्षरता में व्यापक वृद्धि दर्ज की गयी है। इस बीच कुल साक्षरता में 17.54 प्रतिशत पुरुष साक्षरता में 14.91 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता में 20.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस बीच प्रदेश की कुल साक्षरता में वृद्धि मात्र 14.94 प्रतिशत ही रही। इस प्रकार जनपद में साक्षरता बढ़ाने के कार्यक्रमों का परिणाम सकारात्मक रहा है। निम्न तालिका के माध्यम से जनपद की साक्षरता की तुलना 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश और देश की साक्षरता से प्रस्तुत है।

सारणी-7.1

देश, प्रदेश एवं जनपद में साक्षरता स्थिति (1991-2001)
(साक्षरता कुल जनसंख्या के प्रतिशत में)

देश / प्रदेश / जनपद	वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	स्त्री साक्षरता
देश -	1991	52.21	64.13	39.29
	2001	65.38	75.85	54.16
वृद्धि		17.17	11.72	14.87
प्रदेश	1991	40.71	54.82	24.87
	2001	57.36	70.23	42.98
वृद्धि		16.65	15.41	18.11
जनपद	1991	42.30	61.40	23.4
	2001	59.84	76.31	43.56
वृद्धि		17.54	14.91	20.16

स्रोत- भारत की जनसंख्या - 2001, ऑकडे एवं तथ्य, उपकार प्रकाशन, आगरा एवं सांख्यिकी पत्रिका-2001, देवरिया जनपद।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल साक्षरता की वृद्धि प्रतिशत जहाँ देश में 17.17 प्रदेश में 16.65 रही वहीं जनपद में कहीं अधिक 17.54 प्रतिशत बढ़ी। इसमें पुरुष साक्षरता में वृद्धि का प्रतिशत देश में 11.72 रहा वहीं प्रदेश में 15.41 रहा। जनपद में अपेक्षाकृत कम वृद्धि 14.91 प्रतिशत दर्ज की गयी। परन्तु स्त्री साक्षरता में वृद्धि का प्रतिशत जनपद में देश और प्रदेश दोनों के औसत से अधिक रहा। देश में जहाँ स्त्री साक्षरता में मात्र 14.87 प्रतिशत एव प्रदेश में 18.11 प्रतिशत की ही वृद्धि हुयी वहीं जनपद में 20.16 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार जनपद में साक्षरता की प्रगति सतोषजनक स्तर से हो रही है। वर्तमान समय में जनपद में साक्षरता कार्यक्रम के अतर्गत— दीप शिखा— उत्तर साक्षरता कार्यक्रम* चलाया जा रहा है।

जनपद स्तर पर साक्षरता की दृष्टि से एक सार्थक उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अभी भी विकासखण्ड स्तर पर इसमें काफी भिन्नता है। 2001 की जनगणना के अनुसार आज भी 15 में से मात्र 5 विकासखण्डों में ही साक्षरता जनपद के औसत साक्षरता (59.84) से अधिक है। विकासखण्ड के स्तर पर उच्चतम साक्षरता लार में (67.7) तथा निम्नतम स्तर रुद्रपुर में (49.7) पायी जाती है। अर्थात् इसमें 18.0 प्रतिशत का अंतर है। विकासखण्ड स्तर पर पिछले दशक में

सारणी 7.2

साक्षर व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत एव साक्षरता वृद्धि (1991-2001)

विकास खण्ड	साक्षरता प्रतिशत (1991)	साक्षरता प्रतिशत (2001)	साक्षरता वृद्धि
1 लार	48.6**	67.7**	19.1
2 सलेमपुर	47.6	66.2	18.6
3 भागलपुर	46.7	64.2	17.5
4 भटनी	42.4	62.2	19.8
5 बरहज	42.1	61.4	19.3
6 देवरिया सदर	40.9	56.8	15.9
7 भलुआनी	40.7	54.5	13.8
8 भाटपारसानी	39.8	59.8	20.0**
9 देसही देवरिया	38.5	56.8	18.3
10 रामपुर कारखाना	38.1	57.3	19.2
11 बैतालपुर	36.6	52.5	15.9
12 बनकटा	36.2	49.9	13.9
13 रुद्रपुर	36.1	49.7*	13.6*
14 गौरीबाजार	36.0	55.9	19.9
15 पथरदेवा	35.0*	53.0	18.0

स्रोत— सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 एव उत्तरप्रदेश एक अध्ययन-2003, प्रतियोगिता साहित्य

** — अधिकतम

* — न्यूनतम

सीरीज क्रमशः पृ 165 एव 32

साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः भाटपार रानी (200) गौरी बाजार (199) भटनी (198) बरहज (193) रामपुर कारखाना (192) और लार में (191) दर्ज की गयी। सारणी 7.2 एव चित्र (7.1) तथा रेखाचित्र (7.2) के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर 1991 से 2001 के मध्य साक्षरता में वृद्धि के प्रतिरूप को स्पष्ट किया गया है।

7.5 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत केवल स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत स्कूल से बाहर दी जाने वाली शिक्षा पद्धति नहीं आती है। इसमें प्रौढ शिक्षा स्त्री शिक्षा घरेलू प्रशिक्षण आश्रम शिक्षा तथा स्वयंसेवी संस्थाओं आदि द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को समाहित नहीं किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जूनियर बेसिक स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल हायर सेकेंड्री स्कूल तथा महाविद्यालय आदि का वर्णन किया गया है। ये इकाइयाँ ही सेवाकेन्द्र पर स्थित होती हैं तथा इन्हीं इकाइयों के माध्यम से सेवाकेन्द्र क्षेत्रीय जनसंख्या को शिक्षा सेवा उपलब्ध करा पाता है।

(अ) जूनियर बेसिक विद्यालय

शिक्षा विकास की आधारशिला है और शिक्षा की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा है। इसी स्तर से शिक्षा व्यक्तित्व को गढ़ना और परिष्कृत करना आरम्भ करती है, जिससे आगे चलकर व्यक्ति चमत्कृत होता है और एक समुन्नत समाज का निर्माण करता है। शिक्षा के विकास में प्राथमिक शिक्षा की इस महत्ता को स्वीकारते हुए ही आर्थिक मानचित्र के शिखर पर बैठे विश्व के प्रमुख देश जापान और कोरिया प्राथमिक शिक्षा में अधिकतम निवेश करके विकास के वर्तमान स्तर तक पहुँचे। परन्तु हमारे देश में आज भी उच्च शिक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सम्पूर्ण जनपद में वर्ष 2000-01 में जूनियर बेसिक स्कूलों की कुल संख्या 1813 थी। इसमें 55 विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित थे। कुल संख्या की दृष्टि से विद्यालयों की सर्वाधिक संख्या पथरदेवा विकासखण्ड में (151) तथा न्यूनतम संख्या देसही देवरिया विकासखण्ड में (81) थी। परन्तु शिक्षा पर प्रभाव विद्यालयों की संख्या से नहीं व्यक्त होता है बल्कि जनसंख्या एवं विद्यालय के अनुपात से व्यक्त होता है। इस दृष्टि से प्रतिलाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः भागलपुर लार भाटपाररानी बरहज रुद्रपुर विकासखण्डों में हैं। न्यूनतम संख्या गौरीबाजार विकासखण्ड में है यहाँ एक लाख जनसंख्या पर मात्र 71.4 ही विद्यालय हैं। इस प्रकार जनपद में विकासखण्ड स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या में 37.5 तक का अंतर है। यह प्राथमिक शिक्षा के विकास में अच्छी स्थिति नहीं है। प्रत्येक विकासखण्ड में जनसंख्या-स्कूल अनुपात बराबर होना चाहिए तथा प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता बढ़नी चाहिए। यदि विद्यालयों की उपलब्धता को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की दृष्टि से देखा जाय तो कुल ग्रामीण जनसंख्या (19,87,509) पर 1758 जूनियर बेसिक स्कूल हैं तथा

जनपद देवरिया का साक्षरता प्रतिरूप (% में) 2001

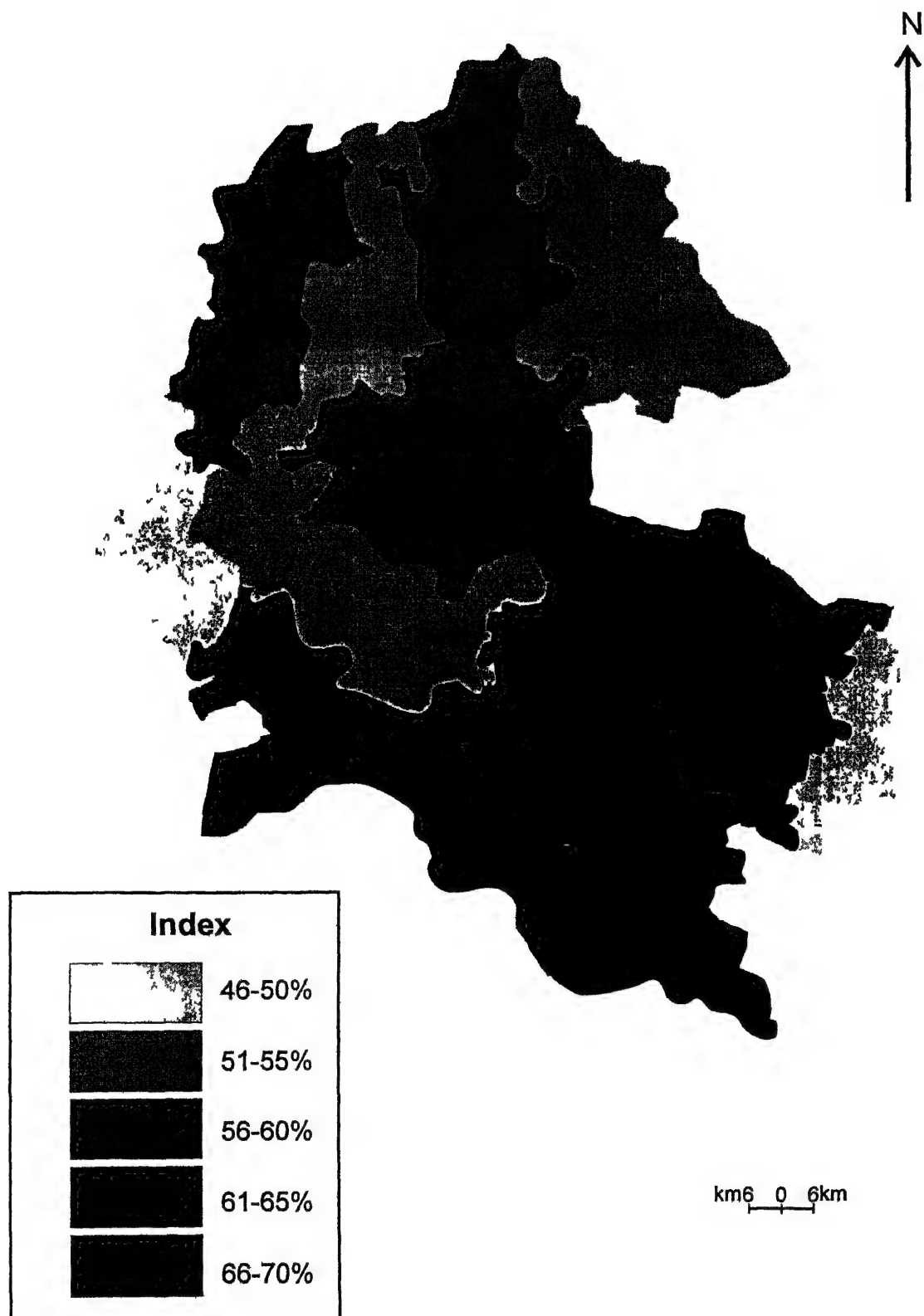
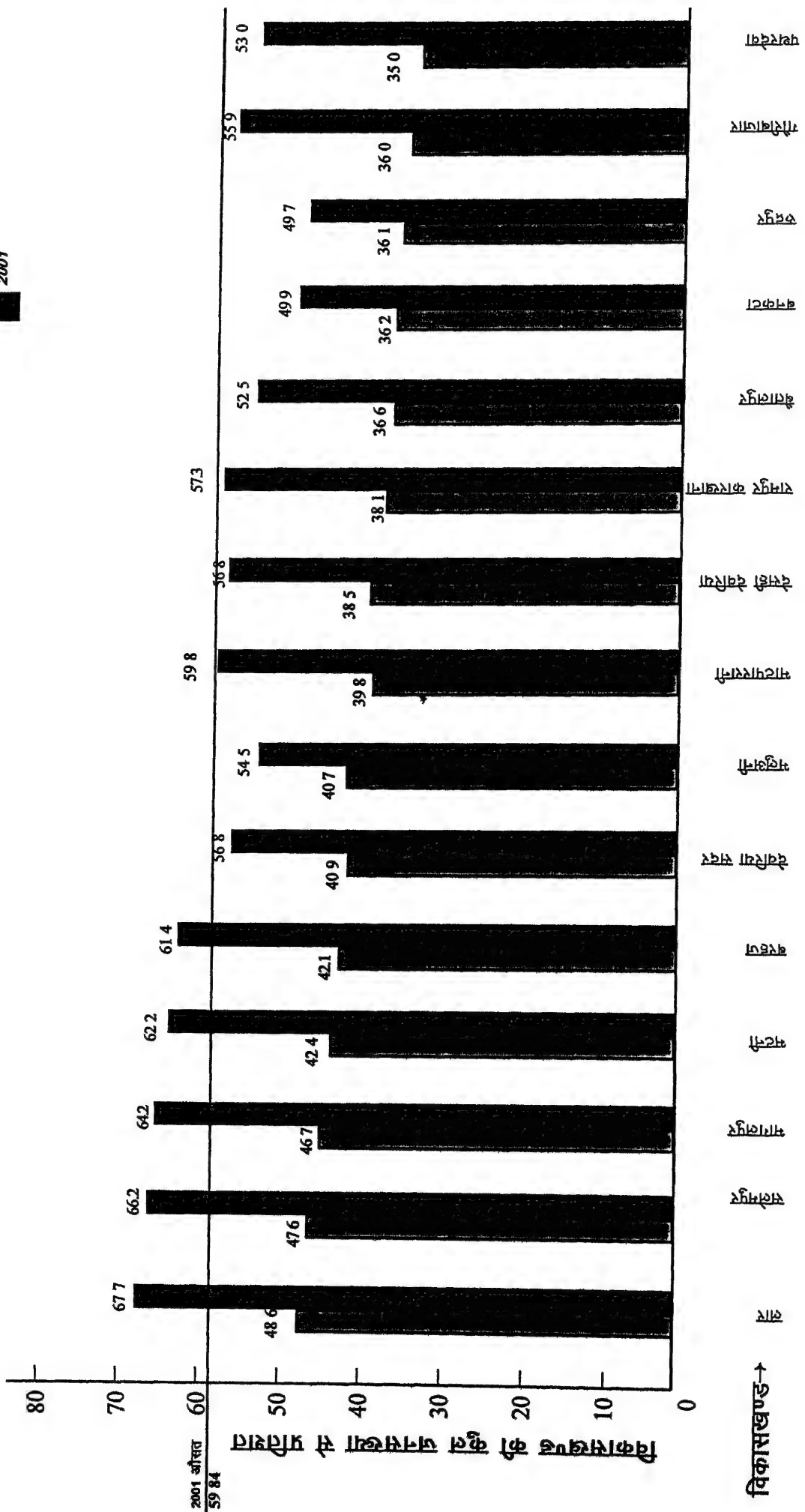


Fig 7 1

जनपद देवरिया में साक्षरता प्रतिशत 1991-2001



जनपद में विकास खण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या एवं प्रति लाख जनसंख्या पर उनकी संख्या- 2000-01

विकास खण्ड	जूनियर बेसिक स्कूल		सीनियर बेसिक स्कूल		हायर सेकेंड्री स्कूल		महाविद्यालय संख्या
	संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर स	संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर स	संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर स	
1 गौरीबाजार	117	714 *	31	189	5	31 *	1
2 बैतालपुर	105	724	25	172	6	41	-
3 देसही देवरिया	81	722	13	116 *	10	89	-
4 पथरदेवा	151	794	35	184	15	79	1
5 रामपुर कारखाना	114	931	22	180	7	57	-
6 देवरिया सदर	129	807	26	163	22	138	3
7 रुद्रपुर	126	988	26	204	7	55	1
8 भलुअनी	114	811	23	164	14	100	1
9 बरहज	101	1043	25	258	10	103	1
10 मटनी	112	914	22	180	16	131	-
11 भाटपारसानी	126	1047	26	216	7	58	1
12 बनकटा	108	926	16	137	11	94	1
13 सलेमपुर	131	915	50	349 * *	20	140 * *	1
14 भागलपुर	115	1089 * *	16	151	12	114	1
15 लार	128	1062	27	224	9	75	2
योग ग्रामीण	1758		383		171		6
नगरीय	55		30		32		8
योग जनपद	1813		413				14

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया- पृ संख्या - 89 125 126 169 170 से संगणित।

** = अधिकतम

* = न्यूनतम

कुल नगरीय जनसंख्या (2 17 363) पर मात्र 55 विद्यालय हैं। अर्थात् जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय—जनसंख्या अनुपात 1 1131 है वहीं नगरीय क्षेत्र में ये अनुपात 1 3952 है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में इस सुविधा का अभाव प्रतीत होता है परन्तु नगरों में निजी क्षेत्रों द्वारा अधिकाधिक संख्या में स्कूलों की स्थापना हो रही है जिससे शिक्षा विकास पर इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार देखा जाय तो शहरों में निजी क्षेत्रों द्वारा स्कूल/कान्वेन्ट स्थापना के लिए यह एक अप्रत्यक्ष कारण है।

(ब) सीनियर बेसिक विद्यालय

जनपद में वर्ष 2000-01 में सीनियर बेसिक स्कूलों की कुल संख्या 413 है। इसमें से 383 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 30 नगरीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। कुल 413 विद्यालयों में बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 86 है। इनमें से 8 नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। यद्यपि शिक्षा में लड़कों और लड़कियों में भेद नहीं बरता जाना चाहिए तथा लड़कों और लड़कियों के लिए समन्वित शिक्षा प्रणाली पर जोर देना उनके विकास के लिए हितकर होगा, न कि दानों के लिए पृथक—पृथक संस्थाओं की स्थापना करना। परन्तु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और बच्चों की संख्या के मध्य एक सा अनुपात होना आवश्यक है। इससे दोनों क्षेत्रों का एक समान विकास प्रोत्साहित होगा। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या (50) सलेमपुर में पायी जाती है जबकि देसही देवरिया में मात्र 13 ही विद्यालय हैं। विद्यालय एवं जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से भी सर्वोत्तम स्थिति सलेमपुर एवं न्यूनतम स्थिति देसही देवरिया की ही है। इस प्रकार विकासखण्डों में जहाँ प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम संख्या 34.9 एवं न्यूनतम संख्या 11.6 है वहीं दोनों के बीच का अंतर 23.3 का है। अर्थात् विकासखण्ड स्तर पर स्कूलों और जनसंख्या के अनुपात में भारी असंतुलन है जो न्यूनतम स्कूल संख्या के लगभग दूना के बराबर है। अतः यह जनपदीय शिक्षा प्रतिरूप का एक चिन्तनीय पहलू है। विभिन्न विकासखण्डों में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या को सारणी 7.3 में प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की दृष्टि से स्कूल और जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात 1 5189 है तथा नगरीय क्षेत्रों में 1 7245 है। इस प्रकार साक्षरता की दृष्टि से यहाँ भी विरोधाभास प्रतीत होता है, परन्तु नगरीय क्षेत्रों में कान्वेन्ट स्कूलों की स्थापना से ये कमी दूर होती है।

(स) हायर सेकेंड्री विद्यालय

हायर सेकेंड्री विद्यालय के अन्तर्गत हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट दोनों प्रकार के विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। जनपद में हायर सेकेंड्री विद्यालयों की संख्या 1997 में 153 थी जो 2000-2001 में बढ़कर 203 हो गयी। इसमें 171 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थे तथा नगरीय क्षेत्रों में 32 संस्थाएँ अवस्थित थीं। इसमें 24 विद्यालय बालिकाओं के थे, जिसमें 14 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 10 नगरीय क्षेत्र में स्थित थे। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक विद्यालय देवरिया सदर में (22) स्थित

है। गौरीबाजार में मात्र 5 ही हायर सेकेन्ड्री स्कूल स्थित हैं। प्रतिलाख जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक संख्या सलेमपुर में (140) है तथा न्यूनतम संख्या गौरीबाजार में (31) है। जनपद में अवरोही क्रम में प्रतिलाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या विकासखण्ड—वार क्रमशः निम्नवत् है— सलेमपुर देवरिया सदर भटनी भागलपुर बरहज भलुअनी बनकटा देसही देवरिया पथरदेवा लार भाटपार रानी रामपुर—कारखाना रुद्रपुर बैतालपुर गौरीबाजार। विकासखण्ड स्तर पर जनसंख्या और विद्यालय अनुपात में भारी अंतर है जो 109 है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय—जनसंख्या अनुपात 1:11622 एवं नगरीय क्षेत्रों में ये अनुपात 1:6792 है। इस प्रकार इस अनुपात में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लगभग दूने का अंतर है जो शिक्षा के सतुलित विकास के प्रतिकूल है।

(द) उच्च शिक्षा केन्द्र

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जनपद में 14 महाविद्यालय हैं। इनमें दो महिला महाविद्यालय हैं जो क्रमशः देवरिया सदर एवं लार विकासखण्ड में स्थित हैं। पूरे जनपद में स्थित महाविद्यालयों के नाम एवं स्थिति निम्नवत् है—

- 1— राजकीय कन्या महाविद्यालय —देवरिया सदर
- 2— बाबा राघवदास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज —देवरिया
- 3— सन्त विनोबा डिग्री कॉलेज —देवरिया
- 4— स्वामी देवानंद डिग्री कॉलेज —मठलार
- 5— फुदैजा मखदूम बीवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज —मठलार
- 6— मदनमोहन डिग्री कॉलेज —भाटपाररानी
- 7— रामजीसहाय डिग्री कॉलेज —रुद्रपुर
- 8— बाबा राघवदास— भगवानदास डिग्री कॉलेज —बरहज
- 9— बुद्ध महाविद्यालय रतसिया कोठी —बनकटा
- 10— डिग्री कॉलेज खुखुन्दू —भलुअनी
- 11— डिग्री कॉलेज —सलेमपुर
- 12— राजकीय डिग्री कॉलेज —इन्दूपुर
- 13— रविन्द्र किशोर शाही डिग्री कॉलेज —पथरदेवा
- 14— राजकीय डिग्री कॉलेज —भागलपुर

विकासखण्डवार डिग्री कॉलेजों की संख्या सारणी 7.3 में प्रस्तुत है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय एवं जनसंख्या अनुपात 1.33:1.251 एवं नगरीय क्षेत्र में ये अनुपात 1.27:1.170 हैं जो असंतुलित हैं (सांख्यिकीय पत्रिका जनपद—देवरिया—2001 पृष्ठ 89 से)।

7.6 जनपद में शिक्षण संस्थाओं की शिक्षक-विद्यार्थी संरचना

शिक्षा में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। प्रस्तुत चरण में जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं का विश्लेषण शिक्षक-विद्यार्थी की संख्या के आधार पर किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता विकास और प्रभावशीलता पर विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या तथा उनपर उपलब्ध शिक्षकों की संख्या का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यह सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थियों का उच्च अनुपात शिक्षा के उच्च स्तर से सम्बन्धित है तथा शिक्षक-विद्यार्थियों के निम्न अनुपात से शिक्षा की ग्राह्यता कम हो जाती है। जिससे शिक्षा के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनपद स्तर पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों का अनुपात विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं में भिन्न-भिन्न है। जूनियर बेसिक स्कूल में ये अनुपात 1.57 है। इसमें भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भारी भिन्नता है। ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 1.54 और नगरीय क्षेत्रों में 1.135 है। सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच अनुपात जूनियर बेसिक स्कूल के जनपदीय अनुपात से भी निम्न है। यहाँ प्रति शिक्षक पर विद्यार्थियों की संख्या 86 है जबकि जूनियर बेसिक स्कूल में ये संख्या 57 है। सीनियर बेसिक विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 84 है जबकि नगरीय क्षेत्र में एक शिक्षक पर 116 विद्यार्थियों का भार है। हायर सेकेंड्री स्कूल में इस अनुपात में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार दृष्टिगत होता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या—48 नगरीय क्षेत्र में—20 तथा सम्पूर्ण जनपद में औसतन प्रति शिक्षक 41 विद्यार्थियों की संख्या है। शिक्षक-विद्यार्थियों के इस अनुपात को ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र जनपदस्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर सारणी 7.4 में प्रस्तुत किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर इनका विश्लेषण विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अनुसार अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है।

(अ) जूनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षक-विद्यार्थी संरचना

जनपद में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 1813 है, (सारणी—7.3)। प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक संख्या भागलपुर विकासखण्ड में है परन्तु शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात की दृष्टि से भागलपुर की स्थिति सभी विकासखण्डों में सबसे बुरी है। यहाँ प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम 89 है जो जनपद औसत से भी 32 अधिक है। जनपद में शिक्षक विद्यार्थी का अपेक्षाकृत अनुकूलतम अनुपात देसही देवरिया विकासखण्ड में है। यहाँ प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या मात्र 29 है। जनपद में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में विकास खण्डस्तर में भारी अन्तर है। जनपदीय औसत से अधिक प्रतिशिक्षक-विद्यार्थियों की संख्या वाले विकासखण्डों में क्रमशः सलेमपुर (1.75)

सारणी 74

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात-2000-2001

विकास खण्ड	जूनियर बेसिक स्कूल शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात	सीनियर बेसिक स्कूल शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात	हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात
1 गौरीबाजार	1 37	1 28 *	1 47
2 बैतालपुर	1 51	1 57	1 50
3 देसही देवरिया	1 29 *	1 102	1 49
4 पथरदेवा	1 45	1 63	1 66
5 रामपुर कारखाना	1 47	1 77	1 38
6 देवरिया सदर	1 50	1 65	1 89 **
7 रुद्रपुर	1 57	1 80	1 53
8 भलुअनी	1 57	1 72	1 29 *
9 बरहज	1 67	1 125	1 44
10 भटनी	1 56	1 130 **	1 43
11 भाटपाररानी	1 42	1 82	1 33
12 बनकटा	1 51	1 88	1 59
13 सलेमपुर	1 75	1 82	1 52
14 भागलपुर	1 89	1 127	1 58
15 लार	1 69 **	1 79	1 46
ग्रामीण क्षेत्र —	1 54	1 84	1 48
नगरीय क्षेत्र —	1 135	1 116	1 20
जनपद —	1 57	1 86	1 41

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृष्ठ-90 91 93 से संगणित

** — अधिकतम

* — न्यूनतम

लार (1 69) और बरहज (1 67) शामिल है। भागलपुर में अधिकतम (1 89) संख्या पायी जाती है रुद्रपुर और भलुअनी विकासखण्डों में ये अनुपात जनपदीय अनुपात के ही बराबर हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के आधार पर इस अनुपात का विश्लेषण करने पर एक विरोधाभास दृष्टिगत होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 54 है, जो जनपदीय औसत से भी 3 कम है वहीं नगरीय क्षेत्र में एक शिक्षक पर 135 विद्यार्थियों का भार है।

(ब) सीनियर बेसिक स्कूलों की शिक्षक-विद्यार्थी संरचना

जनपद में कुल 413 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। इनमें मात्र 30 ही नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। प्रतिलाख जनसंख्या पर सर्वाधिक विद्यालयों की संख्या सलेमपुर विकासखण्ड में है (सारणी-73)। परन्तु इसके आधार पर यदि शिक्षक-विद्यार्थियों के अनुपात का विकास खण्डवार विश्लेषण करे तो सबसे अनुकूल स्थिति गौरीबाजार विकासखण्ड की है। यहाँ प्रति शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 28 है। जबकि भटनी में प्रतिशिक्षक 130 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार इसमें सर्वाधिक 102 विद्यार्थियों का अंतर है। शिक्षक-विद्यार्थी का

जनपदीय औसत 1 86 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र आर नगरीय क्षेत्रों में भारी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ये अनुपात 1 84 है जो लगभग जनपदीय औसत के बराबर है वहीं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिशिक्षक 116 विद्यार्थी हैं। *देसही देवरिया बरहज भटनी बनकटा और भागलपुर* विकासखण्ड प्रति शिक्षक जनपदीय औसत (1 86) से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है। शेष विकास खण्डों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

(स) हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों की शिक्षक-विद्यार्थी संरचना

जनपद में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों की संख्या 203 है जिसमें 171 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 32 नगरीय क्षेत्र में स्थित है। प्रतिलाख जनसंख्या पर अधिकतम संख्या *सलेमपुर* विकासखण्ड में पायी जाती है (सारणी-7 3)। जनपद में प्रति-शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या के साथ इसका विश्लेषण करने पर भिन्न प्रतिरूप उभरता है। जनपद में शिक्षक-विद्यार्थी का औसत अनुपात 1 41 है। ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 1 48 और नगरीय क्षेत्र में 1 20 है। इस प्रकार ये अनुपात जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल से अच्छा है। प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि जहाँ इस दृष्टि से अनुकूलतम स्थिति *सलेमपुर* की है वहीं शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात की दृष्टि से *भलुअनी* की स्थिति सबसे अनुकूल है। यहाँ प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29 है जबकि *देवरिया सदर* में प्रतिशिक्षक सर्वाधिक 89 विद्यार्थी हैं। जनपदीय अनुपात 1 41 से प्रति शिक्षक कम विद्यार्थियों की संख्या *रामपुर कारखाना, भलुअनी भाटपाररानी* विकासखण्डों में है। शेष सभी विकासखण्डों में विद्यार्थियों की शिक्षकों से अनुपातिक संख्या जनपदीय औसत अनुपात से अधिक है।

7 7 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए *छठी पंचवर्षीय योजना* से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979-80 से *अनौपचारिक शिक्षा योजना* अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में आरम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत 9 से 14 वर्ष के ऐसे बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है जो सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अथवा किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही पढाई छोड़ने के लिए विवश हो गए हैं। ऐसे बालक-बालिका शिक्षा से सदैव वंचित न रह जाए इसके लिए उन्हें उनके स्थान एवं समय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गयी है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अशकालिक शिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक मापदण्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित छात्रों को नि शुल्क पाठ्यपुस्तकों अभ्यास पुस्तिकाएँ

स्लेट—पेन्सिल आदि प्रदान की जाती है। केन्द्र का संचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को टाट—पट्टी चार कुर्सी फोल्डिंग एक उपस्थिति रजिस्टर दो स्टाक रजिस्टर दो शिक्षक डायरी दो पट्टी दो चाकू दो डाट पेन दो ताला एक मानचित्र (प्राकृतिक एवं राजनीतिक) उत्तर प्रदेश भारत तथा विश्व का एक—एक तथा चाक का डिब्बा एक एवं डस्टर एक दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से जनपद में जुलाई 2001 से आरम्भ 'स्कूल चलो अभियान' 'सभी के लिए शिक्षा परियोजना' 'शिक्षा गारंटी योजना' एवं दीप शिक्षा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम' चलाया जा रहा है। इनके अतिरिक्त हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्रदेश में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत ही प्रौढ शिक्षा द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विकास में समान रूप से सहभागी बनाने के लिए संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य साक्षरता दक्षता तथा सामाजिक चेतना को बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसार और एक्शन प्लान में बताए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने प्रौढ शिक्षा का एक विशद प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम है— 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' यह 1988 से देश भर में लागू हुआ। जनपद में यह जिला शिक्षा समितियों के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। अवधारणा यह है कि जिले के बुद्धिजीवी समाजसेवी स्वैच्छिक कार्य करने वाले लोग समिति बनायेंगे और साक्षरता कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाएंगे।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1992—2000 में राज्य और सघीय क्षेत्रों में 2.92 लाख केन्द्र चल रहे थे और उनमें 73 लाख बच्चे पढ़ रहे थे¹⁰ सन् 2000 से यह योजना 'शिक्षा गारंटी स्कीम' के रूप में चल रही है और जिन गाँवों में एक किमी तक के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय खोले जा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार सामान्य हुआ है।

(ख) जनस्वास्थ्य विकास

7.8 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वच्छता मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है तथा स्वास्थ्य से यह प्रत्यक्षत सम्बन्धित है। व्यापक सन्दर्भ में देखे तो हमारे यहाँ तन की स्वच्छता से अधिक मन की स्वच्छता को अहमियत प्रदान की गयी है, लेकिन स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अतः तन की स्वच्छता भी प्रमुख है। तन की स्वच्छता का सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्य से है इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता अनिवार्य है, फिर चाहे वह शहरी स्वच्छता हो या ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता की बात चलती है तो स्वच्छता शरीर तथा

घर-परिवार तक ही नहीं सिमट जाती बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अतिरिक्त गली मोहल्ला गाँव समाज तक फैल जाती है। इसलिये ये जानना जरूरी है कि ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता के क्या मायने हैं? क्या मापदण्ड है और वर्तमान में ग्रामीण स्वच्छता की वास्तविक स्थिति क्या है?

लगभग छह लाख गाँवों में सम्पूर्ण भारत की 75 प्रतिशत आबादी बसती है। यहाँ साफ-सफाई पेयजल आपूर्ति कूड़ा-कचरा गंदे पानी कीचड़ भरी नालियाँ मल की गदगी खानपान की सफाई तथा दूषित-प्रदूषित वातावरण के चलते स्वच्छता का स्वरूप और स्थिति आज भी बदतर है। अध्ययन क्षेत्र भी इसी ग्रामीण भारत की प्रतिमूर्ति है। यहाँ 90 प्रतिशत से अधिक आबादी गाँवों में बसती है। हालाँकि स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों की सोच में व्यापक बदलाव आया है मगर यह बदलाव गाँव के कुछ ही परिवारों विशेषकर समृद्ध परिवारों के लोगों में देखने को मिलता है। 1986 में केन्द्र सरकार ने *केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम* शुरू किया था। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के सहयोग से अमल में लाया जाना था। शुरुआत में इसका उद्देश्य ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार लाना और महिलाओं को गोपनीयता तथा मर्यादा प्रदान करना था बाद में इस कार्यक्रम में कई बातें शामिल की गईं जो निम्न हैं—

- × जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिये माँग सृजित करना।
- ✧ ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज की गति बढ़ाना।
- ✧ जल और स्वच्छता से जुड़ी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा
- ✧ ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता शिक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किये गये जिनका परिणाम भी निकला, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना लाभ नहीं पहुँचा। क्योंकि केन्द्र सरकार राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि गाँवों में 75 प्रतिशत से अधिक बीमारियाँ पर्यावरण के स्वच्छ न होने के कारण हो रही हैं। इन सब कारणों से नौवीं योजना में इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव करते हुए ग्रामीण स्वच्छता को व्यापक आधार पर जनोपयोगी व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक और नया कार्यक्रम '*सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान*' के रूप में चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत 2001-2002 के लिए अभी मात्र देश के 200 जिलों का चयन किया गया है।

व्यावहारिक समस्याएँ

देश की जहाँ दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण है वही जनपद की 90 प्रतिशत जनता गाँवों में ही बसती है, जो 10 प्रतिशत तथाकथित नगरों में बसती है वह भी सही अर्थों में विकसित गाँव ही कहे जा सकते हैं क्योंकि नगरों की सम्पूर्ण सुविधाओं का यहाँ भी अभाव है। इस प्रकार ग्रामीण

विकास हेतु सरकार के तमाम कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के बावजूद आज भी यह ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सेवाओं की राह देख रहा है। इस क्षेत्र में स्वच्छता में प्रभावी सफलता हासिल नहीं कर पाने में कई कारण हैं। जिनमें प्रमुखतः निरक्षरता है। जहाँ विश्व का हर तीसरा निरक्षर व्यक्ति भारतीय है वही जनपद में प्रति पाँच व्यक्तियों में तीन निरक्षर हैं। इससे अदाजा लगाया जा सकता है कि बिना ज्ञान के स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का क्या मतलब है।

साफ सफाई से ही बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जानकारी का स्तर बढ़ाना आवश्यक है बिना जानकारी के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता कार्यक्रमों और उपायों की जरूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाती लिहाजा ग्रामीण जनजीवन स्वच्छता के मामले में पिछड़ जाता है। स्वच्छता की इन बुनियादी जरूरतों को समझने की और उनके कारगर उपायों के जरिये निपटने की आवश्यकता है तभी वास्तविक विकास सम्भव है।

7.9 जनस्वास्थ्य एवं विकास

आजादी के बाद से भारत सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ स्वास्थ्य को सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आजादी के तुरन्त बाद सरकार ने जनोन्मुखी स्वास्थ्य नीति की योजना बनाई जो *भोर समिति* की 1946 की रिपोर्ट पर आधारित थी। 1978 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की *अल्माअटा* घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल था। इस वचनबद्धता के आलोक में देशभर में अनेक स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई और चलाई गईं। सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों और अस्सी के दशक में सरकार की स्वास्थ्य नीति का पूरा जोर देशभर में सर्वसुलभ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का ढोंचा तैयार करना था। जिसकी वित्त व्यवस्था और प्रबन्धन सरकार की जिम्मेदारी थी।

स्वास्थ्य रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता का प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाएगा। आजादी के समय पुरुषों और स्त्रियों की आयु सभाव्यता मात्र 32 वर्ष थी जो सन् 2002 में बढ़कर पुरुषों के मामले में 60 वर्ष और स्त्रियों के मामले में 62 वर्ष हो गयी है। 1951 से मृत्युदर में लगातार गिरावट आई है। 1951 में 1000 लोगों पर मृत्युदर जहाँ 29 थी, 1993 में वह केवल 9 रह गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शिशु मृत्युदर 1000 नवजातों पर लगभग 200-225 होने का अनुमान था। *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2* के अनुसार 1998-99 में महज 68 रह गया था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से अभी भी ऊपर (73 प्रति हजार) है। इसके बावजूद विगत 55 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियाँ आश्चर्यजनक हैं। लेकिन निरन्तर बढ़ रही आबादी के कारण ये उपलब्धियाँ सतोषजनक स्थिति पैदा नहीं कर पा रही हैं। देश में जहाँ 1991-2001 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि

जहाँ 21 34 रही वहीं उत्तर प्रदेश में 25 8 रही। हालाँकि जनपद में ये वृद्धि ऋणात्मक अको में (−38 5) दर्ज की गयी। पर इसका प्रमुख कारण *देवरिया* जनपद का विभाजन कर *कुशीनगर* नामक नया जनपद बनाया जाना था।

वर्तमान में औसत आयु बढ़ने के साथ-साथ जहाँ वृद्ध लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है वहीं सक्रमित करने वाली बिमारियों के साथ-साथ संक्रमण न फैलाने वाले रोगों यथा- नाडी सम्बन्धी रोग रक्तचाप कैंसर मधुमेह अधता आदि के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार बड़ी जनसंख्या की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों में सुधार की जरूरत और उनकी स्वास्थ्य सबधी जरूरतों की पूर्ति धीमी गति से विकास के कारण एक बड़ी चुनौती है। खासकर तब जब देश की जनसंख्या में हर वर्ष लगभग 1 8 करोड़ की वृद्धि हो रही है।

अतः इस मूल्यांकन की विशेष जरूरत है कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा जनस्वास्थ्य के लिए जो तन्त्र विकसित किया है उनसे लक्ष्य प्राप्त करने में वह कितनी सफल रही है। इस तरह का मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों के सन्दर्भ में और भी जरूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोगग्रस्तता और इसके फलस्वरूप मृत्युदर अधिक पायी गई है। ग्रामीण आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग तीन चौथाई है। 1991 की जनगणना में यह हिस्सा 74 प्रतिशत था और वर्ष 2001 की जनगणना में 72 प्रतिशत।

7 10 स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रारूप

हमारे सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों का समूचा जोर समाज और उसमें रहने वाले मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बेहतरी की ओर उन्मुख होता है। वर्ष 1993 में लागू की गई *राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति* में एक एकीकृत दृष्टि अपनाई गई है। इसमें प्रतिरोधी और अरोग्य प्रदान करने वाले उपायों के साथ-साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता अपनाने के उपाय शामिल हैं। *छठी पंचवर्षीय योजना* में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को शामिल किया जाना देश के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक उल्लेखनीय घटना थी। इसी दौरान '*सबके लिए स्वास्थ्य*' का लक्ष्य रखा गया था जिसे आगे की योजनाओं में भी जारी रखा गया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा नागरिकों को पूर्णतया स्वस्थ बनाये रखने की प्रतिबद्धता के कारण *न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम* के तहत सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि ग्रामीण जन को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं-

- 1 एक हजार की आबादी वाले प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड का प्रावधान।
- 2 पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में 3 000 की आबादी पर और मैदानी क्षेत्रों में 5,000 की

आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र।

- ✧ पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में 20 000 की आबादी पर तथा मैदानी क्षेत्रों में 30 000 की आबादी पर एक जनस्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था (पहले यह सीमा 1 लाख की आबादी की थी) और
- ✧ पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में 80 000 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्रों में 1 12 000 की आबादी पर एक पूर्णतया सुसज्जित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बिस्तरो वाला ग्रामीण अस्पताल होता है। यह चार जनस्वास्थ्य केन्द्रों की आबादी को कवर करेगा और औसतन एक उपकेन्द्र 24 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा अर्थात् यह औसतन साढ़े चार गावों को अपनी सेवाएँ देगा। एक उपकेन्द्र से सेवा पाने वाले गाँव की अधिकतम औसत दूरी 2.8 किमी मानी गई।

उपर्युक्त मानदण्डों को आधार बनाये तो 1991 की जनसंख्या के आधार पर देश में 1 34 108 उपकेन्द्र 22 349 जनस्वास्थ्य केन्द्र और 5 587 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था आवश्यक होगी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 30 जून 1998 को देश में 1,36,818 उपकेन्द्र, 22 991 जनस्वास्थ्य केन्द्र और 2 712 सामुदायिक केन्द्र थे।¹¹ इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों और जनस्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1991 की हमारी राष्ट्रीय जरूरतों से कहीं अधिक और संभवतया 2001 की जनगणना के बाद जो आवश्यकता होती उसके अनुरूप थी। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मामले में हमारी उपलब्धि आधे से भी कम रही है।

आँकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 1991 के आँकड़ों के अनुसार देश के मात्र एक तिहाई गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति अपेक्षाकृत कुछ अनुकूल है यहाँ 73 प्रतिशत गाँवों में किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

7.11 स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं की प्रकृति को समझने के ध्येय से यहाँ संक्षेप में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के नेटवर्क का वर्णन किया जा रहा है—

(क) चिकित्सालय

भारत के लगभग दो प्रतिशत गाँवों में चिकित्सालय हैं। देशभर में औसतन 10 000 की जनसंख्या पर चिकित्सालयों में सात बिस्तर उपलब्ध हैं। यह औसत 1981—91 के दशक में लगभग अपरिवर्तित बना रहा है। लेकिन इस सन्दर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तुलना करने पर चकित कर देने वाला फर्क दिखाई देता है। 1991 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या मात्र 2 थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 22 थी।¹² इससे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बड़े पैमाने पर शहरी

पूर्वाग्रह को देखा जा सकता है। 1991 में 10 000 की आबादी पर उपलब्ध शय्याओं का औसत उत्तर प्रदेश में 3.4 था¹³ जनपद में 2001 की जनसंख्या के आधार पर प्रति 10 000 की आबादी पर उपलब्ध शय्याओं का औसत 3.1 है। जनपद में स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केन्द्र जिला चिकित्सालय है। यहाँ स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके बाद 7 स्थानों पर (रुद्रपुर भाटपार सलेमपुर लार गौरीबाजार पथरदेवा बरहज) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख आधार जनसंख्या है। 1 20 000 से अधिक की आबादी पर इसकी स्थापना की जाती है। इन केन्द्रों पर जिला स्तर की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जनपद में क्षय रोग का एक कुष्ठ रोग के तीन तथा सक्रामक रोग का एक स्वास्थ्य केन्द्र है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ सामुदायिक विकास खण्ड में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या का आधुनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली से सम्पर्क का यह पहला स्तर होता है। गाँवों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का यह केन्द्रबिन्दु है। मगर राष्ट्रीय स्तर पर केवल तीन प्रतिशत गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा और सात प्रतिशत गाँवों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गाँव के बीच की कड़ी होता है।

जनपद देवरिया में 30 000 से 1 20 000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इनकी संख्या जनपद में देवरिया मुख्यालय को छोड़कर 71 है। नगरीय क्षेत्र में 10 केन्द्र स्थित हैं। इस प्रकार कुल 81 केन्द्र जनपद में स्थित हैं। इसमें 30 000 से कम जनसंख्या के आधार पर स्थापित नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भी संख्या शामिल है। जनपद में कुल स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या 329 है।¹⁴ इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल शय्याओं की संख्या 848 है सारणी (7.5)।

(ग) नर्सिंग होम

नर्सिंग होम स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में एक शहरी अवधारणा है इसलिए गाँवों में इसका अनुपात बेहद गौण है। कुल मिलाकर देश में एक प्रतिशत से भी कम गाँवों में नर्सिंग होम की सुविधा उपलब्ध है। जनपद में असहायताप्राप्त तथा आर्थिक सहायता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की संख्या क्रमशः दो और एक है।

(घ) परिवार एवं मातृशिशु कल्याण केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र आदि

भारत में केवल दो प्रतिशत गाँवों में मातृत्व गृह और बालकल्याण केन्द्र हैं जबकि उत्तर प्रदेश में छ प्रतिशत गाँवों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश के दो प्रतिशत गाँवों में परिवार नियोजन केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध है। जनपद में सभी विकासखण्डों में न्यूनतम एक परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र एवं उपकेन्द्र स्थापित है। जनपद में इसकी कुल संख्या 20 है। परिवार

जनपद में विकास खण्डवार एलोपैथी चिकित्सा सेवा

क्रम संख्या	विकास खण्ड	एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	समस्त उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	समस्त में कर्मचारी			परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र	
					डाक्टर	पैरा मेडिकल	अन्य	केन्द्र	उपकेन्द्र
1	गौरीबाजार	-	5	20	10	78	1	1	26
2	बैतालपुर	-	5	20	5	68	1	1	23
3	देसही देवरिया	-	4	16	7	56	1	1	18
4	पथरदेवा	1	8	74	14	122	1	1	30
5	रामपुर कारखाना	-	4	16	5	55	1	1	19
6	देवरिया सदर	-	5	20	8	112	1	1	23
7	रुद्रपुर	-	5	42	8	74	1	1	21
8	भलुआनी	-	4	32	9	72	1	1	19
9	बरहज	-	5	62	8	66	1	1	17
10	भटनी	-	5	20	6	68	1	1	18
11	भाटपारसानी	1	4	50	10	67	1	1	20
12	बनकटा	-	4	28	5	63	1	1	19
13	सलेमपुर	-	5	46	12	84	1	1	22
14	भागलपुर	-	4	16	5	60	1	1	20
15	लार	-	4	52	7	63	1	1	22
	योग ग्रामीण	2	71	514	119	1108	15	15	317
	नगरीय	6	10	334	32	140	22	5	1
	योग जनपद	8	81	848	151	1248	37	20	318

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 98 एवं 100

सारणी 76
जनपद में विकास खण्डवार आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

विकास खण्ड	आयुर्वेदिक			यूनानी			होम्योपैथिक		
	चिकित्सालय एव औषधालय	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	डाक्टरों की संख्या	चिकित्सालय एव औषधालय	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	डाक्टरों की संख्या	चिकित्सालय एव औषधालय	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	डाक्टरों की संख्या
1 गौरीबाजार	3	12	2	-	-	-	3	-	2
2 बैतालपुर	2	8	1	-	-	-	3	-	3
3 देसही देवरिया	4	8	3	-	-	-	1	-	-
4 पथरदेवा	1	4	-	-	-	-	3	-	3
5 रामपुर कारखाना	3	12	2	-	-	-	2	-	2
6 देवरिया सदर	3	12	2	1	1	1	2	-	1
7 रुद्रपुर	4	12	2	1	4	1	2	-	1
8 भलुआनी	3	8	1	-	-	-	2	4	2
9 बरहज	3	8	2	-	-	-	2	-	2
10 भटनी	2	4	2	-	-	-	-	-	-
11 भाटपारसानी	2	4	1	-	-	-	-	-	-
12 बनकटा	1	4	1	-	-	-	1	-	1
13 सलेमपुर	2	8	1	-	-	-	-	-	-
14 भागलपुर	2	8	-	-	-	-	2	-	1
15 लार	4	16	3	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण	39	128	23	2	4	2	23	4	18
नगरीय	5	41	4	-	-	-	2	4	2
योग जनपद	44	160	27	2	4	2	25	8	20

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 99

एव मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्रों की संख्या 318 है जिनमें मात्र 1 नगरीय क्षेत्र में है (सारणी-7 5)।

(ड) सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मि

भारत के 18 प्रतिशत गाँवों में सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएँ उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 59 प्रतिशत गाँवों में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की सुविधा है। जनपद स्तर पर भी कमोबेश यही अनुपात है।

(च) अन्य चिकित्सकीय सुविधाएँ

इसके अंतर्गत वे चिकित्सा सुविधाएँ आती हैं जो प्रायः स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालय अस्पताल नर्सिंग होम मातृगृह अथवा बाल कल्याण केन्द्रों आदि द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं। कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ शामिल हैं। इस तरह की अन्य सुविधाओं की उपलब्धता दर काफी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के लगभग एक प्रतिशत गाँवों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। जनपद में इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों को शामिल किया जा सकता है। जनपद में इनकी संख्या क्रमशः 44 2 और 25 है। इनमें उपलब्ध शय्याओं की संख्या क्रमशः 169 4 एवं 8 है। यूनानी चिकित्सालय केवल देवरिया सदर एवं रुद्रपुर में हैं। रुद्रपुर में मात्र 4 शय्याएँ हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय में मात्र भलुआनी में ही 4 शय्याओं की सुविधा है। विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों शय्याओं और डाक्टरों की संख्या को सारणी 7 6 में प्रस्तुत किया गया है।

7 12 जनस्वास्थ्य प्रणाली का मूल्यांकन

जनस्वास्थ्य राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रस्तुत अध्याय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं जनपदीय स्तर पर जनस्वास्थ्य सुविधाओं का विश्लेषण किया गया है। जनपद स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विश्लेषण के लिए जनपद में उपलब्ध मूल स्वास्थ्य सुविधाओं यथा— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या शय्याओं की संख्या तथा चिकित्सकों की संख्या को प्रतिलाख जनसंख्या पर उपलब्धता को आधार बनाया गया है। इससे विकासखण्ड स्तर पर इसकी तुलना सहज हो जाती है। फलस्वरूप इसका प्रतिरूप स्पष्ट हो जाता है। इसे सारणी 7 7 में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर निवास स्थान के अनुरूप भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को सारणी 7 8 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विश्लेषण से स्वास्थ्य प्रणाली का प्रतिरूप स्पष्ट हो जाता है।

सारणी 7 8 में प्रस्तुत स्वास्थ्य सम्बन्धी आँकड़ों तथा सारणी 7 7 में जनपद में मूल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक सफलता नहीं मिल पायी है। विकास का एक प्रमुख घटक जनस्वास्थ्य है, इसीलिए सरकार ने निरंतर इस पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा। इसके बावजूद 'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य

कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) से स्पष्ट होता है कि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र लोगो की स्वास्थ्य रक्षा सबधी आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वे देश की महज 31 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा पाते हैं। अधिकांश ग्रामीण जनो (लगभग 66 प्रतिशत) को अपनी स्वास्थ्य सबधी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए निजी चिकित्सालयो की शरण लेनी पडती है (देखें सारणी न 78)। इस प्रकार कल्पना किया जा सकता है कि गाँवो मे रहने वाले निर्धनो के लिए शहर मे जाकर निजी चिकित्सको से अपना उपचार करवाना कितना दुष्कर हो सकता है। सारणी 77 से स्पष्ट होता है कि जनपद मे विभिन्न विकास खण्डो के स्तर पर प्रति लाख जनसख्या पर स्वास्थ्य केन्द्रो की उपलब्धता मे भारी अंतर (23 केन्द्र) हैं जो लगभग दूने के करीब हैं। प्रतिलाख जनसख्या पर जनपद मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का औसत 36 है। इसमे ग्रामीण क्षेत्रो मे ये औसत 35 है जबकि नगरीय क्षेत्र मे 46 है। बरहज विकासखण्ड मे जनपद मे सर्वाधिक तथा नगरीय क्षेत्र के औसत से भी अधिक 51 स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जबकि भलुअनी मे न्यूनतम 28 स्वास्थ्य केन्द्र ही एक लाख जनसख्या पर उपलब्ध हैं। जनपदीय औसत से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धता केवल

सारणी 77

प्रतिलाख जनसख्या पर जनपद मे विकासखण्डवार स्वास्थ्य सुविधाओ की स्थिति

विकास खण्ड	प्रतिलाख जनसख्या पर प्रा स्वास्थ्य केन्द्र की सख्या	प्रतिलाख जनसख्या पर शैयाओ की स	प्रतिलाख जनसख्या पर डाक्टर की सख्या
1 गौरीबाजार	30	12.2	6.1
2 बैतालपुर	34	13.8	3.4
3 देसही देवरिया	35	14.2	6.2
4 पथरदेवा	42	39.0	7.3
5 रामपुर कारखाना	32	13.0	4.0
6 देवरिया सदर	31	12.5	5.0
7 रुद्रपुर	39	32.9	6.2
8 भलुअनी	28	22.7	6.4
9 बरहज	51	64.0	8.2
10 भटनी	40	16.3	4.9
11 भाटपाररानी	33	41.5	8.3
12 बनकटा	34	24.0	4.2
13 सलेमपुर	35	32.1	8.3
14 भागलपुर	37	15.1	4.7
15 लार	33	43.1	5.8
ग्रामीण क्षेत्र	35	25.8	6.0
नगरीय क्षेत्र	46	153.6	14.7
योग जनपद	36	38.4	6.8

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ- 25 एवं सारणी 75 से संगणित

पथरदेवा रुद्रपुर बरहज भटनी भागलपुर विकासखण्डों में ही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा ज्यादा असफल साबित हुई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गाँवों में नवजात और शिशु मृत्युदर का औसत क्रमशः 73 और 104 है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 47 और 63 है। इसी प्रकार 10 000 शिशुओं के जन्म पर मातृ मृत्युदर गाँवों में 62 है जबकि शहरों में यह केवल 27 ही है। प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं में भी शहरों और गाँवों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। हालाँकि शहरों में पर्यावरण का क्षय अधिक हुआ है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोगग्रस्तता का स्तर शहरों के मुकाबले बहुत अधिक है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन सभाव्यता शहरों के मुकाबले कम है।

यह एक दुखद तथ्य है कि भारत के गाँवों में जनसंख्या का तीन चौथाई हिस्सा निवास करता है लेकिन उनके हिस्से देश के कुल अस्पतालों का मात्र पॉचवा हिस्सा ही आता है उनके पास देश के कुल औषधालयों का 50 प्रतिशत से भी कम है। शहरों की 80 प्रतिशत जनसंख्या को दो किमी की दूरी के भीतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त है जबकि गाँवों में यह सुविधा महज 3 प्रतिशत जनसंख्या को ही प्राप्त है। शहरों और गाँवों के बीच इतने बड़े अंतर का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च नगरोन्मुख ज्यादा रहा है।

गावों में सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन करने के ध्येय से प्रसव के दौरान माताओं को और मृत्यु से पूर्व बीमार लोगों को प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों द्वारा प्राप्त सेवाओं के प्रतिशत को देखा जा सकता है। किसी भी समाज में जन्म और मृत्यु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना होती है। इन दोनों अवसरों पर सबको चिकित्सक और उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की जरूरत कभी-कभी इतनी हो जाती है कि उसके अभाव में अथवा समय पर उपलब्ध न होने पर कोई अकाल ही काल के गाल में समा सकता है। यह किसी के साथ हो सकता है चाहे वह बीमार व्यक्ति हो या नवजात या फिर उसकी सद्यः प्रसवा माता। इससे जुड़े आँकड़ों से ज्ञात होता है कि गाँवों में प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ शहरों के मुकाबले अपर्याप्त हैं।

ग्रामीण इलाकों में प्रसव के दौरान केवल 21 प्रतिशत माताओं को ही प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की सेवा प्राप्त हो पाती है जबकि 27 प्रतिशत नागर स्त्रियों को यह सुविधा प्राप्त होती है। *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2* के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि देश के गाँवों में होने वाले कुल प्रसव के 74.4 प्रतिशत घरों में ही करा लिए जाते हैं जबकि शहरों में घर में कराए जाने वाले प्रसव का प्रतिशत मात्र 34 है। गाँवों में केवल 23 प्रतिशत मामलों में डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है जबकि शहरों की 56 प्रतिशत माताओं को प्रसव के दौरान चिकित्सक की सेवाएँ मिल जाती हैं,

सांख्यिकी 7.8		
निवास स्थान के अनुरूप भारत में स्वास्थ्य की स्थिति		
	शहरी	ग्रामीण
बाल मृत्युदर		
* नवजात मृत्यु दर ¹	47.0	73.0
* 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर ² 63.0 104.0		
जनस्वास्थ्य रक्षा के माध्यम		
* सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र 23.5 30.6		
* निजी स्वास्थ्य क्षेत्र	74.8	66.2
स्वस्थ मातृत्व और महिलाओं में पुनर्जनन संबंधी स्वास्थ्य		
* माताओं की मृत्युदर (10,000 जीवित जन्म पर)	27.0	62.0
* गर्भ निरोध उपायों को अपनाने वाली विवाहित महिलाओं का प्रतिशत	58.2	44.7
प्रसव से पूर्व निम्नांकित का लाभ उठाने वाली माताओं का प्रतिशत³		
1 किसी स्वास्थ्यकर्मी से प्रसवपूर्व जांच	86.4	60.2
2 दो अथवा उससे अधिक टिटनेस टाक्साइड के टीके लगवाने वाले	81.9	62.5
3 जिन्होंने लौह अथवा कास्टिक एसिड की गोली या सीरम का सेवन किया	75.7	52.5
जिन माताओं को प्रसव के दौरान निम्नांकित सुविधाएं प्राप्त हुईं⁴ उनका प्रतिशत		
1 चिकित्सक की सुविधा	55.8	23.0
2 एएनएम/नर्स/दाई/एलएचवी की सुविधाएं	17.2	9.8
* कम से कम एक प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के मामले का प्रतिशत ⁵	39.2	44.2
* घर में ही प्रसव कराने वालों का प्रतिशत	34.0	74.4
एड्स संबंधी जागरूकता		
* ऐसी महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने एड्स के बारे में सुन रखा हो	70.3	29.7
रोगग्रस्तता		
* पिछले एक वर्ष के दौरान दमा यक्ष्मा पीलिया से पीड़ित तथा पिछले तीन महीनों के दौरान मलेरिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत	6.0	9.4
बाल स्वास्थ्य		
* तीन वर्ष तक की उम्र तक बच्चों को स्तनपान कराने की मध्यम अवधि	21.8	26.3
* ऐसे बच्चों का प्रतिशत जिन्हें निम्नलिखित टीके लगाए गए ⁶		
अ बीसीजी	85.1	64.3
ब डीपीटी (तीन खुराक)	70.6	46.6
स पोलियो (तीन खुराक)	74.9	54.4
द चेचक	59.7	36.2
इ सभी टीके	51.9	29.3
ई कोई टीका नहीं	8.6	20.2
* पिछले दो हफ्तों में डायरिया का शिकार हुए बच्चों का प्रतिशत	19.6	19.0
* पिछले दो हफ्तों में सास संबंधी संक्रमण का गंभीर रूप से शिकार हुए ऐसे बच्चों का प्रतिशत जिन्हें चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाई ⁶	75.1	61.4
पोषण		
* किसी भी किस्म की रक्तल्पता की शिकार महिलाओं का प्रतिशत	45.7	53.9
* 6-35 महीने की आयुवर्ग में रक्तल्पता के शिकार शिशुओं का प्रतिशत	70.8	75.3
* कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत	38.4	49.6
स्रोत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 1998-99 पर आधारित मुंबई आईआईवीएस और ओआरएस मैक्रो 2000		
1 सर्वेक्षण से पूर्व के पांच वर्षों (1994-98) के लिए		
2 पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए जन्म के लिए		
3 15-49 वर्ष की आयुवर्ग की विवाहित स्त्रियों में		
4 12-23 महीने की आयु वाले बच्चों		
5 तीन वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों		

(सारणी-7 8)। ऐसी स्थिति में गाँवों में उच्च जच्चा-बच्चा मृत्युदर का पाया जाना स्वाभाविक ही है।

जनसंख्या के आँकड़ों से प्रकट होता है कि शहरों के 52 प्रतिशत के मुकाबले गाँवों के 37 प्रतिशत लोगों को ही गंभीर बीमारियों के दौरान प्रशिक्षित चिकित्सक की सेवाएँ मिल पाती हैं। ऐसी बीमारियों में समुचित चिकित्सा का अभाव मरीज की मृत्यु का कारण बनता है। इस सिलसिले में देश में उत्तरप्रदेश की स्थिति काफी बेहतर प्रतीत होती है। यहाँ 50-74 प्रतिशत गंभीर रूप से बीमार ग्रामीणों को प्रशिक्षित चिकित्सक की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जनपद में विकासखण्ड स्तर पर चिकित्सकों की सर्वाधिक उपलब्धता भाटपाररानी एवं सलेमपुर में प्रतिलाख जनसंख्या पर 83 है। न्यूनतम उपलब्धता गौरीबाजार में (34) है। यहाँ नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता जहाँ 147 प्रति लाख जनसंख्या पर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 60 है। अर्थात् दूने से भी अधिक का अंतर है। प्रतिलाख जनसंख्या पर शैय्याओं की सर्वाधिक संख्या बरहज विकासखण्ड में है जबकि गौरीबाजार में न्यूनतम 122 शैय्या ही प्रतिलाख जनसंख्या पर उपलब्ध है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपलब्धता क्रमशः 153.6 और 25.8 है। अर्थात् इसमें लगभग 6 गुने का अंतर है।

7.13 स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की असफलता के कारण

ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक जनस्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की असफलता के अनेक कारण हैं। यहाँ न केवल विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों की अपेक्षित और उपलब्ध संख्या में अंतर है बल्कि विशेषज्ञ डाक्टरों नर्सों मिडवाइफों रेडियो-ग्राफर फार्मासिस्ट पुरुष स्वास्थ्य सहायक महिला स्वास्थ्य सहायिका तथा सामान्य फिजिशियनों जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की अपेक्षित और उपलब्ध संख्या में भी भारी अंतर है। दूसरी समस्या यह है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में जॉच और उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें तैनात स्वास्थ्य कर्मी अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते। कुछ स्वास्थ्यकर्मी अपने नियुक्ति वाले स्वास्थ्य केन्द्रों पर महीने में एक या दो बार ही जाते हैं। चिकित्सकों के अपने उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में न जाने की सबसे बड़ी वजह इन केन्द्रों में दवाइयों और चिकित्सा के लिए अन्य सहयोगी सामग्रियों की अनुपलब्धता है। दवाइयों, चिकित्सा सामग्रियों और उपकरणों की कमी के कारण उन्हें मरीज के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त डाक्टर भी शहर में ही रहना पसंद करते हैं ताकि वे नागर सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ और साथ ही वहाँ निजी प्रैक्टिस कर अतिरिक्त कमाई भी कर पाएँ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल न होने की एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि उन्हें बड़े क्षेत्र में बिखरी हुई ग्रामीण आबादी को अपनी सेवाएँ उपलब्ध करानी होती हैं। स्वास्थ्य केन्द्र के निकट स्थित गाँव के बासिंदों को तो स्वाभाविक रूप से बेहतर सेवा

मिल जाती है लेकिन दूरस्थ गाँवों को यह उपलब्ध नहीं हो पाती। परिणामतः दूर बसे गाँवों के लोग इन स्वास्थ्य केन्द्रों में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसके लिए उन्हें पैदल लम्बी दूरी तय करनी पड़ेगी। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहुँचने पर यह आवश्यक नहीं कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ मिल ही जाएँ। इस आशंका की मुख्य वजह यही है कि कभी-कभार ही चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध होते हैं। यदि वे मिल भी जाएँ तो भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव या काम के प्रति समर्पण के अभाव के कारण वे अपेक्षित उपचार नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। यही वजह है कि लोग बड़े अस्पतालों या निजी चिकित्सकों के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं।

देश के अधिकांश क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करने पर अमल के मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस स्थिति के लिए यातायात की समुचित सुविधाओं की अनुपलब्धता कार्मिकों को दैनिक और यात्रा भत्ते के भुगतान में विलंब आवासीय सुविधाओं का अभाव आकस्मिक घटनाओं के लिए अपर्याप्त कोष क्षरणशील कार्य सस्कृति और चिकित्सकों तथा नर्सों का निजी प्रैक्टिस में अधिकाधिक लिप्त होने जैसे कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है फिर भी समूचे देश में यह स्थिति बनी हुई है और अपनी जड़े निरन्तर मजबूत करती जा रही है। उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग न हो पाने अथवा कम हो पाने के पीछे यही मूल कारण है।

लेकिन ग्रामीण जनसंख्या को सुलभ हाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति या उनके स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति का कारण केवल स्वास्थ्य संबंधी संरचनात्मक व्यवस्था का अपर्याप्त होना भर ही नहीं है। सेवा उपलब्ध कराने की अनुचित विधि, उनको अमली रूप देने में बरती जाने वाली कोटाही स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वालों की निजी कमियाँ और उदासीनता तथा मरीजों और उनके संबंधियों में अशिक्षा आदि के कारण जागरूकता का अभाव भी इसके अन्य कारण बनते हैं। अशिक्षा के कारण ग्रामीणजन न तो अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझ पाते हैं न ही वे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली व्यवस्था की कार्याविधि को जान पाते हैं। इस तरह स्वास्थ्यकर्मियों की उदासीनता और अरुचि की तरह वे भी इन सेवाओं के प्रति लगभग उदासीन बने रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दयनीय स्थिति के कारण अलग-अलग अंचलों में भिन्न-भिन्न हैं। लेकिन इन सबमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उनका ठीक तरीके से काम नहीं करना है।

7.14 सामाजिक सुविधाओं का नियोजन

(क) स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन

स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन, उनकी वर्तमान मात्रा एवं अवस्थिति का निश्चित मानदण्डों से तुलना करके भविष्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

नियोजन को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त ससाधनो की आवश्यकता पडती है। ससाधनो का अनुमान तथा उसके निवेश की प्राथमिकता का निर्धारण सरकार करती है इसलिए ससाधनो की उपलब्धता व निवेश प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य मे नही किया गया है।

1993 से लागू *राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति* के अनुसार मैदानी क्षेत्र मे प्रति 1 12 000 की जनसख्या पर एक *सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र* होना चाहिए जिसमे कम से कम 30 बिस्तर उपलब्ध हो। जनपद मे वर्तमान मे मात्र 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है जबकि 2001 की जनसख्या (27 30 376) के आधार पर इसकी सख्या 24 होनी चाहिए। ये केन्द्र मात्र रुद्रपुर भाटपार (जसुई मे) सलेमपुर लार गौरीबाजार पथरदेवा और बरहज मे ही उपलब्ध हैं। अत कम से कम सभी विकासखण्ड मुख्यालयो पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार न्यूनतम 30 000 की जनसख्या पर मैदानी क्षेत्रो मे एक *जनस्वास्थ्य केन्द्र* तथा 5,000 की आबादी पर एक *उपकेन्द्र* होना चाहिए। इन मानदण्डो के अनुसार जनपद मे वर्तमान मे क्रमश 91 *जनस्वास्थ्य केन्द्र* एव 546 *स्वास्थ्य उपकेन्द्र* होने चाहिए, जबकि वर्तमान मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो सहित *जनस्वास्थ्य केन्द्रो* की कुल सख्या 69 है एव *स्वास्थ्य उपकेन्द्रो* की सख्या 329।¹⁵ इस प्रकार जनपद मे क्रमश 17 *सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र* 22 *जनस्वास्थ्य केन्द्र* तथा 217 *स्वास्थ्य उपकेन्द्रो* की स्थापना होनी चाहिए तब जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप स्थिति होगी। इन केन्द्रो की स्थापना मे उन स्थानो को वरीयता दी जानी चाहिए जो अपेक्षाकृत अधिक पिछडे है तथा जहाँ परिवहन एव शिक्षा सुविधाओ का विकास कम हुआ है। जनपद मे अभी भी 9 चिकित्सालय ऐसे है जिनमे एक भी चिकित्सक तैनात नही किए गये¹⁶। अत सभी चिकित्सालयो मे चिकित्सको की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जनपद-वासियो का जडी-बूटी पर पर्याप्त विश्वास है। अत आयुर्वेदिक यूनानी एव होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की और आवश्यकता है। साथ ही समस्त विकासखण्ड मुख्यालयो पर कम से कम 100 शय्याओ वाला एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

उत्तम स्वास्थ्य का सम्बन्ध केवल स्वास्थ्य सुविधाओ की उपलब्धि से ही नही है बल्कि स्वच्छ पर्यावरण से इसका सीधा सम्बन्ध है। अत पोष्टिक आहार शुद्ध वायु, शुद्ध पेय जल उचित सफाई व्यवस्था शुद्ध वातावरण की उपलब्धता तथा इसे बनाये रखने का प्रयास होना चाहिए। इनमे से अधिकाश की प्राप्ति स्वविवेक तथा जागरुकता से की जा सकती है। अपने शरीर सहित अपने परिवेश की स्वच्छता से न केवल रोगो से मुक्ति मिलती है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है, जो उत्तम स्वास्थ्य का सूचक है।

इन सब के अलावे ग्रामीण क्षेत्रो मे सचार और यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उतना ही जरूरी गाँवो मे डाक्टरो के काम करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना भी है। यह निर्धन ग्रामीणो के लिए भी आवश्यक है। स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली

को विकेन्द्रित करना और इन केन्द्रों के प्रबन्धन में पचायतों के मार्फत स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। यद्यपि इस दिशा में प्रयास जारी हैं और नई स्वास्थ्य प्रणाली की जिम्मेदारी और अधिकार सौंपने की इच्छा व्यक्त की गई है। इससे जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों और खड तथा पचायतों के बीच समन्वय कर आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति स्वास्थ्यकेन्द्रों में डाक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की अनुपस्थिति रोकने और स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जबाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी अर्थात् सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के पुनर्गठन की जरूरत पड़ेगी। अतः इस प्रणाली को ज्यादा स्वायत्तता और पर्याप्त कोष उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

प्रायः सरकार के कार्यक्रमों का उल्लेखनीय असर दिखाई न पड़ने का मुख्य कारण तेजी से बढ़ रही जनसंख्या बताया जाता है। निश्चित रूप से जनसंख्या विस्फोट गहरी चिंता का विषय है लेकिन सरकार के समस्त कार्यक्रमों की असफलता के लिए एक मात्र इसे ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वस्तुतः यदि केवल महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आ जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर अकुश लगने लगेगा। इसी प्रकार महिलाओं की साक्षरता के स्तर में सुधार से सामाजिक कुप्रथाओं को नियंत्रित करने के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। अब जबकि स्वतंत्र रूप से एक स्वास्थ्य नीति और एक जनसंख्या नीति अपनाई जा चुकी है जनसंख्या और स्वास्थ्य रक्षा के इस अंतर्सम्बन्ध को समझना और तदनुरूप कार्यक्रम तैयार करना आसान होगा।

(ख) शैक्षणिक नियोजन

जनपद में साक्षरता की स्थिति शिक्षण संस्थाओं के प्रतिरूप एवं उनकी निश्चित जनसंख्या पर उपलब्धता तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के विश्लेषण के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई कमियाँ दृष्टिगत हुयी हैं। जनपदीय साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत से 55.4 प्रतिशत कम है। इसमें स्त्री साक्षरता की स्थिति सबसे चिंताजनक है। इस दृष्टि से (स्त्री साक्षरता) राष्ट्रीय साक्षरता और जनपदीय साक्षरता का अंतर 10.6 प्रतिशत है। जनपद में जनसंख्या के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की अपर्याप्तता है जो शिक्षण संस्थाएँ हैं भी उनमें शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात सतोषजनक नहीं है। जूनियर बेसिक स्कूल में यह अनुपात 157, सीनियर बेसिक स्कूल में 186 तथा हायर-सेकेंडरी में 141 है। अतः अध्ययन क्षेत्र में शैक्षणिक नियोजन को उपर्युक्त सन्दर्भ में ही प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि शिक्षा का विकास जनपद के विकास में सहभागी बन सके। इसके अंतर्गत दो स्तरों पर नियोजन अपेक्षित है— पहला साक्षरता के विकास हेतु चलाये गए विभिन्न अभियानों के सदर्भ में तथा दूसरा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर।

पहला— देश में प्रदेश में तथा जनपद में साक्षरता के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम और

परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं परन्तु इनका सार्थक और अनुकूलतम परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। साक्षरता प्रतिशत को यदि छोड़ दे और गुणवत्ता पर निगाह डाले तो साक्षरता की स्वीकृत परिभाषा के अनुसार जिन व्यक्तियों को ऑकड़ों के लिए साक्षर मान लिया गया है उनमें सभी सार्थक अर्थ में साक्षर नहीं हैं। कई तो महज अपना नाम लिखना भर जानते हैं फिर भी ऑकड़ों की टोकरी में ही उन्हें रखा गया है। 1988 से चल रहा साक्षरता अभियान केरल के अरनाकुलम जिले में मिली सफलता से प्रेरित होकर सम्पूर्ण देश में लागू हुआ बिना इसे ध्यान में रखे कि सम्पूर्ण भारत केरल जैसा सजग नहीं है। परिणामतः साक्षरता कार्यक्रम अभियान का रूप नहीं ले सका और महज सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया। अतः साक्षरता कार्यक्रम में आई शिथिलताओं पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। निरक्षरता मुख्यतः—

- * ग्रामीण क्षेत्रों में है।
- * ग्रामीण क्षेत्रों के अभिवर्धित वर्गों में है।
- * निरक्षरों में महिलाओं की बहुतायत है।
- * अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं में साक्षरता न्यूनतम स्तर पर है।

साक्षरता इन वर्गों तक पहुँचे इसके लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

- 1— अभी पढ़ाने वाले मुख्यतः स्कूल के विद्यार्थी होते हैं उन्हें पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाये।
- 2— साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय। ग्राम पंचायत ही निरक्षरों का सर्वेक्षण कर कार्यक्रम बनाकर कौन पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे? यह सब तय करे।
- 3— जिला साक्षरता समिति अपने को निरीक्षण और पर्यवेक्षण तक ही सीमित रखे।
- 4— निरक्षरों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को इस कार्यक्रम के लिए धन आवंटित कर दी जाये, तथा खर्च करने की प्राथमिकता का निर्धारण भी स्वयं पंचायत ही करे।
- 5— राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मार्गदर्शन केवल मुद्दों तक सीमित रहे कि किन-किन मदों पर राशि खर्च की जा सकती है।
- 6— प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना हो जिसमें सरल भाषा में लिखी कृषि पशुपालन पर्यावरण स्वास्थ्य जैसे ग्रामीण जीवन के लिए उपयोगी विषयों पर पुस्तकें रहे कुछ अखबार और पत्रिकाएँ भी रहे जिससे साक्षरता अभियान सतत शिक्षा में प्रभावकारी रूप से अपने को ढाल सके। आगे चलकर उन्हें और सुदृढ़ किया जा सकता

है। सरकार सकल्प दिखाए तो स्थिति बदल जाएगी। लोकजीवन मुरझाया हुआ है मगर जीवित है। अवसर मिलते ही लोग आगे आ जाएंगे पुस्तकालयों के निर्माण और संचालन में सहयोग देगे ज्ञान प्राप्त करेंगे अपना जीवन उन्नत बनाएंगे। लोगों को अपने पर आश्रित बनाकर सरकार ने लोकशक्ति को सुला दिया है। साक्षरता और शिक्षा अभियान में सरकार की भूमिका सहायक की रहनी चाहिए, निर्णायक की नहीं। तभी लोग आगे आएंगे स्वयं सेवी संस्थाएँ जीवित बनेंगी लोकशक्ति जागेगी और विकास के मार्ग खुलेंगे।

दूसरा— नियोजन—शिक्षा में निवेश शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शिक्षण संस्थाओं में सुधार और संरचना से सम्बन्धित है। आज विश्व के आर्थिक मानचित्र के शिखर पर बैठे देश *जापान कोरिया संयुक्तराज्य अमेरिका* आदि प्राथमिक शिक्षा में अधिकतम निवेश करके ही विकास के वर्तमान स्तर तक पहुँचे किन्तु हमारे देश में उच्च शिक्षा पर ही विशेष ध्यान दिया जाता रहा। आज भी जनपद में 53 प्रतिशत बालिकाओं को 5 किमी या उससे अधिक दूरी तय करके सीनियर बेसिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है। शिक्षण संस्थाओं का वितरण अपर्याप्त है एवं उनमें प्रायः योग्य शिक्षकों का अभाव है। अतः जनपद के प्रत्येक गाँव में कम से कम प्राथमिक विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जाय। इनकी स्थापना में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाय जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं तथा जहाँ कोई विद्यालय नहीं है। अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति कर संरचनात्मक दोषों को दूर किया जाय तथा शिक्षण सुविधाओं का विकास किया जाय। वर्तमान में जनपद में इण्टर कालेजो/उमावि की संख्या (सहायता प्राप्त एवं असहायता प्राप्त) 236 है। परन्तु इनमें से अधिकांश केवल कागज तक ही सीमित हैं। वास्तविक रूप में भूमि पर एक कमरे के अलावा इनमें और कोई शिक्षण संसाधन नहीं। अतः ऐसी संस्थाओं से ऑकड़े भले ही दुरुस्त लगें परन्तु इनसे सेवा में कोई योगदान नहीं होता। ऐसे संस्थानों की संख्या विकास खण्डवार भटनी—21 लार—14 सलेमपुर—29 देवरिया सदर—37 बैतालपुर—9 रामपुर मारखाना—9 देसही देवरिया—10 पथरदेवा—20 भाटपार रानी—17 बनकटा—11 रुद्रपुर—12 गौरीबाजार—4 बरहज—11 भलुअनी—18 भागलपुर—14 है।¹⁷ इन संस्थानों का वास्तविक धरातल पर कामयाब बनाने का प्रयास होना चाहिए साथ ही जनसंख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए।

जनपद में वर्तमान में 14 डिग्री कॉलेज हैं जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 27 लाख से अधिक हो चुकी है। अर्थात् 1.95 लाख जनसंख्या पर एक डिग्री कॉलेज है जो शिक्षा की समुचित जरूरत एवं विकास के अनुकूल नहीं है। यदि प्रतिलाख जनसंख्या पर भी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय तो जनपद में अभी और 13 कॉलेज खोलना अपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या और कॉलेजों का अनुपात और भी विरोधाभासपूर्ण है। नगरीय क्षेत्रों में जहाँ

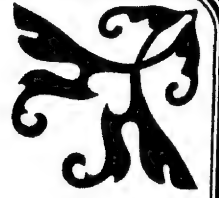
27 हजार जनसख्या पर ही एक डिग्री कॉलेज है वही ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए जनसख्या आधार 33 लाख है जो बहुत अधिक है। अतः अब जो भी डिग्री कॉलेज स्थापित हो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाय। इससे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का अंतर मिटेगा। इन सबके अलावे नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर तक किया जाना चाहिए।



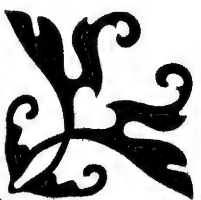
References

- 1 योजना 'गणतंत्र दिवस'— 98 विशेषांक प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पटियाला हाउस नई दिल्ली पृ— 14—15
- 2 *Thapaliyal, B K and Ramanna, D V, 'Planning for Social Facilities' 10th Course on DRD, NKD, Hyderabad 1977, Sept-Oct, p-1 (Unpublished paper)*
- 3 वही पृष्ठ—1
- 4 'कुरुक्षेत्र' अक्टूबर 2002 प्रकाशन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली पृ 17
- 5 कुरुक्षेत्र सितम्बर 2002 प्रकाशन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली— पृ 5
- 6 चौदना आर सी 'जनसख्या भूगोल' कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली 1987 पृ 179&
- 7 सदर्थ— 4 पृ 16
- 8 सामाजार्थिक समीक्षा जनपद देवरिया 2000—2001 पृ 9
- 9 वही पृ 9
- 10 कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2002 प्रकाशन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली— पृ 20
- 11 वही पृ 6
- 12 वही पृ 7
- 13 वही पृ 9
- 14 मुख्य चिकित्सापदाधिकारी देवरिया के कार्यालय से प्राप्त ऑकड़ों पर आधारित
- 15 वही
- 16 मुख्यमंत्री की साप्ताहिक समीक्षा से संबंधित 33 बिन्दुओं का प्रगति विवरण प्रोफार्मा सख्या—28 चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति— वर्ष 2001—02 माह फरवरी जनपद देवरिया।
- 17 जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) जनपद देवरिया के कार्यालय से प्राप्त सूचना पर आधारित





અધ્યાય-આટ



ऊर्जा-अवधारणा एवं समन्वित क्षेत्र-विकास

‘समन्वित क्षेत्र-विकास’ की सकल्पना एक व्यापक सकल्पना है। किसी क्षेत्र के विकास का तात्पर्य केवल कुछ सुविधाओं की वृद्धि करना ही नहीं है वरन् समग्र विकास करना है। पिछले अध्यायो में अध्ययन क्षेत्र के कृषि उद्योग परिवहन संचार शिक्षा तथा स्वास्थ्य से सबधित प्रवृत्तियों प्रतिरूपों एवं समस्याओं को विश्लेषित कर उनका विकास-नियोजन प्रस्तुत किया गया है। परन्तु किसी क्षेत्र का समग्र विकास इसके अलावे अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है यथा—आवास स्वच्छता प्रौद्योगिकी विकास विकसित मानव ससाधन, पर्यावरण सतुलन मनोरंजन के साधन सामाजिक सद्भाव तथा चरित्र निर्माण आदि। इनके बिना समग्र विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। परन्तु इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा विकास, क्योंकि विकास के प्रत्येक क्षेत्र—चाहे कृषि उत्पादन में सुधार हेतु, उद्योगों को चलाने अथवा दैनिक जीवन स्तर में सुधार के लिए ऊर्जा उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पोषण के बाद ऊर्जा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। शायद इसी कारण किसी भी देश की सम्पन्नता के समुचित मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के औसत उपभोग के पैमाने को प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु एक शोध-प्रबन्ध में समग्र विकास के लिए आवश्यक सम्पूर्ण भौगोलिक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारकों का अध्ययन सम्भव नहीं है। इसके लिए शोध-श्रृंखला की आवश्यकता है। एक शोधकर्ता के लिए समय ससाधनों तथा विशेषज्ञता के अभाव में समग्र अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्र विकास से सम्बन्धित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

जिस क्षेत्र की (जनपद देवरिया) 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण हो लगभग 40 प्रतिशत निरक्षर हो कृषि कार्य की प्रधानता हो, कुल कर्मचारों का 83.9 प्रतिशत कृषि कार्य में सलग्न हो तथा मात्र 51 प्रतिशत बस्तियाँ ही सड़कों से अभिगम्य हो, ऐसे क्षेत्र के समग्र-विकास के लिए विकास के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को गतिशील करना होगा। इस सदर्भ में विकास की सकल्पना क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति जनसंख्या ससाधन तथा आवश्यकता के अनुरूप सापेक्षिक होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसके विकास के लिए उसकी विशिष्ट माँग होती है। समतल एवं ऊपजाऊ भू-भाग वाले इस अध्ययन क्षेत्र में कृषि की प्रधानता है जनसंख्या गहनता अधिक है। अतः स्वाभाविक रूप से औद्योगिकरण भी कृषि आधारित ही होगा क्योंकि खनिज उपलब्धता शून्य है।

8.1 ऊर्जा की अवधारणा और समन्वित विकास में इसकी भूमिका

ऊर्जा मानव जीवन का आधारभूत सबल है। प्रकृति की गोद में जब मानव ने पहली बार अपनी आँखें खोली तो उसे सर्वप्रथम ऊर्जा से ही गति मिली और तदुपरांत गति ही जीवन का आधार बनी। इसी तरह के कई सदृश प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं। आज ऊर्जा विकास का प्रतीक है। ग्रामीण विकास के रूप में ऊर्जा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। यह न केवल आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है बल्कि बुनियादी घरेलू क्रियाकलापों में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में चाहे कृषि उत्पादन में सुधार हेतु उद्योगों को चलाने अथवा दैनिक जीवन स्तर में सुधार के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा सबकी जरूरत है। अतः समुचित ऊर्जा उपलब्धता समन्वित क्षेत्रीय विकास की पहली अनिवार्य प्राथमिकता है। ऊर्जा की उपलब्धता से कृषि उद्योग शिक्षा चिकित्सा परिवहन, संचार आदि सभी क्षेत्र गतिशील हो जाएंगे जिससे अंततः क्षेत्र का समन्वित विकास होगा।

ग्राम्य प्रधान अध्ययन क्षेत्र में जहाँ शिक्षा चिकित्सा, आवागमन दूरसंचार आदि सुविधाओं और साधनों का अभाव है, तो दूसरी ओर आए दिन ऊर्जा की कमी के कारण असहाय किसान अपने जीवनदायिनी कृषि संबंधी कार्यों को भी समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इस कारण उसका अपना नुकसान तो होता ही है, साथ में देश को भी उस नुकसान से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि खुद एक दुखद और निराशा से भरा जीवन जीने के बावजूद ये किसान ही अपनी खून-पसीने की मेहनत से देश की 100 करोड़ की आबादी का भरण-पोषण करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत पारंपरिक ऊर्जा पर आधारित आयातित बिजली है। कृषि क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल का उपयोग विकल्प रूप में करने के अतिरिक्त जनपद की सम्पूर्ण गतिविधियाँ (कृषिकार्य उद्योग संचार स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएँ आदि) इसी आयातित विद्युत पर विकास की ओर सरकती हैं। वर्तमान (फरवरी-2002 की स्थिति) में देवरिया में 45 विद्युत फीडर हैं तथा 3 455 ट्रांसफार्मर जिनमें 27 खराब हैं। वर्तमान में लगभग 72 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं परन्तु विद्युत उपलब्धता का औसत ग्रामीण क्षेत्र में 11.05 घंटे और नगरीय क्षेत्रों में 14.45 घंटे ही है। जनपद मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति औसतन 19.00 घंटे है (मुख्यमंत्री की 33 बिन्दुओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा फरवरी-2002, जनपद देवरिया)। इस प्रकार ऊर्जा के इस आधार पर क्षेत्र के समन्वित विकास की सकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति तब है जब अभी 72 प्रतिशत गाँवों में ही बिजली पहुँची है (सारणी-8.1)। अतः इसके लिए शेष 28 प्रतिशत गाँवों में भी विद्युत को पहुँचाना अनिवार्य होगा नहीं तो वे विकास में पीछे छूट जाएंगे और क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देगे जो स्वयं में एक समस्या है। सारणी 8.1 और आरेख 8.1 के माध्यम से प्रत्येक विकासखण्ड में विद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति एवं विकास को स्पष्ट किया गया है।

सारणी 8 1

विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत एव विकास

विकास खण्ड	आबाद ग्राम संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत	
		1990-91	2000-01
1 गौरीबाजार	114	69 0	72 8
2 बैतालपुर	127	64 8	74 8
3 देसही देवरिया	88	58 0	71 6
4 पथरदेवा	162	64 3	72 8
5 रामपुर कारखाना	113	65 2	71 7
6 देवरिया सदर	155	73 4	79 4
7 रुद्रपुर	159	51 0	52 2
8 भलुअनी	171	61 3	62 0
9 बरहज	94	67 4	70 2
10 भटनी	107	72 9	93 5**
11 भाटपाररानी	117	81 2	75 2
12 बनकटा	148	48 0*	52 0*
13 सलेमपुर	203	81 3**	80 8
14 भागलपुर	122	74 2	79 5
15 लार	124	68 5	75 0
समस्त विकासखण्ड	2004	64 0	71 7

स्रोत- सांख्यिकी पत्रिका जनपद देवरिया-2001 पृ 15 एवं 40 से संगणित

** - अधिकतम

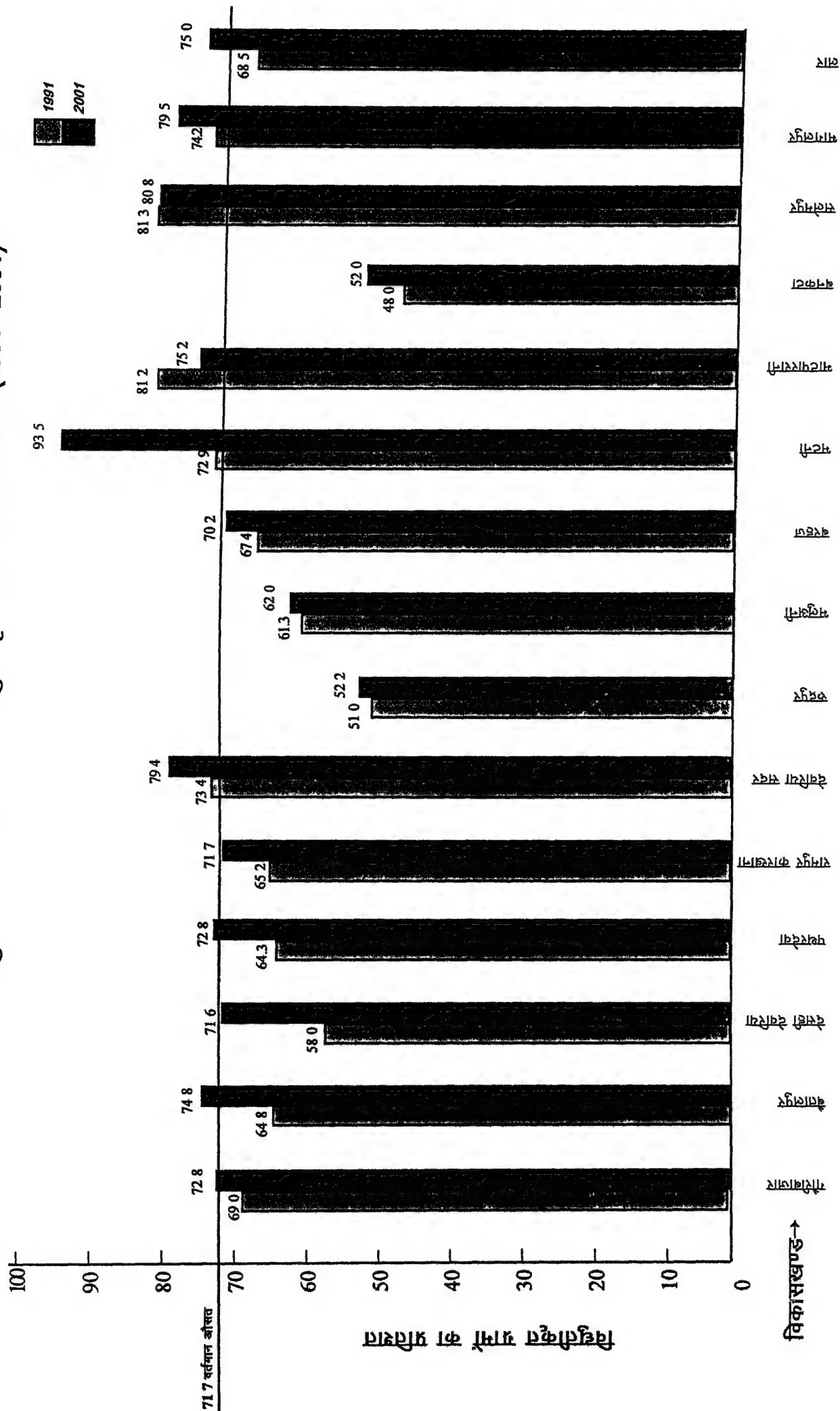
* - न्यूनतम

सारणी 8 1 से स्पष्ट है कि 1990 से 2001 के मध्य जनपद में विद्युतीकृत ग्रामों में मात्र 7 7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई तथा अभी भी देसही देवरिया रुद्रपुर, भलुअनी बरहज बनकटा विकासखण्डों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत जनपदीय औसत (71 7) से भी कम है। सर्वाधिक प्रतिशत (93 5) भटनी विकासखण्ड में पायी जाती है।

ग्रामीण विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसे अनन्त काल तक चलाए रखने के लिए वाछित ऊर्जा भी सतत् उपलब्ध और निरन्तर विद्यमान होनी चाहिए। अभी तक उद्योग कृषि, घरेलू उपभोग परिवहन आदि सभी क्षेत्रों को गतिमान बनाए रखने में बिजली, कोयला एवं पेट्रोलियम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन ऊर्जा के इन परंपरागत साधनों की कुछ सीमाएँ हैं जैसे—

- * बढ़ती जनसंख्या एवं ऊर्जा खपत के कारण इन स्रोतों के भण्डार कुछ सौ वर्षों बाद समाप्त होने की संभावना है।
- * इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के लिए सम्बन्धित परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश की आवश्यकता है जो विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी बाधा है।

जनपद देवरिया में कुल आबाद ग्रामों से विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत (1991-2001)



- * ऊर्जा के परंपरागत तौर पर उपलब्ध सभी रूप सामान्यतः ऊर्जा के सकेन्द्रित रूप हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इनके वितरण के लिए एक पूरी विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित करनी पड़ती है जो व्ययसाध्य है।
- * इन स्रोतों से पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और प्रदूषण के कारण मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

इस प्रकार आज ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों के प्रकार और उनका दायरा इतना बढ़ गया है कि समन्वित क्षेत्रीय विकास के लिए उन सबको सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। परन्तु विडंबना यह है कि ऊर्जा के आधिक्य की जरूरत वाले ऐसे दौर में ऊर्जा निरंतर अपर्याप्त पड़ती जा रही है। ऐसे में अन्य स्रोतों से भी ऊर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है।

8.2 विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा की अवधारणा

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ऊर्जा उत्पादन की समस्या का निदान गैर परंपरागत ऊर्जा ससाधनों में ही है। गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप *गोबर गैस पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा, कूड़ा-कचड़ा से ऊर्जा जैव ऊर्जा* आदि हैं। बढ़ती जनसंख्या कृषि गहनता से बढ़ती तीव्रता तथा इसके साथ-साथ पारंपरिक ऊर्जा का दिनों-दिन घटता भंडार (टिकाऊ विकास तथा राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए) जैसे कारण गैरपरंपरागत ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं। यही हमें दीर्घकालिक *टिकाऊ विकास* तथा *ऊर्जा सुरक्षा* प्रदान कर सकता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा आवश्यकता के कारण इसका विशेष महत्व है।

8.3 गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं सभाव्यता

ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में व्यापक संभावनाएँ परिलक्षित हो रही हैं। इसका विश्लेषण दो स्तरों पर करना अपेक्षित है पहला *राष्ट्रीय स्तर* पर एवं दूसरा *जनपदीय स्तर* पर। इससे तुलनात्मक रूप से जनपद में गैर परंपरागत स्रोतों की सभाव्यता का आकलन हो जाएगा।

(क) राष्ट्रीय स्तर पर गैरपरंपरागत ऊर्जा सभाव्यता

भौगोलिक दृष्टि से भारत गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की सम्भावना से परिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के आकलन के क्रम में यह पाया गया है कि मैदानी भागों में *सौर, जल* तथा *वायु ऊर्जा* के असीमित भंडार हैं। ये निम्नवत् हैं—

(अ) कृषि उत्पादों से ऊर्जा

देश में प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादों से लगभग 30 करोड़ टन बेकार पदार्थ निकलते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित किया जा सकता है।

(ब) पवन ऊर्जा

यदि हम पवन ऊर्जा को कम अनुमानित करके देखे तो भी इस स्रोत से देश में 20 000 मेगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

(स) लहर ऊर्जा

भारत की 1 600 किमी लंबी तट रेखा है जहाँ समुद्र की लहरों से 40 000 मेगावाट बिजली प्राप्त हो सकती है।

(द) सौर ऊर्जा

भारत में प्रतिदिन प्रतिवर्ग मीटर 5—7 किलोवाट/घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा को सौरतापीय उपकरणों और प्रणालियों से सीधे ताप ऊर्जा में बदला जा सकता है।

(इ) भूतापीय ऊर्जा

इसकी प्राप्ति पृथ्वी की सतह से 10 किमी गहराई तक की उष्णता से होती है। भूतापीय द्रव्य का तापमान 130 डिग्री से० होने की स्थिति में बिजली बनाने के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति की व्यापक संभावनाएँ हैं क्योंकि देश में गर्म भूगर्भीय स्रोत वाले 340 स्थान हैं।

अभी देश में कुल ऊर्जा उत्पादन का 3 प्रतिशत (3 400 मेगावाट) गैरपरम्परागत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। इसमें पवन ऊर्जा के अंतर्गत समुद्रतटीय क्षेत्रों में 43 मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। समुद्री ऊर्जा के अंतर्गत केरल के विज़िगम में 1 500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाया गया है। इससे वर्ष के 10 महीने 75 किलोवाट के औसत से बिजली उत्पादित की जा सकती है। सौर ऊर्जा के अंतर्गत देशभर में अब तक 10 000 पानी गरम करने की घरेलू प्रणालियाँ, 5,000 औद्योगिक व्यावसायिक प्रणालियाँ, 2 25 लाख सौर कुकर, 10 000 सौरस्टिल ओर 200 सौरकुटी (सोलर हट) लगाई गई हैं। भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के योगदान को वर्ष 2012 तक 10 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को लयबद्ध करना भी एक उचित तथा सार्थक कदम होगा।

(ख) जनपद (देवरिया) स्तर पर गैर परम्परागत ऊर्जा संभाव्यता

गैरपरम्परागत ऊर्जा विकास की संभाव्यता जनपदीय स्तर पर काफी अधिक है। यहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल ऊर्जा के अलावे कृषि प्रधानता के कारण लाखों टन कृषि उत्पाद बेकार पदार्थ के रूप में निकलते हैं, जिनसे ऊर्जा उत्पादन संभव है। धान अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख फसलों में है। धान की भूसी से भी ऊर्जा उत्पादन की पर्याप्त संभाव्यता है। जनपद में पॉंच चीनी मिलें (प्रतापपुर, गौरीबाजार, भटनी, देवरिया एवं बैतालपुर में) स्थापित हैं। गन्ने की खोई से ऊर्जा

उत्पादन का प्रयोग सफल हो चुका है। अतः इससे अध्ययन क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र समतल मैदानी क्षेत्र है और उर्वर मृदा के कारण कृषि सघनता भी उच्च है। लगभग 89 प्रतिशत कर्मकार कृषि क्षेत्र में ही लगे हैं जबकि गाँवों में औसतन 11.05 घंटे ही बिजली उपलब्ध होती है। इससे कृषि कार्य मुख्यतः सिंचाई प्रभावित होती है। क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर काफी ऊँचा है तथा पवन ऊर्जा की भी पर्याप्त संभाव्यता है। अतः पानी निकालने सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। पशुधन के मामले में क्षेत्र सम्पन्न है। अतः जिन परिवारों के पास अधिक पशु हैं, वे बायोगैस सयंत्र की सहायता से ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र गैर परम्परागत ऊर्जा के विकास की संभावना से परिपूर्ण है। जरूरत है इन संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से अधिकाधिक दोहन करके विकास की गति बढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने की। विशेषकर इस लाभदायक पहलू को ध्यान में रखते हुए कि इसके उत्पादन और वितरण में पर्यावरण प्रदूषण के खतरे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि सयंत्रों की निर्माण लागत को निकाल दिया जाए तो गैर परम्परागत ऊर्जा की उत्पादन लागत नगण्य रहती है।

8.4 ग्रामीण क्रियाकलापों में गैरपरम्परागत ऊर्जा का उपयोग

सूर्य पवन पशुमल जैविक पदार्थों कूड़ा-कचड़ा आदि से बेमोल मिलने वाली इस ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण जनजीवन से जुड़े विभिन्न खेतिहर और गैर-खेतिहर कार्यों में किया जा सकता है। जिन ग्रामीण क्रियाकलापों में इस ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से हो सकता है वे हैं—

- * पेयजल की पंपिंग
- * लघुस्तर पर खेतों की सिंचाई
- * घरेलू व पथ प्रकाश व्यवस्था
- * सामुदायिक केन्द्रों में प्रकाश व्यवस्था
- * भोजन पकाना आदि।

अध्ययन क्षेत्र में 28 प्रतिशत गाँव अभी भी बिजली से वंचित हैं। इससे इनका विकास रुका हुआ है। ये गाँव दूरदराज में बसे होने तथा अपनी जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण परम्परागत ग्रिड बिजली द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं किए जा सके हैं। इन गाँवों में सौर फोटोवोल्टिक पद्धति से सामुदायिक और पथ प्रकाश की व्यवस्था को संयोजित और संभव किया जा सकता है। इस पद्धति के जरिये सीधे सूर्य की किरणों से ऊर्जा का उत्पादन करके उसे संग्रहीत कर लिया जाता है जिसका जरूरत के मुताबिक उपयोग किया जाता है। इसमें केबलों की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके जरिये ऊर्जा का उत्पादन स्थान विशेष पर ही हो जाता है।

परन्तु गाँवों में जीवन स्तर सुधारने और सौर विद्युत या अन्य गैर परम्परागत ऊर्जा के उपयोग में सबसे बड़ी बाधा है ग्रामीणों को इसके लिए प्रोत्साहित करना। अतः ग्रामीण स्तर पर पहले गैर परम्परागत ऊर्जा के लाभ एवं उपयोग की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके लिए अनेक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी अपेक्षित लाभ पहुँचा सकता है।

8.5 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

देश के विशाल भूभाग में बसी ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने तथा गैरपरम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों के लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 'एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम' का सूत्रपात किया है। राज्य जिला और खण्ड स्तर पर उपयुक्त गैरपरम्परागत ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना तथा इस सदर्भ में जरूरी सस्थानिक अनुरूपता को नियोजित करना इस कार्यक्रम के जरिये सम्भव हो रहा है। ग्राम पंचायतों गैरसरकारी संगठनों तथा अन्य क्षेत्रीय सस्थाओं को साथ जोड़ने के परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम ग्रामीण ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकतम जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने में भी सफल हुआ है।

8.6 समन्वित विकास के अन्य पहलू

अध्ययन क्षेत्र का समन्वित विकास इस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों, यहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं महत्वाकांक्षाओं उनके तकनीकी कौशल और पर्यावरण बोध पर निर्भर है। यहाँ के प्राकृतिक उपहारों का साधन के रूप में मूल्य तभी बढ़ेगा जब लोगों को उनके उपयोग का ज्ञान हो जायेगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सभाव्य साधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु उपयोगिता के ज्ञान के अभाव तथा आर्थिक कारणों से उनका विकास नहीं हो पाया है या पर्यावरणीय पहलू की अनदेखी कर विकास के प्रयास हुए जिसका दुष्परिणाम अब सामने आने लगा है। इस दृष्टि से जनपद के समन्वित विकास के लिए कई स्तरों और कई दिशा में सार्थक पहल की अपेक्षा है। प्रस्तुत अध्याय में दिशाओं को स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है पर उनमें कितना और किस तरह की कार्ययोजना होनी चाहिए इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक शोध की आवश्यकता है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सबसे पहले वन एवं पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व को जनपद की जनता को समझना होगा। अध्ययन क्षेत्र आरम्भ में अरण्य प्रदेश था। प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूलता के कारण यह क्षेत्र देवों एवं ऋषियों की तपोस्थली के लिए आकर्षण का केन्द्र बना, जिससे यह प्रदेश 'देवारण्य प्रदेश' हुआ। परन्तु बाद के कालावधि में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप कृषि भूमि एवं आवास हेतु भूमि की बढ़ती माँग के कारण तीव्र गति से वनों का ह्रास हुआ। फलस्वरूप यह 'देवारण्य प्रदेश'—'देवरिया'

हो गया। इसमें से *अरण्य* निकल गया और ये *अरण्य* अब केवल बाग-बगीचों तक ही सिमट कर रह गये हैं।

देवारण्य के *देवरिया* में इस रूपान्तरण से अनेक पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय समस्याओं का जन्म हुआ है। इनमें सर्वप्रमुख समस्या बाढ़ सूखा मृदाअपरदन एवं प्रदूषण की है। अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी भाग *राप्ती* एवं *घाघरा* के बाढ़ से प्रत्येक वर्ष आक्रांत रहता है तो उत्तरी एवं उत्तरी-पश्चिमी भाग में ग्रीष्म काल में सिंचाई हेतु नहरों में जल का अकाल पड़ जाता है। विद्युत आपूर्ति भी समयबद्ध न होने से परिणाम दुःखद हो जाता है। वनों के न रहने से वर्षा का जल सीधे बहकर छोटी नदियों एवं तालाबों से होते हुए बड़ी नदियों (*राप्ती घाघरा*) में चला जाता है और अपने साथ भारी मात्रा में मृदा अपरदित कर ले जाता है। इससे जहाँ नदियों में अवसाद के निरन्तर जमा होते रहने से तली उथली हो रही है, जिससे बाढ़ के पानी का विस्तार दूर तक के क्षेत्रों में हो रहा है वही कृषि भूमि के उपरी परत के अपरदित होकर बह जाने से उर्वरता भी प्रभावित होती है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन कम होता है।

इस प्रकार वन क्षेत्र घटने से पारिस्थितिकीय सतुलन अव्यवस्थित हो रहा है। वन नष्ट होते हैं तो जल नष्ट होता है पशु-पक्षी नष्ट होते हैं। पर्यावरण चक्र अव्यवस्थित होता है जिसका दुःखद परिणाम सूखा, अकाल बाढ़ बढ़ता तापमान और दूषित वायु है। वन वर्षा की प्रवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। वर्षा की कमी से भूजल स्तर घट रहा है जिससे मिट्टी सूख रही है और पेड़ पोछे नष्ट हो रहे हैं। अतः वनों के कटाव पर रोक एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

जल (सतही जल एवं भूमिगत जल समेत) का प्रमुख स्रोत वर्षा ही है। अध्ययन क्षेत्र में औसत 100–150 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। कुल वर्षा का 75–80 प्रतिशत *ग्रीष्मकालीन मानसून* के दौरान जून से *सितम्बर* के मध्य होता है परन्तु इसमें भी अनियमितता एवं अनिश्चितता बनी रहती है। वर्तमान वर्ष (2002) मानसून काल में वर्षा न हाने से खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्षा की इस प्रवृत्ति से जल उपलब्धता भी प्रभावित होती है। वन न होने से वर्षा का ये जल बहकर निकल जाता है और हम सूखा तथा बाढ़ की विनाश लीलाएँ देखते ही रह जाते हैं।

भारत में 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है। इसके घातक प्रभाव से मानव, पशु-पक्षी और हरे-भरे खेत सभी प्रभावित हैं। नदियों झीलों जलाशयों के साथ-साथ भूमिगत जल भी प्रदूषण की चपेट में आ गया है। भूजल का स्तर भी उत्तरोत्तर नीचे की ओर जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में भी यही प्रवृत्ति है। यहाँ अनियंत्रित सिंचाई पद्धति अधाधुनिक रासायनिक खाद एवं कीटनाशक प्रयोग से न सिर्फ जल बल्कि मृदा भी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषित जल में प्रायः भौतिक रासायनिक तथा जैविक अशुद्धियाँ होती हैं जिससे वह कई रोगों का कारण बन जाता है। एक आकलन के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के 90 प्रतिशत रोग दूषित जल के कारण ही होते हैं। इस प्रकार जल

प्रदूषण की समस्या राष्ट्र के जीवन और स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है। इसके लिए यदि जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पेयजल के निःशुल्क परीक्षण तथा उसके उपचार की व्यवस्था की जा सके तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

उपर्युक्त समस्याओं के सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु ऐसी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जरूरत है जिससे हमारी जनशक्ति पशुशक्ति तथा भूमि वन जल नदी जलाशय सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा खनिज ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा जैसे प्राकृतिक ससाधनों का पूर्ण विकास एवं उपयोग किया जा सके। इसके लिए प्रथमतः वन एवं जल संरक्षण अनिवार्य है। इस हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं—

- (1) नदियों के किनारे—किनारे जहाँ तक संभव हो हरे-भरे वृक्षों की पट्टी का विस्तार किया जाना चाहिए। यह हरी पट्टी प्रदूषित जल एकत्र कर उनका शोधन कर सकती है और नदी में दूषित जल के प्रवाह को रोकने में सहायता कर सकती है। इससे मिट्टी तथा जल संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- (2) नदियों नहरों तालाबों रेलवे लाइनों झीलों सड़कों आदि के किनारे ऐसे वन वृक्षों का विस्तार किया जाना चाहिए जो मिट्टी तथा जल के संरक्षण में सहायक हों जिनसे लकड़ी ईंधन खाद्य तथा चारा भी उपलब्ध किया जा सके।
- (3) किसानों द्वारा खेतों के बीच की मेड़ ऊँची करके उसके दोनों ओर मिश्रित वृक्ष लगाए जा सकते हैं।
- (4) अध्ययन क्षेत्र में 437 प्रतिशत भूमि (11023 हेक्टेयर) परती एवं बजर है। इसके लिए किसानों को इसके 30 प्रतिशत क्षेत्र पर वन वृक्ष उद्यान तथा स्थायी वनस्पति का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्राकृतिक पशुजनित खाद तथा जल पहुँचाकर बजर भूमि को धीरे-धीरे वनस्पतियों से भरापूरा किया जा सकता है। वन जल संरक्षण एवं जल के शुद्धिकरण में भी सहायता करते हैं।
- (5) गाँवों में प्राकृतिक जलाशयों का जीर्णोद्धार कर उसके किनारे वृक्षारोपण किया जाय तथा ग्राम पंचायतों को जलाशयों तथा वन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेवारी दी जाय।
- (6) ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा प्रत्येक गाँव तथा नगर में कोंच पॉलीथीन तथा धातु के टुकड़े निश्चित स्थानों पर एकत्र करने के लिए योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- (7) ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लश शौचालयों के लिए पक्के गढ़े का निर्माण किया जाय एवं इन्हें कम्पोस्ट पिट के साथ जोड़ा जाय। इससे जल-मल से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। इससे भूमि तथा जल के प्रदूषण पर नियंत्रण भी किया जा सकता है।

(8) प्रत्येक हैडपम्प के साथ जल निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण किया जाना चाहिए।

जल प्रदूषण एवं जल सकट की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2002 को नई राष्ट्रीय जल नीति का प्रारूप राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इससे जल संबंधित समस्याएँ हल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। राष्ट्रीय जल नीति में वर्षा के जल संग्रहण तथा सदुपयोग पर अत्यधिक बल दिया गया है। केन्द्रीय जलनीति के आधार पर राज्य सरकारें अपनी कार्य-योजनाओं सहित राज्य-स्तरीय जलनीतियाँ भी बना सकेंगी।

अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सबके लिए आवास सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ निर्धारित की गई थी जो इस प्रकार हैं—

1— प्राथमिक स्वास्थ्य उपचर्या

2— प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

3— सुरक्षित पेयजल

4— सभी आवासहीन परिवारों को आवास सम्बन्धी सरकारी सहायता

5— पोषाहार

6— सभी गाँवों और व्यक्तियों को आपस में सड़कों द्वारा जोड़ना और

7— गरीबों की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना।

इस प्रकार न्यूनतम सेवाओं में आवास एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश ग्रामीण बस्तियाँ कच्चे एवं झोपड़ी के रूप में हैं। आर्थिक कारणों से इनकी मरम्मत तक नहीं हो पाती है। अतः सरकार द्वारा इनके पुराने मकान की मरम्मत एवं नये मकान के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। जिन मकानों में शौचालय नहीं है उनमें इसके निर्माण के लिए भी वित्तीय मदद की आवश्यकता है। प्रत्येक गाँव में नाली की सुविधा गलियों में खड़जा तथा सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी अपेक्षित है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण गाँवों में सामुदायिक भावना में वृद्धि है। इसके द्वारा भी सफाई नाली तथा सड़क अव्यवस्था से मुक्ति पायी जा सकती है। अधिकांश ग्रामीण समस्याएँ नगरों की नकल करने से उत्पन्न हो रही हैं। अतः गाँवों में सुविधाओं का विस्तार एवं विकास इस प्रवृत्ति पर अकुश लगाएगा।

ग्रामीण आवास की गंभीरता के मद्देनजर सरकार ने 1998 में एक राष्ट्रीय आवास और पर्यावासी नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों को लाभ पहुँचाना तथा सभी

के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सरकार 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–2007) के अंत तक आवासहीनता की स्थिति को समाप्त करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना का क्रियान्वयन चल रहा है जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं

- * इंदिरा आवास योजना
- * ऋण सहसंबिद्धी योजना
- * ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए ग्रामीण निर्मिति केन्द्र
- * ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'हडको' को दिए जाने वाले इक्विटी सहयोग में वृद्धि
- * समग्र आवास योजना,
- * ग्रामीण आवास और पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मिशन।

कार्यक्रम के फोकस को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु वर्ष 2002–2003 से ग्रामीण आवास की सभी स्कीमों को (समग्र आवास योजना को छोड़कर) मिलाकर 'इन्टीग्रेटेड रूरल हाउसिंग स्कीम' के अंतर्गत कर दिया गया है।¹

अध्ययन क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए 1985–86 से ही इंदिरा आवास योजना चलन में है। इसके द्वारा 2001 तक जनपद में 3438 आवासों का निर्माण किया जा चुका है तथा 2001–2002 के दौरान 1758 आवासों का निर्माण किया गया। 13758 आवास 50 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिए गये थे।² इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय इकाई प्रदान की जाती है जिसमें मुक्त बधुआ मजदूर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, दैवी आपदा प्रभावित परिवार गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। स्वच्छ शौचालय और धुँआरहित चूल्हे इंदिरा आवास योजना का अभिन्न अंग हैं।

जनपद में आवास निर्माण के लिए एक और योजना 'क्रेडिट कम सब्सिडी फॉर रूरल हाउसिंग कार्यक्रम'³ के नाम से चल रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निवासियों को आवास हेतु ऋण प्रदान की जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण आवास के उपर्युक्त कार्यक्रमों से अभी तक आवास सम्बन्धी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा अधिकारियों एवं बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। या तो उचित पात्र का चयन नहीं हो पाता या आवास निर्माण या मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग अन्यत्र हो जाता है। इंदिरा आवास के निर्माण में एक बात और देखने को मिली कि उसमें बालू-सीमेन्ट का अनुपात भी सही नहीं रखा जाता जिससे उसकी मजबूती सदेहास्पद हो जाती है। अतः योजनाओं के सही ढंग से

क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आमतौर पर नगरीकरण को विकास का प्रतीक माना जाता है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में विकास को नगरीकरण से नहीं मापा जाना चाहिए। क्योंकि नगरीकरण स्वयं एक समस्या है। वह दिन दूर नहीं जब नगरो से गँवो की ओर परालय होगा। नगरो के *स्लम एरिया* में रहने वाले लोगो से देवरिया के गँवो में रहने वाली जनजातियाँ अधिक खुशहाल हैं। वर्तमान में सुख की अनुभूति एवं विकास कार्यक्रमों से खुशहाली में लगातार वृद्धि होना ही समन्वित विकास है।

देवरिया जनपद में खेलकूद एवं मनोरजन के साधनों का अभाव है। खेलकूद को प्रोत्साहन देकर प्राचीन मठों किलों मंदिरों तथा प्राकृतिक स्थलों को सड़कों से सम्बद्ध कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। विकासखण्ड स्तर पर खेल-प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी चारित्रिक विकास एवं मनोरजन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। भारतीय संस्कृति में मात्र भौतिक सुविधाओं में वृद्धि ही समन्वित विकास नहीं है बल्कि सामुदायिक भावना उच्च चरित्र तथा वर्ग-द्वेष की भावना का अभाव भी समन्वित क्षेत्र-विकास की संकल्पना को पूर्ण करते हैं।

समतल मैदानी भू-भाग होते हुए भी जनपद की मृदा संरचना, तथा अन्य भौगोलिक विशेषताओं में विकासखण्ड स्तर पर विविधता है। संसाधनों के वितरण में असमानता है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन अपेक्षित है जबकि समाग नियोजन प्रणाली अपनायी जा रही है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। इस विकास प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता समाप्त होती जा रही है तथा निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसे समुचित विकास नहीं कहा जा सकता है। उपर्युक्त सभी विकास खण्डों में उनके संसाधनों के अनुरूप विकास प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता है। अर्थात् हमें अपने विकल्पों से ही विकास करना चाहिए तभी समुचित एवं आत्मनिर्भर विकास किया जा सकता है। यहाँ के अरण्यों में रहने वाले सत बिना किसी भौतिक सुविधा के सम्पूर्ण विश्व की संवेदना रखते थे। क्या आज का भौतिक युग तथा तथाकथित विकसित विश्व उन्हें पिछड़ा कह सकता है?

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को उसका सभाव्य संसाधन माना जाता है। इसमें उनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों ही सम्मिलित हैं। लोगों की गुणवत्ता में उनकी कार्य क्षमता उत्पादकता वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कौशल सांस्कृतिक मूल्य एवं उसके सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन को सम्मिलित करते हैं।

संख्या की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र सम्पन्न है बस व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। इसके लिए एक साथ अनेक दिशाओं में लगातार एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में परिवार, समाज तथा विद्यालय जैसी सामाजिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके प्रभावी भूमिका पर शोध के लिए विस्तृत क्षेत्र खुला है।

समन्वित क्षेत्र-विकास के लिए कुछ अन्य लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त करना अनिवार्य है। ये लक्ष्य हैं— सबमे कर्तव्य परायणता तथा कार्य के प्रति निष्ठाभाव पैदा करना स्त्रियों को शिक्षित कर उनकी क्षमताओं का विकास करना श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा का उपयोग करना आदि। इस प्रकार लक्ष्य स्पष्ट हैं लेकिन उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय तथा किस प्रकार उपयोग किया जाय? शोध का विषय है।

अतः अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए विकास की व्यूह रचना इस प्रकार करनी होगी जिससे न केवल सभी विकासखण्ड एक दूसरे के पूरक हो जाय बल्कि *आत्म निर्भर विकास* ऐसा हो कि सम्पूर्ण गाँव न्यायपचायत एवं विकासखण्ड एक ही माला में पिरोए हुए प्रतीत हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। कई अन्य कारक भी हैं जो जनपद के समन्वित विकास के लिए आवश्यक हैं परन्तु अनेक कारणों से उन्हें प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) के समन्वित विकास के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है जिसमें भूगोलविदों के साथ अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों से सहयोग अपेक्षित है।



References

- 1 'कुरुक्षेत्र अवदूबर-2002 पृ० 33-34
- 2 मुख्यमंत्री की साप्ताहिक समीक्षा से सम्बन्धित 33-बिन्दुओं का प्रगति विवरण फरवरी-2002 देवरिया।
- 3 'जनचेतना'-2000 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देवरिया पृ० 26





सारांश

सारांश

क्षेत्र विशेष में स्थित ऐसा केन्द्र जो क्षेत्र के निवासियों को वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करता है 'सेवाकेन्द्र' कहलाता है। अपने सम्पूर्ण क्षेत्र की सेवावृत्ति ही सेवाकेन्द्र का प्रमुख आधार है। सेवाकेन्द्र के लिए 1931 में मार्क जेफरसन ने *Central Place* शब्द का प्रयोग किया जबकि क्रिस्टालर ने इसके समानार्थक '*Zentralort*' शब्द का उपयोग किया। सेवाकेन्द्र चूँकि अपने प्रदेश के केन्द्र होते हैं और प्रायः लगभग केन्द्रस्थ भी होते हैं इसीलिए उनको 'केन्द्रस्थल' भी कहते हैं। लेकिन कोई भी सेवाकेन्द्र अपने प्रदेश के ठीक-ठीक केन्द्र में ही स्थित हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। सेवाकेन्द्र नगरीय केन्द्र ही नहीं होते बल्कि अपने चतुर्दिक क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करने वाली ग्रामीण बस्तियाँ भी सेवाकेन्द्र हो सकती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त नगरीय केन्द्र सेवाकेन्द्र होते हैं परन्तु समस्त सेवाकेन्द्रों को नगर नहीं कहा जा सकता। सेवाकेन्द्रों के लिए उसके चतुर्दिक कुछ न कुछ क्षेत्र होने आवश्यक हैं जहाँ वे अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। सेवित क्षेत्र के अभाव में सेवाकेन्द्रों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी सेवाकेन्द्र को घेरते हुए उस समूचे क्षेत्र को उसका सेवा प्रदेश कहते हैं जो अपनी विनिमयात्मक आवश्यकताओं या सेवाओं के लिए पास में स्थित लगभग उसी स्तर के अन्य केन्द्रों की अपेक्षा इस केन्द्र पर अधिक निर्भर रहता है। सेवाकेन्द्र एक बहुकार्यात्मक केन्द्र होता है जिसमें स्थित भिन्न-भिन्न कार्यों के अपने अलग-अलग प्रदेश होते हैं। इस प्रकार सेवा प्रदेश भी बहुकार्यात्मक सकेन्द्रीय प्रदेश होता है। केन्द्र के किसी एक कार्य का प्रदेश एक कार्यात्मक सकेन्द्रीय प्रदेश होता है। किसी केन्द्र के सभी कार्यों के सभी ऐसे प्रदेशों को संयुक्त रूप से एक साथ देखने पर या एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करने पर एक ऐसा 'सामान्य सेवा प्रदेश' बन सकता है जिसमें दिए हुए केन्द्र का कुल प्रभुत्व या नियंत्रण पास के प्रतिस्पर्धा करते हुए केन्द्र की तुलना में अधिक होता है। ऐसे ही सामान्य सेवा प्रदेश को सम्बन्धित सेवाकेन्द्र के सेवा प्रदेश के रूप में जाना जाता है।

सेवाकेन्द्र के सन्दर्भ में अपनी 'केन्द्र स्थल परिकल्पना' के माध्यम से क्रिस्टालर ने 1933 में बताया कि सभी तरह से एक समाग क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों का वितरण परस्पर बराबर दूरी पर प्रोत्साहित होगा एवं उनका सेवा क्षेत्र षट्भुजाकार होगा जिसके परिधि पर कम महत्व के छे सेवाकेन्द्र होंगे। इस प्रकार सेवाकेन्द्रों का विकास विभिन्न पदानुक्रमों में होता है। इनमें निम्नस्तरीय पदानुक्रम वाले सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति पास-पास होती है तथा उनके द्वारा सेवित प्रदेश छोटा होता है। इसके विपरीत उच्चस्तरीय पदानुक्रम वाले सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति दूर-दूर होती है तथा उनके सेवा प्रदेश बड़े होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय सेवाकेन्द्रों के मध्य अन्योन्याश्रिता पायी

जाती है जिससे वे एक दूसरे के विकास एवं सम्पोषण में सहायक होते हैं। सेवाकेन्द्रों की अन्योन्याश्रितता तथा उनके मध्य पदानुक्रम स्थापित करने हेतु *क्रिस्टालर* ने कई पद-सोपान बताया एवं बताया कि इसमें आनुपातिक सम्बन्ध होता है। इस अनुपात को उन्होंने 'K' मूल्य नाम दिया तथा विभिन्न दशाओं में 'K' के तीन मूल्य बताये। एवं इसके आधार पर तीन प्रतिरूपों की व्याख्या की—

1 'K' = 3 बाजार सिद्धान्त

2 'K' = 4 परिवहन सिद्धान्त

3 'K' = 7 प्रशासकीय सिद्धान्त

क्रिस्टालर की परिकल्पना से प्रेरित होकर विभिन्न विद्वान किसी क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों की अवस्थिति प्रतिरूप तथा सेवा प्रदेश के विकास में इनके प्रभाव के विश्लेषण की ओर उन्मुख हुए।

विकास के प्रेरक तत्व सेवाकेन्द्रों पर सग्रहित रहते हैं। इन्हीं तत्वों से सेवा क्षेत्र में विकास संचरित होता है। इस प्रकार सेवाकेन्द्रों पर सग्रहित कार्यों एवं सेवाओं द्वारा सेवा क्षेत्रों में धनात्मक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन को *विकास* कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में वाछनीय दिशा में नियोजित गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं। विकास की धारणा सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न पायी जाती है। विकास एक सम्मिश्र अवधारणा है। किसी क्षेत्र के विकास में कृषि उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन संचार उर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को शामिल किया जाता है। सामान्यतः विकास सतत होता है परन्तु जब विकास त्वरित, आकस्मिक एवं अप्रत्यासित होता है तब उसे *क्रांति* कहते हैं। वर्तमान समय में विकास की संकल्पना *टिकाऊ विकास* या *सविकास* (*इकोडेवलपमेन्ट*) हो गयी है। अर्थात् पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए विकास करना। दूसरे शब्दों में *सविकास* या सधृत विकास का उद्देश्य है— *मानव समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना भावी पीढ़ियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार नुकसान पहुँचाए सुनिश्चित करना।*

प्राकृतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सस्थायी आर्थिक विकास के तीन आधारभूत प्राचल हैं जिनके द्वारा विकास की दिशा तथा स्तर निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए *पेरॉक्स* ने 1955 में *'विकास ध्रुव संकल्पना'* का प्रतिपादन किया। *बोडविले* ने इसे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। *पेरॉक्स* के अनुसार किसी क्षेत्र में विकास एकाएक प्रकट नहीं होता है अपितु वह कुछ सीमित केन्द्रों पर विभिन्न रूपों में दृष्टिगत होता है तथा उसका प्रभाव अनेक रूपों में अनेक माध्यमों द्वारा फैलता है। विकास की इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकताएँ पूरी होने की क्षमता छिपी होती है। प्रस्तुत अध्ययन में विकास के लिए इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न सेवाकेन्द्रों की इसमें भूमिका को ओंकने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का नामकरण ऐतिहासिक काल में इसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्ता के आधार पर हुआ है। आरम्भ में यह क्षेत्र घने जंगलों (अरण्य) से आवृत था जिसको चीरते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर छोटी गण्डक एवं दक्षिणी भाग में सरयू (घाघरा) प्रवाहित होती है। इस कारण यह क्षेत्र देवो एवं ऋषियों के आकर्षण का केन्द्र बना जिससे यह प्रदेश देवारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी देवारण्य से देवरिया की उत्पत्ति हुयी है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व है। यह कभी भगवान श्री राम के पुत्र कुश के राज्य क्षेत्र का भाग था जिनकी राजधानी कुशीनगर में थी। अहिल्यापुर भागलपुर (भार्गवपुर आरम्भिक नाम भृगु ऋषि के नाम पर) रुद्रपुर सोहनाग आदि पौराणिक महत्त्व के स्थान आज भी विद्यमान हैं।

ऐतिहासिक काल में यह क्षेत्र मल्लों के अधीन था बाद में कोशल राज्य का अंग बना। इस पर क्रमशः महापद्मनद एवं चन्द्रगुप्त मौर्य ने भी शासन किया। इस भूमि पर अनन्त महाप्रभु एवं देवरहा बाबा ने तप एवं ध्यान साधना किए तो बाबा राघवदास जैसे देश का सपूत इसी भूमि से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़ा हुआ। इस प्रकार अतीत काल से ही यह क्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत में अत्यन्त गौरवशाली रहा है। विश्व में शील क्षमा एवं करुणा का सन्देश देने वाले देवदूतों की परम्परा रही हो या सत्य-अहिंसा जैसे सतत मानवीय मूल्यों के उपदेशकों की बात अथवा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य जैसे सामाजिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार रहा हो, महान सन्त परम्परा एवं गरिमामयी ऐतिहासिक धरोहरो हेतु यह धरती सदैव से ही नितान्त वैभवशाली रही है।

अध्ययन क्षेत्र (देवरिया जनपद) उत्तर प्रदेश के उत्तरी-पूर्वी छोर पर 26° 6' और 27° 18' उत्तरी अक्षांशों एवं 83° 29' से 84° 26' पूर्वी देशान्तर के मध्य 2389 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसके उत्तर में कुशीनगर दक्षिण में मऊ एवं बलिया, पूर्व में बिहार राज्य तथा पश्चिम में गोरखपुर जनपद अवस्थित हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद पाँच तहसील एवं पन्द्रह विकास खण्डों में विभक्त है। इसका क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 1 प्रतिशत (0.99) प्रतिशत है। 1801 से 1946 तक देवरिया गोरखपुर में सम्मिलित था। 1946 से 1994 तक इसमें वर्तमान कुशीनगर जनपद भी समाहित था। 1994 में ही इसके 54.6 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ कुशीनगर नामक नये जनपद का निर्माण हुआ।

भौतिक पृष्ठभूमि के अतर्गत अध्ययन क्षेत्र जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित 72 मीटर औसत ऊँचाई (समुद्र तल से) वाला समतल मैदान है। उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर सामान्य ढाल के अनुरूप इसमें छोटी गण्डक राप्ती घाघरा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में नवीनतम जमाव से निर्मित भाट क्षेत्र, पश्चिम में प्राचीनतम जलोढ़ निर्मित बोंगर क्षेत्र तथा दक्षिण में पतली पट्टी के रूप में कछारी क्षेत्र का विस्तार है। अपवाह प्रतिरूप को पश्चिम में प्रवाहित राप्ती नदी तत्र मध्य में प्रवाहित छोटी गण्डक नदी तत्र एवं दक्षिण-पूर्व में प्रवाहित घाघरा नदी तत्र के अतर्गत रखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में बाढ़ एक स्थायी विपदा है। इसकी देवरिया तहसील

बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित तहसील है जिसके 21 प्रतिशत गाँव बाढ़ से आक्रांत रहते हैं। क्षेत्र की संरचना सामान्यतः जलोढ़ है परन्तु इसके विभिन्न भागों में गहराई के अनुसार बालू, कणों, सिल्ट, क्ले और कंकड़ों का विभिन्न अनुपात पाया जाता है जिसका निक्षेप *प्लीस्टोसीन युग के चतुर्थ कल्प* से लेकर *आधुनिक काल (होलोसीन)* तक हुआ माना जाता है।

यहाँ की जलवायु *उष्ण-आर्द्र मानसूनी* है। औसत वार्षिक तापमान 26.4° से एव वर्षा का वार्षिक औसत 153 सेमी है। वर्षा का 85 से 90 प्रतिशत तक *ग्रीष्मकालीन मानसून* से प्राप्त होता है। वर्ष में तीन प्रमुख ऋतुएँ पायी जाती हैं— *वर्षा शीत और ग्रीष्म*।

उर्वर मृदा अनुकूल जलवायु, समतल भूमि एवं सतत प्रवाही नदियों के कारण क्षेत्र प्राचीनकाल से ही मानव बसाव का केन्द्र रहा है। 1901 में देवरिया की जनसंख्या 7.4 लाख थी जो बढ़कर 1991 में 44.4 लाख तक पहुँची। 1994 में जनपद के विभाजन के पश्चात् वर्तमान (2001) में इसकी जनसंख्या 27.30 लाख रह गयी है। 1971 में जब प्रदेश का जनघनत्व 300 था तब जनपद का घनत्व 595 था। 2001 में प्रदेश और जनपद का घनत्व बढ़कर क्रमशः 689 और 1077 हो गया। इस प्रकार जनपद में घनत्व में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। आज जनपद की 90 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में तथा मात्र 10 प्रतिशत नगरों में रहती है। जबकि प्रदेश और देश की क्रमशः 20.8 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। क्षेत्र का लिंगानुपात 1901 में 1011 था जो 100 वर्षों बाद 2001 में 1003 बना हुआ है, परन्तु 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 964 ही है जो एक चिन्तनीय प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। जनपद स्तर पर अनेक साक्षरता प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में क्षेत्र की साक्षरता 59.84 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 76.31 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 43.56 प्रतिशत है। जनसंख्या का वितरण क्षेत्र में असमान है। उत्तर-मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में उच्च जनसंख्या पश्चिम तथा मध्य-पूर्व में मध्यम-उच्च जनसंख्या तथा दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।

कृषि अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख कार्य है। 80.3 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि कार्य किया जाता है तथा कुल कर्मकारों का 80 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न हैं। जनपद का *सकल कृषित क्षेत्र* 3,14,532 हेक्टेयर है। *कृषि सघनता* 157.4 है। इसके 50 प्रतिशत क्षेत्र पर खरीफ, 48.3 प्रतिशत पर रबी एवं 1.57 प्रतिशत क्षेत्र पर *सब्जियों* की कृषि की जाती है। 0.12 प्रतिशत क्षेत्र गन्ना के अंतर्गत हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन *नलकूप* हैं। इससे 81.71 प्रतिशत भागों पर सिंचाई होती है। नहरी सिंचित क्षेत्र 17.63 प्रतिशत है।

उद्योग-धंधों की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। कुटीर उद्योग, लघुस्तरीय उद्योग आदि से सम्बन्धित कारखाने विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं। वृहद् उद्योगों के अंतर्गत चीनी उद्योग आता है जो *प्रतापपुर गौरीबाजार, भटनी देवरिया और बैतालपुर* में स्थापित हैं।

परिवहन तन्त्र में समतल भू-भाग के कारण सड़क एवं रेल परिवहन का विकास सुगमता पूर्वक हुआ है।

सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास में वहाँ की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्षेत्र के भौतिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सम्मिलित रूप में इसके उद्भव एवं विकास को सम्पन्न करते हैं। चूँकि सेवाकेन्द्र मानव अधिवासों के अभिन्न अंग होते हैं। अतः इनका उद्भव—विकास मानव अधिवासों की स्थापना से संबंधित होता है। उपर्युक्त कारकों के बदलते समीकरणों के साथ सेवाकेन्द्रों के महत्व एवं आकार में वृद्धि होती है अथवा उनका ह्रास होता है। सेवाकेन्द्रों के उद्भव विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को भौतिक एवं मानवीय वर्गों में बाँटा जा सकता है। *भौतिक कारक* सेवाकेन्द्र के आधार को निर्धारित करते हैं। इनमें जल की उपलब्धि तथा धरातल का स्वरूप सर्वप्रमुख कारक हैं। सेवा केन्द्र एक मानवीय रचना है तथा प्रशासकीय कारक यातायात मार्ग और आर्थिक विकास का स्वरूप एवं अवस्था— ये शक्तिशाली *मानवीय कारक* हैं। ये केन्द्रों के उद्भव एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार भौतिक तथा मानवीय कारक परस्पर पूरक हैं। परस्पर समन्वित रूप से कभी पूर्वगामी तो कभी अनुगामी होकर कार्य करते हैं सेवाकेन्द्रों के उद्भव एवं विकास के लिए कुछ अन्य शक्तियाँ भी उत्तरदायी होती हैं जैसे— विनिमय प्रक्रिया क्षेत्रीय आवश्यकता, प्रशासकीय क्रियाएँ परिवहन सम्बद्धता एवं कार्यात्मक आधार।

उपर्युक्त शक्तियों के प्रभाव एवं परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक काल में अनेक सेवाकेन्द्रों का जन्म—विकास एवं ह्रास हुआ। इनमें कुछ पुरातात्विक स्थलों के रूप में आज भी दृष्टव्य हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इन्हें *प्राचीनकाल* के अतर्गत— लार, सोहनाग, खुखुन्दू, साहिया, भागलपुर आदि को, *मध्यकाल* के अतर्गत सिधुआ जोबना सलेमपुर मझौली राज रुद्रपुर आदि को रखा जा सकता है। शेष सभी सेवाकेन्द्र *आधुनिक काल* में उद्भूत हुए। आधुनिक काल में सेवाकेन्द्रों के विकास में प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना, पक्की सड़कों का विकास तथा वस्तु निर्माण उद्योग एवं व्यापार के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। ऐतिहासिक कालावधि में उत्पन्न सेवाकेन्द्रों में *प्रशासनिक सेवाकेन्द्र* के अतर्गत सहनकोट सुरौली मझौली रुद्रपुर सलेमपुर काहोन को, *व्यापारिक एवं यातायात सम्बन्धी सेवाकेन्द्र* के अतर्गत साहिया बैकुण्ठपुर कर्हौव खुखुन्दू भागलपुर बरहज को तथा *धार्मिक सेवाकेन्द्र* के अतर्गत खुखुन्दू, सोहनाग लार, बरहज भरोली तथा बभनी, दीर्घेश्वरनाथ दुग्धेश्वरनाथ आदि को रखा जा सकता है।

प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसका निर्माण न केवल वहाँ प्राप्त संसाधनों द्वारा अपितु वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा भी होता है। संसाधनों तथा आर्थिक क्रियाओं के असमानता के कारण ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय सेवाकेन्द्रों का अभ्युदय एवं विकास होता है। नगरों का विकास गाँवों से होता है परन्तु सामाजिक—आर्थिक अधःसंरचना की दृष्टि

से ये ग्रामीण बस्तियाँ नगरो से पिछड़ी हैं। इसी कारण गावों से नगरो की ओर जनसंख्या का पलायन हो रहा है। इस समस्या का समाधान ग्रामीण बस्तियों की सामाजिक-आर्थिक अर्थसंरचना के विकास में निहित है। इस प्रकार का क्षेत्रीय विकास सेवाकेन्द्रों के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ लगभग सभी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं का केन्द्रीकरण हो। सेवाकेन्द्रों को परिवहन एवं संचार माध्यमों से परस्पर गुँथ कर विकास को और तीव्र किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्र के विकास में सेवाकेन्द्रों की भूमिका का आकलन करने एवं क्षेत्र के भावी विकास के लिए सेवाकेन्द्रों के माध्यम से व्यवस्थापना एवं नियोजन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अध्ययन क्षेत्र के ऐसे सभी प्रकार के विकास जनक केन्द्रों को सेवाकेन्द्र कहा गया है जिनका अभिनिर्धारण उनकी विशिष्ट स्थिति एवं कार्यों के केन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप सेवाकेन्द्रों के रूप में स्वयमेव हो जाता है। सेवाकेन्द्र की स्थापना एवं स्थायित्व उन सामाजिक-आर्थिक कार्यों पर निर्भर करता है जिसके द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अतः ये केन्द्र परिधीय क्षेत्र से इष्टतम रूप से जुड़े होते हैं। इन केन्द्रों की सेवाओं का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे इसके लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में विभिन्न स्तर के सेवाकेन्द्रों का जाल होना चाहिए।

क्षेत्रीय विकास के सन्दर्भ में सबसे जटिल प्रक्रिया सेवाकेन्द्रों के निर्धारण की है। आँकड़ों की अनुपलब्धता इसमें सबसे बड़ी बाधा है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के 2004 बस्तियों में से *बी एन मिश्र* (1980) द्वारा प्रयुक्त विधि का उपयोग करते हुए कार्यों की *औसत कार्याधार जनसंख्या, उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप* और *बस्तियों की सम्बद्धता* के माध्यम से सेवाकेन्द्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यों के क्षेत्रीय महत्व औसत कार्याधार मूल्य और उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप के आधार पर 51 केन्द्रीय कार्यों एवं सेवाओं का चयन किया गया है जो अध्ययन क्षेत्र में वितरित बस्तियों द्वारा सम्पादित होते हैं। *औसत कार्याधार जनसंख्या* की गणना *रीड मुञ्च* विधि द्वारा की गयी है। पुनः कार्याधार सूचकांक की गणना कर कार्यों के *चार पदानुक्रम* निर्धारित किये गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्तियों में से न्यूनतम 5 केन्द्रीय कार्यों को आधार बनाकर जनपद में कुल 47 सेवाकेन्द्रों को मान्यता प्रदान की गयी है। *उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप* के अंतर्गत उपभोक्ताओं के द्वारा उनके आवश्यक सामानों के क्रय-विक्रय हेतु सेवाकेन्द्रों तक संचरण के स्वरूप एवं उनकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में उपभोक्ताओं के संचरण प्रतिरूप के अध्ययन हेतु 150 ग्रामों का सर्वेक्षण कर जनपद के उपभोक्ता संचरण प्रतिरूप का आकलन किया गया है। इन 150 ग्रामों के प्रतिचयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। कि प्रतिचयनित ग्राम लगभग पूरे जनपद का प्रतिनिधित्व करे। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के संचरण का प्रतिरूप उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों के प्रकार तथा उनकी आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित होता है। जनपद में अधिकतम संचरण 45 किमी के लगभग है। उपभोक्ताओं के संचरण की दृष्टि से देवरिया मुख्यालय सबसे बड़ा सेवाकेन्द्र है। इसके लिए इसकी लगभग केन्द्रीय

अवस्थिति बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। उपभोक्ता सचरण की दृष्टि से दूसरे क्रम के सेवाकेन्द्र—सलेमपुर रुद्रपुर गौरीबाजार पथरदेवा गौराबरहज लार भाटपार भटनीबाजार रामपुर कारखाना भलुअनी बैतालपुर और बनकटा है। देसही देवरिया भागलपुर मझौलीराज एव तरकुलवाँ तीसरे क्रम के सेवाकेन्द्र हैं। चतुर्थ क्रम के सेवाकेन्द्रों की सख्या क्षेत्र में 30 है। इनपर केन्द्र से लगभग 4—5 किमी अर्द्धव्यास तक की जनसख्या सचरण करती है। इस प्रकार सचरण की दृष्टि से इनका स्थानीय महत्व ही अधिक है। कार्यों एव सेवाओं के लिए सचरण परिवहन मार्गों द्वारा ही सम्पन्न होता है। अतः सेवाकेन्द्र का उद्भव—विकास एव अस्तित्व परिवहनीय सम्बद्धता पर निर्भर करता है। अध्ययन क्षेत्र में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क एव रेलमार्ग है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़को तक के सभी प्रकार पाये जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में जनपद के सकल परिवहन मार्गों की लम्बाई एव परिवहन मार्ग विशेष की लम्बाई के आधार पर प्रत्येक प्रकार के परिवहन मार्ग का मूल्य ज्ञात किया गया है। इस क्रम में राज्य उच्चपथ एव जिलामार्ग का मूल्य ग्रामीण मार्गों से उच्च प्राप्त हुआ है। परिवहन मार्गों के मूल्यों के आधार पर प्रत्येक सेवाकेन्द्रों का सम्बद्धता मूल्य ज्ञात किया गया। इसमें अधिकतम मूल्य 166 तथा न्यूनतम मूल्य 1 प्राप्त हुआ। सेवाकेन्द्रों के निर्धारण में 3 से ऊँचे मूल्य के सेवाकेन्द्रों का चयन किया गया। सर्वाधिक सम्बद्धता मूल्य देवरिया मुख्यालय का (166) प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों आधारों—औसत कार्याधार जनसख्या, उपभोक्ता सचरण प्रतिरूप एव परिवहनीय सम्बद्धता के आधार पर जनपद में 47 केन्द्रों को सेवाकेन्द्र के रूप में मान्यता की पुष्टि हो जाती है। तीनों ही आधारों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि उच्च सूचकांक उच्च सेवाकेन्द्र एव निम्न सूचकांक निम्न सेवाकेन्द्र को प्रदर्शित करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के सेवाकेन्द्रों के केन्द्रीयता निर्धारण में कार्यों व सेवित जनसख्या को आधार बनाया गया है। कार्यों के महत्व एव मूल्य की गणना प्रत्येक कार्य के औसत कार्याधार जनसख्या सूचकांक के द्वारा की गयी है। केन्द्रीयता के आधार पर ही सेवाकेन्द्रों का चार पदानुक्रम विनिश्चित किया गया। इस प्रकार प्रथम अनुक्रम में—1 द्वितीय में—12, तृतीय में—4 और चतुर्थ में—30 सेवाकेन्द्र सम्मिलित हुए। प्रथम स्तर का एकमात्र केन्द्र देवरिया है।

अध्ययन क्षेत्र के सभी चयनित सेवाकेन्द्रों के सेवित क्षेत्र की गणना रीले (1931) के 'फुटकर केन्द्राकर्षण नियम' (Law of retail gravitation) एव 'विच्छेद बिन्दु समीकरण' (Breaking point equation) के आधार पर की गई है। जहाँ प्रथम क्रम के सेवाकेन्द्र देवरिया का प्रभाव समूचे जनपद पर फैला है वही सलेमपुर रुद्रपुर गौरीबाजार पथरदेवा बरहज, लार भाटपार भटनी बाजार रामपुर कारखाना भलुअनी बैतालपुर, बनकटा द्वितीय स्तर के प्रभावशाली सेवाकेन्द्र हैं।

अध्ययन क्षेत्र मूलतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कुल कार्यशील जनसख्या का 78.76 प्रतिशत भाग कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यों में लगा हुआ है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 80.90 प्रतिशत भाग पर कृषि होती है। कृषि के आधारभूत सघटक मृदा, जल की उपलब्धता, श्रम एव तकनीक उर्वरक

प्रयोग है परन्तु कृषि कार्य में कुछ ऐसे तत्वों का भी समावेश होता है जो कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में जिनकी स्थापना से विकास तीव्र होता है। ये तत्व पूर्णतः मानवीय हैं तथा इनकी स्थापना सेवाकेन्द्रों पर ही होती है। इन्हीं इकाइयों के माध्यम से सेवाकेन्द्र सेवा क्षेत्र को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं कृषि विकास के इन उत्प्रेरक तत्वों में बीज गोदाम/उर्वरक डिपो ग्रामीण गोदाम कीटनाशक डिपो शीतभण्डार कृषि सेवाकेन्द्र मण्डी समिति पशुचिकित्सालय पशुसेवा केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सहकारी समितियाँ एवं वित्तीय संस्थाएँ प्रमुख हैं। इन इकाइयों की विभिन्न केन्द्रों पर स्थापना का कृषि विकास पर प्रभाव—कृषि प्रतिरूप उत्पादन उत्पादकता गहनता शस्य साहचर्य फसलचक्र पशुपालन—मत्स्यपालन का कृषि के साथ संयोजन आदि के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप वितरण के लिए कालिक पक्ष को अपनाया गया है। क्योंकि इसमें स्थानिक प्रतिरूप का स्वतः समावेश हो जाता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल प्रतिरूप में 1971–2001 के तीस वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1971–72 में जहाँ खरीफ सर्वप्रमुख फसल थी और इसमें धान एवं गन्ना की सर्व प्रमुख भूमिका थी वही 2001 में सम्पूर्ण खरीफ फसलों के प्रतिशत क्षेत्र में गिरावट हुयी परन्तु धान के अतर्गत प्रतिशत क्षेत्र लगभग समान बना रहा। 1971–72 से 2001 तक के कृषि विकास कालावधि में फसल प्रतिरूप विविधीकरण से विशेषीकरण की ओर उन्मुख हुआ है।

विगत 30 वर्षों में कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुयी है। सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः मक्का (1561 प्रतिशत) ज्वार (718 प्रतिशत) बाजरा (380 प्रतिशत) में हुयी। क्षेत्र की प्रमुख फसलों— धान गेहूँ, गन्ना में ये वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुयी।

अध्ययन क्षेत्र में 1971–72 में शस्य गहनता 116.98 थी तथा एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र शुद्ध कृषित क्षेत्र का 31 प्रतिशत था जबकि 2001 में शस्य गहनता बढ़कर 155.63 हो गयी। इस समय एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्र से प्रतिशत 55.63 था।

अध्ययन क्षेत्र के शस्य संयोजन की गणना दोई के सूत्र के आधार पर की गई है। 1971–72 में चावल क्षेत्र की प्रमुख फसल थी गेहूँ गन्ना का प्रतिशत भी उच्च था। पूरे क्षेत्र में तीनों ही फसलों का साहचर्य था। 2001 तक आते-आते ये साहचर्य परिवर्तित होकर मात्र गेहूँ और धान का (दो फसली) रह गया। ये क्षेत्र के कृषि विशिष्टीकरण की ओर संकेत करता है। विकासखण्ड स्तर पर तीन फसली साहचर्य वर्तमान में केवल देसही देवरिया और रामपुर कारखाना में ही पाया जाता है। बाकी सभी विकास खण्डों में दो फसली साहचर्य है। गौरीबाजार और पथरदेवा में ये साहचर्य चावल और गेहूँ के रूप में है तथा शेष सभी में गेहूँ और चावल के साथ।

1971–72 में अध्ययन क्षेत्र के किसान परंपरा और अनुभवाधारित फसल चक्र अपनाते थे। जिसमें फसलों की विविधता होती थी। क्षेत्र के विभिन्न भागों में ये चक्र मृदा प्रकार और सिंचाई

सुविधा से नियंत्रित था। वर्तमान में कृषक परंपरा के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिकता एवं लाभ को ध्यान में रखकर फसल चक्र अपना रहे हैं। इसमें विशिष्टीकरण के प्रभाव के कारण फसल चक्र सीमित फसलों तक ही सिमट कर रह गया है। ये फसल चक्र— धान—गेहूँ, मक्का—आलू, मक्का—तोरिया—गेहूँ, धान—गेहूँ—गन्ना आदि के रूप में पाया जाता है।

पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है। 1993 में क्षेत्र में कुल 7 98 121 पशु थे। इसमें गौजातीय (38.4 प्रतिशत) महिषवशीय (17.91 प्रतिशत) पशुओं की प्रमुखता थी। 1997 तक सभी प्रकार के पशुओं की संख्या में भारी कमी हुई है। सर्वाधिक कमी भेड़ों एवं गौजातीय पशुओं की संख्या में (क्रमशः 42.68 प्रतिशत एवं 42.15 प्रतिशत) हुई है।

अध्ययन क्षेत्र के कृषक की सहनशीलता उल्लेखनीय तथ्य है। लगातार बाढ़—सूखा का शिकार होने के बावजूद कृषक देव—अधीन कृषि कार्य करने में लगे हैं। क्षेत्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए समन्वित फसल पशुधन मत्स्यपालन तथा बागवानी जैसे उद्यमों के जरिये कृषि में विभिन्नता लाकर कृषि आमदनी बढ़ानी होगी। चूंकि कृषि विकास के बिना अध्ययन क्षेत्र की गरीबी को दूर करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः कृषि विकास को केवल और अधिक अनाज उपजाने के साधन के रूप में ही नहीं लेना है बल्कि आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप में भी लेना है। कृषि विकास नियोजन के लिए भूमि—सुधार कृषि—यन्त्रीकरण पशुधन एवं डेयरी विकास दलहन एवं तिलहन विकास औद्योगिक फसलों का विकास मिश्रित खेती, शुष्क भूमि कृषि खरपतवार नियन्त्रण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि रसायनों एवं उर्वरकों के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने बचत तथा को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकिंग सुविधाओं के विकास की भी आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर गिनी—चुनी मात्र कुछ औद्योगिक इकाइयों हैं। चूंकि जनपद सिन्धु—गंगा मैदान के जलोढ़ निक्षेपों तथा राप्ती, छोटी गण्डक एवं इनकी शाखाओं द्वारा निर्मित कृषि प्रधान मैदानी क्षेत्र है, साथ ही औद्योगिकरण मुख्यतः क्षेत्र में प्राप्य ससाधनों एवं ऊर्जा उपलब्धता पर निर्भर करता है और क्षेत्र प्राकृतिक ससाधन की दृष्टि से निर्धन है परन्तु कृषि क्षेत्र में समृद्ध है। अतः यहाँ मूलतः कृषि आधारित उद्योग ही प्रोत्साहित हुए। औद्योगिक पिछड़ेपन की दृष्टि से शासन द्वारा इस जनपद को 'सी' श्रेणी में रखा गया है।

अध्ययन क्षेत्र में वृहद् उद्योग के अंतर्गत चीनी उद्योग को रखा जा सकता है। यह उद्योग क्षेत्र का प्राचीनतम उद्योग है। 18 वीं शदी में यहाँ गुड तथा खाड़सारी उद्योग विकसित थे जिसका केन्द्र रामपुर कारखाना था। बरहज चीनी के गोदामों के लिए प्रसिद्ध था। 20 वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जनपद में चीनी उद्योग के बड़े—बड़े कारखानों की स्थापना के साथ खाड़सारी उद्योग नष्ट हो गया। पूरे अध्ययन क्षेत्र में चीनी उद्योग हेतु अनुकूल स्थितियाँ सुलभ हैं। क्षेत्र में गन्ना की उच्चतम पैदावार है घनी जनसंख्या सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराती है तथा ईंधन के रूप में खोइया का उपयोग

होता है। देवरिया मुख्यालय की उत्तर-पूर्व रेलवे पर अवस्थिति तथा विकसित सड़क परिवहन जाल के कारण चीनी के निर्यात एवं व्यापार के कारण इसे आदर्श स्थिति प्राप्त है। वर्तमान समय में जनपद में चीनी उद्योग सकट के दौर से गुजर रहा है। चीनी उद्योग को सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग से मुक्त करने (1998) तथा जनवरी 2000 से लेवी व खुली बिक्री अनुपात 40:60 से घटाकर 30:70 किये जाने के बावजूद उद्योग की समस्या बढ़ती ही जा रही है। चीनी गोदामों में ही पड़ा हुआ है तथा किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है।

कृषि-कृषक एवं उद्योग की इस परस्पर सम्बद्धता के कारण चीनी उद्योग की इस समस्या का दुष्प्रभाव समूचे कृषि प्रतिरूप में गन्ना के अंतर्गत क्षेत्र का ह्रास कृषक का गिरता आय स्तर एवं अतंत ह्रासोन्मुख आर्थिक एवं सामाजिक विकास के रूप में दिख रहा है। क्षेत्र की प्रमुख चीनी मिलें प्रतापपुर गौरीबाजार भटनी देवरिया एवं बैतालपुर में स्थित हैं।

अध्ययन क्षेत्र लघु उद्योग में भी पिछड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत भी कृषि पर आधारित उद्योग ही मुख्य रूप से विकसित हैं। इनमें राइस मिलें एवं आटा चक्की सर्वप्रमुख हैं। ये उद्योग विभिन्न सेवाकेन्द्रों पर स्थापित हैं। दफ्ती एवं कागज उद्योग की दो इकाइयों गौरी बाजार विकासखण्ड में तथा एक-एक इकाइयों देवरिया एवं लार में स्थापित हैं। गन्ने की खोई एवं पुआल इसके प्रमुख कच्चा माल हैं।

जनपद के लगभग सभी सेवाकेन्द्रों पर ग्रामीण बाजारों में तथा बड़े ग्रामों में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विकसित हैं। इसके अलावे विभिन्न विकास खण्डों में मत्स्य पालन उद्योग का भी विकास किया जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में श्रम के बाहुल्य तथा पूँजी के अभाव को देखते हुए कुटीर उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता है। जनपद कृषि फल एवं पशुधन में सम्पन्न है परन्तु वित्तीय अनुपलब्धता की समस्या है। अतः समुचित वित्त प्रबन्धन द्वारा इनपर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्षेत्र आरंभिक काल में आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र रहा है। सम्बन्धित स्थल आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। इन केन्द्रों पर अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास कर जनपद पर्यटन उद्योग में अग्रणी भूमि निभा सकता है।

परिवहन तंत्र आर्थिक विकास की रीढ़ है सेवाकेन्द्रों से सेवाओं एवं कार्यों का संचरण परिवहन मार्गों के सहारे ही चतुर्दिक क्षेत्र में संचरित हो पाती है। परिवहनीय दृष्टि से जिस सेवाकेन्द्र की सम्बद्धता जितनी ही अच्छी होती है उसका सेवाक्षेत्र तथा पदानुक्रम उतना ही ऊँचा होता है। अतः परिवहन तंत्र वह मार्ग जाल है जिससे होकर विकास प्रवाहित होता है। अध्ययन क्षेत्र में विकास के मुख्य प्रेरक तथा ससाधनों के प्रमुख संयोजक तत्व परिवहन एवं संचार का अपेक्षाकृत अभाव है। परिवहन के प्रमुख साधन सड़कें एवं रेलवे हैं। जनपद में 111 किमी लम्बी इकहरी ब्राडगेज की रेलवे लाइन है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास में इसकी विशेष भूमिका है। चीनी उद्योग की सभी इकाइयों रेलमार्ग के किनारे ही स्थापित हैं। जनपद के 10 विकासखण्डों में रेलमार्ग का विस्तार है। सर्वाधिक

विस्तार सलेमपुर एव भटनी विकासखण्ड में है। जनपद में कुल 19 रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) हैं।

क्षेत्र के समतल भू-भाग के कारण सड़कें सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग हैं क्योंकि इनसे सभी सेवाकेन्द्रों को सम्बद्ध किया जा सकता है। क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर राज्य उच्चमार्ग मुख्य जिलामार्ग अन्य जिलामार्ग तथा पीडब्लूडी की सड़कें हैं। पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1940 किमी है।

प्रस्तुत अध्ययन में सड़क घनत्व की गणना दो प्रकार से की गयी है—

- 1— विकासखण्ड स्तर पर प्रति 1 000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर तथा
- 2— 1 00 000 की मानक जनसंख्या पर (विकासखण्ड स्तर पर)।

प्रथम आधार पर सर्वाधिक घनत्व देवरिया सदर विकासखण्ड में तथा न्यूनतम भलुअनी विकासखण्ड में है। इस दृष्टि से क्षेत्र का उत्तरी आर पूर्वी क्षेत्र सम्पन्न है जबकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम घनत्व के क्षेत्र हैं। दूसरे आधार पर देवरिया सदर सर्वाधिक घनत्व एवं भलुअनी न्यूनतम घनत्व वाला विकासखण्ड है। अध्ययन क्षेत्र में सड़क घनत्व एवं विकास में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। क्षेत्र के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। कम घनत्व वाले और कम विकसित हैं। पक्की सड़कों के विकास द्वारा इनके क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सड़क अभिगम्यता के मापन के लिए पक्की सड़कों को आधार बनाया गया है। इससे प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार जनपद का 52.13 प्रतिशत क्षेत्र सड़क मार्ग द्वारा अभिगम्य है। सर्वाधिक अभिगम्यता भाटपाररानी विकासखण्ड में (83.76 प्रतिशत) है। भलुअनी में न्यूनतम मात्र 29.23 प्रतिशत गाँव ही सड़कों द्वारा अभिगम्य हैं। भाटपाररानी देसही देवरिया, भागलपुर रामपुर कारखाना रुद्रपुर और लार विकास खण्डों में अभिगम्यता जनपद औसत से ऊँची है।

अध्ययन क्षेत्र में सम्बद्धता को तीन माध्यमों से तीन स्तरों पर ज्ञात किया गया है।

प्रथम— परिवहनीय सम्बद्धता— देवरिया सेवाकेन्द्र का सम्बद्धता मूल्य सर्वाधिक (55.33) है। उसके बाद क्रमशः सलेमपुर (46.00) गौरी बाजार (38.0), बैतालपुर (31.16) आदि सेवाकेन्द्रों का स्थान है। न्यूनतम मूल्य घाटी का (1.00) है।

द्वितीय— सेवाकेन्द्रों की सम्बद्धता— इसे 'कनेक्टिविटी मैट्रिक्स' के आधार पर ज्ञात किया गया है। जनपद का सबसे सम्बद्ध सेवाकेन्द्र देवरिया है जो प्रत्यक्षतः 13 सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध है। इसके बाद क्रमशः सलेमपुर, रामपुर कारखाना रुद्रपुर, गौरीबाजार आदि हैं। सबसे कम सम्बद्धता भटनी बनकटा और पथरदेवा सेवाकेन्द्र की मात्र 1 है।

तृतीय— मार्गजाल की सम्बद्धता— इसके अतर्गत अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़कों के जाल के सन्दर्भ में प्रमुख बिन्दुओं की संख्या— 43 बाहुओं की संख्या 115 तथा असम्बद्ध ग्राफ की संख्या 16

है। इन बिन्दुओं एवं बाहुओं के माध्यम से सड़क जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले *अल्फा बीटा* तथा *गामा निर्देशांक* की गणना की गयी है। अध्ययन क्षेत्र के सड़क जाल का *अल्फा निर्देशांक*— 0.69 है *बीटा निर्देशांक*— 2.67 है तथा *गामा निर्देशांक*— 0.93 है,

सड़क सम्बद्धता के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सड़क सम्बद्धता तथा अधिगम्यता औसत से अच्छी है परन्तु यह केवल पक्की सड़कों पर ही आधारित है। इस सम्बद्धता में क्षेत्रीय स्तर पर काफी भिन्नता मिलती है। सम्बद्धता में सबसे बड़ी बाधक नियतकालिक बाढ़ है।

अध्ययन क्षेत्र के यातायात प्रवाह का मापन सड़कों पर चलाने वाले व्यक्तिगत तथा सरकारी बसों के माध्यम से किया गया है। प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार जनपद का सबसे व्यस्ततम मार्ग *सलेमपुर—देवरिया—गौरीबाजार मार्ग (एसएच-1)* है जो देवरिया को गोरखपुर से सम्बद्ध करता है। इस पर बसों की सर्वाधिक आवृत्ति प्रतिदिन 110 तक है।

अध्ययन क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान पक्की सड़कों में सुधार तथा उन्हें चौड़ा करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत *देवरिया—तरकुलवा मार्ग (एसएच-79)*, और *सलेमपुर—देवरिया—गोरखपुर मार्ग (एसएच-1)* को दोहरा करना आवश्यक है। चूंकि ग्रामीण सड़कें ही ग्रामीण विकास का आधार हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र की 90.14 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को सेवाकेन्द्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल होना आवश्यक है। गाँवों को सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध कर क्षेत्र का बहुमुखी विकास किया जा सकता है।

विकास में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्ययन क्षेत्र की व्यक्तिगत संचार साधनों की स्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ देश में औसत 4,731 लोगो पर एक डाक घर है वही जनपद में 9,892 लोगो पर एक डाकघर है। जनपद के रामपुर कारखाना विकासखण्ड की स्थिति इस दृष्टि से सबसे बुरी है। जहाँ 12,248 व्यक्तियों पर एक डाकघर है। जिले में तारघर की कुल संख्या मात्र 21 है। संचार के इस युग में जहाँ देश में प्रति हजार व्यक्तियों पर 32 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध हैं। वही जनपद में ये उपलब्धता मात्र 2.17 प्रति हजार ही है। यदि जनपद के सभी टेलीफोन एक्सचेंज (35) की कुल कनेक्शन क्षमता (31,832) का सम्पूर्ण विकास कर लिया जाय तब भी प्रति हजार टेलीफोन कनेक्शन उपलब्धता मात्र 11.65 ही हो पायेगी जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 20.35 कम है। पीसीओ केन्द्र के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति हजार जनसंख्या पर उपलब्धता 26 है। वही जनपद में ये संख्या 0.24 ही है। परन्तु सम्पूर्ण संख्या का 60.9 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है, इससे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति ग्रामीण रुझान व्यक्त होती है।

जनसंचार के माध्यमों में अध्ययन क्षेत्र में दूरदर्शन चलचित्र समाचार प्रमुख माध्यम है। परन्तु जनपद में संचार तंत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा—साक्षरता का अल्प विकास है क्योंकि शिक्षा का संचार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जनपद में संचार के विकास के लिए प्राचीनतम माध्यमों (डाक तार आदि) एवं नवीनतम तकनीकी माध्यमों (टेलीफोन, कम्प्यूटर इन्टरनेट, दूरदर्शन रेडियो

आदि) का परस्पर समन्वय आवश्यक है क्योंकि विकास में सबके लिए एक सुनिश्चित भूमिका है। इन सभी माध्यमों का विकास कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारकों से अन्तर्सम्बन्धित है जैसे शिक्षा-साक्षरता का विकास सुसम्बद्ध एवं अभिगम्य परिवहन तंत्र एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता। अतः प्रथमतः उपर्युक्त सुविधाओं का जनपद में विकास किया जाय तथा उसके बाद जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सुविधाओं की क्षेत्र में स्थापना की जाय।

किसी भी क्षेत्र का विकास दो स्तरों पर प्रतिबिम्बित होता है— मानवीय विकास स्तर पर तथा क्षेत्रीय विकास के स्तर पर। दोनों क्षेत्रों के विकास स्तर मापन के अपने-अपने प्राचल हैं परन्तु सर्वांगीण विकास दोनों के सन्तुलित विकसित स्वरूप से ही झलकता है। मानवीय विकास के बिना क्षेत्रीय विकास विरोधाभास पैदा करता है जिससे विकास बाधित होता है। उपर्युक्त आधार पर विकास के दो पक्ष हुए—आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। अभी तक विकास के आर्थिक क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों की भूमिका का विश्लेषण ही किया गया है। जो एकांगी है। समन्वित विकास हेतु सामाजिक क्षेत्र के विकास में सेवाकेन्द्रों की भूमिका के अतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुविधाओं का विश्लेषण किया गया है।

शिक्षा किसी समाज के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमारी विश्लेषण क्षमता और तर्क बुद्धि का विकास करती है और सही-गलत का निर्णय कर पाने का विवेक पैदा करती है।

2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 57.36 प्रतिशत है जबकि जनपद की साक्षरता 59.84 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रदेश में पुरुष और स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 76.31 और 43.56 है। इस प्रकार 1991 से 2001 के मध्य जनपद की कुल साक्षरता में 17.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसमें पुरुष साक्षरता में 14.91 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता में 20.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि इस बीच प्रदेश की कुछ साक्षरता में वृद्धि मात्र 14.94 प्रतिशत ही रही। इसमें पुरुष साक्षरता में 18.11 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। इस प्रकार जनपद स्तर पर साक्षरता की दृष्टि से एक सार्थक उपलब्धि हासिल करने के बावजूद अभी भी विकासखण्ड स्तर पर इसमें काफी भिन्नता है। 2001 की जनगणना के अनुसार आज भी 15 में से मात्र 5 विकासखण्डों में ही साक्षरता जनपद के औसत साक्षरता (59.84 प्रतिशत) से अधिक है। उच्चतम साक्षरता लार विकासखण्ड में (67.7 प्रतिशत) तथा निम्नतम साक्षरता रुद्रपुर विकासखण्ड में (49.7 प्रतिशत) पायी जाती है। अर्थात् इसमें 18.0 प्रतिशत का अंतर है।

औपचारिक शिक्षा के अतर्गत जनपद में जूनियर बेसिक स्कूलों की कुल संख्या 1813 है। इसमें से 55 विद्यालय नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। प्रतिलाख जनसंख्या के आधार पर स्कूलों की सर्वाधिक संख्या भागलपुर में तथा न्यूनतम संख्या गौरीबाजार विकासखण्ड में है। विकासखण्ड स्तर पर प्रतिलाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या में 37.5 तक का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय-जनसंख्या अनुपात 1:1131 है, वहीं नगरीय क्षेत्र में ये अनुपात 1:3952 है। इस प्रकार

नगरीय क्षेत्रों में इस सुविधा का अभाव प्रतीत होता है। शहरों में निजी क्षेत्रों द्वारा स्कूल/कॉन्वेंट स्थापना के लिए यह एक अप्रत्यक्ष कारण है। जनपद में 413 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। विद्यालय एवं जनसंख्या अनुपात की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थिति *सलेमपुर* एवं न्यूनतम स्थिति *देसही देवरिया* की है। प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम संख्या 34.9 एवं न्यूनतम संख्या 11.6 है। इसमें 23.3 का अंतर है जो न्यूनतम स्कूल संख्या के लगभग दूने के बराबर है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की दृष्टि से स्कूल और जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात 1.5189 है तथा नगरीय क्षेत्रों में 1.7245 है। हायर सेकेंड्री विद्यालयों की जनपद में कुल संख्या 203 है। इसमें से 171 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 32 नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित थी। प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक संख्या *सलेमपुर* में (14.0) है तथा न्यूनतम संख्या *गौरीबाजार* में (3.1) हैं। इसमें भी विकासखण्ड स्तर पर भारी अंतर है जो 10.9 है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय-जनसंख्या अनुपात 1.11622 एवं नगरीय क्षेत्रों में ये अनुपात 1.6792 हैं। इस प्रकार इस अनुपात में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लगभग दूने का अंतर है जो शिक्षा के सतुलित विकास के प्रतिकूल है। उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जनपद में 14 महाविद्यालय हैं। इनमें दो महिला महाविद्यालय हैं जो *देवरिया सदर* एवं *लार* विकासखण्ड में स्थिति हैं। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय एवं जनसंख्या अनुपात 1.331251 एवं नगरीय क्षेत्रों में ये अनुपात 1.27170 है जो असतुलित है।

जनपद में शिक्षक एवं विद्यार्थियों का अनुपात विभिन्न स्तर के शिक्षण संस्थाओं में भिन्न-भिन्न है। जूनियर बेसिक स्कूल में ये अनुपात 1.57 है। ये अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 1.54 और नगरीय क्षेत्रों में 1.135 है। सीनियर बेसिक स्कूल में ये अनुपात 1.86 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.84 और नगरीय क्षेत्रों में 1.116 है। हायर सेकेंड्री स्कूल के स्तर पर यह अनुपात जनपद में 1.41 है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 1.48 और नगरीय क्षेत्र में 1.20 है।

जनपद में साक्षरता की स्थिति शिक्षण संस्थाओं के प्रतिरूप एवं उनकी निश्चित जनसंख्या पर उपलब्धता तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के विश्लेषण के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई कमियाँ दृष्टिगत हुयी हैं। जनपदीय साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत से 5.54 प्रतिशत कम है। इसमें स्त्री साक्षरता की स्थिति सबसे चिन्ताजनक है। इस दृष्टि से (स्त्री सा) राष्ट्रीय साक्षरता और जनपदीय साक्षरता का अंतर 10.6 प्रतिशत है। जनपद में जनसंख्या के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की अपर्याप्तता है। जो शिक्षण संस्थाएँ हैं भी उनमें शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात सतोषजनक नहीं है। अतः अध्ययन क्षेत्र में शैक्षणिक नियोजन को उपर्युक्त सन्दर्भ में ही प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि शिक्षा का विकास जनपद के विकास में सहभागी बन सके। इसके अन्तर्गत दो स्तरों पर नियोजन अपेक्षित है— *पहला*— साक्षरता वृद्धि हेतु चलाए गए विभिन्न अभियानों के सन्दर्भ में, तथा *दूसरा* विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर।

जनपद में स्वास्थ्य सुविधा का प्रमुख केन्द्र जिला चिकित्सालय है। यहाँ स्वास्थ्य से सम्बन्धित

सभी सुविधाएँ उपलब्ध है। इसके बाद 7 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। जनपद में क्षय रोग का एक कुष्ठ रोग के तीन तथा सक्रामक रोग का एक स्वास्थ्य केन्द्र है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये सामुदायिक विकासखण्ड में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये प्रदान की जाती है। ग्रामीण जनसंख्या का आधुनिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली से सम्पर्क का यह पहला स्तर होता है। जनपद में इनकी संख्या देवरिया मुख्यालय को छोड़कर 71 है। नगरीय क्षेत्र में 10 केन्द्र स्थित है। इस प्रकार कुल 81 केन्द्र जनपद में स्थित है। जनपद में कुल स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या 329 है। इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल शैयाओं की संख्या 848 है। जनपद में असहायता प्राप्त तथा आर्थिक सहायता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की संख्या क्रमशः 2 और 1 है। जनपद में परिवार एवं मातृशिशु कल्याण केन्द्र परिवार नियोजन केन्द्र की कुल संख्या 20 है।

जनपद में प्रतिलाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का औसत 3.6 है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये औसत 3.5 है जबकि नगरीय क्षेत्र में 4.6 है। बरहज विकासखण्ड में जनपद में सर्वाधिक तथा नगरीय क्षेत्र के औसत से भी अधिक 5.1 स्वास्थ्य केन्द्र है। जबकि भलुआनी में न्यूनतम 2.8 स्वास्थ्यकेन्द्र ही एक लाख जनसंख्या पर उपलब्ध हैं। जनपदीय औसत से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों की उपलब्धता केवल पथरदेवा रुद्रपुर बरहज भटनी भागलपुर विकासखण्डों में ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। हालाँकि शहरों में पर्यावरण का क्षय अधिक हुआ है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोगग्रस्तता का स्तर शहरों के मुकाबले बहुत अधिक है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन सम्भाव्यता शहरों के मुकाबले कम है।

जनपद में विकासखण्ड स्तर पर चिकित्सकों की सर्वाधिक उपलब्धता भाटपाररानी एवं सलेमपुर विकासखण्ड में प्रतिलाख जनसंख्या पर 8.3 है। न्यूनतम उपलब्धता गौरीबाजार में (3.4) है। यहाँ नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता जहाँ 14.7 प्रति लाख जनसंख्या पर है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 6.0 ही है अर्थात् दूने से भी अधिक का अंतर है। प्रतिलाख जनसंख्या पर शैयाओं की सर्वाधिक संख्या बरहज विकासखण्ड में है जबकि गौरीबाजार में न्यूनतम 12.2 शैया ही प्रतिलाख जनसंख्या पर उपलब्ध है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपलब्धता क्रमशः 153.6 और 25.8 है। अर्थात् इसमें लगभग 6 गुने का अंतर है।

ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक जनस्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की असफलता के अनेक कारण हैं। यहाँ न केवल विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों की अपेक्षित और उपलब्ध संख्या में अंतर है, बल्कि विशेषज्ञ डाक्टरों नर्सों मिडवाइफों रेडियो-ग्राफर फार्मासिस्ट, पुरुष स्वास्थ्य सहायक महिला स्वास्थ्य कर्मियों की अपेक्षित और उपलब्ध संख्या में भारी अंतर है। स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य उपकरणों एवं दवाओं का भी अभाव है तथा प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त डाक्टर भी शहर में ही रहना पसंद करते हैं ताकि नागर सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ और साथ ही वहाँ निजी प्रैक्टिस कर अतिरिक्त कमाई

भी कर पाएँ।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन आवश्यक है। इसके लिए 1993 से लागू *राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति* के अनुरूप 1 12 000 की जनसंख्या आधार पर 30 बिस्तरो वाले केन्द्र की स्थापना 2001 की जनगणना आधार पर कम से कम 24 होनी चाहिए। इसकी स्थापना कम से कम सभी विकासखण्ड मुख्यालयों पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य नीति के अनुरूप ही वर्तमान जनसंख्या आधार (2001) पर 91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 546 स्वास्थ्य उपकेन्द्र होने चाहिए। जबकि वर्तमान में इनकी संख्या क्रमशः 69 और 329 ही है। इस प्रकार जनपद में क्रमशः 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 22 जनस्वास्थ्य केन्द्र तथा 217 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए। तब जाकर *राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति* के अनुरूप स्थिति होगी। इन केन्द्रों की स्थापना में परिवहन एवं शिक्षा विकास से अछूते अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिए।

किसी भी क्षेत्र के विकास का तात्पर्य केवल कुछ सुविधाओं की वृद्धि करना ही नहीं है वरन् क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए ऊर्जा उपलब्धता आवास स्वच्छता प्रौद्योगिकी विकास विकसित मानव संसाधन पर्यावरण सतुलन, मनोरंजन के साधन सामाजिक सद्भाव, तथा चरित्र निर्माण भी अनिवार्य शर्त है। इनमें क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पोषण के बाद ऊर्जा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। चाहे कृषि कार्य हो उद्योग हो अथवा दैनिक क्रिया-कलाप सबके लिए ऊर्जा उपलब्धता अनिवार्य है।

ग्राम्य प्रधान अध्ययन क्षेत्र में जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, आवागमन दूरसंचार आदि सुविधाओं और साधनों का अभाव है वही ऊर्जा की कमी के कारण असहाय किसान अपने जीवनदायिनी कृषि सम्बन्धी कार्यों को भी समय पर पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ऊर्जा का प्रधान स्रोत आयातित बिजली है। जनपद के 72 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं, परन्तु विद्युत उपलब्धता का औसत ग्रामीण क्षेत्र में 11 05 घंटे और नगरीय क्षेत्र में 14 45 घंटे ही है। इस प्रकार ऊर्जा के वर्तमान स्वरूप पर क्षेत्र का समन्वित विकास सम्भव नहीं है। ये स्थिति तब है जबकि 28 प्रतिशत गाँवों में अभी बिजली ही नहीं पहुँची है। जनपद के एक मात्र भटनी विकासखण्ड में 93 5 प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत हो चुके हैं। जबकि शेष सभी विकासखण्डों में विद्युतीकरण 80 8 प्रतिशत से भी कम गाँवों में है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में ऊर्जा सिकट का समाधान गैर परम्परागत ऊर्जा ससाधनों के विकास में ही है। यही हमें दीर्घकालिक टिकाऊ विकास तथा ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आवश्यकता के कारण इसका विशेष महत्व है। अध्ययन क्षेत्र में गैर परम्परागत ऊर्जा विकास की संभाव्यता बहुत अधिक है। यहाँ सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा एवं जल ऊर्जा विकास की पर्याप्त संभाव्यता के अलावे लाखों टन कृषि उत्पाद बेकार पदार्थ के रूप में निकलते हैं, जिनसे ऊर्जा उत्पादन संभव है। अध्ययन क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर काफी ऊपर है तथा वर्ष भर पुरुआ या पछुआ हवाएँ चलती हैं। अतः पवन चक्की द्वारा सिंचाई सुविधा की पर्याप्त

सभावना है। पाँच चीनी मिलों से हजारों टन खोई निकलता है इसका उपयोग विद्युत निर्माण में सभव है। पुनः धान प्रधान क्षेत्र होने के कारण धान की भूखी से भी विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। जनपद पशुधन में सम्पन्न है अतः बायोगैस सयंत्रों के विकास की भी पर्याप्त सभावना है।

अध्ययन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों, निवासियों की आवश्यकताओं महत्वाकांक्षाओं तकनीकी कौशल और लोगों के पर्यावरण बोध पर निर्भर है। यहाँ के प्राकृतिक उपहारों का मूल्य तभी बढ़ेगा जब लोगों को उनके उपयोग का ज्ञान हो जाएगा। अतः समन्वित विकास हेतु कुछ अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करना आवश्यक है जैसे— सबसे कर्तव्यपरायणता कार्य के प्रति निष्ठाभाव स्त्रियों को शिक्षित कर उनकी क्षमताओं का विकास श्रमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु विज्ञान—प्रौद्योगिकी एवं उर्जा का उपयोग आदि। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयास एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ये उद्देश्य किस प्रकार पूरे होंगे? इसके लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है जिसमें भूगोलविदों के साथ अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों सभी का सहयोग अपेक्षित है।

* **सतीश कुमार सिंह**
शोध छात्र 'भूगोल'
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद।

★★★★★

परिशिष्ट-1

शब्दावली

अर्थव्यवस्था	<i>Economy</i>
अध्ययन क्षेत्र	<i>Study Area</i>
अपरदन	<i>Erosion</i>
अनौपचारिक	<i>Non-formal</i>
आकारकीय	<i>Morphological</i>
आदान	<i>Input</i>
आर्थिक सवृद्धि	<i>Economic Growth</i>
आधारभूत उद्योग	<i>Basic Industry</i>
आधारभूत कार्य	<i>Basic Function</i>
उपभोक्ता उद्योग	<i>Consumer Industry</i>
औद्योगिक क्रांति	<i>Industrial Revolution</i>
कार्यात्मक आकार	<i>Functional Size</i>
कार्यात्मक अंक	<i>Functional Score</i>
कार्यात्मक सूचकांक	<i>Functional Index</i>
कार्याधार जनसंख्या	<i>Threshold Population</i>
कुटीर उद्योग	<i>Cottage Industry</i>
केन्द्रस्थल	<i>Central Place</i>
केन्द्रीयता	<i>Centrality</i>
केन्द्रीयता अंक	<i>Centrality Score</i>
केन्द्रीयता सूचकांक	<i>Centrality Index</i>
केन्द्रीय कार्य	<i>Central Function</i>
कृषियोग्य भूमि	<i>Culturable Land</i>
कृषित	<i>Cropped</i>
कृषिसम्पदा	<i>Agricultural Resources</i>
खनन	<i>Mining</i>
खनिज अयस्क	<i>Mineral ore</i>
खरीफ	<i>Kharif</i>
गहन कृषि	<i>Intensive Agriculture</i>
गैर आबाद	<i>Uninhabited</i>
गृह उद्योग	<i>House hold Industry</i>
चकबंदी	<i>Consolidation of Holding</i>

जलग्रहण क्षेत्र	<i>Catchment Area</i>
जलस्तर	<i>Water Table</i>
जोत	<i>Holding</i>
डेयरी उद्योग	<i>Dairy Industry</i>
ढलान	<i>Gradient</i>
तालाब	<i>Tank</i>
तिलहन	<i>Oilseeds</i>
तृतीयक कार्य	<i>Tertiary work</i>
नलकूप	<i>Tube well</i>
नौ परिवहन	<i>Navigation</i>
पदानुक्रम	<i>Hierarchy</i>
पर्यटन	<i>Tourism</i>
प्रवेशी जनसख्या	<i>Intry Point Population</i>
फसल कोटि	<i>Crop rank</i>
वृहद् उद्योग	<i>Large scale Industry</i>
वृहत् स्तरीय	<i>Macro level</i>
भौम जल	<i>Ground Water</i>
मध्यम स्तरीय	<i>Meso level</i>
लघु उद्योग	<i>Small scale Industry</i>
विकास केन्द्र	<i>Growth Centre</i>
विकास ध्रुव	<i>Growth Pole</i>
विनिर्माण	<i>Manufacturing</i>
संपृक्त जनसख्या	<i>Saturation point Population</i>
शस्य गहनता	<i>Crop-Intensity</i>
शस्य संयोजन	<i>Crop-Combination</i>
शुद्ध कृषित क्षेत्र	<i>Net Swon Area</i>
सडक जाल	<i>Road Network</i>
सडक सम्बद्धता	<i>Road Connectivity</i>
समन्वित	<i>Integrated</i>
सहत	<i>Compact</i>
सविकास	<i>Eco-development</i>
सूचकांक	<i>Index</i>
सूक्ष्म स्तरीय	<i>Micro-level</i>
सेवाकेन्द्र	<i>Service Centre</i>
सेवाक्षेत्र	<i>Service Area</i>
सेवित जनसख्या	<i>Served Population</i>
शुष्क कृषि	<i>Dry Farming</i>
हृदय क्षेत्र	<i>Heart Land</i>

परिशिष्ट-2

शब्द सक्षेप (ABBREVIATIONS)

<i>A A A G</i>	-	<i>Annals of the Association of American Geographers</i>
<i>Can Geog</i>	-	<i>Canadian Geographer</i>
<i>C G R</i>	-	<i>Calcutta Geographical Review</i>
<i>Econ Geog</i>	-	<i>Economic Geography</i>
<i>Geog obs</i>	-	<i>The Geographical Observer</i>
<i>Geog Out</i>	-	<i>Geographical Outlook</i>
<i>G R I</i>	-	<i>Geographical Review of India</i>
<i>I G J</i>	-	<i>Indian Geographical Journal</i>
<i>I G U</i>	-	<i>International Geographical Union</i>
<i>I S C A</i>	-	<i>Indian Journal of Marketing Geography</i>
<i>I J M G</i>	-	<i>Indian Science Congress Association</i>
<i>J Mad G A</i>	-	<i>Journal of Madras Geographical Association</i>
<i>J Reg Sc</i>	-	<i>Journal of Regional Science</i>
<i>J R S S</i>	-	<i>Journal of Royal Statistical Society</i>
<i>N C A E R</i>	-	<i>National Council of Applied Economic Research</i>
<i>Nat Geog</i>	-	<i>National Geographer</i>
<i>N G J I</i>	-	<i>National Geographical Journal of India</i>
<i>N G S I</i>	-	<i>National Geographical Society of India</i>
<i>P H R</i>	-	<i>Pacific Historical Review</i>
<i>Prof Geogr</i>	-	<i>The Professional Geographer</i>
<i>Scot Geog Mag</i>	-	<i>Scottish Geographical Magazine</i>
<i>T I B G</i>	-	<i>Transactions of the Institute of British Geographer</i>
<i>T I I G</i>	-	<i>Transaction of the Institute of Indian Geographers</i>
<i>U B B P</i>	-	<i>Uttar Bharat Bhoogol Parishad/Patrika</i>

परिशिष्ट-3

(FURTHER READING)

- Abder, R , - 'Spatial Organisation' Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1967*
- Agarwal, S N , - 'Indian Population Problems', Tata McGraw Hill, Bombay-1972*
- Ahmed E , - 'Geomorphic Regions of Peninsular India', Journal of Ranchi University, 1/9 1962, pp 1-29*
- Ahmad, E , - 'Origin & Evolution of Towns of Uttar Pradesh', Geographical Outlook No 1 1956*
- Arora, R C , - 'Development of Agriculture and Allied Sectors- An Integrated Area Approach', New Delhi, 1976 pp 1-9*
- Berry, B J L - 'Geography of Market Centres and Retail Distribution', Prentice Hall, 1967*
- Bhatia, S S , - 'A Reconsideration of the Urban Concept of the Primate City', I G J 1962*
- Bhalla C S , - 'Changing Agrarian Structure in India, A study of the Impact of Green Revolution in Haryana', Meenakshi Prakashan, Meerut 1972*
- Bhatt, L S , - 'Regional Planning in India', Statistical Publishing Society, Calcutta, 1972*
- Carter, H , - 'The Study of Urban Geography', Edward Arnold London 1977*
- Christaller, W - 'Central Place in Southern Germany', Translated by C W Baskin, 1966 New Jersey*
- Champion, H G , - 'A Preliminary Survey of Forest Types of India and Burma', Indian Forest Record, New Series, Silviculture, Vol 1, Delhi, 1936*
- Carter, H - 'Urban Grade and Sphere of Influence in South West Wales', S G M Vol 71 (1955), pp 43-58*
- Chauhan, D S , - 'Studies in the Utilisation of Agricultural Land', Shiv Lal & Co , Agra-1966*
- Chandna, R C and*

- S Manjit* , - *'Introduction to Population Geography'*, Concept Publishing Company, New Delhi, 1980
- Davies, W K D* , - *'Centrality and Central Place Hierarchy'*, Urban Studies
- Dubey, B and N Singh*, - *'Integrated Rural Development'*, Jeevan Dhara Publication, Varanasi-1985
- Dutta, A K* , - *'Two Decades of Planning-India An Anatomy of Approach'*, N G J I Vol XVIII (3-4), 1972, pp 187-205
- Friedman J* , - *'Cities in Social Transformation, Reprinted in J Friedman et al (ed) 1964, Regional Development Planning- A Reader (1961) pp 343 60*
- Gadgil, D R* , - *'District Development Planning'*, Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona, 1967 pp 1-38
- Glasson, J* , - *'An Introduction of Regional Planning-Concept, Theory and Practice'* London, 1978, pp 24-31
- Gould, P R* , - *'The Development of the Transportation Pattern in Ghana'*, Illinois, 1960 p 132
- Government of India*, - *'Irrigation and Power Projects'*, Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, 1970
- Haggerstrand, T* , - *'Innovation Diffusion as a Spatial Process'*, Chicago-1970
- Hanson, N M* , - *'Growth Centres in Regional Economic Development'*, The Free Press, New York
- Haggett, p* , - *'Location Analysis in Human Geography'*, Arnold, London 1967
- Hansen, N M (ed)*, - *'The Regional Economic Development'* The Press, New York-1972
- Harvey D* , - *'Social Justice and the City'*, Edward Arnold, London-1973
- Johnson, R J* , - *'Central Place and the Settlement Pattern'*, A A A G No 56 1966
- Khan S A* , - *'An Application of the Nearest Neighbour Analysis in the Spacing of Central Place'*, Nat Geog , Vol-23, No 2 1988
- Kharkwaw, S C & Bhatt H P*, - *'Rural Central Place in Central Garhwal Himalaya'*, Nat Geog , Vol 13, No 1 1988
- Kar, N R* , - *'Urban Hierarchy and Central Function Around Calcutta and their Significance'*, Land Studies in Geography, Series B, Human Geog No 24, 1962

- Kuznetsov, VI*, - *'Economic Integration- Two approaches', Progres Publishers, Moscow, 1975 pp 13-35*
- Khan W & R N Tripathi*, - *'Plan for Integrated Rural Development in Paurigarhawal', N I C D Hyderabad 1976*
- Mishra B N*, - *'Spatil Pattern of Service Centres in Mirzapur Dist U P', Unpublished Thesis, in Geography, 1980*
- Mishra, H N* - *'The Concept of Umland A Review', nat Geog, Vol 6 1971*
- Majid Hussain,,* - *'Crop Combination in India', Concept Publishing Company, New Delhi, 1982*
- Mandal R B*, - *'Central Place Hierarchy in Bihar Plain', N G J I, Vol 21 1975*
- Mishra, R P* - *'Growth Pole Strategy for Rural Development in India', J I E G 1970*
- Mishra, R P* - *'The Process of Regional Development, Theoretical Foundation in Regional Development Planning in India', (eds) R P Mishra et al , Vikash Publishing house, New Delhi 1975*
- Mishra, R P*, - *'Local level Planning and Development' Sterling Publishers, New Delhi-1983*
- Mishra, R P*, - *'District Planning A Handbook, Concept Publishing & Co , New Delhi-1990*
- Moseley, M J* - *'Growth Centres in Spatial Planning', Pergaman Press, Oxford 1974*
- Myrdol G M* - *'Economics Theory and Underdevelopment Region', London 1975*
- Mukherjee, A B*, - *'Spacing of Rural Settlement in Rajasthan, A Spatial Analysis', Geog Outlook 1970*
- Nicholson, M*, - *'The Environmental Revolution', Penguin, Harmondsworth, 1972*
- Pandey, J N*, - *'Role of Central Place in Integrated Rural Development', I S C A - 1987*
- Rao, V L S P*, - *'Regional Planning', Indian Finance, Calcutta, 1949*
'Regional Planning', Asia Publishing House, Bombay, 1963
- Scoott P*, - *'The Hierarchy of Central Places in Tasmania', Aust Geog, No 9 1964*

- Sen, L K , - *'Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development A Study in Miryalguda Taluka', N I C D , Hyderabad 1971*
- Sen, L K , - *'Growth Centres in Raichur An Integrated Area Development Plan for A district in Karnatka', N I C D , Hyderabad 1975*
- Singh, J & Ved Prakah, - *'Central Place and Spatial Integration- A Critical Approach' N G J I Vol 21, 1973*
- Singh L , - *'An Approach for Delimitation of Central Place Region- A case Study of Patna District', U B B P, Vol 18, No 1 1982*
- Singh, O P, - *'Towards Determining Hierarchy of Service Centre- A methodology for Central Place Study', N G J I , Vol 17, No 4, 1971*
- Singh O P, - *'Central Places, Indentification, Selection and Types', U B B P, Vol X, No 3 1974*
- Singh, H P, - *'Development Pole Theory Review and Appraisal', Nat Geog Vol 13, No 2 1978*
- Singh, J, - *'Transport Geography in South Bihar', N G S I, Varanasi, 1964*
- Singh, L R , Savindra, Tiwari, R C and Srivastava, R P, *'Environmental Management (ed)', Allahabad Geographical Society, Geog Deptt A U 1983*
- Singh, R N & Sahab Deen , - *'Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U P A Case Study of Trade and Commerce', I G J Vol 56*
- Tiwari, R C , - *'Rural Settlement Systems of Pratabgarh District- A Study in Spatial Pattern', Nat Geog Vol-17, No 2 1982*
- Wadia, D N , - *'Geology of India (Economic Minerals) 5th ed , Mac Millan, London, 1965*
- Wanmali, S , - *'Regional Planning for Social Facilities An Examination of Central Place Concept and their Aplication.'*

